1

प्रस्तावना
(Introduction)

“आतंकवाद एक बर्बर कार्यवाही है, आतंकवाद का समर्थन करने वाले वहशी लोग होते हैं।”

–राष्ट्रपति रीगन

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की दोनों महाशक्तियों – अमेरिका तथा सोवियत संघ में शीत युद्ध का प्रारम्भ हो गया और यूरोप की साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी ताकतों से अपनी मातृ भूमियों को आजाद कराने के लिए एशिया एवं अफ्रीका के देशों के मूल निवासियों ने छापामार युद्ध को अपना कर अपने राष्ट्रों को स्वतंत्र करवाया।

गुरिल्ला युद्ध कर्म के परम्परागत योद्धा माओत्सेतुंग एवं हो ची मिन्ह, वी. एन. गियाप एवं ची ग्वेरा तो इस युद्ध विधि को सुदूर ग्रामीण अंचलों, पर्वतीय क्षेत्रों, घने जंगलों एवं गुफाओं में आधार क्षेत्र बना कर प्रयोग करते थे, परन्तु बाद के छापामार विचारक जैसे कार्लोस मैरीघेला के साथ नगरीय छापामार युद्ध का युग आया और इस नई युद्ध पद्धति के नये हथियार के रूप में आतंकवाद का प्रयोग किया जाने लगा।

आतंकवाद भी विश्व के अनेक भागों में फैलकर क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय हो गया और 11 सितम्बर 2001 को अमेरिका के विश्व व्यापार केन्द्र (डब्ल्यू. टी. सी.) के दोनों टॉवरों पर अलकायदा के आत्मघाती–हमलावरों द्वारा उनका विध्वंश कर दिया गया ।

इस घटना के बाद से तो अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद में “आत्मघाती–हमलों” का प्रयोग बहुत अधिक संख्या में होने लगा। ‘आत्मघाती–हमलों’ का प्रयोग आज विश्व के अनेकों खतरनाक आतंकी समूह कर रहे हैं। **इनमें लिट्टे, हमास, इराक–अफगानिस्तान में तालिबान, अलकायदा, लश्करे–तैयबा, उत्तरी आयरलैण्ड में आई. आर. ए. (आयरिश रिपब्लिकन आर्मी) इत्यादि** आतंकवादी आत्मघाती हमलों का प्रयोग बढ़–चढ़ कर कर चुके हैं।

ऐसा कोई भी दिन खाली नहीं जाता, जब हम सुबह अखबार पढ़ते समय कहीं–न–कहीं आत्मघाती हमलों के बारे में कोई खबर न पढ़ते हो। आज विश्व के हर कोने में आत्मघाती हमले अत्यधिक प्रचलन में हैं। विश्व का कोई भी नागरिक इनसे सुरक्षित नहीं है। इसलिये “आत्मघाती हमले” आज के मानव

जीवन की सबसे भयंकर समस्या बन कर उभरे हैं। अतः उनके समाधान और नियंत्रण पर शोध कार्य अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। इसी सोच के साथ इसफस्तक को लिखा गया है।

आज आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, समृद्धि, सहयोग, स्थिरता, सहिष्णुता, सामर्थ्य एवं स्थापित मूल्यों के लिये एक बहुत बड़ी आपदा के रूप में उभरा है, जिससे संपूर्ण विश्व किसी–न–किसी रूप में आहत हो रहा है। अब आतंकवाद न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के लिये अपितु संपूर्ण संसार के लिये एक बड़ी आपदा बन चुका है। आत्मघाती हमला वास्तव में बुद्धि के दुरुपयोग का परिणाम तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी के अभिशाप का भयंकर उदाहरण है। यह एक ऐसा दानव है, जिसकी परिधि में विश्व का प्रत्येक देश आता है और जो किसी देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति या सुदृढ़ संरचना को भी ध्वस्त करने में सक्षम है। संपूर्ण राष्ट्र की सामूहिक बुद्धि जिस ठिकानों को सुरक्षित समझती है, वहाँ भी अप्रत्याशित रूप से यह हमला करते हैं तथा आतंकवाद के शिकार राज्य व राष्ट्र स्वयं को शक्तिहीन और निर्बल पाते हैं। आतंकवाद का दावानल इतना भयानक रूप धारण कर चुका है कि इसके थमने के आसार अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं।

आत्मघाती आक्रमण आतंकवाद का सबसे घातक व विनाशक स्वरूप है। यह एक ऐसा साधन है, जिसका प्रतिरोध अब तक दुनिया की किसी भी सुरक्षा एजेंसी, सरकार, सेना व शक्ति के पास नहीं है। **अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी** की हत्या के कुछ दिन पूर्व **सी.आई.ए. (अमेरिकी खुफिया एजेंसी)** के तत्कालीन निदेशक ने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को मरने का डर न हो तो उससे अधिक खतरनाक दुनिया का कोई भी आदमी नहीं होता। वैसे भी कहा जाता है कि अकेला शत्रु अधिक घातक होता है। मानव बम या आत्मघाती हमला करने वाले व्यक्ति की खतरनाक स्थिति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि मानव बम बने व्यक्ति को हर पल याद रहता है कि उसके द्वारा उठाये गये इस कदम से सबसे पहले उसी की मौत होगी। इसके बावजूद अगर उसमें अपने लक्ष्य को पूरा करने का जोश, जुनून, जिद्द और जज्बा रहता है तो उसकी लक्ष्य प्राप्ति की पराकाष्ठा को स्पष्ट रूप से अनुमानित किया जा सकता है।

''आज की तिथि में **आत्मघाती दस्ता (फिदायीन)** मजहबी लड़ाई का ही एक घातक हथियार है, जो कट्टरपंथ की ही देन है। एटम बम से भी घातक बना मानव बम एक चलता–फिरता विस्फोटकों से लैस इंसान होता है, जो अपने निर्धारित लक्ष्य के परखच्चे उड़ाने के साथ ही स्वयं को भी असंख्य चीथड़ों में तब्दील हो जाता है। इस प्रकार के आत्मघाती दस्तों को तैयार करने में सबसे ज्यादा महारत श्रीलंका के कुख्यात आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) को प्राप्त थी, जिसने (वी.आई.पी.) को मानव बम का शिकार

बनाया। मानव बम लिट्टे आतंकवादी संगठन का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बना, जिसका जवाब श्रीलंका की सेना व रणनीतिकारों को बहुत मुश्किल से मिल पाया।''[1]

मानव बम का मनोविज्ञान

आत्मघाती हमला करने वाला मानव बम कब और क्यों बनता है कोई? वे कौन–सी परिस्थितियाँ होती हैं, जब कोई व्यक्ति सदैव जीवित रहने की स्वाभाविक इच्छा के विपरीत **'मानव बम'** बनने को तैयार हो जाता है। सवाल यह उठता है कि क्या आम आदमी मानव बम बन सकता है? कहा जा सकता है कदापि नहीं। वस्तुतः जब किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर धर्म, जाति, क्षेत्र या नस्ल का जोरदार व जबरदस्त जुनून सवार हो जाता है तो वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है और अपनी आत्माहुति से भी संकोच नहीं करता। मानव बम की मानसिकता केवल एक मानसिक रोग के कारण ही नहीं बनती, बल्कि उसके समूचे व्यक्तित्व में बने असंतुलन के कारण ही पैदा होता है। जिस व्यक्ति में मानसिक असंतुलन होगा, उसे ही कोई आतंकवादी गिरोह अपने मकड़जाल में फंसा पाता है। यह भी एक प्रकार की व्यक्तित्व विक्षिप्तता है। इसके चलते ही वह अपने मुखिया के आदेशों का अक्षरशः पालन करने लगता है। मानव बम अथवा आत्मघात के पीछे एक मास्टर माइंड काम करता है।

मरने–मारने का संकल्प लिये एक चलता–फिरता इंसान, जब घातक विस्फोटों से लैस हो, मानव बम में तब्दील हो जाता है, तो यह आतंकवाद का चरम बन जाता है। 'दुनिया में दहशत और भयानक परिदृश्य का पर्याय बने मानव बम बनना कोई हंसी–खेल नहीं है। यह एक दीक्षा है, बहुत कठिन दीक्षा, जो इसमें सफल होते हैं, उसे ही यह दुर्लभ सम्मान मिलता है।' अब हम संक्षिप्त में उन कारणों का उल्लेख करते हैं, जिसके कारण मानव बम बन जाने हेतु प्रेरित होता है।

1. घोर गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा एवं अपरिपक्वता मूल कारण हैं जो किसी नवयुवक को मानव बम बन जाने हेतु प्रेरित करते हैं।
2. जज्बा व जोश के साथ अपने लक्ष्य हेतु जुनून जागृत करने के लिये प्रतिकूल परिदृश्य दिखाकर प्रेरित करना।
3. ड्रग का सेवन करवा करके जब वह मानसिक रोगी बन जाये तो अपनी कठपुतली बनाकर आत्मघाती बम बनाया जाता है।
4. मानसिक परिवर्तन करके व नशीले पदार्थ देकर उनके शून्य मस्तिष्क में मन–मुताबिक इबारत लिखी जाती है।
5. दमन और बेबसी की पराकाष्ठा से छुटकारा पाना।
6. साहसहीनता की ग्रंथि से मुक्त होना।
7. आत्मगौरव की लालसा रखना।

---

[1]डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र, ''आतंकवाद व आपदा प्रबंधन'', 2010, राधपब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, पृष्ठ संख्या–110–112

8. फनर्जन्म पर कट्टर आस्था रखना।
9. अपने लक्ष्य को दुनिया का सबसे महान लक्ष्य मानना।
10. अपने गुरू, नेता तथा अगुआ के प्रति उन्मादी आस्था रखना। ऐसे लोग ही मानव बम बनने का निर्णय लेते हैं।

तमाम तरह के प्रेरित जज्बों के अलावा एक आत्मकेंद्रित मनोविज्ञान, किसी को मानव बम बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव बम बनने की इच्छा आमतौर पर अहं–केंद्रित लोगों के मन में पैदा होती है। आत्महत्याओं पर होने वाले शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्महत्याएं ज्यादातर वे ही लोग करते हैं, जो अहं से चूर होते हैं और शारीरिक रूप से कमजोर। **यही कारण है कि युवतियाँ मानव बम बनने के लिए सबसे ज्यादा उतावली रहती हैं।** आत्महत्याओं के आँकड़ों को भी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाली जवान औरतें ही होती हैं। मानव बम बनने वाला इंसान समाज से पूरी तरह कट कर अपने सीमित लक्ष्य के जुनून में हर पल जीता है। वह न तो आदर्श पति बन सकता है, न पत्नी, न बेटा, न बाप, न माँ, न बहन। उसके जेहन में हरदम बस एक ही लक्ष्य घूमता रहता है कि वह किस तरह अपने शिकार को दबोचे और उसके साथ ही अपनी इहलीला भी समाप्त कर ले।

आत्मघात के मनोविज्ञान का एक बड़ा आधार धार्मिक और नस्ली रुझान वाला समाज भी होता है। जिन समाजों में धर्म और नस्ल को वरीयता दी जाती है, वहाँ आत्मघात की गुंजाईश ज्यादा आसानी से विकसित हो जाती है। यही कारण है कि जर्मनी में हिटलर रातों–रात सितारा बन गया था, क्योंकि जर्मन समाज नस्ली श्रेष्ठता बोध से ओत–प्रोत समाज है। यही वजह है कि मानव बम आमतौर पर धर्मभीरू इस्लामिक देशों, विशेषकर मध्यपूर्व के इलाके और श्रीलंका जैसे देश में पैदा हुए हैं। इंग्लैंड और अमेरिका जैसे उन्मुक्त समाजों में मानव बम उतनी सहजता से नहीं पैदा होते, जितनी आसानी से कट्टरवाद समाजों में। धार्मिक कट्टरता भी जुनून पैदा करती है।

आत्मघाती हमले के तरीके

मानव बम जिन विस्फोटक तत्त्वों का इस्तेमाल करता है, उसके प्रमुख चार तरीके इस प्रकार हैं – केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेकैनिकल। केमिकल विस्फोट दो से अधिक रसायनों के मिश्रण से प्रभावी होता है। इसका प्रयोग आमतौर पर आत्मघाती दस्ते द्वारा नहीं किया जाता। जब कभी इसका इस्तेमाल करने के लिये विस्फोट हेतु गोदामों को आमतौर पर चुना जाता है। इस विधि में विस्फोट हेतु मानव बम या आत्मघाती आतंकवादी उस जगह मौजूद नहीं रहता। इस तरह के विस्फोट के लिये बम के खोल से जुड़ी दूसरी परत में एक निश्चित मात्रा में तेजाब भर दिया जाता है, जो एक निश्चित अवधि में उस परत को काट देता है और इससे भयानक विस्फोट होता है। इस तरह के बमों का इस्तेमाल मानव बम अक्सर शस्त्र गोदामों, बिल्डिंग उड़ाने आदि के लिये करते हैं। मानव बम सबसे ज्यादा जिस विस्फोट विधि का इस्तेमाल करते हैं वह है

इलेक्ट्रिकल विस्फोट विधि। मानव बम के लिये आर.डी.एक्स. इसलिये भी एक अनुकूल विस्फोटक है, क्योंकि इसे किसी भी शक्ल में ढ़ाल कर शरीर से संबंधित किया जा सकता है। अमूमन कोई मानव बम 6 से 8 किलोग्राम आर.डी.एक्स. को बेल्ट में भरकर उसे ब्लास्टिंग डिटोनेटिंग कैप और बैटरी से जोड़कर कमर से बाँध लेता है। राजीव गाँधी की हत्या करने वाली मानव बम महिला ने इसी विधि से विस्फोट किया था। ऐसी विधि में मानव बम की सुविधाजनक पहुँच में एक बटन मौजूद होता है, जिसको दबाते ही टारगेट चाहे जितनी सुरक्षा से घिरा हो, परखच्चे उड़ जाते हैं। शेष दो विधियों का इस्तेमाल पारंपरिक तरीके से होता है।

श्रीलंका के आतंकवादी संगठन लिट्टे को मानव बमों के मामले में दुनिया के सबसे खूँखार आतंकवादी संगठनों मे गिना जाता रहा, जो विस्फोट विशेषज्ञों और रक्षा मनोवैज्ञानिकों के लिये रहस्य का विषय रहा। स्वीडन स्थित पीस फाउंडेशन में विगत वर्षों में इसका अध्ययन, मनन, चिंतन एवं शोध करने का अथक प्रयास किया कि आखिर खूँखार आतंकवादी संगठन लिट्टे अपने लड़ाकों में कौन–सा ऐसा जज़्बा, जोश एवं जुनून पैदा कर देता है, जिसके कारण संगठन का व्यक्ति बिना किसी भय के हँसते हुए मौत को गले से लगा लेता है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर विगत दिनों में जब बौद्ध धर्म अपने विकास एवं विस्तार हेतु संघर्ष कर रहा था, उसी समय अपने धर्म की रक्षा के लिये बलिदान करना गौरव व गरिमापूर्ण समझा जाने लगा, जिसके फलस्वरूप ही चरम–ध्वंस का यह घातक तरीका विकसित हुआ। बौद्ध अनुयायी सत्ता संघर्ष करने के लिये अपने अस्तित्व की परवाह नहीं करते थे।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जापानी सेनाओं ने अपनी रक्षा पंक्ति को बनाये रखने के लिए अनेक आत्मघातक कौशल दिखाये। जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका एवं जापान के बीच लड़ा गया आकोनावा युद्ध बहुत मशहूर हुआ। जापान के तटीय क्षेत्र तरावा में हुई यह भीषण लड़ाई मानव बमों (आत्मघाती दस्तों) के वर्तमान विध्वंसक चेहरे की शुरुआत थी। एक सप्ताह की इस लड़ाई में लगभग 1000 जापानी सैनिकों ने आत्मबलिदान कर दिया और जापानी बेड़े के सामने आखिर अमेरिकी बेड़े को पीछे हटना पड़ा।

जिस समय जापानी सेना अपने अनेक अथक प्रयासों के बावजूद असफलता की ओर बढ़ रही थी, उसी समय एक व्यापक रणनीति के तहत 150 मोटर नौकाएँ अमेरिकी युद्धपोतों पर चारों ओर से लपकीं और जब तक अमेरिकी सैनिक इस स्थिति का अनुमान लगा पाते तब तक एक भयंकर विस्फोट के साथ ओकीनावा का समुद्र अमेरिकी सैनिकों के रक्तपात से लाल हो गया। अमेरिका के पाँच युद्धपोत जो कि समुद्री क्षेत्र में अजेय पहाड़ की तरह खड़े थे, देखते ही देखते घास–पूफस की तरह बिखर गये। जापान की सेनायें एक हारते हुए युद्ध मोर्चे से जीत की ओर मुड़ गई। इसके पीछे वास्तव में जापानी मोटर नौकायें भारी विस्फोटक पदार्थों से लदी थीं, जो अमेरिकी युद्धपोतों से 11 सितम्बर, 2001

की भाँति टकराकर स्वयं नष्ट होने के साथ ही अमेरिकी युद्धपोत के भी परखच्चे उड़ा दिये।

जापानी जाँबाज सैनिकों को यह स्पष्ट रूप से आभास था कि इस आत्मघाती रणनीति के द्वारा ही अमेरिकी युद्धपोतों को आगे बढ़ने से रोका जा सकेगा। इसी कारण वे जुनून, जोश, जज्बे व ज़मीर के बल पर अपनी मोटर नौकाओं को विशालकाय युद्धपोतों से टकराकर स्वयं के साथ ही अमेरिकी सैनिकों के भी चीथड़े–चीथड़े कर दिये। इनको **वर्तमान आत्मघाती दस्ता या मानव बम का जनक कहा जा सकता है।** अमेरिकी इतिहासकारों ने इस युद्ध को मानव बमों के **अंध उन्माद** के रूप में वर्णित किया है। जापानी सेना इन मानव बमों को **'कामी–काजी'** नाम दिया था। ओकीनावा युद्ध के बाद तो जैसे आत्मघाती उन्माद का सैलाब आ गया। अमेरिका के 27 युद्धपोतों को जापान के इन **'कामी–काजी'** दस्तों ने देखते ही देखते ही ध्वस्त कर दिया। यही नहीं इन **'कामी–काजी'** ने पर्ल हार्बर में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों की चिमनियों में कूदकर आत्मघाती दुस्साहस का एक नया अध्याय शुरू कर दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जापानी सेना के पास लगभग 950 मानव बम थे, वे सभी युद्ध में मारे गये थे। वास्तव में यह मानव बमों का अंत नहीं, बल्कि एक मजबूत आधार स्थापित हुआ था। इसका प्रमाण उस समय मिला जब 9 मई 1972 में इजरायल के एक हवाई अड्ड़े में एक आत्मघाती व्यक्ति या मानव बम ने विस्फोट कर 26 लोगों के परखच्चे उड़ा दिये थे। इस घटना को **'जापानी रेड आर्मी'** ने अंजाम दिया था। इसी के साथ मानव–बमों के प्रयोग का दुस्साहस शुरू हो गया था।

आधुनिक सदी में मानव बम की टोली बनाने का काम सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1979 में ईरान के अयातुल्ला खुमैनी ने शुरू किया, जिसमें उन्हें भरपूर सहयोग मिला, लीबिया के कर्नल मुअम्मार गद्दाफी और फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन (PLO) के नेता यासिर अराफात से और इसका संचालन केंद्र बना लेबनान। एक साल के अंदर इस्लामी जिहाद के बैनर तले मिड्ड से लेकर फिलीपींस तक पूरे मुस्लिम जगत में आत्मघाती दस्ते का जाल बिछ गया। 1982 में लेबनान में फिलीस्तीनी शरणार्थी शिविरों पर की गई इजरायली बमबारी के बाद उग्रवादियों ने खूँखार रुख अपनाया और फिलीस्तीनियों की जो भी जमीन इजरायल ने छोड़ी है, उसका श्रेय आत्मघाती दस्ते को जाता है। अभी इस्लामी जगत में सक्रिय **'हिजबुल्ला'** व **'इस्लामी इत्तेहाद'** यासिर अराफात के नेतृत्व में काम करने वाले **'हमास'** के साथ मिलकर काम करते हैं। वैसे तो कहने को **'हिजबुल्ला'** का सबसे बड़ा समर्थक है ईरान, लेकिन दरअसल इसके लिये पंफड पूरे मुस्लिम जगत से आता है। ये सारे आत्मघाती दस्ते ओसामा–बिन–लादेन (जो 2 मई 2011 को मारा गया) के नेतृत्व वाले **'अलकायदा'** के साथ मिलकर योजनाएँ बनाते हैं, जिसने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में अपने को ज्यादा केंन्द्रित कर रखा है। इसमें पाकिस्तान का **'हिजबुल मुजाहिदीन'** भी शामिल है। सूडान, मिड्ड, अल्जीरिया, तुर्की के मानव बम दस्ते इसी के

दिशा–निर्देश पर चलते हैं। तुर्की की '**खुर्दिस्तान वर्क्स पार्टी**' के नेता अब्दुल्ला ओमालम ने इसी हथियार की बदौलत अपने हक हासिल किये। अमेरिका की शान दाव पर लगी हुई है, पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा है, अफगानिस्तान मरने–मारने पर उतारू है और भारत के पास भी इस लड़ाई में शामिल होने के सिवाय कोई चारा नहीं है।

अमेरिकी धमकियों की अफगानिस्तान को इसलिये परवाह नहीं है, क्योंकि वे हमेशा युद्धरत रहने वाला मुल्क है। कबीलाई मानसिकता वाले इन अफगानिस्तानियों को किसी बाहरी हमले की जरूरत भी नहीं रहती, वे आपस में ही लड़ते रहते हैं, भले ही देश कंगाल हो जाये। अगर उन्हें ओसामा–बिन–लादेन को अमेरिका के हवाले करना होता तो 1998 में केन्या व तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों को उड़ाने के बाद ही कर देते, जिसके बाद अमेरिका ने ओसामा–बिन–लादेन को पकड़वाने के लिये पाँच करोड़ डॉलर ईनाम की घोषणा की थी। इसके पहले कि अमेरिका अफगानिस्तान की मोर्चाबंदी करे, लादेन काबुल छोड़कर किसी गुप्त ठिकाने पर चला गया, सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए 15,000 फिदायीन जवान हमेशा तैनात रहते थे। इसके पहले भी अमेरिका ने सूडान और रियाद में लादेन के संदिग्ध ठिकाने पर बमबारी की थी पर हाथ कुछ न लगा। यह लड़ाई अगर मजहबी रंग पकड़ लेती है तो मानव बम की टोली बढ़ती जाएगी और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गृहयुद्ध भी छिड़ सकता है। उससे भारत की कौन कहे, अमेरिका भी अछूता नहीं बचेगा, जहाँ मुस्लिमों की आबादी एक करोड़ है।

आतंकवाद की यह आपदा उस समय अपने चरम पर पहुँच जाती है, जब मरने–मारने का संकल्प लिये एक चलता–फिरता आदमी घातक, विस्फोटक एवं विध्वंसक साधन से लैस हो **मानव बम या आत्मघाती या फिदायीन में तब्दील हो जाता है।** दुनिया में दहशत और भय का पर्याय बने मानव–बम के कारण आतंकवाद अत्यंत घातक बन चुका है। आतंकवाद के इस खूँखार स्वरूप के कारण दुनिया दहशत में आ गई है। शक्तिशाली व्यक्ति, राज्य, राष्ट्र व समाज अब अपने को सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त के बावजूद सुरक्षित अनुभव नहीं कर पाता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका भी आखिरकार आतंकवाद के इसी आत्मघाती दस्ते का शिकार हुआ।

अमेरिकी मिसाइलों का जवाब दुनिया भर में फैले कट्टरपंथी मुस्लिम आतंकवादी मानव बम से देंगे, जिसे आत्मघाती दस्ता कहा जाता है। अमेरिका ने यों तो यह जंग, आतंकवाद का सफाया करने के लिये छेड़ी है, मगर मुस्लिम देशों में इसे मुसलमानों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान के रूप में लिया गया है क्योंकि आतंकवाद उनका सुरक्षा कवच है और इस कवच का इस्तेमाल ठीक ऐसे समय में करने की नौबत आ गई, जब अमेरिका अपने लिये मिसाइल रक्षा कवच योजना को अंतिम रूप देने में जुटा था। इसके पहले कि इस योजना के लिये अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिले, आतंकवादियों के खिलाफ विश्व भर को गोलबंद करने की जरूरत पड़ गई। अमेरिका को विभिन्न देशों में अपने दूतावासों को बचाने की

भी फिक्र है। यह लड़ाई अमेरिका अपनी साख बचाने के लिये लड़ेगा और मुस्लिम जगत पूरी तरह से मजहबी जंग (जिहाद) में शामिल होंगे। आत्मघाती दस्ता (फिदायीन) मजहबी लड़ाई का ही हथियार है, जिसकी काट कोई हथियार नहीं हो सकता। मानव बम का मुकाबला परमाणु बम भी नहीं कर सकता, जिसके इस्तेमाल का सुझाव पूर्व विदेश मंत्री हेनरी कीसिंगर ने जॉर्ज बुश को दिया है। 1995 में सउदी अरब में अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर यही सोचकर हमला किया था कि मक्का–मदीना जैसी पवित्र जमीन पर अमेरीकियों का होना इस्लाम का अपमान है।

उग्रवादियों के पास न तो पैसे की कमी है, न ही हथियार की। उनके हाथ में भी वैसे हथियार हैं, जो अमेरिकी फौज इस्तेमाल करती है और अमेरिका से ही खरीदे हुए हैं, लेकिन मानव बमों का जखीरा बनाने का श्रेय जाता है, **'ओसामा–बिन–लादेन'** को जिसको पकड़ने के लिये अमेरिका ने ऐड़ी–चोटी एक करने के बाद अब अफगानिस्तान की घेराबंदी शुरू की है। अमेरिका ने 15 अरब देशों के सामने दो विकल्प रखे हैं कि या तो उग्रवाद के खिलाफ सहयोग करें अथवा उसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहे। 11 सितंबर की घटना से कुछ ही दिन पहले सउदी अरब की मदद से दुबई में एक गुप्त बैंक की स्थापना की गई, जिसका संचालन ओसामा के जिम्मे था। इस बैंक का काम फिदायीन दस्ते में शामिल युवकों के परिवारजनों की परवरिश व पढ़ाई–लिखाई की व्यवस्था करनी है। लेबनान के **'अखबार अल अहराम'** के मुताबिक इस बैंक में सारे मुस्लिम देशों ने पैसा लगाया है और इसमें खरबों डॉलर हमेशा जमा रहते हैं। फिदायीन के हथियार व हथियारों के साथ छापामार युद्ध के प्रशिक्षण का एकाउंट अलग हैं। ओसामा–बिन–लादेन का तो ब्रांड नाम चलता है, इसके लिये सारे अरब देश मिलकर फंड जुटाते हैं।

आत्मघाती आतंकवाद के पैर पसारने और अपनी क्रूर ताकत से पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी आपदा खड़ी हो गई। इस बात को कदापि नकारा नहीं जा सकता कि अब आतंकवादी अपने अभियानों में नित नई पद्धतियाँ अपना कर पहले से अधिक आक्रामक होते जा रहे हैं, क्योंकि विध्वंस व विनाश हेतु नवीनतम तकनीकी की अनेक विधियाँ अपना रहे हैं। मानव बम का इतिहास तो वैसे सदियों फराना है, मगर आधुनिक जगत में संसार का सबसे सशक्त आत्मघाती दस्ता तैयार किया श्रीलंका में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे तमिल उग्रवादियों के संगठन लिबरेशन टाइगरर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) ने जिसकी नींव एक साथ अमेरिका व ब्रिटेन में रखी गई। आज आतंकवाद के खिलाफ मैदाने–जंग में उतरने वाले अमेरिका ने ही सबसे पहले लिट्टे को अपने यहाँ मुख्यालय बनाने के लिए पनाह दी। आत्मघाती आतंकवाद की घटनायें अमेरिका के दो प्रमुख शहरों – व्यापारिक राजधानी न्यूयार्क तथा राजनीतिक राजधानी वाशिंगटन के दो महत्त्वपूर्ण ठिकानों पर 11 सितंबर 2001 को एक साथ घटित हुई। इन हमलों में एक नया आत्मघाती तरीका अपनाया गया। आतंकवादियों ने

बोस्टन हवाई अड्ड़े से यात्री विमानों का अपहरण कर उन्हें पूर्व निर्धारित निशानों से टकराया। अपहृत चार विमानों में से दो विमानों को विश्व व्यापार केन्द्र के ट्विन टावर्स से अलग–अलग 15 मिनट के अंतराल में टकराया गया। तीसरे विमान को पेंटागन (वाशिंगटन डी.सी., भवन जो कि अमेरिका का रक्षा मुख्यालय है), से टकराया गया। चौथा विमान लक्ष्य पर टकराने से पूर्व ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टी.वी. चैनल के अनुसार चौथा लक्ष्य व्हाइट हाउस (राष्ट्रपति भवन) को उड़ाने का था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का पहला टॉवर 1364 फीट तथा दूसरा टॉवर 1362 फीट ऊँचाई के आधार पर बना था। इन दोनों भवनों में लगभग 1500 लोग कार्यरत थे। आत्मघाती विमानों के हमले से दोनों गगनचुंबी इमारतें देखते–ही–देखते ध्वस्त हो गई तथा पेंटागन के विशाल क्षेत्र में बने पाँच मंजिला भवन के एक हिस्से को भारी नुकसान हुआ।

आत्मघाती हमलों को अंजाम देने के कारण आतंकवाद की आपदा, विध्वंसक व विनाशक स्वरूप ले चुकी है। फिलीस्तीन में चल रहे संघर्ष में हमास, इस्लामिक जिहाद और अल–अक्स ब्रिगेड प्रेरित कर भोले–भाले युवक–युवतियों की पर्याप्त आपूर्ति करते हैं, जो आत्मघाती आतंकवादी आक्रमणों को अंजाम देने को अपना धार्मिक दायित्व मानते हैं। इस प्रकार की स्थिति पाकिस्तान में भी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिहादी स्वयं को रूस में उड़ा दे या भारत व अमेरिका आदि अन्य देशों में। आतंकवादियों के मामले में पाकिस्तान की आपूर्ति सीमाहीन है। असंख्य युवाओं को हजारों मदरसों में जिहाद के लिये तैयार और फिर जिहादी संगठनों में शामिल किया जाता है। गरीबी, भुखमरी, अज्ञानता एवं अशिक्षा से ग्रसित जनता पाकिस्तान के लोगों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है। गरीबी एवं जनसंख्या विस्तार का मिश्रण एक ऐसा ज्वलनशील मिश्रण है, जो इस्लामिक जिहाद को अनिश्चित काल तक जारी रख सकता है। इस अभावग्रस्त गरीब वर्ग को रूढ़िवादी तत्त्वों के अधीन रखने के लिये परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती है। बल प्रयोग व बंदूक के जोर से आधुनिकता के विरोध पर जोर दिया जाता है। आत्मघाती मिशनों के संयोजक युद्ध के एक एकीकृत हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह उन्हें अत्यंत शक्तिशाली विरोधियों के विरुद्ध एक असीमित विकल्प प्रदान करता है।

20वीं शताब्दी के अन्तिम चरण से लेकर 21वीं शताब्दी के प्रथम चरण तक आतंकवाद विशेष रूप से आत्मघाती आतंकवाद का विशेष बोलबाला रहा। एक शतक से अधिक ऐसी भीषण व भयानक आतंकवादी घटनायें घटित हुईं, जो कि आत्मघाती दलों या व्यक्तियों द्वारा अंजाम तक पहुँचाई गई। **इनमें प्रमुख घटनायें निम्न प्रकार से हैं –**

1. 23 अक्टूबर, 1983, स्थान बेरुत स्थित अमेरिका का क्षेत्रीय सैन्य मुख्यालय और उसी से सटा हुआ फ्रांसीसी सैन्य मुख्यालय, समय – दिन के ठीक बारह बजे, घटना–तेज रफ्तार से आते हुए दो सैनिक ट्रक एक ही क्षण और एक ही अंदाज में, अमेरिका तथा फ्रांस के सैन्य मुख्यालय में प्रविष्ट हुए।

जब तक सुरक्षाकर्मी उन ट्रकों के बारे में कुछ सोच पाते या रोक पाते, तब तक दिल दहला देने वाला भयंकर विस्फोट हो चुका था। यह सारी घटना महज 40 सैकिंड में घट गई थी। इस घटना में 100 से भी ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, मीडिया के लोग, राजनयिक तथा नौकरशाह मारे गये थे और 400 से भी ज्यादा आम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इन दोनों ट्रकों को मानव बम ही चलाकर लाये थे।

2. 1984 में फिलीस्तीन मुक्ति संघर्ष (PLO) की एक मानव बम **शाहिना अबनूर (पहली महिला मानव बम)** गाजा पट्टी स्थित इजरायली फौजी कैंप में जा घुसी थी। फलस्वरूप एक भयानक विस्फोट के साथ फौजी कैंप उड़ गया। इस महिला मानव बम को भी कई तरह की बाधाओं के जरिये कैंप के सुरक्षाकर्मियों ने रोकने की कोशिश की थी, मगर हर तरह की बाधाओं को तोड़ते हुए यह महिला मानव बम कैंप में घुस गई थी। इस हादसे में 14 सैन्य अधिकारी तथा 20 सैनिक मारे गये थे।
3. 1985 में इजरायल के एक हवाई अड्डे पर जे.आर.ए. तथा पी.एल.ओ. के मानव बमों ने एक साथ धावा बोलकर कहर बरपा दिया। इस हादसे में दो दर्जन से ज्यादा लोग मारे गये तथा 5 विमान जलकर राख हो गये।
4. 1987 में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी (IRA) के दो मानव बमों ने इंग्लैंड की एक पुलिस इमारत को ध्वस्त कर दिया, जिसमें 17 लोग मारे गये तथा 400 से ज्यादा घायल हुए।
5. 21 मई 1991 को श्रीपेरम्बदूर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की लिट्टे की एक महिला मानव बम ने विस्फोट से हत्या कर दी।
6. श्रीलंका में तो राष्ट्राध्यक्षों, मंत्रियों और दूसरे राजनेताओं की मानव बमों के जरिये हत्याओं का एक अंतहीन सिलसिला लंबी अवधि तक जारी रहा। राष्ट्रपति रणसिंह प्रेमदास, गामिनी दिशानायके, ललित अतुलात मुदली तथा सीवी गुणवर्धने सहित 10 मंत्री और प्रधानमंत्री मानव बम का निशाना बन चुके। इसके अलावा महत्त्वपूर्ण लोगों पर 50 से ज्यादा नाकाम हमले भी हो चुके हैं। चंद्रिका कुमार तुंग पर तीन बार, श्रीमाओ भंडारनायके पर दो बार नाकाम हमले हो चुके हैं। नेताओं और मंत्रियों के अलावा दो दर्जन से ज्यादा सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तथा सैकड़ों लोग इन मानव हमलों से अपनी जान गवाँ चुके हैं। लिट्टे के अंत के साथ ही आत्मघाती दस्ते के सबसे घातक एवं बड़े संगठन का फिलहाल अंत हो गया, किंतु आत्मघाती आतंकवाद के रूप में लिट्टे को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। 1980–1990 के दौरान आत्मघाती आतंकवाद की घटनायें मुख्य रूप से लेबनान, कुवैत और श्रीलंका तक ही सीमित थी, किंतु अब यह वैश्वी घटनाक्रम बन चुका है। इसके तहत इजरायल, भारत, फिलीस्तीन, लेबनान, फ्रांस, सीरिया, अफगानिस्तान, पनामा, अल्जीरिया, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, क्रोसिया, तुर्की, तनजानिया, केन्या, अमेरिका (यू.एस.ए.), मध्य एशियाई गणराज्य तथा इंग्लैंड

(यू.के.)। इसके साथ कुछ आतंकवादी संगठन अपनी सीमाओं से बाहर भी अपनी यह रणनीति अपना रहे हैं। **हिजबुल्ला एक ऐसा आतंकवादी संगठन है, जिसने इस आत्मघाती आतंकवाद को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया है।**

7. **2001** – न्यूयॉर्क की 11 सितम्बर की आत्मघाती आतंकवाद की घटना ने पेंटागन में हमला करके 5000 से अधिक लोगों को मौत का शिकार बना दिया।
8. **2005** – लंदन में 7 जुलाई को आत्मघाती दस्ते द्वारा भीषण बम विस्फोट करके 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 700 से अधिक लोग बुरी तरह से घायल हुए।

अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं इराक में तो आत्मघाती हमला करने की घटना अब सामान्य सी हो गई है, शायद ही कोई भी दिन, महीना गुजरता हो, जब आत्मघाती हमला इन देशों में घटित न होता हो। जहाँ तक इस समय दुनिया में आत्मघाती आतंकवाद का अहम प्रश्न है तो आज दुनिया का कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। एक अनुमान के अनुसार इस समय संसार भर में 100 से अधिक ऐसे आतंकवादी संगठन हैं, जिनके पास मानव बम मौजूद हैं। इसमें लिट्टे की अग्रणीय भूमिका रही है, लिट्टे के पास ब्लैक टाइगर के नाम से सबसे घातक एवं प्रभावशाली आत्मघाती दल था, जिसके पास लगभग इसकी एक पूरी ब्रिगेड थी, जिसमें 250 मानव बम हरदम कार्यवाही के लिये तत्पर रहते थे।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के एक संभावित हथियार के रूप में आत्मघाती हमलों का आविष्कार वर्तमान विश्व समुदाय के लिये घातक आपदाओं के रूप में उभर कर सामने आया है। आतंकवाद का यह रूप खुद को किसी स्थान या किसी समय पर अभिव्यक्त कर सकता है। इसका विध्वंसक एवं विनाशकारी प्रभाव न केवल अधिकांश जनसंख्या पर बल्कि समाज के मानसिक और सामाजिक–आर्थिक कल्याण पर भी प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। यह विश्व के अनेक भागों में अपना भयंकर, विध्वंसक व प्रलयकारी स्वरूप धारण कर चुका है। 11 सितंबर 2001 की आत्मघाती हमले के द्वारा हुए व्यापक तबाही, बर्बादी एवं मौत के तांडव को देखते हुए अमेरिका इस प्रकार के आतंकवाद का सबसे प्रमुख शिकार रहा है। आत्मघाती हमले का यह स्वरूप अपने आप में न केवल अनूठा था, बल्कि आश्चर्यजनक एवं अनुमान से परे आक्रमण था।

'आतंकवाद' जैसी जटिल समस्या से कैसे निपटा जाये? जिसकी अभी तक कोई एक निश्चित सर्वमान्य परिभाषा तक नहीं बन पाई है! यू. एन. ओ. इस कार्य में पिछले कई दशकों से विद्वानों के कई विश्व सम्मेलन आयोजित कर चुका है। लेकिन सर्वसम्मति से कोई भी परिभाषा निर्मित नहीं हुई है। क्योंकि **'एक व्यक्ति' एक क्षेत्र विशेष के लिए तो 'स्वतंत्रता सेनानी या शहीद' कहा जाता है और वहीं उसी क्षेत्र के कुछ अन्य लोगों द्वारा 'हत्यारा' या 'आतंकी' कहलाता है।** जैसे शहीद भगत सिंह भारत के लिए स्वतंत्रता सेनानी (शहीद) था और ब्रिटिश सरकार के लिए वह आतंकवादी था। आज 'आत्मघाती हमले' आतंकवादियों का

एक कारगर और प्रभावशाली शस्त्र (हथियार) बन चुका है इसमें कोई शक नहीं। आज आतंकवाद को परिभाषित करना एक बड़ी समस्या है। एक सर्वमान्य परिभाषा के अभाव में आतंकवाद के विरूद्ध सख्त कानून कैसे बनाये जा सकते हैं?

विश्व का कोई भी देश आज आतंकवाद की चपेट से अछूता नहीं है। इसीलिये आतंकवाद एक भौगोलिक क्षेत्र या सामाजिक या राष्ट्रीय ग्रुप तक सीमित नहीं है। आतंकवाद को किसी सीमा में भी नहीं बाँधा जा सकता। वह अमेरिका में प्रहार कर सकता है तो यूरोप, मध्यपूर्व, लैटिन अमेरिका, एशिया तथा अफ्रीका को भी अपनी चपेट में लेकर हाहाकार मचा सकता है। आतंकवाद एक विश्व परिघटना है और इसका इतिहास भी काफी फराना है। छापामार (Guerrill) शब्द का प्रयोग फ्रेंच क्रांति के दौरान (1789–1799) किया गया था। उन दस वर्षों के दौरान की गयी नृशंसतापूर्ण एवं बर्बरता की कार्यवाही को एक नया उपनाम मिल गया – आतंक का दौर। आतंकवाद शब्द आतंक + वाद अर्थात आतंक या भय की विचारधारा को प्रतिबिम्बित करता है। दुर्भाग्य से आज आतंकवाद छाया युद्ध चलाने के लिये शत्रुतापूर्ण राष्ट्रों के हाथ में एक शक्तिशाली औजार बन गया है। इसके अन्तर्गत भय तथा आतंक पैदा करने के एकमात्र लक्ष्य से प्रेरित होकर हिंसात्मक कार्यवाही की जाती है। आतंकवाद की सबसे खास बात यह है कि इससे कोई देश अपने दुश्मन के विरुद्ध आतंकवाद को प्रोत्साहित करके कोई जिम्मेदारी लिये बिना आक्रमण में लगा रह सकता है।

''ऐसा लगता है कि आतंकवाद की शुरूआत स्वतंत्रता, संघर्ष जैसे एक पवित्र उद्देश्य से हुई थी अर्थात् साम्राज्यवाद के जुएँ या भ्रष्ट प्रशासन को उखाड़ फेंकने के लिये। परन्तु शनैः शनैः इसका स्वरूप भयावह होता गया और इसकी चपेट में दुनिया के तमाम देश आ गये हैं। क्षेत्रीय विवाद, धार्मिक उन्माद, भाषायी हिंसा और जातीय उग्रवाद ने आतंकवाद के सशक्त विनाशकारी घृणा से ओत–प्रोत परम्परा को अपनाया और महत्त्वाकांक्षाओं को शीघ्र पूरा करने की उतावली विदेशी प्रलोभन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक उन्माद तथा बेरोजगारी ने आतंकवाद के नये शरीर को जन्म दिया।''[2] राजनीतिक नेताओं ने अपने चुनावी लक्ष्यों की पूर्ति के लिये जन विश्वास जीतने की कठिनाई महसूस करते हुए जनता में आतंक के माध्यम से अपना प्रभाव विस्तार शुरू किया। इसके लिये राजनीतिज्ञों ने जातीय, धार्मिक एवं क्षेत्रीय आधारों को आगे रखकर आपराधिक तत्त्वों का सहारा लिया। लेकिन जब आपराधिक तत्त्वों को यह अनुभव हुआ कि राजनीतिज्ञ उनके सहारे अपना पद और सत्ता बचा रहे हैं तो उन्होंने स्वयं को नेता घोषित कर दिया और उनकी महत्त्वाकांक्षा जैसे–जैसे बढ़ती गई, वैसे–वैसे क्षेत्रीय आतंकवाद फैलता गया।

---

[2] डॉ. लल्लन जी सिंह, ''राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा'', 2006, प्रकाश बुक डिपो, बड़ा बाज़ार, बरेली–243003, पृष्ठ संख्या – 49

उदाहरणार्थ पंजाब के जनरेल सिंह भिंडरवाले को उत्प्रेरित करने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने किया था परन्तु यही कारण बाद में वह श्रीमती गाँधी का दुश्मन बन गया। ऐसे ही नेशनल लिब्रेशन प्रफंट, नागा और मिजो विद्रोहियों, उल्फा, जे.के.एल.एफ. आदि संगठनों तथा आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आदि कई राज्यों में इस तरह की पृथक्कतावादी गतिविधियों के कई नेता अपने उद्देश्यों में सफल रहे हैं।

''आतंकवाद और हिंसा दो जुड़वे भाई हैं। आतंकवाद के साथ कुछ निश्चित राजनीतिक, सामाजिक उद्देश्य जुड़े रहते हैं। आतंकवादी कार्यवाहियों के दो उद्देश्य होते हैं तत्कालिक उद्देश्य ख्याति पाना और दूसरा है अपने जाहिरा लक्ष्य या दावे को मान्यता दिलाना। ऐसे आतंकवादी के लिये जिसके सामने हासिल करने योग्य कोई निश्चित लक्ष्य है किसी ने ठीक ही कहा है हर तरह की ख्याति पाना लाभदायक तो है ही नहीं इसलिये कुख्याती ही भली।''[3]

साधारण शब्दों में भय के माध्यम से किसी साध्य के उद्देश्य की पूर्ति की विचारधारा आतंकवाद कहलाती है एक फिलीपीन नेता के अनुसार ''आतंकवादी कार्यवाहियाँ शीघ्र परिणाम के लिये, केवल निजी बदले के लिये अथवा निरंकुश अपराध के लिये सम्पन्न नहीं की जाती, वरन् इसके पीछे एक निश्चित विचारधारा पवित्र उद्देश्य तथा किसी केन्द्रित शक्ति का समर्थन नहीं है और मंजिल की प्राप्ति तक पहुँचने से पहले इसका व्यापक उद्देश्य दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना है। आतंकवाद का इतिहास इतना ही फराना है जितना कि मानव सभ्यता।''[4]

आतंकवाद का एक बदलता स्वरूप : अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद

जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रारम्भ का प्रश्न है, छठवें दशक में लैटिन अमेरिकी देशों में हुई आतंकवादी गतिविधियों को इसकी शुरुआत माना जा सकता है। तत्पश्चात् 1968 में पश्चिमी जर्मनी, इटली व जापान आदि देशों में असन्तुष्ट युवकों व विद्रोही छात्रों द्वारा भी आतंकवादी गतिविधियाँ प्रारम्भ की गयी जिनके अन्तर्गत उन्होंने अपहरण जैसी विधियों का सहारा लिया। सर्वप्रथम वेनेजुएला में फरवरी 1962 में एक मालवाही विमान का अपहरण करके ब्राजील ले जाया गया तथा नवम्बर 1963 में अमेरिकी सैन्य संस्थान के उप–प्रमुख कर्नल जेम्स चेनाल्ट का अपहरण करके वेनेजुएला के आतंकवादियों ने विश्व में उत्तेजना उत्पन्न कर दी। ग्वाटेमाला के गुरिल्लाओं द्वारा भी विदेशी राजनयिकों के अपहरण व हत्या के कई सफल प्रयत्न किये गये। इसी प्रकार मार्च–जून 1966 में भारत के दार्जिलिंग जिले में नक्सलवादी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ जो बाद में त्रिपुरा, मध्यप्रदेश, बिहार, आन्ध्रप्रदेश, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में फैल गया। आन्दोलनकारियों द्वारा हत्या व विनाश की विधि अपनाने के फलस्वरूप यह

---

[3] Quoted in Terrorism Inter Diciplinary Perspective, p.19

[4] डॉ. धीरेन्द्र द्विवेदी, संजय कुमार, अनुराग जायसवाल, गुलाब चन्द्र ललित, ''अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति'', 2006, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली–110094, पृष्ठ संख्या – 189

आन्दोलन आतंकवाद में परिवर्तित हो गया। कलकता ऐसी समस्त कार्यवाहियों का केन्द्र था। स्पेन, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली व अमेरिका आदि देशों में भी छात्र विद्रोहियों की गतिविधियाँ प्रारम्भ हुई जिन्होंने अपहरण, हत्या व डकैती जैसी तकनीकों का सहारा लेकर अन्तर्राष्ट्रीय समाज में आतंक फैलाने का प्रयास किया। मध्य–पूर्व में फिलीस्तीन मुक्ति संगठन (P.L.O.) के उदय से जापान, जर्मनी व इटली आदि देशों के आतंकवादी समूहों को नई प्रेरणा व ऊर्जा मिली। सन् 1967 में अरब–इजराइल युद्ध ने अरब देशों के पराजित होने के बाद फिलीस्तीन मुक्ति संगठन की गतिविधियाँ काफी घातक व त्वरित होती गई तथा अरब देशों से प्राप्त नैतिक व भौतिक समर्थन के फलस्वरूप यह विश्व का प्रमुख आतंकवादी संगठन बन गया। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के इतिहास में P.L.O. का उदय एक ऐसा कारक था जिससे विश्व के अन्य संगठनों को वैचारिक प्रेरणा प्राप्त हुई।

विश्व के प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के मध्य स्थापित पारस्परिक सम्पर्कों व संबंधों से आतंकवाद का क्षेत्र काफी विस्तृत होता गया। सर्वप्रथम लैटिन अमेरिकी आतंकवादी संगठनों ने 1973–74 में एक संयुक्त बैठक करके सामूहिक प्रशिक्षण, आर्थिक सहयोग, शस्त्र–आपूर्ति, सूचना, संगठन व वैचारिक क्षेत्रों में सहयोग का निर्णय लेकर संयुक्त रूप से आतंकवादी गतिविधियों की शुरूआत की। फलस्वरूप, फिलीस्तीन में सर्वप्रथम विश्व के विभिन्न आतंकवादी समूहों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी जिसमें इराक, जोर्डन, लेबनान, सीरिया, लीबिया व दक्षिण यमन आदि देशों के अतिरिक्त जापान व जर्मनी के आतंकवादी संगठनों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। मध्यपूर्व में चल रहे इस आतंकवादी प्रशिक्षण केन्द्र के अतिरिक्त क्यूबा भी न केवल ऐसे प्रशिक्षण–केन्द्रों को चलाता रहा है अपितु उसके प्रशिक्षक लेबनान व अल्जीरिया आदि में फिलीस्तीनी आतंकवादियों को प्रशिक्षण देते रहे हैं। अमेरिका में भी कई ऐसी संस्थायें चल रही हैं जहाँ विश्व के विभिन्न देशों के आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को प्रेरित करने में अमेरिका की गुप्तचर एजेन्सी C.I.A. तथा सोवियत संघ की K.G.B की प्रमुख भूमिका रही है। ये संस्थायें न केवल आतंकवाद के प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करती रही हैं अपितु इसके एजेन्ट विश्व के कई देशों में सरकार–विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहन देते रहे हैं।

आतंकवाद उत्पन्न करने की तकनीकें

आज आतंकी समूहों के दुनिया भर में सम्बन्ध स्थापित हो चुके हैं, बल्कि वे भूमण्डलीयकृत दुनिया का अपने हित में इस्तेमाल कर रहे हैं। अंतर्देशीय आपराधिक संगठनों, मादक पदार्थों व हथियारों के तस्करों ने आतंकवादियों की पहुँच का दायरा व मारक क्षमता को और भी बढ़ा दिया हैं अतः दुनिया का कोई भी कोना, देश इनकी पहुँच से अछूता नहीं बचा है। दुनिया अधिकांश गैर–मुस्लिम एवं मुस्लिम देश ऐसे हैं जो आतंकवाद को प्रायोजित कराने, शिविर लगाकर

प्रशिक्षण देने व आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं जिससे आतंकवादी आयाम बढ़ता जा रहा है। सच यह है कि 21वीं सदी में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक ऐसी जटिल व कठिन समस्या बनकर उभरता जा रहा है जिससे सम्पूर्ण मानव जाति आतंकित है। आतंकवादी अपनी नृशंस कार्यवाहियों से दहशत फैलाते हैं जिसका उस देश की आर्थिक व्यवस्था पर भयंकर असर होता है। कश्मीर का पर्यटन उद्योग पूर्णतः चौपट हो चुका है। इसी तरह 1996 में अल–जमात–अल–इस्लामिया ने मिस्र में 58 पर्यटकों की हत्या की जिससे वहाँ का पर्यटन उद्योग बिल्कुल चौपट हो गया। पिछले दो दशकों में आतंकवाद का स्वरूप ही बदल गया है। आतंकवादी गिरोह छः तरह की कारगुजारियाँ करते हैं जैसे – विमान अपहरण, बंधक बनाना, बमबारी, हत्या, हथियार बन्द आक्रमण और बन्दी बनाने की घटनाएँ। इन सभी के पीछे तीन लक्ष्य होते हैं – खौफ का वातावरण तैयार करना, पूर्व घटनाओं और परिस्थितियों का बदला लेना, उन प्रक्रियाओं पर असर डालना जिन्हें आतंकवादी संगठन अपने हितों के विरुद्ध समझते हैं।

आज आतंकवादियों की तीसरी पीढ़ी चल रही है। पहली पीढ़ी दूसरे विश्वयुद्ध के बाद पैदा हुई। इसमें आतंकवादी थका देने वाली नीति अपनाते थे इसलिये विमान अपहरण, दूतावास हथियाना जैसी कार्यवाहियाँ होती थीं। दूसरी पीढ़ी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पैदा हुई जिसमें आतंकवादी संगठन चाहते थे कि सभी उन्हें जानें। इसके लिए ये तरह–तरह के कुचक्र रचते थे। आइरिश रिपब्लिकन आर्मी और फिलीस्तीनी गिरोहों के कारनामें इसके उदाहरण हैं। **इंटेलिजेंस थ्रेट हैंडबुक** के अनुसार आतंकवादी गिरोह–देशी या बहुराष्ट्रीय निजी गिरोह होते हैं, सरकारी मदद से चलते हैं, सरकार के निर्देश पर चलते हैं। आज आतंकवाद के मूलतः तीन उद्देश्य हैं –

1. आम आदमी का सरकार पर से विश्वास हिला देना।
2. सरकार पर प्रतिरोधात्मक कार्यवाही करने के लिए दबाव डालना।
3. लोगों को आतंकवाद के समर्थन में हथियार उठाने की प्रेरणा देना।

आतंकवादी गिरोह इंटरनेट को भी अपना हथियार बना चुके हैं। कई गिरोहों के अपने वेबसाइट हैं जहाँ उनकी प्रसार सामग्रियाँ रहती हैं। **मेक्सिको के सापातीस्ता गिरोह** ने मई 2001 में अमरीका के पेंटागन के प्राथमिक इंटरनेट सूचना देने वाले डिफेंस साइट को ही निष्क्रिय कर देने की कोशिश की थी। आतंकवादियों द्वारा मूलतः निम्न तरीकों एवं आयामों को अपनाया जाता है –

1. **संचार सेवा नष्ट करना –** इससे न केवल जनता का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट होता है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था अस्त–व्यस्त हो जाती है। इसके अन्तर्गत रेलवे की पटरी को हटा देना, विद्युत पोल को उड़ा देना, टेलीफोन लाईनों को तोड़ देना, ट्रेन–बसों में बम रखकर उनको ध्वस्त कर देना, स्टेशनों, सार्वजनिक स्थानों अथवा अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों में बम रखना, डाकघर, तारघरों को विस्फोटित करना आदि कार्यवाही की जाती है। इस

तरीके से बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। हालाँकि समय, स्थान और व्यक्ति के आधार पर इस कार्यवाही का स्वरूप बदलता रहता है।

2. **अपहरण करना और बन्धक बनाना** – इसके अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों, राजनीतिज्ञों, अधिकारियों, शिक्षाविदों, प्रबन्धकों तथा इसके बच्चों, पत्नी आदि का अपहरण करके आतंकवादी अपनी माँग मनवाने के लिए सरकार को बाध्य करते हैं। यदि इनकी माँग एक निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है तो फिर बन्धक बनाये व्यक्तियों को प्रायः मार देते हैं, जैसे 10 अप्रैल, 1996 को कश्मीर घाटी में भारत माँ के तीन सपूतों कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मुशिल उल हक, उनके निजी सचिव उप कुलसचिव तथा एच.एम.टी. के महाप्रबन्धक श्री एच.एल. खेड़ा की अपहरणकर्त्ताओं द्वारा माँग न पूरी होने पर नृशंस हत्या कर दी गई। तत्कालीन राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के केन्द्रीय गृहमंत्री मुफ्रती मोहम्मद सईद की बेटी डॉ. रूबिया सईद को अपहरण करके बन्धक बनाये रखना (8 दिसम्बर से 14 दिसम्बर 1997) और रिहाई के बदले में 5 कुख्यात आतंकवादियों को सरकार से छुड़ाना आदि 1995 में जम्मू–कश्मीर के कुछ पश्चिमी पर्यटकों का अपहरण आतंकवादियों द्वारा किया गया। इसके अन्तर्गत विमानों को अपहरण करके यात्री सहित विमान को बम से उड़ा देने की धमकी आदि की कार्यवाही भी आतंकवादियों द्वारा की जाती है। उदाहरणार्थ ''क्यूबा के विमान का अपहरण करके अमेरिका लाते वक्त ही मध्य आकाश में विमान उड़ा देना। कनाड़ा से आ रहे भारतीय विमान कनिष्क को आतंकवादियों द्वारा उड़ा देना आदि घिनौनी घटनायें आती हैं। इसमें 329 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी।''[5] इसी तरह टी.डब्ल्यू.ए. 847 विमान को लेबनान के शिया मिलीशिया वालों ने अपहरण किया था और 39 अमरीकियों को बन्धक बनाकर उनके बदले इजरायली कैद से अपने नेताओं को रिहा करने का प्रयास किया गया है। ऐसे ही दुनिया में अनेकों उदाहरण मिलेंगे।

संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव (नवम्बर 1966) पास करके सभी राष्ट्रों से अनुरोध किया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को रोकने का हर सम्भव प्रयास करें तथा मुकदमा चलाने और दण्डित करने से परहेज न करें। इस तरह हेग सम्मेलन 19 दिसम्बर, 1970 में इस पर प्रतिबन्ध लगाया गया। फिर भी विमान अपहरण की घटनायें जारी हैं। कुछ राष्ट्रों ने तो इसको बढ़ावा दिया है जैसे 1969 में सीरिया ने विमान अपहरणकर्त्ताओं के नाम पर डाक टिकट जारी करके आतंकवाद की परोक्ष नीति को अपनाया। पाकिस्तान की शह पर ही भारतीय विमान को पाकिस्तान में आतंकवादियों ने जला दिया था। इतना ही नहीं 24 दिसम्बर, 1999 इंडियन एयर लाइंस के विमान का अपहरण करके तालिबान शासित कंधार में उतारना और उसके बदले कुछ आतंकवादियों को छोड़ने के लिए भारत

---

[5] वही पृ.सृ. – 202

सरकार को मजबूर करने के पीछे पाकिस्तान, तालिबान और कश्मीर के आतंकवादियों का ही हाथ रहा जिसमें चार यात्रियों को मौत के घाट उतार भी दिया था। इसी तरह 11 सितम्बर, 2001 को ओसामा बिन लादेन के संगठन अल–कायदा के आतंकवादियों के इतिहास में पहली बार अपने विरोधी अमरीका पर निशाना साधने के लिए उसी के विमानों को अपहृत करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और रक्षा मंत्रालय पेंटागन से टकराकर ध्वस्त कर दिया जिसमें चार विमानों के भी यात्री और करीब 10,000 अन्य लोग मारे गये। इन हमलों के कारण 150 अरब डालर का नुकसान हुआ।

3. **सामूहिक नरसंहार और हत्यायें** – इसका उद्देश्य जनता में दीर्घ पैमाने पर आतंक फैलाना होता है सामूहिक नरसंहार का प्रयोग भारत के पंजाब में आतंकवादियों द्वारा किया गया। इसमें बसों, ट्रेनों से यात्रियों को उतारकर गोलियों से भून देना, बाराती लोग (शादी) पर दनादन गोलियाँ बरसाना, बाजार में अचानक फायर करके लोगों को हताहत कर देना आदि कार्यवाही की जाती है। आतंकवादी इस पद्धति का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इसका उद्देश्य जनता में दीर्घ पैमाने पर आतंक फैलाना होता है। सामूहिक नर–संहार का प्रयोग भारत के जम्मू–कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा प्रायः किया जा रहा है। 22 मार्च, 2000 को अनंतनाग जिले (कश्मीर) के छतीसिंहफर में आतंकवादियों ने अल्पसंख्यक सिख समुदाय के 40 लोगों का सामूहिक नर–संहार करके एक इतिहास बना डाला। इतना ही नहीं जम्मू जिले के डोडा गाँव में करीब 30–32 परिवारों की निर्मम हत्यायें आतंकी गुट ने की थी। पूर्वोत्तर भारत के एन.डी.एफ.बी. के आतंकवादियों ने शांति दूत महात्मा गाँधी की जयंती (2 अक्टूबर, 2004) के दिन धुबड़ी में 15 निरपराध लोगों को अंधाधुंध फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। इसी तिथि की पूर्व संध्या पर उधर नागालैण्ड में दीमाफर रेलवे स्टेशन और इस वाणिज्यिक शहर के भीड़–भाड़ वाले बाजार में एक ही समय में उग्रवादियों ने रिमोट से दो बारूदी सुरंगों को उड़ा दिया जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 26 लोग मारे गये तथा 100 से अधिक लोग घायल हो गये। इतना ही नहीं 17 नवम्बर, 1997 को मिड्ड में दो बसों में लादकर विदेशी पर्यटक नील नदी के किनारे लक्शर कस्बे में 3000 साल फराने रानी हात्शेप्सुत का मन्दिर देखने के लिये पहुँचे तो अल–जमात इस्लामिया नामक दक्षिणपंथी आतंकवादी संगठन के सदस्यों ने दनादन गोलियाँ चलाकर 68 लोगों को मौत के घाट उतार दिया।

4. **आत्मघाती–हमले** – इसमें अपनी जान की बाजी लगाकर उद्देश्य की पूर्ति आतंकवादियों द्वारा की जाती है। उदाहरणार्थ सन् 1984 में लेबनान में एक युवक आतंकवादी ने अपनी कार में डाइनामाइट भरकर दूतावास का गेट तोड़ते हुए दूतावास में गाड़ी घुसा दी जिससे 30–40 लोग मारे गये। 21 मई, 1991 की रात्रि को मद्रास से 40 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बदूर में लिट्टे (LTTE) की सदस्य महिला ने बेल्ट बम का प्रयोग करके भारत के भूतपूर्व

प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी को अपने सहित मार डाला। इस प्रकार के हमले के लिये आतंकवादियों को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। आतंकवाद हिंसा, त्रास व गुरिल्ला गतिविधि से पृथक होता है। सशस्त्र गुरिल्ला कार्यवाही सर्वप्रथम 'मुक्त क्षेत्र' की स्थापना करने के पश्चात् राज्य या राष्ट्र की सैन्य शक्ति से खुला संघर्ष करता है। वहीं आतंकवाद इस प्रकार से संघर्ष से बचता है तथा इससे आभास होता है कि इसके पास इस प्रकार के संघर्ष हेतु समुचित शक्ति का अभाव है। ''कुछ लोग भारतीय या किसी भी राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी आतंकवादी करार देते हैं। किन्तु परतंत्रता की स्थिति से उबरकर स्वतंत्रता की वायु में जीना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है।''[6]

भारत में कुछ प्रमुख आतंकवादी हमले

क्र.सं.	*तारीख*	*घटना*	*मृतक*
1.	12 मार्च, 1993	मुम्बई में सीरियल बम ब्लास्ट	257
2.	14 फरवरी, 1998	कोयम्बटूर बम ब्लास्ट	46
3.	1 अक्टूबर, 2001	जम्मू–कश्मीर विधानसभा में बम ब्लास्ट	35
4.	13 दिसम्बर, 2001	संसद पर हमला	7
5.	21 दिसम्बर, 2002	कुरनूल बम ब्लास्ट	20
6.	10 सितम्बर, 2002	रफीगंज रेलवे बम ब्लास्ट	130
7.	27 फरवरी, 2002	गोधरा ट्रेन दुर्घटना	57
8.	24 सितम्बर, 2002	अक्षरधाम मंदिर पर हमला	31
9.	13 मार्च, 2003	मुम्बई ट्रेन में बम ब्लास्ट	11
10.	14 मई, 2003	जम्मू में सेना कैंप पर हमला	30
11	25 अगस्त, 2003	मुम्बई में सीरियल बम ब्लास्ट	52
12.	15 अगस्त, 2004	असम में आंतकवादी हमला	16
13.	2005	जौनफर में ट्रेन में बम ब्लास्ट	13
14.	5 जुलाई, 2005	रामजन्मभूमि पर हमला	0
15.	29 अक्टूबर, 2005	नई दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट	70
16.	7 मार्च, 2006	वाराणसी में कई बम ब्लास्ट	21
17.	11 जुलाई, 2006	मुम्बई की ट्रेनों में कई बम ब्लास्ट	209
18.	8 सितम्बर, 2006	मालेगाँव में मस्जिद में बम ब्लास्ट	37
19.	18 फरवरी, 2007	समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट	68
20.	18 मई, 2007	हैदराबाद की मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट	13
21.	25 अगस्त, 2007	हैदराबाद में बम ब्लास्ट	42
22.	11 अक्टूबर, 2007	अजमेर शरीफ दरगाह में बम ब्लास्ट	3

[6] Aakrosh, Journal, Vol. 8, No. 26, January 2005, Page No. 9

23.	24 नवम्बर, 2007	उत्तर प्रदेश के कई कोर्टों में बम ब्लास्ट	16
24.	13 जुलाई, 2008	जयफर में बम ब्लास्ट	63
25.	25 जुलाई, 2008	बेंगलूरू में बम ब्लास्ट	2
26.	26 जुलाई, 2008	अहमदाबाद में बम ब्लास्ट	29
27.	13 सितम्बर, 2008	दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट	21
28.	30 अक्टूबर, 2008	असम में बम ब्लास्ट	77
29.	26 नवम्बर, 2008	मुम्बई में कई जगह आतंकवादी हमले	171
30.	13 फरवरी, 2010	फणे में आतंकी हमला	11
31.	21 फरवरी, 2013	हैदराबाद में बम ब्लास्ट	18
32.	26 सितम्बर, 2013	जम्मू में पुलिस व सेना पर आतंकी हमला	10

विश्व की कुछ प्रमुख आतंकवादी घटनायें (इस सदी की घटनायें)

1. **11 सितम्बर, 2001:** अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (WTC) पर आतंकियों ने दो हवाई जहाज टकराये, तीसरा हवाई जहाज पेंटागन की इमारत पर टकराया, चौथा पेनसिल्वेनिया के एक खेत में गिरा, 19 आतंकी अपहरणकर्त्ताओं के अलावा इस सबसे बड़े हमले में करीब 3000 लोग मारे गये थे।
2. **12 अक्टूबर, 2002:** इंडोनेशिया के बाली में दो बम विस्फोट, 202 लोग मारे गये थे।
3. **23 अक्टूबर, 2002:** चेचन आतंकवादियों ने मास्को के एक थिएटर पर कब्जा कर कई बंदियों को मार दिया, सुरक्षा बलों ने गैस छोड़कर आतंकियों को बेहोश कर 50 को मार गिराया, लेकिन इसमें 179 बंदी भी मारे गये थे।
4. **16 मई, 2003:** मोरक्को के कासाब्लांका में पाँच विस्फोटों में 41 लोग मारे गये थे।
5. **20 नवम्बर, 2003:** तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में विस्फोटकों से लदे एक ट्रक ने 60 लोग मार दिये थे, मरने वालों में ब्रिटिश काउंसिल जनरल भी शामिल थे।
6. **11 मार्च, 2004:** स्पेन की राजधानी मेड्रिड की ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 191 लोग मारे गये थे।
7. **13 सितम्बर, 2004:** रूस के बेसलान में आतंकियों ने एक स्कूल पर कब्जा कर 1000 बच्चों व अध्यापकों को बंदी बना लिया, एक विस्फोट में कई बंदी मारे गये, इसके बाद सुरक्षाबलों ने हमला कर दिया, इस पूरे प्रकरण में 330 लोगों की मौत हुई थी।
8. **7 जुलाई, 2005:** लंदन की ट्रेनों में हुए बम धमाकों में 52 लोग मारे गये थे।
9. **16 अक्टूबर, 2006:** लिट्टे विद्रोहियों ने हमला कर 103 श्रीलंकाई सैनिकों को मार डाला था।

10. **27 दिसम्बर, 2007:** पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या की गई थी।
11. **अक्टूबर, 2009:** अफगानिस्तान स्थित भारतीय दूतावास में बम विस्फोट में 45 मरे व अनेकों घायल हुए थे।
12. **इराक में धमाका (15 जनवरी 2010, शुक्रवार)** – इराक के पवित्र शहर नजफ में तीन बम विस्फोट में 25 लोगों की मौत हो गई और 72 लोग घायल हो गये थे।[7]
13. **बारामूला पुलिस थाने पर हमला (15 जनवरी 2010, शुक्रवार)** – कश्मीर घाटी के बारामूला जिले में स्थित सोपोर थाने पर दो बार हमला किया जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत दो लोगों की मौत हो गई थी। व 4 पुलिस जवान घायल हुए थे।[8]
14. **पेशावर में विस्फोट, विधायक घायल (20 जनवरी 2010, बुधवार)** – पाकिस्तान के उत्तर–पश्चिमी शहर पेशावर में हुए बम विस्फोट में एक विधायक समेत तीन लोग घायल हो गये।[9]
15. **कराची में दो धमाके (5 फरवरी 2010, शुक्रवार)** – शिया समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाकर कराची में पहले एक बस और बाद में अस्पताल पर किये गये आतंकवादी हमलों में 32 लोग मारे गये और 50 से ज्यादा घायल हो गये थे।[10]
16. **फणे में आतंकी हमला (13 फरवरी 2010, शनिवार)** – फणे में कौरे गाँव पार्क स्थित एक बेकरी में बम धमाका कर 11 लोगों को मार डाला और करीब 40 लोग घायल हुए थे।[11]
17. **अफगानिस्तान में विस्फोट (31 मार्च 2010, बुधवार)** – दक्षिणी अफगानिस्तान के हेलमंद प्रान्त की राजधानी लश्करगाह में एक साइकिल में रखे बम से हुए विस्फोट में 8 व्यक्तियों की मौत हो गई और 38 लोग घायल हो गये थे।[12]
18. **बगदाद में विस्फोट (6 अप्रैल 2010, मंगलवार)** – इराक की राजधानी बगदाद में सात सिलसिलेवार बम धमाकों के 39 लोगों की जान चली गई व 130 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे।[13]
19. **थाईलैण्ड में विस्फोट (21 अप्रैल 2010, बुधवार)** – थाईलैण्ड के उपद्रवग्रस्त दक्षिणी पट्टानी प्रान्त में मोटर बाइक पर सवार दो हमलावरों ने एक पुलिस

---

[7] 16 जनवरी 2010, शनिवार, हरिभूमि, पृष्ठ संख्या – 5
[8] 16 जनवरी 2010, शनिवार, दैनिक भास्कर, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 9
[9] 21 जनवरी 2010, गुरूवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 7
[10] 6 फरवरी 2010, शनिवार, सीमा संदेश, श्री गंगानगर, पृष्ठ संख्या – 8
[11] 14 फरवरी 2010, रविवार, सीमा संदेश, श्री गंगानगर, पृष्ठ संख्या – 1
[12] 1 अप्रैल 2010, वीरवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 9
[13] 7 अप्रैल 2010, बुधवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 9

थाने को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका। इसके फटने से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 43 जवान घायल हो गये। इसके कुछ ही मिनटों के भीतर एक कार में छिपाकर रखा गया करीब 20 किलोग्राम विस्फोटक थाने से कुछ ही दूरी पर फटा इसमें 17 लोग घायल हुए थे।[14]

20. **बगदाद में सीरियल बम धमाके (23 अप्रैल 2010, शुक्रवार)** – बगदाद (इराक) के शिया बहुल इलाकों में सीरियल कार बम धमाकों से करीब 50 लोग मारे गये। उनमें से दो विस्फोट सद्र शहर में हुए। एक विस्फोट शियाओं के जिहादी नेता मुक्तदा अल सद्र के दफ्तर के पास हुआ, दूसरा विस्फोट बाजार में हुआ जिसमें 39 लोग मारे गये। करीब 56 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा तीन विस्फोट बगदाद की मस्जिदों में हुए जिसमें 11 लोग मारे गये और 50 लोग घायल हुए थे।[15]
21. **सउदी राजनयिक की हत्या (16 मार्च 2011, सोमवार)** – मोटरसाइकिल पर सवार बंदूकधारियों ने कराची में सउदी अरब में एक राजनयिक की दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी।[16]
22. **पाक में धमाका (14 अगस्त 2011, रविवार)** – पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर बलूचिस्तान प्रान्त बम धमाकों और हिंसक वारदातों से दहल उठा। बलूच राष्ट्रवादी गुटों द्वारा अन्जाम दिये गये बम धमाके और हिंसा की अलग–अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत हुई और 30 से अधिक घायल हुए।[17]
23. **अफगानिस्तान में स्वतंत्रता दिवस पर हमला (19 अगस्त 2011, शुक्रवार)** – अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों द्वारा ब्रिटिश काउंसिल को निशाना बनाकर किये गये दो विस्फोटों में 10 लोग मारे गये व 4 अन्य घायल हुए।[18]
24. **इराक में 22 शिया तीर्थ यात्रियों की हत्या (13 सितम्बर 2011, मंगलवार)** – इराक के सुन्नी बहुल अनबर प्रान्त में बन्दूकधारियों ने 22 शिया तीर्थयात्रियों की हत्या कर।[19]
25. **इराक के 13 शहरों में हमले (23 जुलाई 2012, सोमवार)** – रमजान के महीने में इराक के विभिन्न इलाकों में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों और गोलीबारी में 93 लोगों की मौत हुई तथा लगभग 150 लोग घायल हुए।[20]
26. **कराची में चीनी दूतावास के पास बम विस्फोट (23 जुलाई 2012, सोमवार)** – पाकिस्तान के कराची शहर में चीन के वाणिज्यिक दूतावास के पास एक बम धमाका

[14] 22 अप्रैल 2010, गुरूवार, दैनिक भास्कर, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 12
[15] 24 अप्रैल 2010, शनिवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 2
[16] 17 मई 2011, मंगलवार, दैनिक भास्कर, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 11
[17] 15 अगस्त 2011, सोमवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 17
[18] 20 अगस्त 2011, शनिवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 10
[19] 14 सितम्बर 2011, बुधवार, दैनिक भास्कर, पानीपत–रोहतक, पृष्ठ संख्या – 12
[20] 24 जुलाई 2012, मंगलवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 10

हुआ। जिसमें अर्द्धसैनिक बल के 1 जवान सहित 3 लोग घायल हो गये। विस्फोट रिमोट की सहायता से किया गया।[21]

27. **पाक में बम धमाका (10 सितम्बर 2012, सोमवार)** – पाकिस्तान में हुए एक कार बम धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई और 45 से अधिक घायल हो गये।[22]
28. **सीरिया में दो धमाके (26 सितम्बर 2012, बुधवार)** – सीरिया की राजधानी दमिश्क स्थित सेना के मुख्यालय पर दो धमाके हुए। सेना के मुताबिक विद्रोहियों के इस हमले में सैनिक बच निकले लेकिन मौके पर मौजूद ईरानी प्रेस टीवी के 2 पत्रकार घायल हो गये। मुख्यालय के चारों ओर गोलीबारी हुई।[23]
29. **धमाकों से दहला हैदराबाद (21 फरवरी 2013, वीरवार)** – निजामों के शहर हैदराबाद के भीड़–भाड़ वाले इलाके दिलसुख नगर में सिलसिलेवार तीन बम धमाकों में 18 लोगों की मौत हो गई करीब 50 लोग जख्मी हुए। हैवानों ने ज्यादा से ज्यादा जान लेने के लिये फफट ओवर ब्रिज में भी बम लगाया था। धमाके के लिये विस्फोटक आईईडी का इस्तेमाल किये जाने की संभावना है। इस आतंकी वारदात के पीछे इण्डियन मुजाहिदीन पर सन्देह जताया गया।[24]
30. **पाकिस्तान में बम धमाका (11 मार्च 2013, वीरवार)** – पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिम इलाके में एक शरणार्थी शिविर में हुए जोरदार बम धमाके में महिलाओं व बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हो गई व कई अन्य लोग घायल हुए। यह बम एक कार में रखा गया था।[25]
31. **बगदाद में सिलसिलेवार बम धमाका (14 मार्च 2013, वीरवार)** – इराक की राजधानी बगदाद के केन्द्र में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 22 लोगों की मौत हो गई। मारे गये लोगों में 6 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। धमाकों में 50 लोग घायल हुए।[26]
32. **बी.एस.एफ. जवानों पर आतंकी हमला (21 मार्च 2013, वीरवार)** – श्रीनगर में नौगाम बाईपास पर सीमा सुरक्षा बल (B.S.F.) के एक दल पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इसमें 1 जवान शहीद हो गया जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए।[27]
33. **अमेरिका में आतंकी हमला (16 अप्रैल 2013, मंगलवार)** – अमेरिका (बोस्टन) में हुए आतंकी हमले में 3 लोगों की मौत हो गई व 176 से अधिक जख्मी हो

[21] 24 जुलाई 2012, मंगलवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 10
[22] 11 सितम्बर 2012, मंगलवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 5
[23] 27 सितम्बर 2012, वीरवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 7
[24] 22 फरवरी 2013, शुक्रवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 1
[25] 12 मार्च 2013, शुक्रवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 13
[26] 15 मार्च 2013, शुक्रवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 11
[27] 22 मार्च 2013, शुक्रवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 14

गये। अमेरिका में 2001 में हुए 9/11 आतंकी हमले के 11 साल बाद यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है।[28]

34. **बेंगलुरू में बम विस्फोट (17 अप्रैल 2013, बुधवार)** – कर्नाटक में सत्ताधारी भाजपा के कार्यालय 'जगन्नाथ भवन' के सामने एक आतंकी कार्यवाही के तहत बाइक में हुए जोरदार विस्फोट में कम से कम 16 लोग घायल हो गये। घायलों में 11 पुलिसकर्मी शामिल।[29]
35. **चीन में आतंकी हमला (24 अप्रैल 2013, बुधवार)** – चीन के शिवजियांग प्रान्त में आतंकवादियों द्वारा किये गये बम हमलों में 21 लोगों की मौत हो गई व अन्य कई घायल हुए।[30]
36. **पाकिस्तान में विस्फोट (23 मई 2013, वीरवार)** – दक्षिण–पश्चिम पाकिस्तान के क्वेटा शहर में सुरक्षाकर्मियों को लेकर जा रही बस को निशाना बनाकर किये गये बम विस्फोट से 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा घायल हो गये।[31]
37. **पाकिस्तानी जेल पर तालिबानी हमला (30 जुलाई 2013, मंगलवार)** – पाकिस्तान में एक जेल पर धावा बोल कर तालिबान लड़ाके अपने 250 साथियों को छुड़ा ले गये और 14 लोग मारे गये इनमें 6 शिया कैदी, 6 पुलिसवाले और 2 हमलावर हैं व 5 पुलिसवाले तथा 2 नागरिक घायल हुए।[32]
38. **इराक में धमाका (7 अगस्त 2013, बुधवार)** – इराक की राजधानी बगदाद और इसके आस–पास के बाजारों को निशाना बनाकर किये गये कम से कम 8 कार बम हमलों में 37 लोग मारे गये व करीब 120 से अधिक जख्मी हुए।[33]
39. **इराक में बम धमाका (10 अगस्त 2013, शनिवार)** – इराक की राजधानी बगदाद में 9 बम धमाके हुए। इनमें 64 लोगों की मौत हो गई व करीब 150 से अधिक लोग घायल हुए।[34]
40. **सीरिया में आतंकी हमला (17 अगस्त 2013, शनिवार)** – सीरिया में शनिवार को दो जगह आतंकी हमले हुए जिनमें 28 लोग मारे गये।[35]
41. **केन्या में आतंकी हमला (21 सितम्बर 2013, शनिवार)** – केन्या की राजधानी नैरोबी में आतंकियों ने शॉपिंग मॉल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।

---

[28] 17 अप्रैल 2013, बुधवार, हरिभूमि, रोहतक, पृष्ठ संख्या – 1
[29] 18 अप्रैल 2013, वीरवार, अमर उजाला, चंडीगढ़, पृष्ठ संख्या – 1
[30] 25 अप्रैल 2013, वीरवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 12
[31] 24 मई 2013, शुक्रवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 9
[32] 31 जुलाई 2013, बुधवार, दैनिक भास्कर, पानीपत–रोहतक, पृष्ठ संख्या – 1
[33] 8 अगस्त 2013, गुरुवार, दैनिक भास्कर, पानीपत–रोहतक, पृष्ठ संख्या – 10
[34] 11 अगस्त 2013, रविवार, दैनिक भास्कर, पानीपत–रोहतक, पृष्ठ संख्या –12
[35] 18 अगस्त 2013, रविवार, दैनिक भास्कर, पानीपत–रोहतक, पृष्ठ संख्या – 12

फायरिंग से पहले हमलावरों ने कहा – जो मुस्लिम हैं वे निकल जायें, हम सिर्फ गैर मुस्लिमों को मारना चाहते हैं। घटना में 2 भारतीय सहित 30 लोग मारे गये और करीब 100 लोग घायल हुए।[36]

42. **केन्या में आतंकी हमला (22 सितम्बर 2013, रविवार)** – केन्या की राजधानी नैरोबी के शॉपिंग मॉल दो दिन बाद भी सोमालियाई आतंकी समूह अल–शबाब के कब्जे में था। यहाँ मुम्बई 26/11 हमले जैसी स्थिति बनी थी। इस गुट के हमले में 6 भारतीयों समेत 68 लोग मारे गये थे। मरने वालों में केन्याई राष्ट्रपति का भांजा और उसकी मंगेतर भी शामिल है। 200 से ज्यादा लोग घायल हुए इनमें कई भारतीय थे।[37]
43. **जम्मू में पुलिस, सेना पर आतंकी हमला (26 सितम्बर 2013, वीरवार)** – आतंकियों ने जम्मू क्षेत्र में पिछले 10 साल में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। दो जिले – कठुआ और सांबा में हुए इस हमले में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रमजीत सिंह, 3 जवान और 4 पुलिसवाले शहीद हो गये। 2 आम लोग भी मारे गये। कर्नल ए. अचीन समेत 6 जवान घायल हुए। गुरुवार को हुई यह मुठभेड़ 8 घंटे चली। आखिर में तीनों आतंकी मार गिराये। आतंकी पाकिस्तान से आये थे।[38]
44. **पाकिस्तान में बस में बम विस्फोट (27 सितम्बर 2013, शुक्रवार)** – पाकिस्तान के अशान्त पश्चिमोत्तर इलाके में सरकारी कर्मचारियों से भरी एक बस में विस्फोट होने से 19 लोग मारे गये और 40 से अधिक घायल हो गय।[39]
45. **यमन में आतंकी हमला (2 नवम्बर 2013, शनिवार)** – यमन के उत्तरी प्रान्त सादा में शिया विद्रोहियों द्वारा किये गये घातक हमलों में 18 लोगों की मौत हो गई तथा 50 से अधिक घायल हो गये।[40]
46. **यमन के रक्षा मंत्रालय पर आतंकी हमला (5 दिसम्बर 2013, वीरवार)** – यमन की राजधानी सॉना में रक्षा मंत्रालय के परिसर में आतंकी हमले में 25 लोग मारे गये व कई अन्य घायल हुए। यमन अमेरिका का सहयोगी देश है। यहाँ अलकायदा के हमले होते रहते हैं।[41]
47. **इराक में सीरियल बम ब्लास्ट (8 दिसम्बर 2013, रविवार)** – इराक की राजधानी बगदाद और उसके आस–पास के इलाकों में हुए सिलसिलेवार बम

---

[36] 22 सितम्बर 2013, रविवार, दैनिक भास्कर, रोहतक, पृष्ठ संख्या – 3
[37] 23 सितम्बर 2013, सोमवार, दैनिक भास्कर, रोहतक, पृष्ठ संख्या – 1
[38] 27 सितम्बर 2013, शुक्रवार, दैनिक भास्कर, रोहतक, पृष्ठ संख्या – 1
[39] 28 सितम्बर 2013, शनिवार, दैनिक भास्कर, रोहतक, पृष्ठ संख्या – 10
[40] 3 नवम्बर 2013, रविवार, पंजाब केसरी, हिसार, पृष्ठ संख्या – 1
[41] 6 दिसम्बर 2013, शुक्रवार, दैनिक भास्कर, रोहतक, पृष्ठ संख्या – 14

धमाकों में 33 लोगों की मौत हो गई व अन्य कई घालय हुए। सभी धमाके भीड़–भाड़ वाली जगहों पर किये गये थे।[42]

48. **इराक में आतंकी हमला (25 दिसम्बर 2013, बुधवार)** – इराक में क्रिसमस पर चर्च के पास आतंकी हमलों में 47 लोगों की मौत हो गई व अन्य कई घायल हुए। बगदाद के दुरा बाजार में दो बम धमाके हुए। इनमें 35 लोगों की मौत हो गई व 56 लोग घायल हुए थे।[43]
49. **जलपाईगुड़ी में बम विस्फोट (26 दिसम्बर 2013, वीरवार)** – पश्चिमी बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के बजरापारा क्षेत्र में बम विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई व 4 अन्य घायल हो गये।[44]
50. **पाक में पोलियो टीम पर आतंकी हमला (1 मार्च 2014, शनिवार) –** पाकिस्तान में पोलियो टीकाकरण टीम को निशाना बनाकर किये गये बम धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई व 10 अन्य घायल हुए।[45]
51. **कतर में आतंकी विस्फोट (2 मार्च 2014, रविवार) –** कतर की राजधानी दोहा के एक मॉल में स्थित रेस्तरां में हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई व 35 अन्य घायल हुए, मरने वालों में 5 भारतीय भी शामिल थे।[46]
52. **नाइजीरिया में बम विस्फोट (2 मार्च 2014, रविवार) –** नाइजीरिया के मैदुगुरि शहर में दो बम धमाके हुए। ये धमाके शहर के भीड़–भाड़ वाले बाजार में हुए और इन धमाकों में कम से कम 51 लोगों की मौत हो गई व कई अन्य घायल हुए।[47]
53. **इराक में बम विस्फोट (16 मार्च 2014, रविवार) –** इराक की राजधानी बगदाद और उसके आस–पास के इलाकों में कार बम धमाकों में 19 लोगों की मौत हो गई व अन्य कई घायल हो गये।[48]

1.1 आतंकवाद की अवधरणा और अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद में आत्मघाती–हमलों की भूमिका
(Concept of Terrorism and Role of Suicide Attacks in International Terrorism)

जिस प्रकार 18वीं–19वीं सदी साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के विस्तार के लिए, 20वीं सदी साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद की चरम परिणति और उसकी समाप्ति एवं शीतयुद्ध

---

[42] 9 दिसम्बर 2013, सोमवार, दैनिक भास्कर, रोहतक, पृष्ठ संख्या – 14
[43] 26 दिसम्बर 2013, गुरुवार, दैनिक भास्कर, रोहतक, पृष्ठ संख्या – 12
[44] 27 दिसम्बर 2013, शुक्रवार, दैनिक भास्कर, रोहतक, पृष्ठ संख्या 10
[45] 2 मार्च 2014, रविवार, दैनिक भास्कर, रोहतक, पृष्ठ संख्या – 11
[46] 3 मार्च 2014, सोमवार, दैनिक भास्कर, रोहतक, पृष्ठ संख्या – 10
[47] वही, पृ. सं. – 10
[48] 17 मार्च 2014, सोमवार, दैनिक भास्कर, रोहतक, पृष्ठ संख्या – 10

के लिए जानी जाती है, उसी प्रकार 21वीं सदी आतंकवाद की चरम परिणति और उससे मुक्ति के लिए जानी जाएगी।

आतंकवाद का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रुसेल्स में दंडविधान को समेकित करने के लिए 1931 में बुलाए गए तीसरे सम्मेलन में किया गया था जिसके अनुसार आतंकवाद का अभिप्राय ''जीवन भौतिक अखण्डता अथवा मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाला या बड़े पैमाने पर संपत्ति को हानि पहुँचाने वाला कार्य करके जानबूझकर भय का वातावरण उत्पन्न करना है''

साधारणतः आतंकवाद का अभिप्राय आतंक उत्पन्न करना है आतंक उत्पन्न करने के पीछे किसी संगठन अथवा समूह को कोई निश्चित लक्ष्य प्राप्त करना होता है यह लक्ष्य राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत भी हो सकता हैं, आतंकवाद में ऐसे बर्बर हिंसक तरीकों को अपनाया जाता है जिन्हें आज के सभ्य मानवतावादी समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है। आतंक का सरल अभिप्राय भय उत्पन्न करना है। भय उत्पन्न करके अपने उद्‌देश्य की पूर्ति करना ही आतंकवाद है। अतः आतंकवाद कोई विचारधारा (Ideology) या सिद्धान्त (Theory) नहीं है, अपितु एक तरीका (Method), एक प्रक्रिया (Process) या फिर एक उपकरण है जिसका प्रयोग कर कोई राज्य, राजनीतिक संगठन, स्वतंत्रावादी समूह, अलगाववादी संगठन, जातीय या धार्मिक उन्मादी अपने उद्‌देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ''गुरिल्ला युद्ध को आतंकवाद का पर्यायवाची मानना भी भूल है क्योंकि गुरिल्ला युद्ध करना युद्ध की एक तकनीक है जिसका प्रयोग आतंकवादी भी करते हैं।''[49]

जब से वैश्वीकरण या ग्लोबलाईजेशन शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्रियों ने किया है तब से आतंकवाद के साथ भी यह शब्द जुड़ गया है। आतंकवादी संगठन जब परस्पर संबंध स्थापित कर एक–दूसरे को अपने समान मानकर परस्पर सहायता करते हैं और उनके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो जाते तब यह कहा जाता है कि आतंकवाद का वैश्वीकरण (Globalization of Terrorism) हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रमुख अध्येता ब्रियान क्रोजर (Brian Crozer) का भी यह मानना है कि बीसवीं शताब्दी का आतंकवाद अपने स्वरूप में विश्वपरक (Global) है। ''विश्व के आतंकवादियों में आपसी एवं कार्यपद्धति प्रायः एक ही प्रकार की हैं। यह एक–दूसरे को प्रशिक्षण और हथियारों की पूर्ति में सहायता करते हैं।''[50]

परंतु अभी भी विश्व भर में आतंकवाद की सही परिभाषा नही की गई है। ''एक देश का आतंकवाद दूसरे के लिए स्वतंत्रता सेनानी बन जाता है। इस दुविधा का कारण हिंसा के प्रति अस्पष्ट रूख है। अगर हिंसा को राजनीति का

---

[49] प्रतियोगिता दर्पण, आगरा, दिसम्बर, 2001, पृष्ठ संख्या – 849
[50] वही, पृ. सं. – 849

सही रास्ता मान लिया जाए तो आतंकवाद और अन्य किसी भी प्रकार की हिंसा के प्रति स्पष्ट रूख अपनाना असंभव हो जाता है।''[51]

आतंकवाद ऐसी विचारधारा है जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए और राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार की शक्ति तथा अस्त्र–शस्त्र के प्रयोग करने में विश्वास रखती है। आतंकवादियों द्वारा अस्त्र–शस्त्रों का प्रयोग विरोधी वर्ग, सम्प्रदाय अथवा राष्ट्र विशेष को गैर कानूनी ढ़ंग से डराने, धमकाने, जान से मार देने के लिए किया जाता है। हिंसा के माध्यम से सरकार को गिराने तथा शासन तंत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास किये जाते हैं।

इस प्रकार आतंकवाद उस प्रवृत्ति को कहा जाता है जिसके माध्यम से कतिपय अवांछित तत्त्व अपनी सभी प्रकार की माँगे स्थापित सरकार से मनवाने के लिए अनेक प्रकार के घोर हिंसात्मक उपायों एवं जघन्य अमानवीय साधनों एवं अस्त्र–शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आतंकवादी **आटोमोबाईल बम, प्लास्टिक बम, स्वचालित राईफलों (ए.के. 47, ए.के. 56 राईफल), मानव बम, वाकीटाकी सेटों, पत्र बमों, ट्रांजिस्टर बम, मोबाईल बम, व्हीकल बम, साइकिल बम, आर.डी.एक्स. (विस्फोटक), मिसाइलें, हल्के हथगोले, छोटे रॉकेट लॉचर आदि** तथा अन्य तरीकों के अब पूर्णतः अभ्यस्त है। हत्या, अपहरण तथा बम वर्षा तो इनकी आम बात हो गई है।

आज लगभग सम्पूर्ण विश्व में आतंकवाद व्याप्त है अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये सार्वजनिक हिंसा और सामूहिक हत्याओं का कुत्सित रास्ता अपनाया जा रहा है। **अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी तथा राजीव गाँधी व शेखमुजीब, बेनजीर भुट्टों आदि की नृशंस हत्या, भारत के विमान आई. सी. 814 का अपहरण, भारतीय संसद पर हमला व अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर व पेंटागन पर हमला आदि घटनायें हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कतिपय उल्लेखनीय उदाहरण है।**

आतंकवादी संगठन के उद्देश्य (Goals/Objectives of Terrorist Organization)

आतंकवादी संगठनों के उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है–

1. अपने उद्देश्य व आदर्शों का अधिकाधिक प्रचार करना और जनता का अधिकाधिक समर्थन प्राप्त करना।
2. अपनी शक्ति में वृ(के लिये विशेषकर युवा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करना और अपने आदेशों के पक्ष में सोच को बदलना, उन्हें संगठन के लिये मर मिटने को तैयार करना। उनके दिलों–दिमाग में यह भावना पैदा करना कि **'हम मिशन के लिए जीयेंगे और मिशन के लिए ही मर जायेंगे'।**

[51] अरूंधति राय (लेख), दैनिक भास्कर, 24 अक्टूबर, 2001, पृष्ठ संख्या – 4

3. धमकी, हिंसा, हत्या, अपहरण तथा सामाजिक सम्पत्ति को नष्ट करके सरकार या शासन पर अपनी माँगे स्वीकार करने के लिये दबाव बनाना।
4. विरोधियों और मुखबिरों को किसी भी स्तर पर सहन या क्षमा न करना। उनको नष्ट करने के लिए आवश्यक कदम उठाना। आन्दोलन या गतिविधियों के मार्ग में आने वाली प्रत्येक बाधा को दूर करना। अपने समर्थकों या अनुयायियों की हर दृष्टि से सहायता करना और उनके पकड़े जाने पर उन्हें छुड़ाने के लिए सभी प्रयास करना।
5. शासन व सेना के मनोबल को गिराने का प्रयास करना जिससे उनकी गतिविधियाँ निर्बाध रूप से चल सके।
6. देश की अन्य पृथक्कतावादी शक्तियों को भड़काना।
7. विरोधी सरकार व जनता को भयभीत करके उस पर दबाव बनाकर अपनी माँगे मनवाना।

आतंकवाद की विभिन्न गतिविधियाँ (Various Terrorist Acts)

आतंकवाद की विभिन्न गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं–

1. सार्वजनिक सम्पत्ति व संचार सेवाओं को नष्ट करना।
2. अपहरण व बन्धक बनाना।
3. सामूहिक जनसंहार।
4. सार्वजनिक एवं धार्मिक पूजा स्थलों पर एकत्रित भीड़ (जनसमूह), यात्रियों से भरी बस, ट्रेन, या वायुयान, उत्सवों पर बाजारों की भीड़ वाले इलाके इनका Soft Targets होते हैं जहाँ अधिक से अधिक संख्या में लोग मारे जाते हैं व घायल हो जाते हैं जिससे लोगों में आतंक एवं भय की भावना पैदा हो जाती है।
5. उन व्यक्तियों पर हिंसात्मक आक्रमण करके जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त हैं। जैसे राष्ट्राध्यक्ष, महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व, कूटनीतिज्ञ इत्यादि।
6. विमानों पर अनाधिकृत कब्जा और नागरिक उड्डयन में बाधा डालना।
7. समुद्री मार्गों पर डकैती करना।
8. समुद्री प्रदूषण जिनमें कुछ हानिकारक पदार्थ सम्मिलित हैं।
9. आणविक शक्ति का गैर कानूनी उपयोग।
10. नशीले पदार्थों का गैर–कानूनी यातायात।
11. मुद्रा का गैर कानूनी हस्तान्तरण और नकली मुद्रा छापकर बाजार में उतारना।
12. दासों का व्यापार।
13. अश्लील साहित्य का वितरण।
14. ज्वलनशील पदार्थों, बमों, तथा आग्नेयशस्त्रों के प्रयोग द्वारा की गई विध्वंसात्मक कार्यवाही।
15. बारूदी सुरंगे जमीन में बिछाकर सुरक्षा बलों के विरूद्ध घात लगाना।

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद में आत्मघाती–हमलों की भूमिका (Role of Suicide Attacks in International Terrorism)

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद में आत्मघाती–दस्तों की भूमिका बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि आतंकवादियों ने आत्मघाती–दस्तों का प्रयोग एक सफल एवं प्रभावशाली हथियार के रूप में प्रयोग करने में कामयाबी हासिल कर ली है। अलकायदा के आत्मघाती–दस्तों ने अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर एवं पेंटागन पर आत्मघाती हमले करके विश्व की महाशक्ति अमेरिका के लगभग 3000 निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारकर और बहुमूल्य सम्पदा का विनाश करके अपनी कारगर भूमिका का प्रमाण प्रस्तुत किया। आत्मघाती–दस्ता रूपी हथियार इतना कारगर है कि इसकी काट के लिए दुनिया के किसी भी देश के पास कोई भी हथियार नहीं है इसीलिये विश्व के सभी देशों के रक्षा–विशेषज्ञ, वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक मिलकर आत्मघाती–दस्तों की प्रभावशाली भूमिका पर गहन चिन्तन, मनन एवं शोध करने में लगे हुए हैं कि किस प्रकार दुनिया के निर्दोष नागरिकों को इन आत्मघाती–दस्तों से सुरक्षित किया जा सकता है? आत्मघाती–दस्तों को मानव बम और फिदायीन के नाम से भी जाना जाता है। इन आत्मघाती–दस्तों की प्रभावशाली भूमिका क्षेत्रीय आतंकवाद के संगठनों लिट्टे और हमास तथा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन अलकायदा ने अपनी गतिविधियों के द्वारा प्रमाणित कर दी है।

आत्मघाती–दस्तों ने मानव जाति को अपार क्षति पहुँचाई है दुनिया के महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व, महान् फरूषों के योगदान से विश्व समाज को वंचित कर दिया है जिनकी कमी समाज को हमेशा खलती रहेगी। आज आत्मघाती हमलों की प्रभावशीलता इतनी बढ़ गई है कि इनकी तुलना परमाणु बम से की जाने लगी है। अतः इनकी रोकथाम के लिए विश्वस्तर पर गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं।

आतंकवाद का सबसे खतरनाक रूप है – आत्मघाती हमले अर्थात् मानव बम। क्योंकि उसे खुद मरने की परवाह नहीं होती इसलिये वह किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होता। मानव बम तैयार कर लेना किसी भी आतंकवादी संगठन के लिये गर्व की बात है। यह कार्य वही कर सकता है जिसमें प्राणोत्सर्ग की उच्च कोटि की भावना हो। मानव बम की बहुत कड़ी ट्रेनिंग 12 से 18 महीने की होती है। यह तेज दिमाग, भावुक, शारीरिक रूप से उत्कृष्ठ कठोर होता है। यह एथलीट की तरह भागता भी है, उसके दिलों–दिमाग में यह बात भर दी जाती है कि उनका बलिदान एक कौम को अमर बना देगा। एक देश की बुनियाद रखेगा। मिशन पर जाने से पहले मानव बम संगठन को प्रमुख के साथ पूरा एक दिन बिताता है और मुखिया का आशीर्वाद लेकर वह अपने मिशन पर निकल जाता है।

मानव बम आतंकवादियों का एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिसकी काट अब तक विश्व की किसी भी सुरक्षा एजेन्सी, सरकार और सेना के पास नहीं है। मरने–मारने का संकल्प लिये उच्च्च विस्फोटकों से लैस चलता–फिरता कोई

युवक या युवती मानव बम बना वह व्यक्ति 6 से 8 किलोग्राम आर.डी.एक्स. (RDX – Research Developed Explosives – शोध विकसित विस्फोटक) या आई.ई.डी. (IED – Improved Explosive Device – विकसित विस्फोटक यन्त्रा) को बेल्ट में भरकर अपनी कमर से बाँधे रहता है जो ब्लास्टिंग कैप और बैटरी से जुड़ी है। बेल्ट में भरे विस्फोटक का विस्फोटन इलैक्ट्रोनिक प्रणाली पर आधारित होता है जिसे मात्रा एक छोटे से बटन को दबाकर विस्फोटित किया जा सकता है और वह बटन मानव बम बने व्यक्ति की सुविधाजनक पहुँच के भीतर मौजूद होता है। ऐसे मानव बम फिलीस्तीन के हमास, लिट्टे, अलकायदा, लश्करे–तैयबा, जैश–ए–मुहम्मद आदि दुनिया के आतंकवादी संगठनों में तैयार किये जाते हैं।

आत्मघाती आक्रमण आतंकवाद का सबसे घातक व विनाशक स्वरूप है। यह एक ऐसा साधन है, जिसका प्रतिरोध अब तक दुनिया की किसी भी सुरक्षा एजेंसी, सरकार, सेना व शक्ति के पास नहीं है। **अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी** की हत्या के कुछ दिन पूर्व **सी.आई.ए. (अमेरिकी खुफिया एजेंसी)** के तत्कालीन निदेशक ने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को मरने का डर न हो तो उससे अधिक खतरनाक दुनिया का कोई भी आदमी नहीं होता। वैसे भी कहा जाता है कि अकेला शत्रु अधिक घातक होता है। मानव बम या आत्मघाती हमला करने वाले व्यक्ति की खतरनाक स्थिति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि मानव बम बने व्यक्ति को हरपल याद रहता है कि उसके द्वारा उठाये गये इस कदम से सबसे पहले उसी की मौत होगी। इसके बावजूद अगर उसमें अपने लक्ष्य को पूरा करने का जोश, जुनून, जिद्द और जज्बा रहता है तो उसकी लक्ष्य प्राप्ति की पराकाष्ठा को स्पष्ट रूप से अनुमानित किया जा सकता है।

''आज की तिथि में **आत्मघाती दस्ता (फिदायीन)** मजहबी लड़ाई का ही एक घातक हथियार है, जो कट्टरपंथ की ही देन है। एटम बम से भी घातक बना मानव बम एक चलता–फिरता विस्फोटकों से लैस इंसान होता है, जो अपने निर्धारित लक्ष्य के परखच्चे उड़ाने के साथ ही स्वयं को भी असंख्य चीथड़ों में तब्दील हो जाता है। इस प्रकार के आत्मघाती दस्तों को तैयार करने में सबसे ज्यादा महारत श्रीलंका के कुख्यात आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) को प्राप्त थी, जिसने (वी.आई.पी.) को मानव बम का शिकार बनाया। मानव बम लिट्टे आतंकवादी संगठन का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बना, जिसका जवाब श्रीलंका की सेना व रणनीतिकारों को बहुत मुश्किल से मिल पाया।''

आत्मघाती हमला करने वाला मानव बम कब और क्यों बनता है कोई? वे कौन–सी परिस्थितियाँ होती हैं, जब कोई व्यक्ति सदैव जीवित रहने की स्वाभाविक इच्छा के विपरीत **'मानव बम'** बनने को तैयार हो जाता है। सवाल यह उठता है कि क्या आम आदमी मानव बम बन सकता है? कहा जा सकता है कदापि नहीं। वस्तुतः जब किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर धर्म, जाति, क्षेत्र या नस्ल का जोरदार व जबरदस्त जुनून सवार हो जाता है तो वह मानसिक रूप

से विक्षिप्त हो जाता है और अपनी आत्माहुति से भी संकोच नहीं करता। मानव बम की मानसिकता केवल एक मानसिक रोग के कारण ही नहीं बनती, बल्कि उसके समूचे व्यक्तित्व में बने असंतुलन के कारण ही पैदा होता है। जिस व्यक्ति में मानसिक असंतुलन होगा, उसे ही कोई आतंकवादी गिरोह अपने मकड़जाल में फंसा पाता है। यह भी एक प्रकार की व्यक्तित्व विक्षिप्तता है। इसके चलते ही वह अपने मुखिया के आदेशों का अक्षरशः पालन करने लगता है। मानव बम अथवा आत्मघात के पीछे एक मास्टर माइंड काम करता है।

मरने–मारने का संकल्प लिये एक चलता–फिरता इंसान, जब घातक विस्फोटों से लैस हो, मानव बम में तब्दील हो जाता है, तो यह आतंकवाद का चरम बन जाता है। 'दुनिया में दहशत और भयानक परिदृश्य का पर्याय बने मानव बम बनना कोई हँसी–खेल नहीं है। यह एक दीक्षा है, बहुत कठिन दीक्षा, जो इसमें सफल होते हैं, उसे ही यह दुर्लभ सम्मान मिलता है।'

राजीव गाँधी हत्याकाण्ड (Assassination of Sh. Rajiv Gandhi)

21 मई 1991 की रात को तमिलनाडू के पेरम्बदूर नामक स्थान पर श्री राजीव गाँधी को एक जन सभा को सम्बोधित करना था तब एक महिला मानव बम जिसने अपनी बेल्ट में रखे विस्फोटक पदार्थ से, पूफलमाला चरणों में रखने के बहाने आत्मघाती विस्फोट करके स्वयं को और राजीव गाँधी तथा अन्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह 30 वर्षीय महिला जिसका नाम 'धनु' था, लिट्टे की सदस्या थी।

''21वीं शताब्दी में आतंकवाद को एक वैश्विक समस्या के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आज विश्व का लगभग प्रत्येक देश किसी–न–किसी रूप में आतंकवाद की समस्या से त्रास्त है। वैसे भी वर्तमान में आतंकवाद एक ऐसी नीति के रूप में विकसित हो चुका है, जिसके आगे विश्व की बड़ी शक्तियाँ भी विवश हैं। 11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका जैसे विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र पर हुई आतंकवादी हमलों की घटना इसका ज्वलन्त प्रमाण है।''[52] क्योंकि अमेरिका में हुए इस हमले से सिर्फ इमारतें ही नहीं ध्वस्त हुई बल्कि अमेरिकी ताकत का समूचा मिथक ही भरभरा कर गिया गया। ''ओसामा बिन लादेन के संगठन अलकायदा के इस आतंकवादी हमले ने एकाएक भय और ताकत के पारम्परिक प्रतिमान बदल दिये। इस हमले ने यह साबित कर दिया कि आज की तारीख में दुनिया का बड़े–से–बड़ा मुल्क चाहे वह कितनी बड़ी सैन्य शक्ति हो, चाहे वह परमाणु हथियारों का जखीरा ही क्यों न रखता हो और उसकी प्रयोगशालाओं में कुछ ही घण्टों के भीतर जैविक हथियार तैयार किए जाते हों, किन्तु इन सारी चीजों से वह (ताकतवर मुल्क) साबित नहीं हो पायेगा। इन हथियारों की ताकत के बावजूद वह (अमेरिका) आतंकवाद से सुरक्षित नहीं हो पाया, से भारत जैसे देश का क्या वजूद है?

[52] डॉ. कृष्णानन्द शुक्ला का शोध आलेख, आतंक की नीति, तूणीर वर्ष, अंक 8, 26 जनवरी, 2007

आज समूची दुनिया आतंक की परिधि में आ गई है। वर्तमान में विश्वव्यापी स्वरूप हो चुका है। विश्व के लगभग सभी लोकतांत्रिक देश इसकी चपेट में हैं।''[53]

उल्लेखनीय है कि ''आतंकवाद मानव जाति का सहचर रहा है और इसका प्रयोग प्रारम्भ से ही किया जाता रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतिक शब्दावली में आतंकवाद सम्भवतः वह शब्द है, जिसने सम्पूर्ण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। राष्ट्रों के नीति निर्धारक और राजनीतिज्ञ आये दिन आतंकवादी खतरे की और, इसके षविरुद्ध कठोरतम कदम उठाने की चर्चा करते रहे हैं। 20वीं शताब्दी के सातवें दशक से इसका प्रयोग राजनीतिक हितों को साधने के लिये किया जा रहा है। यही नहीं आतंकवाद को संघर्ष की एक नई विद्या के रूप में विकसित किया जा रहा है। सातवें दशक से आतंकवाद की तीव्रता में 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से वृ(हो रही है। इस प्रकार अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 3500 आतंकवादी घटनाये हुई हैं।''[54]

''वास्तव में आतंकवाद इस सदी में अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा खतरा है। इस तथ्य को संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर एवं पेंटागन पर हुए आतंकी हमलों ने साबित कर दिया है। इतनी जन और धन की हानि हुई है कि उसकी कल्पना मात्रा से मानव तिलमिला जा रहा है। पिछले 20 वर्षों में आतंकी हमलों में से 60,000 लोग मारे गये हैं और 35,000 लोगों की प्रोपर्टी का नुकसान हुआ, जिससे लगभग डेढ़ मिलियन की क्षति का अनुमान है।''[55]

''आज सम्पूर्ण मानवता आतंकवाद से त्रास्त है और विश्व में अनेक स्तरों पर आतंकवाद सक्रिय हैं – क्षेत्रीय, राज्य–स्तरीय, राष्ट्रीय, सीमापार, उपमहाद्वीपीय, महाद्वीपीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके साथ ही आतंकवाद की किस्में – नक्सलवादी, माओवादी, उग्रवादी, अलगाववादी, जिहादी, मजहबी, कट्टरपंथी, नस्लपंथी, उग्र दक्षिण पंथी, सियासी, सम्प्रदायों एवं आत्मघाती आदि अनेक रूप में भी उभर कर आई हैं। आतंकवाद की उत्पत्ति सनसनीखेज हिंसा से राज्य की शक्ति को चुनौती देने वाली साम्यवादी विचारधारा में देखी जाती है, लेकिन धीरे–धीरे धार्मिक कट्टरता और जातीयता से गठजोड़ कर आतंकवाद अपने में एक स्वतंत्र सिद्धान्त एवं प्रक्रिया बन चुका है। आतंकवाद के इस विस्तार में राष्ट्र–राज्यों की दमन और संरक्षण की दोगली नीति ने सक्रिय भूमिका निभाई है। आज बार–बार कहा जा रहा है कि सभी देशों को मिलकर आतंकवाद का अन्त करना चाहिए। यदि सभी राष्ट्र–राज्यों ने अपने क्षेत्राधिकार के जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध दमनकारी नीतियाँ न अपनाई होती, तो आतंकवाद पैदा ही नहीं होता और किसी कारण जन्म भी हो जाता तो इसका वैश्विक, विनाशक,

---

[53] प्रो. लल्लन जी सिंह, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा, पृष्ठ संख्या–54

[54] डॉ. भगवती धर द्विवेदी का आलेख, ''आतंकवाद और दक्षिण एशियाई देश''

[55] डॉ. कृष्णानन्द शुक्ल द्वारा सम्पादित, फस्तक ''स्त्राातेजिक वातावरण'', पृष्ठ संख्या–198

विध्वंसक, विस्फोटक, विस्तारक, विषाक्त, विस्मित, वैषम्य, व्यापक, विप्लव, विद्रोही एवं विचित्रा रूप से व्याप्त स्वरूप परिलक्षित नहीं होता।''[56]

राष्ट्र–राज्यों ने अपने निजी स्वार्थ हेतु जिस तरह आतंकवाद के दमन और संरक्षण की दोहरी नीति अपनाई, उससे आतंकवाद की विष–बेल निरन्तर फैलती गई। राष्ट्र–राज्यों की यह अघोषित नीति बन गई है कि आतंकवाद अपने लिये खतरा है, तो उसका दमन करो और पड़ोसी के लिए घातक है, तो उसको प्रोत्साहित करो और जब परिपक्व हो जाये तो उसे कूटनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग करो। इस प्रक्रिया में हथियार देना, प्रशिक्षण देना और पनाह देना सब कुछ शामिल है। पाकिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान व अरब देशों ने किया किन्तु इनमें अमेरिका अग्रणीय रहा। आतंकवाद जो इस्लामी आतंकवाद का रूप ले चुका है, दुनिया में सबसे खतरनाक है। अमेरिका के विश्व व्यापार केन्द्र एवं हाल ही में भारत को अपना निशाना बनाकर यह सिद्ध कर दिया। इस घटना पर भारत की प्रतिक्रिया उफपरी तौर पर भले अमेरिका जैसी लग रही हो, परन्तु दोनों में बड़ा अन्तर है। अमेरिका की प्रतिक्रिया में विषमय दानेश्वर की तरह फनफनाहट दिखाई दी, परन्तु भारत की प्रतिक्रिया में एक दन्तहीन व विहीन राष्ट्र के अपने दर्द को सत्यापित होने का सन्तोष है।

आतंकवाद किसी प्रत्यक्ष युद्ध से ज्यादा भयावह है और उससे निपटना आसान नहीं है। **'आतंकवाद' शब्द का अर्थ है – आतंक फैलाना ताकि दहशत बना रहे।** इसे करने वाला आतंकवादी कहलाता है। ये आतंक फैलाने के लिए अलग से निशाना बनाते हैं। आतंकवाद का वैज्ञानिक तथा राजनैतिक अर्थ यह है कि अनिश्चितता पैदा करना। कभी–कभी धोखे में यह करामात कर दिखाता है क्योंकि यह तो कोशिश में रहता है, और मौका पाते ही अपना कार्य कर देता है। ''एक आतंकवादी को ढूँढ़ निकालना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि मछली को नदी से निकालना। बड़े से बड़ा जाल लगा देने के बाद भी एक–दो मछली नदी में छूट ही जाती हैं। उसी तरह कुछ आतंकवादी बच निकलते हैं।''[57] आज आतंकवाद अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है।

इस्लामी आतंकवाद भारत में जिस तरह प्रवेश कर गया है, यह एक गम्भीर चिन्ता की बात है। इस बढ़ते हुए आतंक का सामना करने के लिए सारे देश को एक जुट हो जाना चाहिये। चिन्ता की बात केवल यह है यह ही नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुजाहिदीनों ने भी भारत में प्रवेश कर लिया है। सूडानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी जिस तरह कश्मीरी आतंकवादियों के साथ मिलकर भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं तथा राष्ट्र को खण्डित करने में लगे हुए हैं, उसे अनदेखा करने पर भारत निश्चित ही गंभीर समस्या में फंस जायेगा। पाकिस्तानी आतंकी कार्यवाही की सूचियों में कारगिल घुसपैठ, मुम्बई बम

---

[56] डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र का आलेख, ''आतंकवादः अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिये चुनौती''

[57] कृष्णानन्द शुक्ल, ''शांति, सुरक्षा और विकास की समस्यायें'', 2009, राधा पब्लिकेशन, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, पृष्ठ संख्या–84

काण्ड, 13 दिसम्बर, 2001 को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में संसद पर हमला इत्यादि हैं।

आज पाकिस्तान कश्मीर एवं अन्य राज्यों में आतंकवाद का नग्न प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय जनता धार्मिक कार्य करने में संकोच कर रही है। गत दिनों अमरनाथ दर्शनार्थियों पर पाक आतंकवादियों द्वारा जो अंधाधुंध फायरिंग की गई और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया उसे देखकर कौन साहस करेगा कि अमरनाथ का दर्शन करें। यद्यपि आम आतंकवाद विश्वव्यापी संकट बन गया हैं लेकिन वर्तमान परिवेश में भारतीय सुरक्षा को अत्याधिक खतरा कश्मीर में पाक समर्थित आतंकवाद से है।

स्थिति यह है कि आतंकवादियों के आत्मघाती दस्ते न केवल नागरिक प्रतिष्ठानों पर हमला करने में सक्षम हैं बल्कि सुरक्षाबलों के अभेद्य समझे जाने वाले ठिकानों पर भी खुलेआम आक्रमण कर रहे हैं। चिन्ता की बात यह है कि हमला करके वे निकल भागने में भी सफल होते जा रहे हैं। कश्मीर में आज हिंसा का बोलबाला है। कश्मीर घाटी में रहने वाले हिन्दू और सिक्खों के प्राण खतरे एवं संकट में हैं। अगर उनके प्राण संकट में नहीं होते तो अपना घर–बार छोड़कर शरणार्थियों की तरह अपने ही देश में इधर–उधर क्यों भटकते।

आतंकवाद कमजोर का सशक्त के षविरुद्ध हथियार है। पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अखण्डता पर प्रभाव पड़ता है। पाकिस्तान की नीतियाँ 1971 के बांग्लादेश के जन्म के प्रतिकार के रूप में हैं। ऑल पार्टी हुरिर्यत कॉन्प्रेफंस के पूर्व चेयरमैन अहमद शाह गिलानी सण्डे आब्जर्बर को दिये गये साक्षात्कार में कहा भी है कि यदि भारतीय सेना बांग्लादेश के जन्म में अपना रोल कर सकती है तो इसमें गलत क्या है कि यदि पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर की स्वतंत्रता में अपनी भूमिका अदा करते हैं।

आज जब यह स्थिति है तो भारत को पाकिस्तान के द्वारा घोषित आतंकवाद के षविरुद्ध कदम उठाने में कोई हिचक नहीं करनी चाहिए। भारत के आन्तरिक मामलों में पाकिस्तान का हस्तक्षेप जिस तरह बढ़ रहा है और जिस तरह आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है वह कोई छिपी बात नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत–पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने में सक्षम नहीं है। पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को खुलकर बढ़ावा दे रहा है लेकिन फिर अमेरिका और अन्य शिखर राष्ट्र सच्चाई को देखने से इंकार कर रहे हैं।

"अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को जिन्दा या मुर्दा पकड़ने का संकल्प लेने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश की भर्त्सना करते हुए 11 सितम्बर जैसे हमले करने की धमकी अल जजीरा चैनल के माध्यम से जारी वीडियो टेप के द्वारा दी। ओसामा के टेप की पहली पंक्ति यही है – हे अमेरिकी जनता! मैं आपको एक–दूसरे मनहैटन (युद्ध), उसके कारण तथा परिणामों से बचने के आदर्श रास्ते के बारे में बताता हढ्ढू। आपकी सुरक्षा न तो केरी के हाथों में हैं, न

बुश के हाथों में और न ही अलकायदा के ही हाथ में हैं। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में हैं और जो भी देश हमारी सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुँचायेगा वह सुरक्षित रहेगा।''[58]

भारत के लिये बेहतर यही है कि वह कश्मीर मसले पर – **'देखो और इंतजार करो'** की नीति पर अमल करे और पाकिस्तान में हो रहे घटनाक्रमों पर भी पैनी नज़र रखे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शौकत अजीज ने भी कुछ सकारात्मक संकेत दिये हैं। उन्होंने फरमाया है कि दोनों देशों के मध्य आर्थिक सहयोग बढ़ाये जाने की प्रक्रिया को तेजी से अग्रसरित किया जाना चाहिये। शौकत अजीज की मंशा है कि ईरान से शुरू होने वाली प्राकृतिक गैस की पाइप लाईन पाकिस्तानी भू–भाग से होकर भारत पहुँचे। अजीज की धारणा है कि दोनों मुल्कों के बीच व्याप्त किसी सियासी मसले को आर्थिक सहयोग के रिश्तों में आड़े नहीं आना चाहिये, जबकि अतीत में पाकिस्तान की ओर से यह बात कही जाती रही है कि कश्मीर मसले का समाधान हुए बगैर अन्य द्विपक्षीय मुद्दों को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

आत्मघाती–हमलों की संक्षिप्त क्रमबद्ध सूची (A Brief List of Suicide-Attacks in Chronological Order)

प्रस्तुत अध्याय में आतंकवाद के आत्मघाती–हमलों की एक संक्षिप्त सूची बेतवदवसवहपबंस वतकमत में निम्न प्रकार दी जा रही है –

1. 7 दिसम्बर 1941 को अमेरिका के पर्लहार्बर पर जापानी आत्मघाती दस्तों ने हमला किया जिसमें 3000 लोग मारे गये।
2. 1972 में जर्मनी के म्यूनिख हवाई अड्ड़े पर 6 इजरायली एथलीटों की फिलीस्तानी आत्मघाती आतंकवादियों ने हत्या की।
3. 23 अक्टूबर 1983 को बेरूत स्थित अमेरिका के क्षेत्रीय सैन्य मुख्यालय और इसी से सटे प्रफांसीसी सैन्य मुख्यालय पर दो मानव बमों के बारूद से भरे ट्रक ले जाकर टकरा दिया जिससे लगभग 600 लोग मारे गये।
4. सन् 1984 में एक लेबनानी मानव बम ने अपनी कार में डायनामाइट भरकर अमरीकी दूतावास का गेट तोड़ते हुए कार को अन्दर घुसा दिया जिसमें 40 लोग मारे गये थे ।
5. सन् 1984 में फिलीस्तीन मुक्ति संघर्ष (P.L.O.) का मानव बम शाहीना अब्तूर गाजापट्टी स्थित इजरायली फौजी कैम्प में हर तरह की बाधा तोड़ते हुए मोटरसाइकिल लेकर जा घुसी उसकी कमर में विस्फोटक बंधा था। इस विस्फोट में 14 वरिष्ठ अधिकारी मारे गये।

[58] वही, पृ.सं.–86

6. सन् 1985 में इजरायल के एक हवाई अड्ड़े पर पी. एल. ओ. के मानव बमों ने एक साथ हमला बोलकर कहर बरसा दिया जिसमें 7 विमान जलकर राख हो गये और 4 दर्जन लोग मारे गये।
7. 1987 में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी (IRA) के दो मानव बमों ने इग्लैण्ड की एक पुलिस इमारत को ध्वस्त कर दिया जिसमें 17 फलिकर्मी मारे गये।
8. 21 मई 1991 को मद्रास के निकट पेरम्बदूर में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी लिट्टे की एक महिला मानव बम 'धनु' के भयानक विस्फोट का शिकार हुए।
9. 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअन्त सिंह की भी एक मानव बम दिलावर सिंह के द्वारा चण्डीगढ़ सचिवालय में हत्या की गई।
10. 1995 में श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रणसिंह प्रेमदास की लिट्टे मानव बम द्वारा हत्या हुई।
11. 31 जनवरी 1996 को स्ज्ज्म (लिट्टे) के आत्मघाती दस्ते ने एक ट्रक में बम (विस्फोटक) लादकर श्रीलंका की राजधानी कोलम्बो में स्थित एक बैंक को उड़ा दिया जिसमें 91 लोग मारे गये थे।
12. 7 अगस्त 1998 को अल–कायदा के आत्मघाती आतंकवादियों ने ट्रक में बम (विस्फोटक) रखकर कीनिया और तंजानिया में स्थित अमेरिकी दूतावासों को इन ट्रकों की टक्कर मारकर एक जबरदस्त आत्मघाती विस्फोट किया जिसमें 250 लोग मारे गये थे।
13. 1998 में चेचेन विद्रोहियों के मानव बम ने मास्को की एक सरकारी इमारत में घुसकर भयानक विस्फोट किया जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गये।
14. 25 दिसम्बर 2000 को कश्मीरी अलगाववादियों ने एक कार में बम (विस्फोटक) लादकर एक जबरदस्त आत्मघाती हमला श्रीनगर में किया जिसमें 8 लोग मारे गये थे।
15. 24 मार्च 2001 को चेचन्या के अलगाववादी आतंकवादियों ने एक कार में बम (विस्फोटक) लादकर चेचन्या में अपने आप को उड़ा लिया और 20 लोग मारे गये।
16. 1 जून 2001 को हमास और इस्लामिक जिहाद आत्मघातियों ने एक बेल्ट बम का प्रयोग करते हुए तेल अभिव के नाइट क्लब पर आत्मघाती हमला बोल दिया जिसमें 22 लोग तत्काल मारे गये।
17. जुलाई 2001 में लिट्टे मानव बमों द्वारा कोलम्बो हवाई अड्ड़े पर जबदस्त हमला किया गया जिसमें 13 विमान जल कर राख हुए।
18. **11 सितम्बर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर और रक्षा मंत्रालय पेंटागन** को ओसामा बिन लादेन के अलकायदा पायलेट मानव बमों द्वारा अपहृत विमान की टक्कर से जिस तरह से धराशायी किया गया, वह इतिहास प्रसिद्ध है जिसमें 150 अरब डालर के नुकसान का अनुमान तथा 20,000 से ज्यादा लोग मारे गये।

19. 1 अक्टूबर 2001 को कश्मीर के अलगाववादी आत्मघातियों ने एक कार में बम (विस्फोट) लादकर कार को कश्मीर की विधानसभा के गेट पर जाकर टक्कर मारी जिसमें 30 लोग तत्काल मारे गये।

20. 13 दिसम्बर 2001 को कुछ आतंकवादियों ने अग्नियास्त्रों के साथ भारतीय संसद नई दिल्ली पर आत्मघाती हमला बोल दिया जिसमें 7 लोग मारे गये।

21. कश्मीर श्री नगर में 6 अगस्त 2004 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 65वीं बटालियन पर मात्रा दो आतंकवादियों के आत्मघाली हमलों में सहायक कंमाडेट सहित 10 जवानों को मौत की नींद सुला दिया।

22. लंदन में 7 जुलाई 2005 को आत्मघाती दस्ते द्वारा भीषण बम विस्फोट करके 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 700 से अधिक लोग बुरी तरह से घायल हुए।[59]

23. **पाकिस्तान में आत्मघाती हमला (23 अगस्त, 2008, शनिवार)** – पाकिस्तान के सूबा सरहद की 'स्वात घाटी' में शनिवार तड़के एक पुलिस चौकी को निशाना बनाकर किये गये आत्मघाती हमले में 20 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गये। 'तहरीक–ए–तालिबान' ने इसकी जिम्मेदारी ली थी।[60]

24. **मस्जिद में आत्मघाती हमला (27 मार्च 2009, शुक्रवार)** – पाकिस्तान – अफगानिस्तान सीमा के पास खैबर क्षेत्र में जमरूद शहर के पास प्रार्थियों (भक्तों) से खचाखच भरी मस्जिद में एक अकेले आत्मघाती हमलावर ने एक मानव बम के रूप में स्वंय को विस्फोट से उड़ाया, 50 लोग तत्काल मारे गये और करीब 100 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गयैं

25. **परमाणु ठिकानों तक पहुँचने के आतंकी प्रयास (23 अक्टूबर 2009, शुक्रवार)** – तालिबान आतंकियों ने एक के बाद एक, पाक में तीन बड़े हमले किये। इनमें से एक हमला तो कामरा वायुसेना ठिकाने पर बोला गया। इसे पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा अहम् ठिकाना माना जाता है। आतंकियों ने बारात ले जा रही बस को उड़ा दिया। एक रेस्तरां के बाहर भी धमाका किया गया। इन हमलों में 26 लोगों की जान चली गई व कई जख्मी हुए। आतंकियों ने जुमे के दिन पहला हमला पंजाब प्रान्त में पाकिस्तानी वायुसेना के कामरा ठिकाने पर बोला। साइकिल सवार आत्मघाती हमलावर ने सुबह सवेरे इस ठिकाने की एक चेक पोस्ट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया जोरदार धमाके की चपेट में आये 8 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमलावर की उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। सुरक्षा गार्डों ने जैसे ही उसे रोका तो उसने अपनी सुसाइट जैकेट में धमाका कर दिया।

---

[59] डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र, ''आतंकवाद व आपदा प्रबंधन'', 2010, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, फोन 23247003, पृष्ठ संख्या – 120

[60] 24 अगस्त 2008, रविवार, राजस्थान पत्रिका, पृष्ठ संख्या – 3

26. **संयुक्त राष्ट्र गेस्ट हाउस पर हमला (28 अक्टूबर 2009, बुधवार)** – अफगानिस्तान की राजधानी में स्थित संयुक्त राष्ट्र का एक गेस्ट हाउस आतंकी हमले का निशाना बना। भीषण गोलीबारी में तीन आत्मघाती हमलावरों समेत 13 लोग मारे गये। इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है।

27. **पाक में आत्मघाती हमला (2 नवम्बर 2009, सोमवार)** – पाकिस्तान के रावल पिंडी शहर में सेना मुख्यालय के पास सुबह 10 बजकर 40 मिनट पर आत्मघाती हमले में सेना के एक जवान सहित 34 लोग मारे गये। मोटरसाइकिल सवार आत्मघाती हमलावर ने एक सरकारी बैंक के बाहर विस्फोट कर दिया।

28. **आत्मघाती हमले में पेशावर के मेयर समेत 12 लोगों की मौत (8 नवम्बर 2009, रविवार)** – पेशावर के बाहरी इलाके मत्तनी में लगने वाले मवेशियों के बाजार में रविवार सुबह 9.30 बजे आत्मघाती हमला हुआ था। इसमें तालिबान विरोधी मेयर समेत 12 लोग मारे गये और 35 घायल हो गये। इस विस्फोट की अभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन, प्रशासन इस हमले के पीछे भी 'तहरीक–ए–तालिबान' का हाथ मान रहा है।[61]

29. **पाक में आत्मघाती विस्फोट (9 नवम्बर 2009, सोमवार)** – पेशावर के समीप स्थित हवाई अड्ड़े के पास हुए एक शक्तिशाली आत्मघाती बम विस्फोट में 4 लोग मारे गये और 25 अन्य घायल हो गये।

30. **आतंकियों का आई.एस.आई. पर फिर हमला (13 नवम्बर 2009, शुक्रवार)** – आतंकवादियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी 'इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस' (आई.एस.आई.) को फिर अपना निशाना बनाया है। इस बार आतंकियों ने आई.एस.आई. के पेशावर स्थित मुख्यालय पर आत्मघाती हमला बोला। उन्होंने अशांत पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रान्त में ही एक पुलिस थाने पर भी हमला किया। इन हमलों में सात खुफिया अधिकारियों समेत 20 लोगों की जान चली गई। दोनों हमलों में करीब 85 लोग जख्मी हुए।[62]

31. **रावलपिंडी में एक मस्जिद में आत्मघाती हमला (4 दिसम्बर 2009, शुक्रवार)** – पाकिस्तान में हुई दो अलग–अलग आतंकी वारदात में 41 लोगों की मौत हो गई और 73 लोग घायल हो गये।[63]

32. **पाक में अदालत के बाहर आत्मघाती हमला (7 दिसम्बर 2009, सोमवार)** – पाकिस्तान के पेशावर शहर स्थित एक अदालत के बाहर हुए बम विस्फोट में पाँच लोगों की मौत हो गई और 49 से अधिक घायल हो गये। रिक्शे पर सवार एक आत्मघाती हमलावर ने सेशन कोर्ट के मुख्य द्वार के समीप खुद

---

[61] 9 नवंबर 2009, दैनिक जागरण, सोमवार, हिसार, पृष्ठ संख्या – 7

[62] 14 नवम्बर 2009, शनिवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 9

[63] 5 दिसम्बर 2009, शनिवार, दैनिक भास्कर, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 11

को विस्फोट कर उड़ा लिया। मौके से हमलावर का धड़ से अलग हुआ सिर बरामद किया गया।[64]

33. **बगदाद में शक्तिशाली आत्मघाती हमले (8 दिसम्बर 2009, मंगलवार) –** इराक की राजधानी बगदाद में पाँच शक्तिशाली कार बम धमाकों से दहल उठा। जिसमें 127 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 448 से अधिक घायल हो गये। पुलिस के अनुसार पहला धमाका दक्षिण बगदाद के डोरा इलाके में सुबह 10 बजकर 25 मिनट पर हुआ। यहाँ एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी अपनी कार को पुलिस गश्ती दल से टकरा दिया। इसके बाद शहर में लगातार बम धमाके सुनाई पड़े। शहर अदालत परिसर की पार्किंग में एक आत्मघाती हमलावर ने एक कार में विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया। एक विस्फोट वित्त मंत्रालय की अस्थाई इमारत में हुआ।[65]

34. **आई.एस.आई. दफ्तर पर हमला (8 दिसम्बर 2009, मंगलवार) –** पाकिस्तान की मुल्तान छावनी स्थित आई.एस.आई. के दफ्तर में आत्मघाती हमले में 12 लोगों की मौत हो गई तथा 35 से ज्यादा घायल हो गये।

35. **पाक में आत्मघाती हमला (18 दिसम्बर 2009, शुक्रवार)–** उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के आतंकवाद ग्रस्त इलाके मलकंद स्थित टिमरगढ़ में एक आत्मघाती हमले में चार लोग मारे गये। जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गये। हमला पुलिस लाईन के नजदीक एक मस्जिद के पास हुआ था।[66]

36. **स्कूल के बाहर आत्मघाती हमला (24 दिसम्बर 2009, वीरवार)–** व्यस्त मालरोई (पेशावर) पर मिशन स्कूल के बाहर एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी जैकेट का बटन दबाकर विस्फोट कर दिया जिससे 5 लोग मारे गये तथा 25 घायल हुए।[67]

37. **शियाओं के जुलूस पर आत्मघाती हमला (28 दिसम्बर 2009, सोमवार) –** पाकिस्तान के कराची में मुहर्रम के मौके पर 'शिया' मुसलमानों को निशाना बनाकर एक बार फिर आतंकी हमला किया गया। मुहर्रम के जुलूस में हुए आत्मघाती विस्फोट में 20 लोगों की मौत हो गई थी और 60 लोग घायल हो गये।[68]

38. **अनबर के प्रान्तीय गवर्नर पर आत्मघाती हमला (30 दिसम्बर 2009, बुधवार) –** इराक में सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ ताजा हमलों की कड़ी में पश्चिमी शहर रमादी में दो आत्मघाती धमाके किये गये थे। इस हमले का निशाना अनबर के

---

[64] 8 दिसम्बर 2009, मंगलवार, दैनिक भास्कर, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 3
[65] 9 दिसम्बर 2009, बुधवार, दैनिक भास्कर, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 9
[66] 19 दिसम्बर 2009, रविवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 7
[67] 25 दिसम्बर 2009, शुक्रवार, दैनिक भास्कर, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 11
[68] 29 दिसम्बर 2009, मंगलवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 7

प्रान्तीय गवर्नर थे। धमाकों में 23 लोगों की मौत हो गई और गवर्नर व आला सुरक्षा अधिकारियों समेत 30 लोग जख्मी हो गये थे।[69]

39. **पाक में खेल मैदान पर आत्मघाती हमला (1 जनवरी 2010, शुक्रवार) –** पाकिस्तान में तालिबान के नये साल के पहले ही दिन फिर एक आत्मघाती हमला किया। इस बार खेल के मैदान को निशाना बनाया गया। पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रान्त में एक आत्मघाती हमलावार ने विस्फोटकों से भरा वाहन स्टेडियम की दीवार से टकरा दिया। इस हमले मे तीन लोग मारे गये और करीब एक दर्जन लोग जख्मी हो गये थे।[70]

40. **श्रीनगर के लाल चौक (भारत) पर आत्मघाती हमला (6 जनवरी 2010, बुधवार)–** तीन साल और तीन माह की लम्बी चुप्पी के बाद श्रीनगर के लाल चौक में हुए आत्मघाती हमले से पूरा इलाका गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस आत्मघाती हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद व टीवी चैनल के एक कैमरामैन सहित 10 अन्य लोग जख्मी हो गये थे। सनद रहे कि इससे पहले 12 अक्टूबर 2007 को डल के पास सुरक्षाबलों के शिविर पर तथा 4 अक्टूबर 2006 को लाल चौक में आत्मघाती हमला हुआ था।[71]

41. **काबुल पर आत्मघाती हमला (18 जनवरी 2010, सोमवार) –** अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के आत्मघाती हमलावरों ने कई जगह एक साथ हमले किये। जिसमें 14 लोग मारे गये तथा 71 से अधिक घायल हुए।[72]

42. **पाक में आत्मघाती बम विस्फोट (30 जनवरी 2010, शनिवार)–** पाकिस्तान के बाजौर क्षेत्र में सुरक्षा चौकी के पास हुए एक आत्मघाती विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई।[73]

43. **उत्तरी बगदाद में 'शियाओं' पर आत्मघाती हमला (1 फरवरी 2010, सोमवार)** – उत्तरी बगदाद में एक महिला आत्मघाती हमलावर ने करबला जा रहे तीर्थ यात्रियों के बीच पहुँचकर खुद को विस्फोट कर उड़ा दिया। इस धमाके से 50 लोगों की मौत हो गई और 100 के करीब घायल हो गये थे। इस आत्मघाती हमले में महिला हमलावर ने अपने कपड़ों में विस्फोटक छिपा रखा था।[74]

44. **इराक में आत्मघाती विस्फोट (5 फरवरी 2010, शुक्रवार) –** एक आत्मघाती हमलावर ने 'करबला' में 'शिया जायरीन' की भीड़ के बीच अपनी कार में रखे

---

[69] 31 दिसम्बर 2009, गुरूवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 7
[70] 2 जनवरी 2010, शनिवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 9
[71] 7 जनवरी 2010, वीरवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 2
[72] 19 जनवरी 2010, मंगलवार, दैनिक भास्कर, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 11
[73] 31 जनवरी 2010, रविवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 10
[74] 2 फरवरी 2010, मंगलवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 10

विस्फोटकों में धमाका कर दिया जिसमें कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई और 60 अन्य घायल हो गये।

45. **पाकिस्तान में आत्मघाती विस्फोट (18 फरवरी 2010, वीरवार)** – पाकिस्तान के 'सूबा–ए–सरहद' में अफगान सीमा के निकट खैबर एजेन्सी में तीरा घाटी की एक मस्जिद में हुए एक आत्मघाती बम विस्फोट में कम से कम 30 लोग मारे गये तथा 100 से ज्यादा लोग घायल हो गये।[75]

46. **लाहौर में आत्मघाती विस्फोट (12 मार्च 2010, शुक्रवार)** – सैनिकों को निशाना बनाकर आत्मघाती हमलावरों ने लाहौर (पाक) में 15 सैकिण्ड में दो बम विस्फोट किये। इनमें 10 सैनिकों सहित 45 लोग मारे गये।[76]

47. **स्वात घाटी बनी आत्मघाती हमलावरों का निशाना (13 मार्च 2010, शनिवार)** – आतंकवादियों ने लाहौर (पाकिस्तान) में सैन्य छावनी पर निशाना साधने के बाद शनिवार को मिंगोरा की अदालत को दहलाया। पश्चिमोत्तर 'स्वात घाटी' में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वाले अदालत परिसर के बाहर सुबह एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। विस्फोट में 13 लोग मरे थे जबकि 52 घायल हुए थे।[77]

48. **मास्को (रूस) में आत्मघाती हमला (29 मार्च 2010, सोमवार)** – मास्को में दो महिला आत्मघाती हमलावरों ने यात्रियों से भरी मेट्रो ट्रेन में विस्फोट कर दिया। विस्फोट में 38 लोग मारे गये, जबकि 63 घायल हो गये। मास्को पर करीब साढ़े तीन साल बाद कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ है।[78]

49. **मास्को (रूस) में आत्मघाती हमला (31 मार्च 2010, बुधवार)** – मास्को में आतंकवादियों ने एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। दागिस्तान के अशांत उत्तरी काकेशस इलाके में आत्मघाती हमलावरों ने दो शक्तिशाली हमलावारों ने दो शक्तिशाली विस्फोट किये। इस हमले में 9 पुलिस कर्मियों सहित 12 लोग मारे गए व 27 घायल हो गये।[79]

50. **इराक में आत्मघाती विस्फोट (4 अप्रैल 2010, रविवार)** – इराक की राजधानी बगदाद में हुए तीन आत्मघाती कार बम धमाकों से 30 लोगों की मौत हो गई और 168 लोग घायल हो गये। इन धमाकों का निशाना विदेशी दूतावास थे।[80]

51. **अमेरिकी दूतावास पर आत्मघाती हमला (5 अप्रैल 2010, सोमवार)** – तालिबान ने पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रान्त की राजधानी में छावनी इलाके मे स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर आत्मघाती विस्फोट हुआ।

---

[75] 19 फरवरी 2010, शुक्रवार, राजस्थान पत्रिका, श्री गंगानगर, पृष्ठ संख्या – 14

[76] 13 मार्च 2010, शनिवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 1

[77] 14 मार्च 2010, रविवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 9

[78] 30 मार्च 2010, मंगलवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 1

[79] 1 अप्रैल 2010, वीरवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 2

[80] 5 अप्रैल 2010, सोमवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 9

इससे कुछ देर पहले प्रान्त में सत्तारूढ़ अवामी नेशनल पार्टी की एक रैली में आत्मघाती धमाका हुआ। दोनों वारदात में 44 लोगों की मौत हो गई व 100 से ज्यादा लोग घायल हुए।[81]

52. **रूस में आत्मघाती विस्फोट (5 अप्रैल 2010, सोमवार)**– रूस के उत्तरी काकेशस के इंगुसेतिया क्षेत्र में दो आत्मघाती विस्फोट हुए जिसमें 2 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई और एक घायल हो गया।[82]

51. **पाक में महिला आत्मघाती विस्फोट (17 अप्रैल 2010, शनिवार)** – पाकिस्तान में पश्चिमोत्तर प्रान्त के शहर हांगू से 30 किलोमीटर दूर स्थित कच्चा–पक्का इलाके में लगाये गये विस्थापितों के लिये खाद्य वितरण शिविर (कैम्प) में दो बुर्काधारी महिला आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोट कर खुद को उड़ा दिया। इन दो सिलसिलेवार विस्फोटों में 38 लोगों की मौत हो गई और 65 लोग घायल हो गये। दोनों विस्फोट 10 मिनट के अन्तराल पर हुए थे। दोनों आत्मघाती हमलावर बुर्का पहने थे।[83]

54. **पाक में आत्मघाती हमला (19 अप्रैल 2010, सोमवार)** – पाकिस्तान के अशांत पश्मिोत्तर प्रान्त की राजधानी में जमात–ए–इस्लामी के विरोध प्रदर्शन के दौरान, मशहूर किस्सा ख्वानी बाजार में शाम 6 बजकर 30 मिनट पर जोरदार आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 23 लोग मारे गये और 42 लोग जख्मी भी हुए थे। किशोर उम्र के आत्मघाती हमलावर ने भीड़ के बीच पहुँचकर विस्फोटकों से भरी अपनी जैकेट में धमाका कर दिया।[84]

55. **कैदियों की वैन पर आत्मघाती हमला (24 अप्रैल 2010, शनिवार)** – पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में कैदियों को ले जा रही एक वैन को निशाना बनाकर किए गये आत्मघाती हमले में 2 पुलिसकर्मी मारे गये व 10 पुलिसकर्मी घायल हो गये।[85]

56. **फलिस चौकी पर आत्मघाती हमला (28 अप्रैल 2010, बुधवार)** – पाकिस्तान के अशांत पश्चिमोत्तर प्रांत के पेशावर शहर के बाहरी इलाके में एक आत्मघाती कार बम विस्फोट में 5 पुलिसकर्मी मारे गये जबकि 8 घायल हो गये। आत्मघाती हमलावर ने अपनी कार पुलिस चौकी से टकरा दी। कार के टकराते ही उसमें विस्फोट हो गया।[86]

57. **पाकिस्तान के अर्द्धसैनिक बल पर आत्मघाती हमला (13 मई 2011, शुक्रवार)** – पाकिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान ने अपने सहयोगी संगठन अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन की मौत का बदला लेते हुए पाकिस्तान के

---

[81] 6 अप्रैल 2010, मंगलवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 1
[82] 6 अप्रैल 2010, मंगलवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 9
[83] 18 अप्रैल 2010, रविवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 1
[84] 20 अप्रैल 2010, मंगलवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 9
[85] 25 अप्रैल 2010, रविवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 9
[86] 29 अप्रैल 2010, वीरवार, हरिभूमि, पृष्ठ संख्या – 5

अर्द्धसैनिक बल को निशाना बनाया है। अशांत उत्तर–पश्चिमी पाकिस्तान की अर्द्धसैनिक अकादमी पर हुए दो आत्मघाती हमलों में 80 लोग मारे गये हैं व 115 से अधिक घायल हुए। मरने वालों में सुरक्षाबल के जवान अधिक हैं।[87]

58. **पाक में कार बम विस्फोट (25 मई 2011, बुधवार)** – पाकिस्तान में अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद तालिबान के हमले जारी है। पेशावर के पश्चिमोत्तर शहर में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार ले जाकर पुलिस स्टेशन के गेट में भिड़ा दी। इससे हुए भीषण विस्फोट में 5 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 22 घायल हो गये। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है।[88]

59. **पाक में आत्मघाती हमला (26 मई 2011, वीरवार)** – पाकिस्तान के उत्तर–पश्चिम इलाके में एक आत्मघाती हमले में 24 लोगों की मौत हो गई। हांगू इलाके में मौजूद कोर्ट परिसर और सरकारी दफ्तर के नजदीक हुए इस विस्फोट में मारे गये लोगों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है।[89]

60. **पाकिस्तान में दो बम धमाके (12 जून 2011, रविवार)** – 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन की पाक के ऐपटाबाद में अमेरिकी सील कमाण्डो के हाथों मौत के बाद आतंकियों के बम धमाके लगातार पाकिस्तान को दहला रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम राज्य खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में हुए दो आत्मघाती बम धमाकों में 34 लोग मारे गये जबकि 94 घायल हो गये।[90]

61. **अफगानिस्तान में आत्मघाती कार बम धमाका (15 जून 2011, बुधवार)** – तालिबान आतंकवादियों ने आज कार बम विस्फोट से और रॉकेट दागकर अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति और गृहमंत्री को निशाना बनाकर हमला किया जिसमें 7 लोग मारे गये व 4 घायल हो गये। उपराष्ट्रपति और गृहमंत्री इस हमले में बाल–बाल बच गये।[91]

62. **पेशावर (पाक) में महिला आत्मघाती हमला (11 अगस्त 2011, वीरवार)** – पेशावर में बुर्का पहने एक आत्मघाती महिला हमलावर के हमले और सकड़ किनारे छिपा कर रखे गये बम के विस्फोट में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 37 अन्य घायल हो गये। किसी महिला के आत्मघाती हमले में शामिल होने का भी यह एक दुर्लभ मामला है। माना जा रहा है कि एक और महिला आत्मघाती हमलावर विस्फोट करने वाली थी लेकिन इसके पहले ही उसकी मौत हो गई।[92]

---

[87] 14 मई 2011, शनिवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 10
[88] 26 मई 2011, वीरवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या–9
[89] 27 मई 2011, शुक्रवार, दैनिक भास्कर, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 3
[90] 13 जून 2011, सोमवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 2
[91] 16 जून 2011, वीरवार, हरिभूमि, रोहतक, पृष्ठ संख्या – 5
[92] 12 अगस्त 2011, शुक्रवार, हरिभूमि, रोहतक, पृष्ठ संख्या – 5

63. **अफगान गवर्नर के घर पर आत्मघाती हमला (14 अगस्त 2011, रविवार)** – तालिबान के 6 सदस्यीय आत्मघाती दस्ते ने परवान प्रांत के गवर्नर के घर पर जबर्दस्त हमला किया। इसमें गवर्नर तो बच गये लेकिन 22 लोगों की मौत हो गई और 40 घायल हो गये। तालिबान के प्रवक्ता जैबुल्ला मुजाहिद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।[93]

64. **पाकिस्तान में आत्मघाती हमला (19 अगस्त 2011, शुक्रवार)** – आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रान्त के कबाईली इलाके में नमाजियों को आत्मघाती विस्फोट का शिकार बनाया गया। मस्जिद में किये गये इस विस्फोट में 53 लोगों की मौत हो गई और 123 लोग घायल हो गये। आतंकियों ने इस विस्फोट को एक किशोर के जरिये अंजाम दिलाया। सामान्य तौर पर ऐसे विस्फोटों के लिये पाक तालिबान को जिम्मेदार ठहराया जाता है।[94]

65. **काबुल में तालिबानी हमला (13 सितम्बर 2011, मंगलवार)** – अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के दूतावास इलाके में तालिबान के आत्मघाती हमलावरों ने एक निर्माणाधीन इमारत पर कब्जा कर लिया। वहाँ से कई दूतावासों और नाटो की गठबंधन सेनाओं के मुख्यालय पर रॉकेट दागे गये। काबुल के पश्चिमी इलाके एवं एयरपोर्ट के पास भी इन्होंने हमले किये। इसमें 1 पुलिसकर्मी की मौत हो गई तथा 6 घायल हो गये।[95]

66. **बगदाद में आत्मघाती हमला (28 नवम्बर 2011, सोमवार)** – बगदाद के उत्तर में एक जेल के बाहर एक आत्मघाती बम हमलावर ने विस्फोट से भरी अपनी कार को उड़ा दिया। जिससे 11 लोगों की मौत हो गई जबकि कम से कम 15 अन्य घायल हो गये।[96]

67. **अफगानिस्तान आत्मघाती हमलों से दहल उठा (6 दिसम्बर 2011, मंगलवार)** – अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा, युद्ध से जर्जर अफगानिस्तान आत्मघाती बम धमाकों से दहल उठा। आतंकियों ने राजधानी काबुल और मजार–ए–शरीफ में स्थित शिया समुदाय की दरगाहों पर हमले किये। इन हमलों में 59 लोग मारे गये 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हताहतों में बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की है जो आशूरा (मुहर्रम की दसवीं तारीख) का जुलूस देखने आये थे।[97]

68. **इराक में आत्मघाती हमला (5 जनवरी 2012, वीरवार)** – इराक की राजधानी बगदाद और नसीरिया में हुए आत्मघाती बम धमाकों में 67 लोगों की मौत हो

---

[93] 15 अगस्त 2011, सोमवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 15
[94] 20 अगस्त 2011, शनिवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 10
[95] 14 सितम्बर 2011, बुधवार, दैनिक भास्कर, पानीपत–रोहतक, पृष्ठ संख्या – 12
[96] 29 नवम्बर 2011, मंगलवार, हरिभूमि, रोहतक, पृष्ठ संख्या – 5
[97] 7 दिसम्बर 2011, बुधवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 2

गई व करीब 150 लोग जख्मी हुए। धमाके शिया समुदाय को निशाना बनाकर किया गया था।[98]

69. **सीरिया में आत्मघाती हमला (6 जनवरी 2012, शुक्रवार)** – सीरिया में हिंसा का दौर जारी है। राजधानी दमिश्क आत्मघाती हमले से दहल गया। इसमें 25 लोग मारे गये और 46 घायल हो गये।[99]

70. **पाकिस्तान में आत्मघाती हमला (17 फरवरी 2012, शुक्रवार)** – पश्चिमोत्तर पाकिस्तान के खुर्रम कबाईली इलाके में शिया बहुल इलाके की एक मस्जिद के बाहर आत्मघाती हमला हुआ। पराचिनार के कुर्मी बाजार में हुए इस हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हुए। शुक्रवार की नमाज के बाद बाजार में स्थित मस्जिद के बाहर काफी चहल–पहल थी। मोटरसाइकिल सवार आत्मघाती हमलावर ने खुद में विस्फोट कर दिया।[100]

71. **पूर्वी अफगानिस्तान में आत्मघाती हमला (27 फरवरी 2012, सोमवार)** – पूर्वी अफगानिस्तान में जलालाबाद हवाई अड्डे के गेट पर एक आत्मघाती कार हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। हमले में 9 लोगों की मौत हो गई व 7 घायल हो गये। आतंकियों का कहना है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के एक शिविर में पवित्र कुरान की प्रति जलाये जाने के प्रतिशोध में यह हमला किया गया।[101]

72. **सीरिया के सैन्य मुख्यालय पर आत्मघाती हमला (10 मई 2012, वीरवार)** – सीरिया की राजधानी दमिश्क में दो आत्मघाती विस्फोटों में 55 लोग मारे गये और 372 लोग घायल हो गये।[102]

73. **इराक में आत्मघाती विस्फोट (16 जून 2012, शनिवार)** – इराक की राजधानी बगदाद में शिया तीर्थस्थल को निशाना बनाकर किये गये दो अलग–अलग आत्मघाती कार बम विस्फोटों में कम से कम 32 तीर्थयात्री मारे गये जबकि 68 लोग घायल हो गये।[103]

74. **अफगानिस्तान में आत्मघाती हमला (20 जून 2012, बुधवार)** – अफगानिस्तान के पूर्वी प्रान्त खोस्त में हुए आत्मघाती हमले में 3 नाटो सैनिक समेत 20 लोगों की मौत हो गई और 30 घायल हो गये। हमलावर विस्फोटकों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया और नाटो सेना के काफिले को निशाना बनाया।[104]

---

[98] 6 जनवरी 2012, शुक्रवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 9
[99] 7 जनवरी 2012, शनिवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 12
[100] 18 फरवरी 2012, शनिवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 2
[101] 28 फरवरी 2012, मंगलवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 2
[102] 11 मई 2012, शुक्रवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 4
[103] 17 जून 2012, रविवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 14
[104] 21 जून 2012, वीरवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 2

75. **यमन में आत्मघाती हमला (11 जुलाई 2012, बुधवार)** – एक आत्मघाती हमलावर ने यमन की राजधानी में पुलिस अकादमी के बाहर खुद को उड़ा दिया जिससे कम से कम 22 लोग मारे गये व कई जख्मी हुए। इनमें युवा पुलिस कैडेटों की संख्या अधिक थी। जाँचकर्त्ताओं का कहना है कि हमले में अलकायदा का हाथ होने के सुबूत मिले हैं।[105]

76. **यमन के दक्षिणी शहर जार में आत्मघाती हमला (5 अगस्त 2012, रविवार)** – यमन के दक्षिणी शहर जार में आत्मघाती हमले में 42 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गये। यमन की सेना ने इस शहर को अलकायदा आतंकियों के कब्जे से छुड़ाया था। घटना को देखते हुए लगता है कि यह अलकायदा का काम है। यमन के दक्षिणी क्षेत्रों पर अलकायदा ने अच्छी–खासी पकड़ बना रखी है। वह इन इलाकों में अलगाववाद की मुहिम चला रहे हैं।[106]

77. **अफगानिस्तान में आत्मघाती हमला (4 सितम्बर 2012, मंगलवार)** – अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में एक शव यात्रा के दौरान हुए आत्मघाती हमले में 25 लोगों की मौत हो गई और 50 घायल हो गये।[107]

78. **आत्मघाती विस्फोटों से दहला इराक (9 सितम्बर 2012, रविवार)** – इराक में एक के बाद एक कई धमाकों और हमलों में 56 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 250 लोग घायल हुए। देश के 10 शहरों में 20 हमले हुए। एक आत्मघाती कार बम धमाका नंसीसी महावाणिज्य दूतावास के बाहर हुआ।[108]

79. **इराक में आत्मघाती हमला (17 सितम्बर 2012, सोमवार)** – इराक की राजधानी बगदाद के अति सुरक्षित इलाके ग्रीन जोन में हुए एक आत्मघाती कार बम विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई व अन्य 26 लोग गंभीर रूप से घायल हो गये।[109]

80. **काबुल में महिला आत्मघाती हमला (18 सितम्बर 2012, मंगलवार)** – एक महिला आत्मघाती हमलावर ने यहट्टा विस्फोटकों से भरी कार को एक मिनी बस से टकरा दिया जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। आतंकी संगठन हिज्ब–आइ–इस्लामी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि इस्लाम का मजाक उड़ाने वाली फिल्म का बदला लेने के लिये इस घटना को अंजाम दिया गया। संगठन के प्रवक्ता हारून जरघून के मुताबिक एक 22 वर्षीय महिला फातिमा ने इस घटना को अंजाम दिया। अफगानिस्तान में कार चलाकर महिलाओं द्वारा आत्मघाती हमले की घटना बहुत कम ही होती है।

---

[105] 12 जुलाई 2012, वीरवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 14
[106] 6 अगस्त 2012, सोमवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 2
[107] 5 सितम्बर 2012, बुधवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 7
[108] 10 सितम्बर 2012, सोमवार, दैनिक भास्कर, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 10
[109] 18 सितम्बर 2012, मंगलवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 11

प्रवक्ता के मुताबिक महिला अपनी इच्छा से आत्मघाती हमला करने को तैयार हुई थी।[110]

81. **पाकिस्तान में आत्मघाती हमला (13 अक्टूबर 2012, शनिवार)** – पाक के अशांत दर्रा आदम खेल क्षेत्र में तालिबान विरोधी मिलिशिया के कार्यालय को आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे वाहन से टकराकर निशाना बनाया जिसमें 16 व्यक्ति मारे गये जबकि 40 से अधिक अन्य घायल हो गये।[111]

82. **अफगानिस्तान में मस्जिद पर आत्मघाती हमला (26 अक्टूबर 2012, शुक्रवार)** – ईद–उल–जुहा की नमाज के दौरान आज अफगानिस्तान में एक मस्जिद पर आत्मघाती हमले में 40 लोगों की मौत हो गई तथा 70 अन्य घायल हो गये। उप प्रान्तीय गवर्नर अब्दुल सत्तार बारेज ने बताया कि हमलावर पुलिस की वर्दी पहने हुए था और उसने फरयाब प्रान्त की राजधानी स्थित ईदगाह में भीड़ के बीच विस्फोट कर दिया।[112]

83. **पाक में शियाओं के जुलूस पर आत्मघाती हमला (22 नवम्बर 2012, वीरवार)** – पाकिस्तान में तालिबान आतंकियों ने शियाओं पर हमले तेज कर दिये हैं। इसी क्रम में सर्वाधिक सुरक्षित माने जाने वाले रावलपिंडी शहर में आत्मघाती तालिबान हमलावर ने गुरुवार को शियाओं के मुहर्रम जुलूस को निशाना बनाते हुए भीषण विस्फोट किया जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई और 68 गंभीर रूप से घायल हो गये।[113]

84. **सीरिया में आत्मघाती कार बम विस्फोट (28 नवम्बर 2012, बुधवार)** – सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास हुए दो आत्मघाती कार बम विस्फोटों में 38 लोगों की मौत हो गई व अन्य कई घायल हो गये।[114]

85. **पाक पुलिस थाने पर आत्मघाती हमला (10 दिसम्बर 2012, सोमवार) –** उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान के एक पुलिस थाने पर तालिबान के 4 आत्मघाती हमलावरों के हमले में कुछ पुलिसकर्मियों समेत 8 लोग मारे गये व कई अन्य घायल हुए। इस वारदात को तालिबान के प्रमुख बैतुल्ला मेहसूद की हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से अंजाम दिया गया।[115]

86. **सोमालियाई प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर आत्मघाती हमला (29 जनवरी 2013, मंगलवार)** – सोमालियाई प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर एक आत्मघाती हमलावर ने सुरक्षा अधिकारियों के बीच खुद को उड़ा लिया। सेना के

---

[110] 19 सितम्बर 2012, बुधवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 7
[111] 14 अक्टूबर 2012, रविवार, पंजाब केसरी, हिसार, पृष्ठ संख्या – 1
[112] 27 अक्टूबर 2012, शनिवार, पंजाब केसरी, हिसार, पृष्ठ संख्या – 1
[113] 23 नवम्बर 2012, शुक्रवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 9
[114] 29 नवम्बर 2012, वीरवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 7
[115] 11 दिसम्बर 2012, मंगलवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 12

अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई तथा कई अन्य लोग घायल भी हुए।[116]

87. **पाकिस्तानी मस्जिद के बाहर आत्मघाती हमला (1 फरवरी 2013, शुक्रवार)** – पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शियाओं की एक मस्जिद के बाहर हुए आत्मघाती विस्फोट में 22 लोगों की मृत्यु हो गई तथा करीब 40 लोग घायल हो गये।[117]

88. **इराक में पुलिस मुख्यालय पर आत्मघाती हमला (3 फरवरी 2013, रविवार)** – इराक के किर्कुक में पुलिस मुख्यालय पर आत्मघाती हमले में 33 लोगों की मौत हो गई जबकि 90 से अधिक घायल हो गये।[118]

89. **पाकिस्तान में सरकारी परिसर पर आत्मघाती हमला (18 फरवरी 2013, सोमवार)** – पश्चिमोत्तर पाकिस्तान के अशांत पेशावर शहर में एक सरकारी परिसर पर आत्मघाती हमलावरों ने हमला कर 4 सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी तथा अन्य 7 लोग घायल हो गये।[119]

90. **हेगल की यात्रा के दौरान धमाका (9 मार्च 2013, शनिवार)** – अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल के राजधानी काबुल की यात्रा के दौरान हुए आत्मघाती हमले में 9 लोगों की मौत हो गई व कई घायल हुए। साइकिल पर सवार आत्मघाती हमलावर ने मौके पर खुद को विस्फोटक से उड़ा लिया। यह हमला कड़ी सुरक्षा वाले एक मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर हुआ। हमले के तुरन्त बाद तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हमले का मकसद काबुल पहुँचे हेगल को संदेश देना था।[120]

91. **कश्मीर में आत्मघाती हमला (13 मार्च 2013, बुधवार)** – घटते कैडर और सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव से हताश आतंकियों ने श्रीनगर के बाहरी इलाके में बसे बेमिना के पुलिस पब्लिक स्कूल मैदान में क्रिकेट खेलने के बहाने दाखिल होकर हमला किया। क्रिकेट किट में छिपाकर लाये हथियारों से किये हमले में सी.आर.पी.एफ. (केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल) के 5 जवान मारे गये जबकि 15 जवान व 3 स्थानीय नागरिक घायल हुए। घटना की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली लेकिन शक लश्कर–ए–तैयबा पर किया गया था।[121]

92. **पाकिस्तान में 2 आत्मघाती हमले (20 मार्च 2013, बुधवार)** – पाक में आतंकी संगठनों के बीच भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। प्रतिबंधित तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों ने सरकार समर्थक अंसार–उल–इस्लाम के मुख्यालय के कार्यालय पर कब्जा कर लिया जिसके बाद 2 आत्मघाती हमले हुए। इन हमलों

---

[116] 30 जनवरी 2013, बुधवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 5
[117] 2 फरवरी 2013, शनिवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 12
[118] 4 फरवरी 2013, सोमवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 10
[119] 19 फरवरी 2013, मंगलवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 11
[120] 10 मार्च 2013, रविवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 16
[121] 14 मार्च 2013, वीरवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 1

में 46 तालिबानी आतंकी मारे गये और दर्जनों अन्य घायल हो गये। मरने वालों में अबू इस्लाम नामक एक उज्बेक कमाण्डर भी शामिल है।[122]

93. **पाक में चुनाव प्रचार के दौरान धमाके (7 मई 2013, मंगलवार)** – पाकिस्तान के उत्तर–पश्चिमी भाग में चुनाव प्रचार के दौरान राजनेताओं को निशाना बनाकर किये गये दो आत्मघाती हमलों में 18 लोगों की मौत हो गई और 55 घायल हो गये।[123]

94. **काबुल में तालिबानी आत्मघाती हमला (24 मई 2013, शुक्रवार)** – तालिबान आतंकवादियों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जमकर कहर ढ़ाया। दहशतगर्दों ने राजधानी के अति व्यस्त समझे जाने वाले बुर्ज–ए–शाहरारा इलाके में भारतीय दूतावास की खाली पड़ी फरानी इमारत के निकट एक के बाद एक चार जोरदार धमाके हुए। आत्मघाती हमलावरों व बन्दूकधारियों के निशाने पर अफगानिस्तान की पब्लिक प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स (एपीपीपीएफ) व खुफिया विभाग का मुख्यालय और संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय खासतौर पर था। अचानक हुई इस गोलीबारी और बमबारी में कई लोग मारे गये व 2 अन्य जवान घायल हुए।[124]

95. **अफगानिस्तान में आत्मघाती हमला (3 जून 2013, सोमवार)** – अफगानिस्तान में दो अलग–अलग आत्मघाती हमले की घटनाओं में 10 स्कूली बच्चों समेत 20 लोग मारे गये। इनमें नाटो सेना के दो जवान भी शामिल हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे तालिबान का हाथ हो सकता है।[125]

96. **इराक में आत्मघाती हमला (8 जून 2013, शनिवार)** – इराक में आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी कार से ईरानी श्र(ालुओं को ले जा रही बस और पुलिस चौकी से टक्कर मार दी। इससे 17 लोगों की मौत हो गई और 44 घायल हो गये।[126]

97. **इराक में आत्मघाती बम धमाका (10 जून 2013, सोमवार)** – मध्य इराक में फल और सब्जियों के एक थोक बाजार में हुए एक आत्मघाती हमले और दो कार बम विस्फोट में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों लोग घायल हो गये। इस तरह के सिलसिलेवार कार धमाके इराक स्थित अलकायदा समूह करता है।[127]

---

[122] 21 मार्च 2013, गुरुवार, पंजाब केसरी, हिसार, पृष्ठ संख्या – 8
[123] 8 मई 2013, बुधवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 8
[124] 25 मई 2013, शनिवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 7
[125] 4 जून 2013, मंगलवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 14
[126] 9 जून 2013, रविवार, दैनिक भास्कर, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 18
[127] 11 जून 2013, मंगलवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 7

98. **इराक सैन्य काफिले पर आत्मघाती हमला (22 जुलाई 2013, सोमवार)** – इराक के पूर्वी शहर मोसुल में सेना के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में 22 सैनिकों और 3 नागरिकों की मौत हो गई व कई अन्य घायल हो गये।[128]

99. **अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के पास आत्मघाती हमला (3 अगस्त 2013, शनिवारद्ध–** अफगानिस्तान के जलालाबाद में भारत के वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाकर आत्मघाती हमला किया गया इसमें 12 लोगों की मौत हो गई व 24 घायल हो गये।[129]

100. **पाकिस्तान में आत्मघाती हमला (8 अगस्त 2013, वीरवार)** – पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक पुलिस अधिकारी के जनाजे के लिये जमा हुए लोगों पर आत्मघाती हमले में 38 लोग मारे गये। इनमें क्वेटा के डीआईजी ऑपरेशन्स पैफयाज संबल सहित 5 वरिष्ठ अफसर शामिल हैं। हमले में 62 लोग घायल हुए।[130]

101. **जनाजे पर आतंकी हमला (14 सितम्बर 2013, शनिवार)** – इराक के निनेवेह प्रान्त में एक अन्तिम संस्कार के दौरान आत्मघाती हमले में 26 लोग मारे गये। इसमें 46 लोग घायल हुए।[131]

102. **यमन में आत्मघाती हमला (20 सितम्बर 2013, शुक्रवार) –** दक्षिणी यमन में एक साथ किये गये 3 हमलों में कम से कम 56 पुलिस कर्मियों और सैनिकों की मौत हो गई व अन्य कई घायल हुए।[132]

103. **पेशावर की चर्च में आत्मघाती हमला (22 सितम्बर 2013, रविवार) –** पाकिस्तान के पेशावर शहर में एक चर्च में हुए दोहरे आत्मघाती हमले में 78 लोगों की मौत हो गई। इनमें 7 बच्चे, 30 महिलायें शामिल है व 130 से ज्यादा अन्य लोग घायल हो गये। तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान के जनदुल्लाह ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली है।[133]

104. **पेशावर में कार आत्मघाती बम ब्लास्ट (29 सितम्बर 2013, रविवार) –** पाकिस्तान के अशांत उत्तर–पश्चिम क्षेत्र में एक कार आत्मघाती बम विस्फोट में 37 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक ही परिवार के 9 सदस्य शामिल हैं व करीब 80 अन्य घायल हुए। खैबर पख्तूनख्वा प्रान्त की राजधानी पेशावर में खान रजिक थाने के समीप ऐतिहासिक किस्सा खवानी बाजार में यह धमाका हुआ। विस्फोट में 225 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया।[134]

---

[128] 23 जुलाई 2013, मंगलवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 12
[129] 4 अगस्त 2013, रविवार, दैनिक भास्कर, पानीपत–रोहतक, पृष्ठ संख्या – 1
[130] 9 अगस्त 2013, शुक्रवार, दैनिक भास्कर, पानीपत–रोहतक, पृष्ठ संख्या – 12
[131] 15 सितम्बर 2013, रविवार, दैनिक भास्कर, रोहतक, पृष्ठ संख्या – 14
[132] 21 सितम्बर 2013, शनिवार, दैनिक भास्कर, रोहतक, पृष्ठ संख्या – 12
[133] 23 सितम्बर 2013, सोमवार, दैनिक भास्कर, रोहतक, पृष्ठ संख्या – 1
[134] 30 सितम्बर 2013, सोमवार, दैनिक भास्कर, रोहतक, पृष्ठ संख्या – 10

105. **रूस में महिला आत्मघाती हमला (29 दिसम्बर 2013, रविवार)** – रूस के वोल्गोग्राद शहर में फिर आतंकी हमला हुआ है। इस बार आतंकियों ने भीड़–भाड़ वाले वोल्गोग्राद रेलवे स्टेशन को अपना निशाना बनाया विस्फोटकों से लैस एक महिला आत्मघाती हमलावर ने धमाके में खुद को उड़ा कर इस हृदयविदारक घटना को अंजाम दिया। इस वारदात में 18 लोग मारे गये और 50 से अधिक घायल हुए।[135]

106. **सोमालिया में आत्मघाती हमला (2 जनवरी 2014, वीरवार)** – सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक हवाई अड्डे के निकट होटल के बाहर हुए आत्मघाती बम हमलों में 11 लोग मारे गये और 17 अन्य घायल हो गये। पुलिस के अनुसार इन धमाकों में कम से कम 2 आत्मघाती हमले थे। आतंकवादियों ने हमले के लिये कार का इस्तेमाल किया था।[136]

107. **पाक में पुलिस बस पर आत्मघाती हमला (13 फरवरी 2014, वीरवार) –** पाकिस्तान में आतंकियों ने पुलिस की बस को निशाना बना कर आत्मघाती विस्फोट किया। इसमें 11 लोग मारे गये तथा 30 घायल हो गये।[137]

1.2 आतंकवाद की परिभाषा
;क्मपिदपजपवद व ज्मततवतपेउद्ध

आतंकवाद के संदर्भ में आम सोच है कि आतंकवाद हिंसा अथवा हिंसा की धमकी का उपयोग है तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिये संघर्ष या लड़ाई की एक विधि या रणनीति है व अपने शिकार में भय पैदा करना इसका मुख्य उंर्श्यि है। यह क्रूर है और मानवीय प्रतिमानों का पालन नहीं करता, इसकी रणनीति में प्रचार आवश्यक है। **आतंकवाद दो शब्दों से बना है – आतंक + वाद। आतंक का अर्थ है भय या डर तथा वाद का अर्थ है सिद्धान्त।** यह भय व हिंसा पर आधारित है। विध्वंसक विचारधाराओं के अघोषित युद्ध को आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। आतंकवाद के युद्ध में मानवीय मूल्यों, मान्यताओं, सिद्धान्तों और आदर्शों के लिये कोई स्थान नहीं होता है इसीलिये आतंकवादी निर्दोष बच्चों, बूढ़ों, औरतों और जवानों को मौत के घाट उतारते हैं। सुरक्षा के अभाव में अवाम की मौत, सरकारी और गैर–सरकारी सम्पत्तियों का विध्वंस और दहशतगर्दी फैलाना ही आतंकवादियों का प्रमुख उंर्श्यि होता है ''आतंकवादी हरकतों के पीछे कभी इंतकाम (बदले की भावनाद्ध, कभी जिहाद (धर्मरक्षा की भावनाद्ध, कभी आजादी (सत्ता–परिवर्तन की भावनाद्ध, कभी न्याय और कभी–कभी अमर्ष (बिना वजह) की भावना होती है। सम्पूर्ण विश्व में घट रही आतंकी घटनायें उक्त मानसिकता की

---

[135] 30 दिसम्बर 2013, सोमवार, दैनिक जागरण, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 5
[136] 3 जनवरी 2014, शुक्रवार, पंजाब केसरी, हिसार, पृष्ठ संख्या – 2
[137] 14 फरवरी 2014, शुक्रवार, दैनिक भास्कर, रोहतक, पृष्ठ संख्या – 15

तरफ ही इशारा कर रही हैं। अमेरिका और रूस तथा उनके सहयोगी राष्ट्र, क्या पूरा विश्व इस्लामी आतंकवादी मानसिकता का शिकार है, चाहे वह इस्लामी राष्ट्र ही क्यों न हो। अमेरिका, रूस, प्रफांस, इंग्लैण्ड, चीन ही नहीं, तमाम अन्य देशों को कभी आतंकवाद के समर्थन, कभी विरोध में बार–बार देखा गया है। आतंकी युद्धों के समर्थन और विरोध में तमाम देशों को खुल्लम–खुल्ला हिस्सा लेते हुए भी देखा गया है। अफगानिस्तान, इराक, कश्मीर, चेचन्या, झिनझियांग, तिब्बत, जार्जिया आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। अफगानिस्तान और इराक के बाद अब पाकिस्तान अमेरिका के निशाने पर आ चुका है।''[138]

जिस समय व्यक्ति अपनी आत्मा की सचेतन आवाज को स्वार्थ के वशीभूत होकर कुचल देता है उसी क्षण उसका पशुत्व प्रबल हो उठता है और सभी समस्याओं के प्रति उसके विचार एवं दृष्टिकोण दूषित हो उठते हैं, तभी आतंकवाद की प्रक्रिया उपजती है।

आतंकवाद के लम्बे इतिहास के बावजूद दुनिया अभी भी एक के लिये **'आतंकवादी'** दूसरे के लिये **'स्वतंत्रता सेनानी'** की नैतिक और राजनीतिक दुविधा का सामना कर रही है। अमेरिका व इजरायलियों के लिये जो आतंकवादी हैं, अरबों व फिलीस्तीनियों के लिये वे स्वतंत्रता सेनानी हैं। भारत के लिये जो कश्मीरी खतरनाक आतंकवादी हैं, पाकिस्तान उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बताता है। आतंकवादी या स्वतंत्रता सेनानी की यह दुविधा निकट भविष्य में समाप्त नहीं होने जा रही है। यहाँ तक कि ''संयुक्त राष्ट्र संघ भी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर, अध्याय 2, धारा 1;2) को मान्यता देता है।''[139]

आतंकवाद क्या है? किसे आतंकवादी माना जाये और किसे अपराधी? आतंक और आतंकवाद में क्या फर्क है? आतंकवाद के कितने रूप हैं? क्या इसका कोई सकारात्मक पक्ष भी है? इन सारे सवालों पर बहुत समय से बहस चल रही है और आगे भी चलेगी लेकिन एक बात तो तय है कि किसी समूह अथवा व्यक्ति का राजनीतिक एजेंडा जो भी हो पर उसे निर्दोष व्यक्ति को मारने का अधिकार नहीं है। वास्तव में आतंकवाद एक हिंसक नीति है जिसमें हिंसा के माध्यम से समाज में आतंक फैलाया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनय की शब्दावली में आतंकवाद सम्भवतः वह नवीन शब्द है जिसने विश्व धरातल पर सभी का ध्यान आकृष्ट किया है। आतंकवाद की सर्वमान्य और सर्वसम्मति वाली परिभाषा आज तक नहीं ढूट्टढ़ी जा सकी है क्योंकि विश्लेषक इस विषय में अपनी अवधारणा में अपने मूल्यों एवं हितों से प्रभावित होते हैं।

---

[138] डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र, ''आतंकवाद व आपदा प्रबंधन'', 2010, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, पृष्ठ संख्या – 2, फोन 23247003

[139] अरुण त्रिपाठी, अरुण पाण्डे, आनंद प्रधान, दिलीप चौबे, बृजबिहारी चौबे, अखिलेश सुमन, ''मुस्लिम आतंकवाद बनाम् अमेरिका'', 2002, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ संख्या – 20

आतंकवाद की एक सर्वमान्य परिभाषा रचने में एक बड़ी कठिनाई इस कारण भी होती रही है कि पिछले 50 वर्षों में आतंकवाद का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति व द्विपक्षीय राजनय में काफी दुरुपयोग हुआ है। सच तो यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 40 वर्षों तक चले शीतयुद्ध के दौरान दोनों ने विशेषकर अमेरिका ने ज्यादा उग्र तरीके से अघोषित व परोक्ष युद्ध के हथियार के रूप में आतंकवाद का प्रयोग किया। दोनों ने एक–दूसरे के मामलों में एक–दूसरे के समर्थक देशों के खिलाफ आतंकवादी संगठनों को खड़ा करने में हथियार से लेकर हर तरह की मदद करने में कोई संकोच नहीं किया। ''अमेरिकी लेखक **क्लेयर स्टर्लिंग** ने इसी आधार पर लिख दिया कि आतंकवाद सोवियत संघ प्रेरित एक हथियार है जिसका लक्ष्य 'पश्चिमी लोकतांत्रिक समाजों' को अस्थिर करना है। उन्होंने आतंकवाद को सर्वसत्तावादी या साम्यवादी व्यवस्था से जोड़कर देखा और आतंकवादियों को लेनिन के बच्चे तक की संज्ञा दे डाली।''[140] विश्लेषकों ने आतंकवादियों को नये मीडिया युग का शिशु कहा। **''ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री मारेग्रेट थैचर के अनुसार यह शिशु पब्लिसिटी की ऑक्सीजन से जीवन पाता है।''[141]**

आतंकवाद पर प्रभावकारी नियंत्रण लगाने के लिये **संयुक्त राष्ट्र संघ (न्ण्छण्व्) ने सातवें दशक में इसकी समुचित व सर्वमान्य परिभाषा हेतु प्रयास प्रारम्भ किये जिसके अन्तर्गत पारस्परिक विचार–विमर्श को प्रमुखता दी गई।** जहाँ एक ओर संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसी राज्य अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के हितों को हानि पहुँचाने अथवा उससे रियायतों की प्राप्ति के लक्ष्य से की जाने वाली सैन्य कार्यवाहियों को आतंकवाद की परिधि में लेने की बात कही, ''वही गुट निरपेक्ष देशों ने उक्त परिभाषा के अन्तर्गत उपनिवेशवादी व रंगभेदी शासन द्वारा मुक्त सेनानियों के षविरुद्ध की जाने वाली दमनात्मक कार्यवाहियों को भी आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित करने की अपील की।''[142] फलतः राष्ट्रों के मध्य मतैक्य के अभाव में **संयुक्त राष्ट्र संघ आतंकवाद को परिभाषित करने में असफल रहा** तथापि समय–समय पर विभिन्न विचारक, विश्लेषक एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, आतंकवाद को परिभाषित करने हेतु प्रयत्नरत है। किन्तु अभी तक कोई एक सर्वमान्य एवं संतोषपूर्ण परिभाषा वर्णित नहीं की जा सकी है। **फिर भी कुछ परिभाषायें निम्नलिखित हैं –**

---

[140] नोम चॉम्सकी, पिरेट्स एण्ड एम्परर्सः इन्टरनेशनल टेरॉरिज्म इन द रियलवर्ल्ड, 1986, क्लेयरमांट एण्ड पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या–2

[141] अमर उजाला, 10 अगस्त 2002, कानफर संस्करण, साप्ताहिकी परिशिष्ट

[142] डॉ. बाबूराम पाण्डेय एवं रामसूरत पाण्डेय, ''राष्ट्रीय सुरक्षा के मूलाधार'', 2004, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, पृष्ठ संख्या – 129

1. **कन्वेंशन ऑन प्रिवेन्शन एंड पनिशमेंट 1973 के अनुसार,** ''आतंकवाद का अभिप्राय उन आपराधिक कृत्यों से है जो किसी राज्य के **'विरुद्ध'** उन्मुख हो और जिसका उर्ध्यि कुछ विशेष कर्म या जनसाधारण के मन में भय की दहशत पैदा करना हो।''[143]
2. **संयुक्त राज्य के राज्य विभाग के अनुसार,** ''आतंकवाद जानबूझ कर एक दहशतपूर्ण वातावरण बनाने को कहा जा सकता है जो या तो शक्ति के बल पर या बल प्रयोग की धमकी द्वारा किया जाता है, जिसके माध्यम से किसी वर्ग अथवा व्यक्ति को आतंकित कर निश्चित राजनैतिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।''[144]
3. **आर.सी. मिश्रा के अनुसार,** ''Terrorism is a form of violence in principle immoral and inhuman, often used by the retardation powers, which mask and excuse their actions with the fight for progressive and eligible interests of their supporters.''[145] **अर्थात्** आतंकवाद एक प्रकार का हिंसात्मक कृत्य है, जो सैद्धान्तिक रूप से अनैतिक तथा अमानवीय है। यह अक्सर पिछड़ी हुई शक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है जो अपने आतंकवादी कृत्यों को अपने समर्थकों के हितों के परदों से ढ़कते हैं।
4. **जे.एम. मार्टिन तथा ऐने टोमानो ने अपनी फस्तक, ''इन्टरनेशनल क्राइम'' में इसे निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है** – ''Terrorism is an international crime that functions well with drugs, arms trafficking and espionage. It functions like a modern business corporation.''[146] **अर्थात्** आतंकवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय अपराध है जो मादक द्रव्यों तथा आग्नेयास्त्रों की तस्करी तथा गुप्तचरी द्वारा कुशलतापूर्वक संचालित होता है। यह काफी कुछ आधुनिक व्यापार कॉर्पोरेशन के रूप में कार्य करता है।
5. **एस.के. घोष ने इसे अपनी फस्तक, ''टेररिज्म वर्ल्ड अण्डरसीज'' में निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है** – ''It is a systematic use of murder and destruction to terrorise communities or governments into conceding to the terrorists political aims. It is a method of combat and strategy to achieve certain targets. It aims to induce a state of fear in the intended victim, that is ruthless and does not conform with the humanitarian rules. The victim could be a class, an

[143] डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र, ''आतंकवाद व आपदा प्रबंधन'', 2010, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, फोन 23247003, पृष्ठ संख्या–3

[144] आर.सी. मिश्रा, ''टेररिज्म–इम्प्लीकेशनंस ऑफ टैक्टिक्स एण्ड टेक्नोलॉजी'', ऑथर्स प्रेस, नई दिल्ली, 2004, पृष्ठ संख्या–22

[145] मेजर जनरल (रिटायर्ड) राजेन्द्र नाथ – ''टेररिज्म एण्ड इण्डिया'', काम्बटिंग टेररिज्म (फस्तक), सम्पादक–पी.सी. डोगरा एवं अशोक मलिक, अभिषेक पब्लिकेशन्स, चण्डीगढ़, पृष्ठ संख्या–56

[146] वही, पृ.सं. – 56

organisation or a nation.'' [147] **अर्थात्** आतंकवाद हत्याओं तथा विध्वंसकारी गतिविधियों का एक व्यवस्थित प्रयोग है जो समुदायों अथवा सरकारों को भयभीत कर राजनैतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु किया जाता है। यद्यपि कोई भी परिभाषा अपने में परिपूर्ण नहीं मानी जा सकती है फिर भी आतंकवाद के कुछ सामान्य पक्ष हैं जो प्रत्येक दशा में समान रहते हैं। जैसे –

1. यह अच्छाई या बुराई के मध्य कोई विभेद नहीं करता।
2. यह भौतिक क्षति से कहीं अधिक मानसिक आघात पहुँचाता है।
3. यह निरंकुश होता है।
4. यह अनैतिकता का भाव लिये हुए होता है।
5. यह समाज की नैतिक सीमाओं से परे होता है।
6. यह वैचारिक युद्ध में कमजोर पक्ष का आदर्श हथियार होता है।

6. **डेविड कार्लटन एवं कार्लोशेरिफ द्वारा सम्पादित, ''इन्टरनेशनल टेरेरिज्म एण्ड वर्ल्ड सिक्यूरिटी'', के ''इन्टरनेशनल टेरेरिज्म – ए न्यू मोड ऑफ कांफ्रिलक्ट'' नामक आलेख में ब्रिआन एम. जेन्किन्स ने आतंकवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि** ''हिंसा की धमकी, व्यक्तिगत हिंसात्मक कृत्य और लोगों को आतंकित करने के उेंश्यि से हिंसा का विचार आतंकवाद है।''[148]
7. **जार्ज श्वार्जनबर्गर ने अपनी फस्तक ''International Law and Order", page 219 में कहा है कि** ''एक आतंकवादी को उसके तात्कालिक लक्ष्य के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यह लक्ष्य होता है, भय पैदा करने के उेंश्यि से शक्ति का प्रयोग करना और इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना।''[149]
8. **मेजर ओ.एन. दुबे ने आतंकवाद के संदर्भ में लिखा है,** ''आतंकवाद अपने आप में भयंकर विष है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति और उेंश्यि दोनों ही नकारात्मक और विध्वंसक है। आतंकवाद अपने समर्थकों और विरोधियों दोनों को बराबर नुकसान पहुँचाता रहा है और आज भी पहुँचा रहा है। अमेरिका, रूस, इंग्लैण्ड, प्रफांस, चीन सभी इसी दो मुँह आतंकवाद के शिकार हैं। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के समर्थन और आतंकवाद के विरोध दोनों से अमेरिका तिलमिला उठा है।''[150]

---

[147] आर.सी. मिश्रा, ''टेररिज्म–इम्प्लीकेशन्स ऑफ टैक्टिक्स एण्ड टेक्नोलॉजी'', ऑथर्स प्रेस, नई दिल्ली, 2004, पृष्ठ संख्या–22

[148] ठतपंद डण श्रमदापदे दृ प्दजमतदंजपवदंस ज्मततवतपेउ ंदक ूवतसक ेमबनतपजलए च. 13

[149] डॉ. लल्लन जी सिंह, ''राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा'', 2006, प्रकाश बुक डिपो, बड़ा बाजार, बरेली–243003, दूरभाष–2470217, पृष्ठ संख्या–60

[150] डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र, ''आतंकवाद व आपदा प्रबंधन'', 2010, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, फोन 23247003, पृष्ठ संख्या – 3

9. **इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल सांइस के अनुसार,** ''आतंकवाद ऐसा तरीका है जिसके द्वारा एक संगठित समूह अथवा दल अपने प्रकट उद्देश्यों की प्राप्ति मुख्य रूप से हिंसा के योजनाबद्ध उपयोग से करता है।''[151]
10. **चेम्बर के शब्द कोष के अनुसार,** ''आतंकवाद किसी स्थान अथवा समाज में भय उत्पन्न करने का संगठित तरीका है।''[152]
11. **ऑक्सफोर्ड के अनुसार,** ''आतंकवाद राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु हिंसा अथवा भय का प्रयोग करने को कहा गया है।''[153]
12. **पियरे मार्टिन के शब्दों में,** ''आतंकवाद का अर्थ शांति एवं युद्ध के समय अलग होता है।''[154]
13. **जै. मैलिन ने माओ, चेग्वेरा, फिदेल कास्त्राो और फिलीस्तिीनी कार्यवाहियों का व्यापक अध्ययन व विश्लेषण करने के उपरान्त आतंकवाद को परिभाषित करते हुए कहा कि** ''आतंकवाद एक तरह का सशस्त्र संघर्ष है। अतः इसे सैनिक कार्यवाही माना जाना चाहिये। जब कूटनीति असफल होती है तब सैनिक कार्यवाही शुरू होती है और जब सैनिक असफल होते है तो उनका स्थान आतंकवादी ले लेते हैं।''[155]
14. **क्तण् झ्ीपजपर च्तंइीं के अनुसार,** ''आतंकवाद एक विश्वस्तरीय तत्त्व है इसे मान्य करना तो आसान है, परन्तु परिभाषित करना अत्यन्त दुरूह है, इसकी उत्पत्ति सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से होती है और यह समाज में हैव (Have) और हैव नाट (Have Not) के मध्य संघर्ष होता है तथा इससे राजनीतिक हित साधित किये जाते हैं।''[156]
15. **जोर्डन जे. पोस्ट के अनुसार,** ''शासन व उसके अवयवों से आमने–सामने के संघर्ष में अक्षम होने के कारण सरकार के साधनों, व्यक्ति, प्रतिष्ठानों व संचार माध्यमों को नष्ट करके आतंक का वातावरण उत्पन्न करने के लक्ष्य से की गई कार्यवाही ही आतंकवाद है।''[157]

---

151 वही, पृ.सं. –2

152 डॉ. धीरेन्द्र द्विवेदी, संजय कुमार, अनुराग जायसवाल, गुलाब चन्द्र ललित, ''अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति'', 2006, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली–110094, पृष्ठ संख्या–183

153 वही, पृ. सं.–183

154 वही, पृ.सं.–183

155 श्रंल डंससपद दृ ज्मततवतपेउ प्दजमतकपेबपचसपदंतल चमतेचमबजपअमए च्ण 95

156 क्तण् झ्ीपजपर च्तंइींए ष्क्मपिदपदह ज्मततवतपेउ पद ैजतंजमहपब ।दंसलेपेए ।चतपस 2000ए च्ण125

157 डॉ. बाबूराम पाण्डेय, सैन्य अध्ययन की पाठ्य फस्तक, 2004, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, पृष्ठ संख्या–114

16. **ले. कर्नल वी.के. आनन्द के अनुसार,** ''आतंकवाद असन्तोष की अभिव्यक्ति है, वह चाहे व्यक्तिगत हो अथवा समूह द्वारा या उसके मुखिया के द्वारा, यह भय एवं हिंसा के साये में अपनी माँगों को पूरा करता है।''[158]

17. **राष्ट्रसंघ 1937 के अनुसार,** ''आतंकवाद वे आपराधिक कार्य है जो राज्य के 'विरुद्ध किये जाते हैं जिनका उद्देश्य या प्रभाव भय की स्थिति को उत्पन्न करना है यह स्थिति कुछ व्यक्तियों की या जनसामान्य की हो सकती है।''[159]

18. **1985 में आतंकवादी गतिविधि निरोधक कानून में आतंकवाद को परिभाषित करते हुए तीन भागों में बाँटा गया है**[160] –
    1. समाज के एक वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त सौहार्द को खत्म करने के लिये की गई हिंसा।
    2. ऐसा कोई भी कार्य जिसमें ज्वलनशील बम तथा अग्निशस्त्रों का प्रयोग किया गया हो।
    3. ऐसी हिंसात्मक कार्यवाही जिसमें एक या उससे अधिक व्यक्ति मारे गये हो अथवा घायल हुए हो, आवश्यक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा सम्पत्ति को हानि पहुँचे।

उपरोक्त परिभाषा विस्तृत आयामों वाली परिभाषा है जिसमें राज्य के 'विरुद्ध' और राज्य द्वारा पोषित आतंकवाद दोनों को शामिल किया गया है।

19. **पेफलिक्स ग्रीस के अनुसार,** ''आतंकवाद का परिदृश्य युवा पीढ़ी में है एवं देखा जा सकता है। जैसे च्स्ब् के युवा में।''[161]

20. **श्री ऐलेक्स सेनिड के अनुसार,** ''आतंकवाद उग्र हिंसा की कार्यवाही है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर भय उत्पन्न करना तथा खास राजनीतिक लक्ष्य पूरा करना।''[162]

21. **संयुक्त राष्ट्र से सम्बन्धित डॉ. प्रेडो आर. डेविड लोवर्च के अनुसार,** ''आतंकवाद एक सुनियोजित हिंसा है जिसका लक्ष्य प्रचार, बल प्रयोग और लूट–खसोट है और जिसका अन्तिम लक्ष्य राजनीतिक अस्थिरता पैदा करके वांछित उद्देश्य को सिद्ध करना है।''[163]

---

[158] ले. कर्नल वी.के. आनन्द, ''आतंकवाद और सुरक्षा'', 1984, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या–19

[159] डॉ. अशोक कुमार सिंह, ''राष्ट्रीय सुरक्षा'', 1997–98, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, पृष्ठ संख्या–617

[160] वही, पृ.सं.–617

[161] डॉ. धीरेन्द्र द्विवेदी, संजय कुमार, अनुराग जायसवाल, गुलाब चन्द्र ललित, ''अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति'', 2006, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली– 110094, पृष्ठ संख्या–184

[162] वही, पृ. सं.–184

[163] वही, पृ. सं.–185

22. **एम.सी. हचिन्सन महोदय ने आतंकवाद की सात अवस्थाओं का उल्लेख किया है**[164]

1. आतंकवादी कारनामों की सुसंगठित पद्धति।
2. बर्बर अथवा स्तम्भित कर देने वाला व्यवहार।
3. भय पैदा करने का उद्देश्य।
4. हिंसा हेतु निश्चित लक्ष्यों का चयन।
5. बिना भेदभाव के लक्ष्यों का चयन।
6. अबौद्धिकता।
7. अनैतिक और अन्यायपूर्ण कर्म।

एम.सी. हचिन्सन के शब्दों में किसी भी घटना के पीछे इन सात अवस्थाओं की तलाश की जा सके तो उस घटना को आतंकवादी घटना कहा जा सकता है।

23. **जे.एन. सक्सेना के शब्दों में,** ''अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद वह हिंसा व भय का कार्य है जिसका क्षेत्राधिकार अन्तर्राष्ट्रीय होता है तथा जिसे करने वाला एक राज्य का है और जिसके 'विरुद्ध किया गया हो वह दूसरे राज्य का या ऐसी घटना की हिंसा हो जो दोनों के ही क्षेत्राधिकार से बाहर की हो।''[165]

24. **ब्रिटिश विचारक पाल विलिंकसन ने आतंकवाद को 4 समूहों में विभाजित किया है**[166]–

1. **युद्ध आतंक** – जनसमूह को विभिन्न प्रकार से आतंकित करना।
2. **क्रांतिकारी आतंक** – क्रांति में विभिन्न कदम क्रांतिकारी द्वारा उठाया जाना।
3. **दमनकारी आतंक** – सरकार द्वारा अपनाये गये आतंकित करने के तरीके।
4. **उपक्रांतिकारी तरीके** – सैद्धान्तिक तरीके जिनका मुख्य उद्देश्य राज्य पर अधिकार करना हो।

दरअसल आतंकवाद की ठीक–ठाक परिभाषा देना इसलिये और भी कठिन हो जाता है क्योंकि इसका स्वरूप देश–काल सापेक्ष होता है। जिस तरह फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन (P.L.O.) को इजरायल आतंकवादी संगठन मानता है, उसे निर्गुट राष्ट्र 'राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन' के रूप में देखता है जो स्वतंत्रता के लिये संघर्ष कर रहा है। परिभाषा बताती है कि आतंक का प्रयोग अत्याचारी शासन के 'विरुद्ध' उचित उद्देश्य से और दूसरी ओर संकीर्ण तथा आपराधिक उद्देश्य से भी किया जा सकता है।

---

[164] वही, पृ. सं.–186
[165] डॉ. ए.के. सिंह, भारत में आतंकवादी कार्यवाहियाट्ट, पृष्ठ संख्या–235
[166] सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, अगस्त 1968, पृष्ठ संख्या–35

25. **प्रो. हैल्डेन ने इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार,** ''यह कमजोर का शक्तिशाली के 'विरुद्ध एक दुर्दांत संघर्ष है, इसे शब्दों की हिंसा न मानकर कार्य की हिंसा के रूप में देखा जाना चाहिये इस अघोषित युद्ध में सैनिकों से अधिक जनसाधारण को जूझना पड़ता है और समाज की तैयारी के बिना सेना और सरकार इस जीते हुए युद्ध को भी हार सकती है।'' [167] इसीलिए आतंकवाद को छापामार युद्ध का पर्याय माना जाता है।

26. **साधारण शब्दों में आतंकवाद की सामान्य धारणा है,** ''आतंकवाद हिंसा या हिंसा की धमकी का उपयोग है तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिये संघर्ष, लड़ाई की एक विधि या रणनीति है। अपने शिकार में भय पैदा करना इसका प्रमुख उर्द्देश्य है। यह क्रूर है और मानवीय प्रतिमानों का पालन नहीं करता। इसकी रणनीति में प्रचार एक जरूरी तत्त्व है।''[168]

27. **मार्था क्रेन्सा ने आतंकवाद की व्याख्या करते हुए कहा है कि** ''आतंकवाद का आशय निश्चित राजनीतिक लक्ष्य को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से प्राप्त करना होता है।''[169]

28. **उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के पश्चात् आतंकवाद को निम्न शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है – "आतंकवाद एक असामाजिक, अनैतिक, असांस्कृतिक, असंवैधानिक कार्यवाही है जिसका लक्ष्य निरपराध (निर्दोष) लोगों की हत्या कर आम जनता में आतंक फैलाकर कानून व्यवस्था को छिन्न–भिन्न कर सरकार को अपदस्थ कर अपने राजनीतिक उर्द्देश्यों की पूर्ति के लिये सरकार को विवश करना है।"**

इस तरह यदि देखा जाये तो ज्ञात होता है कि विभिन्न विश्लेषकों एवं विशेषज्ञों ने समय–समय पर विभिन्न परिस्थितियों में अपने ढ़ंग से आतंकवाद की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है लेकिन कोई भी परिभाषा इसे पूर्णता नहीं प्रदान कर पाई क्योंकि हर विश्लेषक ने अपना दृष्टिकोण तो दृष्टिगत रखा परन्तु आतंकवादी के दृष्टिकोण एवं सोच को समायोजित नहीं किया।

सम्पूर्ण विश्व को आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा ढूट्टढ़ने में तो दिक्कतें आ रही हैं उसका यह मतलब कतई नहीं कि इस दिशा में कोई प्रयास ही नहीं किये जायें। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों, सेमिनारों में यह प्रयास जारी ही रहने चाहिये। 1937 में लीग ऑफ नेशंस ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में एक गम्भीर प्रयास किया था। इसके मुताबिक ''किसी राष्ट्र या व्यक्ति के खिलाफ आतंक व अव्यवस्था फैलाने के लिये किये गये आपराधिक कार्य आतंकवाद के दायरे में आयेंगे।'' चूँकि इससे हर एक राष्ट्र सन्तुष्ट नहीं

---

[167] डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र, ''आतंकवाद व आपदा प्रबंधन'', 2010, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, फोन 23247003, पृष्ठ संख्या–4

[168] वही, पृ.सं.–3–4

[169] डंतजीं ब्तमदेीं दृ जीमवतपमे व ्जमततवतपेउ रू प्द जीम श्रवनतदंस व ्पदजमतदंजपवदंस ं्रिंपतेए टवसण 10ए छवण 4ए क्मबण 1987ए चण 13

हुआ, इसलिए यह प्रस्ताव कभी कानून का रूप नहीं ले पाया। इस प्रस्ताव के 62 वर्ष बाद यानि 1999 में आतंकवाद की अन्तर्राष्ट्रीय परिभाषा के गठन की महती आवश्यकता एक बार फिर महसूस की गई। भारत समेत तमाम देश इस बात पर जोर दे रहे थे। भारत विश्व के उन चंद देशों में से एक है, जो पिछले डेढ़ दशक से आतंकवाद से जूझ रहा है। न सिर्फ जम्मू–कश्मीर में, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी आतंकवाद जारी है। इस क्रम में एक परिभाषा पेश की गई, जिसमें कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ –

1. कहीं पर भी और किसी के द्वारा फैलाये गये हर तरह के आतंकवाद को आपराधिक मामला करार देते हुए उसकी कड़ी निंदा करता है।
2. किसी राष्ट्र में आतंक मचाने के लिये वर्ग विशेष, विशेष व्यक्ति के खिलाफ राजनीतिक उर्देश्य हासिल करने के लिये फैलाई जाने वाली हिंसा को आतंकवाद की श्रेणी में रखता है, भले ही उसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, जातिगत या अन्य किसी भी आधार पर तार्किक ठहराने की कोशिश क्यों न की जाये।

यह प्रस्तावित परिभाषा भी हर एक के गले नहीं उतर सकी। 1988 में संयुक्त राष्ट्र संघ की अपराध शाखा के आतंकवाद विशेषज्ञ ए.पी. श्मिड ने एक सुझाव दिया, जिसे '**विद्वतापूर्ण सर्वमान्य परिभाषा**' कहा जाता है। इसके मुताबिक आतंकवाद एक चिंताजनक विधि है, जिसमें बारंबार हिंसात्मक गतिविधियाँ और व्यक्तिगत अथवा सरकारी तौर पर राजनीतिक या आपराधिक कारणों से व्यक्ति अथवा समूह द्वारा अवांछित कार्यवाही अंजाम दी जाती है और यह किसी हत्याकाण्ड से एकदम विपरीत होती है, जिसमें हिंसा का शिकार ही मुख्य लक्ष्य नहीं होते। आतंकवादी संगठन तथा पीड़ित प्रभावित व्यक्ति के बीच धमकी और हिंसा आधारित संचार प्रक्रिया का इस्तेमाल मुख्य लक्ष्य को प्रभावित करने के लिये ही होता है।

संक्षेप और सार में होते हुए भी यह प्रस्ताव आतंकवाद की सही परिभाषा नहीं करता। कारण यह वैधानिक स्तर पर निरपराध मासूमों की हत्या सरीखे अपराध और भगतसिंह सरीखे लोगों द्वारा उपनिवेशी शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले कृत्यों के बीच के अन्तर को स्पष्ट रूप से रेखांकित नहीं करता है। इस क्रम में एक बार फिर इस्लामाबाद का ही उदाहरण ध्यान आता है। वह जम्मू–कश्मीर में जारी आतंकवाद को स्वतंत्रता संघर्ष करार देने पर ही तुला हुआ है। वह भी तब जब बुश प्रशासन समेत कई अन्य देश व इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास तक कई–कई बार पाकिस्तान प्रेरित जम्मू–कश्मीर में घुसपैठ को गलत ठहरा चुके हैं और उसकी निंदा कर चुके हैं। आतंकवाद की यह परिभाषा ध्येय, मकसद, कारण और आतंक के शिकार लोगों के पैमाने पर एफ.बी.आई. (Federal Beaurow of Investigation – USA) द्वारा प्रस्तुत परिभाषा पर भी फिट नहीं बैठती है।

एफ.बी.आई. की आतंक की परिभाषा के मुताबिक "आतंकवाद, शक्ति या हिंसा का वह अवैधानिक रास्ता है जो राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिये व्यक्ति विशेष या समूहों, सरकारी व नागरिक सम्पत्ति के लिये प्रयोग में लाया जाता है।"[170] संयोग से अपराध और आतंकवाद के संदर्भ में अमेरिकी आतंकवाद शोध केन्द्र के निदेशक **नील ए. पोलार्ड** के पेपर का उल्लेख भी किया जा सकता है, जो उन्होंने जनवरी 2009 में प्रस्तुत किया। इसके मुताबिक "तार्किक उद्देश्य को ध्यान में रखें तो कुछ आतंकी संगठनों और अन्तर्देशीय संगठित अपराध गिरोहों में एक प्राकृतिक साझेदारी देखने में आती है। संगठित गिरोह की पहुँच आसानी से राजनीतिज्ञों तक होती है। नेताओं पर उनका प्रभाव भी होता है। ऐसे में संगठित अपराध से जुड़े गिरोह आतंकी समूहों के लिये खासे मददगार साबित होते हैं, क्योंकि उन्हें अपना प्रभाव व दायरा बढ़ाने के लिये सरकार नष्ट करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसके बदले में संगठित अपराध गिरोह आतंकी समूहों का इस्तेमाल क्षेत्रीय अस्थिरता से उत्पन्न स्थितियों में अपने को शक्ति सम्पन्न बनाने में करते हैं। इस परिभाषा के आलोक में सर्वप्रथम नाम दाऊद इब्राहिम का ही सामने आता है।"[171]

जाहिर है कि जब तक आतंकवाद की एक सर्वमान्य परिभाषा अस्तित्व में नहीं आती तब तक उसके प्रति अपनाये जा रहे दोहरे नजरिये से निजात मिलने वाली नहीं। आज सम्पूर्ण संसार इस सदी के आतंकवाद से भीषण त्रास्त है और यह खतरा निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि विज्ञान व प्रौद्योगिकी का प्रयोग मनुष्य की सृजनात्मक ऊर्जा को जागृत करने और दिलों के फासलों को दूर करने की बजाय केवल भौगोलिक दूरी कम कर रही है। आतंकवाद बुद्धि के दुरूपयोग का परिणाम तथा विज्ञान व तकनीकी के अभिशाप का एक भयंकर उदाहरण है। यह एक ऐसे दानव की तरह है, जिसकी पहुँच विश्व के हर कोने में है और जो किसी देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति या मजबूत संरचना को ध्वस्त करने में सक्षम है। इसके कार्यकर्त्ता या एजेंट, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं, सभी जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवा कर भयंकर आघात करते हैं और राष्ट्र की महत्त्वपूर्ण गतिविधियों को पंगु बना देते हैं। सम्पूर्ण राष्ट्र की सामूहिक बुद्धि जिन ठिकानों को सुरक्षित समझती है, वहाँ भी अप्रत्याशित रूप से ये हमला करते हैं तथा आतंकवाद के शिकार राज्य स्वयं को शक्तिहीन और कमजोर पाते हैं। आधुनिक समय में आतंकवाद बर्बरता, क्रूरता, विध्वंसक एवं महाप्रलय के दर्शन में बदल गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पारिभाषिक अस्पष्टता ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ अधिक अर्थपूर्ण तरीके से कार्यवाही करने के लिये एक आम सहमति हासिल करने मे बाधा पहुँचाई है। पारिभाषिक भूलभुलैया पर बात

---

[170] डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र, "आतंकवाद व आपदा प्रबंधन", 2010, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, फोन 23247003, पृष्ठ संख्या–5

[171] वही, पृ.सं.–6

करने से पहले कुछ परिभाषाओं या अपरिभाषाओं पर एक नज़र डालना उचित होगा, **जो समय–समय पर सामने आती रही हैं –**

1. ''रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमिर फतिन ने 20 अक्टूबर, 2001 को हुई एशिया प्रशान्त महासागरीय आर्थिक सहयोग (**APEC**–Asia-Pacefic Economic Co-operation) बैठक में कहा कि राष्ट्रीय कानूनों और अन्तर्राष्ट्रीय विधि दस्तावेजों से आतंकवाद की परिभाषा अब भी नदारद है।''[172]
2. अमेरिकी सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, ''राजनीतिक, धार्मिक या सैद्धान्तिक प्रकृति वाले लक्ष्य हासिल करने के लिये हिंसा का इस्तेमाल या हिंसा का भय दिखाना आतंकवाद है, जो जोर–जबरदस्ती, आक्रमण या दहशत फैलाकर किया जाता है।''[173]
3. ''कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आतंकवाद को परिभाषित करते समय आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किये गये उपाय उनके वर्गीकरण के लिये एक महत्त्वपूर्ण संकेतक होते हैं।''[174]
4. ''जिस प्रकार जनसंहार के लिये कोई स्पष्टीकरण नहीं है उसी प्रकार सामूहिक हत्या के लिये भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जो लोग आतंकवाद (निर्दोष नागरिकों की हत्या करने या उन्हें निशाना बनाने) का सहारा लेते हैं, वे इस बात का अधिकार खो देते हैं कि समझदार लोग और कानून–सम्मत देश उनके कारण को समझेंगे। इस मुॅयानि आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र को एक रेखा खींचनी चाहिये। आतंकवाद फैलाने वाले या उसकी अनदेखी करने वाले और आतंकवाद के 'विरुद्ध खड़े होने वाले देशों के बीच नैतिक सापेक्षता का युग समाप्त होना चाहिये। नैतिक सम्बद्धता का इस चर्चा और बहस में कोई स्थान नहीं है।''[175]
5. ''आखिर में सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या यह है कि दुनिया के लोगों के दिमाग में क्या है? बहुत से लोग ऐसे हैं, जो एक आतंकवादी और एक स्वतंत्रता सेनानी के बीच का अन्तर नहीं जानते। यह अन्तर स्पष्ट है, क्योंकि आतंकवाद की परिभाषा सरल और त्राुटिहीन है। आतंकवादी अपनी बात मनवाने या रास्ता निकालने के लिये यथासम्भव बड़े पैमाने पर निर्दोष नागरिकों को हिंसा का

---

[172] मेजर जनरल विनोद सहगल, ''अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद'', 2006, प्रभात प्रकाशन, 4/19, आसफ अली रोड़, नई दिल्ली–110002, पृष्ठ संख्या–168

[173] चॉम्स्की, 'स्टेट्समैन', 7 नवम्बर, 2001

[174] मेजर जनरल विनोद सहगल, ''अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद'', प्रभात प्रकाशन, 4/19 आसफ अली रोड़, नई दिल्ली–110002, पृष्ठ संख्या–168

[175] न्यूयॉर्क के मेयर रुडोल्फ गिलानी, आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्रा के उद्घाटन के अवसर पर, 1 अक्टूबर, 2001

शिकार बनाते हैं। जो भी इस बिन्दु पर भ्रमित होने का दावा करता है, उसे आतंकवाद के लिये जवाबदेह होने का सामना करना पड़ेगा।''[176]

कट्टरवाद पर की गई यह टिप्पणी आतंकवाद की व्यावहारिक परिभाषा सुनिश्चित करने में सहायक हो सकती है – ''सरल रूप में देखें तो अपने विस्तृत प्रकार में कट्टरवाद को किसी ऐसी प्रणाली या समूह के रूप में देखा जा सकता है, जो हिंसा या बल–प्रयोग द्वारा अन्य लोगों पर अपने मूल्य और मत थोपना चाहता है। कोई भी प्रणाली या सरकार जो विचार, कार्य, परिधान और इस प्रकार की अन्य चीजों में पूरी तरह समानता की माँग करती है और जो अन्य मतों, मूल्यों या आचार–व्यवहार को नकार कर हिंसा या जोर–जबरदस्ती से अपने सिद्धान्तों को लागू करती है, वह मानव–गरिमा और प्रगति के 'विरुद्ध है।''[177] आतंकवाद की परिभाषा का **उप–अध्याय 1.2** इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि आज आतंकवाद की सर्वमान्य एवं सर्वसम्मति वाली परिभाषा की आवश्यकता है क्योंकि आतंकवाद के विरूद्ध कठोरतम कानून तभी बनेगा जब यह परिभाषित हो जायेगा कि कौन सा कार्य आतंक की श्रेणी में आता है? कौन आतंकी है? और कौन स्वतंत्रता सेनानी?

आतंकवाद के प्रकार
(Types of Terrorism)

श्री महेन्द्रा वेद ने आतंकवाद के पाँच[178] प्रकार बताये हैं जो निम्नलिखित हैं –

1. **राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद (State Sponsored Terrorism)**– जो अधिकांशतः एक कमजोर राज्य द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार का मानना है कि जम्मू–कश्मीर में जिहाद या आजादी की लड़ाई के नाम पर जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं वह पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा ही प्रायोजित हैं।
2. **गुट द्वारा प्रायोजित आतंकवाद (Faction Sponsored Terrorism)** – यह एक सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिव्यक्ति है। इस प्रकार का आतंकवाद राज्य या शासन के विरोध में पृथक्कतावादी आन्दोलन के एक अंग के रूप में पैदा होता है जैसे पंजाब में भिंडरावाला गुट का खालिस्तानी आतंकवाद जो कि पंजाब में पृथक्क व स्वतंत्र खालिस्तान की स्थापना करना चाहता है। इसी

---

[176] पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज पी. शल्ट्ज द्वारा वर्जीनिया में जॉर्ज पी. शल्ट्ज नेशनल फॉरन अपेफयर्स ट्रेनिंग सेन्टर के समर्पण समारोह में दिये गये भाषण का अंश, 'द वर्क ऑफ डिप्लोमेसी', 29 मई, 2002

[177] जून, 2001 के प्रथम सप्ताह में कट्टरवाद और सम्प्रदायवाद पर ढ़ाका में हुए दक्षिण एशियाई सम्मेलन में विनोद सहगल के भाषण का अंश

[178] डॉ. आर.बी.सिंह, ''भारत में आतंकवाद'', 2010, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, पृष्ठ संख्या–14

प्रकार के पृथक्कतावादी सिद्धान्त पर आधारित श्रीलंका का आतंकवादी संगठन लिट्टे (लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम) है।

3. **अपराध सम्बन्धित आतंकवाद (Crime Related Terrorism)** – यह आतंक फैलाने के लिए हिंसा को अपना प्रमुख हथियार बनाता है और राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए धन का उपयोग करता है। दाऊद इब्राहिम जैसे अन्डरवर्ल्ड सरगनाओं द्वारा संचालित गुटों के कारनामें इसी श्रेणी में आते हैं।[179]
4. **नार्को आतंकवाद (Narco Terrorism)** – यह धन को प्राप्त करने के लिए मादक द्रव्यों के धंधे को समर्थन देता है। समाचार – पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं से पता चलता है कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कुख्यात सरगना ओसामा–बिन–लादेन ने मादक पदार्थों की तस्करी से अथाह धन कमाया था। पूर्वोत्तर भारत और कश्मीर में बड़े पैमाने पर तस्करी का कार्य होता है।
5. **मुद्दों से प्रेरित एवं उद्देश्यपरक आतंकवाद (Issue Motivated Terrorism)** – यह परमाणु हथियारों पर निषेध, भूमि संघर्ष, संसाधन बट्टवारा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना में प्राथमिकता की माँग अथवा बहिष्कार, राजनयिक प्रक्रिया की बहाली अथवा विरोध, सरकारी नीतियों का विरोध, अलगाववादी (स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए) जैसे खालिस्तान (भारत), ईलम (श्रीलंका) आदि मुद्दों से प्रेरित होता है। उदाहरणार्थ बंगाल का नक्सलवादी आतंकवाद भूमिहीन श्रमिकों को भूमिपति बनाने के मुद्दे से प्रेरित था। उसी प्रकार जम्मू–कश्मीर में कुछ आतंकवादी संगठन हिंसा व धमकी की रणनीति अपना कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।[180]

आतंकवाद के प्रकार

आतंकवाद अपने आप में एक अत्यन्त जटिल राजनैतिक समस्या है तथा इनको वर्गीकृत करना एक कठिन कार्य है, विशेषकर आधुनिक वैश्वीकरण के युग में। **फिर भी मोटे तौर पर हम इन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं–**

1. क्रांतिकारी आतंकवाद (Revolutionary Terrorism)
2. क्षेत्रीय आतंकवाद (Regional Terrorism)
3. राज्य / राष्ट्रीय आतंकवाद (State Terrorism)
4. अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद (International Terrorism)
5. राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद (State-sponsored Terrorism)
6. मादक पदार्थों एवं आर्थिक अपराध से संबंधित आतंकवाद (Narco Terrorism)
7. साइबर आतंकवाद (Cyber Terrorism)

1. **क्रांतिकारी आतंकवाद (**Revolutionary Terrorism**) –** इस प्रकार के आतंकवाद का उद्देश्य राज्य को अस्थिर करके वहाँ की सरकार को बदलना होता है।

[179] प्राथमिक स्त्रोत, महेन्द्र वेद, हिन्दुस्तान टाइम्स, 22 मार्च 1993, पृष्ठ संख्या–8
[180] वही

''आधुनिक आतंकवाद की शुरुआत प्रफांसीसी क्रान्ति (1789) के साथ हुई। शुरुआत में 'आतंकवाद' का प्रयोग क्रान्तिकारियों के षविरुद्ध सरकारी गतिविधियों के लिए किया गया।''[181] किन्तु 1848 तक आते–आते इसका अर्थ पूर्णतः परिवर्तित हो गया तथा यह हिंसात्मक क्रान्तिकारी गतिविधियों को परिभाषित करने के लिए किया जाने लगा जो सरकारी तन्त्रा के विरोध में था। 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में आतंकवाद के विभिन्न गुटों द्वारा, जैसे – मजदूर संगठनों, राष्ट्रवादियों इत्यादि द्वारा किए गए हिंसात्मक कृत्यों को वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् इसका प्रयोग तीसरी दुनिया के राष्ट्रों द्वारा यूरोपीय शक्तियों के 'विरुद्ध राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन हेतु हिंसात्मक गतिविधियों को चिन्हित करने के लिए किया जाने लगा। **माओ–त्से–तुंग** ने इस प्रकार के आतंकवाद को क्रान्तिकारी प्रक्रिया का प्रारम्भिक चरण माना है, जो आगे चलकर पारंपरिक युद्ध में परिणत हो जाता है किन्तु वर्तमान में इस प्रकार के आतंकवाद का प्रचलन काफी कम हो चुका है।

2. **क्षेत्रीय आतंकवाद (**Regional Terrorism**) –** जब किसी क्षेत्र विशेष के कुछ लोग अपने राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये चलाये जा रहे सशस्त्र आन्दोलन में उस क्षेत्रीय सरकार के विरूद्ध आतंकवाद का सहारा लेते हैं। तब वह क्षेत्रीय आतंकवाद कहलाता है। उदाहरण : जैसे उत्तरी आयरलैण्ड में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, श्रीलंका में लिपे (LTTE) द्वारा श्रीलंका सरकार के विरूद्ध अपनाया गया आतंकवाद इस श्रेणी में आता है। क्योंकि इस प्रकार का आतंकवाद उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहता है। उस क्षेत्र से बाहर नहीं निकलता।

क्षेत्रीय आतंकवाद वह होता है जहाँ एक राष्ट्र के अन्तर्भूत क्षेत्रों या समुदायों की ओर से अपने स्वतन्त्र भाषाई, साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय स्वतन्त्राता की माँग को लेकर आतंकवाद का सहारा लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर, उत्तरी आयरलैण्ड की आयरिश रिपब्लिकनन आर्मी (I.R.A.), इटली की रेड आर्मी या रेड ब्रिगेड, जर्मनी का बादेरमैन हौफ गैंग, स्पेन का प्रफीडम फार द वास्कये, होमलैण्ड, श्रीलंका का लिट्टे, भारत का खालिस्तान कमाण्डो फोर्स, नागा और मिजो विद्रोही, उल्फा तथा कश्मीर के जे. के. एल. एफ. आदि को लिया जा सकता है। ये आतंकवादी एक निर्धारित लक्ष्य और भावभूमि पर काम करते हैं। इनका उद्देश्य वहाँ के शासन को डगमगाना, जनता को आतंकित करके अपने प्रभाव का विस्तार करना और इस प्रकार अपनी माँगों को मानने के लिये सरकार को विवश करना होता है। ''इन आतंकवादियों के दल में बेरोजगार युवक, जातीय या धार्मिक उन्माद से प्रभावित लोग, विदेशी प्रलोभन से आकर्षित युवक, व्यक्तिगत या सामाजिक अपमान के षविरुद्ध उठ खड़े लोग

---

[181] मेजर जनरल अफसर करीम (रिटायर्ड), ''काउफण्टर टेररिज्म – दी पाकिस्तान पैफक्टर'', लांसर इण्टरनेशनल, 1991, पृष्ठ संख्या–2

आदि शामिल हो जाते हैं। इस तरह इनका संगठन विभिन्न उद्देश्यों को लेकर लड़ने वालों का एक बड़ा समूह बन जाता है।''[182]

3. **राज्य/राष्ट्रीय आतंकवाद (State Terrorism)** – जब कोई राज्य या देश स्वयं अपने ही देश के विद्रोही नागरिकों के साथ आतंकवाद रूपी हथियार का प्रयोग करता है तो इस प्रकार का आतंकवाद राज्य–आतंकवाद कहलाता है। उदाहरणः जैसे श्रीलंका सरकार अपने ही देश के विद्रोही नागरिकों द्वारा बनाये गये आतंकवादी संगठन लिपे (LTTE) के विरूद्ध कई बार आतंकवाद का सहारा लेकर स्र्ज्ज्म के आतंकवादियों को मार गिराया था। जैसे कहावत है कि 'Fight Guerrilla Like Guerrilla' अर्थात् गुरिल्ला को अगर हराना है तो दूसरी (विरोधी) पार्टी को भी गुरिल्ला बन जाना चाहिये यानि गुरिल्ला को गुरिल्ला बनकर ही मारा जा सकता है। इसमें आतंकवादी तत्त्वों को विभिन्न राष्ट्रों द्वारा मदद, शरण और आतंकवादी कार्यवाहियों के लिये हथियार प्रदान किये जाते हैं। इस श्रेणी में पाकिस्तान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, लीबिया, सीरिया, इराक, ईरान आदि के नाम उल्लेखनीय है। राष्ट्रीय आतंकवाद अपनी भौगोलिक सीमाओं के अन्दर लड़ा जाता है। इसमें अपने नागरिकों में से ही आतंकवादी बनते हैं और इन्हें विदेशी सहायता धन, हथियार, गाड़ी तथा प्रशिक्षण के रूप में मिलता है। जैसे लिट्टे (श्रीलंका) को उत्तरी अमरीका, यूरोप तथा एशिया में रहने वाले तमिल समुदाय से तथा अन्य देशों से मदद मिलती है। 'हमास' को फिलीस्तीनियों, ईरान और सउदी अरब से आर्थिक सहायता मिलती है। 'हिजबुल्लाह' को ईरान और सीरिया से न केवल वित्तीय सहायता मिलती है बल्कि इसके सदस्यों को उनसे सैन्य प्रशिक्षण, हथियार, विस्फोटक सामग्री भी मिलती है। हरकत–उल–मुजाहिदीन को सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से आर्थिक एवं सैन्य सहायता मिलती है। चेचन्या के आतंकवादियों को सीरिया, जॉर्डन और सउदी अरब धन उपलब्ध कराते हैं।

लश्कर–ए–तैयबा (LeT) को अल–कायदा से तथा इसका संबंध फिलीपीन्स, मध्यपूर्व और चेचन्या के खूँखार आतंकवादियों से हैं इसी तरह जैश–ए–मुहम्मद को हरकत–उल–जिहाद–अल–इस्लामी और हरकत–उल–मुजाहिदीन से आर्थिक एवं सैनिक सहायता मिलती है। आइरिश रिपब्लिकन आर्मी को लीबिया, फिलीस्तीन लिबरेशन प्रफन्ट से आर्थिक एवं आयुध प्रशिक्षण की सुविधा मिलती है। मुजाहिदीन–ए–खल्क (ईरान) को इराक के अलावा अन्य देशों में रहने वाले ईरानी लोगों से । इसी तरह फरवरी 1998 में हरकत–उल–मुजाहिदीन ने ओसामा बिन लादेन के इंटरनेशनल इस्लामिक प्रफंट (आई.आई.एफ.) के गठन में मदद की, जिसका मकसद क्रूसेडरों और यहूदियों के खिलाफ जिहाद छेड़ना था तत्पश्चात् पाकिस्तानी जिहादी

---

182 डॉ. लल्लन जी सिंह, ''राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा'', 2006, प्रकाश बुक डिपो, बड़ा बाजार, बरेली–243003, पृष्ठ संख्या–61

आतंकवादी संगठन लश्करे–तैयबा, हरकत–उल– जिहाद– अल–इस्लामी व जैश–ए–मुहम्मद भी आई. आई. एफ. में शामिल हो गये। राष्ट्रीय आतंकवाद में हम उन राष्ट्रों की स्वतन्त्राता संग्राम की गतिविधियों को भी ले सकते हैं जो उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी ताकतों के दमन चक्र में पिस रहे हैं, जैसे फिलीस्तीनी जनता, द. अप्रफीका की जनता अथवा आजादी प्राप्त करने वाले स्वापो (SWAPO) के स्वतन्त्राता सेनानी। ये लोग अपने विरोधियों तथा उनके समर्थकों को आतंकवादी कार्यवाहियों द्वारा दण्डित करते रहे हैं। फलतः उसकी नजर में यह कार्यवाही आजादी का एक अंग रहा है परन्तु उनके विरोधियों की दृष्टि में यह आतंकवाद है। इसीलिये इन पर कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इसी तरह सरदार भगत सिंह ब्रिटिश शासन की नजर में आतंकवादी थे लेकिन भारतीयों की दृष्टि में शहीद। ऐसा लगता है कि आतंकवाद की सार्थकता उसकी अन्तिम सफलता से आङ्की जाती है।

4. **अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद (**International Terrorism**) –** इस प्रकार का आतंकवाद व्यापक रूप से पूरे विश्व में फैला होता है। इसलिये इसको ळसवइंस ज्मततवतपेउ (भूमण्डलीय या विश्वव्यापी आतंकवाद) भी कहा जाता है। इस प्रकार के आतंकवाद में विश्व के अनेक देशों में सक्रिय आतंकवादी समूह आपस में मिलकर किसी विश्व शक्ति के विरूद्ध (जैसे अमेरिका, रूस, चीन इत्यादि) आतंकवादी गतिविधियों का प्रयोग करते हैं जैसे ओसामा बिन लादेन के अलकायदा नामक आतंकवादी समूह ने 11 सितम्बर 2001 को अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर (WTC) के दोनों टॉवरों व अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन को विस्फोटक से भरे वायुयानों द्वारा टक्कर मारकर आत्मघाती हमले द्वारा सारे विश्व को आश्चर्य चकित कर दिया था और इस घटना से यह संदेश गया कि जब विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका भी आतंकवादियों से सुरक्षित नहीं है तो दुनिया की अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का तो कहना ही क्या? इससे पहले भी अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद केन्या व तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों में आत्मघाती हमले करवाकर सैंकडों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यह भी अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का उदाहरण है। मुस्लिम धार्मिक कट्टरपंथी जिहाद का सहारा लेकर अमेरिका और उसके नाटो मित्रों (NATO alli) की सेनाओं के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लेते हैं। अफगानिस्तान के तालिबान और इराकी आतंकवादी अमेरिका पर दबाव बनाते हैं कि वो अपनी सेनायें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक एवं खाड़ी क्षेत्रों से हटाकर वापिस अपने देशों में ले जाये और अरबों व फिलीस्तीनियों के खिलाफ इजरायल की मदद न करे। इसी कारण आज अमेरिका मुस्लिम कट्टरपंथियों (Radical) का सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ है।

जेद्गएनद्ग सक्सेना के शब्दों में, ''अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद वह हिंसा या भय का कार्य है जिसका क्षेत्राधिकार अन्तर्राष्ट्रीय होता है तथा जिसे करने वाला एक राज्य का हो और जिसके विरूद्ध किया गया हो वह दूसरे राज्य

का या ऐसी हिंसा की घटना हो जो दोनों के ही क्षेत्राधिकार से बाहर की हो।''

यद्यपि राज्य प्रायोजित आतंकवाद को हम एक प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की श्रेणी में रख सकते हैं। किन्तु आधुनिक विश्व में विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विकास तथा वैश्वीकरण को प्रक्रिया के चलते प्रत्येक आतंकवादी गुट ने एक वैश्विक स्वरूप धारण कर लिया है। ''आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रायः सभी आतंकवादी संस्थाओं को अपने अभियान को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की सुविधा प्रदान कर दी है। इन सबके मूल में अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी में आर्थिक विकास की अत्यधिक असमानता, विकसित राष्ट्रों द्वारा अर्द्धविकसित राष्ट्रों का शोषण, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का संवेदनहीन व्यवहार, इन राष्ट्रों पर पूर्व में किए गए निर्मम अत्याचार, नस्लवाद की अवधारणा तथा अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा केवल अपने को महान् मानने की मानसिकता जैसे अनेक कारण उत्तरदाई हैं।''[183] ''अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के उद्भव में दो प्रमुख पड़ाव रहे हैं – 1975 तथा 1998 । 1975 में कार्लोस मेरीघेला ने दो प्रफांसीसी अधिकारियों जो प्रफेंच आतंकवाद विरोधी एजेन्सी कैज से सम्बन्धित थे, की हत्या कर आतंकवाद की शुरुआत की। तत्पश्चात् वैचारिक समानता वाले विभिन्न आतंकवादी गुटों जैसे – त्मक ।तउल थ्बजपवद व िळमतउंदल ंदक श्रंचंदए जीम च्वचनसंत थ्तवदज वित जीम स्पइमतंजपवद व िच्ंसमेजपदम (PFLP) इत्यादि को एक समान मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। इस संयुक्त मोर्चे के अन्तर्गत प्रत्येक घटक दलों को अपनी स्वतन्त्र गतिविधियों को स्वतन्त्रातापूर्वक संचालित करने की छूट थी जबकि कुछ समान लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु तथा समान शत्राुओं के षविरुद्ध साझा आक्रमण करने की बात की गई थी। दो समान शत्राुओं को चिन्हित किया गया–जियोनिज्म तथा पूाइजीवाद।''[184]

1998 अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का अन्य प्रमुख पड़ाव रहा है क्योंकि इस दौरान कार्लोस से मिलती–जुलती एक अन्य शख्सियत ओसामा बिन लादेन अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर उभरी जिसने “International Islamic Front for Jihad Against the US and Israel” का निर्माण किया। **इस प्रफन्ट में निम्नलिखित संगठन सम्मिलित थे।**[185]

- ❖ मिश्र एवं पाकिस्तान के तीन आतंकी गुटँ

---

[183] मानचन्द खण्डेला, ''अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद'', आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयफर, 2002, पृष्ठ संख्या –16

[184] बी.रमन, ''टेररिज्म दी न्यू कनटैक्स'', स्ट्रैटजिक एनालिसिस, दिसम्बर 2001, वाल्यूम–ग्ग्ट, नं. 9, पृष्ठ संख्या–995

[185] वही, पृ.सं.–996

- ❖ बिन लादेन का अल कायदाँ
- ❖ तालिबान (अफगानिस्तानद्धँ
- ❖ उज्बेकिस्तान के दो संगठनँ
- ❖ चीन के सिंकियांग प्रान्त का एक संगठनँ और
- ❖ दक्षिणी फिलीपीन्स का एक गुट।

प्रत्येक संगठन के अपने राजनैतिक लक्ष्य हैं। अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के साथ–साथ इनके कुछ समान शत्रु हैं जिनके 'विरुद्ध इन्होंने लादेन के नेतृत्व में युद्ध छेड़ रखा है। यह समान शत्रु हैं अमेरिका, भारत, रूस, इजरायल इत्यादि।

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का अभिप्राय है विभिन्न आतंकवादी संगठनों का एक–दूसरे से जुड़ जाना। उदाहरणार्थ, भारत के ''उल्फा'' आतंकवादी श्रीलंका के लिट्टे से जुड़े हैं अथवा यूरोप के कई आतंकवादी पी. एल. ओ. (फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन) से जुड़े हैं। इसी प्रकार दक्षिण अप्रफीका के ए. एन.सी. का स्वापो से सम्बन्ध बनाकर संयुक्त कार्यवाही करना। भारत में पंजाब के खालिस्तान समर्थकों और कश्मीर के जे.के.एल.एफ. आतंकवादियों का पाकिस्तान, अमरीका और ब्रिटेन स्थित आतंकवादी संगठनों से जुड़ना व संयुक्त कार्यवाही आदि। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का स्वरूप अत्यन्त भीषण होता है। कभी–कभी सम्पूर्ण विश्व में एक साथ कार्यवाही होती है। जैसे खाड़ी युद्ध के समय सद्दाम ने फिलीस्तीनी मुक्ति मोर्चे के विश्वव्यापी संगठन से आतंकवादी कार्यवाहियाँ करने का आह्वान किया जिसके परिणामस्वरूप एक साथ विश्व के कई देशों में अमेरिकी दूतावास तथा अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों के इर्द–गिर्द बम विस्फोट हुए थे।,

अगस्त 1998 में अमरीकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने सूडान और अफगानिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइलों से हमला कराया भी इसमें कोई संदेह नहीं था कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ यह एक साहसपूर्ण कदम था। इसी महीने केन्या और तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर जिस तरह भीषण बम विस्फोट किये गये, उससे एक बात तो साफ हो गयी थी कि इस्लामी कट्टरवादी अब अमरीका को कठोरतम सबक सिखाना चाहते थे क्योंकि केन्या और तंजानिया के दूतावासों में विस्फोटों में एक दर्जन से अधिक अमरीकी नागरिक मारे गये। इसके अलावा उन दूतावासों में काम करने वाले अनेक स्थानीय लोगों की भी मृत्यु हो गयी। अनगिनत लोग घायल हुए। एक कुख्यात आतंकवादी पाकिस्तान में पकड़ा गया जिसने यह रहस्योद्घाटन किया कि इन दोनों दूतावासों को ध्वस्त करने के पीछे अफगानिस्तान में रह रहे और सउदी अरब से निकाले गये कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का हाथ था। अतः अमरीका ने अफगानिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइलों से हमला लादेन और उसके सहयोगियों को समाप्त करने के विचार से किया था। परन्तु

उस समय लादेन अपने सेल्युलर फोन पर विदेश में किसी आतंकवादी से बातें कर रहा था, उसी से अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों को पता लग गया कि लादेन किस जगह खड़ा है पर लादेन की तकदीर कहिये कि मिसाइल गिरने से एक मिनट पहले वहाँ से भाग खड़ा हुआ और फोन को बन्द कर दिया। लादेन बहुत धनी आतंकवादी है जिसके पास कम से कम 300 अरब डॉलर की सम्पत्ति है। उसके जीवन का एक मात्रा उद्देश्य इस्लामी कट्टरपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। उसके पास पाँच हजार से अधिक प्रशिक्षित आतंकवादी हैं जो दुनिया के विभिन्न देशों से या तो रिटायर हुए बड़े फौजी अफसर हैं या नये भर्ती किये हुए नौजवान जो इस्लाम के नाम पर हर वक्त जान देने को तैयार रहते हैं।

अफगानिस्तान में अलकायदा की देखरेख में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इन आतंकवादियों का मूल उद्देश्य है भारत, खासकर कश्मीर में व्यापक रूप से तोड़–फोड़ करना। इतना ही नहीं दुनिया के विभिन्न देशों के अमरीकी दूतावासों को बमों से उड़ाना। तालिबान एक अत्यन्त ही भयानक और खतरनाक आतंकवादी संगठन है। यह पूर्णतः कट्टरपंथी है। सच कहा जाए तो तालिबान सही अर्थ में अमरीका द्वारा ही तैयार किया हुआ एक आतंकवादी संगठन है, जो पूर्णतः पाकिस्तान की जेब में है। अमरीका को मध्य एशिया के तेल और गैस की पूर्ति इनकी मदद से ही होती रही है। इसीलिए वह अब तक इनकी हरकतों की अनदेखी करता रहा है। यह बात सिद्ध हो चुकी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकवादियों के शिविर चल रहे हैं और उन्हें 'जिहाद' के नाम पर जम्मू–कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिये भेजा जाता है। लादेन जैसे अरब देशों में अनेक इस्लामी कट्टरपंथी तालिबान को आर्थिक एवं अस्त्र–शस्त्रों की मदद कर रहे हैं।

5. **राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद (State-Sponsored Terrorism)** – जब कोई राष्ट्र अपने यहाँ आतंकवादियों को आश्रय देकर उनको प्रशिक्षण, धन, हथियार, विचारारोपण, बुद्धि–परिवर्तन या बुद्धि–प्रक्षालन (Brainwashing) इत्यादि प्रदान करके किसी दूसरे राष्ट्र के विरूद्ध प्रयोग करे तो उसको राज्य द्वारा प्रायोजिक आतंकवाद कहते हैं। उदाहरणः जैसे पाकिस्तान भारत के विरूद्ध इस प्रकार के आंतकवाद का प्रयोग पिछले कई वर्षों से करता चला आ रहा है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के षविरुद्ध किया गया विघटनकारी एवं हिंसात्मक कृत्य है जो उस राष्ट्र को अस्थिर करने के उद्देश्य से किया जाता है। इनको दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है–

(क) एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के लोगों के षविरुद्ध दमनकारी कृत्यों के माध्यम से (जैसे–इजरायल द्वारा फिलीस्तीन में)

(ख) एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के षविरुद्ध असंतुष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रेरित आतंकवाद (जैसे–पाकिस्तान द्वारा भारत के जम्मू–कश्मीर व अन्य राज्यों में)

''राज्य प्रायोजित आतंकवाद के द्वारा एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के षविरुद्ध हिंसा तथा बल प्रयोग द्वारा दीर्घकालीन राजनैतिक एवं युद्धनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, आधुनिक युद्धकला का एक प्रमुख स्वरूप बना चुका है।''[186]

इस प्रकार का आतंकवाद आज अधिक चर्चित है। इस प्रकार के आतंकवाद में पड़ोसी या शत्रु राष्ट्र अपने विरोधी राष्ट्र के विद्रोही गुटों को अपने में मिलाकर उन्हें पैसा, हथियार और प्रशिक्षण तथा संरक्षण देकर अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करता है। दुनिया को दिखाने के लिए वह आतंकवादियों से दूर रहता है लेकिन उसे अपने विदेश नीति और युद्ध नीति का अंग बनाकर लम्बे समय तक विरोधी को परेशान और कमजोर करने की कोशिश करता है।

आजकल किसी भी राष्ट्र के लिए सम्भव नहीं है कि वह एक लम्बा और खर्चीला युद्ध कर सके, कमजोर राष्ट्र के लिये यह और भी असम्भव है इसलिये छद्म युद्ध एक विकल्प बनकर उभरा है। इसमें विरोधी राष्ट्र के विद्रोही आतंकवादियों और महत्त्वाकांक्षी राजनीतिज्ञों की मदद की जाती है। आर्थिक मदद, राजनीतिक कुप्रचार, कूटनीतिक समर्थन और पड़ोसी राष्ट्र की कमजोर नीतियों का लाभ उठाना ये सभी परोक्ष या छद्म युद्ध कला की विशेषता है।

कुछ लोग इसे रक्षात्मक कार्यवाही कहते हैं और कुछ आक्रमणात्मक, शक्तिशाली देश इसे आक्रामक मानते हैं जबकि कमजोर राष्ट्रों के लिए यह एक रक्षात्मक विकल्प है। यह एक ऐसी रणनीति कही जा सकती है जिसमें विरोधी राष्ट्र को शक्तिहीन करने के लिए उसके राजनैतिक परिस्थितियों का लाभ उठा कर अलगाववादी गुटों को मदद दी जाती है और उसके साधनों तथा संसाधनों का अपव्यय करने के लिए मजबूर किया जाता है।

आज का युग अर्थव्यवस्था और जनमत का युग है छोटे से छोटे राष्ट्र का महत्त्व बढ़ गया है, यदि कोई छोटा राष्ट्र किसी बड़े राष्ट्र के साथ मिला है तो उसका शत्रु राष्ट्र कितना भी शक्तिशाली हो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी भी राष्ट्र के लिए युद्ध बड़ा महट्टगा सौदा है इसलिए छद्म युद्ध एक आसान, सस्ता और सुरक्षित तरीका है, यह युद्ध आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों के माध्यम से लड़ा जाता है इसलिए इसे राजकीय आतंकवाद कहा जाता है।

भारत के षविरुद्ध पाकिस्तान द्वारा चलाया जाने वाला यह युद्ध राजकीय या राज्य प्रायोजित आतंकवाद का एक उदाहरण है। पाकिस्तान ने आई.एस.आई. के माध्यम से जम्मू–कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर राज्यों में बड़े ही सुनियोजित ढ़ंग से यह छद्म युद्ध चला रखा है उसने भारत की राजधानी और आर्थिक महानगर

---

[186] डॉ. सतीश चन्द्र पाण्डेय – आतंकवाद एवं अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सम्पादक – डॉ. ए.पी. शुक्ल, डॉ. राहुल मिश्र, ''राष्ट्रीय सुरक्षा की समसामयिक समस्यायें'', 2006, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1बी, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, पृष्ठ संख्या–88

मुम्बई को भी निशाना बनाया। धार्मिक भावनायें भड़काकर साम्प्रदायिक दंगे करवाने की साजिश भी बार–बार हुई। उसने भारत की धार्मिक, सामाजिक, क्षेत्रीय और आर्थिक विषमताओं का लाभ उठाना चाहा फिर भी भारत स्थिर और अडिग होकर अपने विकास के मार्ग पर निरन्तर आगे जा रहा है।

6. **मादक पदार्थों एवं आर्थिक अपराध से संबंधित आतंकवाद (Narco Terrorism)**–इस प्रकार के आतंकवाद में आतंकवादी मादक पदार्थों जैसे – हेरोईन, अफीम, गाट्टजा, चरस, स्मैक, पोस्त इत्यादि पदार्थों की तस्करी करके अपने समूह के लिये धन एकत्र करते हैं। जैसे ळवसकमद ज्तपंदहसम (म्यांमार, थाईलैण्ड व लाओस) और ळवसकमद ब्तमेबमदज (अफगानिस्तान, ईरान व पाकिस्तान) के मार्गों से मादक पदार्थों की तस्करी चलती है और इस धन से नार्को आतंकवाद फलता–फूलता है और इस धन से आतंकवादी छोटे हथियारों (Small Arms) के अवैध व्यापार से हथियार खरीदते हैं। अफगानिस्तान के तालिबान आतंकवादी अफीम की खेती करके अपने समूह के लिये धन एकत्रित करते हैं। सउदी अरब के पेट्रोल उत्पादन का धन भी आतंकवादी संगठनों की मदद के लिये दिया जाता है।

प्रत्येक आतंकवादी कृत्य जो राजनैतिक कारणों से विभिन्न कारकों द्वारा प्रोत्साहित हो, को हम आपराधिक आतंकवाद की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे मादक द्रव्य तस्करी एवं आतंकवाद इत्यादि। सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य वैज्ञानिक विकासों के चलते तथा वैश्वीकरण के इस माहौल में, वर्तमान समय में राजनैतिक आतंकवाद तथा आपराधिक आतंकवाद में विभेद करना अत्यन्त कठिन कार्य हो गया है। आज प्रायः सभी आतंकवादी संगठन अपने संगठन की आर्थिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के आतंकवादी कृत्यों में संलग्न है। ये आपराधिक कृत्य निम्नवत् हैं –

- मादक द्रव्यों की तस्करीँ
- लघु आग्नेयास्त्रों का अवैध व्यापारँ
- समुद्री डाका (पायरेसी) एवं समुद्री नाविकों के अपहरण से प्राप्त फिरौतीँ
- साइबर अपराध इत्यादि।

आज अन्तर्राष्ट्रीय अपराध विभिन्न आतंकी संगठनों के लिए अत्यन्त लाभकारी व्यापार बन चुका है। जिसके चलने से आज यह अत्यन्त प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग का रूप धारण कर चुका है। यदि हम अलकायदा के आर्थिक स्त्रोतों पर नजर डालें तो आतंकवाद एवं अपराध के मध्य सम्बन्ध स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा।[187]

---

187 क्षितिज प्रभा, ''टेरर इन्टरप्राइजेज – ऑर्गेनाईजेशन, इंप्रफास्ट्रक्चर एण्ड रिसोर्सेज'', स्ट्रैटजिक एनालिसिस, दिसम्बर 2001, वाल्यूम –ग्ग्ट, नं. 9, पृष्ठ संख्या–1049

संसार में नशीले पदार्थ (Poppy) के तीन ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं, जहाँ इनका उत्पादन व्यापक मात्रा में होता है।[188]

1. South – East Asia (Golden Triangle – स्वर्ण त्रिभुज) – इस क्षेत्र के अन्तर्गत बर्मा (म्यांमार), लाओस तथा थाईलैण्ड आते हैं।
2. South – West Asia (Golden Crescent – स्वर्ण v(चन्द्राकार) – इसके अन्तर्गत ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान आते हैं।
3. Part of Latin America – इसमें कोलम्बिया, मैक्सिको तथा ब्राजील इत्यादि आते हैं।

''उपरोक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त ˇमेज ‌ेपं जिनमें **Bekka Valley** जो लेबनान में स्थित है, अफीम तथा हशीश के उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र है। साथ ही Central Asi में भी मादक द्रव्यों का उत्पादन होता है।''[189] चूँकि ''मादक द्रव्य (VQHE) सबसे अधिक धन संग्रह करने वाली उपभोक्ता वस्तु है, इसीलिए मादक द्रव्यों की तस्करी में राजनेताओं से लेकर असंगठित अपराध में लगे अपराधी तथा छोटे हथियारों के तस्कर भी शामिल हैं।''[190]

''नशीले पदार्थ आज किसी भी राष्ट्र की एकता, अखण्डता एवं सम्प्रभुता के समक्ष एक प्रमुख समस्या के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। नशीले पदार्थों का कुप्रभाव किसी भी राष्ट्र की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति एवं उसकी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। नशीले पदार्थों के व्यापार से प्राप्त अथाह धन का इस्तेमाल आतंकवाद, कट्टरवाद एवं अलगाववाद बढ़ाने में किया जा रहा है। इस तरह नशीले पदार्थों के व्यापार, वितरण एवं उपभोग से न सिर्फ स्वास्थ्य, समाज एवं अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। बल्कि नशीले पदार्थों के व्यापार से प्राप्त काला धन विश्व शान्ति एवं सौहार्द के लिए भी खतरा उत्पन्न करने का कारण बनते जा रहे हैं।''[191]

''मादक द्रव्यों के अन्तर्गत चरस, गाङ्जा, अफीम, हेरोईन, मारफीन, हशीश, कोका, केन्नोबीस, सिंथेटिक उत्पादन आदि आते हैं। नशीले पदार्थ आज अपने परिवर्तित रूप में एफिटामाइंस, डेक्सट्रोफिटामाइंस, मेटोफिटामाइंस और इनके जैसे पदार्थों को एंफिटामाइंस के नाम से जाना जाता है। नशेड़ियों के बीच

188 आर.सी. मिश्रा, ''सिक्योरिटी इन साउथ एशिया, क्रॉस बॉर्डर एनालिसिस'', ऑथर प्रेस, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या–31

189 वी.डी. चोपड़ा, ''ग्लोबल चैलेंस ऑफ टेररिज्म'', ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2002, पृष्ठ संख्या–117

190 इकरामुल हक, ''पाकिस्तान प्रफॉम हैज टु हेरोईन'', ऑनर पब्लिशर्स, लाहौर, 1991, पृष्ठ संख्या–32

191 प्रो. श्यामधर सिंह, ''सोशियोलॉजी ऑफ सोशल प्रोब्लम'', मिश्रा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, वाराणसी, 2003, पृष्ठ संख्या–189

में टफिटामाइंस सर्वाधिक प्रचलित है। ये मादक पदार्थ रंगीन गोलियों या सफेद पाउडर जैसे होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं।''[192]

नार्को टेररिज्म शब्द का प्रयोग नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े संगठनों और राजनीतिक अस्थिरता के निकट गठजोड़ को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं अर्थात् नशीले पदार्थों के तस्करों तथा आतंकवादियों के बीच गठजोड़ को नार्को टेररिज्म कहा जाता है। अमेरिकी खुफिया विभाग के प्रमुख विलियम जे. क्रेसी के अनुसार इन दोनों संगठनों के लक्ष्य पूर्णतः भिन्न हैं। नशीले पदार्थों के तस्कर केवल एक वस्तु के पीछे होते हैं और वह है ढ़ेर सारा धन चूँकि ये एक व्यापारी हैं, इसलिए अपने व्यापार की रक्षा करना चाहते हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी में अथाह लाभ को देखते हुए ये स्थापित व्यवस्था को अपने पक्ष में करके उस पर नियन्त्रण स्थापित कर शीर्ष नेतृत्व को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। नशीले पदार्थों के तस्करों का साधन और साध्य दोनों ही धन हैं। वहीं दूसरी तरफ आतंकवादी स्थापित शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ये दोनों ही पक्ष अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध व गतिशील हैं, दोनों के ही लक्ष्य भिन्न हैं। परन्तु शत्रु एक ही है वह है राज्य शक्ति, जिससे दोनों अलग होते हुए भी एक सूत्र में बद्द्धे हुए हैं और क्रियान्वयन के स्तर पर सहयोग को आकर्षित होते हैं।

''विश्व में नशीले पदार्थों का मूल्य किसी भी अन्य उपभोक्ता वस्तु के मूल्य से अधिक है। दक्षिण एशिया में 'स्वर्ण त्रिभुज' से उत्पादित एक किलो हेरोईन का मूल्य एक लाख रुपये है, वहीं पर अमेरिका में इसका मूल्य करीब एक करोड़ रुपये तक होता है।''[193] यह आड़्कड़ें स्थान, माँग और आपूर्ति पर निर्भर करते हैं साथ ही कानून व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।

''पाकिस्तान की हेरोईन एवं हशीश तथा कोलम्बिया की मारिजुआना की अमेरिका तथा यूरोप में अत्यधिक माँग है। इन मादक द्रव्यों से प्राप्त धन का हिसाब लगाना कठिन है चूँकि इन नशीले पदार्थों से अपार धन प्राप्त होता है। इसी कारण इन मादक द्रव्यों के उत्पादन करने वाले सिंडिकेटों ने तस्करी करने वाले असंगठित अपराधियों से गठजोड़ स्थापित कर लिया है और इनके सहयोग से ऑपरेशन आतंकवाद का खर्च वहन कर रहे हैं।''[194]

''उल्लेखनीय है कि नार्को टेररिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में उस समय किया गया था, जब नशीले पदार्थों के तस्करों ने बोलविया, कोलम्बिया, पेरू, निकारागुआ और अन्य केन्द्रीय अमेरिकी देशों में संगठित रुप से नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को एक व्यवसाय के रुप में अपनाया और एक समानान्तर

---

[192] उदयभान सिंह, ''चैलेंज टू बॉर्डर मैनेजमेन्ट इन इंडिया – म्यांमार रिलेशन'', वर्ल्ड फोकस, अगस्त 2006, पृष्ठ संख्या–33

[193] किशटिज प्रभा, ''नार्को टेररिज्म एण्ड इण्डियाज सिक्योरिटी'', स्त्रातेजिक एनालिसिस, नं. 10, जनवरी 2001, पृष्ठ संख्या–1878

[194] वही, पृ.सं.–1878

सरकार की स्थापना कर दी। ये सभी राज्य कोकीन तथा कैनोबीस के प्रमुख उत्पादक हैं। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था इसके उत्पादन और व्यापार पर निर्भर करती है। अमेरिका और यूरोप इसके बड़े उपभोक्ता हैं। जनसंख्या के बड़े भाग द्वारा इन नशीले पदार्थों के प्रयोग ने अमेरिका को इसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए बाध्य कर दिया। इस प्रकार 1980 के दशक में इस नशीले पदार्थ के प्रभाव को देखते हुए प्रथम बार विश्व के सामने इसके खिलाफ जनमत तैयार होना प्रारम्भ हुआ।''[195]

नशीले पदार्थ की तस्करी से प्राप्त धन द्वारा आतंकवादियों को सहायता दी जा रही है। आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता होती है। वह धन उन्हें वैध तरीके से नशीले पदार्थ के उत्पादन, व्यापार या तस्करी से आसानी से प्राप्त हो जाता है। आतंकवादी संगठनों और नशीले पदार्थों के तस्करों के **पारस्परिक गठजोड़ निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है –**

1. मादक द्रव्यों के उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था पूर्णतया या आंशिक रूप से इन नशीले पदार्थों की तस्करी पर निर्भर है। यदि इन देशों में अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया गया तो कानून की सख्ती भी इसके व्यापार को रोक नहीं पायेगी और पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जायेगी।
2. बिना किसी कागजी कार्यवाही के नशीले पदार्थों से बड़ी मात्रा में नकद धन प्राप्त होता है। इसमें लेन–देन नकद में होता है किसी भी कागजी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है।
3. नशीले धन से प्राप्त काले धन को विभिन्न माध्यमों, उदाहरण के लिए छद्म व्यापारिक संघों के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से लान्डरिंग की जाती है साथ ही हवाला के माध्यम से धन को एक जगह से दूसरे जगह स्थानान्तरित भी किया जाता है।
4. आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। वो भी नकद, जो उसे नशीले पदार्थों के व्यापार से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसमें वे अण्डरवर्ल्ड का भी सहयोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आतंकवादी संगठनों तथा अण्डरवर्ल्ड का गठजोड़ उभरकर सामने आता है।
5. आतंकवाद को समर्थन देने में राजनेताओं का महत्त्वपूर्ण हाथ होता है। जिस कारण से अण्डरवर्ल्ड के लोग आतंकवादियों को सहयोग देकर अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक परिदृश्य में अपनी पहुँच बनाते हैं। ये तीनों मिलकर नशीले पदार्थ के व्यापार में लगे हैं। राजनीति के अपराधीकरण का एक प्रमुख कारण भी यह गठजोड़ ही है।[196] ये कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य हैं। जो आतंकवाद और नशीले पदार्थों के गठजोड़ को बढ़ावा देने में सहायक हो रहे हैं।

---

[195] स्टेवन आर. वेल्नको (एडिटेड), ''ड्रग्स एण्ड ड्रग्स पोलिसी इन अमेरिका''

[196] स्त्रातेजिक एनालिसिस, जनवरी 2001, पृष्ठ संख्या–1878–79

मनी लान्डरिंग (Money Laundering)

''नशीले पदार्थों से प्राप्त अथाह धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करना तथा इसे सफेद धन या वैध रूप में उत्पादित दिखाना बहुत कठिन कार्य है। तस्करी से प्राप्त धन का स्थानान्तरण करना मुश्किल होता है। बहुत कम बैंक इस कार्य को करते हैं। उदाहरण के लिए B.C.C.I. (Bank of Credit and Commerce International) तथा पाकिस्तान का हबीब बैंक''[197] इसलिए तस्करों को अन्य माध्यमों को तलाश करना पड़ता है। ''इस प्रकार इस अवैध धन को वैध धन में परिवर्तित करने के लिए अनेक तरीकों की खोज तथा स्थापना की गयी। इनके इस असंगठित लेकिन व्यवस्थित तरीके से धन के लेन–देन को मनी लान्डरिंग के नाम से जाना जाता है। यदि हम राष्ट्रों के बीच प्रवाहित धन का परीक्षण करें तो हम इसे तीन भागों में बाँट सकते हैं।''[198]

1. **सफेद धन (White Money) :** यह धन वैध तरीके से प्राप्त या अर्जित किया जाता है।
2. **काला धन (Black Money) :** यह धन कर न अदा करने से अर्जित किया जाता है।
3. **गन्दा धन (Dirty Money) :** यह धन पूर्णतः नशीले पदार्थों और अपराध से उत्पादित धन होता है।

अतः मनी लान्डरिंग को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं – ''अवैध तरीके से प्राप्त धन, व्यक्तिगत पहचान को छुपाये रखते हुए , वैध स्रेतसे प्राप्त में परिवर्तित करना **अर्थात्** ब्लैक मनी तथा डर्टी मनी को व्हाईट मनी में परिवर्तित करना मनी लान्डरिंग कहलाता है इस प्रक्रिया में नशीले पदार्थों से प्राप्त धन का उपयोग विश्व में लेन–देन व्यवस्था तथा राजनीति को प्रभावित करने में हो रहा है।''[199] यह धन राजनीतिज्ञों को खरीदने, चुनावों को प्रायोजित करने तथा राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था को अव्यवस्थित करने में होता है। **मनी लान्डरिंग के तीन आयाम हैं–**

1. मादक द्रव्यों की आमदनी जो देश के अन्दर स्थानीय मुद्रा में होती है। इसकी लान्डरिंग समान्तर अर्थव्यवस्था के माध्यम से होती है।
2. देश/क्षेत्र के बाहर मादक द्रव्यों की आमदनी जो कमीशन के रूप में इसे आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त होती है। यह अमेरिकी डॉलर से होता है।
3. मादक द्रव्यों की तस्करी शस्त्र गुटों द्वारा होती है। अतः इनकों इस सेवा के लिए धन की जगह शस्त्र तथा विस्फोटक वस्तु विनिमय के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

---

[197] वही, पृ.सं.–1889

[198] स्त्रातेजिक एनालिसिस, अगस्त 1997, पृष्ठ संख्या–724–25

[199] डॉ. संजय कुमार, ''असम का नृजातीय संघर्ष और भारतीय सुरक्षा'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स्, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, पृष्ठ संख्या–127

चूँकि ''मादक द्रव्यों की तस्करी तथा उत्पादन शस्त्र गुटों के माध्यम से होती है। ये सभी गुट छोटे हथियारों के तस्करों के मार्ग का प्रयोग मादक द्रव्य की तस्करी में कराते हैं। इस व्यवस्था में क्षेत्र के बाहर व्यापार से धन डॉलर में प्राप्त होता है। इसे वापिस अपने पास लाने के लिए हवाला या धन का विनिमय वस्तुओं, शत्राुओं, बहुमूल्य जवाहरात या सोने के माध्यम द्वारा होता है। इसमें कई राष्ट्रों में स्थित विभिन्न गुट भागीदार होते हैं। यदि एशिया के किसी राष्ट्र में स्थित कोई गुट मादक द्रव्यों की तस्करी अमेरिका या यूरोप में करता है, तो उसे अप्रफीका या यूरोप के संगठन द्वारा धन की जगह हथियार, हीरे या सोने के रूप में मूल्य प्राप्त हो जाता है। मादक द्रव्यों से प्राप्त धन की लान्डरिंग, विदेशी बैंकों, भूमि व्यवसाय, होटल, यातायात और मनोरंजन व्यवस्था के माध्यम से होती है। बैंकों से अधिक व्यक्तिगत वित्तीय कम्पनियों में ड्रग के माफियाओं को अपने धन को व्यवस्थित करने में सहायता मिलती है। स्विट्जरलैण्ड, हांगकांग, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और थाईलैण्ड आदि ऐसे कुछ महत्त्वपूर्ण देश हैं जो व्यवस्थित रूप से यह प्रक्रिया चला रहे हैं। इन्हें सिंडिकेट (Drug Syndicate) कहा जाता है। मादक द्रव्यों से प्राप्त धन की लान्डरिंग निम्न तरीकों से होती है।''[200]

''बैंक में धन जमा करना तथा ऋण लेना, (Double Invoicing) **अर्थात्** द्वैध मूल्य सूची, विदेशी व्यापारों में पूट्टजी निवेश, भूमि व्यवसाय में पूट्टजी निवेश यात्रा और मुद्रा विनिमय संस्थायें, हवाला (Hawal) द्वारा लेन–देन, धन की तस्करी, धन का विनिमय वस्तुओं द्वारा, मनोरंजन व्यवसाय, टैक्स से मुक्त प्रक्रियाओं (VDS etc), इस प्रकार यह पूरी प्रक्रिया मनी लान्डरिंग कहलाती है।''[201]

हवाला (Hawal)

''हवाला वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को धन बिना सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया से गुजरकर पहुँच जाता है। हवाला का चलन कब और कहाँ से हुआ यह कहना मुश्किल है। हवाला का उर्दू में अर्थ है–निर्देश या हवाला और अरबी में अर्थ है–विश्वास। इसका प्रयोग प्राचीनकाल में व्यापारी अपने धन को चोरों और लुटेरों से रक्षा के लिए करते थे। सामान्यतया इसका अर्थ हवा में लेना–देना होता है। अरब व्यापारी इसका प्रयोग रेशम मार्ग के लुटेरों से बचने के लिए करते थे।''[202] लाखों भारतीय, पाकिस्तानी, फिलीस्तीनी और अन्य एशिया के जो बाहर के देशों में कार्य करते हैं अपने घर धन को पहुँचाने के लिए हवाला का प्रयोग करते हैं। यह तीव्र है, इस पर कोई कर नहीं लगता तथा बैंकिंग प्रक्रिया से भी गुजरना नहीं पड़ता। ''अन्तर्राज्य हवाला में धन बिना अन्तर्राष्ट्रीय

---

[200] स्त्राातेजिक एनालिसिस, जनवरी 2002, पृष्ठ संख्या – 1890

[201] वही, पृ. सं. – 1890

[202] एन.एस.जैमवाल, ''हवाला : द इनविजीबल फाइनैंसिंग सिस्टम ऑफ टेररिज्म'', स्त्राातेजिक एनालिसिस, वॉल्यूम 26, नं. 2, अप्रैल–जून 2002, पृष्ठ संख्या–182–83

सीमा पार किये एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है। इस प्रक्रिया से विदेशों में स्थित भारतीय जो अपने परिजनों को पैसा भेजना चाहता है उस पैसे को जो डॉलर में होता है, हवालादार को दे देता है। उस हवालादार को भारत में स्थित एजेन्ट उतना ही पैसा भारतीय रुपये में उस विदेश में रहने वाले व्यक्ति के परिजनों को दे देता है तथा अपना कमीशन काट लेता है। हवाला की प्रक्रिया तीव्र, सस्ती बैंकों की प्रक्रिया से बचाती है साथ ही टैक्सों से भी बचाती है। हवाला के माध्यम से लेन–देन भारत और दक्षिण एशिया में काफी दिनों से चल रहा है। परन्तु आतंकवादियों द्वारा हवाला के माध्यम से पैसा उपलब्ध कराने के कारण यह प्रकाश में आया। कश्मीर में आतंकवादी गुटों (हुर्रियत) तथा भारत में ध्ैपध् की गतिविधियों में लगे लोगों को हवाला के माध्यम से ही धन उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्यवाही से यह प्रकाश में आया है।''[203]

7. **साइबर आतंकवाद (Cyber Terrorism)**– ''साइबर क्राइम का सीधा अर्थ है – किसी भी कम्प्यूटर के जरिए, किसी अन्य व्यक्ति के निजी पहलू तथा उसके कम्प्यूटर से छेड़छाड़ करना। कम्प्यूटर ही नहीं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग कर अन्य व्यक्ति के किसी भी पहलू से खिलवाड़ करना साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। विश्व की सुरक्षा एजेंसियों ने इसे अब तक 166 श्रेणियों में बाँटा है।''[204]

साइबर क्राइम की गति मन से भी अधिक तेज होती है। एक बटन के क्लिक से इसके द्वारा किए जाने वाला अपराध चंद सैकिण्ड में करोड़ों किलोमीटर दूर पहुँच जाता है तथा चाहकर भी कोई सुरक्षा एजेंसी इसके स्वतः ठहराव से पहले इस पर रोक नही लगा पाती। नैनो टैक्नोलॉजी के तहत कम्प्यूटर के जरिए हम छोटे–छोटे जीवाश्म को पकड़, उस पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। इस प्रणाली का प्रयोग करके भी कुछ लोगों ने अपराध को एक नई शक्ल देने की कोशिश की है।

साइबर क्राइम के तरीके व उनके हथियार – वेबसाइट हैकिंग, पासवर्ड ब्रेंक, ई–मेल पासवर्ड थैफ्ट, ई–मेल स्नूफिंग, इंटरनेट वेबसाइट हैकिंग, पासवर्ड कोपिंग तथा बड़े स्तर पर वायरस व वोर्म्स डाल कम्प्यूटर को नुकसान पहुँचाना इनके प्रमुख हथियार हैं। इसके अलावा 152 अन्य तरीकों को प्रयोग कर साइबर क्राइम किया जाता है। ई–मेल के पासवर्ड को तोड़कर या थोड़ी–सी हेरा–फेरी कर किसी को भी नुकसान पहुँचाना बड़ा आसान कार्य होता है। लव लेटर नाम के एक वायरस ने इंडिया ही नहीं 30 देशों के 22 करोड़ कम्प्यूटरों को नुकसान पहुँचाया। इसी का कारण रहा कि तीन दिन तक अमेरिका की माइक्रोसॉफ्रट जैसी बड़ी कम्पनी को भी अपने कार्यों को बंद करना पड़ा।

---

[203] वही, पृ. सं. – 183

[204] साइबर क्राइम : हिन्दुस्तान, 10 सितम्बर 2006

वर्ष 1998 में राबर्ट मेरिस ने इंटरनेट यूजर्स के लिए ऐसा वार्म्स बनाया जो वेबसाइट में इतनी तेजी से घुसा कि कई वेबसाइट खत्म हो गई। इस वार्म्स को निकालने के लिए विश्व के एक्सपर्टों को भी करीब दो महीने से अधिक का समय लगा। मोबाइल की चकाचौंध दुनिया में एम.एम.एस. (मल्टी मीडिया मैसिजिंग सर्विस) का प्रयोग पोर्नोग्राफी, अश्लील वीड़ियो क्लिप जैसी घटनाओं को आसानी से अंजाम दिया जा रहा है। वर्तमान तकनीकी रूप से कम्प्यूटर से जुड़े होने के कारण इसे भी साइबर एक्ट में रखा गया है।

भारत में साइबर अपराध से जुड़े मामले पूरे भारत वर्ष में अब तक 435 बड़े साइबर अपराध हुए हैं, जिनमें अलग–अलग राज्यों की पुलिस ने 6277 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया। साइबर क्राइम के तहत हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है लेकिन अब तक अरबों रुपये की धोखाधड़ी साइबर क्राइम के जरिए हुई है। देश में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम बंगलौर व मुम्बई में हुए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम की संख्या अच्छी खासी रही है। जो कुछ इस प्रकार है। बंगलौर में एक इंजीनियर ने एक वेबसाइट को हैक कर ऐसा वायरस छोड़ा जिसने भारत के कई राज्यों के लाखों कम्प्यूटर खराब कर दिए।

21वीं शताब्दी में आतंकवाद को एक वैश्विक समस्या के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि आज विश्व का लगभग प्रत्येक देश किसी न किसी रूप में आतंकवाद की समस्या से ग्रस्त है ''आज आतंकवाद एक ऐसी नीति के रूप में विकसित हो चुका है, जिसके आगे विश्व की बड़ी शक्तियाँ भी विवश हैं। 11 सितम्बर 2001 की अमेरिका पर आतंकवादी हमलों की घटना इसका ज्वलंत प्रमाण है। इस हमले से सिर्फ इमारतें ही नहीं ध्वस्त हुई बल्कि अमेरिकी ताकत का समूचा मिथक ही भरभरा कर गिर गया। ओसामा बिन लादेन का संगठन अलकायदा के इस आतंकवादी हमले ने एकाएक भय और ताकत के पारम्परिक प्रतिमान बदल दिए। इन हमलों ने यह साबित कर दिया कि आज की तारीख में दुनिया का बड़े से बड़ा मुल्क, चाहे वह कितनी बड़ी सैन्य शक्ति हो, चाहे वह परमाणु हथियारों का जखीरा ही क्यों न रखता हो और उसकी प्रयोगशालाओं में कुछ ही घण्टों के भीतर जैविक अस्त्रा तैयार किए जा सकते हों लेकिन इन सारी चीजों से यह 'ताकतवर मुल्क' साबित नहीं हो जाएगा। इन हथियारों की तमाम ताकत के बावजूद वह (अमेरिका) आतंकवाद से सुरक्षित नहीं हो पाया तो भारत जैसे देशों का क्या वजूद है। आज समूची घटना आतंक की परिधि में आ गई है आज यह विश्वव्यापी स्वरूप ले चुका है। विश्व के लगभग सभी लोकतान्त्रिाक देश इसकी चपेट में हैं।''[205]

''आतंक मानव जाति का चिर सहचर रहा है और इसका प्रयोग प्रारम्भ से ही किया जाता रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतिक शब्दावली में आतंकवाद

---

[205] प्रो. लल्लन जी सिंह, ''राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा'', पृष्ठ संख्या – 54

सम्भवतः वह शब्द हैं जिसने सम्पूर्ण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। राष्ट्रों के नीति निर्धारक और राजनीतिज्ञ आए दिन आतंकवादी खतरे की और इसके षविरुद्ध कठोरतम कदम उठाने की चर्चा करते रहे हैं। बीसवीं शताब्दी के सातवें दशक से इसका प्रयोग राजनीतिक हितों को साधित करने के लिए किया जा रहा है। आतंकवाद को संघर्ष की एक नई विधा के रूप में विकसित किया जा रहा है। सातवें दशक से आतंकवाद की तीव्रता में 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से वृद्धि हो रही है। इस प्रकार 35,000 आतंकवादी घटनाएँ हुई हैं।''[206]

''वास्तव में आतंकवाद इस सदी को अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा खतरा है। इस तथ्य को संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (WTC) एवं पेंटागन पर हुए आतंकी हमलों ने साबित कर दिया है इतनी जन और धन की हानि हुई है कि उसकी कल्पना मात्रा से मानस पटल तिलमिला जा रहा है। पिछले 20 वर्षों में आतंकी हमलों से साठ हजार लोग मारे गए और पैंतीस हजार लोगों की प्रोपर्टी का नुकसान हुआ, जिससे लगभग डेढ़ मिलियन की क्षति का अनुमान है।''[207] आतंकवाद पर अपनी राय व्यक्त करते हुए मार्था क्रेंसा का कथन है कि ''आतंकवाद का आशय निश्चित राजनीतिक लक्ष्य को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से प्राप्त करना होता है।'' वस्तुतः ''आतंकवाद एक तरह का सशस्त्र संघर्ष है। अतः इसे सैनिक कार्यवाही माना जाना चाहिए। जब कूटनीति असफल होती है, तब सैनिक कार्यवाही शुरु होती है और जब सैनिक असफल होते हैं, तो उनका स्थान आतंकवादी ले लेते हैं।''[208] इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ''आतंकवाद एक विश्वस्तरीय तत्त्व है। इसे मान्य करना तो आसान है, परन्तु परिभाषित करना अत्यन्त दुरूह है। उसकी उत्पत्ति सामाजिक–आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से होती है और यह समाज में 'हैव' (Have) और 'हैव नाट' (Have Not) के मध्य संघर्ष होता है तथा इससे राजनीतिक हित साधित किए जाते हैं।''[209]

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि आतंकवाद के पीछे एक उद्देश्य निहित होता है, जो आमतौर पर राजनीतिक होता है। बस यही राजनीतिक उद्देश्य आतंकवाद को एक नीति के रूप में स्थापित करती है जिसका लाभ विभिन्न संगठन धार्मिक और कुछ राज्य अपनी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु अपनाए हुए हैं। फिलहाल कुछ देशों ने इसे बाकायदा अपनी राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बना रखा है, जिनमें पाकिस्तान प्रमुख है।

आतंकवाद की नीति

---

206 डॉ. भगवतीधर द्विवेदी का आलेख – ''आतंकवाद और दक्षिण एशियाई देश'', कृष्णानन्द शुक्ल द्वारा सम्पादित फस्तक ''स्त्रातेजिक वातावरण'', पृष्ठ संख्या–198

207 वही, पृ.सं.–199–200

208 जे. मैलिन, ''टेररिज्म इण्टरडिसीप्लीनरी पर्सपैक्टिव'', पृष्ठ संख्या–95

209 डॉ. क्षितिज प्रभा का शोध पत्रा, ''डिफाइनिंग टेररिज्म'', स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, अप्रैल 2000, पृष्ठ संख्या–125

प्रारम्भ में आतंकवाद कुछ हठी व अतिवादी व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा अपनी माँग को मनवाने का एक शार्टकट रास्ता माना जाता था किन्तु समय के बदलते दौर ने इसे एक प्रवृत्ति और फिर इसी प्रवृत्ति ने आजकल एक नीति का स्वरूप धारण कर लिया है। ''आतंकवाद न केवल संगठनिक स्तर पर अपितु देशीय स्तर पर भी इन दिनों राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनता जा रहा है विगत 5 सितम्बर 2006 को पाकिस्तान सरकार और वजीरिस्तान के तालिबानी समर्थक आतंकियों ने एक शान्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार आतंकियों ने पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी क्षेत्रों में हमला नहीं करने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने उत्तरी वजीरिस्तान के मीरानशाह शहर के एक कॉलेज के फुटबाल मैदान में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार आतंकवादी इस बात पर सहमत हो गए कि वजीरिस्तान क्षेत्र से सभी विदेशियों को हटना होगा और यदि कोई वहाँ रहता है, तो उसे समझौते की शर्तों को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। समझौते के अनुसार पाकिस्तान सरकार वजीरिस्तान में वायु व जमीनी अभियान रोक देगी, नई जाँच चौकियाँ बन्द करेगी और सुरक्षा बलों को फरानी स्थितियों में भेज देगी। सैनिक अभियानों के दौरान गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाएगा और जब्त की गई परिसम्पत्तियाँ लौटाई जाएगी।''[210] इस समझौते से यह जाहिर है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को एक पक्षकार के रूप में मान्यता देता हैं। हालाँकि इस पर कोई हैरान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आतंक फैलाना और प्रायोजित करना पाकिस्तान की राष्ट्रीय नीति का एक हिस्सा है। ''पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह जिया उल हक जब तक जीवित रहे, कश्मीर को हड़पने की साजिश रचते रहे। उन्होंने अप्रैल 1988 में आई.एस.आई. और पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के समक्ष एक भाषण दिया था, जिसमें कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए 'ऑपरेशन टोपैक' अभियान का खुलासा किया था।''[211] यह ऑपरेशन तीन चरणों में लग जाना प्रस्तावित था। कश्मीर को आतंक के दायरे में लेकर यहाँ ऑपरेशन टोपैक को दूसरे चरण पर प्रविष्ट कराने में पाकिस्तान लगभग सफल रहा है। कारगिल चोटियों पर कब्जे जैसी नापाक कार्यवाही भी पाकिस्तान के ऑपरेशन टोपैक का ही एक हिस्सा था। पाकिस्तान कारगिल क्षेत्र की संवेदनशील सुरक्षा ङांृखला पर कब्जा करके लेह–कारगिल क्षेत्र की संवेदनशील सुरक्षा ङांृखला पर कब्जा करके लेह–कारगिल श्रीनगर राजमार्ग को अपने अधिकार क्षेत्र में करना चाहता था। इससे भारत के लिए सियाचिन हिमनद की रक्षा व्यवस्था अस्थिर हो जाएगी। इसके साथ ही कारगिल पर अधिकार होने पर जम्मू–कश्मीर के लद्दाख डिवीजन से भी अलग करने में सहयोग मिलता है। ऑपरेशन टोपैक की योजना भी सफल हो जाती। ''भारत के षविरुद्ध घोषित चार युद्धों (1947–48, 1965, 1971, 1999) में मात खाने के बाद पाकिस्तान भारत के साथ खुलकर आक्रमण करने से डरता है। इसी

---

[210] समसामयिकी महासागर, नवम्बर 2006, पृष्ठ संख्या–29

[211] डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र, ''राष्ट्रीय रक्षा व सुरक्षा'', पृष्ठ संख्या–211

कारण पाकिस्तान अपनी नई रणनीति के तहत अलगाववादी और आतंकवादी गुटों को सहायता देकर अराजकता फैलाने के पूरे प्रयास कर रहा है। पंजाब की जागरूक जनता को पाक के नापाक इरादों का पता चल गया और शान्ति बहाल हो गई, किन्तु कश्मीर के लोगों में कट्टरपंथी धर्म की दुहाई देकर आन्दोलन को अभी चलाया जा रहा है। पाक ने कश्मीर के कुछ गुमराह युवकों को उकसा कर स्वतन्त्र या आजाद कश्मीर की माँग पर जोर दे रखा है। पाकिस्तान की इस साजिश पर पर्दाफाश अभी 'हजरत बल नाटक' के समय विश्व भर में हो गया था। कश्मीर की जनता में भारतीय राज्य के प्रति जो अनास्था पैदा हुई, उसको भरा पाकिस्तानी दुष्प्रचार से उत्पन्न अलगाववाद ने और इस अलगाववाद को संगठित किया इस्लामी कट्टरता ने।''[212]

दिसम्बर 1999 में काठमांडु से अपहृत भारतीय विमान अपहरण काण्ड के बदले छोड़े गए अजहर मसूद एवं अन्य तीन खूँखार आतंकवादियों को अपने यहाँ राजनयिक सम्मान देकर पाकिस्तान ने यह जता दिया था कि आतंकवाद के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है? एक आङ्कड़े के अनुसार जम्मू–कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों में लगभग 90 प्रतिशत पाकिस्तानी हैं, जिन्हें विभिन्न इस्लामी संगठनों व चैरिटी द्वारा आर्थिक, नैतिक व वैचारिक सहायता व समर्थन मिल रहा है। इसमें विशेष रूप से वर्ल्ड एसोसियशन ऑफ मुस्लिम यूथ, राबित–ए–अलम, वर्ल्ड कश्मीर प्रफीडम मूवमेण्ट, कश्मीर अमेरिकन काउंसिल, कश्मीर स्टडीग्रुप तथा प्रफेण्डस ऑफ कश्मीर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस समय पाकिस्तान ऑपरेशन टोपैक के अतिरिक्त 'मिशन पूर्वोत्तर' और 'मिशन डाय' (Mission Damage of Economy) पर भी विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किए हुए है, जो भारत के साथ उसके मौजूदा शीत युद्ध को 'लाल शीत युद्ध' (Red Cold War) में प्रतिबिम्बित कर रहा है। आतंकवादियों के प्रति पाकिस्तान का नजरिया कितना 'सॉफ्रट' (नर्म) है? इस बात का पता सिर्फ इससे लग जाता है कि आज इस्लाम के जिहादी अपने पास परमाणु बम होने का दावा कर रहे हैं। जैसा कि विश्व भर में आशंका जताई जा रही है और परिस्थितियाँ भी इसी तथ्य की ओर इशारा कर रही हैं कि इसके पीछे कहीं–न–कहीं पाकिस्तानी सहयोग अवश्य ही जुड़ा हुआ है।

''11 सितम्बर, 2001 की घटना के बाद सर्वाधिक चर्चित अलकायदा और तालिबानी आतंकियों का सीधा सम्बन्ध पाकिस्तान से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। कश्मीर इन्फारमेशन नेटवर्क से सम्बद्ध एक बेवसाइट पर जारी एक लेख में पाकिस्तान को आतंकवादियों की पौधशाला और खूँखार आतंकवादियों का विश्वविद्यालय बताया गया है।''[213] बेवसाइट एवं सेटेलाइट से जारी चित्रों के

---

[212] कृष्णानन्द शुक्ल, ''शांति, सुरक्षा और विकास की समस्यायें'', 2009, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, पृष्ठ संख्या–231

[213] टेररिस्ट रोल ऑफ पाकिस्तान – इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान : ए नर्सरी ऑफ टेररिस्ट्रस एण्ड ए यूनिवर्सिटी फॉर सुपर टेररिस्ट्स, ूणौउपत.पदजतवउंजपवदण्बवउध्चांपेजंद

अनुसार अफगानिस्तान से लेकर पाक अधिकृत कश्मीर तक आतंकी प्रशिक्षण शिविरों का जाल–सा बिछा हुआ है। कथित इस्लामी जिहाद के लिए तथा भारत को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान द्वारा इन्हें हर सम्भव मदद दी जा रही है। अमेरिकी हमलों से क्षत विक्षत तालिबानियों को फिर से संगठित करने में पाकिस्तान आज भी दिलचस्पी दिखा रहा है। तथ्य यह है कि ''तालिबान एक अत्यन्त ही भयानक और खतरनाक आतंकवादी संगठन है। यह पूर्णतः कट्टरपंथी है। सच कहा जाए तो तालिबान सही अर्थ में अमेरिका द्वारा ही तैयार किया हुआ एक आतंकवादी संगठन है, जो पूर्णतः पाकिस्तान की जेब में है।''

परमाणु आतंक का खतरा और आतंक की नीति

मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण–पूर्व एशिया इस समय आतंकवाद की तीखी पीड़ा से ग्रसित हैं, जिसमें दक्षिण एशिया इस समस्या रूपी आग में बुरी तरह से झुलस रहा है। इस क्षेत्र में प्रायोजित आतंकवाद ज्यादा प्रचलन में, जिसके फलस्वरूप विध्वंसकारी प्रौद्योगिकी एवं तकनीक भी आतंकवादियों के पास पहुँच चुकी है, जिसमें जैविक, रासायनिक एवं परमाणु बमों की तकनीक भी शामिल है। ''4 फरवरी, 2004 में पाकिस्तान के परमाणु तस्करी का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें वहाँ के परमाणु बम के पिता कहे जाने वाले प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. अब्दुल कादीर खान के होने की फष्टि हो चुकी है।''[214] सामान्य तौर पर देखा जाए तो परमाणु तस्करी नाभिकीय आतंकवाद की एक प्रमुख कड़ी है विगत कई वर्षों से परमाणु चोरों का आतंक अपनी चरम सीमा पर है, जिसमें विभिन्न देशों की सरकारों की मिली–भगत की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। फरवरी 2004 में उत्तर कोरिया, लीबिया, ईरान और पाकिस्तान परमाणु तस्करी में लिप्त पाए गए। जार्जिया, रूस, तुर्की, जर्मनी, प्रफांस, नीदरलैण्ड, युक्रेन, पोलैण्ड, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अप्रफीका आदि के नाम भी समय–समय पर परमाणु तस्करी से जुड़े हुए हैं। 1996 में यूक्रेन के शस्त्रागार से अटैची साईज के 200 रूसी परमाणु बम कहाँ गायब हो गए? इसकी सही जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, किन्तु ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये परमाणु शस्त्र कुछ लोभी देशों के साथ–साथ आतंकवादी संगठनों के हाथों में भी लग गए हैं, जिससे परमाणु आतंक का खतरा बढ़ गया है। ''परमाणु हथियार की चोरी–छुपे तस्करी के माध्यम से आतंकवादी संगठनों के हाथों में पहुँचने से अमेरिका सहित पूरे विश्व को परमाणु आतंकवाद का खतरा होना स्वाभाविक है। यह सर्वविदित है कि पाकिस्तान ने अपनी परमाणु क्षमता तस्करी एवं चोरी–छुपे प्राप्त की है, लेकिन यह कहना भी असत्य नहीं होगा कि पाक बम में चीन का भी कम योगदान नहीं है।''[215] गत वर्षों के दौरान 4 फरवरी, 2004 को पाक परमाणु जनक डॉ. अब्दुल कादीर खान ने यह कह कर कि ''जब तक वह रिसर्च

---

[214] दैनिक जागरण, 8 जनवरी 2005

[215] हिन्दुस्तान, 13 फरवरी 2004

लेबोरेटरी के अध्यक्ष थे, उस समय तक परमाणु प्रसार के समस्त गतिविधियों की जिम्मेदारी उनकी है।''[216] समूचे विश्व को चौंका दिया। डॉ. खान द्वारा ईरान, उत्तर कोरिया और लीबिया के परमाणु तकनीक देने की स्वीकारोक्ति ने इस आशंका को और भी बलवती किया है कि परमाणु बम बनाने में उपयोग की जाने वाली तकनीकी और पूर्जो की खरीद बिक्री में विश्वव्यापी काला बाजारियों का नेटवर्क सक्रिय है।

''यहाँ यह बताना प्रासंगिक होगा कि पाकिस्तान ने स्वयं चोरी की नाभिकीय सामग्री न सिर्फ नीदरलैण्ड एवं बेल्जियम से हासिल की, बल्कि जर्मनी के तस्करों ने भी उसका सहयोग किया था। जर्मनी, प्रफांस और ब्रिटेन ने दक्षिण अप्रफीका को परमाणु क्षमता सम्पन्न बनने के करीब पहुँचा दिया है। लैटिन अमेरिकी देशों ब्राजील और अर्जेंटाइना को भी परमाणु तकनीकी जर्मनी ने ही मुहैया कराई थी।''[217] ज्ञातव्य हो कि एकीकरण के पूर्व जर्मनी परमाणु सामग्री की बिक्री का वैध–अवैध केन्द्र रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हामिद रजा आसिफी के अनुसार ईरान ने कालाबाजारियों के माध्यम से परमाणु फर्जे खरीदे थे। अपने परमाणु परीक्षा के बाद उत्तर कोरिया ने भी यह स्वीकार किया कि उसे परमाणु तकनीक 'कुछ मित्रों' के सहयोग से प्राप्त हुई है। ''पाकिस्तान से परमाणु तकनीकी के हस्तान्तरण के मामले में लीबिया में पाये गये ब्लू प्रिन्टों को लेकर जाँच कर्त्ताओं का यह स्पष्ट मानना है कि ये पाक परमाणु हथियारों से मेल नहीं खाते हैं। जाँच कर्त्ताओं ने यह साफ कहा कि लीबिया में पाक वैज्ञानिकों से हस्तांतरित परमाणु हथियारों के जो ब्लू प्रिंट पाए गए हैं, वे उनके अपने अपरिष्कृत किस्म के बम से सम्बन्धित है, न कि पाक के आधुनिक मॉडल से। इससे स्पष्ट होता है कि अन्य देश तथा कई आतंकवादी संगठन भी परमाणु प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण कर रहे हैं।''[218] इसमें कोई दो राय नहीं है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् की परिवर्तित परिस्थितियों में किए जा रहे हैं शस्त्र परिसीमान और निःशस्त्रीकरण के प्रयासों में निहित शर्तों ने विश्व के चन्द महत्त्वाकांक्षी देशों को परमाणु क्षमता हासिल करने के लिए प्रेरित किया जिसका फायदा चन्द व्यापारिक किस्म के देशों और वहाँ अपना नेटवर्क फैलाये काला बाजारियों ने अपने आर्थिक और व्यापारिक स्वार्थ पूर्ति के लिए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र को इन लोगों ने सहज भाव से चुना, क्योंकि इसके लिए बाजार, बिचौलिया, धन और अवसर सभी कुछ सहज रूप से उपलब्ध था। इस अवसर का पूरा–पूरा लाभ उठाया आतंकवादी संगठनों ने। विशेष रूप से ऐसे संगठन या उनसे जुड़े व्यक्ति जिनके पास अकूत धन सम्पदा और एक विस्तृत नेटवर्क उपलब्ध था, ने वक्त की नजाकत को समझते हुए परमाणु के अवैध कारोबार को प्रायोजित किया

---

[216] इंडिया टुडे, मार्च 2004, पृष्ठ संख्या–42
[217] आउट लुक, फरवरी 2004
[218] हिन्दुस्तान, 23 फरवरी 2004

और अपनी कठपुतली संस्थाओं एवं व्यक्तियों के माध्यम से इसे पल्लवित फष्पित भी किया। इससे उन्हें न केवल व्यापारिक उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं, बल्कि अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए विभिन्न देशों यथा – ईरान, इराक, सउदी अरब, लीबिया, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चेचन्या, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका आदि में आधार क्षेत्र तो प्राप्त ही हुए हैं, साथ ही साथ इन्होंने अपने आपको भी परमाणु क्षमता से सम्पन्न बना लिया है। अरब मीडिया ने यह खुलासा करके सबको चौंका दिया है कि पिछले कई सालों से (1997–98) अलकायदा के पास परमाणु हथियार हैं।

अरबी समाचार पत्र 'अल हयात' ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ''आतंकी संगठन अलकायदा के पास खतरनाक परमाणु हथियार हैं। यदि उसके अस्तित्व को चुनौती दी गई, तो वह उसका प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेगा।'' रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ''परमाणु हथियार ओसामा बिन लादेन समूह ने यूक्रेन के एक वैज्ञानिक से प्राप्त किया था, जब वह 1998 में कंधार घूमने आया था। गम्भीर परिणाम की वजह से उसने अमेरिकी सेना के षविरुद्ध इसका प्रयोग नहीं किया।''[219] लेकिन भविष्यै में और विशेष रूप से अमेरिकी धरती पर इसके प्रयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। गलत हाथों में परमाणु प्रौद्योगिकी के पड़ जाने से इसके गलत प्रयोग की आशंका को नकारना बेवकूफी होगी। आज आतंकवादी संगठन जिस प्रकार से अपनी गतिविधियों का दायरा क्षेत्र बढ़ाने के लिए एक क्षेत्र विशेष में कुटिल दृष्टि लगाए हैं, उससे परमाणु आतंकवाद की आशंकाएँ बलवती हो गई हैं, क्योंकि इन आतंकवादियों के पास न तो कोई नैतिकता है और न ही कोई उच्च आदर्श। ये न तो किसी कानूनी बंदिशों को मानते हैं और न ही अपने लक्ष्यों के प्रति ये किसी मूल्य से कोई समझौता ही करते हैं। शायद यही सब देखकर संयुक्त राष्ट्र संघ की परमाणु निगरानी संस्था 'अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी' के प्रमुख मोहम्मद अलबर देई ने कहा कि ''वर्तमान परिदृश्य में नाभिकीय तस्करी, प्रौद्योगिकी व तकनीकी हस्तान्तरण तथा आतंकवादी संगठनों के पास परमाणु हथियारों का होना यह बात सिद्ध करती है कि दुनिया बहुत बड़े परमाणु हादसे की ओर जा सकती है।''[220] संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने भी परमाणु आतंकवाद को रेखांकित करते हुए कहा कि ''परमाणु आतंकवाद हमारे समय के सबसे बड़े खतरों में से एक है। एक हमला भी बड़ी संख्या में लोगों को हलाक कर देगा और हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा।'' ईश्वर न करे ये आशंकाएँ सच हों, किन्तु दुर्भाग्य से यदि यह सच होता है, तो इसके लिए वे देश, संगठन और व्यक्ति जिम्मेदार होंगे, जिन्होंने चन्द स्वार्थ के वशीभूत होकर 'आतंक की नीति' का अनुसरण किया और

---

[219] हिन्दुस्तान, 10 फरवरी 2004

[220] वही

आतंकवाद को प्रायोजित कर रहे हैं। मानवता ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करेगी।

1.4 आतंकवाद के कारण (Etiology/Causes of Terrorism)

"यह तो सच है कि आतंकवादी जन्मजात पैदा नहीं होता है। किसी देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियाँ ही आतंकवाद की आधार भूमि होती है।"[221] इन सब कारणों के अतिरिक्त मनोविश्लेषक आतंकवादी को 'बीमार' मानते हुए उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारणों की तलाश करते हैं जो आतंकवादी किसी संगठन से जुड़े रहते हैं उसके पीछे एक विचारधारा या निश्चित योजना की खोज की जा सकती है किन्तु जो आतंकवादी पेशेवर हैं और व्यक्तिगत रूप से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं उनका विश्लेषण किसी विचारधारा या राजनीतिक दमन के आधार पर नहीं किया जा सकता ऐसे आतंकवादी की बनावट मनोविश्लेषण शास्त्रा के आधार पर तय की जाती हैं ऐसे ही एक विश्लेषण की मनोवैज्ञानिक जोसेफ भार्गोलिन 'हताश उग्र सिद्धांत' के रूप में स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि अधिकांश आतंकवादी राजनीतिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं से अपनी हताशा और कुंठा के उत्पाद ही हैं। एक आतंकवादी अपनी कार्य विधि इस उद्देश्य से करता है कि सरकार दमन करेगी और इस तरह वह अपने सिद्धांतों की व्याख्या करने में सफल हो जाता है। किसी राजनीतिक या राजनयिक की हत्या जैसे कारनामों में आतंकवादियों का नेराथ्य भाव और आहत स्वाभिमान बहुत बड़ा कारक होता है। इस तरह की किसी भी हत्या से आतंकवादी दिखाना चाहता है कि वह 'सर्वशक्तिमान' है और वह कुछ भी कर सकता है। किन्तु मानसिक विकृति ही आतंकवाद का एक कारण नहीं है इसके अतिरिक्त भी आतंकवाद के उपजने व बढ़ने के पीछे कई कारणों को तलाशा जा सकता है ऐसे ही कारणों में ऐतिहासिक अन्याय भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ पनपने वाली कुंठा तकनीकी विकास आदि का उल्लेख किया जा सकता है ऐतिहासिक अन्याय की व्याख्या से इजरायल में आतंकवाद का उदाहरण दिया जा सकता है। हिटलर ने तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों यहूदियों का निर्मम कत्ल कर दिया था। इसी राजनीतिक दमन, हत्या आदि ने इजरायल के यहूदियों के अन्दर सोवियत संघ व अरबी मुसलमानों के खिलाफ स्वाभाविक घृणा कर दी है, जो आतंकवाद के रूप में फूटती है।

औपनिवेशिक कारण की व्याख्या करते हुए उन आतंकवादी संगठनों की बात की जा सकती है जो अपने देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनको स्वतन्त्राता प्रदान कर दी। फिर भी कुछ देश जैसे फिलीस्तीन को इजरायल से आजाद कराने के लिए पी.एल.ओ. आतंकवादी गतिविधियाँ अपनाए हुए हैं। "महाशक्तियाँ भी आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, ऐसा वे

[221] वेद प्रताप वैदिक, "ओसामा मुसलमानों की दुविधा", 29 सितम्बर 2001, नवभारत टाइम्स

गुप्त रूप से करती हैं। इस तरह के आतंकवाद का उद्देश्य उस देश–विदेश की सरकार को अस्थिर करना होता है। इस प्रकार के आतंकवाद में अफगानिस्तान के मुजाहिदीन आदि का उल्लेख किया जा सकता है। एक भ्रष्ट और तानाशाही पूर्ण राजतन्त्रा आतंकवाद को जन्म दे सकता है। किसी राज्य की नौकरशाही यदि भ्रष्ट बेईमान और अकर्मण्य है तो नागरिकों में एक हताशा और निराशा का भाव भर जाता है। ऐसी निराश और हताश जनता यदि ऐसी किसी हिंसक आतंकवादी संगठन को पा जाती है उसे उस भ्रष्ट और अकर्मण्य नौकरशाही से अपने आतंकवादी कारनामों द्वारा मुक्ति दिला सके, तो वह उसे स्वीकार कर लेती है।''[222]

''अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमलों का कारण कट्टरपंथी आतंकवादियों का यह मानना है कि अमेरिका इस्लाम विरोधी नीतियों को पोषित करता है। इजरायल को समर्थन देने, इराक पर आक्रमण करने आदि कारणों से आतंकवादी अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं और उसे दण्डित करना चाहते हैं।''[223]

आतंकवाद के कारण

आतंकवाद के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है –

1. **अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मूल कारण –** ''किसी आतंकवाद एवं राजविद्रोह का मूल कारण आर्थिक असमानता और भेदभाव की नीति के साथ किसी वर्ग विशेष को सामाजिक न्याय से वंचित कर दिया जाना है। जब बहुसंख्यक दबंग समूह किसी अल्पसंख्यक दलित वर्ग का लगातार आर्थिक शोषण करता है, राजनैतिक और सामाजिक तौर पर उपेक्षित और तिरस्कृत किया जाता है। मूल अधिकारों एवं मानव–अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है तब वह कमजोर अल्पसंख्यक समूह उस बहुसंख्यक समूह द्वारा चलाए गए शासन तंत्र के खिलाफ राजविद्रोह एवं अलगाववादी आतंकवादी गतिविधियाँ करने पर मजबूर हो जाता है।''[224]
2. **भ्रष्टाचार –** नवयुवक वर्ग राजनीतिज्ञों, उच्च नौकरशाहों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के अनुचित और भ्रष्ट आचरण से धैर्य खो देता है और आतंकवाद की ओर अग्रसर हो जाता है। आज कोई भी कार्य चाहे वह सरकारी हो या गैर–सरकारी, बिना रिश्वत दिये नहीं होता और पैसे देकर कोई भी असंवैधानिक एवं गैर–कानूनी कार्य करवाया जा सकता है। पैसे देकर समाज का धनी वर्ग अपने नैतिक एवं अनैतिक कार्यों को आसानी से करवा लेता है जबकि गरीब वर्ग पैसे के अभाव में अपने सभी कार्यों से वंचित

---

[222] Hindustan Times, 6 Aug. 2004, New Delhi

[223] डॉ. राजेश जैन, ''भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयवाद समस्या एवं निदान'', प्रतियोगिता दर्पण, जुलाई 1998, पृष्ठ संख्या – 2108

[224] डॉ. आर.एस.सिवाच एण्ड डॉ. हरवीर सिंह, ''इटियोलोजी ऑफ टेररिज्म इन साउथ एशिया'', इंडियन जर्नल ऑफ एशियन अफेयर्स में प्रकाशित, वोल्यूम – 15, दिसम्बर 2002, नं. 2, 4/87– जवाहर नगर, जयफर (राजस्थान), पृष्ठ संख्या – 49

रह जाता है। इस कारण गरीब वर्ग में घोर निराशा एवं हीन भावना पैदा हो जाती है। फलस्वरूप यह वर्ग शासन का विद्रोही होकर देशद्रोह और आतंकी गतिविधियों की तरफ अग्रसर हो जाता है।

3. **शोषण और अन्याय की प्रवृत्तियाँ –** आतंकवाद की स्थिति के लिये केवल आतंकवाद ही दोषी नहीं है, वरन् अन्याय और शोषण की प्रवृत्तियाँ भी समान रूप से उत्तरदायी रही हैं। राज्य विधानमण्डलों ने अनेक भूमि सुधार कानून पारित किये लेकिन राज्यों में भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। भूमि सुधार कानूनों का क्रियान्वित न होना, नक्सलवादी आतंकवाद का और बिहार जैसे राज्य में 'जातीय हिंसा' का एक प्रमुख कारण है।
4. **युवकों में तीव्र असन्तोष –** बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद आदि अनेक कारणों से युवकों में असन्तोष व्याप्त है। यह असन्तोष जब गम्भीर रूप धारण कर लेता है तो वे आतंकवाद की ओर अग्रसर हो जाते हैं।
5. **अवैध शस्त्र व्यापार –** वर्तमान में अवैध शस्त्र व्यापार इतना अधिक बढ़ गया है कि आधुनिकतम और भयानक शस्त्रों को अवैध रूप से प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं रह गया है। ऐसे अवैध शस्त्रों की सहज उपलब्धि के कारण आतंकवाद गम्भीर रूप ले लेता है।
6. **आतंकवादियों को विदेशी सहायता** – विश्व में ऐसे अनेक देश हैं जो आज भी आतंकवादियों को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। दूसरे देशों को आतंकवाद रोकने में सहायता नहीं देते वरन् दूसरे देशों में अस्थिरता उत्पन्न करने के लिये आतंकवादियों को आर्थिक और राजनीतिक सहायता प्रदान करते हैं। भारत के आतंकवादी गुटों को विदेशी शक्तियों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष समर्थन एवं सहायता प्राप्त हो रही है। पाकिस्तान इसी प्रकार से भारत में आतंक फैला रहा है।
7. **दलीय राजनीति –** राजनीतिक दल अपने वोट–बैंक को बढ़ाने के लिए कोई भी अनुचित कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। राजनीति में सलंग्न व्यक्ति अनेक बार व्यक्तिगत और राजनैतिक लाभ के लिये अपराधी एवं आतंकवादी तत्त्वों को प्रश्रय देते हैं। कई बार राजनीतिक दल आतंकवादी संगठनों का सहयोग लेते हैं।
8. **न्याय में विलम्ब –** एक बार आतंकवाद का उदय होने के बाद उसे जल्दी समाप्त कर पाना तभी सम्भव हो सकता है जबकि प्रशासन की विभिन्न इकाइयों में परस्पर समन्वय हो। न्याय व्यवस्था ऐसी हो जिसमें आतंकवादी तत्काल दण्डित हो सके लेकिन न्यायालय विचाराधीन मामलों के निस्तारण में अनेक वर्ष लगा देते हैं जिससे आतंकवादी निर्भीक होकर अपना कार्य करते रहते हैं।

9. **आर्थिक क्षेत्र में संतुलित विकास का अभाव –** अविकसित क्षेत्रों में आतंकवाद के बीज पनपते हैं। जब शिक्षा, जल, स्वास्थ्य, यातायात, संवादवाहन, कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की सुविधायें समान रूप से नहीं दी जाती है। जिस कारण से जनता में असंतोष पैदा होता है और यही असंतोष की भावना उनमें आतंकवाद के बीज बो देती है।

10. **राष्ट्रीयता की पहचान –** "उपनिवेशों की समाप्ति की प्रक्रिया में अनेक छोटे–बड़े राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्त करते चले गए। इन राष्ट्रों में कुछ विशेष जातीयता एवं धार्मिक समूह अपनी पहचान के लिए पृथक्क राष्ट्रों की माँग करने लगे जिसके लिए इन समूहों ने संगठित एवं सुनियोजित आंदोलन प्रारंभ किए जिसमें आतंकवादी गतिविधियों का प्रयोग किया गया। यह राष्ट्रीयताओं के लिए लड़ा जाने वाला आतंकवादी युद्ध आज भी श्रीलंका, चेचन्या (रुस), भारत आदि देशों में जारी है। यह आतंकवाद संबंधित देशों की सरकारों द्वारा इनकी कार्यवाहियों एवं संगठनों को अवैध घोषित कर दिये जाने से और अधिक उग्र रूप धारण करता चला जाता है।"[225] इन संघर्षरत राष्ट्रीयताओं का संबंध धार्मिक, सामाजिक या वैचारिक आधार पर अन्य राष्ट्रीयताओं से होता है जिससे इन्हें हथियारों, धन आदि की सहायता प्राप्त होने लगती है जो सुनियोजित, संगठित एवं प्रायोजित आतंकवाद को जन्म देती है।

11. **राष्ट्रों के राजनीतिक, सामरिक एवं आर्थिक हितों में टकराव –** आतंकवाद को बढ़ावा देने में कुछ राष्ट्र एवं देश अपने राजनीतिक, सामरिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा के लिए रूचि लेते हैं तथा सुनियोजित तरीके से संघर्षरत गुटों को आतंकवादी गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित एवं सहायता करते हैं। भारत में पाकिस्तान द्वारा कराई जा रही आतंकवादी गतिविधियाँ इसका अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार अमेरिका की आतंकवाद के संबंध में अपनी विदेश नीति की कुटिल कूटनीति भी आतंकवाद को पल्लवित करने के लिए उत्तरदायी रही है। अमेरिका ने अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने के लिए अनेक आतंकवादी संगठनों एवं आतंकवादियों जिसमें ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में रूस की सेना को बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने ही सशक्त किया था। अमेरिका के विरुद्ध जो भी आतंकवादी संगठन या आतंकवादी कार्य करने लगते हैं यह उनका अंत करने के लिए कार्य करने लगता है। अफगानिस्तान पर आक्रमण इसी नीति का परिणाम है। अन्य आतंकवादी संगठनों के विषय में यह निष्क्रिय हो जाता है जैसे कश्मीर में व्याप्त आतंकवाद पर अमेरिका की पहल न करना।

---

[225] डॉ. अर्चना उपाध्याय, "भारतीय विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय संबंध", 2005, संजय प्रकाशन, 4378/4–बी, 209 जे.एम.डी. हाउफस गली मुरारीलाल, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, फोन नं. 23245808, पृष्ठ संख्या – 220–221

12. **अल्पसंख्यकों के प्रति सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीति** – उनके राष्ट्रों में अलगाववाद और आतंकवाद का कारण वहाँ की राष्ट्रीय सरकारों द्वारा किसी जाति विशेष या क्षेत्र विशेष की उपेक्षा करना भी है। उनकी समस्याओं का समाधान न करना, वहाँ समुचित विकास कार्य के प्रति उत्साहित न होना और उनकी राष्ट्रीय राजनीति में सहभागिता को महत्त्व प्रदान न करना उन लोगों में हीन भावना को जन्म देती है। राजनीतिक, आर्थिक एवं नागरिक अधिकारों से उन्हें वंचित किये जाने पर उनमें कुंठा जन्म ले लेती है जो विद्रोह, हिंसा और अलगाववादी प्रवृत्ति को जन्म देती है। कल्याणकारी योजनाओं की कमी के कारण रोजगार के अवसरों की कमी होने से यह बेरोजगार, विद्रोह भावना वाले नवयुवक आतंकवादी संगठनों को जन्म देते हैं या फिर इन संगठनों के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं जिनका उद्देश्य होता है अपने को राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग करना, भारत में उत्तर–पूर्व के राज्य और कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के अस्तित्व के पीछे यह प्रमुख कारण रहा है।

13. **सामरिक दुर्बलता** – आतंकवाद का सहारा प्रायः वह जातीयता समूह या अलगाववादी संगठन लेते हैं जो प्रत्यक्ष युद्ध करने में सामरिक रूप से सक्षम नहीं होते। इसका कारण यह है कि कोई भी आंदोलनकारी या पृथक्कतावादी संगठन धीरे–धीरे विकसित होता है जिसका साथ में दमन भी चलता रहता है। अतः वह यकायक एक साथ इतना सशक्त नहीं हो पाता कि आमने–सामने की लड़ाई में विजय प्राप्त कर सके। परिणामस्वरूप अपना अस्तित्व बनाए रखने, विद्रोह को प्रदर्शित करने, सरकार का या विश्व जनमत का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों को कार्य रूप में परिणित करते रहते हैं। जिससे जनता में भय व्याप्त होता है और सरकार पर दबाव बनाने में सफलता मिलती है।

14. **सूचना प्रौद्योगिकी** – पिछले दो दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति हुई है जिससे संचार के त्वरित प्रभावी एवं विश्वव्यापी साधन उपलब्ध हो गए हैं। इंटरनेट, पैफक्स, सैटेलाइट फोन आदि के माध्यम से किसी भी समय कहीं पर भी दूर बैठकर सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जा सकता है। आतंकवादी संगठनों ने भी इस तकनीक का तुरंत एवं प्रभावी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। उनके अपने बेवसाइट हैं जो इंटरनेट पर जारी रहती है। इनके माध्यम से आतंकवादी कार्यों को तेजी से अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। ''अमेरिका का 11 सितंबर की दुर्घटनाओं की योजना को आतंकवादियों ने बेवसाइटों के माध्यम से ही सफल बनाया। सूचना तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों ने आतंकवाद को जन्म तो नहीं दिया लेकिन इसे सुगम बनाकर नई दिशायें प्रदान की है।''[226]

[226] वही, पृ.सं. – 222

15. **अवैध व्यापार और मादक पदार्थों की तस्करी –** अवैध व्यापार आज व्यापार का दूसरा महत्त्वपूर्ण विकल्प बन गया है आज का युवा कम समय में अधिक पैसा जुटाने की नियत से बेहिचक उस दल–दल में पंफसता जा रहा है। फिर चाहे वह हथियारों की तस्करी हो या नकली नोटों का व्यापार या फिर मादक पदार्थों का फैला जाल, ये सभी महत्त्वाकांक्षी युवकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं विश्व के लगभग आधे से अधिक देशों में यह कारोबार फैला है अरबों डॉलर के इस कारोबार में लाखों की संख्या में लोग लगे हैं। आतंकवादियों को इन्हीं स्त्रोतों से अत्यधिक धन प्राप्त होता है जिनका उपयोग वे अपनी कुत्सित योजनाओं में करते हैं।

16. **गुप्तचर सेवाओं और शासन की विफलता–** ''गुप्तचर एजेन्सियों का नाम ले तो केवल दो नाम उभर का आता है पहला सी.आई.ए. (अमेरिकी एजेन्सी) दूसरा आई.एस.आई. (पाकिस्तानी एजेन्सी) एक सुविख्यात है तो दूसरी कुख्यात। अन्य देशों की एजेन्सियाँ सामान्य ढ़ंग से भी काम करने में असमर्थ हैं। भारत को ही ले लीजिए हमारे पास आई.बी., सी.बी.आई. और रॉ जैसी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की एजेन्सी हैं फिर भी इनके कारनामे जगजाहिर हैं।''[227] केवल यह कह देना कि अमुक राज्य या क्षेत्र अथवा अमुक व्यक्ति को आतंकवादियों से खतरा है, उनका काम पूरा नहीं हो जाता बल्कि उन्हें यह भी पता लगाना चाहिये कि कैसा खतरा है कब और कौन उस खतरे को अंजाम देने वाला है और वारदात से पहले उसे कैसे विफल किया जाये। कारगिल में पाकिस्तान ने आगे बढ़कर चौकियाँ बना ली हमारी किसी भी एजेन्सी को भनक तक नहीं लगी। श्रीमती इन्दिरा गाँधी, राजीव गाँधी व अन्य विशिष्ट लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गये लेकिन इसे रोकने में गुप्तचर एजेन्सियाँ नाकामयाब रहीं। शासन का ढुलमुल और अतिवादी रवैया भी आतंकवाद पैदा होने और बढ़ने देने के लिए जिम्मेदार है आतंकग्रस्त क्षेत्रों में तो यह हालत बद से बदतर है। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी निर्भीक और ईमानदारी से कार्य नहीं कर रहा है। कोई वहाँ अपनी पोस्टिंग नहीं करना चाहते हैं। इससे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता है और जनता हतोत्साहित होती है।

17. **नैतिक शिक्षा का अभाव –** ''विद्यालयों और समाज में नैतिक शिक्षा के पतन से देश भक्तों की संख्या घट रही है लोग धन के लिये राष्ट्रद्रोह की सीमा तक जा रहे हैं। रक्षा, सुरक्षा अध्ययन और नैतिक शिक्षा जैसे विषय अनिवार्य होना चाहिये लेकिन आज ये विषय अनावश्यक समझे जाते हैं। आचरण और ज्ञान के अभाव में आतंक विरोधी प्रवृत्ति उभर नहीं पा रही है।''[228]

---

[227] डॉ. आर.बी.सिंह, ''भारत में आतंकवाद'', 2010, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, फोन – 23247003, पृष्ठ संख्या – 38–39

[228] वही, पृ. सं. – 39

18. **नैतिक मूल्यों में गिरावट** – पहले हर परिवार में बच्चों को सत्य, अहिंसा और सच्चे आचरण, कर्त्तव्यों की शिक्षा दी जाती थी, कुरीतियों से उन्हें दूर रखा जाता था। शिक्षा और ज्ञान–विज्ञान का प्रमुख स्थान था। समाज विरोधी तत्त्वों को सामूहिक बहिष्कार झेलना पड़ता था लेकिन आज उसके विपरीत कोई भी धनाढ्य व्यक्ति येन–केन प्रकार से धन अर्जित कर समाज का अगुआ बन जाता है लोग उसके आचरण पर ध्यान न देकर उसकी इज्जत करते हैं। इस वातावरण में भ्रष्टाचार और आतंकवाद को बल मिलता है। नैतिक मूल्यों के पतन से समाज और राष्ट्र को नहीं अपितु धन को प्रधान बना दिया गया है चाहे वह जिस तरह से अर्जित किया जाये।

आतंकवाद के अन्य कारण

1. आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा के अभाव में उसके विरूद्ध कठोरतम कानूनों का न बन पाना भी एक कारण है।
2. ''धार्मिक उन्माद के कारण ही व्यक्ति आतंकवाद जैसी गतिविधियों में लिप्त हो जाता है तथा धर्म की रक्षा करने के लिए वह हत्या विस्फोट तथा आगजनी जैसे कार्य करता है। ओसामा बिन लादेन का तालिबानी आतंकवाद भी पूर्णतया धार्मिक उन्माद पर आधारित था।''[229]
3. वर्तमान के आतंकवाद का प्रमुख कारण युवा वर्ग में विचलन की प्रवृत्ति का पाया जाना है। आज का युवा वर्ग बिना परिश्रम किये हुए अधिक धन कमाना चाहता है। यदि इन्हें एक ऐश्वर्य पूर्ण जीवन का लालच दे दिया जाता है तो बड़े से बड़ा हिंसक तथा अमानवीय कार्य कर सकते हैं।
4. न्यून–तीव्रता संघर्ष (LIC) की नीति आतंकवाद पर आधारित है इसलिए आतंकवाद का प्रमुख कारण राजनीतिक कूटनीतिक चालें हैं जब एक देश अपनी सैनिक शक्ति की सहायता से दूसरे देश को नुकसान पहुँचाने की स्थिति में नहीं होता तब वह आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षित करके तथा उन्हें हथियारों, विस्फोटक पदार्थों तथा धन की मदद देकर उनसे हिंसा और तोड़–फोड़ करवाता है।
5. ''संसार के अनेक देशों की भौगोलिक दशायें इस तरह की होती है कि वहाँ की सरकार को आर्थिक उपार्जन नहीं प्राप्त हो पाता है तब मादक पदार्थों, हथियारों तथा दूसरी वस्तुओं की तस्करी के द्वारा आर्थिक साधन प्राप्त करने के प्रयत्न किये जाने लगते हैं जो आतंकवादी संगठनों की आड़ में सम्पन्न होते हैं।''[230]

---

[229] डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव, ''वैश्विक आइने में आतंकवाद : वर्तमान परिदृश्य एवं भविष्य की चुनौतियाट्ट'', 2011, ओमेगा पब्लिकेशन्स, 4378/4बी, जी–4,जे.एम.डी. हाउस गली मुरारीलाल, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, फोन 65901906, पृष्ठ संख्या – 48

[230] वही, पृ.सं. – 49

6. हिंसा आतंकवाद का सबसे प्रमुख आधार है। आतंकवादी संगठनों से केवल वही लोग जुड़े होते हैं जो हिंसक मनोवृत्ति के होते हैं। जिनके सामने मानवीय मूल्यों का कोई महत्त्व नहीं होता है। आतंकवाद चाहे बंगाल, बिहार और आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवाद की रूप में हो, आसाम और नागालैण्ड के उल्फा या बोडो संगठन के रूप में हो सभी आतंकवादी संगठन हिंसा के द्वारा ही अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
7. बढ़ती हुई आर्थिक विषमतायें आतंकवाद का प्रमुख कारण है। जब कुछ लोग काला बाज़ारी, तस्करी और भ्रष्टाचार के द्वारा बहुत सम्पन्न बन जाते हैं जबकि अनेक क्षेत्रों में अधिकांश लोगों को भरपेट भोजन नसीब नहीं होता है तो लोगों के बढ़ते हुए असन्तोष से वर्ग विद्वेष, अशान्ति और संघर्ष को प्रोत्साहन मिलने लगता है। ऐसा असन्तोष जब संगठित रूप लेने लगता है तो इसी देश के अन्दर आतंकवाद में वृ(होने लगती है।
8. वर्तमान युग लोकतन्त्रा का युग है। आज संसार के अधिकांश देशों में जनता द्वारा ही किसी विशेष राजनीतिक दल को शासन के लिए चुना जाता है। विभिन्न दलों का अन्तिम हथियार आतंकवाद और दबाव द्वारा अपने विरोधी लोगों को वोट देने से रोकना और समर्थक लोगों से जाली वोट डलवाना होता है। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा ये काम करवाया जाता है। इन लोगों को जब भ्रष्ट नेताओं का संरक्षण मिलने लगता है तो यही लोग अपहरण, हत्यायें, आगजनी और लूटपाट के द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने लगते हैं।
9. प्रचलित व्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक पतन और भंजन।
10. असन्तोष की भावना का लगातार व्याप्त रहना और वैधानिक तरीके से इसका निराकरण न हो पाना।
11. लोकतान्त्रिाक खुलेपन के कारण धन व हथियारों का बाहर के देशों से प्रवेश।
12. मानवाधिकारों व जनमत के प्रति संवेदनशीलता के कारण सशक्त कार्यवाही सम्भव न हो पाना।
13. हथियारों के मामले में तकनीकी प्रगति।
14. आतंकवाद को आपराधिक कार्य के रूप में स्थापित करने में अन्तर्राष्ट्रीय समाज की विफलता।
15. पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियाँ।
16. राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा व धार्मिक उन्माद।
17. आय विषमता, जातीय तनाव, मुद्रास्फूर्ति, बढ़ती आबादी।
18. आतंकवाद की घोर निन्दा व भर्त्सना न कर पाना।
19. न्यायिक तन्त्रा की असफलता।
20. प्रशासन की ढुलमुल नीति।

21. गैर–जिम्मेदार सरकार वह जो शासन तन्त्रा पर जमी रहती है मगर उसके काम वास्तव में लोगों की उचित समस्या में सुलझाने की दिशा में नहीं।
22. राष्ट्रीय विचारधारा का अभाव।
23. इस तरह आतंकवाद के कई कारक हैं ''कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं। धर्मान्धता भी आतंकवाद का एक कारण है। दार्शनिक विचारधाराएँ, यथा क्रमिक संघ कभी अराजकतावादी भी आतंकवाद को प्रोत्साहित करती हैं। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक कारण भी कम उत्तरदायी नहीं हैं। क्षेत्रवाद, भाषावाद और हमारे नैतिक मूल्यों का पतन भी आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है।''[231]

''पाक प्रायोजित आतंकवाद भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है अभी तक आतंकवादी पारम्परिक हथियारों से आतंकवादी कार्यवाही को अन्जाम देते रहे हैं।''[232] अब यह एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है कि यदि आतंकवादियों के हाथ ए.बी.सी. (Atomic, Biological, Chemical Weapons) वेपन्स लग गया तो क्या होगा?

पाक प्रायोजित आतंकवाद के कारण[233]

1. 1947–48, 1965, 1971 और 1999 में भारत–पाकिस्तान के पारम्परिक युद्धों में पाकिस्तान की करारी हार के कारण वह कश्मीर को प्राप्त नहीं कर सका तो अन्त में स्प्ब (न्यून तीव्रता संघर्ष) और छापामार युद्धकर्म का सहारा लेते हुए आतंकवाद रूपी हथियार को अपना लिया।
2. पाकिस्तान भारत से जन्मजात शत्रुता रखता है।
3. पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ है।
4. पाकिस्तान की आन्तरिक राजनीति भारत विरोध पर आधारित हो गयी है।
5. पाकिस्तान में सेना का प्रभाव सर्वाधिक है और सेना चार बार पाकिस्तान का तख्ता पलट कर सत्ता पर भी काबिज हो चुकी है।
6. आई.एस.आई. (पाकिस्तानी गुप्त संस्था) हर समय भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहती है।
7. पाकिस्तान 1971 में हुए हार का दंश भुला नहीं पाया है और वह इससे उत्पन्न कुण्ठा को भारत विरोधी गतिविधियों एवं आतंकी कार्यवाहियों द्वारा निकालता रहता है।

---

[231] डॉ. धीरेन्द्र द्विवेदी, संजय कुमार, अनुराग जायसवाल, गुलाबचन्द्र ललित, ''अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति'', 2006, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली–110094, पृष्ठ संख्या – 194

[232] डॉ. अतुल चन्द, डॉ. अजय कुमार– ''पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद : भारत के लिये गम्भीर खतरा'', सम्पादक – नर्वदेश्वर शुक्ल, डॉ. गुलाब चन्द्र ललित, ''भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में हिमालयी क्षेत्रा का स्त्रातेजिक महत्त्व'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स्, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, फोन नं. 23255141, पृष्ठ संख्या–216

[233] वही, पृ. सं. – 217

8. तालिबान इस्लामिक जिहाद के नाम पर पाकिस्तान में आतंकी कार्यवाहियों की झड़ी लगा दी है और इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा है।
9. पाकिस्तान धार्मिक जिहाद के नाम पर इस्लामिक राष्ट्रों से भारी आर्थिक सहायता प्राप्त करता है और इसका एक बड़ा हिस्सा भारत विरोधी गतिविधियों में लगाता है।
10. चीन भारत में अशान्ति फैलाने के लिये पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है।
11. विश्व के कुछ देश जो भारत की प्रगति से ईर्ष्या रखते हैं वह पाकिस्तान के द्वारा भारत में अस्थिरता फैलाकर भारत की प्रगति में बाधा पहुँचाना चाहते हैं।
12. हथियार आपूर्तिकर्त्ता देश भी भारत–पाकिस्तान के तनाव को बनाये रखना चाहते हैं जिससे उनके हथियारों का व्यापार निर्वाद रूप से चलता रहे।
13. आतंकवादी कार्यवाहियों के द्वारा कश्मीर में अस्थिरता फैलाकर पाक विश्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता है।
14. 1947–48 के कबायली आक्रमण के तर्ज पर आतंकवादी आक्रमण द्वारा कश्मीर में कब्जा करने का प्रयास करता रहता है।
15. भारत को अस्थिर करने हेतु वह कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूरे भारत में आतंकवादी कार्यवाहियों को बढ़ावा दे रहा है।

खुफिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख ए.के. डोभाल कहते हैं, ''यह एक अहम स्वीकारोक्ति है अब यह स्पष्ट हो चुका है कि इस्लामी आतंकवादी पाकिस्तानी सेना के अभिन्न हिस्से हैं और वे एक–दूसरे के लिए काम करते हैं – यह युद्ध करने की एक मशीन बन गया है और हमें भी अपनी तकनीक में उसी हिसाब से संशोधन करना पड़ेगा।''[234]

वर्तमान में पाक प्रायोजित आतंकी भारत की एकता और अखण्डता को छिन्न–भिन्न करने के लिए नये–नये समीकरण अपना रहे हैं। अक्टूबर 1993 में श्रीनगर स्थित हजरत बल दरगाह में आतंकवादियों का कब्जा और उसके फलस्वरूप धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश, 1999 में आई.सी. 814 विमान का अपहरण, 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू–कश्मीर विधान सभा के बाहर हमला, 24 सितम्बर 2002 को गाँधीनगर स्थित अक्षरधाम मन्दिर पर सशस्त्र आतंकियों द्वारा हमला, 13 अक्टूबर 2001 भारतीय संसद पर हमला जिसके बाद 1 वर्ष सीमा पर भारतीय सेना जमी रही और युद्ध जैसी स्थिति भारत व पाकिस्तान के मध्य बन गयी। मई 2002 को कालूचंक में हमला, 25 अगस्त 2005 को मुम्बई के प्रसिद्ध मुम्बादेवी मन्दिर पर बम विस्फोट, 11 मार्च 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मन्दिर परिसर में बम विस्फोट, जुलाई 2006 में भाले गाँव एवं ट्रेमो (मुम्बई) में बम विस्फोट, 05 जुलाई 2005 को अयोध्या में पवित्र

---

[234] प्दकपंद जवकंलए 11 वबजण 2006

रामजन्मभूमि परिसर में आत्मघाती हमला इस आतंकी कार्यवाहियों के ये कुछ उदाहरण हैं।

24 अक्टूबर 2000 को इण्डियन एयर लाइंस के विमान आई.सी. 814 का अपहरण नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्ड़े से करा लिया गया अपहरणकर्त्ता विमान को तालिबान शासित देश अफगानिस्तान के कंधार शहर ले गये जहाँ से उन्होंने अपने तीन आतंकवादियों 'मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर तथा अमर शाहिद शेख' की रिहाई की माँग की। तत्कालीन भारत सरकार के विदेश मंत्री जसवंत सिंह व शरद यादव अपने साथ इन आतंकियों को लेकर कंधार छोड़ आये, बाद में यही मौलाना मसूद अजहर का आतंकी संगठन ने भारतीय संसद पर हमला किया।

2

प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का अध्ययन (Analytical Study of the Activities of Some Prime International Terrorist Organizations)

आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और विश्व के लगभग सभी देश कम या ज्यादा इससे प्रभावित हैं या प्रभावित रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश आज दहशतगर्दी से बचा नहीं है। तथ्य बताते हैं कि दहशतगर्दी का सबसे खौफनाक मंजर मध्य–पूर्व या एशियाई देशों में देखने को मिलता है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया के इन गरीबतम देशों में ही भीषणतम आतंकवाद देखने को मिलता है। एक ओर तो यहाँ की जनता दाने–दाने को मोहताज है और दूसरी और कुछ आतंकवादी संगठन सरकार से अपनी माँगे मनवाने के लिए गरीब, मासूमों का खून सरेआम सड़कों पर बहाते हैं। **एशियाई आतंकवाद की प्रमुख खासियत यह है कि यहाँ चलने वाला अधिकतर आतंकवाद, पृथक्तावादी है, ये आतंकवादी गिरोह किसी समुदाय विशेष के लिए अलग राज्य, अलग सत्ता की माँग कर रहे हैं।** ''आतंकवाद का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि इसका शिकार अधिकतर गरीब , मजलूम, लाचार और अभावों से ग्रस्त आम जनता ही बनती है।''[235]

यदि किसी से यह पूछा जाये कि नेपाल, इजरायल, फिलीस्तीन, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, एवं श्रीलंका जैसे देशों में क्या समानता है, तो उन्हें बताने में देर नहीं लगेगी कि वहाँ आतंकवादियों ने सरकारों का जीना मुहाल कर रखा है। भूगोल के विद्यार्थी के लिए इसमें एक तथ्य यह भी जुड़ जाएगा कि ये सभी देश एशिया महाद्वीप में हैं। यह महाद्वीप हिंसा और आतंक का प्रतीक बनता जा रहा है। फिर भी यहाँ के नागरिकों को यह चिंता क्यों नहीं सताती कि आखिर संगठित हिंसा के अभिशाप का केन्द्र बिन्दु एशिया ही है? विश्व के नक्शे को गौर से देखने से पता लगता है कि प्रकृति ने इस भू–भाग पर बहुत मेहरबानी की है, अकूट प्राकृतिक संपदा दी है। लेकिन जहाँ पड़ोसी महाद्वीप यूरोप अपने लिए एक जैसी मुद्रा जारी कर रहा है, अबोध व्यापार के लिए देशों की सीमाएँ खत्म कर रहा है और पूरे महाद्वीप के लिए एक सर्वोच्च अदालत गठित कर रहा है, वही हम अभी भी जाति और धर्म के झगड़ों में फंसे हुए हैं। हम अपने आपको बाँटने का बहाना ढढ्ढ़ते रहते हैं और अपने विरोधियों को मारने पर आमदा हैं। अभी हम सह–अस्तित्व के महत्त्व को समझ नहीं पाए हैं। कहने को तो हमने लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसके मर्म को समझने और मानने से कतराते हैं। लोकतंत्र हमें अपने

235 नरेन्द्र कुमार शर्मा, ''भारत में नक्सलवाद'', 2012, ओमेगा पब्लिकेशन्स, 4378/4 बी, जी–4जे.एम.डी. हाऊस, गली मुरारीलाल, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, फोन 65901906, पृष्ठ संख्या – 172

विरोधियों के साथ जीने की और उस विरोध की ताकत से समाज को बेहतर बनाने की कला सिखाता है। हम अभी भी अपने विरोधी को अपना दुश्मन मानने के कबीलाई मनोविज्ञान के साथ जी रहे हैं और किसी भी तरह उसे समाप्त करने में यकीन रखते हैं।

"एशिया वह महाद्वीप है, जहाँ भगवान बुद्ध जैसे महापुरूष पैदा हुए और उन्होंने लोगों को मध्यम मार्ग अपनाने का संदेश दिया"[236] लेकिन दुर्भाग्य से एशिया अमेरिकी संस्कृतियों तथा उनके अन्तर्विरोधों को झेल रहा है। एक ओर, तालिबान जैसी सोच के लोग, जिनका कहा हुआ वाक्य ही कानून है। दूसरी ओर, वे देश भी हैं, जो अति लोकतंत्रीकरण के रोग से ग्रस्त है। लोकतंत्र के उदार सिद्धान्तों का उपयोग जब समाज की उन्नति के लिए होता है, तो वह फलता–फूलता है, लेकिन जब उनका उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए होता है तो उसका क्षरण होता है। एशिया में लोकतंत्र का लाभ वहाँ के असामाजिक तत्त्वों ने उठाया है। उन्होंने उसकी उदार व्यवस्था में संजीवनी ली, अपने को मजबूत किया और अब एक–एक करके लोकतांत्रिक समस्याओं को नष्ट कर रहे हैं। इसका दोहरा असर हो रहा है। एक ओर, इस व्यवस्था का लाभ उठाने वाले लोग ताकतवर होकर लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। दूसरी ओर, इस अतिलोकतंत्रीकरण के दुरूपयोग को देखकर आम नागरिक का लोकतंत्र से विश्वास उठता जा रहा है। हमें प्रयास करने की जरूरत है। **लोकतंत्र के उदार स्वरूप का दुरूपयोग करने वालों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके।**

एशियाई समाज की अज्ञानता उसका बहुत बड़ा अभिशाप है और यही उसके शासक वर्ग की सबसे बड़ी ताकत है। वहाँ का शासक उस समाज की अज्ञानता का लाभ उठाता है और और अपना हित साधता है। संविधान और कानून को आदर्श समाज की जरूरतों के मुताबिक तैयार किया गया है, लेकिन उसे लागू करने की जमीन अभी परिपक्व नहीं हो पाई है। संविधान या कानून केवल संसद में पारित कर देने मात्रा से लागू नहीं हो जाते। वे तो सब लागू हो पाते हैं, जब वहाँ का समाज उन्हें आत्मसात कर ले। जब समाज का बड़ा वर्ग किसी कानून को स्वीकार करके अपने स्वभाव में ढ़ाल लेता है और समाज का छोट–सा वर्ग उसका उल्लंघन करता है तो कानून का पालन सुनिश्चित करना संभव हो पाता है। एशियाई देशों में कानून बनाकर कर्त्तव्यों को पूरा कर लिया जाता है। जनचेतना जागृत करने के प्रयास नहीं होते, इसलिए कानूनों को लागू करना बहुत कठिन होता है। इसका दूसरा यह है कि इस भू–भाग के लोकतांत्रिक देशों में विपक्ष ने सत्तादल के अंधविरोध की नीति अपना ली है। वे अक्सर 'अपना उल्लू सीधा करने' के लिए सरकारी कोशिशों के बारे में अधूरी और भ्रामक सूचनाएँ देकर लोगों को बरगलाते हैं और वहाँ के समाज का एक वर्ग उन नीतियों के बारे में जाने बगैर ही उसके विरोध में उतर आता है।

---

[236] वही, पृ.सं. – 174

वैसे तो भारत पिछले 13 से भी अधिक वर्षों से सघन आतंकवादी हमलों को झेल रहा है, लेकिन 13 दिसम्बर 2001 को आतंकवाद ने देश के सर्वोच्च प्रतीक संसद पर फिदायीन (आत्मघाती) हमला करके जो संकेत दिया है वह ऐतिहासिक चेतावनी के महत्त्व का है। यह हमला मुम्बई में पकड़े गए एक आतंकवादी के इकबालिया बयान के मुताबिक 11 सितंबर को ही होना था। भारतीय संसद के साथ आस्ट्रेलियाई और ब्रिटेन की संसद भी इसी दिन आतंकवादी निशाने पर थी। निश्चय ही यह अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामिक आतंकवाद की करामातों की एक कड़ी है। इसे छोटा करके नहीं समझना चाहिए। इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। यह घटना तब हुई है जब अफगानिस्तान में तालिबान पिट चुके हैं। कट्टरपंथियों के गढ़ को बहुत बड़ी हद तक क्षत–विक्षत कर दिया गया है। पाकिस्तान का मान–मर्दन हो चुका है। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को भी एक करारा झटका लगा है। भारतीय संसद पर होने वाले इस हमले का यह साफ अर्थ है कि इस्लामिक आतंकवाद का अगला मुख्य निशाना भारत होगा। हो सकता है अफगानिस्तान में राजकाल पटरी पर लाने और अन्तर्राष्ट्रीय फौज के मुकाबले कट्टरपंथी अगले कुछ वर्षों के लिए कुछ न कुछ कर सकें मगर कट्टरपंथियों का सपना ध्वस्त नहीं हुआ हैं। भारत में वह स्वाभाविक रूप से सफलता के आसार देख सकते हैं। भारत में उनका मुकाबला विश्व की सबसे बड़ी शक्ति से नहीं, एक नरम राज्य की रक्षा व्यवस्था से होगा। उसे वह अरसे से तौल चुके हैं। वह निर्णायक कोशिश कर सकते हैं। इस्लामिक आतंकवाद के मामले में कुछ बातें साफ है। एक तो यह अन्तर्राष्ट्रीय चरित्र का है और दूसरे यह भविष्य में जारी रहेगा अगर भारत को इस आतंकवाद से निपटना है तो इसे राजनैतिक चश्मे से देखना बंद करना होगा।

कैसी विडम्बना है कि जब संसद पर फिदायीन हमला हुआ उसके ठीक बीस–पच्चीस मिनट पहले संसद के दोनों सदन विपक्ष के हंगामे के कारण पूरे दिन के लिए स्थगित हो गये थे? ऐसा लगातार तीन दिन से हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? सारे अखबारों ने लिखा है कि विपक्ष की रणनीति संसदीय कार्यवाही को जाम कर बाकी दिन भी इसी तरह निकाल कर पोटो को पास करने की संभावना को समाप्त कर देना था। आतंकवाद कितनी बड़ी और कितनी भयावह वास्तविकता है, इसे 13 दिसम्बर के संसद पर हुए फिदायीन हमले ने बिल्कुल साफ कर दिया है, लेकिन भारतीय संसद का विपक्ष 'पोटो' को राजनैतिक और चुनावी चश्मे से देखता है। 'पोटो' के खिलाफ अलोकतांत्रिक संसद जाम की राजनीति पर विपक्ष उतारू रहा। इस फिदायीन हमले में कितने लोगों की जानें गई। सारा देश आतंकित हुआ। लोगों में असुरक्षा का भाव बढ़ा। सुरक्षाकर्मियों और एजेंसियों को आतंकवाद से निपटने के लिए अधिक अधिकार देने वाले 'पोटो' का ऐसा अंधा विरोध, यह एक राष्ट्रीय विडम्बना ही है। इस देश को इतिहास में ऐसी राष्ट्रीय विडम्बनाएँ अक्सर झेलनी पड़ी है। भारत के राजनैतिक पराभव का भी एक प्रमुख कारण भी यही हैं कि सुरक्षा के खतरों के बारे में भी एकता नहीं हो पाती।

मुम्बई ने हमले के बाद वहाँ के बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने जिस प्रकार कट्टरपंथियों की तरह यह राग अलापना शुरू कर दिया है कि भारत तो हर मामले में पाकिस्तान को दोष देने लगता है। इससे यही स्पष्ट हुआ कि अपनी खामियों को न मानना, उनसे अनजान बने रहने का ढ़ोंग करना या फिर उनसे कन्नी काट लेना पाकिस्तान का राष्ट्रीय चरित्र बन गया है। अब भारत की पहली प्राथमिकता पाकिस्तान के इस चरित्र को बेनकाब करने की होनी चाहिए। उसका यह चरित्र अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर होना चाहिए। यह तब होगा जब अभूतपूर्व कूटनीतिक सक्रियता का परिचय दिया जाएगा। पाकिस्तान को अहसास होना ही चाहिए कि भारत उसकी घेराबंदी कर रहा है और इस बार उसे बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ''मुम्बई में होने वाले आतंकी हमले को लगभग साठ घण्टों के बाद समाप्त किया जा सका। कहा जाता है कि इस दुर्घटना में 183 लोग मारे गये और 350 लोग घायल हुए। प्रायः आतंकी घटना घटने के बाद पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। ऐसा बहुत कुछ स्वाभाविक भी है, क्योंकि भारत–पाकिस्तान विभाजन से लेकर आज तक दोनों पड़ोसी देशों के सम्बन्ध अधिक मधुर नहीं हो पाये हैं और दोनों ही देश एक–दूसरे पर जासूसी करने का इल्जाम लगाते रहें है, किन्तु विगत दिनों में जब से पाक की राजनीति में परिवर्तन हुआ है और वहाँ की भूतपूर्व प्रधानमंत्री एवं जनप्रिय नेत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो स्वयं आतंकवादी हादसे का शिकार हुई है, तबसे उनके पति जरदारी जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी हैं, लगातार आतंकवादी गतिविधियों की भर्त्सना कर रहे हैं और आतंकवाद के विरूद्ध भारत का साथ देने की बात जोर–शोर से उठा रहे हैं।''[237] भारत की भाँति पाकिस्तान भी आजकल आतंकवादी गतिविधियों से जूझ रहा है। मुम्बई कांड की आलोचना भी सबसे पहले पाक प्रधानमंत्री ने ही की थी।

बहुत संभव है कि पकड़े गये आतंकी पाकिस्तान के नागरिक हो। यह भी सम्भव है कि वे अलकायदा के सदस्य हों। तो भी यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त हादसों में पाक सरकार का हाथ रहा है। क्या अगर आतंकी भारत के नागरिक निकल जायें, तो लोग इसी प्रकार सोचने का प्रयास करेंगे? पाक से कई बार युद्ध भी हो चुका है। शीतयुद्ध भी चलता रहता है, किन्तु एक दशक पूर्व अपने देश में आतंकी घटनाएँ नहीं हो रही थी। आतंकवादी किसी भी देश का नागरिक हो सकता है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि उक्त देश आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाला है। आतंकवाद जैसी मनुष्यता द्रोही प्रवृत्ति के विरूद्ध खड़े होने के पूर्व हमे आतंकवाद की जड़ों की तलाश कर लेनी चाहिए। हमे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। यदि मुसलमानों, ईसाइयों, पंजाबियों, असामियों, आदिवासियों, दलितों आदि को बेवजह सताया या मारा जायेगा, तो इन कौमों के युवा तात्कालिक आक्रोश के कारण आतंकवादी दलों मे शरीक हो

[237] डॉ. प्रभा दीक्षित का लेख – घृणित आतंकवादी खेल का कारण क्या है? स्वतंत्रा भारत, 6 दिसम्बर 2008

सकते हैं। अतः हमे 'अल्पसंख्यकों' के साम्प्रदायिक नरसंहारों को भी आतंकवाद की भाँति ही गम्भीरता से लेना चाहिए। और साम्प्रदायिक उन्मादियों के विरूद्ध भी आतंकवादियों की भट्ठाति पेश आना चाहिए। भारत के राजनैतिक दलों को भी इस आपत्तिकाल में मिलकर देश के हित में विमर्श करना चाहिए और हादसे की आग में राजनैतिक लाभ की रोटी सेंकने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए।

''मुम्बई में हुए आतंकी हमलों में एक बार फिर लश्कर–ए–तैयबा की भूमिका उजागर हुई है। इससे पहले 2002 मे लश्कर ने अहमदाबाद के अक्षरधाम मंदिर पर इस तरह के सीधे हमले किये थे। यह खुलासा किया–फलिस व केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मुम्बई में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान के फरीदकोट के रहने वाले तीन आतंकवादियों ने। गिरफ्तार अजमल आमिर कमाल (फरीदकोट) ने बताया कि उनमें से 12 बंदरगाह नगर कराची से वाणिज्यिक पोत से रवाना हुए थे। यह पोत वियतनाम जा रहा था बाद में वे उतर गए और भारतीय जल क्षेत्र में गेटवे ऑफ इंडिया तक नाव में आए। पाँच समूहों में बट्टटकर इन्हीं एक दर्जन लोगों ने ताज व ओबेराय होटलों में कहर बरपाया। आतंकी सूखे मेवे लिए हुए थे, जिससे संकेत मिलता है कि वे लम्बी लड़ाई के लिए तैयार होकर आए थे। सूत्रों ने कहा कि इन समूहों में कुछ स्थानीय लोग भी शामिल हो गए, जिन्होंने बैग और सूखे मेवे जैसे साजोसामान मुहैया कराए। शुरूआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि आतंकी समूह 21 से 24 नवम्बर 2008 के बीच की रात महानगर में दाखिल हुए। हालाँकि नए सुराग संकेत देते है कि वे 26 नवम्बर 2008 को तड़के भारतीय क्षेत्र में पहुँचे। दुनिया में आतंक फैलाने और अलकायदा के साथ रिश्तों के खुलासे पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद लश्कर मुख्यतः अपने भारतीय संपर्को का इस्तेमाल करता रहा है, जिसमें 'इंडियन मुजाहिदीन' शामिल है। इस बार हालाँकि मुम्बई में आतंकवादी समूह ने खुद हमला करने का फैसला किया।''[238]

''26 नवम्बर 2008 को मुम्बई पर आतंकवादी हमले को पूरी दुनिया ने साट्टस रोककर देखा। यह सुनियोजित हमला 59 घण्टे के बाद तब खत्म हुआ, जब करीब दो सौ लोग मारे गए और इससे दोगुने लोग घायल हो गए, बाहर गोलियों की गड़गड़ाहट और अंदर फंसे लोगों का भय बहुत से लोगों ने साझा किया। पाकिस्तान भी आतंकी हमलों से अनजान नहीं है। यहाँ साल भर में सैकड़ों नागरिक ऐसे हमलों में मारे जा चुके हैं।''[239]

---

[238] राष्ट्रीय सहारा, 26 नवम्बर 2008

[239] कैमिला हयात (पूर्व सम्पादिका – द न्यूज, लाहौर) का लेख – ''सीमा पार की सोच'', दैनिक जागरण, गोरखफर, 8 दिसम्बर 2008

"यद्यपि आज यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान अलकायदा और अन्य तत्त्वों का आधार बनता नजर आ रहा है, लेकिन यथार्थ यह है कि उग्रवाद की अवधारणा विश्व के अनेक भागों में भी जोर पकड़ रही है।"[240]

इधर "पाकिस्तान ने शीत युद्ध का नया पैंतरा चलाते हुए भारत पर आरोप लगा दिया कि भारत के विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने मुम्बई में हुए आतंकी हमले के दो दिन बाद 28 नवम्बर 2008 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति को हमला करने की धमकी देते हुए एक फोन किया है।"[241] जबकि श्री मुखर्जी का कहना है कि मई 2008 के बाद से उनकी जरदारी से कोई बात ही नहीं हुई है। वैसे भी भारत इतना गैर जिम्मेदार नहीं है कि वह इस तरह से धमकी देता फिरे। उधर पाकिस्तान में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भारत से विदेशी मंत्री प्रणव मुखर्जी के नाम से की गई फर्जी कॉल के बाद हाईअलर्ट जारी कर दिया गया था। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में इस जानकारी के साथ दोनों देशों के बीच मुम्बई हमले के बाद उपजे तनाव में बढ़ोतरी और हमले तक की आशंका जतायी गई है। 'डॉन' के अनुसार मुम्बई में आतंकवादी हमले के बाद 28 नवम्बर 2008 को नई दिल्ली से जरदारी को मुखर्जी के नाम से धमकी भरे अंदाज में फर्जी कॉल की गई थी। सूत्रों ने इस कॉल और देश में हाईअलर्ट जारी करने की बात उच्च पदस्थ अधिकारियों के हवाले से फष्टि किये जाने की जानकारी दी है। "इसके अलावा सरकार की ओर से वायु सेना को भी अगले 24 घंटे तक हाईअलर्ट जारी करते हुए भारत की ओर से मुम्बई हमले की प्रतिक्रिया स्वरूप कार्यवाही पर बारीक नजर रखने को कहा गया है।"[242]

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी मीडिया में मुम्बई हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिप्त होने की आशंका जाहिर किये जाने के बाद भारत द्वारा हमला करने की बात कही जा रही है। जरदारी को की गई फोन कॉल को भी भारत की ओर से संभावित हमले की धमकी के रूप में व्याख्या की गयी है। 'डॉन' के अनुसार कॉल करने वाले व्यक्ति ने जरदारी को फोन करने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलिजा राइस को भी फोन करने की कोशिश की लेकिन अमेरिकी अधिकारियों की सक्रिय जाँच पड़ताल के कारण वह कामयाब नहीं हो सका। अखबार ने राजनयिक और सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि इस प्रकरण से दोनों देशों के बीच हमले की आशंका प्रबल होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं में खलबली मच गयी। उच्च पदस्थ कूटनीतिक एवं अन्य स्रोतों ने बताया कि फोनकर्त्ता ने कथित रूप से जरदारी से कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमलों के सरगनों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की तो भारत सैन्य कार्यवाही करेगा। 29 नवम्बर 2008 को कुछ पाकिस्तानी अखबारों और टेलीविजन चैनलों ने यह रिपोर्ट दी कि मुखर्जी ने फोन पर धमकियाँ दी। इन रिपोर्टों में यह स्पष्ट नही किया गया

---

[240] डॉ. कृष्णानन्द शुक्ल, "लाल शीत युद्ध की दास्तान–भारत और पाकिस्तान", 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, दूरभाष 011–23255141, पृष्ठ संख्या – 64

[241] आई नेक्स्ट, मेरठ, 8 दिसम्बर 2008, पृष्ठ संख्या – 14

[242] राष्ट्रीय सहारा, 7 दिसम्बर 2008

था कि यह फोन किसको किया गया था। साथ ही, उनकी रिपोर्टों में स्त्रोतों के अनुसार, भारतीय उच्चायोग के अधिकारी इन रिपोर्टों पर हैरान थे उन्होंने मामले की तह तक जाने के लिए जाँच से ठन कर आने वाली सूचनाओं की क्रॉस चेकिंग भारतीय अधिकारियों से की गई गई। जब यह तथ्य स्थापित हो गया कि किसी फर्जी फोनकर्त्ता ने राष्ट्रपति कार्यालय से सम्पर्क किया था, तो भारत सरकार ने पाकिस्तान को सूचित किया कि 28 नवम्बर 2008 की उस फोन कॉल से उसका कोई लेना–देना नहीं है। एक सूत्र बताया, एक स्पष्ट संदेश भेजा गया कि फोन कॉल फर्जी थी और इस महत्त्वपूर्ण समय में इससे आपसी तनाव नहीं बढ़ना चाहिए। यह अब भी साफ नहीं हो सका है कि फोनकर्त्ता कैसे दो देशों के नेताओं के बीच होने वाली फोन कॉलों से संबंधित प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने में सफल हुआ। सूत्रों ने बताया कि दो देशों के नेताओं के बीच इस तरह के सम्पर्क करने के लिए दोनों देशों के राजदूतों को कई घंटे पहले ही उसकी सूचना दे दी जाती है। पाकिस्तानी दैनिक 'डॅान' की एक रिपोर्ट के अनुसार जब यह फोन कॉल आई तो जरदारी के स्टाफ के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने मुम्बई हमलों के चलते दोनों देशों के बीच बढ़े तनावों के मद्देनजर इस तरह के मौकों के लिए तय मानक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने का फैसला किया। दूसरी ओर ''भारतीय विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को मेरी धमकी भरी फोन कॉल का शिगूफा पाकिस्तान की सोची समझी चाल है। प्रणव ने कहा कि मुम्बई पर आतंकी हमलों में पाकिस्तानी शड्यंत्र की बात से दुनिया का ध्यान बट्टाने के लिए ही पाक ने इस फर्जी कॉल का हौवा खड़ा किया।''[243]

''पाक प्रायोजित आतंकवाद ने आज भारत–पाकिस्तान के मध्य जारी शीत युद्ध को रक्तरंजित जामा पहना दिया है जिसके कारण इसे 'लाल शीत युद्ध' कहना ज्यादा उचित होगा''[244] वास्तव में संसार के सबसे बड़े शीत युद्ध (अमेरिका बनाम सोवियत संघ) का 45 वर्षों का इतिहास इतना रक्तरंजित नहीं रहा और यदि कहीं रहा था तो धरती दूसरी थी और बहाना भी दूसरा था जैसे अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप। लेकिन भारत और पाकिस्तान में बहाना कश्मीर का है और धरती भारत की। हालाँकि इन्हीं आतंकवादियों से प्रेरित अन्य आतंकवादी समूह पाकिस्तान की धरती को भी निशाना बनाते आये हैं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आतंक का देश व अतिक्रमण को झेलने के बाद भी पाकिस्तान इसे अपना एक नीतिगत मुद्दा मानता है और भारत विरोध के लिए इसे एक हथियार के रूप से इस्तेमाल कर रहा है।

''अनुमानतः इस समय लगभग 11000 से 15000 पाक समर्पित आतंकवादी भारत में आ गये है।'' स्थिति यह है कि आतंकवादियों के आत्मघाती दस्ते ने केवल

---

[243] अमर उजाला, 8 दिसम्बर 2008

[244] डॉ. कृष्णानन्द शुक्ल, ''लाल शीत युद्ध की दास्तान–भारत और पाकिस्तान'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, दूरभाष 011–23255141, पृष्ठ संख्या – 74

नागरिक प्रतिष्ठानों पर हमला करने में सक्षम है, बल्कि सुरक्षाबलों के अभेद्य समझे जाने वाले ठिकानों पर भी खुलेआम आक्रमण कर रहे हैं। चिन्ता की बात यह है कि हमला करके वे निकल भागने में भी सफल हो जा रहे हैं। कश्मीर में आज हिंसा का बोलबाला है। कश्मीर घाटी में रहने वाले हिन्दू और सिक्खों के प्राण खतरे एवं संकट में है। अगर उनके प्राण संकट में नहीं होते तो अपना घर–बार छोड़कर शरणार्थियों की तरह अपने ही देश में इधर–उधर क्यों भटकते।

ठीक छापामार युद्ध की भाँति "आतंकवाद कमजोर का सशक्त के विरूद्ध हथियार है।"[245] पाकिस्तान द्वारा सीमापार आतंकवाद का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अखण्डता पर प्रभाव पड़ता है। पाकिस्तान की नीतियाँ 1971 के बांग्लादेश के जन्म के प्रतिकार के रूप में है। आल पार्टी हुर्रियत कान्फ्रेंस के पूर्व चेयरमैन अहमद शाह गिलानी ने 'सण्डे आब्जर्बर' को दिये गये साक्षात्कार में कहा भी है कि यदि भारती सेना बांग्लादेश के जन्म में अपना रोल कर सकती है तो इसमें गलत क्या है कि यदि पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर की स्वतंत्रता में अपनी भूमिका अदा करते है।

13 दिसम्बर 2001 की घटना के बाद पाकिस्तानी नेतृत्व भारत से सटी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर अपनी रक्षा मजबूत करने के लिए मंगला स्थित अपनी बन स्ट्राइक कोर और रावलपिंडी स्थित 10वीं कोर को तैनात कर दिया है वैसे इस्लामाबाद अंततः अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को चेताने और भारत को फौजी कार्यवाही से रोकने के लिए अपनी परमाणु शक्ति पर भरोसा कर रहा है।

इस्लामाबाद के सघन सुरक्षा वाले इलाके में भारतीय उच्चायोग के एक समारोह के कुछ घंटों पहले आयोजन स्थल पर आत्मघाती हमला यह बताने के लिए पर्याप्त है कि पाकिस्तान में भारत विरोधी जिहादी तत्त्व किस तरह अभी भी सक्रिय है। यद्यपि पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने इस घटना की निंदा करते हुए जाँच के आदेश देने में देर नहीं लगाई, लेकिन इतने मात्रा से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। वैसे भी इस तरह की घटनाओं की निंदा करने में वह पहले भी देर नहीं लगाते रहे है। दरअसल समस्या है कि आतंकवाद पर लगाम लगाने के मामले में उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। यह अंतर सारी दुनिया को तो अच्छी तरह नजर आने लगा है, लेकिन दुर्भाग्य से अमेरिका की दृष्टि अभी भी साफ नहीं हो सकी। अफगानिस्तान में तैनात नाटो कमांडर और अनेक अमेरिकी अधिकारियों का साफ तौर पर यह मानना है कि पाकिस्तान में तालिबान और अल–कायदा के आतंकी अपने अड्ड़े बनाए हुए है, लेकिन परवेज मुशर्रफ इन सबसे इन्कार करते रहते हैं।

"26 नवम्बर 2008 को मुम्बई पर आतंकवादियों द्वारा अब तक का सबसे भीषण हमला किया गया। तीन दिनों के दौरान कुल साठ घंटों तक चली कार्यवाही के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों पर काबू पाया। इस दौरान विदेशी पर्यटकों सहित 178 नागरिक व सुरक्षाकर्मी मारे गये। सुरक्षाकर्मियों ने भी नौ आतंकवादियों को ढ़ेर कर दिया जबकि 'कसाब' नाम के एक आतंकवादी को जिन्दा पकड़ने में सफलता भी हासिल की। 'कसाब'

[245] वही, पृ.सं. – 81

से पूछताछ के दौरान यह कबूल किया कि वह पाकिस्तान का नागरिक है और जिस संगठन से वह ताल्लुक रखता है, उसे सरकारी संरक्षण भी प्राप्त है।"[246]

बांग्लादेश में हिंसा, विस्फोट के साथ ही आत्मघाती विस्फोट करके घातक हिंसा व आतंकवाद का स्वरूप धारण कर लिया है। निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण एशियाई देशों में श्रीलंका वह देश है जिसने इस प्रकार के आत्मघाती हमलों का सबसे पहले सामना किया। इसके बाद पाकिस्तान और भारत इस घातक अभिशाप के शिकार हुए और अब बांग्लादेश इस रक्तरंजित सूची में शामिल हो गया है। बांग्लादेश में चल रहा कट्टरता का यह नया दौर अशुभ संकेत दे रहा है। कट्टरपंथी इस्लामी गुट जमात–उल–मुजाहिदीन द्वारा पूरे बांग्लादेश में किये गए विस्फोटों का उद्देश्य देश में इस्लामी क्रांति के जरिये तालिबानी राष्ट्र व्यवस्था स्थापित करना है। बांग्लादेश एक नया पाकिस्तान बनने का रास्ता अख्तियार कर रहा है। बांग्लादेश के विस्फोट वाली जगह में जो पर्चे मिले है, उनमें कहा गया है कि हम इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहते है। सत्ताधारी व विरोधी हमें सतर्क करना चाहते हैं यदि उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना करनी चाही तो उन्हें इस्लाम का शत्रु घोषित कर दिया जाएगा। इस्लाम विरोधी शक्तियों को उखाड़ फेंक दिया जाएगा।

किसी स्वतंत्र देश के भीतर होने वाली घटनाएँ उस देश का घरेलू मामला है। लेकिन हमें इस मामले में सतर्क रहने और नजर रखने की जरूरत है जैसे हमारे पड़ोस में जो हो रहा है उसका हम पर क्या असर पड़ेगा। वर्तमान समय में कट्टरपंथियों का उभार हर जगह बड़े पैमाने पर हो रहा है। वह मंजर अर्द्धविकसित या गरीब देशों तक सीमित नहीं है, अमीर देशों में भी कट्टरपंथी अपनी घुसपैठ उसी तरह बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश का कट्टरपंथ कुछ अलग किस्म का है। आबादी के हिसाब से दुनिया में आठवें बड़े इस देश में कट्टरपंथियों ने अपने विचार लादने के लिए हिंसा और दहशत का रास्ता अपना लिया है ऐसे में बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर भारत का चिंतित होना लाजमी है। यदि कट्टरपंथियों के लिए बांग्लादेश एक बड़ा अड्डा बन रहा, तो खालिदा जिया सरकार का भविष्य अधर में लटक जाएगा और बांग्लादेश का तालिबानीकरण उसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तब्दील कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।

भारत के नरम रूख का बांग्लादेश पूरा फायदा उठा रहा है। हालत यह है कि तीन माह में वहाँ पाक खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. और कश्मीर के आतंकवादी संगठनों का जमावड़ा बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक आई.एस.आई. ने भारत के खिलाफ जिहाद चलाने वाले आतंकवादी संगठनों को रियायती दरों पर हथियार देने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अपने प्लान के अनुसार हरकत उल जिहाद अल इस्लाम (HUJI) तथा लश्करे तैयबा (LeT) के नेताओं ने वहाँ चल रहे आतंकवादी कैंपों का दौरा किया और कैंप नेताओं से बातचीत की।

---

[246] वही, पृ.सं. – 100

एक कटु सत्य यह है कि बांग्लादेश के जो हालात बनते जा रहे हैं, इसके केवल भारत को ही नहीं अपितु संपूर्ण दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला है। पाकिस्तान का पिट्ठू बनकर बांग्लादेश विनाश का जो रास्ता चुन रहा है। उससे सुरक्षा के संकट का एक नया दौर शुरू हो गया है। बांग्लादेश की सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए अनेक गुट व अनेक प्रशिक्षण शिविर धड़ल्ले के साथ चल रहे हैं। बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरवाद के बढ़ने से आई.एस.आई. का भी क्रमशः विस्तार हो रहा है। इसके साथ ही सीमांत क्षेत्रों में नित नए मदरसे खुलवाकर वह अपनी गतिविधियाँ चला रही है आई.एस.आई. ने बांग्लादेश में बैठे भारत विरोधी उग्रवादियों की मदद से भारत में जाली नोटों को फैलाने की कोशिश जारी रखी है। बी.एस.एफ. के अतिरिक्त महानिदेशक (पूर्वी क्षेत्र) आई.एस.आई. अहमद ने बताया कि बांग्लादेश भारत की सीमा में लड़कियों, बच्चों, मवेशियों की तस्करी कर रहा है। इस समय कोलकता के रेडलाईट एरिया में तीस प्रतिशत यौन–कर्मी बांग्लादेशी है। उस पार से मादक द्रव्यों की तस्करी को भी बढ़ावा दिया है। अहमद ने अगस्त 2004 तक का एक आँकड़ा पेश किया है, जिसके अनुसार विभिन्न अपराधों में 7206 लोग पकड़े गए। 60.21 करोड़ रूपये का वर्जित माल जब्त किया गया। 20.12 करोड़ रूपये मूल्य के मवेशी पकड़े गए। 6167.48 किलो नशीली दवाओं में गाझ्जा और 8936.65 ग्राम 'ब्राउन शुगर' जब्त किया गया।

बांग्लादेश के विभिन्न इलाकों में करीब दो सौ आतंकी प्रशिक्षण शिविर सक्रिय है, जहाँ भारत विरोधी आतंकवादियों को आई.एस.आई. की निगरानी में ट्रेनिंग दी जा रही है। इन में से कई शिविर तो भारत में सक्रिय प्रमुख आतंकी संगठनों के सदस्यों की ट्रेनिंग के लिए विशेष तौर पर रिजर्व है।

मादक पदार्थों की तस्करी व आतंकवाद में लिप्त महिलायें

प्रतिदिन के समाचार–पत्रों और चैनलों में आतंकवादी घटनएँ प्रमुखता से प्रकाशित हो रही है, इनमें एक नया आयाम और जुड़ गया है, वह है अवैध व्यापर को बढ़ावा देने तथा फरूष आतंकवादियों के साथ जिहादी जुनून की गिरफ्रत में फट्टसी आतंकी महिलाओं की भूमिका। भारत जैसे देश में विभिन्नता और गरीबी ने आतंरिक समस्याओं का पहाड़ खड़ा कर दिया है। कहीं धर्म का जुनून है तो कहीं पैसों की चमक और कहीं विवशता तो कहीं सुरक्षा की आड़ लेकर न केवल फरूष बल्कि महिलाओं ने भी अपराध की दुनिया में अपनी भारी उपस्थिति दर्ज करायी है। पूर्वोत्तर राज्यों, नेपाल और कश्मीर सीमा से लगे क्षेत्रीय लोगों में मादक पदार्थों, अवैध हथियारों, नकली नोटों आदि के अवैध कारोबार की होड़ लगी है। इस व्यवसाय में उनके मददगार के रूप में घरेलू महिलाएँ भी कूद गई है।

भारत दुनिया में नशीली पदार्थों के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के बीच स्थित है। एक ओर ळवसकमद ज्तपंदहसम म्यांमार, थाईलैण्ड और लाओस स्थित है, दूसरी ओर ळवसकमद ब्तमेबमदज ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, सुडान, टर्की, सीरिया, मिस्र आदि मुस्लिम बहुल राष्ट्र अपनी गरीबी और गुटबाजी के साथ–साथ धर्म और पैसों की अंधी दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं। यहाँ "मादक पदार्थों का उत्पादन और सेवन काफी

मात्रा में होता है। दुनिया के अनेक देशों में इनका अवैध कारोबार फैला हुआ है इस रेस में महिलायें और बच्चे भी शामिल हैं। महिलाओं की मदद से आतंकवादी सुरक्षित हवाई यात्राएँ कर रहे हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए रिहायसी ठिकाने हासिल करने, पासपोर्ट और वीजा आदि बनवाने के लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि की नकाब ओढ़ कर महिलाओं की मदद से आतंकवादी अपने अभियानों में सफल को रहे हैं। कोई उन पर संदेह नहीं कर पाता है।''[247]

2.1 अल–कायदा और इसके सहयोगी संगठन
(Al-Qaeda and its Allied Terrorist Outfits)

1. अल–कायदा (Al-Qaeda)

यह सबसे महत्त्वपूर्ण विश्वस्तर का कट्टरपंथी मुसलमानों का संगठन है। जो जिहाद (Jihad) के लिए समर्पित है। इसे 1988 में अब्दल्ला अज्जाम (Abdallah Azzam) ने स्थापित किया था और 1990 के दशक के दौरान ओसामा बिन लादेन (Usama bin Laden) ने इसकी बागडोर संभाली थी। (लादेन 2 मई 2011 को पाकिस्तान के ऐपटाबाद में अमेरिकी सील कमाण्डो द्वारा मारा गया) अल–कायदा की विश्व के अनेक देशों में शाखायें फैली हुई है जहाँ इनके कार्यकर्त्ता अपने कार्यों को अंजाम देते है और एक मुस्लिम शासक (खलीफा) के नेतृत्व में एक 'एकीकृत इस्लामिक राज्य' की स्थापना के लिए लड़ते और संघर्ष करते है और 'मुस्लिम जगत' से सभी विदेशियों और विदेशी प्रभाव को समाप्त करना इनका एक उद्देश्य है।

''अमेरिका ने अल–कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए 50 लाख डॉलर का ईनाम घोषित किया था। जो कि रियाद, सऊदी अरब का निवासी था।''[248] अल–कायदा के पास भयंकर विनाशकारी हथियार है। इसकी 46 देशों में सक्रियता है। वास्तव में अल–कायदा का जन्म 1990 के दशक के अन्त में मिस्र–अल–जिहाद से विभाजित होकर हुआ। इसका संबंध कई सुन्नी आतंकवादी गिरोहों के साथ लेबनान, लीबिया, सीरिया, चेचन्या आदि आतंकवादी संगठनों से रहा है। इस सगठन का मूल उद्देश्य 'जिहादिस्तान' नामक अलग गणराज्य बनाना है जो केवल आतंकवादियों का देश होगा।

''अल–कायदा की सोच दुनिया में इस्लाम का शासन कायम करना है। ओसामा बिन लादेन को यह मकसद हासिल करने के लिए प्रेरित करने वालों में उसके फिलीस्तीनी सरपरस्त शेख अब्दुल्ला आजम ओसामा का शिक्षक रहा है। उसने यह सिखाया कि जिहाद जब तक जारी रहना चाहिए जब तक दुनिया में सिर्फ इस्लाम की

[247] डॉ. आर.बी.सिंह – अवैध व्यापार और आतंकी गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका, फस्तक – ''आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियट्टा'' पृष्ठ संख्या – 182

[248] डॉ. लल्लन जी सिंह, ''राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा'', 2006, प्रकाश बुक डिपो, बड़ा बाजार, बरेली – 243003, दूरभाष 2470217, पृष्ठ संख्या – 77

हुकूमत न हो जाये''[249] शेख ने इस्लामी कट्टरपंथी संगठन 'मुस्लिम ब्रदरहुड' की स्थापना भी की थी। वह बहुत शिक्षित बताया जाता है। सन् 1969 में दमिश्क में उसने शरीया (इस्लामी कानून) में स्नातक करने के बाद काहिरा स्थित अल अजहर विश्वविद्यालय से एम.ए. किया और सन् 1979 में पी–एच.डी. की।

पैसा जुटाने का एक और नायाब तरीका 'अल–कायदा' ने तय कर रखा है नैरोबी और दार–एस–सलाम में अमरीकी दूतावासों पर हमला करने के पहले 'अल–कायदा' के आतंकवादियों ने वहाँ छुट–फट धंधे शुरू किए। इन धंधों से कमाई की रकम ही अपनी साजिशों को अंजाम देने पर खर्च कर दी। ''व्यापार के जरिए धन जुटाने से दो फायदे होते हैं। एक तो उनकी गतिविधियों पर किसी को शक नहीं होता और दूसरा, पैसा लाने–ले जाने की दिक्कत भी पेश नहीं आती।''[250] इस तरह आतंकवाद के लिए पैसा जुटाने वाला 'अल–कायदा' जरूरत पड़ने पर 'हवाला' का इस्तेमाल भी करता है। न्यूयॉर्क में अल–कायदा के एक आतंकवादी पर चल रहे मुकदमे के दौरान सरकारी वकीन ने 'दिहाब शिया' नामक कंपनी के खातों के पन्ने पेश किए थे। इनमें कुवैत और यमन से 1 हजार डॉलर नैरोबी भेजे जाने की प्रविष्टि थी, लेकिन इस सबूत के बावजूद यह साबित नहीं किया जा सका कि यह पैसा कहाँ से आया था? और किसको गया था? कंपनी के वकील ने कहा कि उन्होंने फैक्स संदेश के आधार पर यह पैसा पहुँचाया था। उसके बाद वह संदेश फाड़कर फेंक दिया गया। उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि यह पैसा किसने, किसे और क्यों भेजा था? वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पर हमले के बाद अमरीकी जाँच एजेंसी एफ.बी.आई ने अमरीका के सभी बैंकों से इन हमलों में शामिल आतंकवादियों के खातों का पता लगाने को कहा था।

बहुचर्चित ''अल–कायदा एक खूँखार आतंकवादी संगठन है। उसके एक उर्दू में प्राप्त मैनुअल में उसके संगठन के सिद्धान्त, सैन्य–संगठन की जरूरतों एवं उसके निशान का उल्लेख है।'[251] विरोधी देशों से हमारी जंग सुकरात के तर्कों को नहीं जानती, प्लेटों के सिद्धान्तों को नहीं पहचानती और न ही अरस्तु की कूटनीति को जानती है। यह गोलियों की भाषा को समझती है। हत्याओं, विस्फोट और विनाश के सिद्धांतों को पहचानती है। यह तोपों और मशीनगनों की कूटनीति को समझती है। अल्लाह की तरह लौट रहे मुस्लिम युवकों को यह जान लेना चाहिए कि कुछ रीति रिवाजों का पालन करना ही इस्लाम नहीं है, बल्कि यह धर्म और सत्ता, प्रार्थना और जिहाद, नैतिकता और लोकाचार, कुरान और तलवार का एक पूरा सिस्टम है। मैं इस महान् प्रयास को उन नौजवान मुस्लिम युवकों को समर्पित करता हूँ, जो पाक हैं, जो अल्लाह में विश्वास करते हैं और उसके लिए ही लड़ रहे हैं।

---

[249] विवेक सक्सेना, सुशील राजेश, ''जेहाद का जुनून'', 2011, सत्साहित्य प्रकाशन, 205–बी, चावड़ी बाजार, दिल्ली – 110006, पृष्ठ संख्या – 39–40

[250] वही, पृ.सं. – 47

[251] डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र, ''आतंकवाद व आपदा प्रबंधन'', 2010, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली 110002, पृष्ठ संख्या – 105

सैन्य संगठन के सिद्धान्त

1. सैन्य संगठन का कमांडर और सलाहकार परिषद 2. सैनिक 3. एक सुपरिभाषित रणनीति।

सैन्य संगठन की जरूरतें

1 . नकली दस्तावेज और करेंसी 2. अपार्टमेंट्स और छुपने लायक अन्य जगह 3. संचार के साधन 4. आवागमन के साधन 5. सूचनाएँ 6. हथियार और गोला–बारूद 7. परिवहन

सैन्य संगठन के मिशन

1. दुश्मन, उसकी जमीन, उसके ठिकानों और पड़ोसियों के बारे में सूचनाएँ एकत्र करना।
2. दुश्मन के कर्मचारियों का अपहरण तथा उसके दस्तावेज, गुप्त सूचनाओं और हथियारों को कब्जे में लेना।
3. दुश्मन के कर्मचारियों और विदेशी पर्यटकों की हत्या करना।
4. दुश्मन द्वारा पकड़े गये जिहादी भाइयों को मुक्त कराना।
5. ऐसी अफवाहें फैलाना और पर्चे बँटवाना, जो दुश्मन के खिलाफ लोगों को भड़का दें।
6. मनोरंजन और अनैतिक गतिविधियों के ठिकानों को विस्फोट से उड़ाना।
7. विदेशी दूतावासों और आर्थिक केन्द्रों को नष्ट करना।
8. शहर में जाने वाले और शहर से आने वाले रास्तों पर पड़ने वाले फलों को उड़ाना।

इसमें कोई संदेह नहीं कि आतंकवाद लगभग पूरी दुनिया के लिए चुनौती के रूप में उभर रहा है। विकसित देश हो या विकासशील देश, आज इस गंभीर विषय पर खुले रूप में चर्चा करने के लिए आतुर दिखाई पड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को मजहबी रूप देकर जिस तरह से इसे धर्म और संप्रदायवाद का एक हिस्सा बनाया जा रहा है वह न तो किसी धर्म के लिए शुभ संकेत है और न ही विकास के लिए। सीमापार प्रायोजित आतंकवाद को न सिर्फ हथियार, प्रशिक्षण का स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है, बल्कि उसके संचालक को छुपने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध करा कर और उसे खासी रकम देकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि अगस्त 1998 में केन्या तथा तंजानिया स्थित अमेरिकी दूतावास पर कायरतापूर्ण बमबारी की गई थी। यह बमबारी इसलिए समाचारों की सुर्खियों में छाई हुई थी क्योंकि सात सौ से ज्यादा लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी और 6000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का प्रश्न है यह कोई नई चुनौती नहीं है। 1986 से ही सीरिया में कई आतंकवादी संगठन क्रियाशील है, चाहे वो 'हमास' हो या अहमद जिबरिल ऑफ फिलीस्तीन–जेनरल कमांड या फिर फिलीस्तीनी इस्लामिक जिहाद। सभी संगठनों को सीरिया की सरकार शरण देती रही है।

2. लश्कर–ए–तैयबा (Lashkar-e-Tayba)

इखावान–अल–मुसलमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) संगठन की नींव 1928 में मिस्र में हसन–अल–बनान ने डाली थी। इसी संगठन की कोशिश से 1941 में जमात–ए–इस्लामी का गठन हुआ। ''जमात–ए–इस्लामी को भारतीय उपमहाद्वीप और सुदूरपूर्व एशिया में 'मुस्लिम ब्रदरहुड' फैलाने का जिम्मा सौंपा गया जो लोग इसके मकसद में रोड़ा बने, उन्हें 'खुदा के दुश्मन' घोषित किया गया।''[252] इन खुदा के दुश्मनों से निपटने के लिए जमात ने कुछ मिलिटेंट समुहों का गठन किया, 'लश्कर–ए–तैयबा' जमात–ए–इस्लामी का ऐसा ही संगठन है। इसका अस्तित्व 1974 से ही है। मगर इसे कश्मीर में 1995 के बाद भेजा गया जब जमात–ए–इस्लामी ने यह पाया कि जे.के.एल.एफ. (JKLF) बहुत ही 'सॉफ्रट' साबित हो रहा है। लश्कर–ए–तैयबा की निश्चित ताकत का ठीक–ठाक अनुमान तो नहीं हैं, क्योंकि जिन तीन संगठनों के 'मिलिटेंट' आपस में अदल–बदल करते रहते हैं ये संगठन हैं, 'हिजबुल मुजाहिदीन', 'हरकत–उल–अंसार' तथा 'लश्कर–ए–तैयबा'। फिर भी इसके मिलिटेंटों की संख्या 3000 से 4000 के बीच मानी जाती है। यह सभी तरह की आतंकवादी गतिविधियों में यकीन रखता है ताकि दहशत बनाई जा सके। पहले इसकी गतिविधि का केन्द्र अफगानिस्तान था। आज कल कश्मीर है। मध्य एशिया और चीन के झियांग क्षेत्र में भी इसकी गतिविधियाँ चलती हैं। इसकी आर्थिक जरूरतें जमात–ए–इस्लामी पूरी करता है।

लश्कर–ए–तैयबा एक हिंसात्मक कट्टर पाकिस्तानी समूह है जो कश्मीर के अहली–हादिस (Ahli-Hadis) स्कूल से जुड़ा हुआ है। यह कश्मीर में गतिशील है। 1989 में हाफिज मुहम्मद सईद (Hafiz Muhammad Saeed) ने इस समूह की स्थापना की थी। यह मरकज अल–दवा वाल इरशाद (Markaz-al-Da'wa-wal-Irshad) से जुड़ा हुआ है। यह भारत में और कश्मीर में अनेकों आतंकवादी हमले और आत्मघाती आक्रमण कर चुका है परन्तु पाकिस्तान की सरजमी पर यह हमले नहीं करता।

इस कुख्यात संगठन की स्थापना 1989 ई. मे की गई थी। यह संगठन कई इकाइयों मे विभक्त होकर कार्य करती है। इसके दीर्घकाल तक प्रशिक्षित आतंकवादी जम्मू–कश्मीर में आतंक फैला रहे हैं। यह संगठन अमेरिका विरोधी भी है। अमेरिकी दबाव पर पाकिस्तान सरकार ने इसकी सम्पत्ति जनवरी 2002 में जब्त कर ली थी। सैकड़ों कट्टरपंथी उग्रवादियों वाला यह संगठन एचयूएम (HUM), जैश–ए–मुहम्मद आदि की भाँति पाकिस्तान सरकार और आई.एस.आई. (ISI) से शरण, सहायता और निर्देश लेता रहा है। आई.एस.आई. के भूतपूर्व लेफ्रिटनेंट जनरल हमीद गुल, जनरल जावेद निसार और जनरल अरशाद इस संगठन से जुड़े थे। 1993 में इस संगठन ने भारत में कई आतंकवादी घटनायें की है। ''विश्व में कट्टरपंथी इस्लाम का राज्य स्थापित करने का उद्देश्य लेकर चलने वाला यह

---

[252] डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र, ''आतंकवाद व आपदा प्रबंधन'', 2010, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली 110002, पृष्ठ संख्या – 104

संगठन जिहाद समर्थक है।''[253] अनेक सुरक्षाकर्मियों की हत्या तथा बम विस्फोट करने के अलावा यह संगठन 13 दिसम्बर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले में भी शामिल था। इसके उग्रवादी गैर–कश्मीरी मूल के हैं और अधिकांश उन मदरसों से आये हैं, जहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तथाकथित तालिबान प्रशिक्षित किये जाते हैं। संवेदनशील आधुनिकतम हथियारों के अलावा इस संगठन के पास आधुनिकतम संचार–प्रणाली भी है।

''इस संगठन को आर्थिक मदद इंग्लैंड, गैर–सरकारी इस्लामी संगठनों, पाकिस्तान और अन्य उग्रवाद समर्थक देशों से मिलती है।''[254] पूरे विश्व में धन एकत्र करने के अलावा इसने चरमपंथियों से धार्मिक–सैनिक संबंध बनाये हैं। इसकी जड़े फिलीपीन से लेकर मध्यपूर्व और चेचन्या तक फैली हैं।

लश्कर–ए–तैयबा मरकजे दवा उल इरशाद का यह आतंकवादी संगठन है। इसका मुख्यालय पाकिस्तान के मुरीदके में है, जिसका मुखिया प्रो. हाफीज सईद है। कश्मीर कें आतंकवाद में सक्रिय संगठनों में इसका नाम सबसे ऊपर आता है। ''कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने के बाद इसका नाम चमका था। आत्मघाती हमलों में इसका बड़ा हाथ है। इस संगठन के सदस्यों ने लाल किले पर हमला किया था तथा अब प्रधानमंत्री कार्यालय को उड़ाने की धमकी दे रखी है।''[255] बहुत बड़ा आतंकवादी गुट है। इसका मुख्य कार्यालय निकट नगर मुरीदके में है। असद दुर्रानी दरअसल हरियाणा से शिमला में जाकर आजाद हुआ था और देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया था। उसे जनरल जिया ने करोड़ों की जमीन दी, जिस पर उसने अलदावत अल अरशाद नाम के इस्लामी विश्वविद्यालय का निर्माण किया। इस गुट के वार्षिक उत्सव में दुनिया भर के इस्लामी आतंकवादियों के गुटों के नेता शामिल होते हैं। इसका लक्ष्य यह है कि उपमहाद्वीप सहित तमाम दुनिया में इस्लाम लागू किया जाय। इस गुट ने चेचन्या और बोस्निया की लड़ाइयों में अपने आतंकवादी भेजे। इसे कई इस्लामी देशों से बड़े पैमाने पर मदद मिलती है। कई रिटायर्ड जनरल इसके उत्सवों में शामिल होते हैं। उसने एक बयान में कहा कि काफिरों से लड़ाई में दुश्मनों को कैदी बनाकर न रखो बल्कि उनकी गर्दनें काट कर दुश्मन के कैम्प में पहुँचा दो। इस गुट के अधीन दो हजार के लगभग स्कूल है। इस गुट ने सैयद सल्लाहुद्दीन के हिजबे मुजाहिदीन में अपने आपको शामिल कर रखा है। इसके आदमी पुंछ, अनंतनाग, बड़गाम और कुपवाड़ा में घुसे हुए हैं। इन्हीं ने बहुत से लोगों की हत्या की और हर बार यही प्रोपेगेंडा किया कि यह हत्याएँ भारत की सेना पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए करा रही है। हाल ही में इस संगठन ने

---

[253] डॉ. विपिन कुमार मिश्रा, डॉ. आशुतोष पाण्डेय, ''भारत और आतंकवाद'', 2012, विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली – 110002, पृष्ठ संख्या – 156

[254] वही, पृ.सं. – 157

[255] डॉ. मानचन्द खंडेला, ''अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद'', 2011, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, 807, व्यास बिल्डिंग, चौड़ा रास्ता, जयफर – 302003 (राज.) फोन 0141–2578159, पृष्ठ संख्या – 121

कश्मीर में अपनी गतिविधियाँ काफी बढ़ा दी हैं। कश्मीर में भारतीय सेनाओं के खिलाफ आत्मघाती हमले करने में भी यह गुट आगे रहा है। हर साल इसमें हजारों नए जिहादियों की भर्ती की जाती है। इसके नेता सईद खुलेआम भारत को तबाह करने की बात कहते हैं।

लश्कर–ए–तैयबा कारगिल संघर्ष से लेकर कश्मीर तक में 'फिदायीन' या आत्मघाती दस्ते भेजकर भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले करने वाला यह आतंकवादी संगठन इस समय सबसे क्रूर आतंकवादी संगठनों में गिना जाता है। यह 'मरकल दवा वल इरशाद' और 'अहले हदीथ' नामक मजहबी संगठनों का आतंकवादी चेहरा है। इसक प्रमुख प्रो. हाफिज मुहम्मद सईद था, जिसने अमरीका और पाकिस्तान के दबाव में अब इस्तीफा दे दिया है। ''लश्करे पर भी परवेज मुशर्रफ ने पाबंदी का ऐलान किया था और सैकड़ों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था।''[256]

मरकज की स्थापना सन् 1987 में विश्वविद्यालय के तीन प्राध्यापकों ने की थी। उनका मकसद पाकिस्तान और दुनिया के कोने–कोने में निखालिस इस्लाम की शिक्षा देना था। इन में से जफर इकबाल और हाफिज मुहम्मद सईद लाहौर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में प्राध्यापक थे, जबकि अब्दुल्ला आजम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। सन् 1989 में पेशावर में हुए एक बम विस्फोट में अब्दुल्ला आजम की मौत हो गई उसके बाद से इकबाल और हाफिज मुहम्मद सईद ने इस संगठन की बागडौर संभाल रखी थी। लश्करे तैयबा के 80 फीसदी आतंकवादी पाकिस्तानी है और वे ज्यादातर कश्मीर में सक्रिय हैं। ''शुरू में इस संगठन की सऊदी अरब के शेखों ने खूब मदद की थी, लेकिन अब इसे पाकिस्तानी व्यापारी भी काफी पैसा दान में दे रहे थें।''[257]

लश्कर–ए–तैयबा, कश्मीर में सक्रिय सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह है। इसका शाब्दिक अर्थ है – ''शुद्ध लोगों की सेना''[258] लेकिन इसने हिंसा की ऐसी अशुद्धता फैला रखी है कि मानवता की एकबारगी तो काँप उठे। लश्कर–ए–तैयबा फिलहाल घाटी में दो तरह की आतंकवादी कार्यवाहियाँ कर रहा है – सैन्य तथा सुरक्षा बलों पर नियोजित ढ़ंग से हमले और घाटी के गैर–मुस्लिम नागरिकों की सामूहिक हत्याएँ। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कारगिल समस्या के दौरान जिन पाकिस्तानियों ने भारतीय चोटियों पर कब्जा जमा लिया था उनमें भारी संख्या लश्कर–ए–तैयबा के लड़ाकुओं की ही थी। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जब घुसपैठियों को मार भगाया तो लश्कर–ए–तैयबा ने अपनी रणनीति बदली और

[256] विवेक सक्सेना, सुशील राजेश, ''जेहाद का जुनून'', 2011, सत्साहित्य प्रकाशन, 205–बी, चावड़ी बाजार, दिल्ली – 110006, पृष्ठ संख्या – 104

[257] वही, पृ.सं. – 104

[258] नरेन्द्र कुमार शर्मा, ''भारत में नक्सलवाद'', 2012, ओमेगा पब्लिकेशन्स, 4378/4 बी, जी–4जे. एम.डी. हाऊस, गली मुरारीलाल, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, फोन 65901906, पृष्ठ संख्या–246

अब उसने आत्मघाती दस्तों की सहायता से लश्कर–ए–तैयबा ने महत्त्वपूर्ण ठिकानों पर हमले करने प्रारंभ कर दिए।

लश्कर–ए–तैयबा के आत्मघाती दस्ते (फिदायीन) में दो–पाँच सदस्य होते हैं जो अपने शरीर से घातक गोला–बारूद या आर.डी.एक्स. बांधे रखते हैं। ये प्राणघात फिदायीन किसी की सुरक्षा बल के कैम्प आदि पर हमला कर देते हैं। गैर–मुस्लिमों के नरसंहार के लिए तैयबा के लड़ाके सुरक्षाबल की ड्रेस का प्रयोग करते हैं ताकि लोगों को भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काया जा सके। लश्कर–ए–तैयबा के फिदायीन दस्ते ने सबसे पहला हमला 13 जुलाई, 1999 को बारामूला जिले के बन्दीफर में स्थित सीमा सुरक्षा बल के आवासीय परिसर पर किया। इसके बाद 27 दिसंबर, 1999 को ''स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप'' के मुख्यालय पर हमला किया गया जसमें 10 व्यक्ति मारे गये। इसमें पहले तैयबा 4 सितंबर, 1999 को सीमा सुरक्षा बल के हन्दवारा कैम्प पर भी फिदायीन हमला कर चुका था। इसी प्रकार लश्कर–ए–तैयबा ने सुरक्षा बलों के वजीर बाग (श्रीनगर), मंधार (राजौरी) और महोर (ऊधमफर) आदि कैम्पों पर भी आत्मघाती हमले किए जिसमें कई लोग मारे गये।

30 दिसंबर, 1999 को लश्कर–ए–तैयबा का जम्मू–कश्मीर चीफ अबु सुबाह मारा गया लेकिन तैयबा की आत्मघाती वारदातों पर लगाम नहीं लग सकी। 20 मार्च, 2000 को छत्तीसफरा के नरसंहार में सैकड़ों सिखों को खुलेआम काट डाला गया। यह नरसंहार भी लश्कर–ए–तैयबा ने ही हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर किया था। यह नरसंहार तब किया गया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अगले दिन से भारत की अपनी सरकारी यात्रा शुरू करने वाले थे। क्लिंटन की भारत यात्रा के दौरान लश्कर–ए–तैयबा ने 5 और नरसंहारों को अंजाम दिया जिन में से दो–दो अनंतनाग और डोडा जिलों में और एक कुपवाड़ा जिले में हुआ। इन नरसंहारों में भी सैकड़ों हिंदू मारे गए। लश्कर–ए–तैयबा द्वारा घाटी में गैर–मुस्लिमों की सामूहिक हत्याएँ करने से घाटी के साम्प्रदायिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

गैर–मुस्लिमों की हत्याओं का दौर 1988 में तब शुरू हुआ जब वंधामा में 23 जनवरी को 23 लोगों को मार डाला गया। इसके बाद 19 जुन, 1998 को डोडा में एक विवाह समारोह पर हमला कर 25 लोगों को मार डाला गया। वंधामा में लश्कर–ए–तैयबा द्वारा किए गये मौत के नंगे नाच की वीभत्सता इतनी अधिक थी कि इस नरसंहार में एक वर्ष तक के बच्चों तक को भी नहीं बख्शा गया। इस आतंकवादी संगठन को उस समय गहरा धक्का लगा जब 28 मार्च, 2001 को इसके डिवीजनल कमांडर सलाहुद्दीन को सुरक्षाबलों ने एक मुठभेड़ में मार गिराया लेकिन इसके बावजूद घाटी में लश्कर–ए–तैयबा की गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई, निर्दोष लोगों की हत्याएँ जारी रही, जन–जीवन ठप्प रहा।

वास्तव में लश्कर–ए–तैयबा 'मरकज–उद–दवा–वाल–इरशाद' नामक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन का आतंकवादी गुट है। यह कट्टरपंथी संगठन मूलतः पाकिस्तान के बहावी सेक्टर में स्थित है। फिलहाल लश्कर–ए–तैयबा की कमान

खूँखार आतंकवादी मुहम्मद लतीफ के हाथों में है और इसमें लगभग 300 आतंकवादी सक्रिय हैं जो मुख्य रूप से पुंछ, राजौरी और डोडा जिलों सहित पूरी कश्मीर घाटी में आतंक का पर्याय बने हुए हैं। इसके अलावा पाक कश्मीर के कोटली, सियालकोट व समानी इलाकों में तैयबा द्वारा आतंकवादी प्रशिक्षण कैम्प भी चलाए जा रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व पूरे जम्मू–कश्मीर में लश्कर–ए–तैयबा द्वारा 'हम क्यों जिहाद कर रहे हैं', शीर्षांकित पम्पलेट बाँटा गया जिसमे पूरे हिन्दुस्तान पर इस्लामिक राज्य की वकालत की गई थी और इसके लिए मरते दम तक कुछ भी करने का संकल्प व्यक्त किया गया था।

लश्कर–ए–तैयबा ने कश्मीर में अपनी गतिविधियाँ 1993 में शुरू की। 1997 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. (इन्टर सर्विसेज इंटेलिजेंस) ने लश्कर–ए–तैयबा को अपनी वरीयता पर लिया और इसे भरपूर पैसा व हथियार देने शुरू किए। पाकिस्तान ने हमेशा इंकार किया है कि वो कश्मीर के आतंकवादियों को किसी भी प्रकार की कोई सहायता देता है लेकिन पाकिस्तान की पोल उस समय खुल गई जब पाकिस्तान के तत्कालीन सूचना मंत्री मुसाहिद हुसैन ने लाहौर के निकट लश्कर–ए–तैयबा के मुख्यालय का दौरा किया और आतंकवादियों की एक सभा को संबोधित किया। जब आई.एस.आई. ने कश्मीर घाटी के स्थान पर जम्मू क्षेत्र में अधिक आतंकवादी कार्यवाहियाँ करने का फैसला किया तो एक बार फिर आई.एस.आई. ने लश्कर–ए–तैयबा को ही चुना। राज्य के अल्पसंख्यक (हिन्दू) जम्मू क्षेत्र में ही अधिक हैं इसलिए आई.एस.आई. व लश्कर–ए–तैयबा ने जम्मू क्षेत्र को ही दहशतगर्दी के लिए चुना। यही कारण है कि 1997 के बाद जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों विशेषकर पुंछ और डोडा जिलों में आतंकवादी कार्यवाहियों की बाढ़ सी आ गई।

चूँकि लश्कर–ए–तैयबा का मुख्यालय पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है इसलिए इसके लड़ाई के लिए जम्मू के आम लोगों में घुल–मिल जाना अपेक्षाकृत कभी आसान है। यही कारण है कि आई.एस.आई. लश्कर–ए–तैयबा को बेहद महत्त्व और वरीयता देती है। लश्कर–ए–तैयबा के लड़ाकुओं की एक खासियत यह है कि वे सुरक्षा बलों द्वारा पकड़ लिये जाने की अपेक्षा गोली खाकर मर जाना बेहतर समझते हैं। ''अपनी खूँखारता और पाश्विकता के लिए भी लश्कर–ए–तैयबा अलग से जाना जाता है। अपने फिदायीनों (आत्मघातियों) की सहायता से लश्कर–ए–तैयबा ने सुरक्षा बलों पर भी कई हमले किए जिसमें सैकड़ों जवान मारे जा चुके हैं। कई ऐसी घटनाएँ भी सामने आयी हैं जब लश्कर–ए–तैयबा ने हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर आतंकवादी कार्यवाही को अंजाम दिया।''[259]

3. तालिबान (Taliban)

मुल्ला उमर मुजाहिद के नेतृत्व में अफगानिस्तान के कट्टरपंथी मुसलमानों (Radical Muslim Afghan Organization) का संगठन है। मुल्ला उमर की उत्पत्ति

---

[259] वही, पृ.सं. – 248

(मूल स्थान) पाकिस्तान के देवबन्दी स्कूलों से हुई थी। 1994–96 (तीन वर्षो) के दौरान 'तालिबान' नामक संगठन ने अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन (राज्य) किया और अल–कायदा (Al-Qaeda) नामक आतंकवादी समूह को अफगानिस्तान में शरण–स्थली (Sanctuary) प्रदान करता रहा। 2001 में तालिबान ने पाकिस्तान में जाकर शरण (Refuge) लेली और अफगानिस्तान में अमेरिकी एवं बहुराष्ट्रीय फौजों (Multinational Forces) के विरूद्ध 2004 तक आत्मघाती हमलों के द्वारा लड़ाई जारी रखी।

तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा था। यह एक इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है जो पाकिस्तान की जेब में रहा है। इसका संबंध ओसामा बिन लादेन के संगठन अल–कायदा से हैं। ''11 सितम्बर 2001 को इन दोनों ने मिलकर अमरीका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन तथा वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर को अपहृत विमानों से टकराकर ध्वस्त कर दिया जिसके जवाब में 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर अमरीका ने हमला किया और तालिबान को वहाँ से उखाड़ फेंका।''[260]

4. जैश–ए–मुहम्मद (Jaysh-e-Muhammad)

यह एक हिंसात्मक कट्टरपंथी पाकिस्तानी समूह है जिसका संबंध कश्मीर में सक्रिय देवबन्दी स्कूल (Deobandi School) से हैं, पाकिस्तान के कुछ भागों से भी इसे सहायता (मदद) मिलती है, इसकी स्थापना महमूद अजहर (Mahmud Azhar) ने भारतीय जेल (कारागार) से 2000 ई. में छूटने के बाद की। यह संगठन कश्मीर और पाकिस्तान दोनों में अनेकों आत्मघाती हमले कर चुका है। इस कारण इस पर प्रतिबन्ध (Banned) लगा दिया गया था तब से अब तक यह अपने कई नाम बदल चुका है।

जैश–ए–मुहम्मद नवगठित आतंकवादी संगठन है जिसका नेतृत्व मौलाना महमूद अजहर द्वारा किया गया, जिसे भारतीय विमान के बन्धकों के बदले में रिहा किया गया था। इसके सदस्यों में हरकत उल मुजाहिदीन के सदस्य शामिल हैं। ''यह संगठन कश्मीर में हो रहे आत्मघाती हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है तथा इसी संगठन ने कश्मीर में मानव बम के हमले का पदार्पण किया''[261] यह संगठन बहुत तेजी से अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाता जा रहा है।

जैश–ए–मुहम्मद एक मजबूत एवं प्रभावशाली आतंकवादी संगठन है। अभी हाल में हुई विमान अपहरण की घटना इस संगठन द्वारा ही किया था जिसके बदले कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर की रिहाई हुई थी। यह संगठन भारतीय कश्मीर को भी पाकिस्तान में मिलाना चाहता है। जमायते–उलमाए–इस्लामी फजलुर रहमान शाखा जैसे चरमपंथी राजनीतिक

---

[260] डॉ. लल्लन जी सिंह, ''राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा'', 2006, प्रकाश बुक डिपो, बड़ा बाजार, बरेली – 243003, दूरभाष 2470217, पृष्ठ संख्या – 77

[261] डॉ. मानचन्द खंडेला, ''अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद'', 2011, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, 807, व्यास बिल्डिंग, चौड़ा रास्ता, जयफर – 302003 (राज.) फोन 0141–2578159, पृष्ठ संख्या – 120

संगठनों से इसके गहरे संबंध है। पाकिस्तान ने जनवरी 2002 में इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

यह संगठन जिसके सदस्यों की संख्या हजारों में है विशेषकर पाक अधिकृत कश्मीर, डोड एवं भारत के सीमावर्ती कश्मीरी क्षेत्रों में सक्रिय है। जहाँ इसके चरमपंथी 'हिजबुल–मुजाहिदीन' के आतंकवादियों के साथ आतंक में लिप्त है। संगठन ने भाड़े के अनेक अफगान और अरब आतंकवादी दिये हैं, जिन्होंने अफगान युद्ध में भाग लिया था। ''यह संगठन मशीनगनों, असाल्ट राईफलों, मोर्टारों, विस्फोटक सामग्री और रॉकेट ग्रेनेडों का इस्तेमाल करता है।''[262] पेशावर, मुजफ्फराबाद और अफगानिस्तान में स्थित प्रशिक्षण शिविरों में इसके उग्रवादी भली–भाँति प्रशिक्षित हैं। अक्तूबर 2001 में इस संगठन ने कश्मीर विधानसभा और 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर लश्कर–ए–तैयबा के साथ मिलकर आक्रमण करने की जिम्मेदारी ली थी।

इस संगठन के लिए उग्रवादी और विध्वंसक एवं संचार सामग्री, धन 'हरकत–उल–जिहाद अल इस्लामी' (HUJI) और 'हरकत–उल–मुजाहिदीन' से तथा 'अल–कायदा' से प्राप्त होता है। इसके अलावा ''पाकिस्तान से प्रकाशित समाचार–पत्र और पत्रिकाएँ तथा पम्पलेट बाँटकर यह संगठन स्थानीय लोगों से दान लेता है। इसकी बड़ी धनराशि बैंकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, व्यापार आदि में लगी है।''[263]

''अक्टूबर 2001 के प्रथम सप्ताह में कश्मीर विधानसभा में जिस प्रकार जैश–ए–मुहम्मद के आत्मघाती दस्ते के द्वारा विध्वंस मचाने का प्रयास किया गया, उससे एक बार यह पुनः स्पष्ट हो गया कि आतंकवादी अमेरिका के आतंक से न तो आहत है और न प्रभावित।''[264] भारत अमेरिका का साथ देने का जितना प्रयास करता है वह दीर्घकाल में तो उसके लिए घातक है ही लेकिन तुरन्त भारत पर इस प्रकार कहर बरपा जाएगा इसकी आशंका शायद कम ही लोगों को थी। यह भारत का दुर्भाग्य कहा जाए या कमजोरी कि यह हरकत करने वाला आतंकवादी संगठन वही है जिसके नेता अजहर मसूद को भारत के गृहमंत्री आडवाणी स्वयं वायुयान में लेकर अफगानिस्तान छोड़ने तब गये जब वहाँ पर भारत का एक यात्री विमान अपहृत कर लिया था। हो सकता है भारत सरकार को उस समय में ऐसा शर्मनाक निर्णय लेना पड़ा हो लेकिन आतंकवाद का मुकाबला करने में कमजोर राष्ट्र, कमजोर नीति और कमजोर तैयारी का कोई अर्थ नहीं है। उस समय भारत ने आतंकवादियों के सामने जिस प्रकार आत्मसमर्पण किया और अपने 'अल्पकालीन हितों' के लिए 'दीर्घकालीन

---

[262] डॉ. विपिन कुमार मिश्रा, डॉ. आशुतोष पाण्डेय, ''भारत और आतंकवाद'', 2012, विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली – 110002, पृष्ठ संख्या – 155

[263] वही, पृ.सं. – 155

[264] डॉ. मानचन्द खंडेला, ''अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद'', 2011, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, 807, व्यास बिल्डिंग, चौड़ा रास्ता, जयफर – 302003 (राज.) फोन 0141–2578159, पृष्ठ संख्या – 127

हितों' को दाँव पर लगा दिया उससे आतंकवादियों के हौंसले तो बुलन्द होने ही थे। सबसे दुःखद आश्चर्य यह है कि जो संगठन यह सब कुछ कर रहा है, वह आतंकवाद के इस विरोधी वातावरण में भी चिल्ला–चिल्ला कर इसे स्वीकार कर रहा है।

इस सम्पूर्ण प्रकरण से भारत की विदेश नीति, कूटनीति, रक्षा तैयार और आतंकवाद विरोधी संघर्ष की तथाकथित तैयारियों का खुलेआम पर्दाफाश हो चुका है। इस घटना के बाद भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जैश–ए–मुहम्मद संगठन को प्रतिबंधित सूची में शामिल करने और इसके नेता को भारत ने सुपुर्द करवाने की अमेरिका से जिस प्रकार मिन्नते की हैं और पाकिस्तान ने जिस प्रकार इसे बहुत हल्के तरीके से लिया है, उससे हमारी सभी कमजोरियाँ पूरी तरह से उजागर हो गई है। हमने एक प्रकार से स्वीकार कर लिया है कि हम अपने स्तर पर कश्मीर में चल रहे आतंकवाद का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। हम अमेरिका के सहारे के बिना अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इस घटना ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि पाकिस्तान ऊपरी तौर पर चाहे कुछ भी कहे लेकिन भारत विरोध उसकी आन्तरिक राजनीति का सबसे प्रथम तथ्य है।

भारतीय गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने मसूद को भारत को सौंपने के लिए पाकिस्तान पर जिस प्रकार अनावश्यक और अप्रभावी दबाव डालने के प्रयास किये हैं, उनसे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की हँसी ही ज्यादा हुई है क्योंकि जिस व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान से माँग कर रहे हैं जिसको एक तरह से अतिविशिष्ट व्यक्ति जैसा सम्मान देते हुए हमने भारतीय जेल से आजाद किया था। यहाँ पर प्रश्न यह उठाया जा सकता है कि क्या भारत को वह इसलिए चाहिए जिससे भविष्य में किसी विमान अपहरण की घटना के बाद इसे फिर आजाद कर अपहृत यात्रियों को मुक्त करवाया जा सके? भारत सरकार को पता नहीं यह बात क्यों समझ नहीं आती है कि यह कहावत हर क्षेत्र के लिए सही और शाश्वत है कि 'अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है'।

''भारत के विभिन्न भागों और विशेषकर जम्मू–कश्मीर में आतंकवादी हमले करवाने में पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तानी सेना और वहाँ की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. पाक अधिकृत कश्मीर एवं पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में कम से कम 52 आतंकवादी प्रशिक्षण केन्द्र चला रही है जहाँ तीन हजार से अधिक खूँखार आतंकवादियों को फिदायीन एवं अन्य आतंकवादी हमले करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।''[265] पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने के भारत के तमाम प्रयासों के बावजूद पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. समूचे देश और विशेषकर जम्मू–कश्मीर में आतंकवादी वारदात को अंजाम देने के लिए

[265] प्रो. मानचन्द खंडेला, ''अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद'', 2011, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, 807, व्यास बिल्डिंग, चौड़ा रास्ता, जयफर – 302003 (राज.) फोन 0141–2578159, पृष्ठ संख्या – 81

अपने यहाँ ये केन्द्र चला रही है। इन में से अधिकांश केन्द्र पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों में चलाये जा रहे हैं और वहाँ विभिन्न कट्टर आतंकवादी संगठनों के तीन हजार से अधिक आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में अफगानिस्तान की सीमा के निकट जनजातीय क्षेत्रों में चलाये जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों में बहुत कम उम्र के बच्चों एवं लड़कों को खूँखार आतंकवादी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महत्त्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि खुफिया एजेंसियाँ पहले ही सरकार को समय–समय पर आगाह करती रही हैं कि जैश–ए–मुहम्मद, लश्कर–ए–तैयबा, हरकत–उल–अंसार, जिहाद–ए–इस्लामी, हरकत–उल–मुजाहिदीन और अल बदर जैसे आतंकवादी संगठनों के आतंकवादियों के प्रशिक्षित पाकिस्तानी सेना और वहाँ की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. करती है।

बर्बादी की कहानी

सिर्फ 'स्वात घाटी' में ही नहीं, पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी जहाँ कट्टरपंथी संगठन सरकारी संगठनों पर हमले कर रहे हैं, कानून व्यवस्था के हाल खराब हैं। ''पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस इस्टडीज (पीआईपीएस) की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008 में पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में हुए लगभग 2,148 आतंकवादी हमलों में करीब 2,267 लोग मारे गए और 4,558 घायल हुए। 2008 में हुए 67 आत्मघाती बम धमाकों में 967 लोग मारे गए और 2,108 घायल हुए। ज्यादातर हमले अलकायदा, तंजीम–ए–इस्लामी के तोरा–बोरा समूह और कारी मुस्ताक समूह द्वारा कराए गए।''[266] रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2008 के दौरान रॉकेट हमलों की 381, सर कलम करने की 46, रिमोट कंट्रोल्ड बम हमलों की 112, बारूदी सुरंगों से विस्फोट की 110, गोली मारने की 451, आईईडी धमाकों की 373 घटनाएँ हुईं। इस दौरान 4,113 संदिग्ध आतंककारियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 30 अलकायदा, 3,759 तालिबान और ऐसे ही अन्य संगठनों से जुड़े और 354 बलोच उग्रवादी शामिल हैं। इस पूरी जानकारी के मद्देनजर यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान में यह सब चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पूरा देश तालिबान के कब्जे में होगा और मौजूदा न्यायिक प्रणाली की जगह शरीयत का कानून लागू कर दिया जाएगा।

गैर–कानूनी एफएम पर 'मुल्ला रेडियो' के नाम से पहचाना जाने वाला मौलाना फजलुल्ला पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अभियान की खुद अगुवाई कर रहा है। प्रतिबंध के बावजूद उसका एफएम रेडियो का प्रसारण बिना किसी रोक–टोक के जारी है। जिस पर वह अपने कार्यकर्त्ताओं को शरीयत लागू करने, सेना के खिलाफ लड़ने और क्षेत्र में अपना अधिकार जमाने के आदेश जारी करता रहता है। फजलुल्ला के पास शाहीन कमाण्डो फोर्स के नाम से एक पूरी मुस्तैद सेना है।

---

[266] वही, पृ.सं. – 193–194

पाकिस्तान की सीनेट में वर्ष 2008 के दौरान आन्तरिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा पेश आड्टकडों के अनुसार सीमान्त प्रान्त में करीब 1,200 आम नागरिक और सुरक्ष बलों के 189 सदस्य मारे गये हैं। लगभग 123 सरकारी स्कूल, 10 निजी स्कूल, कई वीडियो सीड़ी और नाई की दुकानें जबरन बन्द की जा चुकी हैं। आन्तरिक सुरक्षा मंत्री के अनुसार तालिबान अदालतों ने 40 लोगों पर अलग–अलग तरह के अपराधों के लिए मुकदमे चला रखे हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि जैश–ए–मुहम्मद का प्रमुख मौलाना मसूद अजहर भी अब अलकायदा और टीटीपी के साथ मिलकर इस क्षेत्र में सक्रिय है। कराची में प्रकाशित अखबार 'डॉन' के एक अनुमान के अनुसार स्वात घाटी की कुल 15 लाख की आबादी में से अब तक लगभग 6 लाख लोग यह क्षेत्र छोड़कर जा चुके हैं। सेना की इस क्षेत्र में चार ब्रिगेड तैनात है। मीडिया सेन्टर के अनुसार अक्टूबर, 2007 के बाद से अब तक सेना और अर्द्धसैनिक बलों के करीब 15 हजार सैनिकों ने 784 आतंकवादियों को मार गिराया जबकि इसी दौरान लगभग 189 सैनिक भी शहीद हुए। "आतंकवादियों ने 2007 के बाद से अब तक सुरक्षा बलों पर 165 बम हमले किए, इन में से 17 आत्मघाती बम धमाके शामिल हैं। आतंकवादियों ने इस अवधि में 20 फलों, 165 गर्ल्स स्कूलों, 80 वीडियो पार्लरों और बाल कटाने की 22 दुकानों को नष्ट कर दिया।"[267]

आतंकवादियों के हमले और अल–कायदा

17 दिसंबर 2002 को दिल्ली की विशेष अदालत ने पोटा एक्ट के तहत भारतीय संसद भवन पर 13 दिसंबर 2001 को हमला करने और देशद्रोह का शड्यंत्र रचने के आरोप में तीन अभियुक्तों को मृत्युदण्ड और उनकी एक महिला सहयोगी को पाँच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दिल्ली में 13 दिसम्बर 2001 के दिन संसद भवन के चारों तरफ गुनगुनी धूप फैली हुई थी, प्रांगण में खासी चहल–पहल थी। प्रश्नकाल में प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी स्वयं उपस्थित होकर उत्तर देने वाले थे, किन्तु किन्हीं कारण से लोकसभा की बैठक स्थगित हो गई थी। सुबह के अभी 11.30 ही बजे थे। केन्द्रीय मंत्री श्री गोयल प्रधानमंत्री की स्थगन की सूचना दे चुके थे। संसद भवन के गेट संख्या – 5 पर, जिससे होकर प्रधानमंत्री गुजरते थे, सुरक्षाकर्मी चौकन्ने थे, क्योंकि उन्हें अभी तक प्रधानमंत्री क्योंकि उन्हें अभी तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव की सूचना नहीं मिली थी। प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा कर रहे गेट नं. – 5 में सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। संसद भवन की मजबूत दीवारों की सी.आर.पी.एफ. तथा संसद भवन के सुरक्षाकर्मी पहरा दे रहे थे।

"एक एंबेसडर कार 13 दिसम्बर 2001 के दिन लगभग 11 बजकर 40 मिनट पर जिसके ऊपर लालबत्ती लगी थी और विंडस्क्रीन पर गृहमंत्रालय और हैविटेट सेंटर के पास चिपके थे, संसद भवन के बाहरी प्रांगण में सुरक्षाकर्मियों के पास से गुजरी। संतरी और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने पास से गुजरती गाड़ी की विंडस्क्रीन पर गृहमंत्रालय के पास आदि देखे। सहसा एक सुरक्षाकर्मी को एहसास हुआ कि कार पर

---

[267] वही, पृ.सं. – 195

समुचित पास नहीं लगा है तो उनसे गाड़ी को रूकने का इशारा किया। रूकने के स्थान पर ड्राईवर तेजी से कार को संसद के मुख्य द्वार की ओर भगाकर चला। सुरक्षा अधिकारी यादव ने अपने वाकी–टाकी पर सभी सुरक्षाकर्मियों को इस कार के बारे में सूचित कर दिया। कार में सवार पाँच लोग कमांडो जैसे लगते थे। अनेक मंत्रियों और सांसदों के पास ऐसे सुरक्षा प्रबंध होते ही हैं। कार में बैठे उन व्यक्तियों ने पहले ही समझ लिया था कि उनका अन्त अब समीप आ चुका है। संसद भवन के चार मुख्य भाग हैं – केंद्रीय हाल, लोकसभा, राज्यसभा और लाइब्रेरी। प्रवेश के लिए 12 द्वार हैं। मुख्य द्वार नंबर एक है। दस, ग्यारह, बारह नंबर के द्वार राज्यसभा के लिए और दो, तीन, चार नंबर के द्वार लोकसभा के लिए प्रयोग किए जाते हैं।''[268]

वाकी–टाकी पर सुरक्षा अधिकारी का संदेश सुनकर सभी सुरक्षाकर्मी चौकन्ने हो गये थे। इसी बीच कार से कूदकर भागे लोगों ने अंधाधुंध गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। उधर कार उपराष्ट्रपति के मोटर गाड़ियों के काफिले से जा टकराई क्योंकि आगे जाने का रास्ता न देखकर हड़बड़ाए ड्राईवर ये यू टर्न लेकर वापिस भागने का प्रयास किया था। अब तक कार में आए उग्रवादी बदहवासी में गोलियाँ चला रहे थे और ग्रेनेड विस्फोट कर रहे थे। वे असाल्ट राईफलों, ग्रेनेडों और बारूद से लैस थे। गोलीबारी की आवाज सुनकर सुरक्षाकर्मियों ने संसद भवन के सभी द्वार बंद कर दिये साथ ही बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने जवाबी कार्यवाही भी आरम्भ कर दी। प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा कर रहे गेट नं.–5 में सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। वे भी सुरक्षा अधिकारी का संदेश सुनकर चौकन्ने हो गये। वहाँ खड़े केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों ने भी उग्रवादियों पर गोलियाँ चलाई। एक उग्रवादी मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, वह ग्रेनेड विस्फोट कर रहा था। उसके शरीर पर भी विस्फोटक सामग्री बंधी थी। सुरक्षाकर्मियों ने उसकी गोलीबारी का जवाब दिया। ग्रेनेड फेंकते हुए वह चीखा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने लगा। तभी उसके शरीर पर बंधी विस्फोटक सामग्री में सुरक्षाकर्मियों की गोलीबारी के कारण भयंकर विस्फोट हुआ और उसके शरीर के चीथड़े चारों और फैल गए। मुख्य परिसर के बाहर उपस्थित समाचार–पत्र एवं टेलीविजन के संवाददाता और कैमरामैन इस आतंकवादी हमले का आँखों देखा हाल प्रसारित कर रहे थे, जिसे पूरा विश्व देख रहा था। चारों तरफ अराजकता का माहौल पैदा हो गया। कुछ संवाददाताओं ने यह भी कहा कि उग्रवादी संसद भवन के भीतर भी प्रवेश करके गोलीबारी कर रहे हैं, इस कारण उपराष्ट्रपति तथा मंत्रियों और सांसदों की सुरक्षा को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक था। आधे घंटे बाद गोलीबारी बंद हुई। चारों और रक्तरंजित शव और घायल लोग पड़े थे। उग्रवादियों द्वारा इस्तेमाल किये गये एंबेसडर कार से भारी पैमाने पर विध्वंसक हथियार बरामद किए गए। दस्तावेजों के अलावा एक मोबाइल फोन भी

---

[268] डॉ. विपिन कुमार मिश्रा, डॉ. आशुतोष पाण्डेय, ''भारत और आतंकवाद'', 2012, विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली – 110002, पृष्ठ संख्या – 180

घटनास्थल से बरामद हुआ। कार में तीन किलोग्राम विस्फोटक सामग्री लदी थी। उग्रवादी कार को संसद भवन से टकराकर ध्वस्त करने की योजना बनाकर आए थे।

घटनास्थल पर बरामद सूत्रों और अन्य विश्वस्त सूचनाओं से पता चला है कि मारे गए उग्रवादी अपने साथ गोला–बारूद के अलावा मेवे भी लाए थे। वे शायद मंत्रियों और सांसदों को बंधक बनाकर संसद भवन के भीतर ही रखना चाहते थे ताकि बदले में कुछ बड़ी कीमत वसूल सकें। विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों से पता चला है कि संसद भवन के हमले की योजना पाकिस्तान में बनाई गयी थी। चौबीस घंटे के अल्प समय में दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ में मारे गए उग्रवादियों से बरामद हुई सूचनाओं के आधार पर दो पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा। गिरफ्तार किए गए ये दोनों पाकिस्तानी नागरिक निरंतर सेल फोन पर हमलावरों से संपर्क साधते रहे थे। इन घटनाओं को अंजाम देने में लश्कर–ए–तैयबा तथा आई.एस.आई. का प्रमुख योगदान था। भारतीय गुप्तचरों ने संसद पर हमले के तुरंत बाद भारत में सक्रिय पाकिस्तानी उग्रवादियों और उनके पाकिस्तान स्थित संपर्क सूत्रों के बीच वायरलेस पर संसद पर हमले से संबंधित वार्तालाप सुना। वैसे भी इस फिदायीन (आत्मघाती) हमले की शैली से यह स्पष्ट था कि जैश–ए–मुहम्मद या लश्कर–ए–तैयबा जैसे संगठन से ही यह हमला कराया है।

"संसद हमले में सम्बन्धित अफरोज मोहम्मद नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया। अफरोज गरीब परिवार में जन्मा ऐसा युवक है जो बड़े–बड़े सपने देखता है वह कॉमर्शियल पायलेट बनना चाहता था लेकिन उसका पिता मामूली सा दर्जी था। वैसे भी अफरोज कॉलेज की पढ़ाई छोड़ चुका था। वह आस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड पायलेट बनने के लिए भी जा चुका था।"[269] आस्ट्रेलिया में उसने रॉयल विक्टोरियन एरो क्लब में 1997–98 में ट्रेनिंग भी की परन्तु बीच में अधूरी ही छोड़ दी थी। 1998–99 में पुनः पायलेट बनने का ख्वाब लेकर वह टेक्सास के एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में भर्ती हुआ परंतु दोबारा प्रशिक्षण अधूरा छोड़कर घर लौट आया। तीसरी बार उसने ट्रेनिंग इंग्लैंड में की। अनुमान किया जाता है कि तीनों देशों में उसकी ट्रेनिंग पर कम से कम 60–70 लाख रूपये का खर्च आया। उसने मुंबई पुलिस को बताया कि लंदन निवासी उसके एक चाचा ने उसका खर्च वहन किया था, जिस पर विश्वास करना कठिन है। इसकी गिरफ्तारी मुंबई पुलिस द्वारा 2 अक्टूबर, 2000 को की गई क्योंकि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक अंतर्राष्ट्रीय क्रैश कार्डो का इस्तेमाल कर रहा है और पानी की तरह रूपया बहा रहा है। मुंबई पुलिस ने तहकीकात के दौरान पाया कि दिल्ली के एएनजेड गिंडलेज बैंक से उसके मुम्बई खाते में सात लाख रूपये भेजे गये थे। किसने भेजे थे – इसका विवरण नहीं मिल सका। ऐसा अनुमान है कि भारत में

[269] वही, पृ. सं. – 182

सक्रिय कुछ उग्रवादी संगठनों ने उसे यह धनराशि भेजी थी। अफरोज सिमी का सदस्य है। यह आशंका जताई गई है कि अफरोज को यह धनराशि आत्मघाती दस्ते में भर्ती के लिए दी गई थी।

कश्मीर विधानसभा पर पहली अक्टूबर 2001 को हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी जैश–ए–मुहम्मद ने ली थी, भले ही चंद घंटे बाद यह संगठन मुकर गया। यूनाईटेड जिहाद काउंसिल का गठन पाक–अधिकृत कश्मीर में किया गया, जिसमें जम्मू–कश्मीर में आतंक फैलाने वाले कई संगठन भी शामिल हैं। इस संगठन के प्रवक्ता ने विधानसभा पर हुए हमले में ओसामा बिन लादेन के आतंकवादी संगठन अल–कायदा के हाथ होने की संभावना जताई थी।

जिहादियों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ने चेचन्या, वेस्ट बैंक, इंडोनेशिया, कश्मीर, फिलीस्तीन तथा फिलीपीन में फैले इस्लामी उग्रवादियों से निकट संपर्क स्थापित किया। उन्हें एकता के सूत्र में पिरोने का सतत प्रयास हो रहा है। वे अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन और इंटरनेट के जरिये एक–दूसरे से जुड़े हैं। विश्व में 'इस्लाम का साम्राज्य' स्थापित करना इन उग्रवादियों का एकमात्र उद्देश्य है। कुरान हाथ में लेकर पाकिस्तानी सेना के मेजर एहसानुलहक ने (जिसने अमेरिकी ग्रीनबेरी के साथ ट्रेनिंग ली थी, जो एक वर्ष पहले तक कश्मीर मुस्लिम जिहाद का कमांडर था) कहा, "पूरी दुनिया अल्लाह की है, इसलिए उसी का कानून पूरी धरती पर स्थापित किया जाएगा।"

ओसामा बिन लादेन तथा उसके संगठन अल–कायदा ने सम्पूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा आतंक तथा घृणा फैलाई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद जब अमेरिका ने अलकायदा सहित ओसामा बिन लादेन का नाम जुड़ा पाया तो उसके विरूद्ध अभियान में कोई कसर नहीं रखी। दक्षिणी यमन के मुहम्मद बिन अबदाह बिन लादेन के यहाँ 1957 में ओसामा बिन लादेन का जन्म हुआ था। यमन में जब साम्यवादियों ने पैर पसारने शुरू किए तो लादेन परिवार सऊदी अरब पलायन कर गया, जहाँ भवन निर्माण के क्षेत्र में उसके पिता ने अथाह धन–दौलत और ईज्जत कमाई। सऊदी अरब में सबसे अधिक धनी गैरशाही परिवार लादेन का ही परिवार ही बना। जेद्दाह विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में वहाँ जोर्डन मूल के डॉक्टर अब्दुल्ला अज्जाम ने उसे बहुत अधिक प्रभावित किया। वह मुस्लिम भाई–चारे का समर्थक था। ओसामा ने स्नातक हो जाने के बाद कुछ समय तक अपने पिता की मदद की और इस्लाम धर्म के रसरंग में डूब गया। ओसामा अस्सी के दशक के आस–पास अफगानिस्तान गया। फिलीस्तीनी हमास के ऐतिहासिक नेता रह चुके अज्जाम और प्रिंस तुर्की इब्न फैजल – जो सऊदी अरब का सुरक्षा प्रमुख था जिसे कुछ वर्ष पूर्व बर्खास्त कर दिया गया था – ओसामा के गुरू माने जाते है बाद में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या के संबंध में दोषी पाया गया डाक्टर जवाहरी उसका धार्मिक प्रणेता बना।

अज्जाम ने सन् 1982–84 के बीच मकतब–अल–खिदमत–अल–मुजाहिदीन–अल– अरब (मक्क) की स्थापना की, जिसे

अफगान ब्यूरो, आफिस ब्यूरो और सर्विस ब्यूरो के नाम से भी जाना जाता है। अज्जाम का प्रमुख सहायक मक्क के प्रमुख कोष संचयी ओसामा को समझा गया।

सन् 1984–86 के मध्य भारी संख्या में अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में अरब मुस्लिम युवकों का पलायन हुआ। उस समय धन इक्ट्ठा करने के लिए ओसामा में ज्यादातर समय अरब यात्रा में बिताया। उसने अरब और मुस्लिम युवकों को इस्लाम के नाम पर लड़ने के लिए भर्ती किया तथा उन्हें धार्मिक, सैनिक और शारीरिक शिक्षा दी। ये युवक अमेरिका से लेकर फिलीपीन तक फैले अनेक देशों से भर्ती किए गए। पश्चिमी देशों का अरबों रूपया मक्क ने अफगानिस्तान में जिहाद के लिए प्रबंध–व्यवस्था, प्रशिक्षण तथा सामरिक साजो–सामान जुटाने आदि पर खर्च कर दिये। मक्क के माध्यम से ओसामा बिन लादेन ने पाकिस्तान की आई.एस.आई. से निकट संबंध स्थापित किए। सऊदी अरब में उसने वहाँ के समाज सेवकों, मिस्र की सरकार तथा अरब जगत के नेताओं के साथ–साथ बहुत बड़ी मुस्लिम बिरादरी से प्रगाढ़ रिश्ता विकसित किया।

पाकिस्तान की आई.एस.आई. के माध्यम से अमेरिकी सी.आई.ए. अफगान और विदेशी मुजाहिदीन की ट्रेनिंग और हथियारों आदि की व्यवस्था करती थी। उन्होंने विशिष्ट हथियार, युद्ध–कौशल के भेद, स्ट्रिंगर मिसाइलें और भू–उपग्रहों के जरिये प्रभावित क्षेत्रों के चित्रा मुजाहिदीन को भेजे। अफगानिस्तान में युद्ध और सहायता कार्यों में दो बैंकों ने विशेष योगदान दिया, जिनके नाम दर अल मल अल इस्लामी (संस्थापक तुर्की के प्रिंस मुहम्मद फैजल सन् 1981) और दल्ला अल बराका (स्थापना सन् 1982) हैं। दोनों बैंकों ने 20 गैर–सरकारी संगठनों की धनराशि भी संभाली और खर्च की। इनमें प्रमुख इंटरनेशनल इस्लामिक रिलीफ ऑर्गेनाईजेशन, इस्लामी राहत एजेंसी और वर्ल्ड इस्लामिक लीग (प्रमुख मुफ्ती अब्दुल अजीज बिन बाज) की छत्रछाया में पनप रही थी। हजारों अनुदान संस्थाओं तथा मस्जिदों में अपनी पकड़ बनाने वाली मक्क एक निरंकुश संगठन के रूप में उभरा जिसकी पकड़ सम्पूर्ण विश्व पर थी।

अफगानिस्तान में रूसियों के विरूद्ध ओसामा बिन लादेन ने कभी भी अमेरिका के प्रति अपनी कटु भावनाओं को प्रकट नहीं किया। लेकिन अफगानिस्तान से रूसी सेनाओं की वापसी के बाद उसने पूरे मुस्लिम जगत को एक सूत्र में पिरोने का निर्णय लिया। अफगानी नेतृत्व पर मतभेद होने के बाद भी ओसामा तथा डॉ. अज्जाम एक साथ काम करते रहे। अल–कायदा ने मक्क के 'पैन इस्लामिक' आदर्शों का पूरा लाभ उठाया और धन और तकनीकी स्रोतों का पूरा दोहन किया।

ओसामा रूस विरोधी युद्ध के बाद सऊदी अरब लौट गया, जहाँ उसने दक्षिणी यमन में जेहादी संगठन बनाने में सऊदी अरब की सहायता की। जब ईराक ने कुवैत पर हमला किया तो अमेरिका खाड़ी युद्ध में कूद पड़ा। सऊदी अरब के अनुरोध पर अमेरिकी सैनिक वहाँ तैनात किए गए तो ओसामा भड़क उठा। उसे दो पवित्र मस्जिदों की भूमि पर गैर मुस्लिम सैनिकों को मौजूदगी मन्जूर नहीं थी। उसने नाराजगी प्रिंस टर्की को बताई। वायदे के अनुसार जब इराकी खतरा खत्म हो गया,

फिर भी वहाँ से अमेरिकी सेनायें नहीं हटाई गई तो उसने सऊदी शासकों को 'काफिर' घोषित कर दिया। उन्हें झूठा मुसलमान माना और एक सच्चा इस्लामी राज्य स्थापित करने की घोषणा की। परिणामस्वरूप 1992 में ओसामा को सऊदी अरब से निकाल बाहर किया गया तथा उसकी सऊदी नागरिकता भी 1994 में समाप्त कर दी गई।

ओसामा ने सन् 1989 के बाद अच्छी तरह प्रशिक्षित और अनुभवी लड़ाकुओं को पाकिस्तान से स्वीडन भेजा। वहाँ उसने 30 ऐसी कंपनियाँ स्थापित की जो तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी थी और आनुवांशिक श्रेतसंबंधी शोधकार्य से लेकर भवन निर्माण कार्य भी करती थी परन्तु 1996 में ओसामा को अन्तर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से पुनः अफगानिस्तन वापिस आना पड़ा। अल–कायदा जैसा मजबूत और सक्रिय कोई उग्रवादी संगठन उस समय विश्व में नहीं था। अफगानिस्तान में ओसामा ने रूसियों से टक्कर लेने के बाद अलकायदा की स्थापना की और मुस्लिम जगत की उन सरकारों को उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया जो पाश्चात्य जगत से प्रभावित थीं। अमेरीकियों तथा यहूदियों के खिलाफ लादेन ने खाड़ी युद्ध के बाद जिहाद छेड़ा। जान–माल की क्षति झेलने की अलकायदा में अनोखी क्षमता है। न तो यह विश्वव्यापी अकेला संगठन है और न ही दर्जनों आतंकवादियों का गठजोड़। यह विश्व भर के इस्लामी उग्रवादी संगठनों का ऐसा संगठन है, जिसमें अलजीरिया, मिस्र, कश्मीर, उज्बेकिस्तान चेचन्या, फिलीपीन, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के उग्रवादी शामिल हैं। इन सभी के अलग–अलग संगठन तथा नियंत्रण एंव संचार प्रणाली हैं परन्तु जरूरत पर सभी साथ–साथ काम करते हैं।

अलकायदा ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यतः योजनएँ बनाने षड्यंत्र रचने और नेतृत्व प्रदान करने का काम करता है। अलकायदा की स्थापना ओसामा बिन लादेन ने इसलिए की थी ताकि अफगानिस्तान में रूसियों के विरूद्ध लड़ने वाले अरब और अन्य देशों के मुसलमानों को एक साथ जोड़ा जा सके। अफगानिस्तान में अलकायदा ने पाकिस्तान को आई.एस.आई. जिसमें अधिकतर सैनिक अधिकारी कार्यरत थे और पाकिस्तानी कट्टरपंथी राजनेताओं की सहायता से अफगान बगावत के दौरान सुन्नी इस्लामी चरमपंथी की भर्ती, ट्रेनिंग तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और धन उपलब्ध कराने में सहायता की। पूरे विश्व में अलकायदा मध्ययुगीन कट्टरपंथी इस्लामी शैली का साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। फरवरी 1998 में वर्ल्ड इस्लामिक फंड फॉर जिहाद अगेंस्ट ज्यूज एंड क्रूसेडर्स के बैनर तले एक वक्तव्य जारी किया गया, जिसमें ओसामा बिन लादेन ने कहा – अमेरीकियों का कत्ल करना विश्व के सभी मुसलमानों पर परम कर्त्तव्य है।

1989 में ओसामा बिन लादेन ने कश्मीर में जिहाद की घोषणा की। उसने हरकत–उल–जिहाद–इस्लामी, हरकत–उल–मुजाहिदीन, लश्कर–ए–तैयबा, हरकत–उल–अंसार और जैश–ए–मुहम्मद नामक तंजीमों की सहायता देने की घोषणा की। उसने पूरे विश्व में जिसमें भारत भी शामिल हैं 'निजाम–ए–मुस्तफा' स्थापित करने का फैसला भी किया। लादेन ने वर्ल्ड इस्लामिक फंड का फरवरी

1998 में जिहाद के लिए संगठन किया। इस संगठन का उद्देश्य मध्यपूर्व को इजरायल से मुक्त कराना, सऊदी अरब की पवित्र भूमि से अमेरिकी सैनिकों को हटाना, वर्तमान सऊदी शासकों को जो उसके अनुसार बेईमान और पथभ्रष्ट मुसलमान हैं – उखाड़ फेंकना है, ताकि मुसलमानों को खलीफा सरकार में एक छत्राछाया के नीचे संगठित किया जा सके। 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद उसने अमेरिका को धमकाया कि यदि भारत की सहायता जारी रखी गई तो और अधिक अमेरिकी मौत के घाट उतरेंगे। रूस और भारत का नाम भी ओसामा ने अमेरिका के साथ–साथ इस्लाम के शत्रुओं में जोड़ दिया।

आई.एस.आई. ने अल–कायदा के गठन, ट्रेनिंग, भर्ती और कार्य योजनाओं को साकार करने के लिए सैनिक शैली की सहायता दी। अल–कायदा दो दर्जन से अधिक उग्रवादी संगठनों का ऐसा सरल गठजोड़ है, जहाँ भिन्न–भिन्न उग्रवादी संगठन अपना शिकार चुनकर योजना बनाते हैं और आतंक का तांडव रचते है। अलकायदा उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्ग–दर्शन और नेतृत्व प्रदान करता है। मिस्र का इस्लामिक जिहाद (ईआईजे) और अल–गमइया, अल–इस्लामिक (आईजी), अल्जीरिया का आम इस्लामिक ग्रुप (जीआईए) और इस्लामिक पार्टी ऑफ तुर्किस्तान (आईपीटी), इस्लामिक मूवमेंट इन उज्बेकिस्तान, जैश–ए–मुहम्मद (जेईएम) और फिलीपीन का अबू सयाफ ग्रुप (एएसजी) शामिल है।

अलकायदा की जड़ें बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के अलावा इण्डोनेशिया, नेपाल, चेचन्या तथा चीन तक फैली हैं। आवश्यकता पडने पर यह संगठन यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भी उग्रवादियों के लिए प्रबंध और सहायता उपलब्ध कराता है। अफगानिस्तान में उसने अपने 30 प्रतिशत केन्द्र खोले थे। जिनमें "विश्व के कोने–कोने से जिहाद के लिए भर्ती किए गए मुस्लिम युवक कट्टरपंथी धार्मिक प्रेरणा, सैनिक और संचार–संबंधी ट्रेनिंग लेते थे। ट्रेनिंग का दौर छः हफ्ते से शुरू होता था, जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण, हथियारों को शिक्षण, गोला–बारूद का इस्तेमाल और आतंक फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। पाकिस्तानी सेना के पूर्व कर्मचारियों को कुशाग्र बुद्धि प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त किया गया। जो उन्हें एडवांस ट्रेनिंग के दौरान गुप्त संदेश भेजने, भू–उपग्रह के माध्यम से संचार व्यवस्था स्थापित करने, इमारतों और महत्त्वपूर्ण संस्थाओं को गोला–बारूद से उड़ाने, सर्विलांश, अपहरण और हत्या की ट्रेनिंग देते थे। आई.एस.आई. की देख–रेख में ही यह काम होता है।"[270]

काबुल के पास स्थित रिशखोर भग्नावशेषों में स्थित स्कूल में एक हजार छियासी पृष्ठ वाला अल–कायदा का अरबी भाषा में लिखा हुआ एक ग्रन्थ मिला है। उसमें हर बात बहुत बारीकी से समझाई गई है। इसकी सूचना शैली से स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ पाकिस्तानी सैन्याधिकारियों और आई.एस.आई. के अधिकारियों की सहायता से रचा गया है। इसमें भारतीय धर्म, समाज, राजनीति, व्यवस्था, हिन्दू संगठनों

[270] वही, पृ.सं. – 190

विशेषकर–विश्व हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, स्वदेशी जागरण मंच, शिवसेना आदि का विस्तृत विवरण है। कारों में शत्रु का पीछा करना, उन्हें नष्ट करना, बूबी ट्रेप लगाना, पानी के जहाजों को नष्ट करने, हवाई जहाजों पर हमले के नुस्खे फस्तक में सचित्रा लिखें है। आतंकवादियों के लिए रचे गए इस ग्रन्थ इस में रासायनिक और जैविक शस्त्रों के विवरण भी हैं। कम–से–कम ग्यारह हजार कट्टरपंथियों को अल–कायदा ने रिशखोर में आतंक फैलाने की शिक्षा दी थी। अल–कायदा ने विश्व भर के लगभग 70,000 चरमपंथी अनुयायियों को जिहाद के लिए ट्रेनिंग दी। अमेरिका ने रिशखोर पर अचूक हवाई हमले किये थे, जो काबुल से केवल 15 किलोमीटर दूर है।

ओसामा ने प्रारम्भ में अफगानिस्तान प्रवास के दरम्यान अमेरिका के प्रति घृणा का प्रदर्शन नहीं किया था। लेकिन जैसे ही रूसी सेनाएँ पीछे हटी, उसने पैर पसारने और अमेरिका को तेवर दिखाने शुरू कर दिए। अलकायदा ने केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर बम विस्फोट किए, जिनमें कम–से–कम तीन सौ लोग मारे गए और पाँच हजार लोग घायल हुए। इस संगठन ने 1993 में अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को मार गिराया और दिसंबर 1992 में यमन में अमेरिकी सैनिकों पर बम भी फेंके। 1994 में मनीला में पोप की हत्या और प्रशांत महासागर के ऊपर एक दर्जन अमेरिकी जहाजों पर विस्फोट करने तथा फिलीपीन यात्रा के दौरन बिल क्लिंटन की हत्या की योजनाएँ भी अल–कायदा ने बनाई थी। पूर्वी अन्रीका में, 1998 में, 2000 में अमेरिकी विध्वंसक पर यमन में और सितंबर 2001 में तीन अलग–अलग स्थानों पर अल–कायदा के उग्रवादियों ने छह हजार से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया।

1997 में ओसामा बिन लादेन चोरी–छिपे कश्मीर घाटी में भी आया था और शोफर और शोफिया में उसने वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की थी। उसी समय कश्मीरी मूल का एक डॉक्टर सऊदी अरब से विशाल धनराशि लेकर ओसामा से मिला था। ओसामा बिन लादेन कश्मीरी मिलिटेंटों से 12 जून 1998 में खोस्त में मिला और कश्मीरियों को भारी धनराशि देने का वादा किया। कारगिल में घुसपैठ और युद्ध के कुचक्र की रचना से सभी परिचित है। अफगानिस्तान में युद्धरत 055 बिग्रेड के 200 सैनिक ओसामा बिन लादेन की अनुमति से कारगिल युद्ध में भाग लेने को भेजे गए। इसमें अरब मूल के यमन, अरब, अल्जीरिया, जोर्डन, स्वीडन, तुर्की, केन्द्रीय, लीबिया, एशिया के तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपीन के आतंकवादी भी थे। "जम्मू–कश्मीर में दो वर्ष के ठेके पर आई.एस.आई. ने विदेशी मूल के अनेक आतंकवादियों को भेजा। इन में से हर एक को दो से पाँच लाख रूपये की धनराशि दी गई। मुठभेड़ में मारे जाने पर उनके परिवारों को इससे दोगुनी राशि का भुगतान किया गया।"[271]

[271] वही, पृ.सं. – 194

अफगानिस्तान से 1989 में रूसी सेनाएँ वापिस लौट गई तो आई.एस.आई. ने अनेक ट्रेनिंग कैंपों को इस्लामी आतंक बढ़ाने के लिए जिहाद के नाम पर इस्तेमाल किया। यह इस्लामी आतंक विश्वव्यापी बनकर उभरा, जिसमें विश्व के अनेक देशों में भर्ती करके लाए गए तालिबान को इस्लामी जिहाद के लिए प्रशिक्षित ही नहीं फिदायीन (आत्मघाती) हमलों के लिए भी तैयार किया गया। इस प्रयास में ओसामा बिन लादेन का अल–कायदा सबसे अग्रणी था। इस्लामी आतंकवादियों ने सी.आई.ए. मुख्यालय के सामने ही इस गुप्तचर संस्था के अधिकारियों की हत्या कर डाली। अफगानिस्तान में रूस के विरूद्ध संघर्ष के प्रयत्नों में जुटा लादेन चुप रहा, लेकिन रूसी सेनाओं की वापसी और अल–कायदा के गठन के बाद उसने अमेरिका, इजरायल और सऊदी अरब विरोधी स्वर बुलंद किया। अमेरिका का नाराज होकर आई.एस.आई. पर अंकुश लगाने (जिस प्रयास में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो असफल रहीं थी) हेतु पाकिस्तान पर दबाव इतना स्वाभाविक था। इस्लामी आतंकवादियों से पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था का गठजोड़ आई.एस.आई. के शीर्षक्रम में परिवर्तन के बाद भी जारी रहा।

आई.एस.आई. का प्रमुख उद्देश्य कश्मीर में स्थानीय लोगों को भड़काना, युवकों में कूट–कूटकर कटरपंथी भावनाएँ भरना और मदरसों में कट्टरपंथियों द्वारा इस्लाम की शिक्षा बच्चों को देना, विरोधी प्रेस, पाकिस्तान रेडियो और टीवी के जरिये भारत विरोधी प्रचार करना, जम्मू–कश्मीर के सरकारी कार्यालयों में अपने एजेंटों की घुसपैठ कराना, कश्मीर के बुद्धिजीवियों को खरीदना (भले ही उसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े) महत्त्वपूर्ण फलों को नष्ट करना, सुरक्षाबलों पर हमले करना ताकि सुरक्षाबलों के आने–जाने में गतिरोध आए, अफगानिस्तान और अन्य देशों से भाड़े के आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने के लिए भेजना और कश्मीर में आतंकवादियों की भड़काने वाली कार्यवाहियों और तोड़–फोड़ के लिए हर प्रकार की सहायता देना शामिल है। नाजुक ठिकानों पर हमला करना तथा कश्मीर को भारत से अलग करना ही आई.एस.आई. का प्रमुख उद्देश्य है।

असम और पश्चिमी बंगाल में आई.एस.आई. के कुछ एजेंट पकड़े गए। उनके पास से भारी मात्रा में आरडीएक्स और अन्य अत्यन्त संवेदनशील विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि आई.एस.आई. पूर्वोत्तर भारत को इस तरह निशाना बनाकर वहाँ उपद्रव फैलाना चाहती है कि शांति व्यवस्था भंग होने के साथ सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जा सके।

अफगानिस्तान में आतंकवाद

अफगानिस्तान में आतंकवादी कार्यवाहियों का इतिहास बहुत फराना है। यहाँ हमेशा कुछ आतंकवादी गिरोहों ने हिंसा के सहारे चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलट कर कई बार सत्ता हथियाई है। यदि हम 1980 के दशक पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि उस समय यहाँ डॉ. नजीबुल्ला के राष्ट्रपतित्व में एक समाजवादी सरकार काम कर रही थी जिसे पूर्व सोवियत संघ का समर्थन हासिल था। धीरे–धीरे कुछ मुजाहिदीन गुटों ने सरकार के खिलाफ लामबंद होना शुरू किया और हिंसा का रूख

अपना लिया। नजीबुल्ला सरकार की हिफाजत के लिए तत्कालीन सोवियत सेना यहाँ आ डटी तो अमेरिका ने पाकिस्तान के माध्यम से अरबों डॉलर के घातक हथियार और बम आदि मुजाहिद दहशतगर्दो को उपलब्ध कराए। मुजाहिदों ने पाकिस्तान और ईरान की धरती से वर्षों तक संघर्ष किया और अंततः नजीबुल्ला सरकार को उखाड़ फेंका तथा अफगानिस्तान में इस्लामी शासन की स्थापना की।

अमेरिकी पैसे और हथियारों के बल पर मुजाहिदीनों ने अफगानिस्तान की धरती पर हिंसा का नंगा खेल खेला जिसके परिणामस्वरूप सोवियत सेनाओं को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और राष्ट्रपति डॉ. नजीबुल्ला के बाद मुजाहिदीन स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय में शरण ली। नजीबुल्ला के बाद मुजाहिदीन सरकार सत्ता में आई जिसका नेतृत्व बुरहानुद्दीन रब्बानी कर रहे थे। इस्लामी क्रान्ति के फलस्वरूप मुजाहिदीन सरकार तो अस्तित्त्व में आ गई लेकिन आतंकवाद के अभिशाप से अफगानिस्तान को अभी मुक्ति नहीं मिली थी। अब 'तालिबान मिलिशिया' नामक कट्टरपंथी आतंकवाद संगठन ने रब्बानी सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। वर्षों तक चले खून–खराबे और लाखों जिंदगियों की कीमत पर रब्बानी सरकार का पतन हुआ और तालिबान के लड़ाकों ने कबुल पर कब्जा कर लिया। 1996 के अन्त में तालिबान के कट्टरपंथियों ने अपदस्थ राष्ट्रपति डॉ. नजीबुल्ला और उनके भाई को एक चौराहे पर खंभे से लटकाकर फांसी दे दी।

बुरहानुद्दीन सरकार को धूल में मिला देने वाला 'तालिबान मिलिशिया', अतिवादी मुस्लिम अफगानों का एक घोर आतंकवादी संगठन था। इसने पाकिस्तानी से मिले पैसे और हथियारों के बल पर रब्बानी सरकार को रूखसत कर दिया और स्वयं गद्दी पर कब्जा कर लिया। अब "तालिबान की बागडोर मुल्ला उमर नामक आतंकवादी ने संभाली और वह अफगानिस्तान का भाग्य–विधाता बन बैठा। कट्टरपंथी तालिबान के शासन के बावजूद अभी अफगानिस्तान में शांति नहीं लौटी थी क्योंकि देश के कई हिस्सों पर अभी भी तालिबान विरोधियों का कब्जा था, जो रह–रहकर हिंसात्मक कार्यवाही कर रहे थे। अब तालिबान विरोधियों ने 'नार्दन एलायंस' के नाम से अपनी बिखरी शक्ति को इकट्ठा किया और तालिबान के खिलाफ और तेजी से हमले प्रारंभ कर दिए। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के अंत की आधारशिला रख थी। 11 सितंबर, 2001 को अमेरिका पर भयानक आतंकवादी हमला हुआ। गगनचुंबी 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर' के दो टॉवरों तथ अमेरिका रक्षा मुख्यालय 'पेंटागन' के एक हिस्से को आतंकवादियों ने नागरिक विमानों की सहायता से उड़ा दिया जिसमें हजारों अमेरिकी मारे गए। अमेरिका ने इस घटना के लिए ओसामा बिन लादेन नामक सऊदी आतंकवादी को जिम्मेदार ठहराया। 'अल–कायदा' नामक आतंकवादी संगठन का सरगना लादेन भाग कर अफगानिस्तान आ छुपा। अमेरिका ने तालिबान शासकों से कहा कि वे लादेन को उसे सुपुर्द कर दें लेकिन धर्मयुद्ध के नाम पर तालिबान ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त सेनाओं ने पाकिस्तानी धरती का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। महीनों युद्ध चला, हजारों मासूम अफगानी मारे गए, लाखों विस्थापित हो गए और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई।

अंततः अफगानिस्तान में तालिबान शासन का अंत हुआ और 'नार्दन एलायंस' सहित कई संगठनों ने मिल–जुलकर सत्ता संभाली। आज भी अफगानिस्तान में कुछ लादेन समर्थन आतंकवादी कार्यवाहियाँ कर रहे हैं, बम–धमाके हो रहे हैं जिसका सीधा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है।''[272]

''अमेरिकी खुफिया प्रमुख जॉन नेग्रोपोंट की पाकिस्तान को अल–कायदा आतंकियों का सुरक्षित स्वर्ग बताने वाली टिप्पणी से इस्लामाबाद में पहले ही खलबली मची हुई थी। अब अमेरिकी विदेशी मंत्रालय ने भी साफ कहा कि पाकिस्तान में अल–कायदा और तालिबानी आतंकी छिपे है और वे बेहद सुरक्षित है। विदेश विभाग के प्रवक्ता सियान मैक्कार्मक ने नेग्रोपोंट के आरोपों की फष्टि एक दिन बाद करते हुए कहा कि अल–कायदा नेताओं का पाकिस्तान में सुरक्षित ठिकाना है।''[273] प्रवक्ता का साफ इशारा अल–कायदा सुप्रीमो ओसामा बिन लादेन और तालिबान प्रमुख मुल्ला उमर के पाक में छिपे होने को लेकर था। हालाँकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उधर, पाक के कबायली इलाकों से अफगानिस्तान में घुसकर आतंकवादियों से चिंतित अमेरिकी रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स ने शीघ्र अफगानिस्तान जाने का कार्यक्रम तय किया ताकि जमीनी हकीकत का पता लगाया जा सके और अफगानिस्तान में तालिबान के फिर से उभार की खबरों की सच्चाई को नजदीक से जाँचा जा सके। दूसरी ओर इस्लामाबाद आए अमेरिकी विदेशी उपमंत्री रिचर्ड बाउचर ने भी उत्तरी वजीरिस्तान में सक्रिय आतंकियों ने समझौता करने की मुशर्रफ सरकार की नीति पर सवालिया निशान लगा दिया। इस बारे में वाशिंगटन की नाराजगी से उन्होंने पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को अवगत करा दिया। इस बीच अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नेग्रोपोंट की टिप्पणी दरअसल आतंकवाद की लड़ाई में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अमेरिकी बैचेनी को ही दर्शाता है क्योंकि एक तरफ तो इस्लामाबाद आतंकवाद की लड़ाई में हमारे साथ है और दूसरी ओर पाकिस्तान ही अल–कायदा व तालिबान का गढ़ बना हुआ है।

2.2 हमास (HAMAS–Harakat al-Muqawama al-Islamiyya)

आज विश्व का शायद ही कोई देश हो जहाँ आतंकवाद एक समस्या न हो। ''प्रायः सभी देशों में धार्मिक उन्मादियों, नशीले पदार्थों के व्यापारियों एवं स्वार्थी तत्त्वों द्वारा हिसां के माध्यम से अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आतंकवादी संगठन बना लिए जाते हैं और ऐसे संगठनों में गरीबी की मार से पीड़ित विकृत मानसिकता वाले व्यक्तियों को भर्ती कर लिया जाता है। उनकी मानसिक अपरिपक्वता के कारण

[272] नरेन्द्र कुमार शर्मा, ''भारत में नक्सलवाद'', 2012, ओमेगा पब्लिकेशन्स, 4378/4 बी, जी–4जे. एम.डी. हाऊस गली मुरारीलाल, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, फोन 65901906, पृष्ठ संख्या–187–188

[273] डॉ. कृष्णानन्द शुक्ल, ''लाल शीत युद्ध की दास्तान–भारत और पाकिस्तान'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, दूरभाष 011–23255141, पृष्ठ संख्या – 48–49

उन्हें अर्थ के साथ ही अन्य प्रकार के लालच दिये जाते हैं।''[274] एक बार जो व्यक्ति ऐसे संगठनों के चंगुल में फंस जाता है, उससे उसका बाहर निकलना प्रायः असम्भव–सा हो जाता है। उदाहरण के लिए दाऊद इब्राहिम प्रारम्भ में केवल मुम्बई तक सक्रिय था लेकिन आज उसका साम्राज्य लादेन की तरह ही संसार के कई देशों में स्थापित हो गया है। इसका कारण यही है कि एक बार व्यक्ति ने ऐसे संगठनों के माध्यम से हिंसात्मक कार्यवाही कर ली तो भविष्य में उसे लगातार ऐसी कार्यवाही करते रहना पड़ता है। दूसरी ओर ऐसे संगठन हिंसा में लिप्त व्यक्तियों को तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक अर्थ का लालच देते हैं। इजरायल, फिलीस्तीन, ईरान और इराक जैसे देशों में जो आतंकवादी संगठन बने हैं, उनका आधार तथाकथित राष्ट्रवाद रहा है जबकि राष्ट्रवाद के नाम पर एक व्यक्ति केवल अपनी सत्ता को बचाये रखने के ही प्रयत्न करता है। ऐसे उग्रवादी संगठन अरब देशों में ही अधिक हैं, जिन्हें राष्ट्रवाद के साथ–साथ धर्म के नाम पर भी संगठित किया गया है।

1. फिलीस्तीन मुक्ति संगठन (Palestine Liberation Organization–PLO)

1962 में एक फिलीस्तीन धर्म निरपेक्ष समूह के रूप में इसकी स्थापना हुई। 1968 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर यासिर अराफात (Yasir Arafat) के नेतृत्व में यह संगठन आ गया और 2004 में अराफात की मृत्यु तक उसी के नेतृत्व में कार्यरत रहा। PLO ने 1993 में ओस्लो समझौते (Oslo Accords) के अन्तर्गत इजरायल को मान्यता प्रदान की और पश्चिमी किनारा (West Bank) और गाजा पट्टी (Gaza Strip) में अपनी सरकार की स्थापना की। यद्यपि 2000 की अन्तिम स्थिति वार्ताओं की शर्तों से असन्तुष्ट होकर इजरायल के खिलाफ दूसरा विद्रोह (2000–2005) प्रारम्भ कर दिया इन पाँच वर्षों के दौरान अल–अक्स मार्तिर्स ब्रिगेड (Al-Aqsa Martyrs Brigades) नामक एक प्रमुख हिंसात्मक समूह ने च्स्ट के साथ मिलकर इजरायल के खिलाफ दर्जनों आत्मघाती–हमलों को अंजाम दिया। "PLO फिलीस्तीनी मुक्ति आन्दोलन को आगे बढ़ाने वाला प्रमुख संगठन है। PLO के पहले अध्यक्ष यासिर अराफात की मृत्यु के बाद महमूद अब्बास को अध्यक्ष बनाया गया।''[275]

2. पॉफलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पेलेस्टाइन

अपने मूल संगठन से अलग हुए इस गुट के नामकरण के साथ 'जनरल कमांड' भी जुडता है। 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के बाद इस गुट की ओर भी शक की निगाहें घूमी थी, लेकिन फिलीस्तीन के राष्ट्रपति यासिर अराफात ने इसका जोरदार खंडन किया था। हालाँकि यह संगठन अराफात के 'फिलीस्तीन मुक्ति संगठन' (पी.एल.ओ.) के विरोध में है। सीरिया में इसका मुख्यालय है, लेकिन लेबनान में भी इसके अड्ड़े बताए जाते हैं। पॉफलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पेलेस्टाइन इसका मूल संगठन है, जिसका नेता अबु अली मुस्तफा था। उसकी हत्या कर दी गई थी। यह

---

[274] प्रो. मानचन्द खंडेला, ''अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद'', 2011, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स , 807, व्यास बिल्डिंग, चौड़ा रास्ता, जयफर – 302003 (राज.), फोन 0141–2578159, पृष्ठ संख्या – 8

[275] डॉ. लल्लन जी सिंह, ''राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा'', 2006, प्रकाश बुक डिपो, बड़ा बाजार, बरेली– 243003, दूरभाष 2470217, पृष्ठ संख्या – 75

संगठन फिलीस्तीन–इजरायल समझौता वार्ताओं का विरोध करता रहा है। सन् 1970 के दशक में इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी हमले किए और सन् 1978 से इस संगठन ने इजराइल और उदार अरब लोगों को 'निशाना' बनाया तथा उन पर लगातार हमले किए। "इस संगठन में करीब 8 सौ आतंकवादी बताए जाते हैं। इसके अड्डे सीरिया, लेबनान, इजरायल, और उसके काबिज इलाकों में है लेकिन सीरिया ही इसका मुख्य मददगार देश है। सैकड़ों आतंकवादियों और समर्थकों की ताकतवाले इस संगठन को सीरिया और ईरान से मदद मिलती हैं।"[276]

3. अल–फतह (Al-Fatah)

"विश्व प्रसिद्ध फिलीस्तीनी संगठन अल–फतह की स्थापना 1959 में मिस्र की राजधानी काहिरा में सक्रिय विद्यार्थी नेताओं द्वारा की गई।"[277] इसके नेता अहमद हुसैन अगीजा है तथा अन्यों में सालाह खालाफ, फारूख कछदाउमी, खलील अल–वजीर और खालिद अल–हसन आदि है।

4. हमास (HAMAS – Harakat al-Muqawama al-Islamiyya)

यह शेख अहमद यासिन (Shaykh Ahmad Yasin) द्वारा 1987 में स्थापित एक प्रमुख फिलीस्तीनी कट्टरपंथी समूह है (जिसकी 2004 में हत्या कर दी गई थी), हमास की एक ऐसी राष्ट्रीय कट्टरपंथी इस्लामिक सोच दृष्टि (Vision) है जिसके अनुसार वह सम्पूर्ण ऐतिहासिक फिलीस्तीन (जिसमें इजरायल, West Bank और Gaza Strip तीनों शामिल हैं) को मुसलमानों की पैतृक सम्पत्ति होने का दावा करता है। हमास अपनी स्थापना वर्ष (1987) से अब तक इजरायल के विरूद्ध अनेकों आतंकवादी और आत्मघाती संक्रियायें (Suicide Operations) कर चुका है। 2006 में हमास ने PNA (Palestinian National Authority - फिलीस्तीनी राष्ट्रीय अधिकरण) की सरकार को मान लिया। PLO ने 1993 ई. में ही PNA की सरकार का घोषण पत्र जारी कर दिया था।

"हमास की स्थापना इजरायल के गाजा जिले और जूडिया तथा सामारा में हुई। इसके सदस्य तरह–तरह के नाम वाले संगठन बनाकर आतंकवादी कार्यवाहियाँ करते हैं। सड़कों पर हिंसा करने में ये पूर्णतः दक्ष है। इसका मुखिया मूसा अबु मारजुक अमरीका में रहता है।"[278]

"इजरायल और उसके काबिजवाले इलाकों में सक्रिय इस खतरनाक आतंकवादी संगठन का मुखिया महमूद–अल–जहर है। हमास का मकसद 'इस्लामी फिलीस्तीनी देश' बनाने का है। लिहाजा वह इजरायल के यहूदियों को निशाना बनाता रहता है और उनके खिलाफ आत्मघाती बमों का इस्तेमाल करता है। हमास के आतंकियों और समर्थकों की अनुमानित संख्या भी उपलब्ध नहीं है। फिलीस्तीन

---

[276] विवेक सक्सेना, सुशील राजेश, "जेहाद का जुनून", 2011, सत्साहित्य प्रकाशन, 205–बी, चावड़ी बाजार, दिल्ली – 110006, पृष्ठ संख्या – 103

[277] डॉ. लल्लन जी सिंह, "राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा", 2006, प्रकाश बुक डिपो, बड़ा बाजार, बरेली–243003, दूरभाष 2470217, पृष्ठ संख्या – 76–77

[278] डॉ. लल्लन जी सिंह, "राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा", 2006, प्रकाश बुक डिपो, बड़ा बाजार, बरेली–243003, दूरभाष 2470217, पृष्ठ संख्या – 77

एवं ईरान के अलावा सऊदी अरब के निजी लाभार्थी गुट भी इस संगठन की मदद करते रहते हैं।''[279]

''हमास का नारा इस्लामिक प्रतिरोधी आन्दोलन छेड़ना है इसका गढ़ गाजा पट्टी व पश्चिमी किनारा है। हमास की स्थापना 1987 फिलीस्तीन क्षेत्र में गृहयुद्ध के साथ हुई हैं। कहते हैं कि हमास को ईरान के कुछ मुल्लों और अमेरिका में रह रहे धनी अरबी मुसलमानों का समर्थन प्राप्त है। हमास और फिलीस्तीनी इस्लामिक जिहाद (PIJ) दस शांति विरोधी समूहों के सदस्य भी है।''[280]

फिलीस्तीन में चल रहे संघर्ष में हमास इस्लामिक जिहाद और अल–अक्स ब्रिगेड प्रेरित और भोले–भाले युवकों–युवतियों की पर्याप्त आपूर्ति करते हैं, जो आत्मघाती हमलों को अंजाम देना अपना धार्मिक कर्त्तव्य समझते हैं। इसी प्रकार की स्थिति पाकिस्तान में भी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेहादी खुद को रूस में उड़ाते हैं या भारत, अमेरिका आदि देशों में। पाक उग्रवादियों के मामले में यह आपूर्ति सीमाहीन है। असंख्या युवाओं को हजारों मदरसों में जिहाद के लिए तैयार और फिर जिहादी संगठनों में शामिल किया गया है। गरीबी से त्रस्त, अशिक्षित तथा अर्द्धशिक्षित जनता पाकिस्तान के लोगों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है। गरीबी और जनसंख्या विस्तार का मिश्रण एक ऐसा ज्वलनशील मिश्रण है, जो इस्लामिक जिहाद को अनिश्चित काल तक जारी रख सकती है। इस अभावग्रस्त गरीब वर्ग को रूढ़िवादी तत्त्वों के अधीन रखने के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं। बल प्रयोग तथा बंदूक के जोर से आधुनिकता के विरोध पर जोर दिया जाता है। इन परिस्थितियों में सामाजिक दबाव बनाना सरल हो जाता है, जो अभिभावकों को अपने बच्चों के बलिदान पर गर्व जताने के लिए प्रेरित करता है। तथाकथित शहीदों के परिवारों को इस शहादत के बदले प्रचुर मात्रा में धन दिया जाता है। इस प्रक्रिया में अधिक–से–अधिक युवा इन संगठनों में शामिल होते हैं, जो मानव बमों का प्रशिक्षण देकर बाहर भेजते हैं। यह एक संयोजित प्रक्रिया है जिसे उसके अंतहीन भर्ती आधार के कारण किसी बड़ी शक्ति द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। जब तक ये समाज जनसंख्या विस्तार, यानि बड़े आकार के परिवारों को प्रोत्साहित करते रहेंगे, इस्लामिक जिहाद अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के किसी भी वार को झेलने, उनका सामना करने और बच निकलने में सफल रहेगा। एक आतंकवादी संरचना को नष्ट करने के लिए इस पक्ष को भी ध्यान में रखना होगा।

इस संदर्भ में, मारे गये लोगों की संख्या महत्त्वपूर्ण हो जाती है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाले देशों, जहाँ जनसंख्या केवल तेईस से पच्चीस वर्षों में दोगुनी हो जाती है, बड़ी संख्या में लोगों का मारना अप्रासंगिक हो जाता है। पहला, तेजी से

---

[279] विवेक सक्सेना, सुशील राजेश, ''जेहाद का जुनून'', 2011, सत्साहित्य प्रकाशन, 205–बी, चावड़ी बाजार, दिल्ली – 110006, पृष्ठ संख्या – 102

[280] डॉ. मानचन्द खंडेला, ''अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद'', 2011, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स , 807, व्यास बिल्डिंग, चौड़ा रास्ता, जयफर – 302003 (राज.), फोन 0141–2578159, पृष्ठ संख्या – 11

बढ़ती जनसंख्या के कारण और दूसरा, इस प्रकार के उपदेशों के कारण कि आत्मघाती मिशन स्वर्ग का पासपोर्ट हैं। इसलिए ऐसे समाज जितने अधिक जिहादी उत्पन्न करते हैं, यह उनके जीवनोपरांत कल्याण के लिए उतना ही बेहतर होता है। उच्च प्रौद्योगिकी वहाँ प्रभावी नहीं होती, जहाँ लक्ष्य धुँधला होता है। उदारण के लिए इजरायल के मामले में पहले के विद्रोह में जहाँ अनुपात एक इजरायली के बदले दस फिलीस्तीनियों का था, हाल तक यह अनुपात एक इजरायली के बदले तीन फिलीस्तीनियों तक पहुँच चुका है। आगामी वर्षों में यह इजरायल के लिए उल्लेखनीय और प्रतिकूल तरीके से बदल सकता हैं।

5. फिलीस्तीनी इस्लामिक जिहाद (PIJ)

हमास का नारा इस्लामिक प्रतिरोधी आन्दोलन छेड़ना है, जबकि फिलीस्तीनी इस्लामिक जिहाद एक रेडिकल ग्रुप है। PIJ की स्थापना 1979 में की गई और इसका कार्यक्रम छापामार युद्ध रहा लेकिन प्रतीत होता है कि इसका अपने विरोधी गुट से समझौता हो गया जो इजरायल के साथ सुलह का समर्थन करने लगा है। हमास और फिलीस्तीनी इस्लामिक जिहादी दस शांति विरोधी समूहों के सदस्य भी है।

''यह आतंकवादी संगठन 'हमास' के नक्शे कदम पर ही चलता है। इसका मकसद भी 'इस्लामी फिलीस्तीनी देश' बनाना है, इसीलए इसके आतंकी इजरायलियों पर आत्मघाती मानव बमों द्वारा हमले करते है लेकिन इस आतंकवादी संगठन का आधार इराक में है। इसके साथ–साथ लीबिया भी इसे आर्थिक मदद पहुँचाता है।''[281]

इजरायल–फिलीस्तीन में आतंकवाद

विश्व के जिन हिस्सों में अभी आतंकवाद पनप रहा है, फल–फूल रहा है उनमें से अधिकतर आतंकवादी अपने संप्रदाय या जाति के लिए एक अलग राष्ट्र की माँग कर रहे हैं और इन पृथक्तावादी आंदोलनों की प्रेरणा–स्रोत इजरायल है। ''इजरायल विश्व का अकेला देश है जिसे आतंकवादियों ने अपनी दहशतगर्दी के बल पर प्राप्त किया था। अलग राष्ट्र के लिए यहूदियों के संघर्ष में तब अमेरिका और ब्रिटेन ने पूरा सहयोग दिया था और आज भी अमेरिका–ब्रिटेन आतंकवाद की कोख से जन्मे इजरायल को पूरा प्रश्रय देते हैं।''[282]

आज इजरायली आतंकवाद को पालने–पोषने वाला अमेरिका ही आज दहशतगर्दी का शिकार बन बैठा है। आज का इजरायल कभी फिलीस्तीन का ही एक हिस्सा था लेकिन यहाँ दहशतगर्दी का आलम 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में तब शुरू हुआ जब 'विश्व यहूदी कांग्रेस' ने 1897 में एक प्रस्ताव पास करके फिलीस्तीन

---

[281] विवेक सक्सेना, सुशील राजेश, ''जेहाद का जुनून'', 2011, सत्साहित्य प्रकाशन, 205–बी, चावड़ी बाजार, दिल्ली – 110006, पृष्ठ संख्या – 102–103

[282] नरेन्द्र कुमार शर्मा, ''भारत में नक्सलवाद'', 2012, ओमेगा पब्लिकेशन्स, 4378/4 बी, जी–4, जे.एम.डी. हाऊस, मुरारीलाल, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, फोन 65901906, पृष्ठ संख्या–185

में अलग यहूदी राज्य की माँग की। इस प्रस्ताव के पास होते ही फिलीस्तीन में यहूदी आतंकवाद शुरू हो गया। सबसे दहशतगर्दों ने यहूदीवादी कमीशन नामक लड़ाकू दस्ता बनाया और फिर 'अगना' नामक आतंकवादी संगठन अस्तित्व में आया। फिलीस्तीनी जनता के खिलाफ सबसे उग्र आंदोलन 'इर्गुन' नामक संगठन ने शुरू किया। इर्गुन ने अरबों की सैकड़ों बस्तियों में आग लगा दी, हजारों अरब महिलाओं के जिस्म पर दहशतगर्दी की छाप छोड़ी और कई सरकारी अधिकारियों, न्यायाधीशों व राजनीतिज्ञों का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी। इर्गुन की तर्ज पर बाद में 'स्टर्न ग्रुप' की स्थापना की गई जिसने अरब जनता पर बेहताशा जुल्म ढ़ाए।

दहशतगर्दी के कारण अरब की धरती पर जब इजरायल का उदय हो गया तो शेष बचे फिलीस्तीन में उग्र प्रतिक्रिया हुई और यहूदी विरोधी आतंकवाद शुरू हो गया। इस प्रकार फिलीस्तीनी आतंकवाद, यहूदी दहशतगर्दी के गर्भ से ही पैदा हुआ था। आज फिलीस्तीन में अनेकों ऐसे संगठन है जो अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला यहूदियों से आतंकवाद के जरिए ले रहे हैं। फिलीस्तीन का सबसे प्रमुख आतंकवादी संगठन 'फिलीस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाईजेशन' अर्थात् पी.एल.ओ. है लेकिन इसके अलावा भी वहाँ कई ऐसे संगठन सक्रिय हैं जैसे – अरब मुक्ति मोर्चा, पॉफलर फ्रंट ऑफ द पैलेस्टाइन लिबरेशन, पॉफलर डेमोक्रेटिक फ्रंट, अल–फतह, दि पॉफलर फ्रंट ऑफ दि लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, जनरल कमांडु ब्लैक सैप्टेबर, ब्लैक जून, अबू निदाल पैलेस्टाइन लिबरेशन फ्रंट, ऑर्गेनाईजेशन ऑफ दि आर्म्ड अरब स्ट्रगल, अरब आर्गेनाइजेशन आदि।

"फिलीस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाईजेशन (पी.एल.ओ.) का मानना है कि यहूदीवाद का खतरा केवल फिलीस्तीन के विरूद्ध न होकर समस्त अरब देशों के खिलाफ है इसलिए सभी अरब देशों को एकजुट होकर यहूदियों का मुकाबला करना चाहिए।"[283] पी.एल.ओ. का गठन मिस्र की राजधानी काहिरा में कुछ छात्रों ने किया था जिसने आज एक वटवृक्ष का रूप ले लिया है। यासिर अराफात आज पी.एल.ओ. के एकमात्र और सर्वमान्य नेता है। अराफात फिलीस्तीन की गाजा पट्टी के मूल निवासी हैं और उन्होंने बचपन से ही यहूदियों का अत्याचार झेला है। कुछ नेताओं ने पी.एल.ओ. से मतभेद होने के कारण एक अलग संगठन बना लिया है जो 'अल–फतह' के नाम से जाना जाता है। इन फिलीस्तनी संगठनों ने कई ऐसी आतंकवादी कार्यवाहियों को अंजाम दिया है कि एक बारगी तो पूरा विश्व थर्रा गया था। न जाने कितने बम विस्फोट, विमान अपहरण और हत्याओं के मामले पी.एल.ओ. के खाते में दर्ज हैं। दशकों पूर्व हुए फिलीस्तीन मुक्ति आन्दोलन ने आज दहशतगर्दी का आलम ओढ़ लिया है और आज भी फिलीस्तीनियों और इजरायलियों के बीच संघर्ष और एक–दूसरे पर जानलेवा हमला आम बात है।

---

[283] वही, पृ.सं. – 186

हिंसा की लपटों में घिरा पश्चिम एशिया

पश्चिम एशिया में एक बार फिर माहौल गरमा गया है और शांति प्रक्रिया खटाई में पड़ गई है। 1 दिसम्बर, 2001 को इजरायल के दो शहरों में फिलीस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के आत्मघाती दस्ते के हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजरायल ने इसे फिलीस्तीन की आतंकवादी कार्यवाही घोषित करते हुए। फिलीस्तीनी अथॉरिटी के दफ़्तरों पर मिसाइल और बमवर्षक विमानों से हमला कर दिया। इजरायल के हमले में फिलीस्तीनी नेता यासिर अराफात का जेनिन शहर में स्थित दफ्तर तबाह हो गया और गोजा शहर में उनके दो रूसी हेलीकॉप्टर नष्ट हो गए। इजरायल नें अपने हमले को आतंक के विरूद्ध युद्ध का नाम दिया और इसकी तुलना अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ चल रही अमेरिकी कार्यवाही से की। इजरायल का आरोप है कि अराफात आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी ओर फिलीस्तीनी अधिकारियों का मानना है कि इजरायल के कब्जे के कारण गाजा पट्टी में आतंकवादी फल–फूल रहे है। दोनों ओर से चल रहे आरोप–प्रत्यारोप के बीच अमेरिका का नजरिया एकतरफा दिख रहा है। फिलीस्तीनी आतंकवादी संगठनों की कार्यवाही पर उसने जो प्रतिक्रिया जताई, उसे इजरायल के पक्ष में माना जा सकता है। इजरायल की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि इजरायल सरकार यासिर अराफात को बर्खास्त कर फिलीस्तीनी अथॉरिटी को भंग करना चाह रही हैं। उधर अराफात ने हमास और इस्लामिक जिहाद के 100 से ज्यादा आतंकवादी को गिरफ्तार कराया है और संकेत दिया है कि वे आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं लेकिन न तो अराफात के लिए आतंकवाद को खत्म कर पाना संभव दिखता है और न इजरायल के लिए अराफात को अपदस्थ करना।

हालाँकि इजरायल और फिलीस्तीनी के संबंधों को देखते हुए हिंसा वहाँ के लिए कोई नई चीज नहीं है लेकिन दिसंबर के पहले हफ्ते में फिलीस्तीनी आतंकवादी गुटों ने सामूहिक रूप से जिस तरह इजरायली लोगों को मारा है उसकी आलोचना पूरी दुनिया में हुई है। इजरायल फिलीस्तीन की हिंसा का जवाब हिंसा से देता रहा है। इस बार भी उसने ऐसा ही किया है, लेकिन इसके साथ उसने अराफात को हटाने की चर्चा भी तेज कर दी। 1 दिसम्बर, 2001 के हमले का जवाब देने के क्रम में इजरायली फौजों ने फिलीस्तीनी को अपनी ताकत का अहसास भी करा दिया है। इजरायली सेना फिलीस्तीनी कब्जे वाली गाजा पट्टी पर पहुँच गई। यह हवाई अड्डा फिलीस्तीन की स्वायत्तता और उसके गर्व का प्रतीक है। इसके अलावा इजरायली फौजें फिलीस्तीन के कब्जे वाले नेब्लस, रामल्ला और तुककार्म गाँव में भी पहुँच गईं। इजरायली प्रधानमंत्री एरियल शैरोन ने टेलीविजन पर दिए गए अपने एक बयान में कहा कि यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है और वे अपने सभी साधनों से इससे लड़ेंगे। गाजा शहर में इजरायल में अराफात के दफ्तर पर एफ–16 लड़ाकू विमानों से हमला किया।

दोनों देशों के विवाद में पहली बार इस लड़ाकु विमान का इस्तेमाल हुआ है। इस हमले में पश्चिमी तट के जेनिन शहर में अराफात का दफ्तर और एक पुलिस स्टेशन नष्ट हुआ।

फिलीस्तीनी आतंवादी गुट के हमले के समय शैरोन अमेरिका में थे लेकिन वे आनन–फानन इजरायल लौटे और कैबिनेट की आपात बैठक की। इस बैठक में वामपंथी गुटों के विरोध के बावजूद कैबिनेट ने इस छह सूत्री प्रस्ताव मंजूर किया। इसमें फिलीस्तीनी अथॉरिटी को 'आतंकवाद समर्थिक इकाई' घोषित किया गया और इस तरह से अराफात के प्रशासन को शांति प्रक्रिया से अलग करने की तैयारी का आभास दिया गया। इस प्रस्ताव में अराफात के संगठन को हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठनों के बराबर बताया गया। एक अन्य प्रस्ताव में इजरायली कैबिनेट ने अराफात के संगठन फतह मूवमेंट के सशस्त्र गुट सिक्योरिटी यूनिट को 'आतंकवादी संगठन' घोषित किया गया। कैबिनेट ने माना है कि इजरायल पर हुए आतंकवादी हमले से पता चलता है कि उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए इजरायली सरकार को इस पर काबू की समिति को यह अधिकार दे दिया कि वह देश सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए।

पश्चिमी एशिया में अमेरिका का रूख साफ–साफ इजरायल के पक्ष में है। लादेन के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए अमेरिका राष्ट्रपति ने अराफात की ओर इशारा कर कहा था पश्चिम एशिया में शांति की बात करने वालों को चाहिए वे लादेन के खिलाफ खड़े हों और आतंक से युद्ध करें। बुश और पॉवेल, दोनों ने फिलीस्तीन के खिलाफ की गई इजरायली कार्यवाही पर कुछ नहीं कहा। अमेरिकी रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफील्ड ने तो अराफात को एक कमजोर नेता करार देते हुए उनकी उपलब्धियों को मामूली करार दिया।

अमेरिका और इजरायली नेताओं के बयानों से लगता है कि वे अराफात को हटाने की तैयारी में है लेकिन सवाल है कि अगर अराफात फिलीस्तीनियों के नेता नहीं रहेंगे तो फिलीस्तीन की स्वायत्तता का क्या होगा और पश्चिम एशिया में शांति बहाली के लिए चल रही प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी? इससे बड़ा सवाल है कि क्या मिस्र और दूसरे अरब देश अराफात की बर्खास्तगी को बर्दाशत करेंगे। यही बातें इजरायल और अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक रही हैं। दूसरी ओर अराफात ने भी मौके की नजाकत को समझा है, इसलिए उनके अधिकारियों ने कहा कि सरकार 'हमास', 'हिजबुल्ला' और 'इस्लामी जिहाद' को खत्म कर देगी। फिलीस्तीनी पुलिस ने हमास के 100 से ज्यादा आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया है। इसी गुट ने इजरायल पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। इसने कहा कि मुहम्मद अबू हनूद की हत्या कर बदला लेने के लिए यह कार्यवाही की गई।

अराफात ने 1996 में हमास को खत्म करने की कोशिश की थी। उस समय वे उसकी जड़ों तक पहुँच गए थे। भारी संख्या में हमास के लोग पकड़े गए थे और उसके ठिकानों पर सरकार ने कब्जा कर लिया था लेकिन अब हालात वैसे नहीं है। एक तरफ जहाँ अराफात की राजनीतिक पकड़ ढ़ीली हुई है वहीं दूसरी ओर सभी

आतंकवादी संगठनों में एक नई एकता पैदा हुई है। हमास और इस्लामी जिहाद ने इजरायल के खिलाफ साझा हमले का ऐलान किया है। इस बार इजरायल पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेते हुए हमास ने कहा – यहूदियों को अपनी जमीन से खदेड़ने के लिए साझा संघर्ष की राह पर पहली कार्यवाही है। इस बयान में अल–अक्सा ब्रिगेड भी शामिल है, जो कभी अराफात के फतह मूवमेंट में भी शामिल था। आतंकवादी संगठनों की इस एकजुटता से अराफात की राह मुश्किल हुई है। 1996 में अराफात के पक्ष में एक बात यह थी कि उस समय पश्चिम एशिया में शांति बहाली की प्रक्रिया जोर–शोर से चल रही थी, लेकिन अब वह स्थिति नहीं है।

2.3 लिट्टे (LTTE - Liberation Tigers of Tamil Eelam)

लिट्टे (तमिल–ऐलम के मुक्ति चीते) 1970 के दशक के मध्यकाल से, श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला एक हिंसात्मक संगठन है जिसकी स्थापना वेलूपिल्लई प्रभाकरण ने की (जो 18 मई 2009 को श्रीलंका सेना द्वारा मारा गया) यह भारत और श्रीलंका में सैकड़ों आत्मघाती हमले कर चुका है। प्रभाकरण 21 मई 1991 के राजीव गाँधी हत्याकाण्ड मामले में भारत में वांटेड भी था। EU (European Union) और अमेरिका ने भी लिट्टे को आतंकी संगठन की सूची में डाल रखा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, प्रभाकरण जमीन से करीब 30 फीट नीचे सर्व सुविधायुक्त वातानुकूलित बंकर में रहता था और पकड़े जाने से बचने के लिये रात में ही बाहर निकलता था।

श्रीलंका में तमिल उग्रवाद

''भारत के दक्षिण में हिन्दमहासागर को रक्तरंजित करने वाला एक छोटा सा देश श्रीलंका भारत के सामने एक समस्या बनकर खड़ा है।''[284] इस देश में तमिल और सिंहली मूल के लोगों के आपसी संघर्ष के परिणामस्वरूप तमिल टाइगर के आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम (LTTE) का जन्म हुआ। विश्व का यह ऐसा कुख्यात और आतंकवादी संगठन है, जिसने भारत और श्रीलंका के दो पूर्व राष्ट्राध्यक्षों की हत्या की। राजीव गाँधी की 1991 में और रणसिंधे प्रेमदास की 1993 में। श्रीलंका में बसे तमिलभाषी लोगों की जनसंख्या 12 प्रतिशत है। वे हिन्दू और ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, जबकि सिंहली बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज बड़ी संख्या में भारतीय तमिलों को श्रमिक बनाकर श्रीलंका ले गए थे। उनके लिए तो उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की थी लेकिन सिंहलियों के लिए नहीं।

1948 में स्वतंत्रता के बाद सिंहली–बहुत श्रीलंका सरकार ने सिंहलियों के वर्चस्व बनाने के लिए व्यवस्था की। तमिल हितों की अनदेखी हुई। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ी। तमिल का विभिन्न नीतियों और निर्देशों के जरिये दमन किया जाता रहा। इसी कारण वहाँ तमिल युवकों में बेरोजगारी बढ़ी।

---

[284] डॉ. आर.बी.सिंह, ''भारत में आतंकवाद'', 2010, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, फोन 23247003, पृष्ठ संख्या – 248

सामाजिक तथा सांप्रदायिक तनाव और संघर्ष बढ़ा। 1972 में अन्य तमिल मिलिटेंटों के साथ–साथ एलटीटीई का जन्म हुआ जिसका नेता कृतसंकल्प, अनुशासित और कर्मनिष्ठ लीडर वेलूपिल्लई प्रभाकरण थे। शुरू में उग्रवादियों ने सरकारी पदों पर आसीन उन तमिलों की हत्याएँ की जिन्हें वे गद्दार मानते थे। तत्पश्चात् नेताओं और पुलिस अफसरों तथा गोपनीय सूचना देने वालों को आतंकवादियों ने लक्ष्य बनाया। उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्रवाद का नारा बुलंद किया। आरंभ में श्रीलंकाई सेना उनसे टक्कर न ले पाई और जब तक सेना को फनर्गठित, शिक्षित, सुसज्जित किया गया, तब तक तमिल उग्रवादी ग्रामीण और नगरीय छापामार युद्ध में माहिर हो चुके थे। उन्होंने संवेदनशील उपकरण, नौकाए, शस्त्रासत्रा, गोला–बारूद और घातक विस्फोट करने वाली पर्याप्त सामग्री एकत्र कर ली। तमिल छापामार प्रशिक्षण लेने मध्यपूर्व एशिया और पड़ोसी देशों में भी गए। उन्होंने घात लगाकर हमले किए, बारूदी सुरंगों से विस्फोट किए, सार्वजनिक स्थानों पर आतंक फैलाया और श्रीलंका के अनेक नेताओं पर निशाना साधा। 1983 में श्रीलंका में खूनी जातीय दंगे हुए, जिनका आरंभ सिंहली संप्रदाय की प्रतिक्रिया के कारण हुआ। उन्होंने तमिलों द्वारा 13 सैनिकों की हत्या के विरोध में दंगे आरम्भ किए। तब लाखों तमिल सिंहली बहुल दक्षिणी प्रांत को छोड़कर उत्तर–पूर्वी प्रांत में पलायन कर गए। तमाम सिंहली भी उत्तर से पलायन कर गए। अगले 5 वर्षों में 20 हजार युवक तमिल स्वतंत्रता आंदोलन के मेरफदंड सिद्ध हुए।

शुरूआती दौर में भारत की गुप्तचर संस्था ने उन लोगों से सामंजस्य बनाया क्योंकि उस समय श्रीलंका का झुकाव पश्चिम की ओर था। भारत में हथियार और गोला–बारूद लेकर तमिलों ने श्रीलंका पर आतंक का कहर ढ़ा दिया। उन्होंने व्यावसायिक वाहनों, पादरियों, धार्मिक यात्रियों और अन्य संप्रदायों पर हमले किये और स्त्री–पुरूष तथा बच्चों को भी मौत के घाट उतार। उन्होंने सेना और पुलिस को निशाना बनाया। बदले में सैनिक और पुलिस दस्ते भी प्रतिक्रिया करते थे जिससे अनेक तमिल परिवार प्रभावित हुए। तमिल छापामार ऐसे परिवारों की सहायता के लिए आगे आए और उनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता ही रहा। मई 1987 में श्रीलंका सरकार ने असैनिक ठिकानों पर भारी बमबारी की जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए, जिससे असंतोष और बढ़ा। श्रीलंका का घटनाचक्र भारत के दक्षिणी तमिल बहुल क्षेत्रों को दुष्प्रभावित कर रहा था। दक्षिण में एक स्वतंत्र तमिल राज्य की माँग शुरू हो गई थी। तमिल उग्रवादी भारतीय गुप्तचर संस्था के नियंत्रण से बाहर हो गये थे। जुलाई 1987 में राजीव गाँधी ने भारत–श्रीलंका शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और प्ब्ज्ञथ् एक लाख सैनिक श्रीलंका में शांति बनाए रखने के लिए भेजे। लेकिन तीन महीने बाद तमिल टाइगरों ने भारतीय शांति–सेना के विरूद्ध भी युद्ध की घोषणा कर दी। यहाँ पर भारतीय सेना के पास हथियार तो नवीनतम थे किन्तु समुद्र तटीय क्षेत्रों एवं घने जंगलों में छापामार युद्ध करने का ज्यादा अनुभव नहीं रहा। स्थानीय लोगों से भी

उन्हें सहायता न मिली। 1989 में प्रेमदास चुनाव जीते और उन्होंने तमिलों से शांतिवार्ता की पहल की। उधर सिंहलियों ने विदेशी सेना (भारतीय सेना) को आक्रांता माना और सरकार के विरूद्ध संघर्ष का बिगुल बजा दिया। हिंसा तेज हो गई, जिसमें लगभग 40 हजार लोग मारे गये। सरकार के विरूद्ध मानव अधिकारों के हनन के अभियोग लगे। प्रेमदास ने भारतीय सेना की वापसी की माँग की, जो दिल्ली ने अस्वीकार कर दी। प्रेमदास ने चोरी–छिपे तमिलों को सैनिक सहायता देनी शुरू की। अंत में मार्च 1990 में भारतीय सेना (IPKF) स्वदेश लौट आई।

''तमिल उग्रवादियों ने अपने हमले की काफी आक्रामक बना दिया और तीन माह में चार सौ पुलिसकर्मियों को मार डाला। **मई 1991 में तमिल आत्मघातियों ने भारत में ही श्री राजीव गाँधी की हत्या कर दी।** तमिल उग्रवादियों की संख्या 1986 में तीन हजार थी जो 1996 में बढ़कर 16 हजार हो गई। उन्होंने विरोधी तमिलों की हत्याएँ की तथा 30 अन्य उग्रवादी संगठनों का सफाया किया।''[285] गद्दारों की मौत के घाट उतारा, आत्मघाती हमले किए, हत्याएँ की और बारूदी विस्फोट किए। उन्होंने राष्ट्रपति प्रेमदास की हत्या कर दी और कितने ही सैनिक–असैनिकों को मौत के घाट उतारा। तमिल टाइगरों का अनुशासन बहुत कठोर है। शराब, धूम्रपान और विवाहेतर संबंध निषि(हैं। संगठन की एक सेंट्रल कमेटी तो है, लेकिन सारे निर्णय प्रभाकरण ही लेता था। आतंकवादी कौशल के क्षेत्र में तमिल टाइगरों ने विश्व ख्याति अर्जित की है। प्रोपेगेंडा, इंटेलिजेन्स, ट्रेनिंग, शस्त्रासत्रा और धन एकत्र करने में भी वे माहिर है। उन्होंने उत्तरी श्रीलंका में दो हवाई अड्ड़े भी बना लिए और हवाई प्रशिक्षण के लिए कैंप को स्थापित किया। उन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन में पायलेट प्रशिक्षित कराए जो आत्मघाती मिशन में राडार पर भी नजर न आने वाले छोटे जहाजों में बारूद भरकर सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक ठिकानों पर विस्फोट करने के लिए देश–विदेश में बसे तमिल मूल के लोगों और भारत विरोधी अन्य संगठनों से संबंध स्थापित किए। 20 लाख डॉलर की धनराशि में कम–से–कम 60 प्रतिशत धनराशि उन्हें विदेशों में बसे तमिलों से ही प्राप्त होती है।

उग्रवादियों का अपना अन्तर्राष्ट्रीय मुख्यालय लंदन में और अन्य फ्रंट कार्यालय आस्ट्रेलिया, कनाडा, ंस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, स्कैंडिनेविया, स्विट्जरलैंड और जापान में स्थापित किए हैं, जो श्रीलंका को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के विरोध में लॉबिंग करते रहते हैं। उग्रवादियों के पास अपना नौसैनिक बेड़ा और भू–उपग्रह संचार व्यवस्था भी है। वे म्यांमार (बर्मा) के यूरोप के लिए हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं। उर्वरक, लकड़ी, चीनी, सीमेंट और अन्य व्यावसायिक वस्तुएँ जहाजों में लादकर ले जाते हैं। उन्होंने

---

[285] डॉ. विपिन कुमार मिश्रा, डॉ. आशुतोष पाण्डेय, ''भारत और आतंकवाद'', 2012, विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली – 110002, पृष्ठ संख्या – 54

यूरोप और एशिया में शेयर बाजार और संपत्ति में धन लगाया और मुद्रा तथा सोने का व्यापार करके भी खासी धनराशि अर्जित की।

''तमिल उग्रवादी जाली पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बनने में भी माहिर हैं। उन्होंने श्रीलंकाई सेना और पुलिस पर असंख्य हमले किए। 1993 के नवंबर माह में उन्होंने श्रीलंका के 640 सैनिक मार डाले। वे श्रीलंका के टैंक, मिसाइलें, नौकाए तेल भंडार और सरकारी इमारते नष्ट करते रहे हैं।''[286] सितम्बर 2002 में श्रीलंका सरकार और एलटीटीई के बीच एक समझौता हुआ। एलटीटीई ने अब अलग तमिल राज्य की माँग छोड़ दी है। 20 वर्ष बाद वहाँ शांति प्रक्रिया की बहाली संभव हुई है।

श्रीलंका : हिंसा का लंबा सिलसिला

श्रीलंका नामक छोटे से एशियाई देश में, जहाँ से कभी युद्ध ने शांति का संदेश सारी दुनिया को दिया था, आज आतंकवादी गतिविधियों के कारण आम जनजीवन लगभग ठप है, तमिलों–सिंहलियों की हिंसा–प्रतिहिंसा में रोज बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं लेकिन दहशतगर्दी की आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। 1982 से जारी हिंसा और आतंक के दौर ने 30 हजार से भी अधिक मासूमों की जान ले ली है।

श्रीलंका में तमिलों और सिंहलियों के बीच संघर्ष तब शुरू हुआ था, जब श्रीलंका 1948 में अंग्रेजों की दासता से मुक्त हुआ था। तमिलों ओर सिंहलियों का उद्गम स्थान भारत ही है। 17 वीं शताब्दी में उत्तरी बिहार और बंगाल से हजारों लोग श्रीलंका गए थे। ये लोग श्रीलंका में दक्षिण–पश्चिमी इलाकों में रहने लगे। दरअसल यही लोग बाद में सिंहली कहलाएँ। धीरे–धीरे इन लोगों का भारत से संबंध टूट गया। हालाँकि शुरू में ये लोग बंगला और बंगला मिश्रित मैथिली बोला करते थे लेकिन धीरे–धीरे इनकी बोली स्थानीय लोगों से घुलमिल गई और एक नई सिंहली विकसित हुई। धीरे–धीरे ये लोग खुद को श्रीलंका के ही मूल निवासी मानने लगे। दूसरी तरफ, श्रीलंका में मौजूद तमिल वे लोग हैं, जो 18वीं शताब्दी में भारत के तमिलनाडु प्रान्त से आकर यहाँ बसे हैं। अंग्रेज शासक ही उन्हें अपने फायदे के लिए तमिलनाडु से श्रीलंका ले गए थे। अंग्रेजों ने तमिल मजदूरों को श्रीलंका की सरहद पर बसाया और इन तमिलों का भारत के साथ संपर्क लगातार बना रहा। कुल मिलाकर श्रीलंका के तमिल खुद को भारतीय ही मानते रहे है और उनका भारत से जुड़ाव भी बना रहा। तमिलों का यही स्वभाव उन्हें सिंहलियों से अलग करने लगा। दोनों के बीच दीवारें खड़ी होने लगीं और इन दीवारों को अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए फख्ता बनाया।

भारतीय तमिलों और सिंहलियों ने बीच उस समय और ज्यादा दूरियाँ बढ़ गई, जब अंग्रजों ने भारतीय तमिलों को हर तरह की आर्थिक सुविधाएँ और राजनीतिक महत्त्व देना शुरू किया। अंग्रेजों के समय भारतीय तमिल श्रीलंका की

---

[286] वही, पृ. सं. – 55

अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका तो निभा ही रहे थे, अंग्रेजों की कृपा के चलते तमाम प्रशासनिक और शासकीय पदों पर भी तमिल विराजमान होने लगे। भारतीय तमिलों की हैसियत सुदृढ़ हुई। इससे श्रीलंका के तमिलों और सिंहलियों में क्रोध और घृणा का भाव पनपा। इसलिए 1948 में जब श्रीलंका आजाद हुआ और अंग्रेज यहाँ से चले गए तो भारतीय तमिलों के विरूद्ध श्रीलंका के मूल सिंहलियों और तमिलों का गुस्सा फूटकर बाहर आया। 1950 और 1952 में श्रीलंका में जबरदस्त जातीय दंगे हुए, जिनमें भारतीय तमिलों को काफी हानि हुई। 1957 में एक डब्ल्यू डी भंडायनायक के द्वारा श्रीलंका सरकार की बागड़ोर संभालते ही वहाँ सिंहली राष्ट्रवाद का परचम पूरी तरह से बुलंद हो गया। भंडारनायक ने खुद सिंहली राष्ट्रवाद को काफी बढ़ावा दिया। भंडारनायक ने तमिलों की अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को धीरे–धीरे छीनना शुरू किया।

अंग्रेजों के जमाने में तमिल श्रीलंका की सरकारी भाषा थी। लेकिन अंग्रेजों के बाद तमिल को राजभाषा के पद से उतार दिया गया। तमिल को सरकारी भाषा भी नहीं माना गया। इसी तरह के भेदभाव दूसरे क्षेत्रों में भी शुरू हो गए। हालत यहाँ तक पहुँचे कि 1977 तक श्रीलंका की पुलिस और सेना में एक भी भारतीय मूल का तमिल नहीं रहा। उनसे बराबरी के तमाम हक छीन लिए गए। यहाँ तक कि उन्हें देश की नागरिकता तक नहीं प्रदान की गई जबकि वे लोग सदियों से यहीं रह रहे थे। भारतीय तमिलों पर हुए इन तमाम अत्याचारों से ही तमिल अलगाववाद पैदा हुआ। ''1971 में तत्कालीन कोलंबो युनिवर्सिटी के एक छात्र वेलूपिल्लई प्रभाकरण ने जब देखा कि तमिलों के साथ दोयम दरजे का व्यवहार होता है, तो उनसे तमिल छात्रों का एक संगठन बनाया। बाद में लिट्टे जैसा खूँखार संगठन सामने आया।''[287] 1981–82 में तमिलों के विरूद्ध श्रीलंका में भयानक दंगे फूट पड़े। श्रीलंका की सेना ने भी तमिलों पर अत्याचार किए। हजारों तमिलों को इन सांप्रदायिक दंगों में अपनी जानें गंवानी पड़ी और श्रीलंका एक अंतहीन गृहयुद्ध में उलझ गया।

पिछले दो दशकों में श्रीलंका में कई सरकारें आईं–गईं। ये सभी सरकारें यूनाईटेड नेशनलिस्ट पार्टी या श्रीलंका फ्रीडम पार्टी की ही थी। दरअसल श्रीलंका फ्रीडम पार्टी चंद्रिका कुमारतुंग के पिता एस. डब्ल्यू. डी. भंडारनायक के द्वारा बनाई गई थी और श्रीलंका की आजादी के बाद सबसे ज्यादा शासनाध्यक्ष भंडारनायक के परिवार से ही आए हैं। श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के अलावा यूएनपी को भी अवसर मिले। श्रीलंका का इतिहास गवाह है कि जब श्रीलंका में यूएनपी की सरकार सत्तारूढ़ हुई है, उसने तमिलों की समस्याओं के बारे में सहानुभूतिपूर्वक सोचा है। तमिलों की समस्या के संबंध में भारत और श्रीलंका के बीच हुआ महत्त्वपूर्ण करार भी यूएनपी की

---

[287] नरेन्द्र कुमार शर्मा, ''भारत में नक्सलवाद'', 2012, ओमेगा पब्लिकेशन्स, 43478/4बी, जी–4, जे.एम.डी. हाऊस, गली मुरारीलाल, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, फोन 65901906, पृष्ठ संख्या–179

सरकार के रहते ही हुआ था। तब श्रीलंका के प्रधानमंत्री जूरियस जयवर्(ने हुआ करते थे। हालाँकि बाद में प्रेमदास ने इस समझौते का विरोध किया और खुद लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण ने भी भारतीय सेनाओं के विरूद्ध जंग लड़ी लेकिन एक ऐसा दौर जरूर आया था, जब जूरियस जयवर्(ने और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने मिलकर श्रीलंकाई तमिलों की समस्या का एक स्थाई हल लगभग खोज निकाला था।

पिछले सात सालों से श्रीलंका में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी की सरकार थी। पिछले चुनाव (वर्ष 2000) में चंद्रिका कुमारतुंग ने अपने साथ कई दूसरे दलों को भी शामिल कर लिया था और इस गठबंधन का नाम पीफल्स एलायंस रखा गया। चुनावों के पहले पीफल्स एलायंस को पूरा विश्वास था कि इस बार भी जीत उसी की होगी लेकिन मतदाताओं ने उसके इस विश्वास को तोड़ दिया। श्रीलंका के लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहला मौका है, जब राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दो अलग–अलग समूहों से आए हैं। हालाँकि प्रधानमंत्री रहते हुए चंद्रिका कुमारतुंग ने राष्ट्रपति के पद को जिस तरह सृजित किया था उसमें तमाम शक्तियाँ प्रधानमंत्री की बजाय राष्ट्रपति के पास हैं इसलिए अगर चंद्रिका के घोर विरोधी रहे रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री बनकर भी तमिल समस्या का कोई स्थायी हल न ढूँढ़ पाए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से श्रीलंका की जनता ने विपक्षी गठबंधन को समर्थन दिया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि यहाँ की जनता शांति और सौहार्द चाहती है।

श्रीलंका में लिट्टे की आतंकवादी गतिविधियाँ सक्रिय रही हैं। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की हत्या के लिए लिट्टे ही जिम्मेदार था। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम अर्थात लिट्टे का प्रमुख वेलूपिल्लई प्रभाकरण था और उसी ने लिट्टे की स्थापना 5 मई, 1976 को की थी। लिट्टे को विश्व का सबसे खतरनाक, संगठित और अनुशासित आतंकवादी संगठन माना जाता है। अपने आत्मघाती दस्तों के लिए भी लिट्टे कुख्यात है। इसे प्रभाकरण का जादू ही कहा जाएगा कि लिट्टे के सदस्य जान हथेली पर लेकर घूमते हैं और सरकारी सेना या बहुसंख्यक सिंहलियों से लड़ते हुए वे आसानी से अपनी जान तक दे देते हैं, पकड़े जाने पर बिना किसी डर के सायनाइड कैप्सूल खाकर मौत को गले लगा लेते हैं।

''लिट्टे के संदर्भ में एक प्रमुख बात यह है कि इसमें महिलाओं और बच्चों की भी संख्या भर्ती है जो अलग तमिल राज्य ईलम के लिए जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। लिट्टे के संगठन में एक–तिहाई से भी अधिक महिलाएँ तथा लगभग 40 प्रतिशत बच्चे हैं जो एक चौंकाने वाला तथ्य है।''[288]

लिट्टे को विश्व का सबसे संगठित और अनुशासित संगठन कहा जाता है तो इसके अपने कारण है। प्रत्येक लिट्टे सदस्य को 4 महीने का कठिन सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें उसे अत्याधुनिक हथियार चलाने से लेकर संचार, कम्प्यूटर और बौद्धिक संगठन की शिक्षा दी जाती है। वी. प्रभाकरण लिट्टे का

[288] वही, पृ. सं. – 183

सर्वोच्च नेता रहे है जो केन्द्रीय समिति का अध्यक्ष और लिट्टे की सेना के 'कमांडर–इन–चीफ' थे। लिट्टे का 'थिंक टैंक' माना जाने वाला एंटोन एस. बालासिंघम, प्रभाकरण को राजनीतिक सलाह देता था। इसके अलावा कई डिप्टी–कमांडर भी थे जो विभिन्न सैन्य–स्कंधों का कार्यभार संभालते थे। इन सैन्य–स्कंधों में भी–टाइगर्स, महिला–स्कंध, ब्लैक–टाइगर्स, आयुध, बौद्धिक स्कंध, गुप्तचर, योजना आदि सम्मिलित हैं।

राजीव गाँधी हत्याकाण्ड (Assassination of Sh. Rajiv Gandhi)

21 मई 1991 की रात को तमिलनाडु के पेरम्बदूर नामक स्थान पर श्री राजीव गाँधी को एक जन सभा को सम्बोधित करना था तब एक महिला मानव बम जिसने अपनी बेल्ट में रखे विस्फोटक पदार्थ से, पूफलमाला चरणों में रखने के बहाने आत्मघाती विस्फोट करके स्वयं को और राजीव गाँधी तथा अन्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह 30 वर्षीय महिला जिसका नाम 'धनु' था, लिट्टे की सदस्या थी।

भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठन

1. यूनाइटेड लिबरेशन प्रफंट ऑफ असम (ULFA)
2. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड
3. पीफल्स लिबरेशन आर्मी (PLA)
4. यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन प्रफंट (UNLF)
5. मणिफर पीफल्स लिबरेशन प्रंफट
6. ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स
7. नेशनल लिबरेशन प्रंफट ऑफ त्रिपुरा
8. बब्बर खालसा इन्टरनेशनल
9. खालसा कमांडों फोर्स
10. इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन
11. लश्कर–ए–तैयबा (LeT)
12. जैश–ए–मुहम्मद
13. हरकत–उल–मुजाहिदीन
14. हरकत–उल–अंसार
15. हरकत–उल–जिहाद–ए–इस्लामी
16. हिजबुल मुजाहिदीन (HM)
17. अल उमर मुजाहिदीन
18. जम्मू–कश्मीर इस्लामिक प्रंफट
19. लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE)
20. स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI)
21. दीनदार अंजुमन
22. पीफल्स वार ग्रुप (PWG)
23. अल बदर

24. अल–कायदा (Al-Queda)

25. तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी

भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन

पूर्वोत्तर राज्य

1. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड – आइजेक मूविया (NSCN-IM)
2. नागा नेशनल काउंसिल–फेडरल
3. नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड – खाप लांग
4. यूनाइटेड लिबरेशन प्रफंट ऑफ असम (ULFA)
5. पीफल्स लिबरेशन आर्मी (PLA)
6. कांगलेई यावोल कन्ना लुप
7. जोमी रेवोल्यूशनरी प्रफंट

उत्तर भारत

1. बब्बर खालसा
2. भिंडरावाला टाइगर्स फोर्स ऑफ खालिस्तान
3. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी)
4. दशमेष रेजीमेंट
5. इन्टरनेशनल सिक्ख यूथ फेडरेशन
6. कामागाटामारू दल ऑफ खालिस्तान
7. खालिस्तान कमांडो फोर्स
8. शहीद खालसा फोर्स

कश्मीर

1. लश्कर–ए–तैयबा (LeT)
2. जैश–ए–मुहम्मद
3. हिजबुल मुजाहिदीन (HM)
4. हरकत–उल–अंसार
5. फरजानदान–ए–मिल्लत
6. यूनाइटेड जिहाद कांउसिल
7. अल–कायदा (Al-Queda)
8. सिमी (SIMI)

मध्य भारत

1. पीफल्स वार ग्रुप (PWG)
2. बलबीर मिलीशिया
3. रणवीर सेना

विश्व के कुछ अन्य प्रमुख आतंकवादी संगठन

1. अबू हफ्रसअल–मास्री ब्रिगेड (Abu Hafsal-Masri Brigades ¼AHAMB))
2. अबू सैयफ (Abu Sayyaf)
3. अप्रीकन नेशनल काङ्ग्रेस (African National Congress ¼ANC))

4. अमल (हरकत अमल) (Harakat Amal)
5. आमिद टाङ्ग (Amida Tong)
6. अन्सार अल्लाह (Ansar Allah)
7. अन्सार अल–इस्लाम (Ansar al-Islam)
8. अन्सार अल–सुन्ना (Ansar al-Sunna)
9. अल–अक्स मार्टिरस ब्रिगेड (Al-Aqsa Martyrs Brigades)
10. अल–अरेबिया (Al-Arabiya)
11. बाथ पार्टी (Baath Party)
12. दार–उल–इस्लाम (Dar-ul-Islam)
13. इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद (Egyptian Islamic Jihad (EIJ))
14. गामाअट अल इस्लामियाँ (Gama at al-Islamiyya)
15. ग्लोबल इस्लामिक मीडिया फ्रंट (Global Islamic Media Front (GIMF))
16. ग्रुप इस्लामिक आर्मी (Groupe IslamQue Armee (GIA))
17. ग्रुप इस्लामिक काम्बेटेण्ट मोरोकेन (Groupe IslamQue Combatant Morocain (GICM))
18. ग्रुप सलाफिस्टे पोर ला प्रेडीकेशन ऐट ली कॉम्बेट (Groupe Salafiste pour la Predication et le combat)
19. हमास (Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (HAMAS))
20. हरकत अल–मुजाहिदीन (Harakat al-Mujahidin (HM))
21. हिज्ब अल–मुजाहिदीन (Hizb al-Mujahidin)
22. हिज्ब अल–तहरीर (Hizb al-Tahrir)
23. हिज्बुल्ला (Hizbullah)
24. अल–हुर्रा (Al-Hurra)
25. इस्लामिक जिहाद (Islamic Jihad)
26. इस्लामिक मोवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान (Islamic Movement of Uzbekistan (IMU))
27. जग्राता मुस्लिम जनता बांग्लादेश (Jagrata Muslim Janata Bangladesh)
28. जामा–ए–इस्लामियाँ (Jama-a-Islamiyya (JI))
29. जमाएते–इस्लामी (Jama'at-Islami)
30. जमाएते–उल–मुजाहिदीन (Jama'at ul-Mujahidin)
31. जैश–ए–मुहम्मद (Jaysh-i Muhammad)
32. अल–जज़ीरा (Al-Jazeera)
33. लश्करे–तैयबा (Lashkar-I Tayba (LeT))
34. लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE))
35. मेहदी आर्मी (Mahdi Army)
36. मजलिस अल–शूरा अल–मुजाहिदीन /मुजाहिदीन शूरा परिषद (Majlis al-Shura al-Mujahidin/The Mujahidin Shura Council)
37. मोरो इस्लामिक लिबरेशन प्रफंट (Moro Islamic Liberation Front (MILF))

38. मोरो नेशनल लिबरेशन प्रफंट (Moro National Liberation Front (MNLF))
39. नर्दन अलाइन्स (Northern Alliance (NA))
40. पैलेस्ताइन लिबरेशन ऑर्गेनाईजेशन (फिलीस्तीन मुक्ति संगठन) (Palestine Liberation Organization (PLO))
41. पैलेस्तीनियन नेशनल अथोरिटी (Palestinian National Authority (PNA))
42. पार्तिया कारकारेन कुर्दिस्तान (Partiya Karkaren Kurdistan (PKK))
43. पोलीसेरियो (POLISARIO)
44. पोफलर प्रफंट फॉर दी लिबरेशन ऑफ पैलेस्ताइन (Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP))
45. अल–कायदा (Al-Qaida)
46. अल–कायदा फि बिलाद अल–रफीदेन (Al-Quida Fi Bilad Al-Rafidayn)
47. रेडियो साबा (Radio Sawa)
48. रियाद अल–सालिहिन (चैचन विद्रोहियों का आत्मघाती ब्रिगेड) (Riyad Al-Salihin)
49. अल–साहब पब्लिकेशनस् (Al-Sahab Publications)
50. साउथ लेबेनीज आर्मी (South Lebanese Army (SLA))
51. तालिबान (Taliban)
52. तान्ज़िम क्वाइदात अल–जिहाद (Tanzim Qaidat Al-Jihad (TQAJ))
53. अल–थावरा अल–इस्लामियाँ अल–हुर्रा (Al-Thawra Al-Islamiyya Al-Hurra)

इसके अतिरिक्त और भी आतंकी संगठन विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय है –

1. हूजी (HUJI) बांग्लादेश में
2. उल्फा (ULFA) भारत में
3. सिमी (SIMI) भारत में
4. रणवीर सेना भारत में

नोट – रेडियो साबा, अलजजीरा, अल–हुर्रा, अल–अरेबिया आदि से सभी आतंकवादियों के रेडियो व दूरदर्शन स्टेशन हैं।

3

आत्मघाती दस्तों की संरचना का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण
(Psycho-Analysis of The Organization of Suicide-Squades)

यह परिकल्पना है कि आत्मघाती हमलावर निम्न कारणों से बनते हैं। जान सभी प्राणियों को प्यारी होती है चाहे वह मानव जाति का हो या कोई अन्य पशु,पक्षी या जीवधारी। मनुष्य बिना किसी कारण या प्रयोजन के अपनी जान गवाना नहीं चाहता, जब उसे कुछ उच्च मानव मूल्यों जैसे देश प्रेम, बलिदान, कुर्बानी, अन्याय एवं अधर्म के खिलाफ युद्ध का उपदेश दिया जाता है तो वह कुछ सीमा तक अपनी जान की बाजी लगाने को इच्छा या अनिच्छा से राजी हो जाता है परन्तु आज के आतंकवादी 'आत्मघाती हमलों' के लिये कैसे तैयार हो जाते हैं? जिसमें उनको शत–प्रतिशत इस बात का पक्का पता होता है कि तुमको मानव बम के रूप में प्रयोग किया जाना है और बच निकलने की कोई गुंजाईश नहीं।

इस बात का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं विद्वानों के विभिन्न मतों का अध्ययन करने के बाद कुछ कारणों की खोज करने के प्रयास किये गयें हैं जो आतंकवादियों को आत्मघात के लिये प्रेरित करते हैं। आत्मघाती अधिकांशतः पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईराक, श्रीलंका, फिलीस्तीन, मुस्लिम समाज से अधिक संबंधित है और उनके मन में अमेरिका जैसे देश के लिये सख्त नफरत की भावना पैदा हो गई। क्योंकि अमेरिका इजरायल की मदद अरब फिलीस्तीनियों के विरूद्ध करता है इराक में उसने सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा कर मुसलमानों को तंग किया, अफगानिस्तान में तालिबानों के खिलाफ लड़ रहा है। इसलिये विश्व के अधिकांश मुस्लिम देश अमेरिका (यू.एस.ए.) के विरूद्ध हो गये।

आतंकवादी जन्मजात नहीं होते हैं उनके हालात व मजबूरियाँ आतंकवादी गतिविधियों के लिये प्रेरित करती हैं। अपनी समस्याओं के समाधान व शोषण का बदला लेने के लिये आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लेना पड़ता है। कुछ युवाओं को धर्म व संस्कृति व देश की रक्षा के लिये आतंकवादी संगठनों में शामिल किया जाता है। इन्हें जिहाद का पाठ पढ़ाया जाता है। **इन युवाओं के मुँह से 'अमेरिका को मौत', भारतीयों को मौत, और 'काफिरों को मौत' आदि नारे बुलवाये जाते हैं।** हष्ट–फष्ट युवाओं को कठिन आतंकवादी प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण 12से 18 महीने का होता है। इन आत्मघाती दस्तों को प्रशिक्षण देकर फर्जी तरीके से विदेशों में भेजा जाता है ताकि वहाँ पर आतंकवाद व आत्मघाती हमलों को अंजाम दे सके और मिशन को पूरा कर सके।

आतंकवादी संगठनों में शामिल होने वाले युवकों को मासिक वेतन दिया जाता है। इस वेतन से गरीब घरों के युवा सन्तुष्ट होकर आतंकवादी संगठनों में शामिल हो जाते हैं और अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। बदले में इनके परिवार वालों को बहुत सारा धन दिया जाता है। इसके अलावा आतंकवादी

संगठन का मुखिया इन युवाओं को बहुत से प्रलोभन देता है। आतंकवादी संगठन मरने वाले को '**शहीद**' या '**स्वतंत्रता सेनानी**' की संज्ञा देता है। उसे '**अल्लाह**' का आदमी बताता है अर्थात् मरने वाले ने अल्लाह के हुक्म का पालन किया है। इसलिये उसे स्वर्ग (जन्नत) की प्राप्ति होगी। यहाँ पर यह कहना भी प्रासंगिक है कि **बाबर ने पानीपत के प्रथम संग्राम (1526 ई0) में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे कहा था, ''अगर तुम युद्ध में मारे गए तो सीधे जन्नत को जाओगे और अगर युद्ध जीत गए तो भारत जैसे वैभवशाली देश की सम्पत्ति का आनन्द लूटोगे''।**

हमें यह याद होना चाहिए कि ''इस्लाम के नाम पर आतंकवाद की शुरूआत 1980 में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के बाद वहाँ के तथाकथित मुजाहिदीनों द्वारा की गयी थी जिन्हें अमेरिका व पाकिस्तान का प्रत्यक्ष समर्थन हासिल था। इतना ही नहीं अफगान संगठन के दौरान अमेरिका की खुफिया एजेंसी सी.आई.ए. ने पाक–अफगान सीमा पर कई सैन्य प्रशिक्षण शिविर स्थापित कर, वहाँ आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया था जो वर्तमान में कश्मीर, चेचन्या, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि जगहों पर तथाकथित जिहाद चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बोस्निया, अल्जीरिया तथा चीन के सिक्याँग क्षेत्र में भी धीरे–धीरे इनकी गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं जो अधिकांश मुस्लिम राष्ट्र को अपनी चपेट में ले रही है।''[289] उस समय अमेरिका के समक्ष सोवियत विरोध की यह नीति शायद सर्वाधिक सहज व सुगम लगी थी और सोवियत–विरोध नीति के रूप में अफगानिस्तान में सोवियत संघ समर्थक डॉ. नजीबुल्लाह की सरकार को उखाड़ फेंक अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता स्थापित की बल्कि विश्व के सबसे बड़े इस्लामी जिहादी संगठन 'अलकायदा' का संस्थापक सरगना भी बना। 11 सितम्बर 2001 की घटना जिसमें आतंकवादियों ने अमेरिका के दो प्रतिष्ठित केन्द्रों – वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एवं पेंटागन को ध्वस्त कर डाला, के बाद अमेरिका का अलकायदा के प्रति मोह भंग तो अवश्य हुआ लेकिन पाकिस्तान का मोह अलकायदा व तालिबानी लड़ाकों के प्रति अभी भी विद्यमान है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि ''उत्तरी पाकिस्तान व अफगानिस्तान के इलाकों में तालिबानों की सल्तनत फिर पनपने लगी है। तालिबानी प्रशिक्षण शिविर फिर उग आए है, जैसे वहाँ की जमीन में ही न जाने कब से दबे हुए, उभरने का इन्तजार कर रहे थे। आत्मघाती दस्ते तैयार किए जा रहे हैं। अलकायदा की मदद से विदेशी रंगरूट दाखिल हो रहे हैं और विगत सितम्बर (05.09.2006) में हुए उत्तरी वजीरिस्तान के समझौते की आड़ लेकर पाकिस्तान की भौगोलिक सीमा के भीतर तालिबानी उग्रवादियों की नई सल्तनत खड़ी हो रही है। तालिबानी उन्माद में आए इस नए उभार को अमेरिकी और नाटो देशों के अधिकारीगण विस्मय से और पाकिस्तानी तथा अफगान गुप्तचर सेवाएँ भयभीत होकर देख रही हैं क्योकि यह

---

[289] डॉ. बाबूराम पाण्डेय, ''राष्ट्रीय रक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध'', पृष्ठ संख्या – 116

'सिनेरियों' उनका पहले से ही देखा हुआ है और वे समझ रहें हैं कि इस बार का 'तालिबिस्तान' पिछली बार से ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है।''[290]

यहाँ एक अहम प्रश्न यह है कि आखिर पाकिस्तान आतंकवाद का मार्ग क्यों नहीं छोड़ पा रहा है और वह अन्तर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद भी ओसामा बिन लादेन जैसे कट्टरपंथी जेहादियों का साथ क्यों नहीं छोड़ पा रहा है? इस प्रश्न का जवाब शायद जिस एक वाक्य में दिया जा सकता है वह है ''पाकिस्तान की अपनी कुछ निजी जरूरतें, जिसकी पूर्ति वह सार्वजनिक स्तर पर नहीं करा सकता और उसकी ये जरूरतें हो सकती हैं– अनुचित कार्यों हेतु धन की आवश्यकता तथा मुश्किलों में असैन्य स्तर से सैनिक मदद।'' इस नजरिये से यदि देखा जाए तो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के लिए काफी उपयोगी था, क्योंकि ''लादेन बहुत धनी आतंकवादी था, जिसके पास कम से कम 300 अरब डॉलर की सम्पत्ति थी। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य इस्लामी कट्टरपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देना था। उसके पास पाँच हजार से अधिक प्रशिक्षित आतंकवादी थे जो दुनिया के विभिन्न देशों से या तो रिटायर हुए बड़े फौजी अफसर थे या नए भर्ती हुए नौजवान, जो इस्लाम के नाम पर हर वक्त जान देने को तैयार रहते थे।''[291]

आत्मघाती दस्ता एक ऐसा हथियार है जिसकी काट कोई हथियार नहीं हो सकता। मानव बम का आज कोई बम मुकाबला नहीं कर सकता। आज आधुनिक जगत में संसार का सबसे सशक्त आत्मघाती दस्ता तैयार किया गया है। श्रीलंका में तमिल उग्रवादी संगठन का नाम है – लिट्टे। अपनी जान पर खेलकर हमले करने वाले दस्ते के दृष्टांत इतिहास में मिलते है। 11वीं सदी में दो खुट्टखार पंथ आत्मघाती दस्ते के नाम से जाने जाते थे। **एक था** यहुदी गुट सिकायरिस और **दूसरा था** इस्लामी गुट हाशीयना। 21वीं सदी के आत्मघाती दस्तों की जड़ 18वीं सदी के गुटों में मिलती है। आधुनिक सदी के मानव बम की टोली बनाने का काम सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 1979 में ईरान के अयातुल्ला खौमैनी ने शुरू किया जिसमें उन्हें सहयोग मिला लीबिया के कर्नल मुअम्मार गद्दाफी और फिलीस्तीनी नेता अराफत का। इनका संचालन केन्द्र बना लेबनान। इसके लिए धन आता है मुस्लिम देशों से। इनके अधिकांश आत्मघाती दस्ते ओसामा की अल–कायदा के साथ मिलकर योजनाएँ बनाते, जिसने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में अपने को ज्यादा केंद्रित कर रखा है।

''अब इस नई किस्म की लड़ाई का सबसे घृणित और अमानवीय पहलू है बच्चों को पढ़ाई की जगह आत्मघाती हमले का प्रशिक्षण देना। हँसने–खेलने की उम्र

---

[290] घनश्याम पंकज, लेख – ''पाकिस्तान में पनपती तालिबानी सल्तनत'', राष्ट्रीय सहारा, गोरखफर, 19 दिसम्बर 2002, पृष्ठ संख्या – 8

[291] प्रो. लल्लन जी सिंह, ''राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा'', पृष्ठ संख्या – 60

में उन्हें जान पर खेलना सिखाया जा रहा है।''[292] यह महामारी आज भारत के कश्मीर, उत्तर–पूर्व नक्सल प्रभावित झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ दक्षिण एशिया में संक्रमीत हो रही है।

''हर मुसलमान को बचपन में ही वफुरान पढ़ाते समय जिहाद की शपथ लेना सिखाया जाता है। 10 मई 1997 को सी.एन.एन. को दिये साक्षात्कार में ओसामा ने अफगान युद्ध के संदर्भ में जिहाद को अपने धर्म की पराकाष्ठा बताया।''[293] ओसामा सीरिया के प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान मुजाहिद तकी अल दिन इब्न तेमियाह का बड़ा प्रशंसक था जिसने मध्यकाल में नास्तिक तारतारों के खिलाफ लड़ने वाले अनेक मुजाहिदीन गुटों को प्रशिक्षण दिया था। उसने मुजाहिदीन की बड़ाई की और जिहाद का गुणगान किया। हदीस का उल्लेख करते हुए उसने न्याय के दिन तक जिहाद जारी रखने की बात कही – ''मेरे देश के लोगों में से कुछ हमेशा ऐसे रहेंगे जो सत्य की स्थापना करेंगे। न्याय के दिन तक उनसे उनके विरोधी या उनसे असहमति रखने वाले जूझ न पायेंगे।''[294]

''जिहाद–ए–अकबर की चर्चा इसलिए की गई है ताकि 9/11 की घटना से हुए विनाश के गुस्से को शांत किया जा सके। इस तरह कुरान व हदीस में जिहाद को काफी महत्त्व मिला है जो मुस्लिम राजाओं व जनता का बराबर समर्थन पाता रहा है।''[295] इस काफिरों के विरोध तथा उनके बलपूर्वक धर्मान्तरण के लिए इस्तेमाल में लाया गया है। कुछ इतिहासकारों ने पैगम्बर के जीवन के 82 जिहादों का अनुमोदन करने और इन में से 26 में स्वयं इनकी अगुवाई का उल्लेख किया।

''आत्मघाती हमलों में मानव शरीर के टुकड़े हो जाते हैं, जबकि नष्ट मकानों का फनर्निर्माण किया जा सकता है।''[296] मुस्लिम देश इजरायल में आत्मघाती हमलों पर भिन्न–भिन्न मत व्यक्त करते रहे हैं। मलेशिया ऐसे मिशनों को समाप्त करने का आग्रह कर रहा है जबकि सऊदी अरब फिलीस्तीनी आत्मघातियों को '**शहीद**' की संज्ञा दे रहा है।

भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर निर्दोष नागरिकों के बीच जाकर खुद को उड़ा लेने की उत्सुकता के पीछे संभावित कारणों का विश्लेषण बहुत से

---

[292] डॉ. वी.एन.अरोरा, डॉ. नन्द किशोर, डॉ. अभय कुमार सिंह, ''दक्षिण एशिया में सुरक्षा चुनौतियों के नये आयाम'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, दूरभाष 011–23255141, पृष्ठ संख्या – 178

[293] आर.के. ओहरी, ''इस्लाम के बढ़ते कदम'', 2007, मानस पब्लिकेशन्स, 4858, गली प्रहलाद, 24, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, फोन 23265523, पृष्ठ संख्या – 40

[294] सलमान रश्दी, ''यैस, दिस इज एबाउट इस्लाम'', संडे हिन्दुस्तान टाईम्स, 4 नवम्बर 2001

[295] आर.के.ओहरी, ''इस्लाम के बढ़ते कदम'', 2007, मानस पब्लिकेशन्स, 4858, गली प्रहलाद, 24, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, फोन 23265523, पृष्ठ संख्या – 42

[296] मेजर जनरल विनोद सहगल, ''अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद'', 2006, प्रभात प्रकाशन, 4/19, आसफ अली रोड़, नई दिल्ली–110002, पृष्ठ संख्या – 190

जाँचकर्त्ताओं तथा लेखकों द्वारा किया गया है। ये कारण लगभग हर किसी को ज्ञात हैं। ये हैं –कुंठा, गरीबी, असमानता, जीवन–स्तर, अपमान। ऐसे कारण के लिए संघर्ष, जो उनके अनुसार न्यायोचित है, ऐतिहासिक शत्रुता में उफान, राजनीतिक सत्ता की तलाश में स्वार्थी गुटों द्वारा ऐतिहासिक घृणा को भुनाना, उपनिवेश काल के बाद की संपत्ति के बारे में मतभेद, जिसका समाधान न हुआ हो, पूर्ण निराशा, जिसमें रोशनी की कोई किरण न दिखे इत्यादि।

आत्मघाती हमलों को अंजाम देने वाले युवाओं की विशाल संख्या को एक साङ्चे में रखना संभव होगा। फिर भी, एक छोटा सा हिस्सा स्वच्छ वर्गीकरण से बाहर होगा। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सामने आने वाले कुछ खास रूझानों को **इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है –**

1. जिस वातावरण से अधिकतम रंगरूटों की भर्ती की जाती है, वे सामान्यतः समान होते हैं चाहे वह पश्चिमी तट हो या गाजा पट्टी या पाकिस्तान। सामान्य परिस्थितियों को अत्यंत गरीबी, बेरोजगारी या काम के अवसर का अभाव, जीने की स्थितियाँ और आतंकवादी गुटों का अत्यंत प्रभाव, जो परिस्थितियों का लाभ उठाने में सफल होते है, से जोड़ा जा सकता है।
2. नागरिक तथा मनोरंजन सुविधाओं का अभाव।
3. जनसंख्या–विस्तार। अधिकांश रंगरूट विशाल आकार वाले परिवारों से संबद्ध होते है। वे शायद ही छोटे आधुनिक परिवारों से संबद्ध होते है जिनमें तीन या चार सदस्यों से अधिक नहीं होते हैं।
4. इस्लामी रूढ़िवादिता का प्रसार।
5. धार्मिक शख्सियतों की जकड़ में आना, जो अपने भाषण–कौशल द्वारा भावनाओं को भड़काने में सक्षम होते हैं।
6. धन की उपलब्धता।

एक चिंताजनक पहलू, जो सामने आ रहा है, "वह है अभिभावकों, खासकर माताओं का ब्रेनवॉश, जो अपने बच्चों के बलिदान को शहादत का गौरवपूर्ण कार्य मानती है। निश्चित रूप से अधिकांश मामलों में शहीद युवा के परिवार को प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराया जाता है। कई मामलों में, विशेषकर पाकिस्तान में, वित्तीय सहायता ने मृत युवा के परिवार का जीवन–स्तर ऊपर उठाने में मदद की है। कम–से–कम यह मदद उन्हें घोर गरीबी के जीवन से तो मुक्त करती ही है। सामान्यतः परिवार की घोर गरीबी ही युवाओं को एक शहीद की मौत मरने के लिए प्रोत्साहित करती है या फिर उसे ऐसा विश्वास करने के लिए प्रेरित किया जाता है।"[297]

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के एक संभावित हथियार के रूप में आत्मघाती हमलों का आविष्कार वर्तमान विश्व समुदाय के लिए खतरनाक पहलुओं में से एक है। आतंकवाद का यह रूप खुद को किसी स्थान या किसी समय पर अभिव्यक्त

[297] वही, पृ.सं. – 193–194

कर सकता है। उसका विनाशकारी प्रभाव न केवल अधिकांश जनसंख्या पर बल्कि समाज के मानसिक और सामाजिक–आर्थिक कल्याण पर भी पड़ता है। यह विश्व के कई भागों में विनाशकारी रूप ले चुकी है। 11 सितंबर, 2001 को हुए व्यापक विनाश को देखते हुए क्षति के स्तर तथा मौतों के संदर्भ में अमेरिका इसके मुख्य शिकारों में से एक रहा है।

''पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध पत्रकार ने लिखा है कि राज्य–प्रायोजित जिहादी लड़ाकों की धमकियों को देखते हुए देश की अदालतें आतंकित हो गई है क्योंकि इस प्रकार के मामलों पर निर्णय देने का साहस करने वाले जजों को मार दिया गया।''[298] पुलिस ने भी शक्तिशाली अपराधी का पक्ष लेना सीख लिया है। पुलिसकर्मी जानते है कि अंतिम निर्णय अनिवार्य रूप से उस अपराधी के ही पक्ष में होगा। ये सब राष्ट्र के पतन के लक्षण है।

आज आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, समृद्धि, सहयोग, स्थिरता, सहिष्णुता, सामर्थ्य एवं स्थापित मूल्यों के लिये एक बहुत बड़ी आपदा के रूप में उभरा है, जिससे संपूर्ण विश्व किसी न किसी रूप में आहत हो रहा है। अब आतंकवाद न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के लिये अपितु संपूर्ण संसार के लिये एक बड़ी आपदा बन चुका है। आत्मघाती हमला वास्तव में बुद्धि के दुरुपयोग का परिणाम तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी के अभिशाप का भयंकर उदाहरण है। यह एक ऐसा दानव है, जिसकी परिधि में विश्व का प्रत्येक देश आता है और जो किसी देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति या सुदृढ़ संरचना को भी ध्वस्त करने में सक्षम है। संपूर्ण राष्ट्र की सामूहिक बुद्धि जिस ठिकानों को सुरक्षित समझती है, वहाँ भी अप्रत्याशित रूप से यह हमला करते हैं तथा आतंकवाद के शिकार राज्य व राष्ट्र स्वयं को शक्तिहीन और निर्बल पाते हैं। आतंकवाद का दावानल इतना भयानक रूप धारण कर चुका है कि इसके थमने के आसार अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं।

आत्मघाती आक्रमण आतंकवाद का सबसे घातक व विनाशक स्वरूप है। यह एक ऐसा साधन है, जिसका प्रतिरोध अब तक दुनिया की किसी भी सुरक्षा एजेंसी, सरकार, सेना व शक्ति के पास नहीं है। **अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी** की हत्या के कुछ दिन पूर्व **सी.आई.ए. (अमेरिकी खुफिया एजेंसी)** के तत्कालीन निदेशक ने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को मरने का डर न हो तो उससे अधिक खतरनाक दुनिया का कोई भी आदमी नहीं होता। वैसे भी कहा जाता है कि अकेला शत्रु अधिक घातक होता है। मानव बम या आत्मघाती हमला करने वाले व्यक्ति की खतरनाक स्थिति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि मानव बम बने व्यक्ति को हरपल याद रहता है कि उसके द्वारा उठाये गये इस कदम से सबसे पहले उसी की मौत होगी। इसके बावजूद अगर उसमें अपने लक्ष्य को पूरा करने का जोश, जुनून, जिद्द और जज्बा रहता है तो उसकी लक्ष्य प्राप्ति की पराकाष्ठा को स्पष्ट रूप से अनुमानित किया जा सकता है।

---

[298] वही, पृ.सं. – 208

''आज की तिथि में **आत्मघाती दस्ता (फिदायीन)** मजहबी लड़ाई का ही एक घातक हथियार है, जो कट्टरपंथ की ही देन है। एटम बम से भी घातक बना मानव बम एक चलता–फिरता विस्फोटकों से लैस इंसान होता है, जो अपने निर्धारित लक्ष्य के परखच्चे उड़ाने के साथ ही स्वयं को भी असंख्य चीथड़ों में तब्दील हो जाता है। इस प्रकार के आत्मघाती दस्तों को तैयार करने में सबसे ज्यादा महारत श्रीलंका के कुख्यात आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) को प्राप्त थी, जिसने (वी.आई.पी.) को मानव बम का शिकार बनाया। मानव बम लिट्टे आतंकवादी संगठन का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बना, जिसका जवाब श्रीलंका की सेना व रणनीतिकारों को बहुत मुश्किल से मिल पाया।''[299]

मानव बम का मनोविज्ञान

आत्मघाती हमला करने वाला मानव बम कब और क्यों बनता है कोई? वे कौन–सी परिस्थितियाँ होती हैं, जब कोई व्यक्ति सदैव जीवित रहने की स्वाभाविक इच्छा के विपरीत **'मानव बम'** बनने को तैयार हो जाता है। सवाल यह उठता है कि क्या आम आदमी मानव बम बन सकता है? कहा जा सकता है कदापि नहीं। वस्तुतः जब किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर धर्म, जाति, क्षेत्र या नस्ल का जोरदार व जबरदस्त जुनून सवार हो जाता है तो वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है और अपनी आत्माहुति से भी संकोच नहीं करता। मानव बम की मानसिकता केवल एक मानसिक रोग के कारण ही नहीं बनती, बल्कि उसके समूचे व्यक्तित्व में बने असंतुलन के कारण ही पैदा होता है। जिस व्यक्ति में मानसिक असंतुलन होगा, उसे ही कोई आतंकवादी गिरोह अपने मकड़जाल में फंसा पाता है। यह भी एक प्रकार की व्यक्तित्व विक्षिप्तता है। इसके चलते ही वह अपने मुखिया के आदेशों का अक्षरशः पालन करने लगता है। मानव बम अथवा आत्मघात के पीछे एक मास्टर माइंड काम करता है।

मरने–मारने का संकल्प लिये एक चलता–फिरता इंसान, जब घातक विस्फोटों से लैस हो, मानव बम में तब्दील हो जाता है, तो यह आतंकवाद का चरम बन जाता है। 'दुनिया में दहशत और भयानक परिदृश्य का पर्याय बने मानव बम बनना कोई हँसी–खेल नहीं है। यह एक दीक्षा है, बहुत कठिन दीक्षा, जो इसमें सफल होते हैं, उसे ही यह दुर्लभ सम्मान मिलता है।' अब हम संक्षिप्त में उन कारणों का उल्लेख करते हैं, जिसके कारण मानव बम बन जाने हेतु प्रेरित होता है।

1. जज्बा व जोश के साथ अपने लक्ष्य हेतु जुनून जागृत करने के लिये प्रतिकूल परिदृश्य दिखाकर प्रेरित करना।
2. ड्रग का सेवन करवा करके जब वह मानसिक रोगी बन जाये तो अपनी कठपुतली बनाकर आत्मघाती बम बनाया जाता है।

---

[299] डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र, ''आतंकवाद व आपदा प्रबंध्न'', 2010, राधपब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, फोन 23247003, पृष्ठ संख्या–110–112

3. मानसिक परिवर्तन करके व नशीले पदार्थ देकर उनके शून्य मस्तिष्क में मन–मुताबिक इबारत लिखी जाती है।
4. दमन और बेबसी की पराकाष्ठा से छुटकारा पाना।
5. साहसहीनता की ग्रंथि से मुक्त होना।
6. आत्मगौरव की लालसा रखना।
7. फनर्जन्म पर कट्टर आस्था रखना।
8. अपने लक्ष्य को दुनिया का सबसे महान लक्ष्य मानना।
9. अपने गुरू, नेता तथा अगुआ के प्रति उन्मादी आस्था रखना। ऐसे लोग ही मानव बम बनने का निर्णय लेते हैं।

तमाम तरह के प्रेरित जज्बों के अलावा एक आत्मकेंद्रित मनोविज्ञान, किसी को मानव बम बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव बम बनने की इच्छा आमतौर पर अहं–केंद्रित लोगों के मन में पैदा होती है। आत्महत्याओं पर होने वाले शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्महत्याएँ ज्यादातर वे ही लोग करते हैं, जो अहं से चूर होते हैं और शारीरिक रूप से कमजोर। **यही कारण है कि युवतियाँ मानव बम बनने के लिए सबसे ज्यादा उतावली रहती हैं।** आत्महत्याओं के आँकड़ों को भी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाली जवान औरतें ही होती हैं। मानव बम बनने वाला इंसान समाज से पूरी तरह कट कर अपने सीमित लक्ष्य के जुनून में हर पल जीता है। वह न तो आदर्श पति बन सकता है, न पत्नी, न बेटा, न बाप, न माँ, न बहन। उसके जेहन में हरदम बस एक ही लक्ष्य घूमता रहता है कि वह किस तरह अपने शिकार को दबोचे और उसके साथ ही अपनी इहलीला भी समाप्त कर ले।

आत्मघात के मनोविज्ञान का एक बड़ा आधार धार्मिक और नस्ली रुझान वाला समाज भी होता है। जिन समाजों में धर्म और नस्ल को वरीयता दी जाती है, वहाँ आत्मघात की गुंजाईश ज्यादा आसानी से विकसित हो जाती है। यही कारण है कि जर्मनी में हिटलर रातों–रात सितारा बन गया था, क्योंकि जर्मन समाज नस्ली श्रेष्ठता बोध से ओत–प्रोत समाज है। यही वजह है कि मानव बम आमतौर पर धर्मभीरू इस्लामिक देशों, विशेषकर मध्यपूर्व के इलाके और श्रीलंका जैसे देश में पैदा हुए हैं। इंग्लैंड और अमेरिका जैसे उन्मुक्त समाजों में मानव बम उतनी सहजता से नहीं पैदा होते, जितनी आसानी से कट्टरवाद समाजों में। धार्मिक कट्टरता भी जुनून पैदा करती है।

आत्मघाती हमले के तरीके

मानव बम जिन विस्फोटक तत्त्वों का इस्तेमाल करता है, उसके प्रमुख चार तरीके इस प्रकार हैं – केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेकैनिकल। केमिकल विस्फोट दो से अधिक रसायनों के मिश्रण से प्रभावी होता है। इसका प्रयोग आमतौर पर आत्मघाती दस्ते द्वारा नहीं किया जाता। जब कभी इसका इस्तेमाल करने के लिये विस्फोट हेतु गोदामों को आमतौर पर चुना जाता है। इस विधि में विस्फोट हेतु मानव बम या आत्मघाती आतंकवादी उस जगह मौजूद नहीं

रहता। इस तरह के विस्फोट के लिये बम के खोल से जुड़ी दूसरी परत में एक निश्चित मात्रा में तेजाब भर दिया जाता है, जो एक निश्चित अवधि में उस परत को काट देता है और इससे भयानक विस्फोट होता है। इस तरह के बमों का इस्तेमाल मानव बम अक्सर शस्त्र गोदामों, बिल्डिंग उड़ाने आदि के लिये करते हैं। मानव बम सबसे ज्यादा जिस विस्फोट विधि का इस्तेमाल करते हैं वह है इलेक्ट्रिकल विस्फोट विधि। मानव बम के लिये आर.डी.एक्स. इसलिये भी एक अनुकूल विस्फोटक है, क्योंकि इसे किसी भी शक्ल में ढ़ाल कर शरीर से संबंधित किया जा सकता है। अमूमन कोई मानव बम से 6 से 8 किलोग्राम आर.डी.एक्स. को बेल्ट में भरकर उसे ब्लास्टिंग डिटोनेटिंग कैप और बैटरी से जोड़कर कमर से बाँध लेता है। राजीव गाँधी की हत्या करने वाली मानव बम महिला ने इसी विधि से विस्फोट किया था। ऐसी विधि में मानव बम की सुविधाजनक पहुँच में एक बटन मौजूद होता है, जिसको दबाते ही टारगेट चाहे जितनी सुरक्षा से घिरा हो, परखच्चे उड़ जाते हैं। शेष दो विधियों का इस्तेमाल पारंपरिक तरीके से होता है।

श्रीलंका के आतंकवादी संगठन लिट्टे को मानव बमों के मामले में दुनिया के सबसे खूँखार आतंकवादी संगठनों मे गिना जाता रहा, जो विस्फोट विशेषज्ञों और रक्षा मनोवैज्ञानिकों के लिये रहस्य का विषय रहा। स्वीडन स्थित पीस फाउंडेशन में विगत वर्षों में इसका अध्ययन, मनन, चिंतन एवं शोध करने का अथक प्रयास किया कि आखिर खूँखार आतंकवादी संगठन लिट्टे अपने लड़कों में कौन–सा ऐसा जज़्बा, जोश एवं जुनून पैदा कर देता है, जिसके कारण संगठन का व्यक्ति बिना किसी भय के हँसते हुए मौत को गले से लगा लेता है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर विगत दिनों में जब बौद्ध धर्म अपने विकास एवं विस्तार हेतु संघर्ष कर रहा था, उसी समय अपने धर्म की रक्षा के लिये बलिदान करना गौरव व गरिमापूर्ण समझा जाने लगा, जिसके फलस्वरूप ही चरम ध्वंस का यह घातक तरीका विकसित हुआ। बौद्ध अनुयायी सत्ता संघर्ष करने के लिये अपने अस्तित्व की परवाह नहीं करते थे।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जापानी सेनाओं ने अपनी रक्षा पंक्ति को बनाये रखने के लिए अनेक आत्मघातक कौशल दिखाये। जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका एवं जापान के बीच लड़ा गया आकोनावा युद्ध बहुत मशहूर हुआ। जापान के तटीय क्षेत्र तरावा में हुई यह भीषण लड़ाई मानव बमों (आत्मघाती दस्तों) के वर्तमान विध्वंसक चेहरे की शुरुआत थी। एक सप्ताह की इस लड़ाई में लगभग 1000 जापानी सैनिकों ने आत्मबलिदान कर दिया और जापानी बेड़े के सामने आखिर अमेरिकी बेड़े को पीछे हटना पड़ा।

जिस समय जापानी सेना अपने अनेक अथक प्रयासों के बावजूद असफलता की ओर बढ़ रही थी, उसी समय एक व्यापक रणनीति के तहत 150 मोटर नौकाए अमेरिकी युद्धपोतों पर चारों ओर से लपकीं और जब तक अमेरिकी सैनिक इस स्थिति का अनुमान लगा पाते तब तक एक भयंकर विस्फोट के साथ ओकीनावा का समुद्र अमेरिकी सैनिकों के रक्तपात से लाल हो गया। अमेरिका के

पाँच युद्धपोत जो कि समुद्री क्षेत्र में अजेय पहाड़ की तरह खड़े थे, देखते ही देखते घास–पूफस की तरह बिखर गये। जापान की सेनायें एक हारते हुए युद्ध मोर्चे से जीत की ओर मुड़ गई। इसके पीछे वास्तव में जापानी मोटर नौकायें भारी विस्फोटक पदार्थों से लदी थीं, जो अमेरिकी युद्धपोतों से 11 सितम्बर, 2001 की भाँति टकराकर स्वयं नष्ट होने के साथ ही अमेरिकी युद्धपोत के भी परखच्चे उड़ा दिये।

जापानी जाँबाज सैनिकों को यह स्पष्ट रूप से आभास था कि इस आत्मघाती रणनीति के द्वारा ही अमेरिकी युद्धपोतों को आगे बढ़ने से रोका जा सकेगा। इसी कारण वे जुनून, जोश, जज्बे व ज़मीर के बल पर अपनी मोटर नौकाओं को विशालकाय युद्धपोतों से टकराकर स्वयं के साथ ही अमेरिकी सैनिकों के भी चीथड़े–चीथड़े कर दिये। इनको **वर्तमान आत्मघाती दस्ता या मानव बम का जनक कहा जा सकता है।** अमेरिकी इतिहासकारों ने इस युद्ध को मानव बमों के **अंध उन्माद** के रूप में वर्णित किया है। जापानी सेना इन मानव बमों को **'कामी–काजी'** नाम दिया था। ओकीनावा युद्ध के बाद तो जैसे आत्मघाती उन्माद का सैलाब आ गया। अमेरिका के 27 युद्धपोतों को जापान के इन **'कामी–काजी'** दस्तों ने देखते ही देखते ही ध्वस्त कर दिया। यही नहीं इन **'कामी–काजी'** ने पर्ल हार्बर में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों की चिमनियों में कूदकर आत्मघाती दुस्साहस का एक नया अध्याय शुरू कर दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जापानी सेना के पास लगभग 950 मानव बम थे, वे सभी युद्ध में मारे गये थे। वास्तव में यह मानव बमों का अंत नहीं, बल्कि एक मजबूत आधार स्थापित हुआ था। इसका प्रमाण उस समय मिला जब 9 मई 1972 में इजरायल के लोड हवाई अड्ड़े में एक आत्मघाती व्यक्ति या मानव बम ने विस्फोट कर 26 लोगों के परखच्चे उड़ा दिये थे। इस घटना को **'जापानी रेड आर्मी'** ने अंजाम दिया था। इसी के साथ मानव–बमों के प्रयोग का दुस्साहस शुरू हो गया था।

आधुनिक सदी में मानव बम की टोली बनाने का काम सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1979 में ईरान के अयातुल्ला खुमैनी ने शुरू किया, जिसमें उन्हें भरपूर सहयोग मिला, लीबिया के कर्नल मुअम्मार गद्दाफी और फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन (PLO) के नेता यासिर अराफात से और इसका संचालन केंद्र बना लेबनान। एक साल के अंदर इस्लामी जिहाद के बैनर तले मिड्ड से लेकर फिलीपींस तक पूरे मुस्लिम जगत में आत्मघाती दस्ते का जाल बिछ गया। 1982 में लेबनान में फिलीस्तीनी शरणार्थी शिविरों पर की गई इजरायली बमबारी के बाद उग्रवादियों ने खूँखार रुख अपनाया और फिलीस्तीनियों की जो भी जमीन इजरायल ने छोड़ी है, उसका श्रेय आत्मघाती दस्ते को जाता है। अभी इस्लामी जगत में सक्रिय **'हिजबुल्ला'** व **'इस्लामी इत्तेहाद'** यासिर अराफात के नेतृत्व में काम करने वाले **'हमास'** के साथ मिलकर काम करते हैं। वैसे तो कहने को **'हिजबुल्ला'** का सबसे बड़ा समर्थक है ईरान, लेकिन दरअसल इसके लिये पंफड पूरे मुस्लिम जगत से आता है। ये सारे आत्मघाती दस्ते ओसामा–बिन–लादेन (जो

2 मई 2011 को मारा गया) के नेतृत्व वाले **'अलकायदा'** के साथ मिलकर योजनाएँ बनाते हैं, जिसने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में अपने को ज्यादा केंन्द्रित कर रखा है। इसमें पाकिस्तान का **'हिजबुल मुजाहिदीन**' भी शामिल है। सूडान, मिङ्ग, अल्जीरिया, तुर्की के मानव बम दस्ते इसी के दिशा–निर्देश पर चलते हैं। तुर्की की '**खुर्दिस्तान वर्क्स पार्टी**' के नेता अब्दुल्ला ओमालम ने इसी हथियार की बदौलत अपने हक हासिल किये। अमेरिका की शान दाव पर लगी हुई है, पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा है, अफगानिस्तान मरने–मारने पर उतारू है और भारत के पास भी इस लड़ाई में शामिल होने के सिवाय कोई चारा नहीं है।

अमेरिकी धमकियों की अफगानिस्तान को इसलिये परवाह नहीं है, क्योंकि वे हमेशा युद्धरत रहने वाला मुल्क है। कबीलाई मानसिकता वाले इन अफगानिस्तानियों को किसी बाहरी हमले की जरूरत भी नहीं रहती, वे आपस में ही लड़ते रहते हैं, भले ही देश कंगाल हो जाये। अगर उन्हें ओसामा–बिन–लादेन को अमेरिका के हवाले करना होता तो 1998 में केन्या व तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों को उड़ाने के बाद ही कर देते, जिसके बाद अमेरिका ने ओसामा–बिन–लादेन को पकड़वाने के लिये पाँच करोड़ डॉलर ईनाम की घोषणा की थी। इसके पहले कि अमेरिका अफगानिस्तान की मोर्चाबंदी करे, लादेन काबुल छोड़कर किसी गुप्त ठिकाने पर चला गया, सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए 15,000 फिदायीन जवान हमेशा तैनात रहते थे। इसके पहले भी अमेरिका ने सूडान और रियाद में लादेन के संदिग्ध ठिकाने पर बमबारी की थी पर हाथ कुछ न लगा। यह लड़ाई अगर मजहबी रंग पकड़ लेती है तो मानव बम की टोली बढ़ती जाएगी और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गृहयुद्ध भी छिड़ सकता है। उससे भारत की कौन कहे, अमेरिका भी अछूता नहीं बचेगा, जहाँ मुस्लिमों की आबादी एक करोड़ है।

आतंकवाद की यह आपदा उस समय अपने चरम पर पहुँच जाती है, जब मरने–मारने का संकल्प लिये एक चलता–फिरता आदमी घातक, विस्फोटक एवं विध्वंसक साधन से लैस हो **मानव बम या आत्मघाती या फिदायीन में तब्दील हो जाता है।** दुनिया में दहशत और भय का पर्याय बने मानव–बम के कारण आतंकवाद अत्यंत घातक बन चुका है। आतंकवाद के इस खूँखार स्वरूप के कारण दुनिया दहशत में आ गई है। शक्तिशाली व्यक्ति, राज्य, राष्ट्र व समाज अब अपने को सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त के बावजूद सुरक्षित अनुभव नहीं कर पाता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका भी आखिरकार आतंकवाद के इसी आत्मघाती दस्ते का शिकार हुआ।

अमेरिकी मिसाइलों का जवाब दुनिया भर में फैले कट्टरपंथी मुस्लिम आतंकवादी मानव बम से देंगे, जिसे आत्मघाती दस्ता कहा जाता है। अमेरिका ने यों तो यह जंग, आतंकवाद का सफाया करने के लिये छेड़ी है, मगर मुस्लिम देशों में इसे मुसलमानों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान के रूप में लिया गया है क्योंकि आतंकवाद उनका सुरक्षा कवच है और इस कवच का इस्तेमाल ठीक ऐसे

समय में करने की नौबत आ गई, जब अमेरिका अपने लिये मिसाइल रक्षा कवच योजना को अंतिम रूप देने में जुटा था। इसके पहले कि इस योजना के लिये अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिले, आतंकवादियों के खिलाफ विश्व भर को गोलबंद करने की जरूरत पड़ गई। अमेरिका को विभिन्न देशों में अपने दूतावासों को बचाने की भी फिक्र है। यह लड़ाई अमेरिका अपनी साख बचाने के लिये लड़ेगा और मुस्लिम जगत पूरी तरह से मजहबी जंग (जिहाद) में शामिल होंगे। आत्मघाती दस्ता (फिदायीन) मजहबी लड़ाई का ही हथियार है, जिसकी काट कोई हथियार नहीं हो सकता। मानव बम का मुकाबला परमाणु बम भी नहीं कर सकता, जिसके इस्तेमाल का सुझाव पूर्व विदेश मंत्री हेनरी कीसिंगर ने जॉर्ज बुश को दिया है। 1995 में सउदी अरब में अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर यही सोचकर हमला किया था कि मक्का–मदीना जैसी पवित्र जमीन पर अमेरिकियों का होना इस्लाम का अपमान है।

उग्रवादियों के पास न तो पैसे की कमी है, न ही हथियार की। उनके हाथ में भी वैसे हथियार हैं, जो अमेरिकी फौज इस्तेमाल करती है और अमेरिका से ही खरीदे हुए हैं, लेकिन मानव बमों का जखीरा बनाने का श्रेय जाता है, '**ओसामा–बिन–लादेन**' को जिसको पकड़ने के लिये अमेरिका ने ऐड़ी–चोटी एक करने के बाद अब अफगानिस्तान की घेराबंदी शुरू की है। अमेरिका ने 15 अरब देशों के सामने दो विकल्प रखे हैं कि या तो उग्रवाद के खिलाफ सहयोग करे अथवा उसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहे। 11 सितंबर की घटना से कुछ ही दिन पहले सउदी अरब की मदद से दुबई में एक गुप्त बैंक की स्थापना की गई, जिसका संचालन ओसामा के जिम्मे था। इस बैंक का काम फिदायीन दस्ते में शामिल युवकों के परिवारजनों की परवरिश व पढ़ाई–लिखाई की व्यवस्था करनी है। लेबनान के '**अखबार अल अहराम**' के मुताबिक इस बैंक में सारे मुस्लिम देशों ने पैसा लगाया है और इसमें खरबों डॉलर हमेशा जमा रहते हैं। फिदायीन के हथियार व हथियारों के साथ छापामार युद्ध के प्रशिक्षण का एकाउंट अलग हैं। ओसामा–बिन–लादेन का तो ब्रांड नाम चलता है, इसके लिये सारे अरब देश मिलकर फंड जुटाते हैं।

आत्मघाती आतंकवाद के पैर पसारने और अपनी क्रूर ताकत से पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी आपदा खड़ी हो गई। इस बात को कदापि नकारा नहीं जा सकता कि अब आतंकवादी अपने अभियानों में नित नई पद्धतियाँ अपना कर पहले से अधिक आक्रामक होते जा रहे हैं, क्योंकि विध्वंस व विनाश हेतु नवीनतम तकनीकी की अनेक विधियाँ अपना रहे हैं। **मानव बम का इतिहास तो वैसे सदियों फराना है, मगर आधुनिक जगत में संसार का सबसे सशक्त आत्मघाती दस्ता तैयार किया श्रीलंका में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे तमिल उग्रवादियों के संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) ने जिसकी नींव एक साथ अमेरिका व ब्रिटेन में रखी गई। आज आतंकवाद के खिलाफ मैदाने–जंग में उतरने वाले अमेरिका ने ही सबसे पहले लिट्टे को अपने यहाँ**

मुख्यालय बनाने के लिए पनाह दी। आत्मघाती आतंकवाद की घटनायें अमेरिका के दो प्रमुख शहरों – व्यापारिक राजधानी न्यूयार्क तथा राजनीतिक राजधानी वाशिंगटन के दो महत्त्वपूर्ण ठिकानों पर 11 सितंबर 2001 को एक साथ घटित हुई। इन हमलों में एक नया आत्मघाती तरीका अपनाया गया। आतंकवादियों ने बोस्टन हवाई अड्ड़े से यात्री विमानों का अपहरण कर उन्हें पूर्व निर्धारित निशानों से टकराया। अपहृत चार विमानों में से दो विमानों को विश्व व्यापार केन्द्र के ट्विन टावर्स से अलग–अलग 15 मिनट के अंतराल में टकराया गया। तीसरे विमान को पेंटागन (वाशिंगटन डी.सी., भवन जो कि अमेरिका का रक्षा मुख्यालय है), से टकराया गया। चौथा विमान लक्ष्य पर टकराने से पूर्व ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टी.वी. चैनल के अनुसार चौथा लक्ष्य व्हाइट हाउस (राष्ट्रपति भवन) को उड़ाने का था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का पहला टावर 1364 फीट तथा दूसरा टावर 1362 फीट ऊँचाई के आधार पर बना था। इन दोनों भवनों में लगभग 1500 लोग कार्यरत थे। आत्मघाती विमानों के हमले से दोनों गगनचुंबी इमारतें देखते–ही–देखते ध्वस्त हो गई तथा पेंटागन के विशाल क्षेत्र में बने पाँच मंजिला भवन के एक हिस्से को भारी नुकसान हुआ।

आत्मघाती हमलों को अंजाम देने के कारण आतंकवाद की आपदा, विध्वंसक व विनाशक स्वरूप ले चुकी है। फिलीस्तीन में चल रहे संघर्ष में हमास, इस्लामिक जिहाद और अल–अक्स ब्रिगेड प्रेरित कर भोले–भाले युवक–युवतियों की पर्याप्त आपूर्ति करते हैं, जो आत्मघाती आतंकवादी आक्रमणों को अंजाम देने को अपना धार्मिक दायित्व मानते हैं। इस प्रकार की स्थिति पाकिस्तान में भी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिहादी स्वयं को रूस में उड़ा दे या भारत व अमेरिका आदि अन्य देशों में। आतंकवादियों के मामले में पाकिस्तान की आपूर्ति सीमाहीन है। असंख्य युवाओं को हजारों मदरसों में जिहाद के लिये तैयार और फिर जिहादी संगठनों में शामिल किया जाता है। गरीबी, भुखमरी, अज्ञानता एवं अशिक्षा से ग्रसित जनता पाकिस्तान के लोगों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है। गरीबी एवं जनसंख्या विस्तार का मिश्रण एक ऐसा ज्वलनशील मिश्रण है, जो इस्लामिक जिहाद को अनिश्चित काल तक जारी रख सकता है। इस अभावग्रस्त गरीब वर्ग को रूढ़िवादी तत्त्वों के अधीन रखने के लिये परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती है। बल प्रयोग व बंदूक के जोर से आधुनिकता के विरोध पर जोर दिया जाता है। आत्मघाती मिशनों के संयोजक युद्ध के एक एकीकृत हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह उन्हें अत्यंत शक्तिशाली विरोधियों के षविरुद्ध एक असीमित विकल्प प्रदान करता है।

20वीं शताब्दी के अंत से लेकर 21वीं शताब्दी के प्रथम चरण तक आतंकवाद विशेष रूप से आत्मघाती आतंकवाद का विशेष बोलबाला रहा। एक शतक के अधिक ऐसी भीषण व भयानक आतंकवादी घटनायें घटित हुईं, जो कि आत्मघाती दलों या व्यक्तियों द्वारा अंजाम तक पहुँचाई गईं। **इनमें प्रमुख घटनायें निम्न प्रकार से हैं –**

1. 23 अक्टूबर, 1983, स्थान बेरुत स्थित अमेरिका का क्षेत्रीय सैन्य मुख्यालय और उसी से सटा हुआ फ्रांसीसी सैन्य मुख्यालय, समय – दिन के ठीक बारह बजे, घटना–तेज रफ्तार से आते हुए दो सैनिक ट्रक एक ही क्षण और एक ही अंदाज में, अमेरिका तथा फ्रांस के सैन्य मुख्यालय में प्रविष्ट हुए। जब तक सुरक्षाकर्मी उन ट्रकों के बारे में कुछ सोच पाते या रोक पाते, तब तक दिल दहला देने वाला भयंकर विस्फोट हो चुका था। यह सारी घटना महज 40 सैकिंड में घट गई थी। इस घटना में 100 से भी ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, मीडिया के लोग, राजनयिक तथा नौकरशाह मारे गये थे और 400 से भी ज्यादा आम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इन दोनों ट्रकों को मानव बम ही चलाकर लाये थे।
2. 1984 में फिलीस्तीन मुक्ति संघर्ष (PLO) की एक मानव बम **शाहिना अबनूर (पहली महिला मानव बम)** गाजा पट्टी स्थित इजरायली फौजी कैंप में जा घुसी थी। फलस्वरूप एक भयानक विस्फोट के साथ फौजी कैंप उड़ गया। इस महिला मानव बम को भी कई तरह की बाधाओं के जरिये कैंप के सुरक्षाकर्मियों ने रोकने की कोशिश की थी, मगर हर तरह की बाधाओं को तोड़ते हुए यह महिला मानव बम कैंप में घुस गई थी। इस हादसे में 14 सैन्य अधिकारी तथा 20 सैनिक मारे गये थे।
3. 1985 में इजरायल के लोड हवाई अड्ड़े पर जे.आर.ए. तथा पी.एल.ओ. के मानव बमों ने एक साथ धावा बोलकर कहर बरपा दिया। इस हादसे में दो दर्जन से ज्यादा लोग मारे गये तथा 5 विमान जलकर राख हो गये।
4. 1987 में आयरिश रिपब्लिक आर्मी (IRA) के दो मानव बमों ने इंग्लैंड की एक पुलिस ईमारत को ध्वस्त कर दिया, जिसमें 17 लोग मारे गये तथा 400 से ज्यादा घायल हुए।
5. 21 मई 1991 को श्रीपेरम्बदूर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की लिट्टे की एक महिला मानव बम ने विस्फोट से हत्या कर दी।
6. **श्रीलंका में तो राष्ट्राध्यक्षों, मंत्रियों और दूसरे राजनेताओं की मानव बमों के जरिये हत्याओं का एक अंतहीन सिलसिला लंबी अवधि तक जारी रहा। राष्ट्रपति रणसिंह प्रेमदास, गामिनी दिशानायके, ललित अतुलात मुदली तथा सीवी गुणवर्धने सहित 10 मंत्री और प्रधानमंत्री मानव बम का निशाना बन चुके। इसके अलावा महत्त्वपूर्ण लोगों पर 50 से ज्यादा नाकाम हमले भी हो चुके हैं। चंद्रिका कुमार तुंग पर तीन बार, श्रीमाओ भंडारनायके पर दो बार नाकाम हमले हो चुके हैं। नेताओं और मंत्रियों के अलावा दो दर्जन से ज्यादा सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तथा सैकड़ों लोग इन मानव हमलों से अपनी जान गवाँ चुके हैं। लिट्टे के अंत के साथ ही आत्मघाती दस्ते के सबसे घातक एवं बड़े संगठन का फिलहाल अंत हो गया, किंतु आत्मघाती आतंकवाद के रूप में लिट्टे को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। 1980–1990** के दौरान आत्मघाती आतंकवाद की घटनायें मुख्य रूप से लेबनान, कुवैत

और श्रीलंका तक ही सीमित थी, किंतु अब यह वैश्वी घटनाक्रम बन चुका है। इसके तहत इजरायल, भारत, फिलीस्तीन, लेबनान, फ्रांस, सीरिया, अफगानिस्तान, पनामा, अल्जीरिया, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, क्रोसिया, तुर्की, तनजानिया, केन्या, अमेरिका (यू.एस.ए.), मध्य एशियाई गणराज्य तथा इंग्लैंड (यू.के.)। इसके साथ कुछ आतंकवादी संगठन अपनी सीमाओं से बाहर भी अपनी यह रणनीति अपना रहे हैं। **हिजबुल्ला पहला आतंकवादी संगठन है, जिसने इस आत्मघाती आतंकवाद को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया है।**

7. **2001** – न्यूयॉर्क की 11 सितम्बर की आत्मघाती आतंकवाद की घटना ने पेंटागन में हमला करके 5000 से अधिक लोगों को मौत का शिकार बना दिया।
8. **2005** – लंदन में 7 जुलाई को आत्मघाती दस्ते द्वारा भीषण बम विस्फोट करके 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 700 से अधिक लोग बुरी तरह से घायल हुए।

अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं इराक में तो आत्मघाती हमला करने की घटना अब सामान्य सी हो गई है, शायद ही कोई भी दिन, महीना गुजरता हो, जब आत्मघाती हमला इन देशों में घटित न होता हो। जहाँ तक इस समय दुनिया में आत्मघाती आतंकवाद का अहम प्रश्न है तो आज दुनिया का कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। एक अनुमान के अनुसार इस समय संसार भर में 100 से अधिक ऐसे आतंकवादी संगठन हैं, जिनके पास मानव बम मौजूद हैं। इसमें लिट्टे के अग्रणीय भूमिका रही, लिट्टे के पास ब्लैक टाइगर के नाम से सबसे घातक एवं प्रभावशाली आत्मघाती दल था, जिसके पास लगभग इसकी एक पूरी ब्रिगेड थी, जिसमें 250 मानव बम हरदम कार्यवाही के लिये तत्पर रहते थे।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के एक संभावित हथियार के रूप में आत्मघाती हमलों का आविष्कार वर्तमान विश्व समुदाय के लिये घातक आपदाओं के रूप में उभर कर सामने आया है। आतंकवाद का यह रूप खुद को किसी स्थान या किसी समय पर अभिव्यक्त कर सकता है। इसका विध्वंसक एवं विनाशकारी प्रभाव न केवल अधिकांश जनसंख्या पर बल्कि समाज के मानसिक और सामाजिक–आर्थिक कल्याण पर भी प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। यह विश्व के अनेक भागों में अपना भयंकर, विध्वंसक व प्रलयकारी स्वरूप धारण कर चुका है। 11 सितंबर 2001 की आत्मघाती हमले के द्वारा हुए व्यापक तबाही, बर्बादी एवं मौत के तांडव को देखते हुए अमेरिका इस प्रकार के आतंकवाद का सबसे प्रमुख शिकार रहा। आत्मघाती हमले का यह स्वरूप अपने आप में न केवल अनूठा था, बल्कि आश्चर्यजनक एवं अनुमान से परे आक्रमण था।

राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती

आतंकवाद विशेष रूप से आत्मघाती दस्ता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक गंभीर चुनौती के रूप में स्थापित हुआ। आतंकवाद के इस घातक स्वरूप ने भस्मासुर का रूप धारण करके राष्ट्रीय सुरक्षा के संकट को न केवल बढ़ा दिया है,

बल्कि एक गंभीर एवं कठिन समस्या सामने खड़ी कर दी है। मानव बम आतंकवाद का वह क्रूर व हिंसक व्यवहार है, जो मानवीय प्रतिमानों का पालन नहीं करता। संचार के ऐसे साधन आ गये हैं, जिससे आतंकवादी संगठन एक–दूसरे के साथ आसानी से संपर्क कायम कर लेते हैं। धन जुटाने से लेकर रणनीति बनाने तक आपस में बेहतर संवाद बना कर विध्वंस को आसानी से अंजाम दे देते हैं।

देश में आतंकवादी घटनाएँ संख्या और गंभीरता दोनों में बढ़ती जा रही हैं और अब इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी ज्यादा भारत आतंकवाद से पीड़ित है। कहा तो यह भी जाता है कि हमारे पास आतंकवाद से लड़ने का लंबा अनुभव है, लेकिन हर आतंकवादी हमला हमारी कमजोरियाँ उजागर कर जाता है। यूं तो भारत 1954–55 से ही नागा, मिजो जैसे अनेक विद्रोहों से मुकाबला करता रहा है, इसी आधार पर कहा जाता है कि 50 के दशक से भारत को आतंकवाद से निपटने का अनुभव है, लेकिन दिनों–दिन आतंकवाद की उग्रता बढ़ती जा रही है और हमारी उसके खिलाफ तैयारी धरी की धरी रह जाती है। आतंकवाद के यूं तो कई रंग हैं, मसलन पूर्वोत्तर राज्यों में एक तरह की जातीय बगावत है, तो दूसरा नक्सलवादियों के कुछ क्षेत्रों में गढ़ हैं। लेकिन सबसे खतरनाक जिहादी आतंकवाद है। यह पहले जम्मू–कश्मीर तक सीमित था, अब समूचे देश में फैल गया है और इसके कुछ स्थानीय संस्करण भी तैयार हो गये हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिमी जैसे संगठन हैं। **सिमी के अगुवा नांगौरी** ने यह कहा भी है कि, ''कुरान ही उनका संविधान है और शरीयत ही कानून। यानि देश के संविधान और कानून से अधिक महत्त्व उनके लिये अलकायदा के फलसपेफ का है।'' ऐसी मानसिकता से ग्रस्त हमारे यहाँ के लड़के, हालाँकि पैदल सिपाही की भूमिका में ही होते हैं। नेतृत्व, निर्देशन, आर्थिक संयोजन, योजना और रणनीति तैयार करने का काम तो बाहरी तत्त्वों के ही हाथ होता है। चाहे वह आई.एस.आई. हो या लश्कर जैसे संगठन। असल में इन आतंकवादियों को भारत में हमले करना कई तरह से आसान मालूम पड़ता है, क्योंकि उन्हें अहसास है कि भारत में आतंकवाद से लड़ने का दृढ़ संकल्प नहीं है। अभी तक यहाँ आतंकवाद के खिलाफ कोई कानून नहीं है। इसलिये वे सोचते हैं कि यहाँ घटनाओं को अंजाम देने में खतरा सबसे कम है। शायद पुलिस से पकड़े जाने का भी डर कम है और पकड़े भी गऐ तो अदालत से छूट जाने की संभावना रहती है। यही नहीं, अगर फांसी भी हो जाए तो उस पर अमल होना मुश्किल हो जाता है। तमाम तरह के मानवाधिकारवादी संगठन सवाल खड़े करने लगते हैं। इस तरह आतंकवादियों का घटनाओं को अंजाम देने में दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। मुम्बई की घटना इसकी गवाह है।

आतंकवाद ने हमारे समाज को और उसके प्रत्येक पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक को समग्र रूप से प्रभावित किया है। इसके कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष अनेक चुनौतियाँ मुँह बाए खड़ी हो गई हैं, जैसे – हिंसा, अनैतिकता, अविश्वास, अंधविश्वास, आपाधापी, अंधेरगर्दी, अपराध, अन्याय, आसुरी अनीति, असंतोष, अव्यवस्था एवं अस्थिरता आदि।

जनसामान्य का उत्साह क्षीण हो गया है, जबकि असामाजिक तत्त्वों को बल मिला है। आतंकवादी गतिविधियों ने राष्ट्र के आर्थिक पहलू को बुरी तरह से और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। लूटपाट, हिंसा, आगजनी, विस्फोट एवं विध्वंस से जहाँ आर्थिक हानि होती है, वहाँ व्यापार करते हुए लोग डरते हैं। इसके साथ ही पूइजी निवेश दिनों–दिन संकुचित होकर निरस्त होता जाता है।

आतंकवाद के कारण हमारे देश का राजनीतिक जीवन भी विषाक्त बन गया है। राजनेता अपने स्वार्थसिद्धि के लिये, प्रतिपक्ष को नीचा दिखाने के लिये राजनीतिक नेता, गुंडों, अपराधियों और असामाजिक तत्त्वों का सहारा लेते हुए देखे जा सकते हैं। विपक्षी नेताओं की हत्या कराना, उनकी सभाओं में हो–हल्ला कराना, पथराव कराना, आपसी विवाद कराना और बम विस्फोट जैसी भयंकर कार्यवाहियाँ हमारे राजनीतिक जीवन का एक सहज अंग बनती जा रही है। आतंकवाद ने हमारे समाज के नैतिक पक्ष को तो बहुत ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया है। नैतिक मूल्यों के प्रति अनास्था के फलस्वरूप समाज अनेक असामाजिक कार्यों को सहज भाव से स्वीकार करने लग गया है। हम सही एवं खरी बात कहते हुए डरने लगे हैं, क्योंकि आतंकवाद का फंदा हर एक के सामने सदैव झूलता रहता है। आतंकवाद के कारण हमारा नैतिक पतन बहुत तेजी के साथ हो रहा है। यह सबसे बड़ी खतरे की घंटी एवं राष्ट्र की चुनौती बन गया है।

अब आतंकवाद का एक घातक रूप अपहरण, फिरौती एवं हत्या के रूप में उभरा है, जिसकी पकड़ एवं पहुँच की जड़ें समाज में बहुत गहराई तक जा चुकी हैं। अब यह एक आतंकवादियों की आय का बड़ा स्रेतएवं धंधा बन गया है। इसे बेरोजगार युवकों ने सस्ता हथकंडा मानकर अपनाना शुरू कर दिया है, बिना परिश्रम एवं परित्याग के पैसा कमाने का एक सरल एवं सस्ता साधन भी बन गया है। इसके साथ धमकी देकर आतंकवादी गतिविधियों को नये–नये रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आतंकवाद की विषबेल सूखने की बजाय निरंतर फैलती जा रही है। आतंकवाद से कितनी आर्थिक एवं जनहानि होती है? वैश्वीकृत इस घटना का अब अनुमान लगाना भी कठिन होता जा रहा है। इसके साथ ही इसके कारण जो अशांति, अफरा–तफरी, भय, तनाव एवं चिंता का वातावरण पनपता है उसकी पूर्ति के लिये राष्ट्र को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. के माध्यम से कश्मीर घाटी में धार्मिक भावनाओं को उभारने, लूटमार, तोड़–फोड़ आदि गतिविधियों का संचालन करके सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दी जा रही है। यही कारण है कि आतंकवाद के शिकंजे में महिला आजादी कसती जा रही है। कबाइली इलाकों में तालिबान द्वारा महिलाओं पर पूरी तरह से शरीयत लागू है। इसी के तहत ही कश्मीर में भी गतिविधि जारी है। कश्मीर घाटी में आतंकवादी संगठनों की धमकी का असर यह हुआ कि सौपोर डिग्री कॉलेज की शिक्षिकाएँ और छात्राएँ शरीयत के मुताबिक पूरी तरह से बुर्का पहनने लगी हैं। कुछ दिनों पहले ही आतंकवादियों ने कॉलेज के प्रिंसीपल प्रो. मोहम्मद अशरफ का अपहरण

कर उनकी जमकर पिटाई की और उन्हें इस आश्वासन पर छोड़ा कि वह कॉलेज में महिलाओं पर पूर्ण रूप से शरीयत लागू करेंगे। जाहिर तौर पर इस घटना ने उक्त कॉलेज की महिलाओं और लड़कियों को बुर्का पहनने के लिए बाध्य किया।

घाटी में पहले भी आतंकवादी संगठनों ने महिलाओं और खासकर स्कूल–कॉलेज की छात्राओं पर इस तरह के नियम लादे हैं और विरोध करने वाली कई छात्राओं को गोलियों से भूना जा चुका है। चेहरे पर तेजाब फेंकने आदि की घटनाएँ भी यहाँ हुई हैं। आतंकवादी संगठन कश्मीर घाटी में को–एजुकेशन का विरोध करते रहते हैं और ऐसे शिक्षण–संस्थानों को ध्वस्त करने का फरमान जारी कर चुके हैं। जम्मू–कश्मीर सरकार आतंकवादियों की इन हरकतों पर आँखें मूँद चुकी है। उसके लिये महिलाओं की आजादी की कोई कीमत नहीं है। महिला संगठनों ने भी अब तक आतंकवादियों के इस अभियान पर कोई नोटिस नहीं लिया है, जबकि इसके खिलाफ व्यापक संज्ञान की जरूरत थी।

सच पूछा जाये तो कश्मीर घाटी में आतंकवाद की सबसे बड़ी कीमत महिलाओं ने ही चुकाई है। वहाँ महिलाओं की आजादी, विकास, उत्थान और शिक्षा सहित सब कुछ प्रभावित हुआ है। उनके विकास के रास्ते में आतंकवाद एक बड़ा रोड़ा बना है। वैसे यह सिर्फ कश्मीर घाटी की ही बात नहीं है। जहाँ भी इस्लाम के नाम पर आतंकवाद का तांडव जारी है, वहाँ अधिकतर शिकार महिलाएँ ही होती हैं। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के दौरान महिलाओं का जीवन बिल्कुल नर्क बन गया था। कट्टरवादी व रूढ़िवादी आबादी इन अभियानों को समर्थन देती है और कश्मीर में ऐसी आबादी की कमी नहीं है। आतंकवादियों द्वारा जिन विधियों से राष्ट्र, सुरक्षा, विकास को जन सामान्य की शांति जो प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभावित किया जाता है, **उनमें से प्रमुख रूप से निम्नलिखित है –**

1. संचार व्यवस्था को भंग करना और परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह से अवरुद्ध करने का प्रयास करना।
2. प्रमुख व्यक्तियों का अपहरण करके फिरौती वसूलना तथा अपनी निर्धारित माँगे रख कर सरकार पर अनुचित दबाव डालने का प्रयास करना, इसके साथ ही हत्या की धमकी और हत्या करना।
3. ऐसी हिंसात्मक, बर्बर कार्यवाहियाँ और विस्फोट करना, जिनसे अनेक व्यक्ति मारे जायें तथा बड़ी संख्या में लहु–लूहान हो जायें व आवश्यक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
4. आत्मघाती हमले द्वारा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति या सामरिक महत्त्व के स्थान को अपना निशाना बना कर विस्फोट से उड़ा देना।
5. बारूदी सुरंगों, विस्फोटकों, बमों एवं अन्य अनेक ज्वलनशील पदार्थों व घातक हथियारों का प्रयोग करके हत्या, खून–खराबा, विध्वंस व विनाश का वीभत्स दृश्य उपस्थित करना।

6. जाली नोटों (फेंक करेंसी) के द्वारा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से फैल करने का प्रयास करना।
7. धार्मिक, कट्टरवादी, रूढ़िवादी एवं अंधविश्वासी लोगों को भ्रमित करके 'जिहाद' का नारा लगाकर राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों में संलिप्त करना और उन्हें आवश्यक साधन एवं सामग्री की आपूर्ति करना।
8. बेरोजगार, युवा एवं उत्साही लोगों को रोजगार दिलाने के नाम पर तस्करी, मादक पदार्थों की आपूर्ति एवं अवैध हथियारों के लेन–देन में लगा कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ सक्रिय करना।

भारत में आतंकवाद का जो रूप दिखाई पड़ता है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय तीनों का सम्मिश्रण है। इसमें प्रेरणा और संजाल अंतर्राष्ट्रीय है, रसद क्षेत्रीय है और अमल स्थानीय है। पिछले कई विस्फोटों की जिम्मेदारी लेने वाला **'इंडियन मुजाहिदीन'** नामक संगठन फर्जी जान पड़ता है जिसके पीछे लश्कर–ए–तैयबा, हूजी, जैश–ए–मुहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे विदेशी और सिमी जैसे देशी संगठन अपने को छिपाना चाहते हैं। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी अभियान के निशाने पर हैं, इसलिये एक कागजी संगठन खड़ा करके उसकी ब्रांडिंग में जुटे हैं। इसका दूसरा मकसद यह भी है कि भारत में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को शुद्ध रूप से स्थानीय असंतोष का विस्फोट और धार्मिक–सांस्कृतिक अस्मिता की लड़ाई साबित किया जा सके। इसके लिये 'इंडियन मुजाहिदीन' से बेहतर क्या नाम दिया जा सकता है?

आत्मघाती आतंकवाद का सहारा लेकर कट्टरपंथी एवं विद्रोही ताकत भारत को निरंतर उलझाये रखना चाहती है। इसके लिये सिर्फ आई.एस.आई. ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अनेक आतंकवादी गुटों ने भारत में अपना नेटवर्क फैला रखा है। ऐसा करने के कारण उनके दो लक्ष्यों की पूर्ति हो रही है। **पहला** कश्मीर को भारत से अलग करने का अच्छा अवसर मिल जाता है तथा **दूसरा** भारतीय सेनाओं को देश में ही व्यस्त रखकर नुकसान पहुँचाते रहना। आई.एस.आई. के प्रमुख रहे लेफ्टीनेंट जनरल हामिद गुल का मानना है कि भारतीय सैनिकों को जेहादियों के जरिये नुकसान पहुँचा कर व्यस्त रखने के कारण ही पाकिस्तान की सेना को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के नई टुकड़ी तैयार करने का मौका मिल जाता है। भारत में अस्थिरता एवं आतंक फैलाने के लिए कई देशी–विदेशी आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। इसमें सिमी और लश्कर–ए–तैयबा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

वास्तव में वर्तमान समय में आतंकवाद का स्वरूप बहुत बदल गया है और ऐसा विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप हुआ है। संचार के ऐसे साधन आ गये हैं, जिससे आतंकवादी संगठन एक–दूसरे के साथ आसानी से संपर्क स्थापित करके और धन जुटाने से लेकर रणनीति बनाने तक आपस में बेहतर संवाद बना पा रहे हैं। संचार की नई तकनीकी और हिंसा के नये हथियार सिर्फ सरकारों को ही नहीं मिल पा रहे हैं, बल्कि आतंकवादी संगठनों को भी

मिल रहे हैं। आतंकवाद अब क्रूरता, बर्बरता, विध्वंसक एवं विनाशक का स्वरूप ले चुका है। आमतौर पर यह माना जाता है कि आतंकवाद से निपटना सरकार का काम है। इस रवैये को बदलना होगा और सरकार एवं आम जनता इस बदलाव में मददगार हो सकती है।

मुंबई में आतंकी हमलों से व्यथित लोग आतंकवादियों का खात्मा करने के साथ ही खुद को सुरक्षा प्रदान करने की भी माँग कर रहे हैं। उनकी यह माँग पूरी तौर पर जायज है, लेकिन आज जैसी स्थितियाँ हैं, उनमें सबको सुरक्षा प्रदान करना एक जटिल कार्य है। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसके पश्चिमी और पूर्वी छोरों से आतंकी घुसपैठ करते रहते हैं। इन आतंकियों ने देश के अंदर भी अपने समर्थकों का एक जाल फैला लिया है। सिमी, इंडियन मुजाहिदीन आदि ऐसे संगठन हैं। इनका संबंध सीमा पार के लश्कर–ए–तैयबा और जैश–ए–मुहम्मद सरीखे संगठनों से है और सब जानते हैं कि उनका संबंध तालिबान एवं अलकायदा से है। स्पष्ट है कि उस आतंकवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है जो पाकिस्तान में फल–फूल रहा है। आज विश्व समुदाय और विशेष रूप से विकसित देश यह अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी बन गया है, लेकिन अपनी शातिर कूटनीति के कारण पाकिस्तान पश्चिमी देशों और भारत के कोप से बचा हुआ है। आतंकवाद के सफाए के लिये बीड़ा उठाने वाला अमेरिका पाकिस्तान में सैन्य कार्यवाही कर अलकायदा और तालिबान से तो लड़ रहा है, लेकिन वह गुलाम कश्मीर में सक्रिय लश्कर, जैश जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ सीधी कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं। ये वे आतंकी संगठन हैं, जिनके निशाने पर भारत है।

पिछले एक दशक में आतंकवाद ने जिस तरह पूरे विश्व को अपने चंगुल में ले लिया है, उसे देखते हुए भारत को जो तैयारी करनी चाहिए थी वह नहीं की गई। न तो पुलिस आतंकियों का सामना करने के लिए तैयार है और न ही खुफिया एजेंसियाँ और अन्य सुरक्षा बल। मुंबई की घटना इस बात की गवाह है कि आतंकियों के समक्ष पुलिस असहाय सी थी और इसीलिये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के दस्ते के साथ–साथ अन्य सुरक्षा बलों को भी बुलाना पड़ा। आतंकियों से लोहा लेने के लिये अब यह आवश्यक है कि पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया जाए और उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाये। भारत सरकार यह तो कह रही है कि सुरक्षा और खुफिया एजेंसियाँ नाकाम रहीं।

अब जरूरत है कि आतंकवादियों के विरुद्ध शक्तिशाली एवं सामूहिक कदम उठाने की, चूँकि फिदायीन (आत्मघाती दस्ता) आतंकवाद का सबसे घातक प्रारूप है, जिससे बचने के लिये आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार करना होगा। खुफिया सूचनाओं के बावजूद हमारे यहाँ सावधानी के प्रति उदासीनता देखी जाती है। नेतृत्व की शिथिलता, कमजोरी, संकल्प की कमी का नुकसान देशवासियों एवं बेकसूर लोगों को भुगतना पड़ता है। असल में समूचे राजनैतिक वर्ग की आतंकवाद को लेकर नीतियाँ ही स्पष्ट नहीं हैं। आतंकवाद पर उसकी वार्षिक

रिपोर्ट में भी चार बिंदु पूरी तरह से स्पष्ट हैं। यानि आतंकवाद को लेकर वे किसी संकोच या हिचक में नहीं पड़ते। हमारे यहाँ कोई भी उपाय आगे नहीं बढ़ता। मसलन, आतंकवाद के लिए संघीय एजेंसी बनाने का विचार अमल में नहीं लाया जा सका। हमारे गृहमंत्री कहते हैं कि राज्य सरकारें सहमत नहीं हैं। उनमें किसी तरह की इच्छाशक्ति ही नहीं है और बिना स्पष्ट नीति और इच्छाशक्ति के आतंकवादी हमले बढ़ते जाएँगे और हम हाथ पर हाथ धरे देखते रहेंगे।

यह सत्य है कि आज विविध विनाशक स्वरूप में आतंकवाद उभरकर सामने आ रहा है। जिसमें **'इंसानियत'** का कत्ल–ए–आम किया जा रहा है। मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बना हुआ है। इसका नतीजा अच्छा तो कतई नहीं हो सकता, अलबत्ता यह मनुष्य के सर्वनाश और महाविनाश का मार्ग अवश्य है। हमें इंसानियत को बचाना है तो इंसानों का लहू बहने से रोकना होगा, आतंकवाद का खात्मा करना होगा। इन दिनों देश आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। जहाँ–तहाँ होते आतंकी हमलों से आमजन भयाक्रांत है। आतंकवाद से मुकाबले के लिये सरकारी स्तर पर क्या तैयारी हैं या कितने प्रयास हो रहे हैं, इस पर हम न जाएँ और यह समझ लें कि हम सबको मिलकर इस समस्या का सामना करना है। आतंकियों का मकसद जनता का मनोबल तोड़ना और देश की छवि खराब करना है। इन मुट्ठी भर आतंकियों के खिलाफ यदि हम एक अरब से ज्यादा लोग एकजुट हो जाएँ तो इनके समूल नाश में ज्यादा देर नहीं लगेगी।

निस्संदेह आत्मघाती हमले के द्वारा आतंकवादी संगठनों की जहाँ शक्ति बढ़ी है, वहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के समक्ष अनेक आपदायें घातक रूप में खड़ी हो गई हैं। फिदायीन या आत्मघाती आतंकवाद 21वीं शताब्दी में एक व्यापक विपदा को लेकर आया है।

अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु चुनौती[300]

आत्मघाती हमला आतंकवाद का वह विध्वंसक, विनाशक, विप्लवकारी, विकराल, विदारक, विषघाती, वेदनादायक एवं विषम रूप लेकर आया है, जिससे मानवता की रुह काँप उठती है। आतंकवादी अपने अभियानों में नित नई पद्धतियाँ अपना पहले से अधिक आक्रामक होते जा रहे हैं। नई तकनीकी विधियों का इस्तेमाल करके मानवता के समक्ष आतंकवादियों ने अनेक चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। आतंकवादियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले जैविक एवं रासायनिक हथियारों से बचने के लिए देश और दुनिया को तैयार रहना होगा। आतंकवादियों द्वारा परमाणु हथियार हथियाने की नाकाम कोशिशें भी निरंतर जारी हैं। अतः दुनिया के देशों को मिलकर आतंकवाद के इस ओर बढ़ते कदमों को यथाशीघ्र रोकना होगा। भारत ने इसी कारण कट्टपंथ और असहिष्णुता पर सख्त रुख अखित्यार कर इससे होने वाले नकारात्मक असर के प्रति आगाह करते हुए संयुक्त राष्ट्र के

[300] वही, पृ. सं.–130–136

सदस्य देशों से वैश्विक आतंकवाद से कारगर ढ़ंग से निपटने के लिये नया अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने का फरजोर आग्रह किया है।

भारतीय विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन को 26 सितम्बर 2009 को यहाँ संबोधित करते हुए कहा, आतंकवाद से मुकाबला करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढ़ाट्टचे को मजबूत बनाने के वास्ते भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर समग्र संधि का प्रस्ताव किया है। श्री कृष्णा ने आतंकवाद का जिक्र करते हुए कहा, अब इसके खिलाफ कारगर कार्यवाही करने का वक्त आ गया है। इसलिये भारत सभी सदस्य देशों से आग्रह करता है कि अगले कुछ हफ़्तों में इस तरह की संधि के प्रारूप पर सहमति कायम करने के लिये गंभीर प्रयास किये जायें। पाकिस्तान का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया, लेकिन संदर्भ स्पष्ट था, क्योंकि उन्होंने मुंबई में पिछले वर्ष 11 नवम्बर 2008 को हुए आतंकवादी हमलों को बर्बर बताते हुए कहा कि इस तरह की कार्यवाहियों को किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह के घिनौने हमलों के न सिर्फ साजिशकारों को बल्कि इनके समर्थकों को भी सजा मिलनी चाहिए। विदेशमंत्री ने कई अन्य ज्वलंत मुद्दों पर भी अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों की खासकर अफगानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की स्थितियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा और वह चाहता है कि सभी प्रमुख मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत से सुलझाया जाये।

आतंकवाद अब दुनिया भर में है। दुनिया भर के आतंकवादी मिलकर संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक–दूसरे के साथ मिलकर ही आतंक भी फैला रहे हैं। इनका मकसद भी एक ही है, जिसे ये **'जिहाद'** कहते हैं। यह आतंकवाद के वैश्वीकरण यानि ग्लोबलाईजेशन का बड़ा सबूत है कि एक ही दिन में सोमालिया, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, सउदी अरब और ब्रिटेन के आतंकियों के बीच आपसी सहयोग और संपर्क की खबरें आई हैं। एक अमेरिकी रिपोर्ट में कुछ ही दिन पहले यह बताया ही जा चुका है कि अलकायदा वैश्विक लक्ष्य के लिये दुनिया भर में छोटे–छोटे प्रेंफचाईजी संगठनों के जरिये एक केंद्रीकृत संगठन के रूप में काम करने लगा है। ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का 'ग्लोबलाईजेशन' भी जरूरी हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन अलकायदा के लिये मुख्य प्रशिक्षण केंद्र अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही नहीं रह गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गृह युद्ध से बर्बर सोमालिया भी अब अलकायदा की आतंकी नर्सरी बनता जा रहा है। राह से भटके ब्रिटिश युवा बड़ी संख्या में 'जिहाद' के प्रशिक्षण के लिये सोमालिया का रुख कर रहे हैं।

विश्व का घातक आतंकवादी संगठन अल कायदा सउदी अरब में धर्मार्थ संगठन बना कर उसके जरिये पाकिस्तान में सक्रिय आतंकियों को पैसे मुहैया करा रहा है। पाकिस्तानी पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक अल कायदा के मुखौटा संगठन के रूप में काम करने वाली इस सउदी धर्मार्थ संस्था ने पाकिस्तान में आतंक फैलाने के

लिये अलकायदा आतंकियों को कम से कम 1.5 करोड़ डॉलर (करीब 74 करोड़ रूपये) दिये हैं। अपराध जाँच शाखा (सी.आई.डी.) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अल–हरामेन फाउंडेशन ने तहरीक–ए–तालिबान को दिल खोल कर आर्थिक मदद की है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अलकायदा से आतंकी साँठ–गाँठ के कारण अल–हरामेन फाउंडेशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

पाकिस्तान जो आतंकवाद का आधार रहा, वह अब स्वयं के ही पैदा किये गये आतंकवादियों के कारण तबाही के कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गये हैं कि पाकिस्तान खंड–विखंड कभी भी हो जाये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जहाँ पाक की आर्थिक स्थिति जर्जर होती जा रही है, वहाँ रोज–रोज के धमाके और लाशों के लगते अंबार से असहाय की स्थिति बनती जा रही है। आतंकवाद का यह घातक सिलसिला अब पाकिस्तान के थामे थम नहीं रहा है। अब आतंकवादी धमाके पाकिस्तान के अत्यंत संवेदनशील स्थानों, जैसे–सेना मुख्यालय (आर्मी हेडक्वार्टर) और परमाणु बमों के जखीरों के करीब तक पहुँच गये हैं।

3.1 आत्मघात को प्रेरित करने वाले तत्त्व (कारण) (Factors or Elements Responsible for the Motivation of Suicide Attackers)

ये आत्मघाती गरीब परिवेश में पले होते हैं। इनके हालात व मजबूरियाँ आत्मघात के लिये प्रेरित करती हैं जिनके कारण वह आत्मघाती हमले के लिये तैयार होते हैं। यहाँ पर हमें इस बात का अध्ययन करना है कि कोई व्यक्ति आत्मघाती आतंकवादी कैसे बन जाता है क्योंकि जान सभी को प्यारी होती है फिर ये लोग अपनी जान की कुर्बानी क्यों देते हैं। वे कौन–से तत्त्व हैं जिनसे प्रेरित होकर ये अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं। प्रमुख आतंकवादी समूहों (संगठनों) के नेता (प्रमुख) **निम्नलिखित तत्त्वों (कारणों) को ध्यान में रखकर आत्मघाती दस्ते तैयार करते हैं –**

1. घोर गरीबी (Poverty)
2. अशिक्षा (Illiteracy)
3. कच्ची उम्र के नवयुवकों का चयन (Teenagers)
4. जन्नत (स्वर्ग) का झूठा आश्वासन (Illusion of 'Jannat')
5. जीवन के प्रति निराशा (Frustration and Desperation)
6. बेरोजगारी (Unemployment)
7. जनसंख्या वृद्धि (Over Population)
8. शिक्षा के अभाव में देशभक्ति की गलत परिभाषा
9. भ्रष्टाचार (Corruption)
10. राजनीतिक संरक्षण(Political Support)
11. विकसित राष्ट्रों की गलत नीतियाँ

उपर्युक्त सभी कारणों (तत्त्वों) का वर्णन निम्नलिखित है –

1. **घोर गरीबी (Poverty)–** इन नवयुवकों का परिवार घोर गरीबी की हालात (दुर्दशा) में जीवन यापन करने को मजबूर होता हैं। इनको जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहना पड़ता है। ऐसे परिवेश में अगर इन्हें कोई आतंकवादी दल अच्छे जीवन का सपना दिखाये तो ये आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। उनका विवाह अच्छे परिवार में हो जायेगा और जीवन की सारी सुख–सुविधायें मिल जायेंगी। इसी लालच में आकर आतंकवादी संगठनों (समूहों) में शामिल हो जाते हैं और फिर प्रशिक्षण प्राप्त करके आत्मघाती दस्तों का रूप धारण कर लेते हैं।
2. **अशिक्षा (Illiteracy)–** आतंकवादियों द्वारा अशिक्षित बेरोजगारों को ढूट्टढ़ा जाता है। ये लगभग अशिक्षित होते हैं क्योंकि इनको अ(र्शिक्षित कठमुल्ले सिर्फ कुरान को पढ़ने और बोलने लायक शिक्षा प्रदान करते हैं। ये कुरान की कुछ पंक्तियाँ पढ़कर रट लेते हैं। उसके अर्थ को समझने की क्षमता इनमें नहीं होती है। क्या उचित है? क्या अनुचित है? इस बात का ज्ञान (बोध) इनकों नहीं होता है। इनमें विवेक और विश्लेषण की क्षमता का अभाव होता है, वैज्ञानिक सोच नहीं होती।

   प्रायः यह देखने में आता है कि जब कोई अशिक्षित होता है तो उसको किसी विशेष क्षेत्र में जानकारी का अभाव होता है और उस क्षेत्र के सम्बन्ध में होने वाले हानि–दोष या लाभों को नहीं जान पाता है। ऐसी स्थिति मे अगर कोई व्यक्ति इन अशिक्षित लोगों को कोई लाभ वाली स्थिति के बारे में अवगत कराता है और उसे जुड़ने की बात कहता है। तो वह व्यक्ति न तो लक्ष्य को समझ पाता है और न ही उस कार्य के अन्तिम परिणाम के बारे में सोच पाता है और प्रारम्भ में अपने हित की बात सोचकर उस कार्य में लिप्त हो जाता है और वह उस रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा की कमी भी आतंकवादियों को जन्म दे रही है। ''अशिक्षित व्यक्ति का बुद्धि परिवर्तन करना आसान होता है क्योंकि उनके सोचने–समझने की क्षमता अति कम होती है। उनके स्वच्छ मस्तिष्क पर घृणा, पाप, बदले जैसी तस्वीरें अंकित कर दी जाती है। जिनको बदलना बड़ा ही मुश्किल कार्य है।''[301]
3. **कच्ची उम्र के नवयुवकों का चयन (Teenagers) –** आतंकवादी संगठनों के संचालक ऐसे अपरिपक्व नवयुवकों की तलाश में रहते हैं जिनकी उम्र 12 साल से लेकर 19 साल के बीच में होती है। ऐसे नवयुवक कोई फैसला लेने में पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते हैं। इनका आसानी से बुद्धि प्रक्षालन (Brain Wash) किया जा सकता है। विचारारोपण और बुद्धि परिवर्तन (प्रक्षालन) अधिक आसान

[301] डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव, ''वैश्विक आइने में आतंकवाद : वर्तमान परिदृश्य एवं भविष्य की चुनौतियाइ्ट'', 2011, ओमेगा पब्लिकेशन्स, 4378/4बी, जी–4, जे.एम.डी. हाउस, गली मुरारीलाल, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, फोन – 65901906, पृष्ठ संख्या – 173

होता है क्योंकि 25 साल के बाद की उम्र के लोगों के विचारों को बदलना बहुत मुश्किल होता है।

उदाहरणः 26 नवम्बर 2008 को पाकिस्तान ने मुम्बई में ताज होटल और अन्य इमारतों पर आतंकवादी हमला करने के लिए 10 आतंकवादियों को समुद्री मार्ग से भेजा था। इन 10 आतंकवादियों की उम्र 18 और 20 वर्ष के आसपास थी इनमें से सिर्फ एक आतंकवादी (अजमल कसाब) बचा था जिसको फांसी की सजा दी जा चुकी है।

4. **जन्नत (स्वर्ग) का झूठा आश्वासन (**Illusion of 'Jannat')- आतंकवादियों के आका (नेता या मुखिया) इन आत्मघाती जीवित मानव बमों को ऐसा आश्वासन देते हैं कि तुम युद्ध भूमि में शहीद होने के बाद सीधे जन्नत (स्वर्ग) में जाओगे वहाँ पर आपको अनन्त सुख प्राप्त होगा। हूर की परियाँ आपकी सेवा करेगी और उच्चकोटि की शराब की बहती हुई नदियाँ, दूध व मधु की नदियाँ भी आपको प्रदान होगी। इस तरह का भ्रांतिपूर्ण आश्वासन मिलने के बाद कोई भी नवयुवक शहीद होने के लिये तैयार हो जाता है तथा '**मरने का भय**' उसके मस्तिष्क से खत्म हो जाता है और खुशी–खुशी वो अपने आत्मदाह के लिये तैयार हो जाता है। इनको हथियार चलाने का कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है और इनको कमाण्डोज (जाँबाज) का शारीरिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। कठोर परिस्थितियों में सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसमों की मार को झेलने की आदत इनमें डाली जाती है। कई–कई दिनों तक इनको भूखा प्यासा रखा जाता है ताकि उनकी शारीरिक और मानसिक सहनशक्ति को बढ़ाया जा सके। वे गंभीर से गंभीर खतरों से आसानी से खेल सके। इनको प्रस्थान करने से पहले खाने के लिये सूखे मेवे (Dry Fruits) दिये जाते हैं ताकि ताजा भोजन के अभाव में ये कई महिनों तक सुखे मेवे खाकर जीवित रह सके।
5. **जीवन के प्रति निराशा (Frustration and Desperation)** – अशिक्षित, गरीब और बेरोजगार नवयुवक आसानी से निराशा के दुष्चक्र में फंसता चला जाता है जो उसको आतंकवादी संगठनों की तरफ मोड़ देता है। नवयुवकों का अशिक्षित, गरीब, बेरोजगार होने के वजह से इन्हें अपना जीवन व भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है। ये नवयुवक घोर निराशाओं व घरेलू समस्याओं से पीड़ित होने की वजह से ये कोई भी गलत कार्य करने को तैयार हो जाते हैं और फिर आतंकवादी संगठनों द्वारा इनको चुनकर अपने दलों में शामिल कर लिया जाता है जहाँ इनको कठोर प्रशिक्षण व धन दिया जाता है।
6. **बेरोजगारी (Unemployment)** – आतंकवादी आका (नेता) ऐसे नवयुवकों को छांटते हैं या चुनते हैं जो गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे होते हैं। इनको पैसा (धन) की अत्यन्त जरूरत होती है। इनके परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत होती है। इनके परिवार में कमाने वाले कम होते हैं। अतः अपने और अपने परिवार के जीवनयापन के लिये ये कुछ भी करने के लिये बड़ी

आसानी से तैयार हो जाते हैं। आतंकवादी संगठन इनको धन का लालच देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे व तुम्हारे परिवार के सारे कष्ट दूर कर देंगे। तुमको इतना धन देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते और तुम्हारी शहादत या शहीद या मरने के बाद तुम्हारे परिवार को बहुत आर्थिक सहायता दी जायेगी और उनको भविष्य में कोई भी कष्ट नहीं होगा। इतना आश्वासन मिलने के बाद कोई भी नवयुवक इनके जाल में बहुत आसानी से फंस जाता है।

आतंकवादियों को उत्पन्न करने में बेरोजगारी सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण तथ्य है। ''आज जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है और रोजगारों का अभाव है। इस परिस्थिति में युवा पीढ़ी पैसा कमाने के चक्कर में कुछ गलत राह का चुनाव कर लेते है या फिर किसी गलत व्यक्ति की बातों में आकर गलत रास्ते पर चले जाते है। आज आतंकवादी गुट इस तरह से नवयुवकों को पथ भ्रष्ट करके उन्हें आतंकवादी बनने पर मजबूर कर देते है।''[302] आज की युवा पीढ़ी जल्दी अमीर बनने की चाह में अपने संस्कारों, सामाजिक भावनाओं एवं देश के प्रति कर्त्तव्य की भावनाओं को भूलकर आतंकवादियों का साथ देते है। आज हमारा दायित्त्व है कि इन युवकों को वह शिक्षा दे जिससे वह अपना कैरियर देश हित को देखकर तय करे। सरकार को चाहिये कि वह नव युवकों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मुहैया करा कर उनकों गलत राह पर जाने से रोकें।

7. **जनसंख्या वृद्धि (Over Population)** – आज बढ़ती हुई जनसंख्या भी इस पहलु का एक प्रमुख कारण बन गया है। आज जिस गति से जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, उस गति से न तो नवयुवकों को रोजगार मिल पा रहे हैं और न ही उनकी दैनिक जरूरतें पूरी हो रही है जिससे आज की युवा पीढ़ी इस आतंकवाद जैसी गलत राह पर आगे बढ़ रही है। आज कुछ लोग इन नवयुवकों को रोजगार दिलाने के बहाने उस रास्ते पर भेज देते है जिस पर जाने के बाद फिर वे चाहकर भी वापिस नहीं आ पाते। उनको धर्म के नाम पर गलत शिक्षा देकर आतंकवादी बना दिया जाता है। यह कार्य उनकी मजबूरी और अज्ञानता का एक प्रमुख कारण है। देखने में आया है कि इनका परिवार बहुत बड़ा होता है क्योंकि उनका मुस्लिम समाज एक से अधिक शादी करने की इजाजत (अनुमति) देता है और इस प्रकार उनकी जनसंख्या भी तेजी से बढ़ जाती है। और गरीब परिवार उनको अच्छी शिक्षा एवं अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाता है। इसलिये आतंकवादियों को ऐसे नवयुवकों की आसानी से प्राप्ति हो जाती है। अतः अनेक कारण एक आम आदमी को आत्मघाती हमलावर (आतंकवादी) बना देते हैं। फिर धार्मिक कफ्रवादी कठमुल्ले इनको **धर्म के नाम पर भ्रमित करते हैं कि –**

---

[302] वही, पृ.सं. – 174

1. अगर आप अल्लाह के नाम पर शहीद हो जाओगे तो सीधा स्वर्ग (जन्नत) में जाओगे।
2. और अगर युद्ध में जीत गये तो संसार की भौतिक सुख–सुविधाओं का आनन्द लुटोगे अर्थात् तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। अतः आतंकवादी गतिविधियों के लिये तैयार हो जाओ।

8. **शिक्षा के अभाव में देशभक्ति की गलत परिभाषा** – अशिक्षित, बेरोजगार युवा पीढ़ी को आतंकवादी तत्त्व अपने शिकंजे मे लेकर उनको देशभक्ति की गलत शिक्षा प्रदान करते हैं। वह कहते है कि जिस देश ने तुम्हे सब कुछ दिया है उस देश के लिए जिहाद करो, देश के लिए खुद को खत्म करना पड़े तो मत झिझकों यह तुम्हारा कर्त्तव्य है। हम मिलकर सभी राज्यों पर राज करेंगे जिससे हमारा देश विकास करेगा और फिर हम सब मिलकर धीरे–धीरे सारे विश्व को अपने अधीन कर उस पर राज करेंगे। यही हृदय परिवर्तन उनको आतंकवादी बना देता है।

9. **भ्रष्टाचार (Corruption)** – भ्रष्टाचार भी आतंकवाद का एक प्रमुख कारण है। आज प्रायः देखने में आता है कि कोई भी कार्य चाहे वह छोटा हो या बड़ा बिना रिश्वत के नहीं होता है। जिसके पास पैसा होता है वह अपना काम आसानी से करवा लेता है। जबकि धनाभाव होने पर जिसका भी कार्य नहीं होता, उसके अन्तर्मन में एक कुण्ठा जन्म ले लेती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है और अनैतिक, असामाजिक और विद्रोही कार्य करने लगता है। यही प्रक्रिया आगे चलकर आतंकवाद का विशाल स्वरूप धारण कर लेती है। ऐसे ही लोग आगे आतंकवादी बन जाते है।

10. **राजनीतिक संरक्षण (Political Support)** – राजनीतिक संरक्षण जैसा कि शब्द से साफ प्रतीत होता है कि राजनेताओं द्वारा दिया जाने वाला संरक्षण अर्थात् आज की राजनीति एवं हमारे नेताओं का आचरण इतना भ्रष्ट हो गया है कि वह अपने लाभ एवं वोट बैंक के लिए आतंकवादियों को शरण देने लगे है और अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इनकी मदद लेने लगे है। यह आतंकवादी जब इन नेताओं की शरण में आ जाते है तो वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करते है। इन्हीं नेताओं की वजह से आज आतंकवादियों को हमारे प्रमुख सबूतों, स्थलों एवं गोपनीय खबरों की जानकारी मिलती है। जो आतंकवाद को और अधिक मजबूती प्रदान करती है।

11. **विकसित राष्ट्रों की गलत नीतियाँ** – विकसित राष्ट्रों की किसी भी विकासशील राष्ट्र को तबाह, बर्बाद करने की धारणा आतंकवादियों को जन्म देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद अमेरिका है। पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई. को संगठित करने का श्रेय अमेरिका को जाता है और न्यून–तीव्रता संघर्ष (LIC) जिसमें आतंकवाद एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है, नीति का आविष्कार सर्वप्रथम अमेरिका ने ही किया था जिसे बाद में पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ अपना लिया। अमेरिका ने विभिन्न

देशों में उत्पात मचाने के विचार से एवं उन देशों की सुरक्षा व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था को तहस–नहस करने के उद्देश्य से इस संगठन एवं स्ष्ठ को बनाया जिसने अमेरिका के इशारे पर भारत समेत कई देशों पर बराबर हमले किये जिसमें न जाने कितने बेकसूर लोगों की जानें गई और कितने ही लोग अनाथ हो गये एवं धन की कितनी हानि हुई इसका अनुमान लगाना असम्भव है। अन्त में अमेरिका को खुद इस गलत कार्य का भुगतान देना पड़ा। वही आतंकवादी संगठन जिसका सरगना ओसामा–बिन–लादेन था उसने जब अमेरिका पर ही हमला किया तब अमेरिका को एहसास हुआ कि आतंकवादी क्या होते है। जो कल तक इसको सहारा बनाकर दादागिरी करना चाहता था आज खुद वो इसकी चपेट में आ गया। ''इसके अतिरिक्त और भी कई कारणों से आज की युवा पीढ़ी आतंकी संगठनों से सम्बन्ध रखने लगी है। इसके जिम्मेदार नेता, पुलिस एवं कुछ धनी लोग है। जो अपने स्वार्थों के लिए कमजोर वर्ग के युवाओं को दबाते है उनका शोषण करते है। जिसकी वजह से वह युवा गलत राह अख्तियार करते है।''[303]

भारत में आज तक बहुत से आतंकवादी संगठनों ने विभिन्न प्रान्तों में हमले किये सन् 1980 के दशक से हमारे देश में इस तरह के आतंकी हमले हो रहे है। जिसके नुकसान का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है। विभिन्न आतंकी संगठनों का निर्माण आये दिन हो रहा है। भारत में जिन आतंकवादी संगठनों का बोलबाला है। वह ज्यादातर पाकिस्तान प्रदत्त है। पाकिस्तान में ही इनके शिविर, प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे है। खुद पाकिस्तानी सरकार इनको बढ़ावा दे रही है और उनका पोषण भी वही से होता है। इसका मुख्य कारण जम्मू–कश्मीर को माना जाता है। पाकिस्तानी सरकार इसे अपने कब्जे में लेना चाहती है जबकि यह हमारा स्वर्ग है। इसके लिए पाकिस्तान ने पहले भी हम पर 1947–48, 1965, 1971, 1999 में पारम्परिक युद्ध किये, पर जब निराशा हाथ लगी तो उसने पारम्परिक युद्ध को त्याग कर न्यून–तीव्रता संघर्ष (LIC) को अपनाकर इन आतंकवादियों का सहारा लेना प्रारम्भ कर दिया और जम्मू–कश्मीर को हथियाने का भरसक प्रयास किया पर विफलता ही हाथ लगी। आज फिर भी पाकिस्तान अपनी गिरी हुई हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और नये–नये माध्यमों एवं तकनीकों का सहारा लेकर हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है। जिसका उदाहरण देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई पर हुआ हमला है। जिसने देश की नींव को हिला दिया यह हमला राष्ट्रीय संकट का प्रतीक है।

आत्मघाती हमलावरों को प्रलोभन देने वाले तत्त्व

आत्मघाती हमलों का जिम्मा लेने वाले युवा जेहादियों की भर्ती धार्मिक प्रेरणा से होती है। उनके साथ–साथ आतंकी कार्यवाही करने वाले लोगों के परिवारों के पालन–पोषण के लिए मोटी रकम दी जाती है। 140 मिलियन (14

---

[303] वही, पृ.सं. – 175

करोड़) की जनसंख्या और दिवालिया होने के कगार पर स्थित पाकिस्तान अपने युवाओं में उग्रवाद की भावना फैलाने वाला प्रमुख देश है। पाकिस्तान के बेरोजगार युवक जन्नत के वादे और छह से लेकर आठ हजार (6000–8000) रूपये तक के मासिक वेतन, जो अभावग्रस्त परिवारों के लिये एक बड़ी रकम है, के बदले आतंकवादी संगठनों में शामिल होने की इच्छा रखते हैं।

एक प्रश्न यह उठता है कि आतंकवादियों व आत्मघाती हमलावरों को वित्तीय अथवा अन्य सहायता कहाँ से प्राप्त होती है? इसका उत्तर अध्याय 5.1.3 में वर्णित है। इसके एक नहीं वरन् अनेक स्रेतहै। लीबिया ने अपने तेल राजस्व का आतंकवादी संगठनों का स्वामी बनने में उपयोग किया है। इसी प्रकार सीरिया और इराक भी इस होड़ में शामिल है। लीबिया व पाकिस्तान प्रशिक्षण शिविर लगाता है और आतंकवादियों को हथियार और झूठे दस्तावेज उपलब्ध कराता है। आतंकवादियों को वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण अन्य मुस्लिम राष्ट्रों द्वारा दिया जाता है।

3.2 जिहाद और धर्म के नाम पर युवाओं को भ्रमित करना
(Illusion of Teenagers in the name of Allah and Jihad)

आतंकवादी संगठनों द्वारा युवाओं को जिहाद व धर्म और सभ्यता–संस्कृति व देश के नाम पर उकसाया जाता है और उन्हें आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें अपने धर्म की रक्षा व धर्म के लोगों की रक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है अर्थात् युवाओं का भावनात्मक शोषण किया जाता है। इस प्रकार अशिक्षित, बेरोजगार व गरीब युवक बिना सोचे समझे इन आतंकवादी संगठनों में शामिल हो जाते हैं और अपने प्राणों की बाजी लगाकर आत्मघाती हमलों को अंजाम देते हैं और बाद में '**शहीद**' या '**स्वतंत्रता सेनानी**' कहलाते हैं।

आतंकवाद को प्रोत्साहन देने में विदेशों का हाथ है जो खुलेआम आतंकवादियों को शरण और प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। जैसे पंजाब और कश्मीर के आतंकवादियों को पाकिस्तान एवं चीन द्वारा नागा और मिजों विद्रोहियों को प्रशिक्षण, हथियार सप्लाई, धन आदि दिया जा रहा है। आतंकवादी बेखौफ होकर सारी दुनिया में दहशत का माहौल तैयार कर चुके हैं। सबसे ज्यादा दहशत फैलाने वाला इस्लामी आतंकवाद है। आज लीबिया, सूडान, पाकिस्तान, अलबानिया, यमन, सीरिया और लेबनान में भी आतंकवादियों को तैयार करने के उद्योग बड़े पैमाने पर चल रहे हैं।

''समाज ही आतंकवादियों का निर्माण करता है।''[304] आज के विश्व में वे अधिकतर समाज के वंचित वर्ग में पाए जाते हैं, जहाँ अत्यधिक जनसंख्या ने निर्धनता, एकांत के अभाव और अत्यधिक शोरगुल द्वारा उत्पन्न पतन को और उग्र बना दिया है। एक अल्जीरियाई आतंकवादी ÚSaVt फेनन को यह कहते सुना

[304] मेजर जनरल विनोद सहगल, ''अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद'', 2006, प्रभात प्रकाशन, 4/19, आसफ अली रोड़, नई दिल्ली – 110002, पृष्ठ संख्या – 32

गया, ''हिंसा शुद्ध करने वाली शक्ति है। यह व्यक्ति को उसकी हीन भावना, निराशा और निष्क्रियता से मुक्त करती है। यह उसे निडर बनाती है और उसका आत्मसम्मान बहाल करती है।''[305] इस प्रकार आतंकवादी हिंसा में विश्वास करते है। जबकि गाँधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे।

''पाकिस्तान के सैनिक तानाशाहों ने 'जिहाद' को अपनी राज्य नीति का एक अंग माना है।''[306] यह इस्लाम व आई.एस.आई. के बुनियादी सिद्धान्तों में से एक है। आई.एस.आई. ने इस्लाम के नाम पर मुस्लिम लोगों को साथ जोड़ने के अनेक हथकण्डे अपनाते हुए उदाहरण भी दिया है कि इस्लाम के अनुसार मानव जाति मोमिनों और काफिरों में तथा धरती इस्लाम के वर्चस्व वाले देशों दार–उल–हरब में बट्टटी हुई है। ''इस्लाम का अपने अनुयाइयों को आदेश है कि वे काफिरों को मुसलमान बनाने या खत्म करने और दार–उल–हरब देशों को दार–उल–इस्लाम बनाने के लिए सतत् संघर्ष और हमला करते रहे। यही लड़ाई जिहाद कही जाती है। जिहाद में यदि वे जीतते है तो काफिर का जान, माल, जमीन, सम्पत्ति तथा स्त्रियाट्टा उन्हे भोग के लिए मिलेंगी, यदि वे जिहाद करते हुए मारे जाते हैं तो वे सीधे जन्नत में जाएँगे जहाँ प्रत्येक के भोग के लिए 72 हूरें, शहद की नदियाँ और हर प्रकार के ऐशो–आराम की अन्य सुविधाएँ उपलब्ध होगी।'' कुरान और हदीसो में जन्नत का विस्तार से वर्णन किया गया है और अनवर शेख जैसे इस्लाम के विद्वानों ने अपनी फस्तकों में जिहाद के संबंध में विस्तार से लिखा है। **वैसे जिहाद का सच्चा अर्थ है – उद्देश्य प्राप्ति के लिए संघर्ष।** इस्लाम के विद्वानों के अनुसार जिहाद की तीन स्थितियाँ होती है। **पहली –** आंतरिक जिहाद, **दूसरी –** प्रचारात्मक जिहाद, और **तीसरी –** सशस्त्र जिहाद। लेकिन इसकी अनिवार्य शर्त यह है कि जिहाद ईश्वर के लिए हो, अपनी इच्छा या मनोकामनाएँ पूर्ण करने के लिए नहीं। आंतरिक जिहाद का तात्पर्य भीतरी बुराइयों से संघर्ष का है। प्रचारात्मक जिहाद धर्म के प्रचार में तर्क–वितर्क और सबसे अव्वल सदाचार, सद्व्यवहार, श्रद्धा और उदारता से विरोधियों को जीतना है। ईश्वर के मार्ग को स्वीकार करवाने व अराजकता के अंत के लिए सशस्त्र जिहाद है लेकिन इसमें भी पहल करने की अनुमति नहीं है। सशस्त्र जिहाद प्रतिरक्षा तक ही सीमित है। इसके अतिरिक्त अच्छाई करना भी जिहाद है। ''इस विषय में पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब के जीवन की एक घटना ध्यान देने लायक है। एक वृद्ध व्यक्ति जिहाद में शामिल होने की अनुमति लेने पैगंबर साहब के पास पहुँचा। पैगंबर साहब ने पूछा – क्या तुम्हारे माता–पिता जीवित है? उसने जवाब दिया–अवश्य ही, हे अल्लाह के रसूल, पैगंबर साहब ने आदेश दिया– जाओ उनकी सेवा करों, यही जिहाद है। अच्छे कर्म करना, ईश्वर को समर्पित होकर आंतरिक व

[305] महमूद बिन मुहम्मद के लेख ''दि एनेटॉमी ऑफ टेररिज्म'', द हिन्दू, 4 दिसम्बर 2001 से लिये गये उ(रण।

[306] डॉ. कृष्णानन्द शुक्ल, ''लाल शीत युद्ध की दास्तान – भारत और पाकिस्तान'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, दूरभाष 011–23255141, पृष्ठ संख्या – 94

बाहरी जीवन में श्रेष्ठता को उतारने के लिए संघर्ष करते रहने में ही जिहाद का मर्म छिपा है।''[307]

वस्तुस्थिति यह है कि आई.एस.आई. की दो रूपरेखा है– **प्रथम** जम्मू–कश्मीर में आतंकवाद को हवा देते रहना और **द्वितीय** भारत के अन्य भागों में आतंकवाद, अलगाववाद एवं उग्रवाद फैलाना। दोनों कार्यों के लिए आई.एस.आई. द्वारा अलग–अलग प्रकार से योजना या कार्यविधि बनाई जाती है। पहली योजना के लिए आतंकवादी नवयुवकों को हथियार व विस्फोटक सामग्री देकर सीमा पार करवाकर कश्मीर पहुँचाया जाता है। एक बार में 30 या 40 लोगों का काफिला कश्मीर आता है। कश्मीर आने के बाद यह नवयुवक 6–7 का एक ग्रुप बनाकर अपनी रणनीति के तहत विस्फोटक कार्य के लिए जुट जाते हैं। इन लोगों को सीधा सा आदेश होता है– 'गोली–बारूद चलाओ और दहशत फैलाओ।' यदि इस दौरान कोई आतंकी इस दौरन ऐसे कार्य से हाथ झाड़ने की सोचता है तो आई.एस. आई के एजेन्टों द्वारा उसे बता दिया जाता है– यदि वह भारत में रहेगा तो उसे पकड़वा दिया जायेगा और यदि वह पाकिस्तान वापिस जायेगा तो जेल में डाल देंगे। मजबूरन यह युवक आई.एस.आई. के लिए काम करने लगते है यदि इस दौरान आतंकवादी नवयुवक इन्हें धोखा देकर इनके चंगुल से निकल आता है तो आई.एस.आई. उसे भगौड़ा घोषित कर अपने एजेन्टों को उसे जान से मारने का हुक्म दे देती है।

''पाकिस्तान में 1976 में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाई गई जिसके तहत वहाँ के बच्चों को शुरू से जिहाद की शिक्षा दी जाती है। वहाँ अलिफ से अल्लाह, बे से बम व बन्दूक, जे से जिहाद, के से खंजर पढ़ाया जाता है। यानि इस प्रणाली का उद्देश्य ही है जिहादी पैदा करना।''[308] इतना ही नहीं वहाँ के पाँचवी कक्षा के छात्रों को जिहाद पर भाषण देने के लिए कहा जाता है। बच्चों को कक्षा में खड़े करके पूछा जाता है कि हिन्दू–मुसलमान में क्या अन्तर है, इस्लाम का दुश्मन कौन है? इनकी यही शिक्षा प्रणाली ही आम व्यक्ति को आतंकवादी सोच का व्यक्ति बना देती है।

आतंकवाद और जिहाद में काफी अन्तर है भारत में बहुत बुद्धिजीवी और रक्षा विश्लेषक ऐसे हैं जिन्हें आतंकवाद और जिहाद में फर्क मालूम नहीं है। ''जिहाद एक बड़ी विचारधारा है, जिसका उद्देश्य है एक युद्ध द्वारा सभी काफिरों (गैर मुस्लिमों) को इस्लाम कुबूल करने के लिए मजबूर करना। यदि काफिर ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें मारा जाए, खत्म किया जाए।''[309] भारत के विरूद्ध जिहाद

---

[307] क्रमांक – 4, पृ.सं. – 330

[308] डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव, ''वैश्विक आइने में आतंकवाद : वर्तमान परिदृश्य एवं भविष्य की चुनौतियाड्ढ'', 2011, ओमेगा पब्लिकेशन्स, 4378/4बी, जी–4, जे.एम.डी. हाउस, गली मुरारी लाल, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, फोन 011–65901906, पृष्ठ संख्या – 20–21

[309] वही, पृ.सं. – 21

चल रहा है। इसी के अन्तर्गत यहाँ हिन्दुओं को मारा जा रहा है, उनमें अपने धर्म और संस्कृति के प्रति अनास्था भरी जा रही है। यह इस्लाम का परम्परागत तरीका है काफिरों के प्रति। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग की वार्षिक बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान नाम से एक इस्लामिक देश बनाना चाहिए। इसके दो–तीन साल बाद ही चौधरी रहमत अली, जो यू.के. में पढ़ते थे, ने एक 'मिल्लत एंड मिशन' बयान जारी किया। इस 'मिल्लत एंड मिशन' को पढ़ने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि क्यों इतने वर्षों से भारत के विरूद्ध जिहाद जारी है। 'मिल्लत एंड मिशन' में उन्होंने लिखा है 'हमे सात काम करना है' किन्तु इनमें भी सबसे बड़ा प्रमुख काम है भारत से हिन्दू सभ्यता को खत्म करना। उन्होंने यह भी लिखा है कि मुसलमानों का ध्येय होना चाहिए भारतीयता को मिटाना। उनका यह भी विचार था कि अन्ततः 'पाक एशिया' के नाम से एक नया उप महाद्वीप बने।

अफगानी आतंकवादी शिविर में प्रशिक्षक रह चुके अबु हिजरत उर्फ मुहम्मद नबाज ने प्रेस को बताया कि कम से कम आठ सौ आतंकवादियों को गुलाम कश्मीर में मुजफ्फराबाद स्थित उमर बस्ती और भागलफर में आत्मघाती दस्तों का फिदायीन बनाने के लिए तीन माह का प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं पाकिस्तान के गुजरावाला जिले के निवासी नबाज के अनुसार चार सौ से अधिक आत्मघाती गुरिल्ला नियन्त्रण रेखा के उस पार भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के इंतजार में है। ''आत्मघाती दस्तों में शामिल होने वाले कट्टर आतंकवादियों में अधिकांश बेरोजगार और अपराधी हैं जिन्हें धन और अपराधों से मुक्त करने का लालच देकर जम्मू–कश्मीर में हमले करने के लिए आई.एस.आई. द्वारा भेजा जाता है।''[310] आई.एस.आई. जिन घुसपैठियों को कश्मीर भेज रही है। उनकी उम्र 20 से 25 वर्ष की होती है ताकि वे वहाँ दो–तीन वर्ष रहकर आतंकवादी हरकत कर सके। अपने आतंकी मकसद के प्रति समर्पित, मजबूत इरादों वाले इन फिदायीन के अनुसार भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंक और कत्लेआम मचा रखा हैं जैसा कि ''भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर में लश्कर–ए–तैयबा का एक 18 वर्षीय फिदायीन खलीलुल रहमान बन्दी बनाया गया है। जिसने बताया कि उसे तो यह बताया गया था कि – हमारे कश्मीर के भाई–बहनों को भारतीय सेना के जुल्मों से बचाना है, हमारी कश्मीर की बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, कश्मीरियों को घरों से निकालकर भारतीय फौजी उन्हें जूतों से रौंदते हैं।''[311] लश्कर–ए–तैयबा के लोग मेरे स्कूल आए थे और मुझे अलग ले गए और कहा कि ''यदि मैं शहीद हो गया तो मेरे परिवार को आर्थिक सहायता दी जायेगी, मैं कश्मीर में हीरों बन जाऊङ्गा, फिर मुझे मरना नहीं है, मुझे तो मारना है इस तरह

[310] कृष्णानन्द शुक्ल, ''शांति, सुरक्षा और विकास की समस्यायें'', 2009, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, पृष्ठ संख्या – 129

[311] वही, पृ.सं. – 129

मैं बहाबलफर में लश्कर की वानी यूनिट के शिविर में आ गया और अपने माँ–बाप भाई–बहनों को छोड़कर आजाद कश्मीर की पहाड़ियों में भाग आया जहाँ मुझे मुजफ्रफराबाद के पास की पहाड़ियों में तीन माह की सख्त ट्रेनिंग दी गई मुझे वहाँ वायरलेस पर बात करना, रॉकेट लॉन्चर चलाना, ए.के.47 रायफल्स चलाना, हथगोले फेंकने आदि का प्रशिक्षण दिया गया।''[312] हम सितम्बर 2000 में भारत में घुसे घने जंगलों, ऊट्टची पहाड़ियों में अपना अड्डा बनाया। हमारा दस्ता 6 फिदायीनों का था जिनमें मेरी उम्र सबसे कम थी। जनवरी 2002 में हम बारामूला शहर में आए यहाँ हम किसी भी घर में 48 घण्टे से ज्यादा नहीं रूकते थे। हमें आर्थिक सहायता आई.एस.आई. अथवा लश्कर के आदमियों से प्राप्त होती थी। 22 जून 2002 को मैं जब बारामूला के नूरबाग में था तब भारतीय सुरक्षा बल के सैनिकों ने मुझे देखा तो पहले तो मैंने भागने की कोशिश की और सोचा कि हथगोला फेंक दूट्ट किन्तु यह करने से पहले ही भारतीय सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया। यहाँ सब देखने के बाद मैं यह कहूँगा कि पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में जो कुछ सिखाया गया और बताया गया था वह सब झूठ था। भारत–विरोधी बातें बेमानी थीं, आई.एस.आई. के द्वारा हमारे मन में ढ़ेर सारा जहर भरा गया था। लेकिन मैंने यहाँ अब देखा कि यहाँ कोई जुल्मों सितम नहीं है जैसा कि मुजफ्रफराबाद में मेरे प्रशिक्षकों ने या बहाबलफर में हमारे नेताओं ने बताया था। मैं दुष्प्रचार में बहक गया था जिसका मुझे अफसोस रहेगा।

इसी तरह मुहम्मद इरफान भारतीय सेना को भारी नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से भारतीय सीमा में घुसा था उसके साथ के सभी 6 फिदायीन साथी भारतीय सेना की गोलियों से मारे गए तथा उसे भारतीय सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया तथा उसे श्रीनगर की बादामी बाग की छावनी में कैदी बना के रखा गया है उसने बताया कि उसने आठवीं जमात की पढ़ाई करने के बाद कई बार लश्कर–ए–तैयबा की बैठकों से समय गुजारा है। इन बैठकों में तकरीर करने वालों का एक ही मकसद होता है भारतीयों के खिलाफ बोलना इन बैठकों में लोग खिंचे चले जाते हैं पाकिस्तान की फौज में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह किसी को भारत के प्रति जहर उगलने से रोक सके। मुशर्रफ ने ऐसी बैठकों पर रोक लगाने की कोशिश की थी किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। मैं कश्मीर के लोगों पर भारतीय फौज की ज्यादतियों और जुल्मों के बारे में सुनता रहता था। जिससे मैं भी लश्कर–ए –तैयबा में शामिल हो गया हालाँकि मेरे परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया। अभी लश्कर–ए–तैयबा में मुझे और ट्रेनिंग पाए सात अन्य फिदायीन को फंछ के पास, सरहद पर छोड़ दिया था। जहाँ पर जीप पर आए सूबेदार कासिम ने हमें एक–एक ए.के. 47 रायफल, दो–दो हथगोले और चार–चार मैगजीनें दी, ग्रुप लीडर को स्निपर राइफल दी। मैंने सुना तो था कि इन संगठनों को पैसा आई.एस.आई की तरफ से मिलता है लेकिन तब यह सच

---

[312] वही, पृ.सं. – 129

साबित हो गया जब हम सभी को बीस–बीस हजार रूपये दिए गए लेकिन बाद में उन्हें वापिस ले लिया गया और हमसे कहा गया कि इतना पैसा लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है यदि हुई, तो ग्रुप लीडर खर्च करेगा। पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर में हमें ट्रेनिंग के समय बताया गया था हमें जाली भारतीय नोट दिए जाएँगे ये सभी नोट वहीं छपे होंगे जहाँ पाकिस्तानी करेन्सी छपती है। भारतीय सीमा पर हमें जो भारतीय नोट दिए गए थे वे जाली थे। हमें सितम्बर 2003 में पीर पंजाल के कठिन रास्ते पर होते हुए हरमिया पहुँचाया गया जहाँ हमें भारतीय फौज ने घेर लिया और मेरे 6 साथियों को मार गिराया मैं जख्मी होने के कारण भाग न सका अतः पकड़ा गया अब मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि लाहौर में कही जाने वाली हर बात किस कदर झूठी थी लेकिन वे मेरे जैसे नौजवानों को गुमराह करके भेजते रहेंगे। मुहम्मद इरफान की जाली नोटों की बात सही प्रतीत होती है। भारत की अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए पाकिस्तान अपने आई.एस. आई. एजेन्टों और आतंकवादियों द्वारा भारी मात्रा में जाली नोट भारत में भेजे रहा है इसका भंडाफोड़ 23 मई 2000 को जाली नोटों के साथ दाऊद गिरोह के चार सदस्यों की गिरफ्तारी से हुआ। आई.एस.आई. ने दाऊद गिरोह के माध्यम से जाली नोटों की एक बड़ी खेप भारत भेजी जिस में से चार लाख दस हजार रूपये पुलिस ने बरामद कर लिए थे। 28 जुलाई 2000 को मुम्बई की पुलिस ने जाली नोटों को तस्करी में लिप्त पाँच लोगों को गिरफ्तार किया इनके पास से एक करोड़ बाईस लाख रूपये बरामद हुए जो पाँच–पाँच सौ के जाली नोट थे। इस तरह पाकिस्तान हर सम्भव प्रयास से भारत की आर्थिक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है।

जिहाद के इस स्वरूप को भी पहचानने का प्रयास करें। टी.पी.हयूज द्वारा लिखित **डिक्शनरी ऑफ इस्लाम** के अनुसार, जिहाद दो प्रकार का होता है, **प्रथम – 'जिहादुल अकबर'** अर्थात् बड़ा धर्म युद्ध जो अपनी वासनाओं व कामेच्छा के विरूद्ध लड़ा जाता है और **दूसरा – 'जिहादुल असगर'** यानि छोटा धर्म युद्ध जो गैर मुसलमानों के विरूद्ध लड़ा जाता है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि हदीसों व कुरान में पहले वाले धर्म युद्ध 'जिहादुल अकबर' का कहीं कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। इन इस्लामी धर्म ग्रन्थों में प्रतिरक्षात्मक धर्म युद्ध जैसी भी कोई बात नहीं है। बुरहानुद्दीन अली के भाष्य 'हिदाया' के आधार पर, जैसा स्वयं टी.पी.हयूज कहते हैं कि बाद वाला धर्म युद्ध 'जिहादुल असगर' कयामत के दिन तक चलने वाला स्थाई युद्ध है।

इस्लामी शब्द कोष के आधार पर जिहाद शब्द का अर्थ है – ''उन लोगों के साथ धर्म युद्ध करना जो मुहम्मद के उद्देश्य में विश्वास नहीं रखते। कुरान और हदीसों द्वारा स्थापित, दैवीय नियमों के रूप में प्रस्थापित और

विशेषकर इस्लाम के विस्तार के लिए आदेशित जिहाद एक अनिवार्य धार्मिक कृत्य हैं।''[313] **इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि –**

1. ''पाकिस्तानी शासकों/तानाशाहों ने पाकिस्तान को एक इस्लामिक मशीनरी बना दिया है, जहाँ जिहादी तैयार किए जाते हैं।''[314]
2. पाकिस्तान की सेना व वहाँ मुजाहिद तैयार करने वाले संगठन सरकारी नियन्त्रण में है। सरकार उनकी हर सम्भव सहायता करती है तथा आवश्यकतानुसार उनका योजनाब(रूप से प्रयोग भी करती हैं।
3. जिहाद का लक्ष्य गैर मुस्लिमों को आतंकी गतिविधियों से प्रभावित कर विश्व में बलात् इस्लाम की सत्ता स्थापित करना है।
4. जिहाद सम्पूर्ण युद्ध का द्योतक है।
5. आतंक जिहाद का मुख्य अस्त्रा हैं।
6. ''जिहाद के प्रसार व प्रशिक्षण में मदरसों की विशेष भूमिका होती है। अतः मदरसों के प्रसार को जिहाद के आगमन की आहट माना जा सकता है।''[315] भारत–नेपाल सीमा तथा बांग्लादेश–भारत सीमा के दोनों ओर आई.एस.आई. के इशारे पर मदरसों की बढ़ती संख्या भारतीय सुरक्षा के लिए खतरे की घण्टी हैं।
7. पाकिस्तान के साथ की गई कूटनीतिक संधियों को कभी तो तोड़ा जा सकता है।
8. पाकिस्तानी जिहादी बिना किसी कारण के भी भारतवर्ष के लिए सदैव आतंकी माहौल पैदा करते रहेंगे। अतः पाक के साथ स्थायी सन्धि करके स्थायी शान्ति की आशा नहीं की जानी चाहिए। वे भारत के लिए सदैव असुरक्षा का माहौल बनाए रखने का प्रयास करते रहेंगे।

कुरान शरीफ में जिसे जिहादे अकबर यानि बड़ा जिहाद कहा है। वह तो अपनी इन्द्रियों पर विजय पाना है और जिसे जिहादे असगर कहा है। वह विधर्मियों से युद्ध करना। यह छोटा जिहाद है। दो प्रकार का जिहाद होता है। आतंकवादियों को बड़े जिहाद (जिहादे अकबर) पर भी ध्यान देना चाहिए न कि केवल छोटे जिहाद (जिहादे असगर) पर।

''अक्सर आतंकवाद और जिहाद का एक ही मतलब लगाया जाता है, इन्हें एक–दूसरे का पर्याय समझा जाता है। सच देखा जाए तो जिहाद का अर्थ

---

[313] डॉ. ए.पी.शुक्ल, डॉ. राहुल मिश्र, ''राष्ट्रीय सुरक्षा की समसामयिक समस्यायें'', 2006, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, फोन 9350551515, 011–23254306, पृष्ठ संख्या – 238

[314] वही, पृ.सं. – 241

[315] वही, पृ.सं. – 242

धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध है।''[316] यह आह्वान उन लोगों के खिलाफ था, जो मुहम्मद साहब को अपनी इच्छा के मुताबिक जीने, विश्वास करने और प्रार्थना करने से वंचित कर रहे थे और अब गैर मुस्लिमों को जिहादी फिरकापरस्त कहते है। वे इस्लाम के नाम पर तबाही मचा देने वाले हमले करते है। ''आज पाकिस्तान की इंटर सर्विसेस इंटेलिजेन्स (ॉ) और तालिबान की ओर से अफगानिस्तान में यह उद्योग शुरू है। शुरू में इन्हें अमेरिका से धन मिला, हथियार मिले, कई स्त्रोतों से धन इकठ्ठा किया गया। साथ ही मादक द्रव्यों के व्यापार से अनुमानतः 5 से 9 अरब डॉलर की मदद मिली।''[317] इसमें कोई शक नहीं की आज का जिहाद किसी भी राष्ट्र की सम्प्रभुता के खिलाफ है। समस्या तो तब खड़ी होती है जब जिहाद के नाम पर गुटबाजी बढ़ जाती है। सभी जिहाद की व्याख्या अपने ढ़ंग से करने लगते है।

मजहबी उन्माद की पराकाष्ठा[318]

आज पाकिस्तान की स्थिति यह है कि शायद ही कोई दिन ऐसा निकलता हो जब वहाँ के किसी नगर में मानव बम का विस्फोट न होता हो और कितने ही लोग मौत के मुख में न जाते हों। **ऐसे मानव बमों को फिदायीन कहा जाता है।** अपने आपको किसी उद्देश्य के लिये न्यौछावर कर देने वाला व्यक्ति फिदायीन है। अपने आपको बम बनाकर अपने निश्चित किये गये निशाने को उड़ा देने के साथ ही अपने को भी मृत्यु के मुँह में धकेल देने का काम कोई भयंकर रूप से उद्देश्य–प्रेरित व्यक्ति ही कर सकता है।

दो–ढ़ाई दशक पहले इस प्रकार की प्रवृत्ति श्रीलंका के तमिल चीतों में दिखाई दी थी। श्रीलंका के सुरक्षा बलों से लड़ते समय जब वे संकट की स्थिति में पड़ जाते थे तो सायनाइड का कैप्सूल खाकर वे आत्महत्या कर लेते थे। फिर उनमें मानव बम बनने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। अपने निशाने के पास पहुँचकर अपने शरीर पर बद्द्धे हुए बम का बटन दबा कर वे स्वयं भी उड़ जाते थे और अपने निशाने को भी उड़ा देते थे। **21 मई 1991 में जब राजीव गाँधी अपनी चुनावी यात्रा में श्री पेरूमबदूर पहुँचे थे तो एक तमिल महिला अपने शरीर में बम बाँधकर किसी प्रकार उनके पास पहुँच गई थी। उसने अपने आपको उड़ा दिया था, साथ ही राजीव गाँधी की हत्या कर दी थी।** इस समय तालिबानी आतंकवादियों ने इस प्रवृत्ति को पूरी तरह अपना लिया है।

प्रत्येक मानव बम धार्मिक या जातीय कट्टरता से प्रेरित होता है। सामान्यतः उसके सम्मुख एक निशाना होता है। यह भी देखा गया है कि ऐसे लोगों की आतंकवादी गतिविधियों का कोई पूर्व इतिहास नहीं होता। ऐसे लोगों

---

[316] डॉ.वी.एन.अरोरा, डॉ. नन्द किशोर, डॉ. अभय कुमार सिंह, ''दक्षिण एशिया में सुरक्षा चुनौतियों के नये आयाम'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, दूरभाष 011–23255141, पृष्ठ संख्या – 179

[317] वही, पृ.सं. – 179

[318] 3 दिसम्बर 2009, वीरवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 6

को या तो तमिल राष्ट्रवाद के नाम पर प्रेरित किया जाता रहा है अथवा इस्लामी हितों के नाम पर। जिहादी आतंकी पूरी तरह मजहबी परिवेश में प्रशिक्षित किये जाते हैं। वहाँ इन्हें बम बनाने, बमों को शरीर से बाँधकर संचालित करने, अपने निशाने तक पहुँचने और फिर उपयुक्त अवसर देखकर अपने शरीर में छिपे हुए बटन को दबाकर विस्फोट करने का कार्य सिखाया जाता है। जिहादी फिदायीन मजिस्दों में जाकर भाषण देते हैं, मजहबपरस्त लोगों के सम्मुख अत्यन्त उत्तेजक ढ़ंग से यह बताया जाता है कि किस प्रकार पश्चिमी देश इस्लाम को नष्ट करने पर उतारू है।

पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में फिदायीन कश्मीर के प्रश्न पर प्रेरित किये जाते हैं। **फिदायीन को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के तीन प्रकार हैं। एक है दौरा–ए–आम। इसमें 21 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरे प्रकार को दौरा–ए–खास कहते हैं। इसकी प्रशिक्षण अवधि 2–3 महीने होती है। तीसरे प्रकार में विशेषता से भरी शिक्षा दी जाती है, जिसकी अवधि अलग–अलग होती है।** इसमें बम बनाने और चलाने और विस्फोटकों का इस्तेमाल करने की विशेष शिक्षा दी जाती है। सभी मुजाहिदीन और जिहादी फिदायीन नहीं बनते हैं। प्रशिक्षण के समय उन नवयुवकों पर विशेष दृष्टि रखी जाती है जिनमें फिदायीन बनने की खास संभावना होती है। इनके सम्मुख शत्रुपक्ष द्वारा किये जाने वाले कथित अन्याय का मार्मिक चित्रा प्रस्तुत किया जाता है और यह भावना भरी जाती है कि उनके मजहब के साथ बेहिसाब भेदभाव किया जाता है। गत वर्ष जिन आतंकवादियों ने **मुम्बई पर आक्रमण किया था वे सभी फिदायीन थे।** उन्हें पता था कि जो कार्य वे करने जा रहे हैं उसमें अन्त में उनका मरना निश्चित है। फिदायिनों के सम्मुख मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली **'जन्नत'** का बड़ा लुभावना चित्रा रखा जाता है। उस आक्रमण के समय एकमात्र जीवित पकड़े गये आतंकवादी अजमल कसाब ने पुलिस को यह बताया है कि उसे प्रेरित करने वाले लोगों ने उससे यह कहा था कि मरने के बाद तुम्हें जन्नत मिलेगी।

फिदायीन बनने वाले ज्यादातर लोग अधिक पढ़े–लिखे नहीं होते, न ही बौद्धिक दृष्टि से तेज होते हैं। ऐसे लोगों में मजहबी उन्माद भरना अपेक्षाकृत सरल होता है। इनकी आर्थिक पृष्ठभूमि भी अच्छी नहीं होती। इन्हें यह भरोसा दिया जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार की भली प्रकार से देखभाल की जायेगी। यह भी देखा गया है कि कुछ परिवारों के लोग अपने किसी सदस्य को फिदायीन बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके पीछे एक उद्देश्य यह होता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात जिहादी संगठनों द्वारा निश्चित रूप से उन्हें आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। दूसरा अधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि फिदायीन स्वयं तो जन्नत में जायेगा ही, उसके परिवार की भी वहाँ जगह सुरक्षित हो जायेगी। यह भी सच है कि ऐसे जेहादियों और फिदायिनों को अपने जीवनकाल में अपनी गुजर–बसर के लिये जितनी रकम मिलती है, अन्य किसी साधन से उतना कमा सकने की उनमें क्षमता नहीं होती। भारत में आने वाले

अधिसंख्य फिदायीन पाकिस्तानी होते हैं। भारत के लिये ये लोग खूँखार आतंकवादी हैं, किन्तु पाकिस्तान के **पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ** उन्हें कश्मीर की आजादी के लिये लड़ने वाले **'मुजाहिदीन'** कहते थे और उनकी पीठ थपथपाते थे।

मध्ययुग में भी ऐसी प्रवृत्तियाँ थी। जब शत्रु से सीधा युद्ध करना संभव नहीं होता था तो गुरिल्ला युद्ध–पद्धति अपनाई जाती थी। मुगल शासन से लड़ने के लिये लम्बे समय तक शिवाजी ने इसी पद्धति से काम लिया था। 18वीं सदी में पंजाब में सिखों के जत्थे भी मुगलों–अफगानों से लड़ने के लिये इसी पद्धति को अपनाते थे। फिदायीन सामान्यतः ऐसा नहीं करते। वे तो मरने के लिये तैयार होकर आते हैं। **इस्लामी आतंकवाद के पीछे मजहबी उन्माद काम करता है।** संसार के किसी भी भाग में घटित ऐसी कोई भी बात जो ऐसे उन्माद को उत्प्रेरित कर सकती है, आतंकवाद के लिये ज्वलनशील ईंधन का काम कर सकती है। फिदायीन बनने की प्रवृत्ति यदि एक समुदाय में बढ़ेगी तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अन्य समुदायों में भी ऐसी प्रवृत्ति उभरेगी। उस समय मानव समाज की स्थिति कैसी हो जायेगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

आत्मघाती–हमलों के लिए अलकायदा महिला ब्रिगेड तैयार[319]

अलकायदा पश्चिमी देशों पर हमले के लिये यमन में ऐसी महिलाओं को आत्मघाती–हमलों का प्रशिक्षण दे रहा है, जो दिखने में गैर–अरबी लगती है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह चेतावनी देते हुए कहा कि इन्हें विमानों और ऊर्जा संयंत्रों पर हमले के लिये तैयार किया जा रहा है।

लश्कर के निशाने पर पूरा विश्व : अमेरिका[320]

ओबामा प्रशासन के एक वरिष्ठ आतंकनिरोधी अधिकारी का कहना है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर–ए–तैयबा की वैश्विक महत्त्वाकांक्षायें है और वह पूरे विश्व में आतंक फैलाकर लोगों के मन में खौफ पैदा करना चाहता है। विदेश मंत्रालय के आतंकनिरोधी संयोजक कार्यालय के संयोजक **डेनियल बेंजामिन ने कहा**, ''डेविड हेडली का उदाहरण बताता है कि केवल अलकायदा ही ऐसा संगठन नहीं है, जिसकी वैश्विक महत्त्वाकांक्षा हो।''

बल्कि लश्कर–ए–तैयबा भी पूरी दुनिया में दहशत फैलाना चाहता है। **बेंजामिन ने कहा**, ''लश्कर के इरादों से साफ पता लगता है कि वह बड़े–बड़े कारनामे करके अलकायदा को खुश करना चाहता है।'' पाकिस्तान स्थित लश्कर के सरगनाओं के इशारे पर ही हेडली ने मुम्बई हमलों के अलावा देश के अन्य ठिकानों का भी जायजा लिया था। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक काटो इंस्टीटयूट को संबोधित करते हुए **बेंजामिन ने कहा**, ''बांग्लादेश में अमेरिकी दूतावास को उड़ाने की संगठन की विफल साजिश ने इन चिंताओं को बढ़ा दिया है कि

---

[319] 25 जनवरी 2010, सोमवार, दैनिक भास्कर, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 12

[320] 17 जनवरी 2010, रविवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 7

लश्कर एक वैश्विक आतंकी चुनौती बनकर उभर सकता है। लश्कर–ए–तैयबा की ताकत और लक्ष्य मुझे चिंता में डालती है। हम क्षेत्र के सहयोगियों के साथ इस खतरनाक संगठन की चुनौती को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।''

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का नया स्वरूप

विज्ञान व तकनीक में हो रही क्रांति के परिणामस्वरूप विश्व में सक्रिय विभिन्न आतंकवादी संगठनों के मध्य स्थापित सम्पर्कों से आतंकवाद की अन्तर्राष्ट्रीयकरण प्रक्रिया व तीव्रता को नया आयाम मिल रहा है। मध्यपूर्व क्षेत्र में फिलीस्तीन मुक्ति संगठन (P.L.O.) के उदय, प्रशिक्षण, शरण व धन–आपूर्ति हेतु विस्तृत इसके नेटवर्क और 1967 में अरब–इजरायल संघर्ष में अरब राष्ट्रों की इजरायल के हाथों हुई पराजय ने आतंकवादी गतिविधियों में उत्प्रेरक का कार्य किया। ज्ञातव्य है कि पी.एल.ओ. को अरब राष्ट्रों से मिली आर्थिक सहायता एवं विश्व के अन्य आतंकवादी संगठनों से स्थापित इसके संबंधों के कारण धीरे–धीरे यह विश्व का सर्वाधिक प्रभावी व खतरनाक आतंकवादी संगठन बन गया। वैचारिक धरातल पर उपनिवेशवाद, पूट्टजीवाद व अन्तर्राष्ट्रीय यहूदीवाद के षविरुद्ध विश्व के विभिन्न आतंकवादी समूहों ने परस्पर सम्पर्क स्थापित करके इस संगठन ने क्रांति का नारा दिया। धर्म के नाम पर विश्व में उभर रहे विभिन्न इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा **'जिहाद'** के नाम पर प्रारम्भ की गयी आतंकवादी गतिविधियों ने अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को अत्यन्त जटिल व अस्थिर कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इस्लाम के नाम पर आतंकवाद की शुरूआत सन् 1980 में अफगानिस्तान में सोवियत–हस्तक्षेप के उपरान्त वहाँ के **'तथाकथित मुजाहिदीनों'** द्वारा की गयी थी जिन्हें अमेरिका व पाकिस्तान का प्रत्यक्ष समर्थन हासिल था। अफगान–संकट के दौरान ब्प्प्।प् ने पाक–अफगान सीमा पर कई सैन्य–प्रशिक्षण शिविर स्थापित कर वहाँ आतंकवादियों को सुप्रशिक्षित किया था जो आज कश्मीर, चेचेन्या, तजाकिस्तान, उज्जबेकिस्तान व तुर्कमेनिस्तान आदि जगहों पर तथाकथित **'जिहाद'** चला रहे हैं। बोस्निया, मिश्र, अल्जीरिया व चीन के सीक्यांग क्षेत्र में भी इनकी गतिविधियाँ धीरे–धीरे बढ़ती जा रही हैं जो विश्व के अधिकांश मुस्लिम देशों को अपनी चपेट में ले रही हैं।

ईरान की क्रांति ने इस्लामी–आतंकवाद को नये सिरे से तो बढ़ावा दिया ही साथ ही सोवियत संघ से लड़ने हेतु अफगानों को दिये गये हथियार भी अफगान–गृहयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् इस्लामिक आतंकवादियों के हाथ में आने एवं प्ैप्छ – तालिबान – अलकायदा अन्तर्बन्धन से आतंकवाद को नया आयाम मिला। उल्लेखनीय है कि वियतनाम में हुई अपनी पराजय का बदला लेने का सुअवसर पाकर अफगानिस्तान में फंसे सोवियत संघ के 'विरुद्ध (सन् 1979–88) पाकिस्तान को अपना 'अग्रिम–आधार' बनाकर प्ैप्छ के माध्यम से मुस्लिम देशों के मुजाहिदीनों को सैन्य–प्रशिक्षण व हथियार मुहाया कराकर अमेरिका ने अन्ततः अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों को 1992 में सत्तारूढ़ तो करा दिया किन्तु बाद में इस क्षेत्र की भू–आर्थिकी व तेल–राजनीति को ध्यान में रखकर उसने मुजाहिदीनों

को सत्ताच्युत कराकर 1996 में तालिबान को काबुल की सत्ता सौंप दी। यद्यपि मुल्ला मोहम्मद उमर के नेतृत्व में अफगानिस्तान में स्थापित तालिबान–सत्ता को पाकिस्तान का प्रत्यक्ष समर्थन हासिल था। तथापि तालिबान के जन्म, विकास व पोषण से वह सदैव इन्कार करता रहा किन्तु अगस्त 1998 में नैरोबी व दारस्सलाम के अमेरिकी दूतावासों पर हुए आतंकवादी हमलों के प्रत्युत्तर में अफगानिस्तान स्थित खोस्त के अलकायदा कैम्प पर जब अमेरिका ने मिसाइल आक्रमण किया तब इन शिविरों में मारे गये आतंकवादियों से यह फष्टि हुई कि यहाँ के प्रशिक्षित पाक आतंकवादी ही अफगानिस्तान व कश्मीर में सक्रिय हैं। इन गतिविधियों से यह स्पष्ट है कि **ओसामा बिन लादेन (2 मई 2011 को मारा गया) के संगठन 'अलकायदा'** के विस्तार व तालिबान से मिले प्रत्यक्ष समर्थन से मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, कश्मीर व चेचेन्या आदि में अपनी सक्रियता बढ़ाकर उसे अपनी जड़े जमाने का अवसर मिला। जहाँ तक बिन लादेन का प्रश्न है, मूलतः सउदी अरब निवासी तथा **'किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी, जेद्दा' के 'अर्थशास्त्रा व प्रबन्धन' के स्नातक,** ने सन् 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप को इस्लामी–उसूलों के षविरुद्ध मानकर जेहादियों की भर्ती के लिये **मकतब–अल–खिदमत (मुजाहिदीन सेवा केन्द्र)** की स्थापना की। दो वर्षों की अल्पावधि में उसने हजारों मुजाहिदीनों की भर्ती करने के साथ–साथ इंग्लैण्ड व अमेरिका सहित विश्व के लगभग 50 देशों में भर्ती केन्द्र स्थापित कर लिया। पेशावर को इन गतिविधियों का केन्द्र बनाकर लादेन ने विश्व के समस्त मुस्लिम कट्टरपंथियों के मध्य समन्वय कायम करने हेतु **'इण्टरनेशनल जिहाद ऑर्गेनाइजेशन'** की स्थापना की। **सन् 1985 में उसने 'इस्लामिक साल्वेशन–प्रफण्ड' (अलकायदा)** की स्थापना की तथा सन् 1994 तक लादेन ने सूडान, लीबिया, सोमालिया, इराक, मिश्र, यमन, तुर्की, सउदी अरब व अन्य कई पश्चिमी देशों में इस्लामी आतंकवादियों की संख्या बढ़ाकर उनके बीच सम्पर्क भी स्थापित कर लिया और सउदी अरब की अमेरिकी–परस्त नीति से खिन्न होने के कारण वह अमेरिका के लिये चुनौती बन गया। **11 सितम्बर 2001 को अमेरिका के 'वर्ल्ड ट्रेड सेण्टर'** पर अलकायदा के फिदायीन आक्रमण से हतप्रभ अमेरिका को अन्ततः आतंकवाद की त्रासदी का अहसास हुआ।

वस्तुतः अलकायदा के आत्मघाती आतंकवादियों के द्वारा पेंटागन व वर्ल्ड ट्रेड सेण्टर (आर्थिक आतंकवाद का केन्द्र) पर किये गये अप्रत्याशित हमले से न केवल अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की बढ़ रही दुस्साहसी प्रवृत्ति उजागर हुई अपितु यह भी स्पष्ट हो गया कि यदि कहीं आतंकवादियों ने अगले चरण में नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल करने की रणनीति अपनाई, जिसकी संभावनायें निरन्तर बढ़ रही हैं, तो 21वीं शताब्दी में तृतीय विश्वयुद्ध को रोक पाना दुष्कर होगा। अमेरिका पर हुए इस हमले से वहाँ अपार जन–धन की बर्बादी तो हुई ही साथ ही उसकी अपराजेय व चक्रवर्ती–राष्ट्र भावना को चोट पहुँची है जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के षविरुद्ध व्यापक स्तर पर अभियान छेड़ने की उसकी

सक्रियता विश्व शांति व व्यवस्था को नई दिशा प्रदान करेगी। विगत दो दशकों (पहले पंजाब और अब कश्मीर में) से आतंकवाद का दंश झेल रहे भारत के लिये अमेरिकी–घोषणा सर्वाधिक राहत देने वाला विषय है क्योंकि दक्षिण एशिया के केन्द्र में स्थित अपनी महत्त्वपूर्ण भू–सामरिक विशिष्टता के कारण जहाँ एक ओर इस क्षेत्र में रूस, चीन और अमेरिकी स्पर्धा इसे अस्थिर व अशान्त कर रही हैं वहीं नाभिकीय–ताप से प्रभावित इस क्षेत्र में भारत के विरूद्ध पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित–आतंकवाद भारतीय सुरक्षा व अखण्डता के समक्ष नित नयी चुनौतियाँ पेश कर रहा है। अफगानिस्तान व पाकिस्तान के मध्य स्थापित सामरिक सम्बन्धों से इस सम्पूर्ण क्षेत्र में आतंकवाद का जो घिनौना स्वरूप सामने आया उस पर भारत द्वारा बराबर (संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट निरपेक्ष आन्दोलन व राष्ट्र मण्डल सम्मेलनों के माध्यम से) विश्व का ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद बेखबर अमेरिका को आतंकवाद के दुष्प्रभाव एवं मानसिक पक्षाघात का आघात पहली बार सही ढ़ंग से हुआ है।

अफगानिस्तान में पनप रहे जिहादी तत्त्वों की चिन्ता अमेरिका को उस समय हुई जब ओसामा बिन लादेन को वहाँ शरण दे दी गई तथा अमेरिका लादेन प्रेरित आतंकवाद का लक्ष्य बन गया। अपने आन्तरिक मामलों में उलझे रूस की भी आँखें उसी समय खुलीं जब उसे चेचेन्या में तालिबान प्रेरित जिहाद का स्पष्ट चेहरा दिखाई पड़ा। अलकायदा के आत्मघाती आक्रमण से हतप्रभ अमेरिका का तालिबान–प्रेम न केवल चकनाचूर हो गया अपितु उसने आक्रामक पहल कर अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के उन्मूलन का संकल्प लेकर घोषणा की कि, ''वह आतंकवादियों या उनको शरण देने वालों अथवा किसी भी प्रकार से उनका सहयोग करने वालों को भी निशाना बना सकता है।

विश्व जनमत की अनदेखी कर व्यापक जनसंहारक रासायनिक व जैविक शस्त्रों ॅडक) के नाम पर इराक पर ढ़ाया गया अमेरिकी कहर उसकी निरंकुशता का ज्वलन्त प्रमाण है। अपने प्रच्छन्न हितों और आतंकवाद के उन्मूलन की आड़ में अमेरिकी हठधर्मिता ने यू.एन.ओ. की गरिमा को हासिये पर लाकर एशिया में पैर पसारने शुरू कर दिये। पहले अफगानिस्तान, फिर इराक में अपनी मनमानी करने के बाद अमेरिका जिस तरह सीरिया, ईरान व उत्तरी कोरिया को धमकी देने के साथ–साथ, कश्मीर, भारत–पाक तनाव और दक्षिणी एशिया की सुरक्षा पर ध्यान देने जैसी दो मुँह ी बातें कर रहा है उससे उसकी नीयत और चक्रवर्ती–भूमिका सन्देह के घेरे में आ गयी है। हैती, लेबनान, वियतनाम, ईरान, लीबिया, पनामा, अफगानिस्तान, सूडान और खाड़ी युद्धों (प्रथम व द्वितीय) के बहाने अमेरिका ने अनेक देशों को अपना निशाना बनाकर यह संकेत दिया है कि उसके नीति निर्धारकों ने सम्भावित खतरों का नये सिरे से आंकलन प्रारम्भ कर दिया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा ऐसे देशों से होगा जो पारम्परिक सैन्य क्षमता में अमेरिकी तुलना में पर्याप्त दुर्बल होते हुए भी परमाणु एवं रासायनिक हथियारों के बलबूते पर अमेरिकी हितों को आघात पहुँचाने का साहस

कर सकते हैं। अतः देर सबेर कुछ देशों को अमेरिकी सेना से सीधा लोहा लेने को विवश होना पड़ सकता है तो कुछ को अमेरिका की आर्थिक नाकेबन्दी और कुछ को राजनीतिक–घेरेबन्दी से जूझना पड़ेगा जिसमें उक्त देशों के अलावा तुर्की, मिश्र, लेबनान, पाकिस्तान, भारत, प्रफांस, जर्मनी व रूस आदि भी शामिल हैं। अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और तेल राजनीति को कारगर बनाने के लिये उसने इराक के फनर्निर्माण में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभावी भूमिका के साथ–साथ प्रफांस, जर्मनी, रूस व चीन आदि के योगदान को रोकने के प्रयास प्रारम्भ कर दिये हैं। इराक में लोकतंत्र की स्थापना की आड़ में उसके पड़ोसी राष्ट्रों पर कड़ी निगरानी रखते हुए अन्तरिम पिट्ठू सरकार से अमेरिकी कम्पनियों को अधिकाधिक लाभ पहुँचाने तथा पश्चिमी तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर, अफगानिस्तान होते हुए कराची बन्दरगाह तक प्रस्तावित 'तेल पाइप लाईन' को साकार रूप देने के लिये अमेरिका कोई भी घटिया हरकत एवं कुटिल पैंतरेबाजी कर सकता है जो अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय देने के साथ–साथ विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिये भी अहितकारी होगा।

''आतंकवाद क्या है और इसका स्वरूप कब और कैसे न्यायोचित रूप ले लेता है? कब, कहाँ भीषण जन, धन हानि का प्रतीक बन जाता है? इन प्रश्नों का उत्तर ढूँढ़ पाना निश्चित रूप से एक कठिन प्रयास होगा। क्योंकि आज विश्व का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ आतंकवाद ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो पूरी दुनिया की मीडिया में यदि कोई शब्द सबसे अधिक पढ़ने–सुनने को मिलता है तो वह है – आतंकवाद। ऐसा लगता है कि सोते–जागते, उठते–बैठते, हर समय, दुनिया भर के सत्ताधारियों को आतंकवाद का भूत सताता रहता है।''[321]

''आतंकवाद का सम्बन्ध भावना से है, क्योंकि एक जिसे आतंक मानता है, दूसरा उसे ही आजादी की लड़ाई के विरूद्ध संघर्ष और अस्तित्व की रक्षा के लिये की गई कार्यवाही मानता है।''[322]

आतंकवाद बुद्धि के दुरुपयोग का परिणाम तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी के अभिशाप का एक भयंकर उदाहरण है। वर्तमान परिवेश में आतंकवाद का स्वरूप अत्यन्त व्यापक व परिवर्तित हो गया है और ऐसा नई तकनीकों के आने के कारण हुआ है। संचार के ऐसे साधन विकसित हो गये हैं, जिनसे आतंकवादी संगठन एक–दूसरे के साथ आसानी के साथ संवाद स्थापित कर लेते हैं और धन जुटाने से लेकर रणनीति निर्धारित करने तक आपस में बेहतर संवाद बना लेते हैं। संचार की नई तकनीकी और हिंसा के लिये नवीन हथियार सिर्फ सरकारों को ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि आतंकवादी संगठनों को भी मिल रहे हैं। अब

---

[321] आलोक रंजन, ''आतंकवाद के बारे में विभ्रम और यथार्थ'', आह्वान फस्तिका तीन, राहुल फाउण्डेशन, जून 2007, पृष्ठ संख्या –5।

[322] डॉ. बाबूराम पाण्डेय एवं डॉ. रामसूरत पाण्डेय, ''राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध'', प्रकाश बुक डिपो, बरेली, 2005, पृष्ठ संख्या – 106

आतंकवाद ऐसी बर्बरता, क्रूरता व विध्वंस के दर्शन में बदल गया है। जिसके कारण इसे शब्दों में परिभाषित करना कठिन हो गया है। सम्पूर्ण राष्ट्र की सामूहिक बुद्धि जिस ठिकाने को सुरक्षित समझती है, वहाँ भी अप्रत्याशित रूप में ये हमला करते हैं तथा आतंकवाद के शिकार राज्य स्वयं को शक्तिहीन और समर्थहीन पाते हैं। आज सम्पूर्ण विश्व में आतंकवाद का जो वातावरण दिखाई दे रहा है उसके प्रमुख कारणों में से एक हथियारों की अत्यधिक उपलब्धता है क्योंकि ''बड़े देशों ने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिये अपने द्वारा उत्पादित हथियारों को विकासशील देशों में मुक्त ह्रदय से निर्यात किया।''[323]

यदि विश्व मानचित्रा का अवलोकन करें तथा फिलीपींस से आरम्भ करके पश्चिम की ओर बढ़ते जाए तो हम पायेंगें कि विश्व में जहाँ कही भी हिंसक आतंकी संघर्ष चल रहे हैं उनमें से अधिकतम आतंकी संघर्ष ऐसे हैं, जिनमें मजहबपरस्ती का एक पक्ष अवश्य है। ये आतंकी संघर्ष कहीं ईसाइयों से हैं तो कहीं बौद्धों से, कहीं हिन्दुओं से, कहीं यहूदियों से, कहीं कम्युनिस्टों से हैं तो कहीं डॉलर धर्मी अमेरिकियों से। जहाँ कोई अन्य विपरीत मतावलम्बी नहीं है वहाँ ये मजहबपरस्त समुदाय आपस में ही एक–दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। साम्प्रदायिक आधार के अलावा क्षेत्रीय और राजनीतिक आधार पर भी पारस्परिक आतंकी संघर्षों की कमी नहीं है। कुर्दों और इराकियों में, इराकियों और ईरानियों में, अफगानों और पाकिस्तानियों के मध्य आतंकी संघर्ष का कोई न कोई स्वरूप विश्व में चलता ही रहता है किन्तु इसकी एक बहुत बड़ी और गम्भीर स्थिति यह है कि आतंकवाद की चपेट में आये नये–नये देश इस सन्दर्भ में सच बोलने का साहस नहीं करते क्योंकि वे इसकी व्याख्या अपने–अपने राष्ट्रीय हित के सन्दर्भ में करते हैं, फलतः किसी देश को पेट्रोल का भय है तो किसी को दंगा–फसाद का भय चिंतित किये हुए है। आतंकवाद से पीड़ित देशों की सम्पूर्ण आबादी इस मुद्दे पर या तो मौन है या आतंकवादियों को यथाशक्ति संरक्षण प्रदान करती है। ''दुनिया ने 1980 के दशक के आरम्भ में ही बसाक, तमिल, क्रोशियाई, अलगाववादियों के स्वरों में तेजी सुनी। भारत में सिक्ख अलगाववादियों की खालिस्तान की माँग ने जोर पकड़ा, कश्मीर को भारत से अलग करने की आतंकवादी कोशिशों में तेजी आयी।''[324] इस तेजी के साथ ही आतंकवादियों की कोशिशों में एक बड़ा बदलाव यह आया कि उन्होंने देशों की सीमायें तोड़ दी। पहले वे अपने राजनैतिक उद्देश्यों हेतु लड़ते थे और अपने दुश्मनों की घोषणा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। वे भाड़े पर भी लड़ने लगे तथा उनके लिये देश की सीमायें टूट गई।

वर्तमान परिवेश में आत्मघात के जरिये आतंकवाद फैलाना आतंकवाद की एक नई खौफनाक प्रवृत्ति है। दुनिया की बहुत सी दूसरी चीजों की तरह ही आतंकवाद का भी भूमण्डलीकरण हो गया है। अब आतंकवाद किसी एक देश

---

[323] दैनिक जागरण, 15 सितम्बर 2001, कानफर संस्करण, पृष्ठ संख्या – 18

[36] अमर उजाला, 1 फरवरी 2001, कानफर संस्करण, साप्ताहिकी परिशिष्ट

का प्रोडक्ट नहीं रहा। अब बहुराष्ट्रीय निगमों की तरह आतंकवाद का भी निगमीकरण हो गया है। एक देश आतंकवाद का उत्पादन करता है और दूसरा देश उसे सहने के लिये अभिशप्त रहता है। ''सन् 2001 से लेकर वर्तमान तक दुनिया को यह देखने को मिला कि आतंकवाद की अर्थव्यवस्था न केवल सुदृढ़ और सुव्यवस्थित है अपितु वह पूरी तरह से आधुनिक कॉर्पोरेट प्रबन्धन की विस्तार की तरह है।''[325]

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका हैं कि प्रारम्भ में अधिकांश आतंकवादी घटनाओं के पीछे कोई न कोई ऐतिहासिक या राजनैतिक कारण रहा है। इजरायल–फिलीस्तीन संघर्ष इसका अच्छा उदाहरण है। ''फिलीस्तीन संघर्ष दुनिया की आतंकी घटनाओं का एक महत्त्वपूर्ण मोड़ है। सैनिक आतंकवाद के बीज यहाँ दिखाई देते हैं। फिलीस्तीन संघर्ष की शुरुआत के अगले दशकों में जर्मनी, इटली सहित अन्य पश्चिमी देशों में आतंकवाद का दौर थमने लगा लेकिन अब दहशतगर्दी का केन्द्र मध्य–पूर्व एशिया बन गया और यहाँ इस्लामी कट्टरवाद ने आतंकवाद को एक नया चेहरा प्रदान किया। दरअसल 1979 की ईरानी क्रांति से इस्लामी कट्टरवाद को बेहद बढ़ावा मिला था। क्षेत्र में हुई कई इस्लामी क्रांतियों ने पश्चिम के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ 'जिहाद' की घोषणा कर दी। इससे एक तरह की आत्मघाती प्रवृत्ति भी पनपी। इसकी परिणति 1983 में लेबनान में हुई जब इस्लामी आतंकवादियों ने 'जिहाद' के नाम पर अमेरिका और प्रफांस के शांति सैनिक ठिकानों में आत्मघाती ट्रक बमों से विस्फोट किये। धीरे–धीरे मध्य–पूर्व के इस्लामी आतंकवाद ने अपने को धर्म से जोड़ लिया और अपनी दहशतगर्दी को 'जिहाद' का नाम दे दिया, वे 'जिहादी' कहलाने लगे।''[326]

''आतंकवाद का वैश्वीकरण होने का अनुभव 1972 में (म्यूनिख) ओलम्पिक में इजरायल के एथेलिटिक्स पर फिलीस्तीनी ब्लैक आतंकवादी गुट द्वारा आक्रमण किया जिसमें 11 एथलीट मारे गये थे।''[327] फिर भी विश्व समुदाय आतंकवाद पर एकजुट नहीं हो सके तथा वे उनके प्रति हमेशा की तरह उदासीन हो गये। क्योंकि आधुनिक समय में महाशक्ति देशों ने हमेशा इसे एक साधन के रूप में अपने हितों की पूर्ति के लिये प्रयोग किया। प्रश्न उठता है कि क्या केवल किसी कार्य को करवाने के लिए हिंसा का मार्ग चुनना ही आतंकवाद है। निश्चय ही इस प्रश्न का सीधा और सरल उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इसका उत्तर जानने से पूर्व आतंकवाद के कारणों, प्रकारों और इसे रोकने के उपायों पर

[325] हिन्दुस्तान, 17 मार्च 2005, लखनउफ संस्करण, पृष्ठ संख्या –16

[326] नरेन्द्र कुमार शर्मा, '' भारत में नक्सलवाद'', 2012, महेन्द्र बुक कम्पनी, 79/23, लक्ष्मी गार्डन, सत्य ज्योति स्कूल के पास, गुड़गाट्टव (हरियाणा)–122001, फोन 9811787417, पृष्ठ संख्या – 162

[327] डॉ. अजय कुमार – ''आतंकवाद : विश्व शांति के लिये चुनौती'', सम्पादक – संजय कुमार, गुलाब चन्द्र ललित, ''राष्ट्रीय सुरक्षा (मुद्दे और चुनौतियाट्ट)'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, असांरी रोड़, दरियागंज, नईदिल्ली–110002, पृष्ठ संख्या – 203

वस्तुनिष्ठ भाव से विचार करने की आवश्यकता है। अमेरिका की नजर में लीबिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान जैसे देश आतंकवाद को फैलाने और सुदृढ़ करने वाले है, जबकि अपने गलत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आतंक फैलाने वाले तत्त्वों को संरक्षण देना, उनके लिए हथियारों की व्यवस्था करना और दूसरे राष्ट्रों में अशांति फैलाने वाले पाकिस्तान जैसे राष्ट्र उसकी ही नजर में आतंकवादी नहीं हैं। स्वयं अमेरिका खुफिया एजेंसी, मानवाधिकार संगठनों व वहीं के जनप्रतिनिधियों द्वारा पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने के लिए अनेक बार माँग की जा चुकी है। बड़े राष्ट्रों का यह दोहरा चरित्र ही मूलतः आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह है कि दुनिया में लिट्टे से लेकर लश्कर–ए–तैयबा संगठन और सद्दाम हुसैन से लेकर ओसामा–बिन–लादेन जैसे व्यक्ति उन्हीं ताकतों के द्वारा पैदा किए और आगे बढ़ाये गये हैं, जिन्हें वे आज घृणा, तिरस्कार व बदला लेने की भावना से देखते हैं। ऐसी ही स्थिति पाकिस्तान के इशारे पर भारतीय कश्मीर में कार्यरत भाड़े के विदेशी आतंकवादियों की है, जिन्हें अफगानिस्तान से रूस को निकालने के उद्देश्य से अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के माध्यम से पोषित और प्रतिष्ठित किया गया था। यहाँ यह कहावत पूरी तरह से चरितार्थ होती है कि **'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होय'** अर्थात् **जैसा बोओंगे वैसा काटोंगे।**

आतंकवाद की समस्या को एक–दूसरे नजरिये से देखने की भी आवश्यकता है। अपने यहाँ परमाणु निषेध संधि को अनुमोदित नहीं कर सकने पर भी भारत जैसे शांतिप्रिय देश को इस संधि पर हस्ताक्षर के लिए मजबूर करना, सद्दाम हुसैन की तथाकथित गलतियों के लिए आर्थिक प्रतिबन्ध लगाकर निर्दोष बूढ़े, निशक्त व अवयस्क इराकियों को भूख, प्यास और बीमारी के माध्यम से मर जाने के लिए मजबूर करना, कश्मीर में हजारों निर्दोष लोगों को मारने वाले आतंकवादी संगठनों के पोषक पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित नहीं करना, लीबिया के कर्नल गद्दाफी के दोषों के लिए पूरे लीबिया को ही बर्बादी के रास्ते पर झोंक देना अमेरिका नाम के राष्ट्र का आतंकवाद नहीं तो क्या है? पाकिस्तान और भारत के परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र होने के बावजूद उन्हें इस श्रेणी में नहीं रखने की हठ लगाये रहना, इराक की सार्वभौमिकता को उसकी सीमा में हर प्रकार के हवाई जहाज उड़ाकर उल्लंघन करना, एक व्यक्ति को मारने के लिए अफगानिस्तान में आक्रमणों की झड़ी लगा देना और चीन की सीमा में जासूसी कार्यवाही करने के बावजूद उसको ही दोषी ठहराना एक राष्ट्र द्वारा की गई आतंकवादी कार्यवाही कैसे नहीं है? इसी प्रकार मानवाधिकारों और पर्यावरण के नाम पर विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों के विकास को पूरी तरह अवरू(कर देना एक प्रकार का आतंकवाद ही है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण में आज भी सर्वाधिक भूमिका अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी राष्ट्रों की है और उन्हीं के द्वारा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करने वाले राष्ट्रों को अधिकतम धमकाया जा रहा है।

व्यापक दृष्टिकोण से यदि विचार किया जाए तो आतंकवाद के मूल कारण हैं असहनीय शोषण, असामान्य भेदभाव, नस्ल की श्रेष्ठता की अवधारण, 'केवल मैं सही और सामने वाला गलत' की भावना, दर्दनाक गरीबी और अज्ञानता, धर्मांधता की अति और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अधिकांश के राजनैतिक अधिकारों का हनन एवं कुछ की व्यक्तिगत उच्चाकांक्षाएँ। इतिहास इस बात का गवाह है कि उपनिवेशवादी ताकतों ने अपने अधीन मानवों को किसी भी प्रकार जानवरों से अधिक नहीं समझा है। ऐसी ताकतों ने सम्पूर्ण एशिया, अप्रफीका और एक सीमा तक लैटिन अमेरिका के सैकड़ों देशों को अपनी गुलामी में जकड़कर सैकड़ों वर्षों तक रखा है। वहाँ की संस्कृति, सम्पूर्ण सम्पदा और मानवीय शक्ति का क्रूरतापूर्ण तरीके से दोहन किया गया है। **सोने की चिड़िया कहे जाने वाल भारत और हीरों के देश वाले** अप्रफीका महाद्वीप के निवासियों को इन शक्तियों ने गुलामों से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया है। आतंकवाद पर काबू पाने के लिए तो दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति, वस्तुनिष्ठ सोच, सामूहिक समन्वित प्रयास, समस्या के मूल तक पहुँचने की ललक, तर्क के आधार पर फैसला लेने के साहस जैसे तत्त्वों का होना आवश्यक है। चोट मूल कारण पर करनी है, उसके परिणामों पर नहीं।

जिहाद के नाम पर आतंकवाद[328]

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एक महत्त्वपूर्ण व सर्वाधिक अमानवीय प्रकार है – जिहाद यानि धर्मयुद्ध (Holy War) के नाम पर लोगों को दूसरे धर्मों, संस्कृतियों व मान्यताओं के षविरुद्ध भड़काना व हिंसा के लिए तैयार किया जाना। धर्म के नाम पर लोग कितने भावुक व उग्र हो जाते हैं, इसका जरा–सा अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 25 दिसम्बर, 2000 को श्रीनगर में भारतीय सेना की 15वीं कोर के हैडक्वाट्र्स पर जिस आत्मघाती हमले के परिणामस्वरूप 9 लोगों की जान गई और 20 से अधिक घायल हुए, उस आत्मघाती दस्ते का मुख्य लीडर एक 24 वर्षीय नौजवान मुहम्मद बिलाल था जो इंग्लैण्ड के बकिंघम नामक शहर से श्रीनगर आया था। गत वर्ष विमान अपहरण द्वारा मुक्त हुए अजहर मसूद द्वारा स्थापित जैश–ए–मुहम्मद नामक आतंकवादी संगठन के अखबार जर्ब–ए–मोमिन ने बड़े गर्व पूर्वक घोषणा की कि शहीद बिलाल ने भारतीय फौज के सदर अड्डे पर जाँबाज हमला करके तबाही मचायी। लन्दन स्थित एक मुस्लिम ग्रुप अल मुहाजिदान ने बड़े फक्र के साथ घोषणा की थी कि बकिंघम के एक मुस्लिम छात्र ने आत्मघाती बम विस्फोट करके मजहब के लिए कुर्बानी दी। इस ग्रुप के संस्थापक और ब्रिटेन में इस्लामी न्यायालय के जज शेख उमर बकरी मुहम्मद को गर्व है कि पिछले एक वर्ष में 1800 ब्रिटिश मुस्लिम नागरिकों ने विश्वव्यापी जिहाद में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जिहाद का लक्ष्य विश्व भर में इस्लामी व्यवस्था स्थापित करना है। इसके लिए हम किशोरावस्था के युवकों

---

[328] डॉ. मानचन्द खंडेला, ''अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद'', 2011, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, 807, व्यास बिल्डिंग, चौड़ा रास्ता, जयफर–302003 (राज.), पृष्ठ संख्या – 6–8

की ही भर्ती करते हैं, वैचारिक प्रशिक्षण देते हैं और जब वे इस्लाम की विचारधारा में पक्के हो जाते हैं तो उन्हें आतंकवादी कार्यविधि और शस्त्रासत्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है।

जिहाद की विचारधारा का शिकार भारतवर्ष अकेला नहीं है। यह एक वैश्विक विचारधारा है जिसका शिकार सभी गैर इस्लामी समाज हो रहे हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस, रूस, बोस्निया, कोसोवो, लेबनान आदि देशों में ईसाई समाज जिहाद का शिकार है तो फिलीस्तीन में पचास वर्षों से यहूदी मुस्लिम संघर्ष चल रहा है। कम्युनिस्ट चीन भी इससे मुक्त नहीं है। इसके सीक्यांग प्रदेश में मुस्लिम विद्रोह की चिंगारी सुलगती ही रहती है।

अब यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि इस्लामी विचारधारा राष्ट्रवाद के भौगोलिक आधार को स्वीकार नहीं करती। वह अन्य धर्मों को इस्लाम के साथ बराबरी का दर्जा देने को तैयार ही नहीं है बल्कि एक सीमा तक उनके अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करती है। उसके अनुसार इस्लाम का रास्ता ही मानव कल्याण का एक मार्ग है। इस मार्ग पर भटके हुए लोगों को लाना, दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदलने के प्रयासों का नाम ही जिहाद है और इस जिहाद में सम्मिलित होना प्रत्येक मुसलमान का पवित्र कर्त्तव्य है। इस विचारधारा के पोषक तथ्य कुरान और हजरत मुहम्मद के जीवन में विद्यमान हैं। उनके बारे में प्रश्न उठाना सम्भव ही नहीं है और कुरान में उसकी एकमात्र सजा दण्ड है। सलमान रुशदी के विरूद्ध यह फतवा आज भी कायम है। ईसाई विचारक बाइबिल और ईसा मसीह का खुलकर आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। वेद, गीता और राम–कृष्ण की आलोचना खुलकर हो सकती है किन्तु यह छूट मुस्लिम विचारकों को नहीं है क्योंकि इस्लामी विचारधारा भौगौलिक सीमाओं को स्वीकार नहीं करती।

जिहादी उग्रवाद के समर्थकों का मानना है कि जेहादियों को किसी भी देश, मुस्लिम अथवा गैर मुस्लिम और किसी भी सरकार के खिलाफ छेड़ने का धार्मिक अधिकार है। उनका यह भी कहना है कि वे सिर्फ उन्माद की सीमाओं को मान्यता देते हैं और सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं। ये सर्वाधिक घातक विचार हैं जो मनुष्य के दिमाग में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपजे हैं। जब तक इन विचारों का विरोध नहीं किया जाता और पाकिस्तान व अफगानिस्तान में इसके समर्थकों को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा पराजित नहीं किया जाता, 11 सितम्बर, 2001 जैसी और घटनाएँ हो सकती हैं। बिन लादेन इन्हीं विचारों की उपज है और प्रमुख उग्रवादी है जो चाहता था कि ये विचार लागू किए जाएँ, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसी उद्‌देश्य के लिए समान ताकत के साथ उग्रवाद चला रखा है।

धर्म की आड़ में फैलाये जा रहे विश्वस्तरीय आतंकवाद की सैद्धांतिक विवेचना की जाये तो भी उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। कोई भी उपासना पद्धति अर्थात् मजहब आतंकवाद की वकालत किसी भी रूप में नहीं

करता है। कुछ धार्मिक फस्तकें मजहब के प्रचार–प्रसार के नाम पर आतंकवाद का पक्ष लेती नजर आ रही हैं। यदि यह स्थिति बनी रहती है तो आतंकवाद को पोषण प्रदान करने वाली जो मानसिकता है, उसका अन्त होने वाला नहीं है। उचित यह होगा कि उस मानसिकता पर प्रहार करने के संदर्भ में गम्भीरता से विचार–विमर्श किया जाए जिसके चलते आतंकवाद फल–फूल रहा है। मजहब के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली मानसिकता कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका प्रमाण है, ओसामा–बिन–लादेन। एक सीमा तक वर्तमान में लादेन विश्व शांति के लिये एक बड़ा खतरा बन गया है। भले ही आज पाकिस्तान लादेन तथा उसके संरक्षक तालिबान के बारे में कुछ भी कह रहा हो, लेकिन इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि अभी तक पाकिस्तान लादेन तथा तालिबान का सबसे बड़ा संरक्षक व सहयोगी था। सच तो यह है कि लादेन, तालिबान और पाकिस्तान इस्लामी आतंकवाद के प्रतीक बन गए हैं। अमेरिका और साथ ही विश्व के अन्य प्रमुख राष्ट्रों को यह पता होना ही चाहिए कि तालिबान और लादेन पाकिस्तान के सहयोग, समर्थन और संरक्षण से ही सशक्त हुए हैं। यह भी एक तथ्य है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के जो प्रशिक्षण स्थल है, उनमें तालिबान शासकों और लादेन की सक्रिय भागीदारी है। वस्तुतः दुनियाभर में इस्लामी आतंकवादियों का 'निर्यात' पाकिस्तान की भूमि से ही अधिक हो रहा है। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में भी आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने के लिए अनेक अड्ड़े चलाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही अड्ड़े अफगानिस्तान में भी चल रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान हर तरह से मदद दे रहा है। इन परिस्थितियों को धर्म के आधार पर तो उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

4

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के समाधान हेतु उपाय
(Mesaures to Control and to overcome the problem of Global Terrorism)

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने के लिये विश्व के सभी देशों को मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाकर सामूहिक कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि आतंकवादी अपनी गतिविधियाँ एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित नहीं रखते। ये किसी भी क्षेत्र में, किसी भी धर्म, जाति, लिंग के निर्दोष नागरिकों को अपना निशाना बना सकते हैं। इस प्रकार इनकी मार से आज विश्व का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आज प्रत्येक देश चाहे वो गरीब है या अमीर है, किसी भी शासन प्रणाली जैसे लोकतंत्र अथवा तानाशाह, साम्यवाद अथवा पूॅंजीवाद, क्षेत्रीय शक्ति अथवा महाशक्ति सभी आज आतंकवाद की पीड़ा से पीड़ित हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र अमेरिका भूतपूर्व साम्यवादी रूस महाशक्ति चीन, ब्रिटेन, फ्रांस सभी इस आतंकवाद की ज्वाला से झुलस रहे हैं। आतंकवाद की रोकथाम के लिये विभिन्न उपायों को खोज रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अनेकों सम्मेलन आतंकवाद को परिभाषित करने तथा इसकी रोकथाम के उपायों को खोजने के लिये सम्पन्न हो चुके हैं।

आतंकवाद पर अंकुश लगाना आज की सामयिक, सामरिक व सामूहिक आवश्यकता है। परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, जिसने निडरता व निर्भीकता से उनका मुकाबला करना सीख लिया वास्तव में उसने जिंदगी की जंग जीत ली। एक आतंकवादी घटना के बाद उस क्षेत्र के पीड़ितों व आहतों को भड़काना आसान हो जाता है और ऐसे दुश्चक्र की शुरूआत होती है जिसे रोकना एवं तोड़ना बेहद कठिन हो जाता है क्योंकि संवेदना के वशीभूत होकर व्यक्ति ऐसे में जज्बाती बन जाता है। आज जरूरत इस बात की है कि आतंकवाद पर अंकुश लगाकर आने वाली आपदा को कैसे रोका जाये? आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि आतंकवाद के आधार को पहले समझा जाये। चूँकि आतंकवादी गतिविधि में आतंकवादियों के व्यक्तिगत स्वार्थ भी छिपे होते हैं किन्तु उन्हें बढ़ावा देने में राजनीतिक अदूरदर्शिता एवं आर्थिक विषमता का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। ''आर्थिक विषमता के कारण सामाजिक विभेद, क्षेत्रवाद, ऊॅंच–नीच, जातिवाद, वर्ग–वर्ण, अमीरी–गरीबी की भावना जन्म लेती है जो आतंकवाद को बढ़ाने में सक्रिय सहभागिता निभाती है।''[329]

आतंकवाद पर अभी तक नकेल न पड़ने का प्रमुख कारण हमारी राष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा तंत्र में खामियाँ तथा आतंकवाद से लड़ने की हमारी क्या नीति

---

[329] डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र, ''आतंकवाद व आपदा प्रबंधन'', 2010, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, पृष्ठ संख्या – 137

है? इसे अभी तक हमारी किसी सरकार ने परिभाषित नहीं किया है। नीति की व्याख्या आवश्यक है। कानून पहले से बेहतर जरूर है परन्तु उसे और सख्त बनाने की आवश्यकता है। अच्छा तो यह होता कि आतंकवाद से लड़ने का एक अलग कानून ही होता। 'इंटेलिजेंस ब्यूरो' में जनशक्ति की बहुत कमी है उसे पूरा किया जाना चाहिए। विदेशों से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्रित करने वाली 'रॉ' की कार्यक्षमता बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने इसे पंगु बना दिया था। 'नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी' और 'सी.बी.आई.' यदि एक ही छतरी के नीचे काम करे तो ज्यादा अच्छा होगा। नेशनल सिक्योरिटी कांउसिल का गठन कुछ वर्षों पहले जोर शोर से किया गया था। यह क्यों निष्कर्ष हो गया है, देखने की जरूरत है। इसी तरह 'नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड' इसलिये बेकार सा हो गया हैं क्योंकि सरकार इसमें अपने समर्थकों को नियुक्त करती है।

निस्संदेह देश के चार महानगरों में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) के हब का सक्रिय हो जाना, आतंक के खिलाफ मोर्चेबंदी की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले के बाद सरकार ने देश में एन.एस.जी. हब स्थापित करने की जो घोषणा की थी, उसका पहला चरण छह महीने की समय सीमा में पूरा हुआ। आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध के लिए दो बातें आवश्यक है– हमले से निपटने की हरसंभव तैयारी एवं हमला हो जाने के बाद तुरंत उसका प्रत्युत्तर। इससे दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ''आतंकवाद को जड़ से उखाड़ पेफंकने के लिए जरूरी है कि इनकी जड़ों का पता लगाकर उन्हें खोद फेंका जाये और एक योजनाबद्ध तरीके से समन्वित एवं सामूहिक कार्यवाही पर बल दिया जाये।''[330]

आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई पुलिस कार्यवाही के माध्यम से आतंकवादियों को थकाकर ही लड़ी जा सकती है। अमेरिका में 11 सितम्बर के हमले के बाद विभिन्न देशों में आतंकवाद विरोधी योजनाओं को लागू करने का दबाव बढ़ा है। अमेरिकी पेट्रियट कानून की तर्ज पर ब्रिटेन समेत विश्व के लगभग पचास देशों में आतंकवाद विरोधी कानून बनाया गया । भारतीय संसद पर हमले की घटना के बाद टाडा के स्थान पर पोटा को अंजाम दिया गया। नई सरकार ने पोटा हटाकर उसके प्रावधानों को दूसरे कानून में समाहित कर दिया।

डी.जी.पी. प्रकाश सिंह की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा। केन्द्र सरकार ने विधि विशेषज्ञ सोली सोराबजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर उसे नये पुलिस अधिनियम का प्रारूप प्रस्तुत करने के लिए कहा जिसे केन्द्र सरकार ने राज्यों को भेज दिया। लेकिन अधिकतर राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को संघीय ढट्टाचे पर हमला करार दिया। केन्द्र सरकार पर भी दबाव डाला कि वह सुप्रीम कोर्ट को

---

[330] वही, पृ.सं. – 142

संघीय ढ़ट्टाचे में पुलिस के विषय को स्वतन्त्र रूप से राज्यों का विषय बना दिए जाने के बारे में कारगर उपाय, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में 1861 के कानून के स्थान पर नया पुलिस कानून बनाने पर जोर दे रहा है।

''आतंकवाद से निपटना एक दुष्कर कार्य है, खास तौर से उस समय जब उसे पड़ोसी संप्रभु राष्ट्रों से अनवरत सहायता प्राप्त हो रही हो और देश के भीतर भी उससे हाथ मिलाने वाली शक्तियाँ उपस्थित हो।''[331] राष्ट्र का एक ही स्वर होता है और उससे भिन्न स्वर रखने वालों के लिए उस राष्ट्र में कोई स्थान नहीं होता है। असन्तोष हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, किन्तु मुख्य धारा में रह कर ही और कोई भी हल राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के मूल चरित्र की कीमत पर नहीं निकाला जा सकता।

आतंकवाद एवं मानवाधिकार (Terrorism & Human Rights)

मानवाधिकार और आतंकवाद को अस्पष्ट बनाए रखने के लिए तथा आतंकवादियों को मानवाधिकार का संरक्षण प्रदान करने के लिए बहुत ही आसानी से यह विचार प्रस्तुत कर दिया जाता है कि ''एक के लिए वह आतंकवादी है तो दूसरे के लिए वह स्वतन्त्राता संग्राम सेनानी।''[332] लेकिन स्वतन्त्राता संग्राम सेनानी और आतंकवादियों द्वारा किया गया हिंसा के प्रयोग में स्पष्ट अन्तर होता है। ''आतंकवादियों द्वारा किया गया हिंसा का प्रयोग अन्याय, असमानता और उत्पीड़न के लिए किया जाता है। जबकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा हिंसा प्रयोग अन्याय, असमानता और उत्पीड़न के विरूद्ध किया जाता है।''[333] मानवाधिकार के पैरोकारों को यह बात भली–भाँति समझनी होगी। वे मानवाधिकार के संरक्षण को सही तरफदारी करते हैं तो ''मानवाधिकार के अन्तर्राष्ट्रीय घोषणापत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि सभी व्यक्तियों को क्रूर, अमानवीय एवं अपमानित व्यवहार या दण्ड या उत्पीड़न से मुक्ति का अधिकार है।''[334] ''आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय संविदा एवं नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय संविदा दोनों के प्रस्तावना में भय से मुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है।''[335] नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय संविदा की धारा 6 में यह बात कही गयी है कि ''निरंकुशतापूर्वक किसी को भी

---

[331] डॉ. गुरूराम जी विश्वकर्मा मधुकर, ''भारत–तिब्बत–चीन का अस्तित्व'', 2011, कल्पज पब्लिकेशंस, सी–30, सत्यवती नगर, दिल्ली–110052, पृष्ठ संख्या – 233

[332] विलियम गुटेरिज ''इन्ट्रोडक्शन द न्यू टेररिज्म'', 1986, पृष्ठ संख्या –1, एडिटेड बाई विलियम गुटेरिज, इसके अलावा देखें नानी ए. पालखीवाला, ''वी द नेशन'', 1994, पृष्ठ संख्या – 25

[333] फरीद काजमी, ''ह्यूमन राईट्स : माइथ एण्ड रियलिटी'', 1997, पृष्ठ संख्या – 25

[334] मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणापत्रा, आर्टिकल 3, 5 GA Res. 217 A. UNDOC. Ae'810 at 71,72,73, 1948.

[335] GA Res. 2200, 21UN GAOR, Supp. (No. 16) 49UNDoc. Ae'6316 (1966).

उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।''[336] परन्तु जम्मू और कश्मीर के आतंकवादियों के सन्दर्भ में उपरोक्त सभी बातें निरर्थक हैं। उनके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार की घोषणाओं, संविदाओं एवं अन्य नियमों, कानूनों का कोई महत्त्व नहीं है। फिर भी यदि मानवाधिकारवादी जम्मू व कश्मीर में भारत सरकार की संस्थाओं पर मानवाधिकार हनन का आरोप लगाते हैं और आतंकवादियों के मानवाधिकार के संरक्षण की बात करते हैं तो इसके कारण अन्यथा ही होंगे न कि मानवाधिकार संरक्षण। ''मानवाधिकार और आतंकवाद के विषय में **खुशवन्त सिंह** ने बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है कि आतंकवाद और सभ्य समाज दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक ही उपस्थिति में दूसरे का अन्त निश्चित है। जो भी हाथों में बन्दूकें लेकर बात करना चाहते हैं, उन्हें बन्दूकों से ही जवाब देना चाहिए। आतंकवाद विरोधी कार्यवाही में गाँधीवादी सिद्धान्त को नहीं अपनाया जा सकता।''[337]

भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जरदारी को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान भारत की भूमि पर आतंकी गतिविधियों को नहीं रोकेगा तब तक उसके साथ कोई भी बातचीत नहीं की जायेगी। भारत सरकार ने **26 नवम्बर 2008** को मुम्बई में हुए आत्मघाती हमलों के सारे सबूत पाकिस्तान को दे दिये हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि सारे के सारे दसों आतंकवादी पाकिस्तान के ही नागरिक थे। और उन्हें पूर्ण प्रशिक्षण, धन, हथियार, प्रेरणा आदि सब कुछ पाकिस्तान ने प्रदान किया था। इस प्रकार पाकिस्तान एक आंतकी देश है जो आतंकवादी तैयार करता है। अतः इसके विरूद्ध अमेरिका एवं नाटों मित्रों व अन्य देशों को मिलकर पाकिस्तान के अलावा अन्य देश जो आतंकवादी संगठनों को शरण देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

"धन ही वो इंजिन है जिसके द्वारा आतंकी कार्य किये जाते हैं" अतः विश्व के उन सभी स्त्रोतों व मार्गों को बन्द कर देना चाहिए जिनके द्वारा आतंकवादियों को धन (पैसा) प्राप्त होता है। स्वीट्जरलैंड के बैकों, इस्लामिक बैकों, जहाँ आतंकवादी संगठनों का पैसा जमा होता है उनके सभी खातों को सीज (खारिज) कर देना चाहिए। काले धन को समाप्त करना चाहिए छोटे हथियारों व मादक पदार्थों की तस्करी रोककर आतंकियों को मिलने वाली सहायता को काट देना चाहिए। जब आतंकवादियों को धन प्राप्त नहीं होगा तो ये किसी भी प्रकार के हथियार नहीं खरीद पायेंगें और वे अपने आंदोलन (संघर्ष) को आगे नहीं बढ़ा पायेंगे। इस प्रकार आतंकवादियों की रोकथाम हो जायेगी।

---

[336] डॉ. ए.पी. शुक्ल, डॉ. राहुल मिश्र, ''राष्ट्रीय सुरक्षा की समसामयिक समस्यायें'', 2006, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, फोन – 9350551515, 23254306, पृष्ठ संख्या – 229

[337] खुशवन्त सिंह, 'ए लास्टिंग सलूशन', टेररिज्म इन पंजाब : कॉज एण्ड क्योंर, में प्रकाशित, 1997

1. **लिपे (LTTE) के आत्मघाती हमले** – एक अनुमान के अनुसार इस समय विश्व में 75 से भी अधिक ऐसे आतंकवादी संगठन है जिनके पास मानव बम मौजूद है। इनमें श्री लंका का उग्रवादी संगठन 'लिपे' (LTTE) प्रमुख है। मानव बमों को तैयार करने में आज भी इस संगठन को सर्वाधिक दक्षता हासिल है। लिपे के पास मानव बमों की एक पूरी ब्रिगेड थी जिसमें 250 मानव बम आतंकवादी कार्यवाही हेतु हरदम तैयार रहते थे और 900 से ज्यादा रंगरूट मानव बम बनने की प्रतीक्षा में रहते हैं। सन् 1980–2000 की अवधि में आतंकवादी कार्यवाहियों को अंजाम देने के लिये लगभग 275 मानव बमों का इस्तेमाल किया गया। इसमें सबसे ऊपर लिपे हैं जिसने तबाही मचाने के लिये सबसे ज्यादा 168 बार मानव बमों का प्रयोग किया जिनमें हजारों लोग मारे गये और अरबों–खरबों की सम्पत्ति नष्ट हुई।
2. लिपे के बाद दूसरे स्थान पर हिजबुल्लाह एवं सीरिया समर्थित आतंकवादी संगठन इस्लामी जिहादी ने इसी अवधि में 52 बार मानव बमों का इस्तेमाल किया। इनके अतिरिक्त ओसामा बिन लादेन का अलकायदा, फिलीस्तीन की स्वतन्त्राता के लिये लड़ रहा, फिलीस्तीन लिबरेशन प्रफन्ट एवं हमास (HAMAS) और पाकिस्तान का लश्कर–ए–तैयबा और जैश–ए–मुहम्मद नामक उग्रवादी संगठन बड़ी संख्या में मानव बमों द्वारा हमला करने की क्षमता रखते है और हमला करते रहे हैं। अमरीकी गृहमंत्रालय की एक रिपोर्ट (2000) के अनुसार इस समय पूरी दुनिया में 550 से 600 तक की संख्या में मानव बम तैयार स्थिति में घूम रहे है और वे कुछ भी कर सकते हैं। आज विश्व के सभी देशों पर मानव बमों के हमले का खतरा मंडरा रहा है। सर्वाधिक खतरा अलकायदा से है। क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा खतरनाक हथियारों से सुसज्जित सर्वाधिक सम्पन्न आतंकवादी संगठन है और इसका नेटवर्क विश्व के 60 देशों में फैला हुआ है।

ओसामा बिन लादेन

1. सऊदी अरब के रियाद शहर में जन्मा ओसामा अरबपति था। शीतयुद्ध के दौर में अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया था। अमरिकी खुफिया एजेन्सी सी. आई. ए. ने ओसामा को प्रशिक्षण दिया। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के वर्चस्व को खत्म करने की लड़ाई विभिन्न अफगान कबीलों ने लड़ी थी। उनकी मदद के लिये ओसामा बिन लादेन तीन हजार अरबियन नौजवानों के साथ मौजूद था।
2. 'ओसामा धनाढ्य है। विरासत में उसे करोड़ों डॉलर अपने पिता से मिले। वे सऊदी अरब में निर्माण व्यवसाय से जुड़े थे। ओसामा की सऊदी अरब नागरिकता खत्म कर दी गई। पिता और भाईयों ने भी नाता तोड़ लिया। लगभग एक दशक से ओसामा अफगानिस्तान के कन्धार क्षेत्र में गोपनीय

ठिकाने पर रहा था। ओसामा ने कंधार में ही अपने फत्रा का विवाह किया था।'

3. इस्लामी कफ्रता का प्रतीक बनकर उभरा ओसामा बिन लादेन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। करीब दस अरब डॉलर की कम्पनी चलाने का पर्याप्त अनुभव रखने वाला यह शख्स सिविल इन्जीनियरिंग, अर्थशास्त्रा व प्रबन्धन की डिग्रियाँ भी रखता था।
4. लादेन 'अलकायदा' नामक जो संगठन चलाता था। उसमें 60 देशों में सक्रिय लगभग 200 आतंकवादी गुट शामिल थे। इस खतरनाक संगठन के मुख्य रूप से कई उद्देश्य है जैसे जिस किसी इस्लामी देश में गैर इस्लामी सेना की उपस्थिति है वह उस देश से चली जाये इस्लामी देशों में सिर्फ इस्लामी सेना ही रह सकती है।
5. अमेरिकी सरकार ने उसे जिन्दा या मुर्दा पकड़वाने वाले को 120 करोड़ रूपये (12 मिलियन डॉलर) के फरस्कार की घोषणा की थी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अमीर और धर्म भीरू परिवार में जन्मा यह शख्स इस्लामी कानूनों का काफी जानकार माना जाता था और इसी जानकारी ने लादेन को 'जिहाद' की तरफ प्रेरित किया।
6. ओसामा बिन लादेन 2 मई 2011 को पाकिस्तान के ऐपटाबाद में अमेरिकी सील कमाण्डों द्वारा मारा गया था।

आतंकवाद का खुला विश्वविद्यालय

दुनिया में इस्लामी आतंकवाद का जो स्वरूप मुखरित हुआ है। उसका खुला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थापित है। इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद में जो इस्लामिक विश्वविद्यालय बना उसमें आतंकवाद क पूरा पाठ्यक्रम एवं प्रयोगशाला बनाई गई। इसमें प्रवेश पाने वाले छात्रों को कफ्रवादिता का ऐसा पाठ एवं आतंकवाद का ऐसा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे वे इस्लाम की जिहादी जहनियत की शक्ल अख्तियार करके आतंकवादी फौज के रूप में निकलते हैं।

आतंकवाद की परीक्षा एंव प्रशिक्षण में सफल व्यक्ति को उपाधि (डिग्री) प्रदान की जाती है और जो अपने विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, उनके विशेषज्ञ प्रोफेसर पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान से लगातार कश्मीर घाटी में स्थित इस आतंकवादी विश्वविद्यालय के केन्द्रों का दौरा करते है। आतंकवाद के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना भी एक कठिन कार्य है, क्योंकि इसके प्रत्याशी को एक कठिन परीक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आतंकवाद की उपाधि प्राप्त छात्रों के लिए रोजगार की कोई कमी नहीं होती।

यह धारणा है कि आतंकवाद पर वार्ता से काबू नहीं पाया जा सकता, भ्रामक है। अतः इस दिशा में हमें कुछ ठोस रचनात्मक उपायों पर ध्यान देना होगा तभी आतंकवाद पर नियन्त्रण पाया जा सकता है। **आतंकवादी व आत्मघाती हमलावरों का मुकाबला उसी तरह किया जाये जिस तरह अमेरिका, अफगानिस्तान**

में अलकायदा व तालिबान के आतंकियों के विरूद्ध कर रहा है। इस दिशा में निम्नलिखित उपाय कारगर साबित हो सकते हैं अर्थात् रोकथाम ईलाज से अच्छा है (Prevention is Better than Cure)।

4.1 रोकथाम के उपाय (Preventive Measures)

"जब तक वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव नहीं आएगा तब तक कठोर कानून व व्यापक संहार करने वाले अधिकारों का प्रयोग, आतंकवाद को रोकने में सफल नहीं होगा।"[338] आतंकवाद के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय कानून बने, भारत में भी पोटा व टाडा बने थे परन्तु आतंकवाद का गम्भीर खतरा बढ़ता ही रहा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून को कहना पड़ा है कि हालात बदलने के लिए अब सम्पूर्ण मानव समाज को विवश होना ही चाहिए। आतंकवादियों तक व्यापक संहार के हथियारों की पहुँच रोकनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आम सभा में युनाईटेड नेशनल ग्लोबल काउन्टर टेररिज्म (UNGCT) को अंगीकृत किया। दुनिया भर के देशों में आतंकवाद विरोधी नए कानूनों को अनुमोदित किया है फिर भी हमें अतीत के अनुभवों के प्रति गम्भीरता रखनी होगी। आवश्यकता महसूस की जा रही है कि सभी देशों में लोकतांत्रिक माहौल बनाया जाए। कमजोर राष्ट्रों को डराने व धमकाने से रोका जाए। जब तक ऐसा नही होगा तब तक धरती पर शान्ति लाने का उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। दुनिया के कमजोर देशों में यदि विध्वंसक हथियार आतंकवादियों के हाथ लगते रहे तो आशंका व्यक्त की जा रही है कि भारी विपदाएँ उत्पन्न होंगी व आतंकवाद बढ़ता रहेगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम.के. नारायणन ने स्वीकार किया है कि केन्द्र व राज्यों में समन्वय, सौहार्द की कमी, असन्तोषजनक सूचना तंत्र व सूचना का अभाव, सक्षम समर्पित अधिकारियों की कमी, अपराध अन्वेषण में देरी–अक्षमता, प्रशासनिक लापरवाही, जिम्मेदारी का अभाव व आम जनता में सुरक्षा के प्रति चेतना के अभाव में आतंकी घटनाएँ बढ़ रही हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम राज्य सरकारों का है, उन्हें इसकी जिम्मेदारी वहन करनी ही होगी। कठोर कानून के साथ अपराधों के अनुसंधानों में शीघ्रता लानी होगी। न्यायिक व्यवस्था में सुधार कर मुकदमों के निस्तारण में होने वाली देरी को समाप्त करना होगा। **इसके लिए निम्न उपाय किए जाने की जरूरत है–**

1. घरेलू मोर्चे पर चौकसी, निगरानी और इंटेलिजेंस नेटवर्क को बेहतरीन बनाने की दिशा में सचेष्ट होना अब बहुत जरूरी हो गया है। देशवासियों को भी इन खतरों को भाइ्रप फूट्टक–फड्रूककर कदम रखने और सुरक्षा एजेंसियों के सहायक के तौर पर कार्य करने में जुटना समय की जरूरत बन गया है क्योंकि निचले स्तर की खुफिया जानकारी का महत्त्व अब अधिक हो गया है।

---

[338] प्रो.मानचन्द खंडेला, "भारत–पाक और अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद", 2010, आविष्कार पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 807, व्यास बिल्डिंग, चौड़ा रास्ता, जयफर 302003 (राज.) फोन 0141–2578159, पृष्ठ संख्या – 63

आम लोग इससे जुड़कर किसी भी किस्म की सूचना उपलब्ध कराते चले तभी आतंक के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। आज अलकायदा की इकाई के तौर पर लश्कर के उग्रवादियों ने अपनी व्यूहरचना में बदलाव कर देश के अंदरूनी हिस्सों को भी अपना लक्ष्य तय कर लिया है। ये आतंकी स्थानीय नेटवर्क, स्त्रोतों और कौशल आजमाने में पारंगत होते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों से घुल–मिलकर, उनके आस–पड़ोस में ही बसकर वो अब अपनी कार्यवाही करते हैं। उनकी गतिविधियों और तौर–तरीकों में बदलाव के बाद हम अपनी रणनीति में भी सुधार करें यह स्वाभाविक और आवश्यक हो गया है। ऐसे में राज्य स्तर पर खुफिया एजेंसियों के व्यापक फनर्गठन की जरूरत है। आतंकवाद से लड़ने के लिए नीतिगत परिवर्तनों के साथ खुफिया तंत्रा, कूटनीति और पुलिस का भी सही इस्तेमाल अपेक्षित है। भारत की आबादी अधिक है इसलिए सामुदायिक भागीदारी की भूमिका आतंकवाद से निपटने में अहम् हो सकती है। दरअसल व्यवस्था फख्ता हो तो आसानी से आतंकी गतिविधियों को रोका जा सकता है।

2. शहर–दर–शहर हो रहे धमाकों से जा रही निर्दोष लोगों की जानें भी देश की कानून एवं व्यवस्था को राजनीति से मुक्त नहीं कर पा रही है। केन्द्र अपने हाथ बंधे होने का बातें करता है तो राज्य अपनी बीसवीं सदी की पुलिस व नकारा खुफिया तंत्र के बावजूद अपने अधिकार ढ़ीले करने को राजी नहीं है। देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायेसवाल तो राज्य को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से आतंकवादी खतरे पूरे विश्व में मंडरा रहे हैं उसे देखते हुए राज्य पुलिस के मौजूदा ढ़ाट्टचे से इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। ऐसा मानना पड़ेगा कि पुलिस ढ़ाट्टचे में मूल रूप से बदलाव की जरूरत है।
3. ''इस देश में करोड़ों अवैध शरणार्थी रह रहे हैं जो न सिर्फ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं बल्कि आतंकी घटनाओं में भी अधिकांश मामलों में इन्हीं का ही सीधा हाथ होता है। नेताओं की इस गन्दी राजनीति के कारण ही आज पूरा एक देश इनकी शरणस्थली बनकर रह गया है। अब जरूरी सबसे पहले इन्हें देश से निकालना हो गया है।''[339]
4. आतंकवाद के विरूद्ध सफल लड़ाई के लिए जरूरी है कि आतंकवादी घटना के प्रभाव को कम कर दिया जाए इसलिए सबसे पहला काम जन जागरूकता का होना चाहिए और यह हर स्तर पर हर अभिकरण द्वारा किया जाना चाहिए। पुलिस को चुस्त दिखने का नाटक भर करने के स्थान पर सचमुच चुस्त होना चाहिए और सामान्य जनों के साथ अपने सहज सम्बन्ध बनाने चाहिए ताकि किसी भी हादसे की स्थिति में दोनों पक्षों का तत्काल पारस्परिक सहयोग बन सकें।

[339] वही, पृ.सं. – 69

5. आतंकवादियों की पहुँच और उनकी विध्वंस क्षमता में अत्याधुनिक तकनीक की बदौलत पिछले कुछ सालों में जबरदस्त विस्तार हुआ है। "इंटरनेट, मोबाइल–सैटेलाइट फोन जैसे संचार के साधन, जबरदस्त संहार क्षमता वाले विस्फोटक, रिमोट कंट्रोल परिचालित बम, आकार के छोटे लेकिन मारक क्षमता में सबकों पछाड़ने वाले हथियारों ने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में सरकारों, गुप्तचर एजेंसियों और सुरक्षा बलों की नाक में दम कर दिया है।"[340] इसकी काट इस पर निर्भर करता है कि हम आतंकवाद का विरोध करने वाली तकनीक के विकास और उनके व्यापक प्रयोग को कितना महत्त्व देते हैं। हाल के घटनाक्रम से यह संकेत मिल रहे हैं कि जिस 'तकनीकी क्रान्ति' का फायदा आतंकवादी संगठन उठा रहे हैं उसी के सहारे उन पर काबू भी पाया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ जारी जंग में सुरक्षा एजेंसियों को जीत की गारंटी देने वाली तकनीक में 'बायोमीमैट्रिक्स' सबसे ज्यादा कारगर है। इसके तहत् कुछ खास किस्म के जैविक व रासायनिक सेंसरों को विकसित किया जा रहा है। ये सेंसर विभिन्न वाहनों या उपकरणों में छुपाकर रखे गए विस्फोटकों की पहचान कर सकते हैं। हवा–पानी यहाँ तक कि भोजन में भी किसी 'गलत' तत्त्व की मौजूदगी एक सुरक्षित दूरी से पहचानी जा सकती है। इसी कड़ी में एक और महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकी है– प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस। इसके अन्तर्गत सुरक्षा एजेंसियाँ कम्प्यूटर में दर्ज विभिन्न आँकड़ों और सूचनाओं को कुछ खास किस्म के सॉफ्रटवेयर की मदद से विश्लेषित करती है और उन्हें आतंकवादियों के सम्भावित हमलों के दिन, स्थान, समय के बारे में कई 'भविष्यवाणियाँ' कम्प्यूटर की स्क्रीन पर साफ–साफ लिखी हुई दिखेंगी। टेराहर्ट्ज तकनीक आतंकवादियों द्वारा विस्फोटकों को एक देश से दूसरे देश में भेजने पर रोक लगा सकती है। कुछ समय पहले पेंटागन ने आतंकवाद विरोधी तकनीक का महत्त्व समझते हुए लगभग तीन दर्जन ऐसी नायाब तकनीकों की सूची बनाई थी जिससे आतंकवादियों के होश गुम हो सकते हैं। इन तकनीकों को उपलब्ध करने के लिए सभी को खुला सार्वजनिक निमंत्राण दिया गया था। इस सूची में कई दिलचस्प प्रविष्टियाँ थी मसलन, एक ऐसा सॉफ्रटवेयर जो दुनिया भर में हर ऐसे व्यक्ति की जानकारी कम्प्यूटर रिकॉर्ड में रखेगा जो ऐसे पदार्थ की खरीददारी करता है जिसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जा सकता है। एक ऐसा सॉफ्रटवेयर खरीदने की बात चल रही है जो मध्य–पूर्वी देशों की भाषा बोलने वालों की पहचान कर सके। इसके अलावा बहुरूपिए आतंकवादियों के असली चेहरे की पहचान की क्षमता रखने वाली 'फेशियल रिकोगनिशन' प्रणाली का सार्वजनिक स्थलों का इस्तेमाल तो शुरू भी हो चुका है।

6. यह हकीकत है कि बहुसंख्यक भारतीय मुसलमान देश के प्रति वफादार और सम्बन्धित कानूनों का पालन करने वाले हैं। उनमें से अधिकांश आधुनिक विचारों के,

[340] वही, पृ.सं. – 72

शान्तिप्रिय और विकासशील मनोवृत्ति के माने जाते है। इसके सबूत के तौर पर कहा जाता है कि 1980 के दशक में जब दुनिया भर से करीब दस हजार मुसलमान अफगानिस्तान को सोवियत संघ के चंगुल से बचाने के लिए वहाँ के मुजाहिदीन में शामिल हुए थे तब उनमें भारत का कोई अपवाद स्वरूप ही मुसलमान था। इसी प्रकार पाकिस्तानी मदरसों में दुनिया भर से मुस्लिम आतंकवाद का प्रशिक्षण लेते हैं लेकिन भारतीय मुसलमान उन मदरसों में कभी इस उद्देश्य से नहीं गए। ओसामा बिन लादेन की अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामिक फैडरेशन के तहत् दुनिया भर के तेरह आतंकी संगठन शामिल हैं। इनमें भारत से जुड़ा एक भी आतंकी संगठन शामिल नहीं है। इसी प्रकार 7 अक्टूबर, 2001 को जब अमेरिकी फौजों ने अलकायदा और तालिबान के ट्रेनिंग कैंपों पर हमले शुरू किए तो दुनिया भर में मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किए लेकिन भारत में कहीं ऐसा सामान्यतः नहीं हुआ। अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ शुरू हुई जंग का मुकाबला करने के लिए दुनिया भर से मुसलमान अलकायदा का साथ देने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान आगे होकर गये लेकिन उनमें भारतीय मुसलमान सामान्यतः बिल्कुल शामिल नहीं थे। दुनिया भर से जितने मुसलमान पाकिस्तान में इस्लामिक शिक्षा पाने के लिए जाते हैं करीब–करीब उतने ही मुसलमान इसी उद्देश्य के लिए भारत भी आते हैं। पाकिस्तान से शिक्षा पाकर लौटे मुसलमान अपने देशों में लौटकर आतंकवाद फैलाते हैं, नशीली दवाओं का अवैध धन्धा करते हैं और अपने देश में कानून व्यवस्था तोड़ने वाले बनते हैं जबकि भारत से शिक्षा हासिल करके लौटे विद्यार्थी सामान्यतः ऐसा नहीं करते हैं शायद तब ही तो हामिद करजई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। इससे स्पष्ट है कि लादेन और पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आई.एस.आई. की बरसों की मेहनत मुसलमानों को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सकी हैं।

7. ''आतंकवादियों को आश्रय और सहायता देने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने का संकल्प करना चाहिए।''[341]
8. जैसे की भर्ती और प्रशिक्षण देने वाले राष्ट्रों के खिलाफ दक्षेस (सार्क) ही नहीं बल्कि विश्व जनमत के एकजुट करने की जरूरत है।
9. दक्षेस (सार्क) के नेतृत्व में सदस्य राष्ट्रों को निश्चय करके आतंकवादियों के खिलाफ सबुत देकर कार्यवाही करना जरूरी है। जैसे अमरिका ने अल–कायदा पर पाबंदी लगाई है।
10. पारस्परिक सूचना का आदान–प्रदान करके आतंकवाद का खात्मा किया जा सकता है।
11. आतंकवाद से निपटने के लिए चुस्त और कारगर यंत्राणा की आवश्यकता है।

[341] डॉ.वी.एन. अरोरा, डॉ. नन्द किशोर, डॉ. अभय कुमार सिंह, ''दक्षिण एशिया मे सुरक्षा चुनौतियों के नये आयाम'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, दूरभाष – 011–23255141, पृष्ठ संख्या – 180

12. दक्षेस (सार्क) राष्ट्रों के दुविधापूर्ण बयानों से बचना चाहिए।
13. आतंकवाद विरोधी दस्ते गठित कर उन्हें अध्ययन और प्रशिक्षण देना चाहिए।
14. ''सीमा पर नशीली दवाओं के तस्करों पर कड़ी नजर रखकर तस्करों की वित्तीय सहायता पर रोग लगाए।''[342]
15. दक्षेस (सार्क) के प्रत्येक नागरिक को यह समझना होगा कि लोकतन्त्रा बन्दुक की नली से नहीं बल्कि लोकतन्त्रा आत्मसंयम का दूसरा नाम है।
16. लोगों की समस्या का हल जल्दी निकाला जाना चाहिए।
17. मानव निर्मित अनेक आपदाओं में से आतंकवाद एक अत्यन्त घातक आपदा के रूप में इस 21वीं शताब्दी में सिद्ध हुआ है। वास्तव में यह एक वैश्विक समस्या के रूप में उभर कर आया है क्योंकि आज विश्व का लगभग प्रत्येक देश किसी–न–किसी रूप में आतंकवाद की आपदा से प्रत्यक्ष या परोक्ष ढ़ंग से प्रभावित है। आतंकवाद इस सदी में विश्व शान्ति, सुरक्षा एवं विकास के लिए एक बड़ी आपदा के रूप में उभरा है। 11 सितंबर, 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एवं पेंटागन पर हुए आतंकी हमलों ने इस बात के स्पष्ट संकेत दे दिये। वर्तमान समय में मध्य एशिया, दक्षिण एशिया तथा दक्षिण–पूर्व एशिया आतंकवाद की आपदा से बुरी तरह से त्रास्त है जिसमें विशेष रूप से दक्षिण एशिया आतंकवाद की आपदा का एक केन्द्र–बिंदु बना हुआ है। इस क्षेत्र में प्रायोजित आतंकवाद अधिक प्रचलित है। जिसके परिणामस्वरूप विनाशकारी व विध्वंसक तकनीकी अब आतंकवादियों की पहुँच में आ गई है जिसमें रासायनिक, जैविक एवं परमाणु हथियार भी अनुमानित किए गए है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख एवं वर्ष 2009 में **इंदिरा गाँधी शांति फरस्कार विजेता मुहम्मद अलबरदेई का यह कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है –** ''वर्तमान परिदृश्य में परमाणु तस्करी, तकनीकी हस्तांतरण तथा आतंकवादियों संगठनों के पास परमाणु हथियारों का होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि विश्व इस समय बहुत बड़ी आपदा की ओर अग्रसर हो रहा है।''[343]
18. आतंकवादियों पर अंकुश लगाने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कदम है, स्थानीय लोगों के समर्थन से उन्हें निरंतर वंचित बनाये रखना।
19. अगर कानून सख्त हों और अधिकार पूरे हों तो फिर हमारी जाँच एजेंसी विश्व को पीछे छोड़ देगी, क्योंकि विवेक के मामले में भारत का कोई जवाब नहीं है। एक विदेशी खुफिया एजेंसी (मौसाद) आतंकवाद से निपटने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। लेकिन हमारे यहट्टा राजनीति बहुत है जिससे भारत सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए जमीनी तौर पर हिम्मत ही नहीं जुटा पाती है।

---

[342] वही, पृ. सं. – 181

[343] डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र, ''आतंकवाद व आपदा प्रबंधन'', 2010, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, पृष्ठ संख्या – 149

20. ''वास्तव में यदि आतंकवाद को नियंत्रित एवं नष्ट करना है तो उन जड़ों को काटना होगा जहाँ से उन्हें ताकत मिलती है। इसके लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समर्थन एवं सहयोग जुटाना होगा।''[344]

21. ''मोटे तौर पर आतंकवादियों के लिए वित्त पोषण की बढ़ोतरी आतंकवादियों के लिए ज्यादा बम धमाकों के लिए पैसा उपलब्ध कराती है। लिहाजा जितना जल्द हो सके आतंकवादियों के वित्त पोषण से देश को बचाने का इंतजाम कर लिया जाना चाहिए। वास्तव में आतंकवाद को वित्त पोषण देने वाली विभिन्न गतिविधियों–नकली मुद्रा को चलाना, शस्त्रों की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, हवाला मामले और अंतर्राज्यीय अपराधों जैसे मामलों के लिए अलग से केंद्रीय या संघीय एजेंसी होनी चाहिए। ऐसी एजेंसी सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग की ही तरह स्वायत्त संस्था के रूप में गठित की जानी चाहिए। आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण में सेंध लगाने के लिए देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो को चुस्त और दक्ष बनाना होगा।''[345]

22. आतंकवाद की रोकथाम के लिए जरूरी है कि आतंकवाद की एक परिभाषा बनाई जाये, परिभाषा के द्वारा यह पहचाना जाये कि आतंकवादी कौन है? और कौन नहीं है? उसके बाद परिभाषा के अनुसार सख्त कानून बनाया जाये और शीघ्रतम कानून लागू किया जाये।

23. आतंकवाद की रोकथाम के लिए ATS – Anti Terrorist Squad (आतंकरोधी दस्ता) व SDS – Sniffer Dog Squad (सुंघने वाले कुत्तों का दस्ता) बनाया जाये।

24. आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए इसके प्रचार–प्रसार पर रोक लगाई जाये और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति हेतु राजनीतिक स्थिरता पर बल दिया जाये।

25. आतंकवाद से निपटने के लिए बेहद जरूरी कदम होगा कि एक व्यापक एवं नई रणनीति बनाकर सामूहिक प्रयास किये जायें तथा उसकी आपूर्ति का खात्मा किया जायें।

26. आतंकवाद को नियंत्रित एवं नष्ट करने के लिए हमारे नेतृत्व को ईमानदारी के साथ वोट बैंक की राजनीति का परित्याग करना होगा और तुष्टीकरण का मोह भंग करना होगा। इसके साथ ही समाज में व्याप्त भय, भूख एवं भ्रष्टाचार पर विजय पाकर जन–जागरण अभियान के द्वारा ही नकेल डाली जा सकेगी।

27. सभी देशों को एक अनिवार्य प्रत्यार्पण संधि करनी चाहिए जिससे आतंकवादी सजा से बचकर भागने में सफल न हो सकें। वास्तव में आतंकवाद के विरूद्ध एक ठोस रणनीति एवं उसका क्रियान्वयन किया जाना बेहद जरूरी है।

---

[344] वही, पृ.सं. – 151

[345] वही, पृ. सं. – 152

28. ''आतंकवाद और अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई देश और अन्तर्राष्ट्रीय कानून और संविधान की सीमाओं में रहकर ही लड़ी जानी चाहिए।''[346]

29. ''आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में निर्दोष लोगों को हानि नहीं होनी चाहिए।''[347]

30. ''अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों एवं कानून का पालन होना चाहिए।''[348]

31. पाक प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिए संभावित उपाय –

- ❖ पाकिस्तान में मजबूत लोकतन्त्रा की स्थापना हो।
- ❖ पाकिस्तान में सेना का प्रभाव एवं हस्तक्षेप कम हो।
- ❖ पाकिस्तान में तालिबानों का सफाया हो।
- ❖ ''पाकिस्तान में धार्मिक जिहाद एवं धार्मिक शिक्षा पर रोक लगे जो आतंकवादी पैदा करते हैं।''[349]
- ❖ आतंकवाद की ट्रेनिंग कैम्प बन्द हो।
- ❖ ''विश्व को इस बात से जागरूक करना कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बनता जा रहा है।''[350]
- ❖ पाकिस्तान पर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव एवं प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास करना।
- ❖ कश्मीर समस्या को हल करने का प्रयास करना।
- ❖ आम जनता को यह सन्देश पहुँचाना कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु एवं व्यक्ति की सूचना पुलिस बल को तुरंत दें।
- ❖ ए.बी.सी. हथियारों से बचने हेतु आम जनता को प्रशिक्षित करना।
- ❖ पाकिस्तान की हर आतंकी कार्यवाही का कड़ा जवाब देना।
- ❖ यदि पाकिस्तान स्वयं आतंकवादी ट्रेनिंग कैम्प बन्द नहीं करता है तो उसे हवाई आक्रमण से नष्ट कर देना चाहिए।

---

[346] डॉ. दीपा सिंह, के.पी.सिंह, ''मानवाधिकार एवं फलिस तंत्रा'', 2002, दि ब्राइट लॉ हाउस, 426/427, द्वितीय तल, कूट्टचा बृजनाथ, चाट्टदनी चौक, दिल्ली – 110006, फोन – 23946275, पृष्ठ संख्या – 329

[347] वही, पृ. सं. – 329

[348] वही, पृ. सं. – 329

[349] नर्वदेश्वर शुक्ल, डॉ. गुलाब चन्द्र ललित, ''भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में हिमालयी क्षेत्रा का स्त्राातेजिक महत्त्व'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, दूरभाष – 011–23255141, पृष्ठ संख्या – 218

[350] वही, पृ. सं. – 218

- ❖ यदि आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उन्हें जल्द–से–जल्द मुकदमें चला कर मौत की सजा देना, जिससे आतंकवादियों के हौंसले पस्त हो।
- ❖ आतंकवादियों को देखते ही शूट करने का आदेश हो।
- ❖ ''गुप्तचर व्यवस्था मजबूत हो जिससे आतंकवादी कार्यवाहियों की समय से पहले जानकारी प्राप्त हो सके।''[351]

32. आज की स्थिति में खुफिया तंत्रों द्वारा केवल इलेक्ट्रॉनिक निगरानी संबंधी कार्य लिए जाते है जबकि इस तंत्र को उपरोक्त प्रथम सूत्र के अनुसार मजबूत कर देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जानकारी लेने का भी दायित्व सौंपा जाना चाहिए, भले ही इस कार्य के लिए अधिक–से–अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों की भर्ती करना पड़े।
33. खुफिया तंत्रों को मजबूत कर और विस्तृत कर प्रत्येक राज्य, जिलों, नगरों, कस्बों एवं गाँवों के चप्पे–चप्पे की भौगोलिक निगरानी रखना अत्यन्त आवश्यक है। ये ''खुफिया तंत्र ऐसा होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को उसके जासूस होने का पता न चले और जासूस सबके साथ अंदर मित्रावत व भाईचारे का सम्बन्ध बनाते हुए सबका भेद जान सके।''[352]
34. यह काम केवल प्रशासन एवं खुफिया तंत्रों का ही नहीं है बल्कि हर आम नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि इस आतंकवाद की समस्या को हल करने के लिए प्रशासन एवं खुफिया तंत्रों की सहायता तन–मन–धन से करें। ऐसा करना राष्ट्रीय सेवा करना ही हमारी अपनी सेवा करना है और ऐसा करना हमारा परम् कर्त्तव्य है, परम् धर्म है। यह काम हमें उत्तेजित होकर नहीं करना है बल्कि पूर्ण सतर्कता बरतते हुए गोपनीय रूप से करना है।
35. ''प्रत्येक राज्य में विशेष प्रशिक्षित आतंकवाद विरोधी पुलिस दलों का भी गठित करना अत्यंत आवश्यक है ताकि यदि विशेष कार्यबल आतंकवादियों से संबंधित सूचनाएँ व्यापक स्तर पर एकत्रित कर विशेष प्रशिक्षित आतंकवाद विरोधी पुलिस दलों तक आसानी से पहुँचा सकें व पुलिस बल उन उच्चाधिकारियों व कर्मचारियों की मदद से त्वरित कार्यवाही कर सकें।''[353]
36. हमारे देश की कानून व्यवस्था लचर होने के कारण आतंकवादियों को सजा दिलाने में बहुत विलंब होता है, त्वरित कार्यवाही नहीं हो पाती। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गाँधी प्रकरण में भी आतंकवादियों को सजा देने में काफी विलंब हुआ था। स्वर्गीय राजीव गाँधी प्रकरण में आतंकवादियों को अभी तक

---

[351] वही, पृ. सं. – 219

[352] डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव, ''वैश्विक आइने में आतंकवाद : वर्तमान परिदृश्य एवं भविष्य की चुनौतियाइ्ट'', 2011, ओमेगा पब्लिकेशन्स, 4378/4बी, जी–4 जे.एम.डी. हाउस, गली मुरारीलाल, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, फोन 65901906, पृष्ठ संख्या – 43

[353] वही, पृ. सं. – 44

सजा नहीं मिली है। ''राजीव हत्या कांड से जुड़े कैदी – 1. वी.श्री हरन उर्फ मुरूगन 2. नलिनी 3. टी. सुथेन्द्रराज उर्फ संथन 4. एजी पेरारीवलन उर्फ अरिवु। ये चारों लिट्टे के सदस्य थे इन चारों को अभी तक फाट्टसी नहीं हुई है।''[354]

37. ''फलिस और अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए उन्हें सुसज्जित किया जाना चाहिए और उन्हें ऐसे अधिकार दिये जाये जो आवश्यकतानुसार निर्णय ले सकें।''[355]
38. आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में स्थानीय लोगों का सहयोग बहुत महत्त्व रखता है।
39. भविष्य में इसे सुनिश्चित किया जाये कि आतंकवादी संगठन सेना में सेंध न लगा पाये।
40. राष्ट्रीय समस्याओं पर आम सहमति तैयार करना।
41. कानूनी और न्याय व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण सुधार, भूमि सुधार, कानूनों को लागू करना और आर्थिक–सामाजिक न्याय की प्राप्ति।
42. ''विमान अपहरण रोकने, रेलों में बम विस्फोट, परिवहनों में बमों का प्रयोग, महत्त्वपूर्ण स्मारकों एवं पवित्र स्थलों को खण्डहर बनाने आदि को सुरक्षित रखने के लिए स्पेशल आतंकवाद टास्क फोर्स का गठन किया जाये।''[356]
43. सरकार को आतंकवाद से निपटने के लिए विशेष आधुनिक तकनीकों का उपयोग और सुपर फाइन तकनीकें विकसित कर लेनी चाहिए।
44. ''मीडिया अपनी भूमिका को और सशक्त बनाये ताकि आतंकवाद की जानकारी घर–घर एवं व्यक्तियों के कानों तक पहुँचे।''[357]
45. ''भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की चर्चा कर उसको खत्म करने का आह्वान करें।''[358]
46. आतंकवाद के कहर से निपटने के लिए पुलिस और खुफिया तंत्र में व्यापक फनर्गठन की आवश्यकता है। हालाँकि सभी एक–दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, पर वास्तविकता यह है कि ''आतंकी हमले हुए और खुफिया रिपोर्टों पर अमल नहीं किया गया।'' खुफिया तंत्र की तीन सर्वोच्च इकाइयाँ आन्तरिक खुफियागिरी का जिम्मेदार गुप्तचर ब्यूरो (आई.बी.) बाह्य खुफियागिरी का प्रभारी

[354] 20 फरवरी 2014, वीरवार, दैनिक जागरण, मेरठ, पृष्ठ संख्या – 2

[355] डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव, ''वैश्विक आइने में आतंकवाद : वर्तमान परिदृश्य एवं भविष्य की चुनौतियाङ्'', 2011, ओमेगा पब्लिकेशन्स, 4378/4बी, जी–4 जे.एम.डी. हाउस, गली मुरारीलाल, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, फोन 65901906, पृष्ठ संख्या – 74

[356] वही, पृ.सं. – 145

[357] 12 सितम्बर 2007, हिन्दुस्तान, कानफर, पृष्ठ संख्या – 16

[358] फखराज जैन एवं बी.एल. फड़िया, ''भारतीय शासन एवं राजनीति'', 1994, साहित्य भवन, आगरा, पृष्ठ संख्या – 324

रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) और प्रतिरक्षा गुप्तचर एजेन्सी (डी.आई.ए.) ज्यादातर स्वतंत्र रहकर काम करती हैं और एक–दूसरे से सहयोग नहीं करती हैं। उनमें समन्वय स्थापित करने और खुफिया रिपोर्टों को साझा करने के लिए कुछ साल पहले ही बहु एमैन्स समन्वय समिति (एम.ए.सी.सी.) के गठन किये जाने के बावजूद अधिकारी स्वीकार करते हैं कि यह व्यवस्था कारगर नहीं है। पूर्व सेनाध्यक्ष वी.पी. मलिक इस संदर्भ में कहते हैं कि ''यह बात स्तब्ध करने वाली है कि मुम्बई में हमले का मुकाबला करने के लिए कोई संयुक्त नियंत्रण कमान गठित नहीं की गयी। नौकरशाही को बनायी गयी लौह दीवारों को गिरा देना चाहिए। बजाये निचले स्तर पर गुप्तचर रिपोर्टों का तेजी से आदान–प्रदान होना चाहिए, जिससे विभिन्न स्तरों पर उनका आंकलन किया जा सकें।''

47. राज्य पुलिस बल अपने बजट का 90 प्रतिशत वेतन पर खर्च करती है। उन्हें केवल चोरों, डाकुओं और लुटेरों से निपटने के लिए लैस किया जाता है। इसी वजह से जब विस्फोटकों, अत्याधुनिक राईफलों तथा अन्य हथियारों से सुसज्जित, प्रशिक्षित और अभिप्रेरित आतंकवादियों से उन्हें लड़ना होता है तो उन्हें कुछ नहीं सूझता। इन्टरनेट और सैटेलाइट के माध्यम से संवाद करने वाले आतंकवादियों से निपटने से वे सर्वथा अक्षम होते हैं। मुम्बई के पूर्व आयुक्त एस.एच.सिंह का कहना है कि ''आज आतंकवाद प्रौद्योगिकी पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग चैनल का प्रयोग होता है। इनसे निपटने के लिए राज्य–फलिस बल के पास उपलब्ध उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी व्यवस्था को आधुनिक बनाना होगा।''

48. आतंकवादियों के ई–मेल, सैटेलाइट फोन से संवाद और बैंकिंग चैनलों पर नज़र रखने के लिए राज्य स्तर पर तकनीक और उसके विशेषज्ञों की भी आवश्यकता है।

49. विशेषज्ञ पुलिस अधिकारियों को आतंकवाद विरोधक दस्ते का प्रमुख बनाये जाने की आवश्यकता है और ऐसे अधिकारियों का रिकॉर्ड साफ सुथरा होना चाहिए। पुलिस को अत्याधुनिक हथियार और उसके प्रयोग का उचित प्रशिक्षण भी दिया जाना जरूरी है।

50. इलाके में अजनबियों और संदिग्ध व्यक्तियों, आतंकियों और इनके समर्थकों के विषय में जानकारी देने के लिए स्थानीय समुदाय के सदस्यों को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता है। इन स्थानीय लोगों को समय समय पर संदिग्ध अजनबियों के प्रति सचेत और सतर्क करते रहना भी आवश्यक है।

51. आतंकवाद के विरूद्ध सख्त कानून और उनके क्रियान्वयन के लिए द्रुत नीति से चलने वाली अदालतों को विकसित किया जाये जिनकी सहायता से आतंकवाद के आरोपी, उसको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से समर्थन देने वाले एवं प्रायोजकों की संपत्तियों के साथ–साथ उनके बैंक खातों की जाँच और निगरानी की जा सकें।

52. ऐसे संवेदनशील रसायन जिन्हें विस्फोटक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, की बिक्री पर नियंत्रण लगाने के लिए भी कानून और निगरानी की व्यवस्था हो।
53. प्रति आतंकवादी विचारधारा को विकसित करने की भी आवश्यकता है जिससे सभी आतंकवादियों के विरूद्ध सैनिक अभियान चलाने के साथ–साथ प्रभावित इलाकों के लोगों का हित और विश्वास जीतना भी आवश्यक है।
54. ''आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सरकार को एक साथ कई कदम उठाने पडेंगे, अन्यथा ये दीमक की भाँति राष्ट्र की जड़ों को खा–खाकर खोखला कर देंगे। सरकार को आतंकवाद समाप्त करने के लिए एक व्यापक नीति बनानी चाहिये, जिसमें प्रत्येक पहलू पर विचार हो तभी देश की एकता और अखण्डता सुरक्षित रह सकती है।''[359]
55. सीमा पर चौकियाँ स्थापित करना।
56. ''सीमा पर पुलिस गशत बढ़ाने की व्यवस्था करना।''[360]
57. प्रशासन और सुरक्षा बलों का आपसी समन्वय।
58. देशद्रोही और देशभक्त की पहचान।
59. प्रशासन को विशेष प्रशिक्षण देना।
60. अधिकाधिक ग्रामीण सुरक्षा समितियाँ बनाना।
61. आतंकवादी मारे जाने पर अनिवार्य फरस्कार योजना।
62. सभी देश मिलकर इस संकट का मुकाबला करें और आतंकवादियों को हर प्रकार की सहायता प्रदान करने वालों का भी विनाश और निन्दा की जानी चाहिए, यू. एन. ओ. में प्रश्न उठाकर उनका आर्थिक बहिष्कार और अनेकों प्रतिबन्ध लगाकर उनको दण्ड दिया जाना चाहिए ताकि वे इस हरकत से बाज आयें।
63. आज सम्पूर्ण विश्व के लिये आतंकवाद एक गम्भीर चुनौती है आतंकवादी गतिविधियों के संदर्भ में सभी राष्ट्रों का कर्त्तव्य है कि विश्व बन्धुत्व की भावना जाग्रत कर सभी आतंकवादी संगठनों और आत्मघाती हमलों को विफल करने का प्रयास करें।
64. आतंकवाद निरोधक कानून का सख्ती से पालन हो।
65. जो तलवार के बल पर जीने को कटिबद्ध है उन्हें तलवार से समाप्त करने में कोई ढ़ील नहीं बरतनी चाहिये।

---

[359] डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव, ''आतंकवाद का समकालीन परिदृश्य : स्वरूप एवं समस्यायें'', 2011, ओमेगा पब्लिकेशन्स, 4378/4बी, जी–4 जे.एम.डी. हाउस, गली मुरारीलाल, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, पृष्ठ संख्या – 143

[360] वही, पृ.सं. – 143

66. हमारे पुलिस बल/अर्द्धसैनिक बलों को अत्याधुनिक एवं विश्वसनीय किस्म के हथियारों से लैस किया जाना चाहिये जो आतंकवादियों की तुलना में श्रेष्ठ हो।
67. जघन्य अपराधों में शामिल आतंकवादियों को मृत्युदण्ड तथा सामान्य आतंकवादियों को शेष जीवन ऐसे स्थान पर बिताने के लिये भेजा जाना चाहिए जहाँ प्राकृतिक विषमताओं के तहत जीवन यापन ही कठिन होता है।
68. आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे पुलिस अधिकारी तथा पुलिस प्रमुख तैनात किये जाये जिनका सेवा अभिलेख अविछिन्न रूप से उत्तम हो।
69. आतंकवाद का उन्मूलन करने के पूर्व आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले कारकों की तलाश की जानी चाहिये और ठोस योजना बनायी जानी चाहिये।
70. आतंकवाद, जासूसी और तोड़–फोड़ की साजिशों से निपटने के लिये हमारी (I.B. – Intelligence Beaurow) गुप्तचर व्यवस्था (Intelligence System) को अधिक चुस्त और कारगर बनाये जाने की आवश्यकता है। हमारी सरकार इंटेलिजेन्स पर करोड़ों रूपये खर्च करती है लेकिन इसकी उपलब्धि नहीं के बराबर है। दो–दो प्रधानमंत्रियों की हत्या के अतिरिक्त भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री सीमा पार से देश के भीतर पहुँच गयी लेकिन इस संदर्भ में इंटेलिजेन्स को कोई भनक तक नहीं लग सकी। इसे आप क्या कहेंगे? 6 अप्रैल 2010 को नक्सलवादियों द्वारा **CRPF (सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स)** के 76 जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया और हमारी गुप्तचर व्यवस्था को 1000 नक्सलियों की स्थिति का सही आभास तक नहीं था। यह उसकी गंभीर असफलता है।
71. हमारे सम्पूर्ण पुलिस तन्त्रा को नये सिरे से गठन (overhaul) की आवश्यकता है तथा पुलिस की जो छवि जनमानस में है उसे दूर करने के लिये नये सिरे से प्रयास करने की आवश्यकता है।
72. आतंकवाद से जुड़े प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रमाण मिलने पर उन्हें नष्ट करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहमति तैयार की जानी चाहिये।
73. प्रशासन में राजनीतिक नेताओं की दखलन्दाजी बन्द की जानी चाहिये।
74. राजनेताओं को दुविधापूर्ण बयानबाजी से बचना चाहिये।
75. प्रत्येक प्रान्त के उन इलाकों को जो दूर–दराज तथा पिछड़े हैं, को सांस्कृतिक एकता की परिधि में लाना होगा।
76. राष्ट्रीय नेतृत्व में उन्हीं लोगों को समर्थन दिया जाना चाहिये जिनकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण असंदिग्ध हो।
77. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आतंकवादियों को पकड़वाने में सहायता दी हो उनका राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान किया जाना चाहिये तथा उन्हें राष्ट्रीय सम्पत्ति मानकर उनकी हिफाजत की जानी चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से देश भरा है जो अपनी जान तो बचा सकते हैं किन्तु ऐसे लोग विरले ही हैं जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाते हों।

78. सैन्य बलों की शौर्यतापूर्ण कार्यवाही के लिए उन्हें तत्काल पदोन्नति देने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी चाहिये।

79. प्रत्येक राज्य में जो आतंकवाद से पीड़ित नहीं हैं वहाँ भी आतंकवाद विरोधी दस्ते का गठन किया जाना चाहिये तथा अन्य देशों की आतंकवादी कार्यवाहियों का अध्ययन कर उसी के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये।

80. राजनीति में अपराधी तत्त्वों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबन्ध होना चाहिये क्योंकि आज स्थिति यह बन गयी है कि जब एक राजनीतिक दल किसी अपराधी तत्त्व को चुनाव में टिकट देता है तो अन्य पार्टियाँ भी उसके मुकाबले में उससे भी खूँखार बदमाश की तलाश कर उसे टिकट देती हैं। इस प्रकार एक अनवरत सिलसिला प्रारम्भ हो जाता है।

81. ऐसी स्थितियाँ पैदा की जानी चाहिये जिससे देश में यह वातावरण बन सके कि जायेज माँगों के लिये सरकार हर वक्त तैयार है और नाजायेज माँगों के लिये कोई स्थान नहीं है।

82. जो देश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका सामूहिक बहिष्कार किया जाना चाहिये।

83. कानून में ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिये कि किसी व्यक्ति के बारे में यह प्रमाण मिल जाने पर कि वह आतंकवादी है, उसे उसकी सारी सम्पत्ति से वंचित कर देने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

84. नैतिकता (Ethical Measures) को सर्वोपरि स्थान देने की आवश्यकता है क्योंकि नैतिकता के निष्कासन से कर्म की मर्यादायें नष्ट हुई हैं और इन्हीं मर्यादाओं के नष्ट होने से आक्रामक प्रवृत्तियों का जन्म हुआ है।

85. आतंकवाद से जुड़ी प्रत्येक समस्या से निपटने के लिये सभी राष्ट्रीय तथा स्थानीय नेताओं (चाहें वे किसी भी पार्टी के हों) को बन्दूक से राज करने वाले लोगों के विरूद्ध एकजुट होकर प्रबल जनमत तैयार करना आवश्यक है इसके लिये हमें व्यक्तिगत हितों को तिलांजलि देनी होगी और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी होगी।

86. संविधान और देश के कानूनों की भावनाओं की कद्र की जानी चाहिये। कानून बनाना ही सब कुछ नहीं है, बीमारी का इलाज होना चाहिये, उसके लक्षणों का नहीं। आग लगने पर दमकल बुलाना तर्कसंगत है पर बुद्धिमानी यह होगी कि ऐसी व्यवस्था की जाये कि आग न लगे। इसके लिये ज्वलनशील पदार्थों को आग से दूर रखा जाये। अर्थात् **"Prevention is better than cure." (रोकथाम इलाज से अच्छी है)**

87. ऐसी खतरनाक फिल्मों पर बंदिश लगायी जानी चाहिये जो हिंसा, अपहरण और आतंकवाद के नये तरीकों की ईजाद से सम्बन्धित हों। उल्लेखनीय है कि कनाडा के कुछ आतंकवादियों को भारतीय संसद उड़ाने के आरोप में पकड़ा जा चुका है। इन आतंकवादियों ने दिल्ली के आतंकवादियों से

मिलकर संसद भवन उड़ाने की खतरनाक साजिश तैयार की थी। योजना यह थी कि विरोधी दल के एक संसद सदस्य के बच्चे का अपहरण कर लिया जायेगा और फिर उसे विवश किया जायेगा कि वह संसद भवन के अन्दर बम पहुँचाये। इस खतरनाक योजना का सूत्र उन्हें हॉलीवुड और हिन्दी फिल्मों से मिला प्रतीत होता है।

88. सीमा पर नशीली दवाओं के तस्करों पर कड़ी नजर रखनी चाहिये क्योंकि आतंकवादियों को तस्करों से वित्तीय सहायता मिलती है। जैसे – Golden Crescent (अफगानिस्तान, ईरान व पाकिस्तान) – Golden Triangle (म्यांमार, थाईलैण्ड, लाओस) अर्थात् इन देशों से होते हुए मादक पदार्थ विदेशों में पहुँचते हैं।

89. अगर आतंकवादियों एवं उग्रवादियों की माँगें न्यायोचित एवं संविधान के अनुरूप हो तो उन्हें सरकार को तुरन्त मान लेना चाहिये और आतंकवादियों को देश की मुख्य धारा में जोड़कर उनके आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए।

90. आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे पुलिस अधिकारी तथा पुलिस प्रमुख तैनात किये जायें जिनकी सेवा अभिलेख अविछिन्न रूप से उत्तम हों। इसके साथ ही पुलिस को भी अपने कर्त्तव्य की पहचान करनी आवश्यक है। 25 जुलाई, 1986 को मुक्तसर (पंजाब) में आतंकवादियों ने एक बस में 21 यात्रियों को पिस्तोलों और स्टेनगनों से निकलती गोलियों से भून डाला। उसी बस के एक यात्री के अनुसार यदि पुलिस चाहती तो दुखद घटना टल सकती थी और आतंकवादियों को पकड़ा जा सकता था **क्योंकि हत्याकांड से जुड़ी बस का अपहरण होने के पाँच मिनट बाद ही रास्ते में सिपाहियों से भरी एक जीप को इस घटना की सूचना थी लेकिन जीप में सवार पुलिस वाले यह कहकर आगे बढ़ गये थे कि न तो हम ड्यूटी पर हैं और न ही यह इलाका हमारे कार्यक्षेत्र में पड़ता है।**

91. बिना लाइसेंस के अस्त्रों और अस्त्रा कानून के उल्लंघन की समस्या आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हैं। आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसका इस्तेमाल सबसे अधिक उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में हो रहा है। 1972 और 1974 में अधिकतर अपराधों में इस्तेमाल किये गये हथियार बिना लाइसेंसी थे। 1972 के मुकाबले 1977 में अस्त्रा कानून के तहत दर्ज किये गये मामलों में 109.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्यों में सबसे अधिक शस्त्र कानून का उल्लंघन उत्तरप्रदेश में पाया गया है। एक लाख की जनसंख्या में से 45.6 प्रतिशत ने इसका उल्लंघन किया। पंजाब में इसकी दर 28.91 थी जबकि आज पंजाब सबसे आगे पहुँच गया है। इस दिशा में सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। ब्रिटेन में किसी को जीवन हानि के लिये शस्त्र अपने पास रखना या कैद से बचने के लिये अस्त्रों के इस्तेमाल के लिये आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती

है जबकि हमारे देश में किसी व्यक्ति की अपराधी प्रवृत्ति का प्रमाण मिल जाने के बाद भी उसके अस्त्रा लाइसेंस को निरस्त करने की प्रक्रिया में अनेकों वर्ष लग जाते हैं।

यह सन्तोष का विषय है कि भारत और ब्रिटेन के बीच आतंकवाद निरोधक कानून के तहत एक ऐसे समझौते को मूर्त रूप दे दिया गया है जिसमें ब्रिटेन में सिक्ख गुरूद्वारों में आतंकवादी कार्यवाही हेतु एकत्र की जा रही धनराशि को जब्त किया जा सके। यह कैसी विडम्बना है कि यूरोपीय राष्ट्र आज अपने फराने युद्धों की कटुता भूलकर, जिन्हें उन्होंने सैंकडों साल तक लड़ा है, एक–दूसरे से गले मिल रहे हैं। हमें यह आशा तो करनी ही चाहिये कि दक्षिण एशिया में भी एक न एक दिन यह भावना पैदा होकर रहेगी। भय और विश्वास की जो उफट्टची दीवारें सीमाओं पर बन गयी हैं वे ढ़ह जायेंगी और इस उपमहाद्वीप के लोग अपनी अलग पहचान बनाने तथा सामूहिक हित के लिये कार्य करने हेतु आगे आयेंगे। ''शायद यह सच चौंकने वाला होगा कि पाकिस्तान के निर्माता कायदे आजम जिन्ना ने अपने जीवन के अन्तिम दिनों में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली से कहा था कि पाकिस्तान बनाकर मैंने सबसे बड़ी गलती की है। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली जाकर नेहरू से कहूँ कि फरानी गलतियों को भूल जायें और फिर से दोस्त बन जायें।''

अभी भी समय है कि पाकिस्तान अपने और भारत के साझा हितों को समझे। किन्तु यदि पाकिस्तान और भारत के बीच सन्देहों का सिलसिला जारी रहा तो एक ऐसी स्थिति हो जायेगी कि जिसमें अगर युद्ध न भी हो तो भी कोई समझौता नहीं हो पायेगा। भारत–पाक के मध्य विश्वास निर्माण (जनक) के उपाय अपनाये जायें। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि आज (**CBMs – Confidence Building Measures**) अनेक नरसंहारों की जड़े जातीय पागलपन, राजनीति के रंग और अपनी जाति के नेता बने रहने के इच्छुक इलाके के नेताओं के सधाये हुए गिरोहों की गतिविधियों में है। हर नरसंहार पर आट्टसू बहाने वाले लोग भी वहीं होते हैं जो उसका कारण होते हैं।

आज इस सत्य का अनदेखा नहीं किया जा सकता कि हमने धर्मनिरपेक्षता का सिद्धान्त तो कबूल किया किन्तु धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों पर रोक नहीं लगायी। राष्ट्र ने सभी धर्मों को समान दर्जा तो दे दिया किन्तु भारतीय नागरिकों के अनेक वर्गों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखने से इन्कार कर दिया। उन्होंने धर्म को पहले और राष्ट्र को बाद में रखा। यही कारण है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होते हैं, तो बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी विदेशी पाकिस्तान टीम के विजयी होने पर खुशियाँ मनाते हैं। धर्म राष्ट्रीयता पर हावी हो जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को ध्यान में रखते हुए इस असामान्य भावी द्वेष को समझ पाना कठिन नहीं है, भले ही इसे उचित ढ़ंग से प्रतिपादित न किया जा सके। वोटों की राजनीति के कारण ही

आजादी के बाद से आज तक हमारे राजनीतिज्ञों के लिये धर्म और राजनीति के बीच सीमारेखा खींचने का प्रश्न असंभव हुआ है।

भारत के प्रत्येक नागरिक को यह समझना होगा कि **लोकतंत्र बन्दूक की नली से नहीं निकलता बल्कि लोकतंत्र आत्मसंयम का दूसरा नाम है।** सत्ता की राजनीति लोगों की भावनाओं को भड़काने में तो माहिर है लेकिन भड़की भावनाओं पर काबू पाने के लिये कारगर औजार उसके पास नहीं है। दिशाहीन राजनीति का दर्द समाज भुगतता है और जनता हिंसा के चक्रव्यूह से मुक्ति के लिये कराहती रहती है। जरा भारत में विपक्ष का दृष्टिकोण तो देखिये 1982–1987 के बीच जब तमिलों का नरसंहार चल रहा था तब हमारी विपक्षी पार्टियाँ लोकसभा में कह रही थी कि तमिलों के साथ अत्याचार, भारत को रोकना चाहिये। जब भारत ने शांति सेना भेजी तो उन्होंने कहा कि भारत ने हस्तक्षेप क्यों किया? भारतीय शांति सेना (**IPKF - Indian Peace Keeping Force**) को वापिस आ जाना चाहिये। चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी। इसी तरह का दृष्टिकोण पंजाब, कश्मीर और उत्तर–पूर्व की आतंक से जुड़ी समस्याओं पर भी इनका रहा है। अर्थात् विपक्ष को सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिये।

अमेरिका से प्रकाशित टाइम पत्रिका ने लिखा है कि ''भारत में जैसे–जैसे समस्या सामने आयी सरकार ने उसका सैनिक समाधान ही ढूट्टढ़ा। इसके लिये नये–नये अर्द्धसैनिक बलों की रचना की गई किन्तु समस्या के वास्तविक हल का कोई प्रयास नहीं किया गया, फलस्वरूप समस्या बढ़ती ही गयी। यदि समझदारी व राजनीतिक सूझबूझ से काम लिया जाता तो कश्मीर, पंजाब व उत्तर–पूर्व की समस्यायें पैदा ही न होती।'' आज भारत के नागरिकों का भविष्य राष्ट्र–राज्य की सलामती के साथ जुड़ा है। हम सबके सपने यदि देर–सवेर पूरे होने भी हैं तो यह तभी सम्भव है जबकि भारत की एकता, अखण्डता अक्षुण्ण रहे। लेकिन भारत की भौगोलिक–राजनैतिक एकता भी तभी कायम रह सकती है जब भारत की जनता में एकता कायम रहे। देश आज ओछी हरकतों को देखते–देखते उफब चुका है और यदि अब भी हम में यथार्थ से टक्कर लेने की क्षमता पैदा नहीं होगी तो वह दिन दूर नहीं जब यह अराजक, आत्मघाती और हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ हमारे मानस को विषाक्त बना देंगी। अभी असंख्य ऐसे द्वीप हैं जहाँ टूटे मन में संस्कार जीवित हैं, वैचारिक बेचैनी है, बौद्धिक आक्रोश है और दिल में कुछ कर गुजरने की आकांक्षा है। यदि आगामी दस–पन्द्रह वर्षों में ये द्वीप भी नष्ट हो जायेंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। शुतुरमुर्गी रणनीति (Ostritch Tactics) अपनाने से काल का दण्ड फिर कुछ नहीं छोड़ता। अनेक बुद्धिजीवी आज यहाँ तक कहने लगे हैं कि हमारे देश में विद्यमान कई समस्याओं का समाधान लोकतंत्र में नहीं है और भविष्य में फासिस्टवाद का खतरा दिखाई दे रहा है, अतः हमें इस खतरे से भी सावधान रहने की आवश्यकता है।

यह भी कैसी विडम्बना है कि आतंकवादियों ने अपने मानव साथियों के विरूद्ध हिंसा का मार्ग अपनाया है। जो तलवार के बल पर जीना चाहते हैं उन्हें तलवार से समाप्त कर देना चाहिये। संसार में कहीं भी आतंकवादियों के कब्रिस्तान के लिये भी स्थान नहीं होना चाहिये और यह विश्वव्यापी कार्यक्रम भी तभी सफल हो सकता है जबकि इन्हें शरण देने वाले राष्ट्र का पूर्ण बहिष्कार कर दिया जाये। यही प्रयास विश्व–शांति को आतंकवादियों की जकड़ से मुक्त रखने में सहायक सिद्ध होगा। आज अन्तर्राष्ट्रीय या घरेलू आतंकवाद पर काबू पाना नितान्त कठिन है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब कोई देश दूसरे देश में आतंकवादियों की मदद कर रहा हो। आतंकवाद पर काबू पाने के लिये आवश्यक है कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों को कड़ी सजा दी जाये और जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हों उनके विरूद्ध आर्थिक, राजनयिक तथा राजनीतिक (Economic, diplomatic and political) कदम उठाये जायें।

लोकतांत्रिक देशों को आतंकवाद का मुकाबला अपने देश के कानून के अनुसार ही करना चाहिये और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि आतंकवादियों को कुचलते समय सामान्य नागरिकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही न हो जाये। आतंकवाद की समाप्ति के लिये यह भी आवश्यक है कि इन देशों के बीच अधिक से अधिक **'प्रत्यावर्तन संधियाँ'** हो जहाँ पर यह समस्या है। इस तरह की संधियों का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आतंकवादियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की प्रक्रिया तेज हो सकेगी। इसमें बहस की कोई गुंजाईश नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच **'प्रत्यावर्तन संधि'** न होने के कारण भारत को इस समस्या से बहुत हानि पहुँच रही है। यह जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान प्रत्यावर्तन संधि करें, फिर उसे सख्ती से लागू भी करें जिससे आतंकवादी दानव को जड़मूल से समाप्त किया जा सके।

आतंकवाद एक ऐसा **'हथियार'** है जिससे अलोकतंत्रीय शक्तियाँ ही लाभ उठा सकती हैं। अधिनायकवादी देशों के लिये आतंकवादियों का खतरा बहुत कम है, यह खतरा लोकतंत्रीय समाजों के लिये अधिक है। यदि आतंकवाद का प्रयोग परम्परागत युद्ध के विकल्प के रूप में किया जाये अथवा नगर जनसंख्या का एक वर्ग इसका प्रयोग दूसरे वर्ग या विदेशी सत्ता के विरूद्ध करे तो यह एक सैनिक हथियार बन जाता है। आतंकवादी कार्यवाहियों द्वारा निर्दोष नागरिकों की मौत युद्ध के हथियार के रूप में इसके उपयोग का अन्य परिणाम है।

निःसन्देह आतंकवाद एक ऐसी चाल है जिसका विस्तृत अध्ययन होना चाहिये। इसके विरूद्ध सुरक्षात्मक उपायों का निर्माण करना जरूरी होगा। आतंकवाद विश्व की मुख्य राजनीतिक धारा में प्रविष्ट हो चुका है। विनाश के अपेक्षाकृत छोटे और सस्ते साधनों के सुगमता से उपलब्ध होने के कारण मुट्ठी भर लोग विश्व भर के राज्यों और समाजों पर भारी प्रभाव डाल सकते हैं।

भारत में आतंकवाद की रोकथाम के लिये किये गये सरकारी संवैधानिक उपाय

1. आतंकवाद और विध्वंसकारी गतिविधि निरोधक कानून (TADA) मई, 1985। यह अधिनियम जून, 1995 में समाप्त कर दिया गया।
2. आतंकवाद निरोधक कानून (POTA)
3. गैर कानूनी गतिविधियाँ निवारण अध्यादेश 2004
4. आतंकवाद विरोधी विशेष पुलिस दल (ATS-Anti Terrorist Squad) और अन्य सैन्य दल की व्यवस्था 2004। 'केन्द्रीय सचिव मण्डल' का एक पृथक्क 'सैल' (Cell) बनाया गया।

"वर्तमान में हम जिस प्रकार का आतंकवाद देख रहे हैं उससे केवल सैन्य तौर–तरीकों से निपटना बेहद कठिन है। प्रधानमंत्री और नीति–निर्माताओं को थोड़ा रूक कर तस्वीर पर व्यापक निगाह डालनी होगी। अगर आतंकवाद पर अंकुश लगाना है तो हमें गरीबी, अशिक्षा, भेदभाव, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निपटना होगा।"[361] अब हमें सबसे अधिक आवश्यकता वास्तविक सुशासन की है। अब तक इन समस्याओं के समाधान के लिये कुछ नहीं किया गया। आश्चर्य होता है कि क्या कभी सत्ता प्रतिष्ठान ने इस पर चिन्तन–मनन करने की जरूरत भी महसूस की है कि गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी समस्यायें लोगों के मन में हताशा पैदा कर रही हैं?

4.1.1 यू.एन.ओ. तथा अन्य विश्वस्तरीय एजेन्सियों द्वारा (At the level of U.N.O. and other Global Agencies)

वैश्विक आतंकवाद और संयुक्त राष्ट्र संघ

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में शांति और सद्भावना बनाये रखने के उद्देश्य से **24 अक्टूबर 1945** को की गई थी। विश्व के अधिकतर देश अब इस संगठन के सदस्य हैं। आतंकवाद के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि ऐसे निंदनीय कार्य के लिए विश्व में कहीं कोई स्थान नहीं होना चाहिये। इसके लिये संघ सुरक्षा परिषद के माध्यम से कार्य करता रहा है।

इस विकट समस्या के सम्बन्ध में संघ के सभी सदस्य देश यह संकल्प करते हैं कि **"हम सभी रूपों में किसी भी प्रकार से, किसी के भी द्वारा, कहीं भी और किसी भी उद्देश्य से, किये गये आतंकवाद की कठोर और साफ शब्दों में निंदा करते हैं। आतंकवाद अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिये गंभीरतम खतरों में से एक हैं।" और आगे कहते हैं कि "हम हर उस राष्ट्र को समर्थन और सहयोग देंगे जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा परम्पराओं एवं मानवाधिकारों के आदेशों के अन्तर्गत आतंकवाद को रोकने और उससे लड़ने में सहयोग कर रहा होगा।"**

[361] 9 नवम्बर 2009, सोमवार, दैनिक जागरण, हिसार, पृष्ठ संख्या – 6

संघ का रूख आतंकवाद के विषय पर सख्त है। इसके बाद भी कहीं–न–कहीं इस समस्या के समाधान में यू.एन.ओ. उतना सक्षम नहीं दिखाई दे रहा है जितना वह हो सकता है। इसका कारण यह है कि संघ में शामिल कुछ देश ही अपने निजी स्वार्थ के चलते आतंकवादी घटनाओं का पीछे से समर्थन करते हैं। संघ आतंकवाद के खात्में में अहम भूमिका निभा सकता है जब उसे सदस्य देश खुलकर साफ मन से समर्थन करे। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाये तो सोमालिया, कांगों, अफगानिस्तान, इराक, भारतीय उपमहाद्वीप आदि में जारी हिंसा को रोकने में यू.एन.ओ. कारगर साबित नहीं हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हिंसा (आतंकवाद) के कारण असहाय हुए बच्चों की देखभाल के लिये **यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की थी।** आज यह संस्था कई देशों में गृहयुद्ध एवं आतंकवाद के चलते बेसहारा और लाचार हुए बच्चों के उत्थान के लिये कार्य कर रही है। इसी तरह आतंकवाद के कारण अपना घरबार छोड़ने को विवश हुए लोगों की सहायता के लिये भी संघ की संस्थायें कार्य कर रही हैं। भारत आतंकवाद के विषय पर पूरी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ है। आतंकवाद की रोकथाम के लिये संघ ने जितने भी कदम उठाये हैं उन सबको भारत का समर्थन प्राप्त है।

9 दिसबर 1985 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने एक प्रस्ताव द्वारा आतंकवाद को गम्भीरता से लिया और विश्व समुदाय का संयुक्त मोर्चा बनाकर विश्व की सरकारों से अपील की गई कि –

1. वे आतंकवाद के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करें और इस समस्या के समाधान हेतु कठोर कदम उठाये।
2. अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को निर्वाह करे और किसी दूसरे देश के प्रति आतंकवादी गतिविधियों को संगठित न करे, न ही प्रोत्साहन दे, न सहायता दे और न ही उसमें शामिल हो।
3. आतंकवादियों को पकड़ने, उन पर मुकदमा चलाने तथा उन्हे प्रत्यार्पित करने में एक–दूसरे की मदद करे।
4. अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारणों को खत्म करने हेतु प्रयास करे तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील रहे।
5. आतंकवाद के निवारण तथा उसे दण्डित करने के लिए 1937 का कन्वेंशन।
6. ऑर्गेनाईजेशन ऑफ अमेरिका स्टेट्स का सन् 1971 में सम्पन्न कन्वेंशन।
7. आतंकवाद को रोकने के बारे में 1977 का यूरोपीयन कन्वेंशन।
8. सन् 1978 में पारित संयुक्त राष्ट्र संघ का आतंकवाद विरोधी प्रस्ताव।
9. सार्क देशों का ''कन्वेंशन आन द सप्रेशन ऑफ टेररिज्म''।
10. बन्धक बनाये जाने के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा दिसम्बर 1979 का इण्टरनेशनल कन्वेंशन।
11. आणविक सामग्री की भौतिक सुरक्षा पर कन्वेंशन (वियेना, 1980)
12. खोज के उद्देश्य से निर्मित प्लास्टिक विस्फोटकों के विपणन पर कन्वेंशन (मांट्रियल, 1991)

13. आतंकवादी बमबारी के विरोध में निर्मित अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (1997)

14. आतंकवादी को वित्तपोषण करने के विरोध में निर्मित अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (1999) आदि।

15. **अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व वाले व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध तथा उससे बलात् छीना छपटी का रूप अख्तियार करने वाले आतंकवादी कृत्यों के निवारण और उन्हें दंडित करने हेतु 1971 का कन्वेंशन –** "अमेरिकी राज्यों के संगठन की महासभा ने 25 जनवरी से 2 फरवरी 1971 तक वाशिंगटन में आयोजित इस अधिवेशन में 6 अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व वाले और व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध तथा उससे बलात् छीना–झपटी का रूप धारण करने वाले आतंकवादी कृत्यों के निवारण और उन्हें दंडित करने के लिए कन्वेंशन को स्वीकृती दी।"[362] इस कन्वेंशन में एक प्रस्तावना और 13 धारायें हैं, प्रस्तावना इस पर बल देती है कि अमेरिकी राज्यों के संगठन की महासभा ने अपने 13 जून 1970 के प्रस्ताव संख्या 4 में आतंकवादी कृत्यों विशेषतः व्यक्तियों के अपहरण तथा इस अपराध के क्रम में उनसे बलपूर्वक छीना–झपटी की निन्दा की और ऐसे आपराधिक कृत्यों को गम्भीर आम अपराध घोषित किया है। प्रस्ताव में यह भी बताया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत विशेष संरक्षण के अधिकारी व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक कृत्य बढ़ते जा रहे हैं और इन कृत्यों से राज्यों के बीच सम्बन्धों के लिए जो परिणाम निकल सकते हैं। उनके कारण यह कृत्य अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के हो जाते हैं।

16. **आतंकवाद को रोकने के बारे में 1977 का यूरोपियन कन्वेंशन –** "यूरोपीय देशों के कानूनी सहयोग से आतंकवाद को रोकने के लिए यूरोपियन कन्वेंशन की रचना हुई जिस पर स्ट्रासबोर्ग में 27 जनवरी 1977 को हस्ताक्षर हुए कन्वेंशन में 16 धारायें और एक भूमिका है।"[363] जैसा कि भूमिका में बतलाया गया है कि कन्वेंशन का उद्देश्य ऐसे प्रभावी उपाय करना था जिनसे यह निश्चित किया जा सके कि आतंकवादी कृत्यों के कर्त्ता मुकदमें तथा दण्डों से नहीं बच सकेंगे।

17. **भाड़े का सैन्यवाद, एक अन्तर्राष्ट्रीय अपराध –** 12 दिसम्बर 1973 को महासभा ने घोषण की कि उपनिवेशवादी और विदेशी गुलामी के जुए को उतार फेंकने और स्वाधीनता एवं स्वतन्त्राता के लिए राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन में संघर्षरत जनता के विरूद्ध, उपनिवेशवादी और नस्लवादी हुकूमतों द्वारा भाड़े के सैनिकों का प्रयोग आपराधिक कृत्य माना जायेगा और भाड़े के सैनिक अपराधियों की भाँति ही दंडित होंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 34वें सत्रा के अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर बहस करने के बाद एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार किया। इसमें सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद

---

362 डॉ. आर.बी.सिंह, "भारत में आतंकवाद", 2010, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, फोन 23247003, पृष्ठ संख्या – 317

363 वही, पृ.सं. – 318

की उन सारी कार्यवाहियों की भर्त्सना की गयी, जिनसे मानवीय जीवन खतरे में पड़ जाता है और मूलभूत मानवीय अधिकार दांव पर लग जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उपनिवेशवादी, नस्लवादी और विदेशी आधिपत्य वाली सरकारों का बनना और आतंकवादी गतिविधियाँ जारी रखने और लोगों के आत्मनिर्णय, स्वाधीनता और अन्य मानवीय अधिकारों व स्वतंत्रताओं को ठुकराने की भर्त्सना की। प्रस्ताव में समस्त देशों से अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारणों को समाप्त कर डालने के लिए सहयोग की अपील की गयी। "महासभा ने सभी देशों से अपील की है कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के उन्मूलन और बचाव हेतु सूचनाओं के आदान–प्रदान, विशेष संधियों या अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादियों पर अभियोजन का प्रत्यार्पण के लिए द्विपक्षीय समझौतों द्वारा परस्पर सहयोग को और अधिक मजबूत करें।"[364]

आतंकवाद समाप्ति के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

आतंकवाद के निवारण तथा उसे दण्डित करने के उद्देश्य से विश्व के सभी देश प्रायः एक जुट होकर इससे निपटने के उपाय खोज रहें है। कुछ महत्त्वपूर्ण समझौते इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है –

1. "1 नवम्बर से 16 नवम्बर 1937 में जिनेवा में आतंकवाद के निवारण के लिए एक कान्फ्रेन्स हुई और आतंकवाद से निपटने का चार्टर तैयार हुआ।"[365]
2. अमेरिका राज्यों के संगठन ओ.ए.एस. की महासभा ने 25 जनवरी से 2 फरवरी 1971 तक वाशिंगटन में आयोजित अपने अधिवेशन में 6 अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व वाले आतंकवादी कृत्यों के निवारण और उन्हें दंडित करने के लिए कन्वेंशन को स्वीकृति दी।
3. आतंकवाद को रोकने के लिए 1977 में स्ट्रासबोर्ग में यूरोपीय कन्वेंशन हुई।
4. आतंकवाद के मसले और आतंक को रोकने की दिशा में 7 सितम्बर 2001 को भारत–रूस संयुक्त कार्यदल गठित हुआ।
5. "6 नवंबर 2001 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमिर फतिन के बीच आतंकवाद से निपटने के लिए घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर हुये।"[366]
6. सार्क का 11वां शिखर सम्मेलन 4 से 6 जनवरी 2002 तक काठमाण्डु में सम्पन्न हुआ।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रयास

"संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकवाद के विरूद्ध प्रत्यक्ष रूप से कई प्रयास किये यद्यपि वह उतना सफल नहीं रहा। इसकी असफलता का प्रमुख कारण है विश्व समुदाय में एकजुटता का अभाव तथा इसके द्वारा लिये गये निर्णय को लागू

[364] वही, पृ.सं. – 319

[365] डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव, "आतंकवाद का समकालीन परिदृश्य : स्वरूप एवं समस्यायें", 2011, ओमेगा पब्लिकेशन्स, 4378/4बी, जी–4 जे.एम.डी. हाउस, गली मुरारीलाल, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, पृष्ठ संख्या – 112

[366] वही, पृ.सं. – 112

न करवा पाना''[367] सर्वप्रथम 1972 के अधिवेशन में एक समिति का गठन किया जिसको आतंकवादी गतिविधियों का अध्ययन करने, रिपोर्ट पेश करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया, इसी प्रकार 1976 की साधारण सभा में एक अस्थायी समिति का गठन हुआ जिसको बन्धक बनाये गये व्यक्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। जिसे 1978 से लागू किया गया।

1981 तक विश्व समुदाय को यह आभास लग चुका था कि इस प्रायोजित आतंकवाद को रोकना उसके समक्ष एक चुनौती है। इस वजह से 4 दिसम्बर 1989 को एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया जिसमें आतंकवादियों की भर्ती, वित्तीय और प्रशिक्षण पर विचार–विमर्श किया परन्तु फिर भी आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकी।

''9 दिसम्बर 1994 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अन्तर्गत आतंकवाद पर नियन्त्रण करने के उद्देश्य में मनी लाउन्डरिंग, तस्करी पर सभी देशों का सहयोग होना चाहिए। इसके लिए प्रत्यार्पण संधि की आवश्यकता पर बल दिया। इसी तरह अक्टूबर 2001 के सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसके अन्तर्गत यदि कोई देश या संगठन प्रायोजित आतंकवाद का दोषी पाया गया तो उसके विरूद्ध आर्थिक, राजनैतिक और सैन्य प्रतिबंध लगाया जायेगा।''[368] सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य जो आतंकवाद के विरूद्ध कारगर साबित हो सकता है वह है– **सामूहिक सुरक्षा का सिद्धान्त।** जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कहा कि **'एक सब के लिए, सब एक के लिए'** के रूप में कार्य करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ आतंकवाद के विरूद्ध विश्व को ऐसा करने की क्षमता रखता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ का नेतृत्व

राष्ट्र संघ को इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या को देखते हुए निश्चय ही विश्व संस्था मानना होगा, लेकिन उसका व्यवहार कभी भी इस स्तर का नहीं रहा है। कितनी अजीब बात हैं राष्ट्र संघ आज अफगानिस्तान सरकार को लादेन को अमेरिका के हवाले कर देने का आदेश देता था जबकि अमेरिका उसके विरूद्ध एक भी ठोस सबूत पेश करने में सफल नहीं हो पाया है जबकि इसी राष्ट्र संघ ने भारत द्वारा कश्मीर में पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों की हरकतों के कई प्रमाण दिये जाने के बावजूद भी आज तक कुछ करना तो दूर, सार्थक प्रतिक्रिया तक व्यक्त नहीं की। ''आज पूरा विश्व यह जानता है कि दाऊद इब्राहिम ने मुम्बई में बम विस्फोटों द्वारा सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था और उसी के संरक्षण और सहयोग से कई आतंकवादी संगठन भारतीय कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का संचालन कर रहे है। जिस प्रकार लादेन अमेरिका के लिए मोस्ट वांटेड था, वैसे दाऊद इब्राहिम भारत के लिए है।

---

[367] संजय कुमार, गुलाब चन्द्र ललित, ''राष्ट्रीय सुरक्षा (मुद्दे और चुनौतियाट्ट)'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, दूरभाष 011–23255141, पृष्ठ संख्या – 204

[368] वही, पृ.सं. – 204

आज वह पाकिस्तान में रह रहा है और वहीं से अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहा है तो फिर राष्ट्र संघ पाकिस्तान को दाऊद को भारत के हवाले करने का आदेश क्यों नहीं देता है? राष्ट्र संघ जैसी विश्व संस्था के द्वारा जब तक ऐसा भेदभाव किया जाता रहेगा, आतंकवाद के सम्पूर्ण विनाश की बात का कोई असर होने वाला नहीं है।''[369]

अन्तर्राष्ट्रीय योजना और क्रियान्वयन

''सीधे शब्दों में कहा जाए तो आतंकवाद राष्ट्रीय हो या अन्तर्राष्ट्रीय, किसी एक देश को उसको उखाड़ फेंकने की 'ठेकेदारी' नहीं दी जा सकती है। जैसा कि अब अमेरिका ऐसी ठेकेदारी लेना चाहता है।''[370] आतंकवाद क्या है, उसके संगठन किन–किन देशों में कार्यरत हैं, उनकी गतिविधियाँ कितनी आपत्तिजनक हैं, किन–किन सरकारों का आतंकवादी संगठनों के सिर पर हाथ है, कहाँ, कैसी कार्यवाही, कब की जानी है, इन सबका निर्णय अकेला राष्ट्र नहीं कर सकता है चाहे वह अपने–आपको कितनी बड़ा या बलशाली और महत्त्वपूर्ण माने। होना तो वास्तव में यह चाहिए कि राष्ट्र संघ के नेतृत्व में या तो महासभा में पूरी तरह से बहुमत के आधार पर 11, 15 या कितने भी राष्ट्रों की समिति बनाई जाए या आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को उन्हीं क्षेत्रों के देशों द्वारा मनोनीत किया जाए। साथ ही इस समिति को इस सम्बन्ध में सभी निर्णय करने का सर्वाधिकार दिया जाए। इसी समिति को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि आतंकवाद विरोधी अभियान में कौन देश धन, हथियार और मनुष्यों का सहयोग करेगा। यह सहयोग भी वास्तव में राष्ट्र की आर्थिक एवं सैनिक शक्ति के आधार पर लिया जाना चाहिए। अगर यह योजना इसी प्रकार क्रियान्वित की जाए तो शक्ति के आधार पर आतंकवाद विरोधी योजना सफल बनाने का एक सार्थक प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि तब ही व्यक्तियों के स्वार्थों पर आतंकवाद को समाप्त करने के उद्देश्य को वरीयता दी जा सकती है।

आतंकवादी संगठनों पर अंकुश के उपाय

''जनवरी 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा मे आतंकवादी संगठनों को मिलने वाली वित्तीय मदद रोकने के लिए एक समझौता मंजूर किया। इससे अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ जारी संघर्ष में तेजी आने की सम्भावना है।''[371] इस समझौते का नाम वित्तीय मदद रोकने का अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है। ''इस समझौते के तरह संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए आतंकवादी संगठनों को वित्तीय मदद मुहैया कराने में रिकॉर्ड वोट की कार्यवाही को एक अपराध करार देना अनिवार्य हो

---

[369] डॉ. मानचन्द खंडेला, ''अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद'', 2011, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, 807, व्यास बिल्डिंग, चौड़ा रास्ता, जयफर – 302003 (राज.), फोन 0141–2578159, पृष्ठ संख्या – 101

[370] वही, पृ.सं. – 101

[371] डॉ. धीरेन्द्र द्विवेदी, संजय कुमार, अनुराग जायसवाल, गुलाबचन्द्र ललित, ''अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति'', 2006, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली – 110094, पृष्ठ संख्या – 199

जाएगा।''[372] इसके अलावा सदस्य देशों को इस तरह की वित्तीय सहायता को जब्त करना भी जरूरी हो जाएगा। सभी सदस्य देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादी संगठनों को किसी भी जरिए से अधिक आर्थिक मदद न मिले। सदस्य देशों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि धार्मिक रंगभेदी या राजनीतिक आधारों पर अपनी आपराधिक कार्यवाही को उचित ठहराने वाला कोई व्यक्ति या समूह इस तरह की वित्तीय मदद का इस्तेमाल नहीं कर सके।

''संयुक्त राष्ट्र महासभा से यह समझौता मंजूर किया गया। इसके पक्ष में 149 वोट पड़े, समझौते के खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा जबकि लेबनान और सीरिया मतदान के समय अनुपस्थित रहे।''[373]

उपरोक्त सभी कन्वेंशन अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो पा रहें है क्योंकि ये या तो क्षेत्रीय है अथवा किसी विशिष्ट उद्‌देश्य से सम्पन्न हुए है। इतना ही नहीं, इनमें इस बात की भी छूट है कि जिस देश का अपराधी है यदि वह देश इसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे प्रत्यार्पण हेतु विवश नहीं किया जा सकता। इसी तरह अमेरिकी देशों के कन्वेंशन एशिया व अफ्रीकी देशों पर प्रभावी नहीं हो सकते।

4.1.2. राज्यस्तरीय–सरकारी और गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा (At State Level-State and Non-State Actors)

देश में आन्तरिक सुरक्षा के लिये नया ढ़ट्टाचा[374]

केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने नई दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरों सेटेनरी एंडोवमेंट पर लेक्चर देते हुए देश में नये सुरक्षा ढ़ाट्टचे का जो खाका प्रस्तुत किया है, वह काफी तर्कपूर्ण और भरोसा जगाने वाला है। इससे अपने मंत्रालय के कामकाज पर उनकी गहरी पकड़ दिखाई देती है। मुम्बई हमले के बाद जबसे उन्होंने गृह मंत्रालय की कमान संभाली है, उन्हें देश की सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं की बारीकी और गहराई में जाकर उन्हें समझते और सुलझाते हुए देखा गया है। इस व्याख्यान में एक साल की इसी मेहनत और अनुभव का निचोड़ सामने आया है और इसीलिये यह कुछ जरूरी बुनियादी बदलावों की वकालत करता है। यह देखकर ताज्जुब होता है कि करीब दो–तीन दशक से लगातार किसी–न–किसी रूप से आतंकवाद की समस्या से जूझते रहने के बावजूद देश में एकीकृत आतंकवाद विरोधी सुरक्षा ढ़ाट्टचे का विकास नहीं हो सका। जब–जब चुनौतियाँ और कमियाँ सामने आई, हमने कभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कभी राष्ट्रीय जाँच एजेंसी जैसी कई व उच्चस्तरीय संस्थायें तो गठित कर ली, लेकिन उनके कामकाज में आपसी समन्वय का ध्यान नहीं रखा। ऐसे में वे सारी विसंगतियाँ पैदा होनी ही थी जिनकी ओर

---

[372] वही, पृ.सं. – 199

[373] Aakrosh, Journal, Vol. 8, No. 27, April 2005, Page – 9

[374] 25 दिसम्बर 2009, शुक्रवार, दैनिक भास्कर, पानीपत, पृष्ठ संख्या – 8

गृहमंत्री ने ध्यान दिलाया है। अब उन्होंने एक 'राष्ट्रीय आतंक निरोधी केन्द्र' (NCTC) बनाने का विचार सामने रखा है, जो 2010 तक स्थापित हो जायेगा।

गृहमंत्रालय के काम के बट्टवारे का विचार नया नहीं है। इससे पहले भी आन्तरिक सुरक्षा का जिम्मा गृहमंत्रालय के अधीन एक स्वतन्त्र राज्यमंत्री को सौंपा गया था। ऐसे फैसले अभी तक आमतौर पर राजनीतिक कारणों से लिये जाते रहे हैं। गृह मंत्री का प्रस्ताव विचारणीय है कि गृह मंत्रालय के तहत आने वाले ऐसे विषयों को, जिनका आन्तरिक सुरक्षा से सीधा संबंध नहीं है, एक अलग मंत्री देखे ताकि गृहमंत्री पूरी तरह आन्तरिक सुरक्षा से जुड़े मसलों पर ध्यान दे सके। असली समस्या वही है जिसका जिक्र गृहमंत्री ने अपने व्याख्यान के अन्त में किया है: ढर्रा और लापरवाही। आखिर संस्थायें बनाने और उन्हें आपस में जोड़ने से क्या होगा, अगर वही होना है **जो मुम्बई पुलिस के भीतर 26/11 के शहीद हेमन्त करकरे के बुलेट प्रुफ जैकेट को लेकर हो रहा है।** सबसे बड़ी जरूरत व्यवस्था के भीतर कार्य संस्कृति बदलने की है। यह काम सुरक्षा ढ़ाट्टचे को मुकम्मल बनाने से कहीं ज्यादा कठिन होगा।

वैश्विक आतंकवाद और भारतीय विदेश नीति

आतंकवाद आज विश्वव्यापी समस्या बन गया है। अधिकतर देश इससे जूझ रहे हैं। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। इस समस्या से पीड़ित देश एक–दूसरे की मदद के लिए अपनी विदेश नीति में परिवर्तन कर रहे हैं। भारत भी इन देशों में शामिल है। डब्ल्यू. टी. सी. (WTC) पर हमले के बाद अमेरिका ने भी भारत के प्रति अपना रूख परिवर्तित किया है। वह हर उस देश के साथ सहयोग की बात कर रहा है जहाँ आतंकवादी हिंसक वारदातें कर रहे हैं। अमेरिका के बदले इस रूख के कारण यूरोपीय यूनियन भी भारत के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल कर भारत से नये रिश्तों को वरीयता दे रहा है। आतंकवाद से लड़ाई में भारत की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। इस विषय पर विश्व के अधिकतर बड़े देश भारत की भूमिका से सहमत हैं। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित देश कहीं–न–कहीं भारत का उतना समर्थन नहीं कर रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिये। इसे भारतीय विदेश नीति की असफलता कहा जा सकता है क्योंकि आज भारत में जिस तरह का भी आतंकवाद है, उसकी जड़ों में कहीं–न–कहीं हमारे पड़ोसी देश भी शामिल हैं। वर्तमान परिदृश्य में आवश्यकता है कि भारत अपनी विदेश नीति निर्धारण में आतंकवाद से जंग को वरीयता दे। इस संबंध में यदि कठोर कदम उठाने पड़े तो भी पीछे नहीं हटना चाहिये क्योंकि अब ऐसे हालात बन गये हैं जिन्हें यदि समय रहते बदला नहीं गया तो भविष्य में परिणाम अत्यन्त भयावह हो सकते हैं।

WTC पर हमले के बाद भारत व अमेरिका का बदला रवैया

एक दशक पूर्व शायद ही किसी ने कल्पना की हो कि भारत और अमेरिका एक–दूसरे के करीब आयेंगे। सर्वविदित है कि शीतयुद्ध के दौर में भारत सोवियत संघ के बहुत ज्यादा निकट था। सोवियत संघ ने भी हर प्रमुख मुद्दे पर भारत का खुलकर समर्थन किया था। भारत को एक सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी सोवियत संघ की अहम भूमिका थी। इस दौर में अमेरिका ने भारत की चिन्ताओं को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान को हर संभव सैन्य एवं

आर्थिक मदद उपलब्ध कराई। कश्मीर विवाद पर अमेरिका का रूख पाकिस्तान के पक्ष में ही लगता था। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ने भारतीय बाजार को अपने उत्पादों के उपयुक्त माल, भारत के साथ सम्बंधों में नरमी लाना शुरू किया।

भारत में 90 के दशक से आतंकवादी घटनायें तेजी से बढ़ने लगी। जम्मू–कश्मीर इसका सबसे ज्यादा शिकार हुआ। आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी से हिन्दुओं को सुनियोजित तरीके से भगा दिया। भारत से रिश्तों में सुधार के बाद भी अमेरिका ने इन घटनाओं की तब उस तरह निंदा नहीं की थी जितनी उसे करनी चाहिये थी। कहीं–न–कहीं इस दौर में भी अमेरिका भारत में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के प्रति नरम ही दिखाई देता था।

11 सितम्बर 2001 अमेरिका के लिये अब तक का सबसे काला दिवस बना। इस दिन इस्लामिक आतंकवादियों ने अमेरिका के 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर' (WTC) पर हमला कर उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूत कर दिया। इस घटना से अमेरिका के साथ–साथ पूरा विश्व सहम गया। हजारों बेगुनाहों की जान गई। अमेरिका ने तत्काल आतंकवाद के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी। उसकी विदेश नीति में उसी क्षण परिवर्तन दिखने लगा। वह अपने परम मित्रों की सूची में शामिल पाकिस्तान को भी सन्देह की नजर से देखने लगा। आतंकवाद से ग्रसित भारत उसे मित्रा नजर आने लगा। इस घटना के बाद अमेरिका ने भारत के साथ सामरिक और व्यापारिक संबंधों को तेजी से सुधारना शुरू कर दिया। आज संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। वह चीन के बाद भारत का दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। भारत में जारी आतंकवाद पर अमेरिका के रूख में परिवर्तन आया है। उसने भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे कुछ संगठनों को प्रतिबंधित किया है। **सन् 2008 में अमेरिका ने लश्कर–ए–तैयबा के 4 प्रमुख आतंकियों हाफिज मोहम्मद सईद, रहमान लखवी, हाजी मोहम्मद अशरफ एवं मोहम्मद अहमद बहाजिक की सम्पत्ति जब्त कर ली।**

अमेरिका की आतंकवाद के खिलाफ नीति

1. आतंकवाद प्रभावित देशों के साथ सहयोग और सहायता।
2. आतंकवादियों को किसी भी तरह की रियायत नहीं।
3. खुफिया एजेंसियों को पहले की तुलना में ज्यादा अधिकार।
4. आतंकियों के वित्तीय स्त्रोतों पर नजर।
5. आतंकवादियों की मदद करने वाले देशों को निशाना बनाना।,
6. संयुक्त कार्यबल के गठन पर जोर।
7. पहले हमले की नीति।

भारत द्वारा आतंक का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए जरूरी कदम (उपाय)

1. नेवी, तटरक्षक और तटीय पुलिस के लिए एकीकृत कमांड तैयार की जानी जाहिए। अभी इन तीनों अंगों के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं होती है।

2. ''एंटी टेरर फेडरल एजेंसी (ATFA) का गठन हो, जिसके कामकाज में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप न किया जा सके।''[375]
3. प्रमुख शहरों में एनएसजी (NSG) यूनिट का गठन किया जाये।
4. वीआईपी सिक्योरिटी की समीक्षा की जानी चाहिए। कई नेता बिना किसी खतरें या धमकी के बावजूद रूतबा झाड़ने के लिए ऐसी सुरक्षा साथ रखते हैं।
5. कारगर आपात व्यवस्था और आपदा राहत प्रणाली का गठन किया जाना चाहिए।
6. खुफिया एजेंसियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिससे समय रहते आतंकी योजना का पता लगाया जा सके।
7. पुलिस बल सुधार पर तुरंत प्रभाव से अमल करना चाहिए, जिससे पुलिस नियुक्ति को राजनेता प्रभावित न कर सके।
8. पुलिस बलों की रिक्तियों को तेजी से भरा जाए।

''विस्फोटकों को शक्तिहीन करने के लिए बम विरोधक दस्तों के विशेषज्ञों की सेवाएँ लेना आवश्यक है, क्योंकि न तो यह काम सामान्य नागरिक कर सकता है और न ही उसे करना चाहिए पर कहीं विस्फोटक पड़ा हुआ है, यह सूट्टघने की क्षमता तो नागरिकों को ही अपने में विकसित करना होगा।''[376] स्टेट की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने नागरिकों को उनके सैन्य कर्त्तव्यों के लिए प्रशिक्षित करें। आतंकवादी हमले इंटेलिजेंस फेल्योग के कारण कम और नागरिक उदासीनता के कारण ज्यादा सफल होते हैं। नागरिकों की उदासीनता ज्यादा आतंकित करने वाली है।

आतंकवाद निरोधक कानून टाडा[377] (TADA)

1985 – आतंकवादी व अलगाववादी ताकतों से निपटने के लिए भारत सरकार ने सन् 1985 में यह कानून बनाया था। आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधि रोकथाम अधिनियम (Terrorists and Disruptive Activities Prevention Act) जो संक्षेप में ''टाडा'' (TADA) कहा जाता है, बनाने के पीछे सरकार की मंशा थी कि इस कानून से आतंकवादी गतिविधियों को नियन्त्रित करने में मदद मिलेगी, पर बाद में आतंकवादियों की गतिविधियों की गम्भीरता को देखते हुए यह अनुभव किया गया कि एक और कानून पास किया जाये, इसलिए सन् 2002 में टाडा के स्थान पर एक नया कानून 'पोटा' (Prevention of Terrorism Act)पास किया गया।

टाडा में आतंकवादियों के प्रति कठोर रूख अपनाये, उन्हें पकड़ने और दण्डित करने के लिए मनोनीत (Designated) विशेष अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान था इन विशेष न्यायालयों को अभियुक्त व्यक्तियों के सामान्य अधिकारों में

---

375 डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र, ''आतंकवाद व आपदा प्रबंधन'', 2010, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, पृष्ठ संख्या – 156

376 वही, पृ.सं. – 156–157

377 डॉ. आर.बी.सिंह, ''भारत में आतंकवाद'', 2010, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, फोन 23247003, पृष्ठ संख्या – 306

कटौती करने का अधिकार था। यह कानून जमानत की इजाजत नहीं देता था। अदालत प्रमाण (Evidence) का भार अभियुक्त पर थोपती थी तथा पुलिस को दिये गये इकवालियाँ बयान को सबूत के रूप में स्वीकार करती थी। टाडा अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करके सीधे विशेष न्यायालय के सामने पेश किया जाता था जो अभियुक्त को 6 माह से लेकर एक साल तक पुलिस रिमांड पर सौंप सकता था। एक साल पर आरोप पत्र भी दाखिल करना जरूरी नहीं था। टाडा को सन 1987, 1989 एवं 1993 में संशोधित भी किया गया था। सन् 1985 से 1995 तक कुल 70,411 व्यक्तियों को इस कानून के अन्तर्गत पकड़ा गया था जिनमें अधिकांश लोग छूट गये थे केवल कुछ लोगों को ही दण्डित किया गया था।

आतंकवाद निरोधक अधिनियम[378] (पोटा) – 2002 (Prevention of Terrorism Act. (POTA)- 2002)

आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए कठोर कानून की बहुत जरूरत थी इसी दृष्टि से केन्द्र सरकार ने यह कानून बनाया था। विपक्षी पार्टियों ने इस आतंकवाद निरोधक अध्यादेश (पोटा) का भरपूर विरोध किया और राज्य सभा में इसे पारित होने से रोक दिया। इससे विवश होकर केन्द्र सरकार को लोकसभा और राज्य सभा की एक सांझा बैठक बुलानी पड़ी। 26 मार्च 2002 को संसद के दोनों सदनों की तीसरी संयुक्त बैठक बुलाई गयी। इस बैठक में काफी गर्मागरम बहस हुई। इसके बाद हुए मत विभाजन में तमाम एक जुटता के बावजूद विपक्ष की हार हुई। यह अहम विधेयक 296 विरोधी मतों में मुकाबले 425 मतों से पारित हो गया। गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने विधेयक की पक्षधरता में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य के बदले माहौल और सीमा पार से प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों की चुनौती के कारण देश में पैदा हुई युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए पोटा जैसे कानून की आवश्यकता है। उन्होंने इसके दुरूपयोग को लेकर विपक्ष द्वारा उठाई जा रही शंकाओं को निर्मूल बताया और कहा कि इसका दुरूपयोग करने वालों, पुलिस व अन्य अधिकारियों के खिलाफ पोटा में दण्ड का प्रावधान है।

एक अन्य अवसर पर पोटा जैसे कानून की वकालत करते हुए तत्कालीन केन्द्रीय कानून मंत्री श्री अरूण जेटली ने कहा था कि देश आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह एक जुट है और पोटा जैसे कानून की आवश्यकता को अनुभव करता है क्योंकि 11 सितम्बर के आक्रमण के बाद अमेरिका जैसा देश न केवल बाह्यकारी प्रस्ताव अपना चुका है बल्कि देशवासियों से आतंकवाद का विरोध करने की अपील के साथ ही इस धमकी से निपटने के लिए उपयुक्त कानून बनाये जाने के लिए भी कह चुका है।

पोटा विधेयक की खास बातें – इसके प्रावधान निम्नलिखित है –

1. किसी भी घातक हथियार से किया गया अपराध आतंकवाद माना जायेगा।

[378] वही, पृ.सं. – 307

2. किसी आतंकवादी संगठन को समर्थन देना, आतंकवादियों से हमदर्दी रखने वाले लोगों को संबोधित करना और कोई ऐसी बैठक आयोजित करना जिसमें आतंकवादी संगठनों और इसकी गतिविधियों को मदद करने की बात हो, अपराध माना जायेगा।
3. आतंकवादी संगठनों और उनके हमदर्दों की सम्पत्ति जब्त कर ली जायेगी।
4. संदिग्ध व्यक्तियों की तीन महीने के लिए बिना किसी अभियोग के हिरासत में रखा जा सकता है और यदि विशेष न्यायाधीश की अनुमति मिले तो तीन अन्य महीने तक उन्हें ऐसी ही स्थिति में रखा जा सकता है।
5. फलिस अधिकारी अदालत में संदिग्ध व्यक्ति के हस्तलेखों, अंगुलियों के निशान, पैरों के निशान, खून, थूक, वीर्य और बाल के नमूनों की माँग कर सकता है। यदि ये नमूने नहीं दिये गये तो इसे अपराधी के विरूद्ध कार्यवाही का आधार माना जायेगा।
6. विशेष परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध की स्वीकृति मान्य होगी।
7. किसी आरोपी की जाँच का काम पुलिस उपाधीक्षक या उससे ऊपर स्तर का अधिकारी ही करेगा।
8. फलिस के सामने इकबालिया बयान 48 घंटों के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराना होगा। इसके बाद आरोपी को चिकित्सकीय जाँच के लिए भेज दिया जायेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि जाँच के दौरान उसे प्रताड़ित तो नहीं किया जायेगा।
9. आरोपी के कानूनी प्रतिनिधि (वकील) को तफ़्तीश के दौरान कुछ मौकों पर उसके साथ रहने की इजाजत दी जायेगी लेकिन उसे हमेशा उसके साथ नहीं रहने दिया जायेगा।
10. फलिस अधिकारियों को अपने पद का दुरूपयोग करते हुए पाये जाने पर उन्हें दण्डित किया जायेगा और आरोपियों को मुआवजा देना होगा।

राष्ट्रीय आतंकवाद–निरोधक केन्द्र (N.C.T.C. – National Counter Terrorism Centre) की प्रासंगिकता[379]

आतंकवादी हमला चाहे मुम्बई के ताज होटल, जयफर, दिल्ली में संसद भवन, बनारस, गुजरात अथवा किसी अन्य राज्य में क्यों न हो, माओवादियों और नक्सलवादियों की बढ़ती सक्रियता झारखण्ड, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश, बिहार आदि किसी भी राज्य में हो और जातीय अथवा धार्मिक उन्माद चाहे किसी भी राज्य में क्यों न भड़के, सुरक्षा को लेकर किसी–न–किसी रूप में ऊट्टगली केन्द्र की तरफ जरूर उठती हैं और राज्य सरकारें भी जरूरत के समय सीआरपीएफ, बीएसएफ अथवा अन्य अर्द्धसैनिक बलों की माँग करती रहती है ऐसी स्थिति में यदि केन्द्र

[379] महेन्द्र जैन, ''प्रतियोगिता दर्पण'', सितम्बर 2012, पृष्ठ संख्या – 92

अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए आगे आ रहा है तो यह राज्यों की प्रभुसत्ता और संप्रभुता में हस्तक्षेप कैसे हो सकता है?

एनसीटीसी के गठन के समर्थन में कहा गया है कि आतंकवाद से संबन्धित अभिसूचनाओं के लिए यह सर्वोच्च संस्था होगी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधीन काम करेगी इसे न केवल अभिसूचनाओं के एकत्रीकरण, उनमें सामंजस्य स्थापित करना और उन्हें कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों और सम्बन्धित अधिकारियों को भेजना होगा वरन् इसे आतंकवाद में लिप्त लोगों की तलाशी और उनकी गिरफ्तारी का भी अधिकार होगा। संगठन को यह अधिकार प्रचलित गैरकानूनी गतिविधि (निवारक) कानून के अन्तर्गत प्रदत्त किया जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई को बल और दिशा के लिए एनसीटीसी की तत्काल आवश्यकता है। सच्चाई यह है कि शान्ति व्यवस्था से सम्बन्धित छोटी–से–छोटी घटना से निपटने के लिए राज्य सरकारें केन्द्रीय सहायता और अर्द्धसैनिक बलों की माँग करती हैं अंतर्जातीय संघर्ष हो, सांप्रदायिक दंगे हो, त्यौहारों की व्यवस्था करनी हो, कोई रास्ता रोको या रेल रोको आन्दोलन हो, प्रदेश सरकारे तुरन्त सीआरपीएफ और बीएसएफ की माँग करती है। तब तो वह भूल जाते हैं कि संघीय ढ़ाट्टचे में ऐसी परिस्थितियों से निपटना उनकी जिम्मेदारी है। सभी को यह समझना होगा कि आज देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। यह हमारे अस्तित्व को खत्म करना चाहता है। अर्थव्यवस्था को छिन्न–भिन्न करना चाहता है और समुदायों के बीच दुर्भावना का जहर घोलकर सांप्रदायिक आग लगाना चाहता है। इस खतरे से निपटने के लिए केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत सभी प्रदेशों को काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा भी हो, भारत सरकार की एनसीटीसी बनाने की योजना में खामी तो है ही, अमेरिका में 2004 में एनसीटीसी का गठन हुआ, परन्तु उसकी जिम्मेदारी केवल अभिसूचनाओं के एकत्रीकरण और सामंजस्य तक ही सीमित रखी गई। यहाँ यह संगठन डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के अधीन काम करता है, परन्तु उसे कोई कार्यकारी अधिकार नहीं दिये गए है। जमीनी कार्यवाही की जिम्मेदारी होमलैण्ड सिक्योरिटी विभाग के पास है। इसी प्रकार इंग्लैण्ड में ज्वाइंट टेररिज्म एनालिसिस सेंटर बनाया गया था। इंग्लैण्ड की खुफिया एजेंसी एमआई–5 को भी कार्यकारी अधिकार नहीं दिये गए हैं। जमीनी कार्यवाही काउंटर टेररिज्म कमांड और स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी है।

प्रासंगिकता को लेकर तर्क–वितर्क[380]

अभी देश में आतंकवाद से लड़ने के लिए जितने भी कानून एवं एजेंसियाँ है, क्या उनके माध्यम से आतंकवाद से लड़ा जा सकता है? देश में जो भी कानून है, उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो काफी सफलता मिल सकती है, सिर्फ कानून बनाने से ही आतंकवाद मिटने वाला नहीं

---

[380] वही, पृ.सं. – 94

है। आतंकवाद मिटाने के लिए जो भी कानून है उन पर अमल करने की आवश्यकता है। एनडीए के समय में आतंकवाद से लड़ने के लिए पोटा जैसा सख्त कानून बना था, मगर क्या हुआ? पोटा के रहते हुए ही संसद पर हमला हुआ।

यदि कठोर कानून बनाने मात्रा से ही आतंकवाद समाप्त हो सकता है, तो पोटा के रहते हुए आतंकवाद क्यों नहीं रूका? कानून, तो चाहे जितने भी बना लीजिए, मगर आवश्यकता इस बात की है कि कानूनों पर अमल किया जाए। यदि कानूनों पर ठीक से अमल हो, तो अब तक जितने कानून हैं एवं जितनी एजेंसियाँ है उनसे ही काम चलाया जा सकता है। केन्द्र सरकार को लगता है कि जब किसी राज्य में आतंकी हमला होता है तो उसकी जाँच–पड़ताल में राज्य ठीक से मदद नहीं करते हैं? इस प्रश्न के जवाब में श्री वासुदेव आचार्य का कहना है कि ऐसा कहना ठीक नहीं है कि आतंकी गतिविधियों की जाँच–पड़ताल में केन्द्रीय एजेंसियों को राज्यों का पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है। यदि कोई राज्य ऐसा करता है तो उसे नहीं करना चाहिए। केन्द्र सरकार आतंकी खतरे के सन्दर्भ में जो भी सूचनाएँ एवं हिदायतें राज्यों को देती है, उस पर राज्यों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इन सब समस्याओं के बीच आज सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही है कि हम कोई भी ऐसा कानून नहीं चाहते जिससे किसी भी तरह संघीय ढ़ाट्टचे पर आघात हो।

जब आतंकवाद रोकने के लिए केन्द्र सरकार प्रयास कर रही है, तो राज्य उसमें बाधा उत्पन्न कर रहें हैं। राज्य सरकारों को यदि लगता है कि केन्द्र उनके अधिकारों का हनन कर रहा है तो वे घोषण करें कि उनके राज्य में अब से जो भी आतंकी हमले होंगे, उसकी जिम्मेदारी वे स्वयं लेंगे उसके लिए केन्द्र सरकार को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। क्या इस बात के लिए राज्य सरकारें तैयार होंगी? स्वाभाविक सी बात है कि जब राज्य सरकारें इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेगी तो इसके लिए प्रयास केन्द्र सरकार को ही करना होगा। एनसीटीसी के मामले को कुछ लोग सियासी अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही दिन मे एक ही तरह से यदि कई राज्यों में विस्फोट होता है, जो उसकी जाँच कोई राज्य कैसे कर सकता है? उदाहरण के तौर पर एक ही दिन महाराष्ट्र के मालेगाँव और गुजरात के मोदासा में विस्फोट हुआ मालेगाँव की घटना की जाँच में राज्य सरकार ने अच्छी तरह सहयोग किया।

आज स्थिति यह है कि जब धर्म एवं जाति के आधार पर आतंकवादी घटनाओं की जाँच होगी एवं उसी आधार पर लोगों की गिरफ्तारी होगी, तो आतंकवाद से कैसे निपटा जा सकता है? आज आवश्यकता इस बात की है कि जाति एवं धर्म के नाम पर किसी को प्रश्रय देना बन्द करना होगा। एनसीटीसी को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत् शक्तियाँ हासिल है इसके तहत् केन्द्रीय एजेंसियों को आतंकवाद सम्बन्धी केसों में गिरफ्तारी या तलाशी की अनुमति हासिल है। यह एजेंसी राज्य पुलिस को सम्पर्क में रखेगी, लेकिन किसी ऑपरेशन को शुरू करने से पहले राज्य सरकारों से

इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अगर राज्य सरकारों की बात की जाए तो आतंकवाद की घटनाओं से जुड़ी जाँच में केन्द्र सरकार चाहे तो बिना राज्यों की इजाजत के एक सिपाही तक नहीं भेज सकती है कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जब तक राज्य सरकार से बात कर जाँच की सहमति बनती है, तब तक अपराधी को सूचना मिल जाती है और वह फरार हो जाते है।

केन्द्र सरकार की इच्छा है कि किसी भी आतंकी घटना की जाँच बिना शोर मचाए यदि होगी तो उसमें कामयाबी की सम्भावना बहुत ज्यादा बनती है। शोर मचने से अपराधी सतर्क हो जाता है और जाँच की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। यह सबको पता है कि लोकल पुलिस या स्थानीय प्रशासन इस प्रकार के कार्यों को कभी–कभी अंजाम दे देता है। इस प्रकार की वारदातें भले ही कम होती है, मगर इससे इन्कार तो नहीं किया जा सकता है। राज्यों में आज क्या हो रहा है? यह किसी से छिपा नहीं है। सभी लोग अपनी–अपनी रूचि के हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मामले में जो कुछ भी देखने को मिला उससे तो यही साबित होता है कि वास्तव में एनसीटीसी की जरूरत है। राज्यों को यह बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि यह लॉ एण्ड ऑर्डर का मामला नहीं है।

राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (NCTC) के गठन को मंजूरी

''केन्द्र सरकार ने 12 जनवरी, 2012 को राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (एनसीटीसी) के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी। यह केन्द्र देश में सभी तरह की आतंकवाद निरोधक गतिविधियों के लिए शीर्ष निकाय के रूप में काम करेगा।''[381] इस केन्द्र के माध्यम से आतंकवाद से सम्बन्धित खुफिया सूचना का विश्लेषण करने और सम्बन्धित एजेंसियों को कार्यवाही के लिए सूचना प्रदान करने जैसे कार्यों को व्यवस्थित किया जा सकेगा। एनसीटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं होंगे। ''यह एक केन्द्रीय कार्यालय से ही कार्य करेगा जबकि इसके क्षेत्रीय कार्य को फिलहाल आईबी की मौजूदा शाखाओं के माध्यम से देखा जाएगा।''[382]

क्या है एनसीटीसी?[383]

❖ राष्ट्रीय आतंकवादरोधी केन्द्र (NCTC) राज्य और केन्द्र स्तर पर आतंकवादरोधी कार्यवाही में शामिल खुफिया और सुरक्षा एजेन्सियों के बीच सुरक्षित संचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समर्पित नेटवर्क है।

❖ इसका गठन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए गैर–कानूनी गतिविधि निरोधक कानून के तहत किया गया है।

---

381 उमाकांत सिंह, दीपेश जैन, ''अरिहन्त समसामयिकी महासागर'', मार्च 2012, अरिहन्त मीडिया प्रोमोटर्स, 4577/15, अग्रवाल रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या – 33

382 वही, पृ.सं. – 33

383 राजेश राजन, ''अरिहन्त समसामयिकी महासागर'', मई 2012, अरिहन्त मीड़िया प्रोमोटर्स, 4577/15, अग्रवाल रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या – 62

- ❖ सूचना एकत्र करने के लिए इसमें कोई कर्मचारी नहीं होगा, बल्कि यह अन्य एजेन्सियों की सहायता से सूचनाएँ एकत्रित करेगा।
- ❖ यह केन्द्र अधिशासी आदेश के माध्यम से गठित होगा, जिसे 1 मार्च, 2012 को जारी किया जाना था, परन्तु राज्यों के विरोध के कारण इस पर अभी निर्णय नहीं हो सका है।
- ❖ यह केन्द्र शुरूआत में इन्टेलिजेन्स ब्यूरो के तहत काम करेगा।
- ❖ आईबी का एडिशनल डायरेक्टर स्तर का अधिकारी इसका नेतृत्व करेगा, जो केन्द्रीय गृह सचिव को रिपोर्ट करेगा।
- ❖ आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही के लिए इस केन्द्र के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं होंगे क्षेत्रीय स्तर पर आईबी के केन्द्रों से ही क्षेत्रीय केन्द्रों का काम लिया जाएगा।
- ❖ प्रत्यक्ष कार्यवाही के लिए यह केन्द्र एनआईए के साथ ही राज्य पुलिस की आतंकवादरोधी इकाई का सहयोग लेगा।
- ❖ एनसीटीसी की तीन इकाइयाँ होगी, जो पृथक्क–पृथक्क रूप से खुफिया सूचना एकत्र करने, सूचनाओं का विश्लेषण करने तथा सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर खोज प्रक्रिया चलाएँगी। इन तीनों इकाइयों के अलग–अलग निदेशक होंगे।
- ❖ केन्द्रीय स्तर पर एनसीटीसी के अन्य कर्मचारी आईबी जैसी खुफिया एजेन्सियों से लिए जाएँगे।
- ❖ एनसीटीसी की एक स्टैण्डिग काउन्सिल होगी जिसमें खुफिया एजेन्सियों के अधिकारी शामिल किए जाएँगे।
- ❖ स्टैण्डिंग काउन्सिल संचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा राज्यों के सम्पर्क में रहेगी।
- ❖ काउन्सिल आतंकी धमकियों और चुनौतियों का विश्लेषण करेगी।
- ❖ एनसीटीसी देश के भीतर एवं बाहर सभी प्रकर के मिशनों एवं संस्थाओं से जानकारी हासिल कर सकेगी।
- ❖ एनसीटीसी आतंकवाद से सम्बन्धित सूचनाओं का विस्तृत डाटा बेस बनाएगा।

एनसीटीसी पर विवाद के प्रमुख बिन्दु[384]

- ❖ कानून एवं सुरक्षा राज्य का विषय है, केन्द्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
- ❖ गिरफ्तारी एवं तलाशी के अधिकार से राज्यों की पुलिस भूमिका प्रभावित होगी।

---

[384] वही, पृ.सं. – 63

- ❖ आईबी को एनसीटीसी के समान अधिकर पहले से प्राप्त हैं।
- ❖ एनसीटीसी के लागू होने से केन्द्र–राज्य सम्बन्ध प्रभावित हो सकते हैं।
- ❖ केन्द्र एनसीटीसी के माध्यम से, राज्यों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है।
- ❖ एनसीटीसी से भारतीय संघ का मूल ढ़ाट्टचा प्रभावित हो सकता है।

देश की अखण्डता एवं संप्रभुता को बनाए रखने के लिए केन्द्र–राज्य सम्बन्धों को बदलते समय के साथ परिभाषित करना आवश्यक है। तभी एनसीटीसी जैसे केन्द्र स्थापित किए जा सकते है और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में राज्यों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुतः केन्द्र को मानना पड़ेगा कि राज्य भी कानून एवं व्यवस्था को लेकर उतने ही चिन्तित हैं, जितना कि केन्द्र शासन। अतः राज्यों को एनसीटीसी के जिस बिन्दु पर सबसे अधिक विरोध है वह है– इस संगठन को तलाशी तथा गिरफ्तारी का अधिकार दिया जाना। इसके अनुसार जब संगठन आतंकवाद जैसे मसले की जाँच करेगा तो उसे गिरफ्तारी की जरूरत होगी। पुलिस राज्य सरकार के अन्तर्गत है, जिस कारण राज्य सरकारें इसे अपने कामकाज में केन्द्र की दखलअन्दाजी मान रही हैं। गम्भीर प्रयासों को भी केन्द्र सरकार को बढ़ावा देना होगा, तभी दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

एनसीटीसी की स्थापना एवं विरोध की चर्चा के बीच एक प्रश्न यह भी है कि इस बात की कितनी निश्चितता है कि एनसीटीसी से आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगेगी जबकि पिछले प्रयासों के परिणाम निराशाजनक रहे हैं। ऐसी स्थिति में केवल किसी संस्था या समिति के गठन मात्रा से आतंकी हमलों की रोकथाम नहीं की जा सकती है। इसके लिए जमीनी स्तर के प्रयासों को अमल में लाना होगा। अन्यथा परिणाम वही ढ़ाक के तीन पात जैसा ही रहेगा। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता एवं पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता के बल पर ही किसी प्रयास को अन्तिम रूप दिया जा सकता है। अतः एनसीटीसी पर व्याप्त गतिरोध का निराकरण करके तथा सभी प्रशासनिक इकाइयों के सहयोग से ही किसी आतंकवादरोधी केन्!द्र को मूर्त रूप में दिया जा सकता है।

आतंकवाद के विरूद्ध भारत के द्विपक्षीय समझौते

राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में आतंकवाद निरोधक प्रयास में राष्ट्रों द्वारा आपस में द्विपक्षीय समझौतों का भी अधिक महत्त्वपूर्ण योगदान है। "प्रायः सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए द्विपक्षीय समझौते करते हैं। चूँकि आतंकवाद की अब कोई सीमा नहीं रही, इसलिए विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने आतंकवाद रूपी विभीषिका को अवरूद्ध करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय समझौतों में विश्व के सभी राष्ट्र चाहे वह बड़े हों या छोटे, सम्पन्न हो या विपन्न भागीदारी को देखा जा सकता है। सम्प्रति विश्व में 200 से अधिक राष्ट्र है। राष्ट्रीय सुरक्षा को मुख्य आधार मानते

हुए भारत ने भी अपने सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्त्वपूर्ण राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए है।''[385]

भारत और रूस

भारत और रूस के मध्य वर्षों से आतंकवाद के विरूद्ध द्विपक्षीय समझौते हुए है। ''6 नवम्बर 2001 को मास्को के 'क्रेमलिन पैलेस' के ग्रीन रूम में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद सम्बन्धी 'मास्को घोषणा' पर हस्ताक्षर किये''[386] दोनों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि ''अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए दोहरे मापदंड नहीं अपनाये जाने चाहिए। आतंकवाद का एक ही चेहरा है, फिर मामला चाहे अफगानिस्तान का हो या फिर कश्मीर अथवा चेचन्या का। रूसी राष्ट्रपति फतिन के अनुसार अफगानिस्तान का भविष्य तय करने की प्रक्रिया में भारत को सम्मिलित किया जाना चाहिए।''[387] दोनों ने घोषणा पर हस्ताक्षर किये। हस्ताक्षरित मास्को घोषणा पत्रा में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधान निम्नवत है–

1. अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद सुरक्षा और शान्ति के लिए खतरा और मानवता के प्रति अपराध है इसमें संघर्ष प्राथमिकता है। सभी देशों की मिली–जुली कोशिशों से आतंकवाद से जीत प्राप्त की जा सकती है।
2. आतंकवाद को न्यायोचित नहीं कहा जा सकता, चाहे इसका उद्‌देश्य राजनैतिक, वैचारिक, दार्शनिक, नस्लीय, जातीय या धार्मिक हो।
3. भारत और रूस को पनाह देने वाले, हिमायत करने वाले, पैसा देने वाले, प्रशिक्षण और प्रश्रय देने वाले देशों, लोगों और हस्तियों के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दण्डित करने के पक्षधर है। भारत और रूस के अनुसार आत्मनिर्णय के नारे के नाम पर हिंसक गतिविधियाँ वास्तव में आतंकवाद ही है। अधिकांश मामलों में इनका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर है। आतंकवादियों की ये गतिविधियाँ संयुक्त राष्ट्र के उद्‌देश्यों और सिद्धान्तों के विरूद्ध है।
4. अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की नई चुनौतियाँ या आयाम अपने सभी रूपों परमाणु, रासायनिक, जैविक, साइबर आदि के मूल में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से सम्बद्ध लोगों, संगठित अपराधियों और हथियारों के सौदागरों और आतंकवादियों का गहरा सम्बन्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय स्तर पर और बहुपक्षीय स्तर पर भी नजदीकी संवाद जरूरी है।

---

[385] संजय कुमार, गुलाब चन्द्र ललित, ''राष्ट्रीय सुरक्षा (मुद्‌दे और चुनौतियाट्ट)'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, दूरभाष 011–23255141, पृष्ठ संख्या – 128

[386] वही, पृ.सं. – 128

[387] दैनिक समाचार पत्रा हिन्दुस्तान देश–विदेश, 28 सितम्बर 2007, पृष्ठ संख्या – 11

5. आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की महती भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कानून के मसौदे पर शीघ्र ही विचार–विमर्श पूरा कर लिया जाये।

रूस जैसी महाशक्ति भी आतंक की गिरफ्रत में

सोवियत संघ के विघटन (1991) के बाद इस संघ का सबसे बड़ा देश रूस है। हाल ही के दिनों में रूस ने अपने आप को पुनः महाशक्ति के रूप में विश्वमानचित्रा पर स्थापित कर लिया है। रूस और भारत की दोस्ती काफी फरानी है। भारत को सैन्य रूप से मजबूत करने में सोवियत संघ की अहम भूमिका रही है। रूस विकास पथ पर अग्रसर है। आतंकवाद उसके विकास मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। आतंकवादी वहाँ के कुछ क्षेत्रों में अराजकता उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज रूस के सामने ठीक वैसे ही हालात हैं जैसे भारत के सामने हैं। रूस और भारत दोनों आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर जोर दे रहे हैं।

इस समय रूस की वैश्विक आतंकवाद से ज्यादा अपने देश में जारी आतंकवाद पर नजर है। उसका पहला लक्ष्य देश में अराजकता उत्पन्न कर रहे आतंकियों को खत्म करना है। रूस ने अमेरिका की तरह ही आतंकवाद से निपटने के लिये कठोर नीति अपनाई है। उसके लक्ष्य में वह क्षेत्र है जहाँ से उसे खुद पर हमला होने की आशंका है। रूस भली–भाँति जानता है कि सोवियत संघ के विघटन का कारण उसकी अफगानिस्तान में अपनाई गई नीति थी। वह यह गलती फिर नहीं दोहराना चाहता है। वह कहीं और दखल देने के पूर्व अपने घर में लगी आग को बुझाने का प्रयास कर रहा है। भारत में हो रही आतंकवादी घटनाओं का रूस ने हमेशा विरोध किया है। कश्मीर मामले में रूस भारतीय रूख का समर्थक है। रूस ने भारत को आतंकवाद से मुकाबले में हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। रूस का नैतिक समर्थन भारत के आत्मबल में वृद्धि करता रहा है।

रूस की आतंकवाद के खिलाफ नीति

1. खुफिया विभाग को मजबूत एवं सैन्य बलों को अधिक अधिकार देना।
2. आतंकवाद को मृदद देने वाले सीमावर्ती राज्यों के प्रति कठोर रूख।
3. आतंकवाद के खातमें के लिये विश्वव्यापी नीति बनाये जाने का समर्थन।
4. आतंकवाद से लड़ने के लिए कठोर कानून का प्रावधान।

भारत और जापान

भारत और जापान आपसी प्रतिरक्षा से सम्बन्धित समझौते अप्रैल 2005 में जापानी प्रधानमंत्री जुनिचिरों कोई जुमी की भारत यात्रा के दौरान हुए। दोनों देशों ने यह महसूस किया है कि बढ़ते हुए आतंकवादी क्रियाकलापों एवं बढ़ते हुए जनसंहार के अस्त्रों के निर्माण को रोकने के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है।

1. भारतीय नौसेना और जापानी मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (J.M.S.D.F.) आपसी हितों वाले क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सैन्य अभ्यास करेंगे।
2. दोनों देश समय–समय पर अपने वार्तालाप को बनाये रखेंगे और एक सम्पूर्ण सुरक्षा वार्तालाप के अन्तर्गत सेना की बातचीत बनी रहेगी।
3. दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि भारतीय नौसेना (J.M.S.D.F.) के जहाज एक–दूसरे के स्थान पर जायेंगे और इन सैनिक गतिविधियों को देखने के लिए दोनो देशों के बड़े अधिकारियों को आमंत्रित किया जायेगा।

भारत और अमेरिका

भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद निरोधक प्रयास के अन्तर्गत द्विपक्षीय सहयोग करने के लिए समझौता हुआ है। "यह समझौता भारतीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के अपने अमेरिकी दौरे के दौरान 28 जून 2005 को हुआ। अमेरिका भारत को आतंकवाद निवारण में किए जा रहे प्रयासों में अपना सहयोगी राष्ट्र मानता है। अमेरिका ने भारत द्वारा पाकिस्तान से तनाव दूर करने के प्रयासों की सराहना करते हुए उसे रचनात्मक करार दिया। इन राष्ट्रों के समझौते इस प्रकार है।"[388]

भारत और अमेरिका के बीच विनियामक द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत कंटेनर सुरक्षा पहल के प्रस्ताव पर एक आम सहमति बनी। प्रसार सुरक्षा के तहत आने वाली इस सन्धि के द्वारा जो कि राजनैतिक आधार पर अधिक संवेदनशील था, के विपरीत कंटेनर सुविधा पहले से अधिक स्वीकार है। यह आतंकवादियों द्वारा डर्टी बम के रूप में किये जाने की समस्या के निवारण हेतु किये गये प्रयासों के अनुसार किया गया है।

भारत और अमेरिका के बीच आपराधिक विषयों पर सूचनाओं तथा कानूनी पहल का अनुमोदन, पारस्परिक विधिक सहायता के अन्तर्गत किया गया है। इस सन्धि द्वारा दोनों देशों में कानून लागू करने तथा अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इससे दोनों देशों के मध्य कानूनी प्रक्रियाओं के द्वारा अपराधियों, आतंकवादियों, तस्करों, आर्थिक एवं संगठित अपराध सम्बन्धित दस्तावेजों की जाँच, अभियोजन निषेध और दमन किया जा सकता है। भारत और अमेरिका के बीच सैनिक क्षमता को और अधिक दक्ष करने हेतु 'संयुक्त हवाई अभ्यास' करने हेतु मसौदे पर भी समझौते हुए। भारत–पाकिस्तान नियन्त्रण रेखा पर पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ पर नजर रखने के लिए भारत अमेरिकी सुदूर संवेदी उपकरण लगाने पर भी सहमति बनी।

भारत और ब्रिटेन

भारत और ब्रिटेन के बीच में भी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपसी द्विपक्षीय समझौते हुए है। भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा ब्रिटेन की यात्रा के दौरान इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच आपसी सहमति बनी।

---

[388] सिविल सर्विसेज टाईम, नई दिल्ली, अक्टूबर 2006, पृष्ठ संख्या – 42–43

जुलाई 2005 में आतंकवाद से संबंधित मुद्दे पर समझौते हुए है। भारत तथा ब्रिटेन ने आतंकवाद को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति या सुरक्षा के लिए सर्वाधिक गम्भीर खतरा माना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कहा कि ''आतंकवाद का मुकाबला करके ही सामरिक स्थिति लाई जा सकती है।''[389] भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि चूँकि आतंकवाद के उद्देश्य में से एक है– वैश्विक स्तर पर आर्थिक अस्थायित्व उत्पन्न करना, इसी कारण से वे व्यापारिक शिखर सम्मेलन में इस मुद्दे पर जोर दे रहे हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच चार मौलिक सिद्धान्तों पर सहमति बनी है।

1- आतंकवाद को किसी भी तरह न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।
2- इसके सभी समर्थकों की निन्दा करना चाहिए।
3- संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव संख्या 1373 का समर्थन कराया।
4- आतंकवाद विरोधी अभ्यासों का सहयोग देना।

भारत और पाकिस्तान

भारत–पाकिस्तान ने भी अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की जाँच का अभ्यास करते हुए आतंकवाद से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दों पर समझौते किये हैं इनमें प्रमुख रूप से निम्न मुद्दे हैं–

1- एक निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी द्वारा आतंकवाद को परिभाषित करके उस पर कार्यवाही की जायेगी।
2- मादक पदार्थों की तस्करी से सम्बन्धित वार्ता जारी रहेगी।
3- सीमा पर आतंकी घुसपैठ एवं मादक पदार्थों से सम्बन्धित गतिविधियों को रोकने हेतु तथा दोनों देशों की सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर आपसी तालमेल स्थापित करने के लिए संयुक्त रूप से संयुक्त गश्त करने जैसे मुद्दे सम्मिलित हैं।

भारत–बांग्लादेश

भारत और बांग्लादेश के बीच भी आतंकवाद की विभीषिका को ध्यान में रखते हुए इन पड़ोसी राष्ट्रों के बीच आपसी समझौते हुए हैं। बांग्लादेश के विदेशमंत्री मुर्शीद खान और भारत के विदेश मंत्री के बीच आतंकवाद सम्बन्धित मुद्दों पर हस्ताक्षर हुए। श्री खान ने भारत को आश्वस्त किया कि वह अपनी भूमि का प्रयोग भारत के विरूद्ध आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रयोग नहीं होने देगा। बांग्लादेश ने 4016 किलोमीटर की सीमा पर अधूरे पड़े कांटे की बाड़ लगाने को पूरा करने और इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया। "इस अवसर पर बांग्लादेश ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के साथ भारत की समस्याएँ द्विपक्षीय हैं और इसमें किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।"[390]

भारत और कजाकिस्तान

---

[389] वही, पृ.सं. – 44
[390] वही, पृ.सं. – 45

भारत और कजाकिस्तान के मध्य आतंकवाद के विरूद्ध एकजुट अभियान की घोषणा के साथ–साथ प्रतिरक्षा एवं तकनीकी सहयोग बढ़ाने हेतु 3 जून 2002 को समझौतों पर हस्ताक्षर किये। इन दोनों देशों के मध्य तकनीकी सहयोग पर आधारित सहमति पत्र (MoU) के तहत पनडुब्बियों और मशीनगन के बैरलों के संयुक्त निर्माण की सम्भावनाओं का पता लगायेंगे। दोनों राष्ट्रों ने आतंकवाद के विरूद्ध संयुक्त कार्यदल गठित करने के लिए सहमति पत्र तथा रक्षा एवं पर्यटन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये। इन दोनों देशों ने माना कि उनके मध्य तेल प्राकृतिक गैस, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर समझौते किए।

भारत और तजाकिस्तान

भारत और तजाकिस्तान के बीच आतंकवाद से सम्बन्धित मुद्दों पर आपसी सहमति बनी है। दोनों राष्ट्रों के बीच आतंकवाद से सम्बन्धित जारी संयुक्त घोषणा पत्र में सुरक्षा सम्बन्धित आदान–प्रदान को बनाये रखने के लिए किये गये प्रयासों का उल्लेख किया गया है। ''मध्य एशिया में राजनैतिक हितों को समझते हुए आतंकवाद का सामना करने के लिए भारत और तजाकिस्तान ने एक संयुक्त कार्य दल की स्थापना की है।''[391] दोनों राष्ट्रों ने रक्षा सहयोग को तीव्र करने और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले एक राजमार्ग का निर्माण तथा ईरान से होकर गुजरने वाले एक जलमार्ग का विकास कर दोनों देशों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

भारत और मारीशस

भारत और मारीशस के बीच आतंकवाद के सम्बन्ध में द्विपक्षीय समझौते हुए है। मारीशस विश्व के उन अग्रणी राष्ट्रों में से एक है, जिन्होंने अपने देश के लिए कठोर आतंकवाद विरोधी कानून पास किया है इसके अन्तर्गत आतंकवादियों को नैतिक समर्थन देना भी अपराध माना गया है। इन दोनों राष्ट्रों के बीच आतंकवाद के निवारण के लिए एक संयुक्त कार्यदल के गठन की बात कही गयी है। ''अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद एवं इससे सम्बन्धित अन्य खतरों जैसे संगठित अपराध, शस्त्र तथा नशीली दवाओं की गैर कानूनी तस्करी, अवैध मुद्रा प्रवाह इत्यादि को रोकने हेतु इन राष्ट्रों के बीच में द्विपक्षीय समझौते हुए हैं ताकि इन राष्ट्रों के बीच सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ और कारगर बनाया जा सके।''[392]

भारत और स्पेन

भारत और वांछित अपराधों को एक–दूसरे को सौंपने तथा आतंकवाद से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 20 जून 2002 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में प्रत्यार्पण सन्धि पर हस्ताक्षर किया। स्पेन की पाँच दिवसीय यात्रा पर आये गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी तथा स्पेन के न्यायमंत्री अगेल–ए–पानियुगुआ ने आतंकवाद के निवारण सम्बन्धी कई गम्भीर मुद्दों पर आम सहमति बनाते हुए इस संधि पर हस्ताक्षर किये। सात वर्ष के विचार–विमर्श द्वारा दोनों देशों के बीच

---

[391] पी.ए.सी., क्रानिकल, राजस्थान अगस्त 2002, पृष्ठ संख्या – 32

[392] स्पेन, भारत–अमेरिका संबंध, मासिक पत्रिाका, वाशिंगटन, अक्टूबर–नवम्बर 2005

हुई संधि में न केवल किसी अपराध को उकसाने में मदद करने या साजिश में शामिल व्यक्ति को प्रत्यार्पित करने का प्रावधान है। इस समझौते में एशिया महाद्वीप की सुरक्षा की स्थिति विशेषकर सीमा पार के आतंकवाद पर भी व्यापक चर्चा हुई।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखते हुए समान विचारधारा रखने वाले राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय समझौते किये है। पाकिस्तान द्वारा भारत के विरूद्ध छद्म आतंकवाद का प्रयोग करने के बावजूद भी भारत ने आतंकवाद को एक वैश्विक समस्या मानते हुए पाकिस्तान से द्विपक्षीय समझौता करने में कोई गुरेज नहीं किया क्योंकि भारत का दृढ़ मत है कि इस वैश्विक पाक संबंध आड़े ना आ जाये। भारतीय परम्परा में एक फरानी कहावत है कि 'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाये।' आज स्वयं पाकिस्तान आतंकवाद की चपेट में है और आए दिन वहाँ पर आतंकवादी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे है, जिसके कारण वहाँ अर्थ और जन की भारी हानि हो रही है। भारत 'वसुदेव कुटुम्बकम्' की विचारधारा से वशीभूत होकर अपने स्वार्थों की तिलांजलि देकर आतंकवाद विरोधी मुहिम में सहयोग कर रहा है।

यूरोपीय यूनियन (EU) की आतंकवाद से निपटने में साझा रणनीति[393]

यूरोपीय यूनियन का प्रमुख सदस्य देश प्रफांस भारत का परम्परागत मित्रा है। भारत प्रफांसीसी सैन्य उत्पादों का एक बड़ा खरीददार है। फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किये थे तब भी भारत का विरोध नहीं किया था।

भारत में होने वाली आतंकवादी घटनाओं का फ्रांस शुरू से ही विरोध करता रहा है। पूर्व में निभाई गई दोस्ती को देखकर कहा जा सकता है कि आतंकवाद के इस ज्वलंत विषय पर आगे भी फ्रांस भारत के साथ ही रहेगा। वैश्विक आतंकवाद पर फ्रांस का रूख विश्व समुदाय के पक्ष में है।

भारत और फ्रांस के बीच आतंकवाद को रोकने के संबंध में एक समझौता भी हुआ है। इस समझौते में यह तय किया गया है कि दोनों देश एक–दूसरे को सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी देंगे। सजायेाफ्रता कैदियों की अदला–बदली पर भी दोनों देशों के बीच सहमति हो चुकी है।

यूरोपीय यूनियन की आतंकवाद के खिलाफ नीति[394]

1. अमेरिकी नीतियों का अनुसरण।
2. नागरिकता कानून को सख्त बनाया जाना।
3. फलिस को ज्यादा अधिकार।
4. विशेष कमांडों दस्ते एस ए एस को आधुनिक और मजबूत करना।

---

[393] दैनिक जागरण वार्षिकी, संपादक–संजीव अग्निहोत्री, 2009, प्रकाशक – जागरण रिसर्च सेन्टर एण्ड जागरण प्रकाशन लिमिटेड, कानफर (उ.प्र.) पृष्ठ संख्या – 14

[394] वही, पृ.सं. – 16

5. संदिग्ध लोगों के आर्थिक स्त्रोतों की जाँच।

इजरायल की आतंकवाद के खिलाफ नीति

1. आतंकवादियों पर पहले हमले की नीति।
2. आतंकवादियों के प्रति कोई भी नरमी नहीं।
3. नागरिकों के लिये सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य।
4. प्रमुख खुफिया एजेंसी मोसाद को विशेष अधिकार।

इजरायल आतंकवादियों के निशाने पर

इजरायल इस क्षेत्र में सबसे संवेदनशील है। 1948 में अपनी स्थापना के बाद से ही यह इस्लामिक आतंकवादियों के निशाने पर है। यहाँ के इस्लामिक देश खुलकर कहते हैं कि इजरायल का अस्तित्व उनके लिये खतरा है। इस देश के खिलाफ जंग कर रहे 'हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन' को इस क्षेत्र के सभी मुस्लिम देशों का खुला या गुप्त समर्थन जारी है। विश्व में आतंकवाद के प्रति अगर किसी देश की सबसे ज्यादा आक्रामक रणनीति है तो वह इजरायल की ही है।

भारत ने लम्बे समय तक इजरायल के साथ निजी सम्बन्धों को प्राथमिकता नहीं दी। इसके राजनैतिक कारण भी हो सकते हैं। सन् 1992 में दोनों देशों के बीच राजनैतिक सम्बन्धों की शुरूआत हुई। अब भारत इजरायल के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत कर रहा है। इजरायल ने भारत को आतंकवाद से लड़ने में हर सम्भव मदद देने का वचन दिया है। भारत के सामने अभी भी दुविधा है कि वह इजरायल के साथ अपने सम्बन्धों को प्राथमिकता दे या नहीं क्योंकि ऐसा करने से उसके अरब एवं अन्य इस्लामिक देशों के साथ सम्बन्ध खराब हो सकते हैं।

इराक भारत का फराना सहयोगी

इराक के संदर्भ में देखा जाये तो यहाँ की जनता अमेरिकी समर्थकों एवं विरोधियों के बीच जारी जंग में पिस रही है। किसी समय इराक ने अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में धार्मिक विचारधारा के प्रतिकूल भारत का समर्थन किया था। दोनों देशों के बीच राजनैतिक सम्बन्ध मजबूत थे और इन्हें एक परम्परागत मित्रा के रूप में देखा जा रहा था। भारत में भी यह नारे सुनाई दे जाते थे, **'दोस्ती का एक ही नाम, राजीव गाँधी और सद्दाम।'**

इराक और अमेरिका के सम्बन्धों में खटास आने का असर इराक और भारत के सम्बन्धों पर भी पड़ा। खाड़ी युद्ध के बाद इराक पूरी तरह अमेरिका के दबाव में आ गया है। वहाँ की नीतियाँ अमेरिका के इशारे पर ही तय होती है। आज अमेरिका जब आतंकवाद से जूझ रहा है तो इराक में मौजूद अमेरिका विरोधी ताकतें आतंकवादियों को परोक्ष रूप से मदद कर रही हैं। गृहयुद्ध में फंसा यह देश इस विषय पर फिलहाल किसी भी देश को सहयोग नहीं कर सकता है क्योंकि इराक की प्राथमिकता पहले स्वयं को गृहयुद्ध के हालात से उबारने की है। हाँ, इस बात की काफी संभावना है कि स्थिति ठीक होने पर इराक के भारत

के साथ संबंध पूर्ववत हो जायेंगे। दोनों देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे।

इराक की आतंकवाद पर नीति

फिलहाल इराक आतंकवाद पर अपनी कोई नीति बनाने की स्थिति में नहीं है।

ईरान आतंकवाद पर मौन

ईरान की बात की जाये तो यह साफ है कि भारत के साथ यह अच्छे सम्बन्ध चाहता है। पूर्व में ईरान का रूख भारत के प्रति लगभग दोस्ताना ही था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव, भारत–ईरान सम्बन्धों पर भी भारी पड़ रहा है। **ईरान–पाकिस्तान–भारत गैस पाईप लाईन समझौते** में हो रहा विलंब इस बात की फष्टि करता है।

ईरान आज सैन्य ताकत के रूप में अपने को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। वह भारत के साथ अच्छे सम्बन्ध चाहता है। भारत में हो रही आतंकवादी घटनाओं की वह निंदा करता है। वहीं ईरान का आतंकवाद पर दूसरा पक्ष यह है कि वह इजरायल पर होने वाले आतंकवादी हमलों पर मौन रहता है। ईरान ने भारत से अपनी दोस्ती का निर्वाह करते हुए पहले भी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का विरोध किया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर भारत–ईरान सम्बन्धों पर भी पड़ता दिख रहा है। भारत की मजबूरी है कि वह न तो अमेरिका से सम्बन्ध खराब करना चाहता है और न ही ईरान से। फिलहाल मजबूरी यह है कि इन दोनों देशों से एक जैसे सम्बन्ध रखना अब संभव नहीं दिखाई दे रहा है।

ईरान की आतंकवाद पर नीति

ईरान ने अपनी भूमि पर आतंकवादी गतिविधियों को न चलने देने की बात कही है।

भारतीय उपमहाद्वीप : आरोप–प्रत्यारोप एवं आतंक का पोषण

भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतर देश आज किसी–न–किसी तरह के आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर दावे तो बहुत किये जा रहे हैं, लेकिन यह दावे अमली रूप नहीं ले पाये हैं। **अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार (बर्मा) अपनी–अपनी समस्या से जूझ रहे हैं।** इन सभी देशों में कहीं–न–कहीं भारत विरोधी मानसिकता का पोषण किया जा रहा है। भारत आज जिस आतंकवाद से जूझ रहा है। उसकी जड़ में ये देश परोक्ष या अपरोक्ष रूप से शामिल हैं। भारत में फलपूफल रहे इस्लामिक आतंकवाद के वृक्ष को पाकिस्तान अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से जन एवं धन समर्थन मिल रहा है।

वहीं नक्सलवादी एवं पूर्वोत्तर के आतंकियों को नेपाल एवं चीन का वैचारिक समर्थन हासिल है। ऐसे हालात के लिये भारतीय विदेश नीति भी जिम्मेदार है। भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ तब सख्त कदम उठाने में कोताही

की जब इसकी आवश्यकता थी। आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर आज इस क्षेत्र में भारत अकेला है और उसे इस आतंकवाद की समस्या से अपने बल पर ही निपटना होगा।

अफगानिस्तान : आतंक को खत्म करने की जंग

अफगानिस्तान आज आतंकवाद के खिलाफ अपनी भूमि पर एक अलग तरह की जंग लड़ रहा है। वहाँ की जनता का एक बड़ा भाग धार्मिक मंदाधता के कारण तालिबान चरमपंथियों के साथ है और बाकी लोग अमेरिका के परचम तले तालिबान के खिलाफ जंग में सेना का साथ दे रहे हैं। अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार के साथ भारत के अच्छे सम्बन्ध हैं। भारत दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने 1980 के दशक में सोवियत संघ की सहायता से गठित 'डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान' को मान्यता दी थी। गृहयुद्ध के दौर में भी इस क्षेत्र में अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा मदद देने वाला देश भारत ही था। अफगानिस्तान भारत में होने वाली आतंकवादी हिंसा की निंदा करता है। अफगानिस्तान की मजबूरी यह है कि आतंकवाद का सामना करने के लिये वह खुद नाटो देशों पर आश्रित है। अफगानिस्तान जानता है कि तालिबान के खिलाफ जंग में वह हार गया तो देश में एक बार फिर आतंकवादियों का राज्य हो जायेगा। ऐसे में फिलहाल अफगानिस्तान इस मामले में भारत की मदद करने में सक्षम नहीं दिखाई दे रहा है।

अफगानिस्तान की आतंकवाद के खिलाफ नीति

1. तालिबान के खात्में के लिये निर्णायक जंग
2. जनता को वैचारिक स्तर पर तालिबान से अलग करना।
3. आतंकवाद पर विश्व के कई देशों के निजी महत्त्व की मनोदशा का विरोध।
4. आतंकवाद के खिलाफ विश्वस्तरीय मोर्चे की वकालत।

पाकिस्तान : आतंकवाद का पोषक और शिकार

पाकिस्तान को यदि अफगानिस्तान और भारत में जारी आतंकी हिंसा की जन्मभूमि कहें तो गलत न होगा। आज इन दोनों देशों में जो कुछ भी आतंकवादी कर रहे हैं। उसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है पाकिस्तान दोहरी नीति पर चल रहा है। एक ओर तो वह तालिबान और अलकायदा के खिलाफ अमेरिका को समर्थन देने की भूमिका दिखा रहा है तो दूसरी ओर पीठ पीछे इनकी मदद भी कर रहा है। उसकी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. (ISI) सेना के कैंपों में अलगाववादियों को प्रशिक्षण दिलवा रही है। वहाँ की सरकार का सेना और खुफिया विभाग पर नियंत्रण मात्रा दिखावे का ही लगता है। भारत ने पाकिस्तान से सम्बन्धों को सुधारने के कई बार प्रयास किये लेकिन बदले में भारत को पाकिस्तान की तरफ से हर बार कारगिल जैसी घटनाओं का ही सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को चीन का खुला समर्थन हासिल है। इसमें चीन का एक छिपा स्वार्थ है। चीन भारतीय सेना को पश्चिमी सीमा पर उलझायें रखना चाहता है।

आतंकवाद के खिलाफ अपनाई गई भेदभाव पूर्ण नीति के कारण ही आज पाकिस्तान खुद आतंक का शिकार हो गया है। कबायली क्षेत्रों में उसका नियंत्रण समाप्त हो रहा है। सिन्ध प्रदेश में भी हालत ठीक नहीं है। वहाँ की सेना पर भी चरमपंथियों का शिकंजा मजबूत होता जा रहा है। इसके लिये पाकिस्तान स्वयं दोषी है।

पाकिस्तान की आतंकवाद के खिलाफ नीति

1. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की निंदा करना।
2. अपनी भूमि पर अलगाववादियों के होने से इनकार करना।
3. विश्व समुदाय के साथ इस विषय पर खड़े होने का भरोसा देना।
4. कुछ आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित करना।

श्रीलंका : टाइगर के विनाश की तैयारी

आत्मघाती आतंकवाद की शुरूआत सबसे पहले इसी देश ने आतंकवादी संगठन **लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) ने की थी।** इस संगठन को कभी विश्व का सबसे ज्यादा खतरनाक आतंकवादी संगठन माना जाता था। स्ज्ज्म और श्रीलंका सेना के बीच जारी हिंसा में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। श्रीलंका एक छोटा देश है और विश्वस्तर पर उसकी कोई विशेष भूमिका नहीं है। श्रीलंका और भारत के बीच दोस्ताना सम्बन्ध है। श्रीलंका के मूल निवासियों द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि वहाँ जो आतंकवाद है, उसके पीछे भारत का हाथ है। भारत स्ज्ज्म (एल.टी.टी.ई.) को हर संभव मदद प्रदान करता रहा है। स्ज्ज्म के कारण भारत और श्रीलंका के सम्बन्धों में खटास आ रही है। श्रीलंका के स्ज्ज्म और भारत संबंधी दावों में कोई दम नहीं है। स्ज्ज्म भारत में प्रतिबंधित संगठन है और उसके प्रमुख प्रभाकरण को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की हत्या के आरोप में तलाशा जा रहा है। अर्थात् वर्तमान में प्रभाकरण की मौत हो चुकी है। दोनों देश एक–दूसरे के यहाँ जारी आतंकवाद की निंदा करते हैं। श्रीलंका और भारत का मानना है कि आतंकवाद से निपटने के लिये आवश्यक है कि सभी देश मिलकर साझा प्रयास करें।

श्रीलंका की आतंकवाद के खिलाफ नीति

1. स्ज्ज्म के खिलाफ आक्रामक नीति।
2. सेना का फनर्गठन और पड़ोसी देशों से बेहतर संबंधों पर जोर।
3. इस विषय पर विश्व के साथ रहने का भरोसा।

चीन : ड्रैगन पर भी आतंक का साया

एशिया का सर्वाधिक ताकतवर देश चीन है। विश्व में जनसंख्या के मामले में इसका पहला स्थान है। चीन आतंकवाद के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस समय चीन तिब्बत में किये गये दमन के कारण अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के निशाने पर हैं। अमेरिका के साथ उसके सम्बन्ध मधुर नहीं है और भारत के साथ उसका सीमा–विवाद जगजाहिर है। **भारत और चीन के बीच सन् 1962 में युद्ध भी हो चुका है।** आज भी चीन सामरिक दृष्टि से

भारत को घेरने के लिये पाकिस्तान को खुलकर मदद दे रहा है। वह बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका को भी अपने समर्थन में लेने का प्रयास कर रहा है। भारत की अति उदारता की नीति इन देशों में उसे अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद दे रही है।

भारत के नक्सली आतंकवाद एवं पूर्वोत्तर के राज्यों में सक्रिय अलगाववादियों को चीन के वैचारिक समर्थन की बात कही जा रही है। चीन माओवादी हिंसा पर तो मौन रहता है लेकिन इस्लामिक आतंकवाद पर उसका रूख कठोर ही है। भारत अपने यहाँ जारी आतंकवाद के संदर्भ में चीन से कोई बड़ी मदद की उम्मीद नहीं कर सकता है। चीन भारत में होने वाली आतंकवादी घटनाओं की निंदा करता है।

चीन भी अब धीरे–धीरे आतंकवाद का शिकार होता जा रहा है। उसके सीमावर्ती प्रान्त शिनजियांग में इस्लामिक आतंकवाद की विचारधारा तेजी से पैर पसार रही है। यह चीन के लिये चिन्ता का विषय है। चीनी अधिकारी दबे स्वर यह स्वीकार कर चुके हैं कि इन अलगाववादियों को अफगान तालिबान मदद दे रहे हैं। चीन अपने देश में सर उठा रहे इस आतंकवाद को कुचलने की बात कर रहा है।

चीन की आतंकवाद के खिलाफ नीति

1. आतंकवाद को ताकत से कुचलने का हिमायती।
2. विश्वस्तरीय पहल का पक्षधर।
3. सैन्य बलों को ज्यादा अधिकार।
4. इस सम्बन्ध में भारत को मदद का भरोसा।

बांग्लादेश : पाकिस्तान की राह पर

भारत की पूर्वी सीमा से लगा यह देश आज इस्लामिक अलगाववादियों के लिये सुरक्षित क्षेत्र बन गया है। वहाँ भारत विरोधी मानसिकता तेजी से अपना आधार बना रही है। इसमें वहाँ के राजनैतिक एवं आर्थिक हालात अहम भूमिका निभा रहे हैं। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले इस देश का एक बड़ा भाग गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहा है। अलगाववादी मानसिकता के लोग इन लोगों को धन एवं धर्म का वास्ता देकर गुमराह कर रहे हैं। चरमपंथी संगठन हूजी (HUJI) में बड़ी संख्या में बांग्लादेश के स्थानीय निवासी शामिल हो रहे हैं। भारत के प्रति बांग्लादेश का रूख अब दोस्ताना नहीं कहा जा सकता है। वह सुनियोजित तरीके से अपने देश के लोगों को भारत में भेज कर भारतीय संसाधनों का अनुचित दोहन कर रहा है। इन घुसपैठियों के कारण सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रों को जनसंख्या सन्तुलन (धार्मिक आधार पर) बदल गया है।

भारत ने इस देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। भारत ही वह देश है जिसने इसे स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सबसे पहले मान्यता दी थी। निर्माण के कुछ समय बाद ही बांग्लादेश के रूख में परिवर्तन आना शुरू हो गया। आज बांग्लादेश आतंकवाद के मामले में धार्मिक मानसिकता से ग्रसित होने के कारण

भारत के विरोध में ही दिखाई देता है। भारत में ऐसी कई घटनायें हो चुकी हैं जिसमें आतंकवादी वारदात करके बांग्लादेश में पनाह लेने चले गये हो। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में गतिविधियाँ चला रहे आतंकवादी संगठनों को बांग्लादेश में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहाँ के वर्तमान हालात के सम्बन्ध में यदि भारतीय विदेश नीति को असफल कहा जाये तो गलत नहीं होगा। भारत की अति की नीति बांग्लादेश के सम्बन्ध में आत्मघाती साबित हुई है। बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिलने के बाद भारत ने उसकी जी (दिल) खोलकर मदद की। कुछ समय बाद वहाँ चरमपंथियों ने अल्पसंख्यक हिन्दुओं को अपना निशाना बनाना शुरू किया। भारत चाहता तो उस समय अपने प्रभाव का प्रयोग करके वहाँ चरमपंथियों को दबा सकता था। अहस्तक्षेप की नीति के कारण भारत चुप रहा। परिणाम यह हुआ कि वहाँ अलगाववादियों के हौंसले बुलंद होते गये। अब हालात यह है कि चरमपंथी मानसिकता के लोगा वहाँ इतने मजबूत हो गये हैं कि सरकार पर भी उनका दखल चलने लगा है। बांग्लादेश में जारी राजनैतिक अस्थिरता का लाभ भी अलगाववादियों को मिल रहा है।

बांग्लादेश की आतंकवाद के खिलाफ नीति

1. आतंकवादी संगठनों को अपनी भूमि का प्रयोग न करने देने की बात।
2. भारत के साथ इस समस्या से मिलकर निपटने का भरोसा।
3. अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ पूरे सहयोग का वादा।

म्यांमार : विश्व समुदाय के साथ होने का भरोसा

वैश्विक आतंकवाद के संदर्भ में म्यांमार विश्व समुदाय के साथ होने का भरोसा देता है। आज म्यांमार में आन्तरिक असन्तोष व्याप्त है। भारत के साथ उसके सम्बन्ध पूर्व की भाँति नहीं है। वहाँ के आन्तरिक मामलों में चीन का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। म्यांमार की वर्तमान सरकार भी भारत की तुलना में चीन को निजी संबंधों में वरीयता दे रही है। इसका कारण है कि चीन ही एक ऐसा देश है जिसने वहाँ की सैन्य सरकार के साथ सम्बन्धों को प्राथमिकता दी है। भारत म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना चाहता है। यह वहाँ की सैन्य सरकार को अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन वह भारत के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहती है।

भारत में व्याप्त आतंकवाद पर म्यांमार का रूख साफ नहीं है। वह आतंकवाद की निंदा करता है। विश्वास दिलाता है कि उसकी भूमि का प्रयोग भारत विरोधी कार्यों के लिये नहीं होने दिया जायेगा। इसके बाद भी भारतीय सीमा से लगे म्यांमार के क्षेत्र में भारत विरोधी गतिविधियाँ तेज हो रही हैं। इस सीमा से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। म्यांमार की वर्तमान सरकार इसे रोकने में या तो असमर्थ साबित हो रही है या वह कुछ करना नहीं चाहती है। यह मादक पदार्थ, पूर्वोत्तर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के लिये पारसमणि साबित हो रहे हैं।

म्यांमार की आतंकवाद के खिलाफ नीति

1. आतंकवाद का सामना कर रहे देशों का समर्थन का भरोसा।

2. आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम का आश्वासन।

नेपाल : कम होता भारतीय प्रभुत्व

नेपाल लम्बे समय से भारत का पारम्परिक मित्रा रहा है। एक दशक तक चली राजनैतिक अस्थिरता के बाद नेपाल लोकतंत्र के मार्ग पर अग्रसर हो गया है। वहाँ राजशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले माओवादी मजबूत होकर सामने आये हैं और **प्रधानमंत्री फष्प कमल दहल प्रचंड उनके प्रमुख हैं।** नेपाल का भारत के संदर्भ में बहुत महत्त्व है। सन् 1950 में हुई संधि ने दोनों देशों के सम्बन्धों को नया आयाम दिया है। आज भी दोनों देशों के बड़ी संख्या में नागरिक एक–दूसरे के यहाँ निवास कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं।

भारत में नक्सलवादी आतंकवाद से कम–से–कम 13 राज्य प्रभावित हैं। माना जा रहा है कि नेपाल में माओवादियों की सफलता भारतीय नक्सलवादियों के मनोबल में इजाफा करेगी। नेपाल के माओवादी, नक्सलवादियों का परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच खुली दुर्गम सीमा नक्सलियों के लिये वरदान साबित हो रही है। हाल के दिनों में नेपाल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. ने अपनी जड़ें मजबूत की हैं। भारत में नकली नोटों के कारोबार में भी इस खुफिया एजेंसी की भूमिका ही बताई जा रही है। इसके बावजूद भी नेपाल का रूख भारत के प्रति नकारात्मक नहीं कहा जा सकता है। भारत में होने वाली इस्लामिक आतंकवादी घटनाओं का नेपाल में विरोध किया जाता है। माओवादी भी इससे अछूते नहीं है। **माओवादी प्रंचड का कहना है कि** ''नेपाल के विकास में भारत की अहम भूमिका रही है और उम्मीद है कि भारत आगे भी नेपाल की मदद करता रहेगा।''

नेपाल की आतंकवाद के खिलाफ नीति

1. आतंकवादी विचारधारा को नेपाल में जगह नहीं।
2. चीन और भारत से बेहतर संबंधों के साथ इस समस्या से निपटने की बात।
3. भारत–नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ाने पर विचार।

अफ्रीकी देश : अराजकता की आग में

अफ्रीका के देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे ही हैं। भारत इन देशों के साथ व्यापार और आपसी सहयोग बढ़ाना चाहता है। इस संदर्भ में अफ्रीकी देशों का रूख भी सकारात्मक ही है। आतंकवाद के मामले में ये देश फिलहाल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं दिखाई देते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि अफ्रीका के कई देश अराजकता की स्थिति का सामना कर रहे हैं। जिसके कारण इन देशों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ अलगाववादियों के लिये मददगार साबित हो रही हैं। अलगाववादी वहाँ के निवासियों को चन्द पैसों का लालच देकर अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज ये देश चरमपंथियों के लिए 'सेफ जोन' बनते जा रहे हैं।

सोमालिया : अलकायदा का नया केन्द्र

सोमालिया में लम्बे समय से अराजकता के हालात हैं। वहाँ की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समुद्री जहाजों की लूट (Piracy), आज सोमालिया का मुख्य पेशा बन गया है। वहाँ लोगों के पास खाने को नहीं है। इन्सानों की बिक्री आम बात हो गई है। सोमालिया के मात्रा 100 डॅालर में इन्सानों को खरीदा जा रहा है। इस गरीबी का फायदा अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन उठा रहे हैं। वे चंद पैसे खर्च कर यहाँ के युवकों को अपने दल में शामिल कर रहे हैं। ये आतंकवादी संगठन ही सोमालिया के जल दस्युओं को अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं।

कांगो : कबीलाई युद्ध में तबाह होता देश

अफ्रीकी देश कांगों भी आतंकियों के लिये वरदान साबित हो रहा है। वहाँ लम्बे समय से सेना और विद्रोहियों के बीच जंग जारी है। लाखों लोगों की मौत होने के बाद भी यह संघर्ष खत्म होते नहीं दिख रहा है। ''हुतू'' एवं ''तूत्सी'' समुदाय के बीच जारी इस लड़ाई का सीधा फायदा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों को भी मिल रहा है। ये संगठन हथियार एवं आर्थिक मदद देकर इन दोनों समुदाय के लड़ाकों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांति स्थापित करने के लिये किये जा रहे प्रयास यहाँ विफल हो रहे हैं।

भारत की भूमिका

भारत इन अफ्रीकी देशों में शांति की स्थापना करना चाहता है। इसके लिये वह हर संभव प्रयास कर रहा है। अफ्रीका के अशान्त क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में भारत की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

आस्ट्रेलिया महाद्वीप : अमेरिकी नीतियों के समर्थक

आस्ट्रेलिया महाद्वीप के दोनों प्रमुख देश आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आतंकवाद पर अमेरिका की नीतियों का ही समर्थन करते हैं। ये दोनों आतंकवादी हिंसा का फिलहाल ज्यादा शिकार नहीं है लेकिन जिस तरह आतंकवाद विश्वव्यापी होता जा रहा है उसे देखकर इन देशों ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। वहाँ खुफिया विभाग को सतर्क कर दिया गया है और उन्हें पहले की तुलना में ज्यादा अधिकार दे दिये गये हैं। विदेशी नागरिक जो इन देशों में रह रहे हैं उन पर विशेष नजर रखी जा रही है। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की निंदा करते हैं और उसे रोकने के लिये अपनी तरफ से विश्व समुदाय को पूरा सहयोग देने का वादा भी करते हैं। भारत में जारी आतंकवाद के संदर्भ में भी इन देशों का यही रूख है। इन देशों के साथ भारत के सम्बंधों की समीक्षा की जाये तो उसे सामान्य ही कहा जायेगा।

मुम्बई हमले (26 नवम्बर 2008) के आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक थे

ऑपरेशन के दौरान जीवित पकड़े गये एकमात्र आतंकवादी **अजमल अमीर कसाब** ने कबूल किया कि सभी आतंकवादी, आतंकवादी संगठन लश्कर–ए–तैयबा के सदस्य थे। लश्कर–ए–तैयबा लम्बे समय से कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के साथ

'जिहाद' के नाम पर आतंकवादी कार्यवाहियों में लिप्त रहा है। इसे, भारत, अमेरिका और ब्रिटेन ने आतंकवादी संगठनों की सूची में डाल रखा है। बाद में भारत सरकार ने सीधे तौर पर कहा कि आतंकवादी पाकिस्तान के ही नागरिक थे और उनके आका भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. ने ही उन्हें प्रशिक्षित किया था। साथ ही सरकार ने **अंडरवर्ल्ड डॉन दाउफद इब्राहिम** का नाम भी इस संदर्भ में लिया, जिसने स्थानीय स्तर पर आतंकवादियों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई। दाउफद लम्बे समय से कराची में पाकिस्तानी सरकार की सरपरस्ती में रह रहा है और वहीं से मुम्बई के अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है।

मुम्बई हमले पर भारत का सख्त रवैया और पाक की नाटकबाजी

मुम्बई पर आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई जिसको देखते हुए **केन्द्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटिल** को तुरन्त इस्तीफा देने के लिये मजबूर होना पड़ा। उनके स्थान पर पी. चिदंबरम नये गृहमंत्री नियुक्त किये गये। भारत सरकार ने पाक के खिलाफ अपना रवैया सख्त करते हुए उसे 20 (Most-Wanted) आतंकवादियों की एक सूची सौंप कर उन्हें भारत के हवाले करने की माँग की। सूची में लश्कर सरगना हाफिज मोहम्मद और जैश–ए–मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर के साथ–साथ दाऊद इब्राहिम शामिल थे। हालद्वाकि भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका पाक के खिलाफ कोई सैन्य कार्यवाही करने का इरादा नहीं है। दूसरी ओर पाक ने भारत को आतंकवादी सौंपने से इंकार करते हुए कहा कि आतंकवादी उनके नागरिक नहीं थे। यह कहकर पाक ने पूरी तरह से मुम्बई घटना से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की।

इस मामले में अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायल जैसे देशों ने खुलकर भारत का समर्थन किया। अमेरिका और ब्रिटेन ने तो पाकिस्तान को चेतावनी भी दे डाली कि वह जल्द–से–जल्द अपने यहाँ आतंकवादियों पर कार्यवाही करे और उनके कैंपों को समाप्त करे। **विश्व समुदाय का दबाव देखते हुए पाकिस्तान ने एक बार फिर से कार्यवाही का नाटक शुरू किया।** उसने पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी कैपों को हटाने का ड्रामा किया और कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया। सन् 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद भी राष्ट्रपति मुशर्रफ ने इसी तरह का नाटक किया था। बाद में आतंकवादी कैंप फिर से काम करने लगे थे और आतंकवादियों को भी दहशत फैलाने की खुली छुट मिल गई थी। पकड़े गये आतंकवादी कसाब ने सभी तथ्य भारत के सामने खोल दिये हैं। यहाँ तक पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी सीधे तौर पर पाक नागरिकों के मुम्बई हमले में शामिल होने की बात स्वीकार की है। लेकिन पाक सरकार फिर भी टालमटोल की मुद्रा ही अपनाये हुए है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में पाक बिल्कुल भी संजीदा नहीं है और वह कुछ छिटफट कार्यवाही करके विश्व समुदाय का ध्यान बंटाना चाहता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी सेना व खुफिया एजेंसी किसी भी तरह से सिविल सरकार के कंट्रोल में नहीं है।

ऐसे में भारत सरकार के सामने विकल्प अत्यन्त सीमित हैं। हाल के दिनों में भारत सरकार ने जिस तरह का रवैया अपनाया हुआ है उससे लगता है कि वह आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को किसी सार्थक परिणति तक ले जाना चाहती है। इसमें सैन्य विकल्प भी शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान से सटी सीमा पर सैन्य हलचल बढ़ी है जो दर्शाता है कि इस बार भारत पाकिस्तान के झांसे में आने वाला नहीं। इसके साथ ही भारत राजनयिक स्तर पर लड़ाई के मूड मे भी नजर आ रहा है। उसने मुम्बई हमले में पाकिस्तानी नागरिकों के लिप्त होने के सबूत दुनिया भर के देशों को देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पहले से ही दुनिया भर में आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में बदनाम हो चुका है। इससे निश्चित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का पाकिस्तान पर दबाव पड़ेगा।

मुम्बई हमले में पूरी तैयारी से आये थे आतंकवादी

आतंकवादियों ने जिस तरह से मुम्बई पर हमला किया वह यह बात सिद्ध करता है कि वे न केवल पूरी तैयारी के साथ आये थे बल्कि उनकी योजना भी हाईटेक थी। उन्होंने महीनों पहले ही तैयारी करते हुए दोनों होटलों में कंट्रोल रूम बना लिये थे। आतंकवादी किस कदर तैयारी से आये थे इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी आतंकी घटना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (WTC) में भी सिर्फ एक हवाई जहाज का प्रयोग कर कुछ ही देर में घटना को पूरा कर लिया गया था। लेकिन मुम्बई की इस घटना में आतंकवादियों पर काबू पाने में पूरे 58 घण्टे लगे। आतंकवादी तेज स्पीड वाली बोटस के द्वारा मुम्बई की सीमा में समुद्री सीमा से दाखिल हुए। उनके पास एके–47, एके–56 जैसे ऑटोमेटिक हथियार थे और साथ ही भारी मात्रा में विस्फोटक भी थे। उनके हाईटेक प्लान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि होटल ताज, ओबेराय होटल जैसे संवदेनशील जगहों में यह आतंकवादी किस तरह इतने हथियार और विस्फोटक लेकर घुस पाये। कुछ आतंकियों के पास सेटेलाइट मोबाइल फोन भी थे जो इस बात को भी सिद्ध करता है कि वे तकनीकी रूप से काफी दक्ष और इंटेलिजेंट भी थे। सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने पहले ही होटलों की सुरक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से विश्लेषण कर लिया था।

सार्क (दक्षेस): निंदा तक ही सीमित

दक्षिण एशियाई प्रादेशिक (क्षेत्रीय) सहयोग संगठन 'सार्क' (**SAARC – South Asian Association For Regional Co-operation**) में शामिल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं नेपाल आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। श्रीलंका में लिट्टे (LTTE) शांति व्यवस्था को कायम नहीं होने दे रहा है तो भारत में इस्लामिक एवं नक्सली आतंकवादी अमन–चैन पर भारी पड़ रहे हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को प्रोत्साहित करते–करते अब खुद आतंकवाद का शिकार हो गया है। वहीं बांग्लादेश पाकिस्तान द्वारा भूतकाल में दोहराई गई गलतियों का अक्षरशः पालन

कर इस समस्या को आमंत्राण दे रहा है। आज बांग्लादेश आतंकवादियों के लिये एक 'सेफ जोन' के रूप में परिवर्तित हो रहा है।

'सार्क' संगठन आतंकवाद का मिलकर सामना करने की बात करता है। इस सम्बन्ध में बैठकों में प्रस्ताव भी पास किये जाते हैं लेकिन सदस्य देशों के बीच जारी आपसी वैमनस्यता एवं कटुता के कारण किसी भी प्रस्ताव को अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। भारत अपने यहाँ होने वाली घटनाओं के लिये पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है तो जवाब में पाकिस्तान भी अपने यहा जारी असन्तोष को भारत की देन बताकर खुद को पाक साफ दर्शाने का प्रयत्न करता है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय यह जानता है कि पाकिस्तान में इस्लामिक आतंकवादियों को पनाह मिल रही है। पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाकर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी ओर से हटाने का प्रयास कर रहा है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर है। ऐसे में फिलहाल आतंकवाद से निपटने में 'सार्क' की भूमिका कमजोर ही दिखाई देती है। 'सार्क' संगठन में शामिल देश यदि मिलकर साफ मन से आतंकवाद को रोकने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करे तो निश्चित ही इस क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ी जा सकती है।

4.1.3 धन एवं वित्त की भूमिका (Role of Finance)

आतंकवाद के लिए धन का प्रबंधन करना (धन जुटाना) एक ऐसी भूमिगत दुनियाँ द्वारा सम्पन्न होता है जो गोपनीयता, चालबाजी, धोखाधड़ी और अपराधी प्रयासों द्वारा कार्य करती है। इसके साथ–साथ इस कार्य के लिए व्यक्ति को विश्व स्तर की वित्तीय प्रणाली में दक्ष होना जरूरी है और एक अच्छे दर्जे का आधुनिकतम प्रणाली से भली–भाँति परिचित व्यक्ति ही धन उपलब्ध कराने का कार्य कर सकता है।

इस कार्य का उल्लेख एक समुद्री जीव 'ऑक्टोपस' (Octopus जिसकी आठ भुजायें अनेकों दिशाओं में फैली होती है) से किया जा सकता है। क्योंकि आतंकवादी कार्यों के लिए धन–प्रबन्धन का कार्य भी विश्व के विस्तृत क्षेत्रों में ऑक्टोपस की अनेकों भुजाओं की भाँति फैला होता है और उसे विश्व की अनेकों वास्तविकताओं (जैसे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक) से गुजरना पड़ता है।

''पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. ने भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से भारतीय सीमा से सटे नेपाली इलाकों में कई कट्टरपंथी संगठन और मदरसे बना रखे हैं।''[395] तेजी से विकसित हो रहे संगठन

---

[395] डॉ. कृष्णानन्द शुक्ल, ''लाल शीत युद्ध की दास्तान – भारत और पाकिस्तान'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, दूरभाष 011–23255141, पृष्ठ संख्या – 90

और मदरसे भारत को अस्थिर करने के लिए 1996 के मध्य में शुरू किए गए पाकिस्तान के गोपनीय अभियान का हिस्सा हैं। इस अभियान के तहत स्थानीय मुसलमान युवाओं को बहकाना, उग्रवादियों को प्रशिक्षण देना, उनकी घुसपैठ कराना, आधुनिक हथियार, गोला–बारूद तथा भारत–नेपाल सीमा के जरिये नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी कराना शामिल है।

इस समय कम–से–कम दस ऐसे संगठन और 150 से अधिक मदरसे आई.एस.आई. के संरक्षण में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के नापाक इरादे से कार्य कर रहे है। बताया जाता है कि इन संगठनों ने नेपाल में पृथक्क गणराज्य बनाने के लिए संघर्ष कर रहे वामपंथी माओवादियों से सम्पर्क बना रखे हैं। इन संगठनों को धन हिमालयन बैंक (पाकिस्तान के हबीब बैंक की शाखा समझा जाने वाला) के जरिये मुहैया कराया जाता है। काठमांडु की कश्मीरी मस्जिद में स्थित नेपाल इस्लामिक युवा संगठन के केन्द्रीय कार्यालय के जरिये भी धन आता है। ''आई.एस.आई. कश्मीर में लड़ने के लिए कुछ नेपाली मुसलमानों को प्रलोभन देकर उग्रवादियों के रूप में उन्हें भर्ती करने में सफल रही है।''[396] आई. एस.आई. ने नेपाल की सीमा से सटे राज्यों में भी घुसपैठ कर ली है और इसके एजेंट उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न स्थानों पर विशेष तौर पर पिलखुआ और किशनगंज में सक्रिय है। आई.एस.आई. नेपाल में और विशेष तौर पर भारत से सटी सीमा पर स्थित इलाकों में आबादी का स्वरूप बदलने में भी लगी है। उन्होंने बताया कि 1981 से अब तक दस वर्षों से भी अधिक समय में यहाँ की मुसलमान आबादी एक प्रतिशत से बढ़कर दोगुनी हो गई है। भारत को लक्ष्य कर नेपाल में बढ़ रही आई.एस.आई. गतिविधियों को लेकर चिंतित भारत इन्हें रोकने के लिए नेपाल से कहता रहा है। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश और नेपाल में मजबूती से अपने पैर जमा चुकी पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई. अब भूटान में भी अपने अड्ड़े बना चुकी है। भूटान पर अपना मजबूत आधार बनाने के लिए असम के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन की मदद ली है।

पूर्वोत्तर की सीमा से सटे भूटान तक पहुँचने के लिए आई.एस.आई. मुख्य रूप से सिलीगुड़ी, कूच बिहार, फुलबाड़ी तथा फासीबारा आदि रास्तों का इस्तेमाल कर रही है। खास तौर से सिलीगुड़ी को मुख्य रास्ते के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से लगे, सिलीगुड़ी शहर में बांग्लादेश और नेपाल दोनों और से आसानी से पहुँचा जा सकता है। सिलीगुड़ी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की संख्या बहुत बड़ी है, इसीलिए आई.एस.आई. एजेन्टों के लिए सिलीगुड़ी के माध्यम से फुनसिलिंग होकर भूटान जाना सरल है। इस प्रकार तीनों देशों के इस केन्द्र बिन्दु से मादक पदार्थों की तस्करी तथा अवैध हथियारों की आपूर्ति करके दोहरा खेल आई.एस.

[396] कृष्णानन्द शुक्ल द्वारा सम्पादित फस्तक ''सुरक्षा परिदृश्य'' में डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र का लेख – ''भारत के विरू(आई.एस.आई. की रणनीति'', पृष्ठ संख्या – 80

आई. द्वारा खेला जा रहा है। एक ओर जहाँ भारत–विरोधी अभियान को शक्तिशाली बनाने का कम किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उसने अपनी आय का एक बड़ा साधन भी जुटा लिया है।

आई.एस.आई. का आर्थिक आधार जहाँ पाकिस्तान की सेना व इसके लिए एक निर्धारित बजट पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है, वहाँ आई.एस.आई. अपने अनेक गुप्त अभियानों के द्वारा एक बड़ी मात्रा में आर्थिक आय जुटायी जाती है। अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी अमेरिकी अभियान को संचालित कराने के नाम पर पाकिस्तान की सेना व आई.एस.आई. ने करोड़ों अमेरिकी डॉलर की राशि हड़प कर अपना आर्थिक ढ़ाट्चा सुदृढ़ ही नहीं किया बल्कि अमेरिकी सेना के सहयोग के नाम पर उगाही का लंबा सिलसिला जारी है। अमेरिका को इस बात का अहसास हो चुका है, किन्तु एशिया विशेषकर दक्षिण एशिया में अपना एक सैनिक आधार स्थापित करने के लक्ष्य से पाकिस्तान की चाहे–अनचाहे मदद करनी पड़ती है। इसके साथ ही ''मुस्लिम देशों से 'जिहाद' (अन्याय के विरूद्ध लड़ाई) के नाम पर धन की उगाही की जाती है। मजहब के नाम पर बड़े–बड़े व्यवसायियों एवं राजनेताओं तक से रिश्ते बनाकर आर्थिक मदद ली जाती है। आई.एस.आई. की आय का स्रेतभारत में फर्जी कम्पनियों, मदरसों की मदद अथवा अन्य स्थानों से हवाला के जरिये होता हैं इसके अलावा अपने विभिन्न श्रेणियों के एजेंटों के माध्यम से मादक पदार्थों, विस्फोटकों, ड्रग्स, हथियारों व अन्य घातक व प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति तस्करी से करके धन इकट्ठा किया जाता है।''[397] इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आई.एस.आई. ने अपना आर्थिक आधार अत्यन्त मजबूत बना रखा है और इसके बल पर गरीबों की मदद के नाम पर उनकी भावनाओं को जीतकर घातक अंजाम दिलवाने की रणनीति बना रखी है।

''13 दिसम्बर 2001 को संसद हमले से सम्बन्धित अफरोज मोहम्मद नाम के युवक को नवंबर 2001 को गिरफ्तार किया गया। अफरोज गरीब परिवार में जन्मा ऐसा युवक है जो बड़े–बड़े सपने देखता हैं वह कॉमर्शियल पायलेट बनना चाहता था।''[398] लेकिन उसका पिता मामूली सा दर्जी था। वैसे भी अफरोज कॉलेज की पढ़ाई छोड़ चुका था। वह आस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड पायलेट बनने के लिए भी जा चुका था। आस्ट्रेलिया में उसने रॉयल विक्टोरियन एरो क्लब में 1997–98 में ट्रेनिंग भी की, परन्तु बीच में अधूरी ही छोड़ दी थी। 1998–99 में पुनः पायलेट बनने का ख्वाब लेकर वह टेक्सास के एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में भर्ती हुआ, परन्तु दोबारा प्रशिक्षण अधूरा छोड़कर घर लौट आया। तीसरी बार उसने

---

[397] डॉ. कुष्णानन्द शुक्ल, ''लालशीत युद्ध की दास्तान–भारत और पाकिस्तान'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/2, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, दूरभाष 011–23255141, पृष्ठ संख्या – 92

[398] डॉ. विपिन कुमार मिश्रा, डॉ. आशुतोष पाण्डेय, ''भारत और आतंकवाद'', 2012, विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली – 110002, पृष्ठ संख्या – 182

ट्रेनिंग इंग्लैंड में की। अनुमान किया जाता है कि तीनों देशों में उसकी ट्रेनिंग पर में कम–से–कम 60–70 लाख रूपये खर्च हुए। उसने मुम्बई पुलिस को बताया कि लंदन निवासी उसके एक चाचा ने उसका खर्चा वहन किया था, जिस पर विश्वास करना कठिन है। इसकी गिरफ्तारी मुंबई पुलिस द्वारा 2 अक्टूबर 2000 को की गई। क्योंकि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक अंतर्राष्ट्रीय क्रैश कार्डों का इस्तेमाल कर रहा है और पानी की तरह रूपया बहा रहा है। मुंबई पुलिस ने तहकीकात के दौरान पाया कि दिल्ली के एएनजेड गिंडलेज बैंक से उसके मुंबई खाते में सात लाख रूपये भेजे गये थे। किसने भेजे थे – इसका निवारण नहीं मिल सका। ऐसा अनुमान है कि भारत में सक्रिय कुछ उग्रवादी संगठनों ने उसे यह धनराशि भेजी थी। अफरोज सिमी का सदस्य है। यह आशंका जताई गई है कि अफरोज को यह धनराशि आत्मघाती दस्ते में भर्ती होने के लिए दी गई थी।

फलिस के पूछताछ के दौरान इसने अपना संबंध अलकायदा से बताया उसने काठमांडु से भारतीय विमान का अपहरण कर कंधार ले जाने वाले आतंकवादियों की भी पहचान की। उसने उनके उपनाम भी बताए। "अफरोज ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (अमेरिका) पर 11 सितंबर 2001 को हुए आत्मघाती हमले के 19 संदेहास्पद लोगों में से कम–से–कम आधा दर्जन लोगों की पहचान भी की जिनकी लिस्ट अमेरिकन (फेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन) ने तैयार की थी।"[399] उनमें से एक व्यक्ति अमेरिका के एक महत्त्वपूर्ण स्थान को उड़ाना चाहता था। उसने यह भी बताया कि उग्रवादियों ने एक साथ कई स्थानों पर नागरिक विमानों से आत्मघाती हमले करने की योजना बनाई थी, जिसमें ब्रिटेन का हाउस ऑफ कामर्स, आस्ट्रेलिया की रियल्टो टॉवर और भारतीय संसद शामिल है। 9 सितंबर को अंतिम आदेश दिए गए है। अपहरण किए जाने वाले विमान का यात्रा टिकट भी 10 सितंबर को दोपहर बाद खरीदे गए। लगता है कि उग्रवादी आखिरी समय में घबरा गए। अफरोज 22 सितंबर को मुंबई वापिस लौट आया और घर न जाकर एक होटल में ठहारा। उसने अलकायदा के आस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड में फैले जाल का पूरा विवरण दिया। संदेह के घेरे में लिए गए कुछ लोगों के साथ विमान चलाना सीखते समय उसने वेरीबी इस्लामिक सेंटर (विक्टोरिया) से कई मुलाकातें कीं। इस सेंटर का संचालन मौलाना मंसूर इलियास उर्फ मोहम्मद उस्मानी करता था जो अलकायदा के आत्मघाती दस्तों की भर्ती करने वाले संगठन का मेरूदंड था। संसद पर हुए हमले की सम्पूर्ण विश्व में निंदा की गई।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि लश्कर–ए–तैयबा एक बार फिर भारत में बड़े पैमाने पर खून–खराबा करने का मंसूबा बना रहा है। पाकिस्तान समर्थित इस आतंकवादी संगठन के निशाने पर गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के तटवर्ती क्षेत्र है। लश्कर ने खूरेजी का जिम्मा अपने गल्फ सेल को दिया है। तीनों राज्यों

[399] वही, पृ.सं. – 183

के तटीय क्षेत्रों में कई महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान अब लश्कर के निशाने पर हैं। ''भारत में 26/11 की तर्ज पर तबाही फैलाने के लिए लश्कर के इस सेल को खाड़ी के मददगारों से भारी धन मिल चुका है इसकी सूचना केन्द्र सरकार को है।''[400] गृह मंत्रालय ने तीनों राज्यों समेत सभी तटवर्तीय राज्यों को भी अलर्ट किया है।

वर्जीनिया स्थित जेम्सटाउन फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित सामयिकी 'टेररिज्म मानिटर' में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने लश्कर की मरीन विंग मुंबई में 26 नवम्बर 2008 को हुए आतंकी हमलों को दोहराने की साजिशों पर काम कर रही है। लश्कर का खाड़ी सेल पश्चिमी तट से घुसपैठ कर तबाही मचाने के फिराक में है। हाल में ही गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ने आशंका जताई थी कि आतंकी देश के अहम प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए पश्चिमी तट पर समुद्र मार्ग से घुसपैठ कर सकते हैं। गुप्तचर इकाइयों ने इस बात के लिए आगाह किया है कि भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के खाड़ी देशों से रिश्ते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लश्कर के कई सेल खाड़ी में ऑपरेट कर रहे हैं और भारत के खिलाफ आतंकी कार्यवाहियों के लिए उन्हें धन समेत हर तरह की मदद मिल रही है।

उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें आतंकवादियों द्वारा नए मार्गों का इस्तेमाल किया जाना, भारत के बाहर और भीतर नए ठिकानों की तलाश, आतंकवादियों को धनराशि मुहैया कराया जाना और लश्कर की नए आतंकवादियों की भर्ती की रणनीति में बदलाव की जानकारियाँ शामिल थीं। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा की जाँच के दौरान पता लगा था कि नवंबर 2008 के आतंकवादी हमलों के लिए पैसा लश्कर के खाड़ी नेटवर्क ने मुहैया करवाया था। जाँच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि बेंगलुरू, अहमदाबाद, दिल्ली और सूरत जैसी जगहों पर विभिन्न विस्फोटों की साजिश खाड़ी में सक्रिय नेटवर्क ने रची थी तथा इन घटनाओं को अंजाम भी इसी ने दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि इन सिलसिलेवार हमलों को इंडियन मुजाहिदीन और प्रतिबंधित इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। पश्चिम एशिया से आतंकवादी हमलों के मद्देनजर भारत खाड़ी देशों के साथ आतंकवादी विरोध समग्र संधि करना चाह रहा है। निस्संदेह आतंकवादी हमलों का देश भारत बन चुका है। प्रत्येक पंद्रह दिन के अंतराल में कोई–न–कोई नया धमाका, एक नई साजिश, एक नये आतंकवादी संगठन का नाम एवं उसका काम नये रंग–ढ़ंग में आ रहा है। आतंकवाद की आग में भारत निरंतर झुलसता जा रहा है। आतंकवाद की घातक गतिविधियों से जनमानस में भय और असुरक्षा की भावना बुरी तरह भर गई है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आई.एस.आई. ने अपने एजेंटों तथा उग्रवादी गुटों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में जाली नोट

[400] डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र, ''आतंकवाद व आपदा प्रबंधन'', 2010, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, पृष्ठ संख्या – 88

पहुँचा कर भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर बनाने की योजना भी तैयार की हैं रिपोर्ट के अनुसार इनमें से अधिकतर जाली नोट बैंकाक में छापे गए है। लेकिन काफी समय से ऐने नोट काठमांडु में छापने की भी व्यवस्था की गई है। और इसमें वहाँ स्थित पाकिस्तान दूतावास भी सक्रिय सहयोग दे रहा है। आई.एस.आई. ये जाली नोट भारत में विद्रोही गुटों तथा इस्लामी उग्रवादियों में वितरित करती है और कुछ बेईमान व्यापारी तुरंत धन बनाने के लिए इन नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही पदार्थों के अवैध धंधे से भी काफी गहरे जुड़े हुए है और उसने भारत के विद्रोही गुटों और इस्लामी उग्रवादियों को भी इस धंधे में शामिल कर लिया है। इसमें कहा गया है कि मादक पदार्थों का धंधा कराने का एक उद्‌देश्य भारतीय युवकों को तबाह करना और विश्व में भारत को बदनाम करना है। पाकिस्तानी सेना के कई कर्मी मादक पदार्थों के धंधे के लिए कुख्यात है और हथियारों के अवैध व्यापार से भी जुड़े हुए हैं।

पाकिस्तान की इस खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई. का मुख्य आर्थिक आधार अवैध हथियारों एवं सामग्री सहित मादक पदार्थों की तस्करी पर निर्भर करता है। अनेकों अरब डॉलर तक की राशि प्रतिवर्ष आई.एस.आई. के खजाने में जमा की जाती है। इसकी वास्तविक आय का उल्लेख कर पाना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि यह एक गोपनीय फण्ड होता है। इसके साथ ही पाकिस्तान के सभी बड़े बाजारों में हर तीसरी या चौथी दुकान में जिहादी गुटों के लिए दान–पात्रा रखे जाते है, क्योंकि वहाँ की आवाम के मन में यह बात बिठा दी जाती है कि मुजाहिदीनों की मदद करना अल्लाह का नजर में अच्छा काम है। इस्लामी स्कूल व मदरसों, प्रत्येक मस्जिद के एक हिस्से को जिहाद के केन्द्र के रूप में बदल दिया गया हैं वे कट्‌टर इस्लामी योद्धाओं के लिए उत्पत्ति के आधार हैं तथा एक बड़ा सहायक आर्थिक स्रेतभी है। आपको जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि शिक्षा पर सरकारी व्यय के विपरीत पाकिस्तान में उत्पन्न होते जिहादी तन्त्रा अत्यंत्रा संपन्न है। वर्षों से जिहादियों के साथ आई.एस.आई. की मिली–भगत से मादक पदार्थों की तस्करी करके करोड़ों डॉलर की राशि इकट्‌ठी की जाती है।

''पाकिस्तान का यह कुख्यात खुफिया तंत्र हथियार एवं अवैध धन के माध्यम से पाकिस्तान की राजनीति में भी अपनी पूरी पैठ बनाए हुए हैं। इस बात से कदापि नकारा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान की राजनैतिक प्रणाली पर राजनीतिज्ञों में असहमति के चलते वहाँ लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास नहीं हो सका है। इससे सैन्य बल के राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रोत्साहन मिला है सेना ने अपने आपको राष्ट्र की अखण्डता एवं विचारधारा का इकलौता रक्षक घोषित कर दिया है। वस्तुस्थिति यह है कि पाकिस्तान की सेना को वहाँ

की राजनीति में वीटो जैसा अधिकार प्राप्त है आई.एस.आई. का सेना पर पूरा प्रभाव है।''[401]

आई.एस.आई. का पाकिस्तान की राजनीति में जिया–उल–हक के कार्यकाल में जो दबदबा कायम हो गया था, वह आज भी बरकरार है। कट्टरपंथी व जिहादी संगठन के साथ सीधे जुड़ने के कारण इसके वर्चस्व को नकारने की हिम्मत किसी शासक में नहीं है। जनरल परवेज मुशर्रफ भले ही प्रत्यक्ष रूप से अपने आपकों शक्तिशाली साबित करने की बातें करे किन्तु हकीकत यह है कि आई.एस.आई. के इशारे पर ही उन्हें अपनी गतिविधियाँ करने के लिए मजबूर होना पड़ा हैं। आई.एस.आई. एक ऐसी एजेन्सी है जिसकी किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। अपनी गतिविधियों के लिए स्वतंत्र हैं ''आई.एस. आई. का आर्थिक आधार मादक पदार्थों की तस्करी, जिहाद के नाम पर चन्दा एकत्रित करना, मदरसों एवं मस्जिदों से भी अप्रत्यक्ष रूप से नेक काम करने के नाम पर पैसा ऐंठना तथा अपहरण करके व्यापारियों से धन उगाही करना, अलगाववादी गुटों से संपर्क करके उन्हें अवैध हथियार उपलब्ध कराकर धनराशि वसूलना, अल्पसंख्यक के नेताओं से साँठ–गाँठ करके अपनी प्रचलित संस्थाओं को स्वैच्छिक कोटे से धन आवंटित करवाना आदि है।''[402]

बांग्लादेश एवं नेपाल की सीमा से वहाँ के नागरिकों को अवैध रूप से प्रवेश करवाकर अपनी आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं और इनका प्रयोग अपने एजेन्ट के रूप में करते रहते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में मादक पदार्थों के व्यापार की एक अहम भूमिका है। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की 25–35 प्रतिशत पूर्ति नशीले पदार्थों द्वारा की जाती है। मगर मादक पदार्थों का व्यापक प्रचार–प्रसार अफगानिस्तान युद्ध के वर्षों में हुआ। अफगानिस्तान में डटी सोवियत सेनाओं से लड़ रहे अफगानिस्तानी मुजाहिदीन अमेरिका सरकार ने अरबों डॉलर के हथियार व धन दिया। यह समस्त सहायता राशि आई.एस.आई. के माध्यम से मुजाहिदीन तक पहुँचाई जाती थी। इस प्रकार आई.एस.आई. के धन ऐंठने का एक नायाब तरीका ढूँढ़ निकाला था। इन मुजाहिदीनों को शस्त्र एवं आर्थिक सहायता देने वाली सलाहकार मैडम एन्ड्रयू अल्वा ने अमेरिकी सीनेट में यह आरोप लगाया कि 1980–81 में उसे एक अरब 90 लाख डॉलर की सहायता दी गई जिसमें 7 करोड़ डॉलर की राशि का कोई हिसाब–किताब नहीं मिला। इसके अलावा विगत अनेक वर्षों की सहायत में भी बड़ी हेरा–फेरी हैं। इस पर मैडम अल्वा ने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी एवं आई.एस.आई. के अफसर अफगानी

[401] डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र व डॉ. आकाश मिश्र, ''भारत के पूर्वोत्तर में उग्रवाद'', पृष्ठ संख्या – 323

[402] डॉ. कृष्णानन्द शुक्ल, ''लालशीत युद्ध की दास्तान – भारत और पाकिस्तान'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, दूरभाष 011–23255141, पृष्ठ संख्या – 180

सहायता का लाभ उठाकर रातों–रात लखपति बन गए हैं। इसके साथ ही यह बात भी कही कि सहायता राशि का एक भाग आई.एस.आई. ने छद्म अभियान चलाने में व्यय किया।

आई.एस.आई. चूँकि पाकिस्तानी सेना का एक–दूसरे के सहयोगी के रूप में हैं और आई.एस.आई. का प्रशासनिक ढ़ट्टाचा एवं संरचना में पाकिस्तानी सैनिक अधिकारी ही तैनात होते हैं। यही कारण है कि इनका आपसी तालमेल अधिक रहा है। इसका पूरा लाभ उठाते हुए अमेरिकी सैनिक एवं आर्थिक सहायता को अफगानिस्तान में डटी सोवियत संघ की सेनाओं के विरूद्ध कम प्रयोग करके स्वयं ही दोनों वर्गों के बीच बाँट लिया। समाचार पत्र 'हेराल्ड' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार हेरोइन, अफीम, चरस व गाट्टजा आदि अनेक मादक पदार्थ एन.एल.सी. के ट्रकों में लाए जाते थे और एन.एल.सी. विभाग पूरी तरह पाक सेना के नियंत्रण में है। एन.एल.सी. पाकिस्तानी सेना का एक परिवहन (ट्रांसपोर्ट) विभाग है। इन ट्रकों के ड्राईवर व कुली तक नियमित पाक सैनिक होते थे। कराची तक के मार्ग में पुलिस भी इन ट्रकों की जाँच या निरीक्षण नहीं करती थी, क्योंकि ये ट्रक सेना के होते थे। फिर ''कराची से ड्रग की सप्लाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में की जाती थी। इस प्रकार आई.एस.आई. ने मादक पदार्थों के निर्यात को अपनी आमदनी का एक बड़ा स्रेतबनाया।''[403]

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि दैनिक 'डॉन' ने पाकिस्तान के आर्थिक कारनामों का सनसनीखेज खुलासा किया कि 1994–96 की बजट राशि में सरकारी खजाने से 30 अरब की राशि निकाली गई, किन्तु यह राशि किस मकसद से निकाली गई, इसका खुलासा नहीं किया जा सका। इस सबका आखिरी इशारा आई.एस.आई. और पाकिस्तान सेना की ओर किया गया। प्रश्न यह उठाया जाने लगा कि आखिर इतनी बड़ी धनराशि की क्या जरूरत पड़ी, जबकि इसके लिए पर्याप्त निर्धारित बजट राशि तय की जा चुकी थी। आई.एस.आई. की गतिविधियों से इसका अनुमान अवश्य लगा लिया गया। इससे पूर्व आस्लों (नार्वे) में एक पाकिस्तानी हमीद हसनेन को गिरफ्तार किया गया जिसे जनरल जिया–उल–हक का दत्तक फत्रा कहा जाता था। उस पर मादक पदार्थों की बड़े पैमाने पर तस्करी करने का आरोप लगाया गया। इसके लिए वह हबीब बैंक के आवरण का उपयोग करता रहा है। मिया नवाज शरीफ ने भी बेनजीर भुट्टो पर आरोप लगाया कि उन्होंने हबीब बैंक के युनूस हबीस से करोड़ो रूपये लिए है। इस प्रकार आई.एस.आई. ने अपने आर्थिक आधार को मजबूत बनाए रखने के लिए सरकारी बजट राशि की परवाह किए बिना बड़ी मात्रा में अन्य स्त्रोतों जैसे नशीली दवाओं, मादक पदार्थों व हथियारों की तस्करी आदि से अपनी कमाई का नायाब साधन भी ढड्ढूढ़ रखा है।

---

[403] डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र व डॉ. आकाश मिश्र, ''भारत के पूर्वोत्तर में उग्रवाद'', पृष्ठ संख्या – 325

नकली नोट (Fake Currency) की समस्या

''पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुँचाने की हरचंद कोशिशों में जुटी है। लगता है कि करेंसी नोट छापने के कागज आई.एस.आई. के हाथ लग गए हैं और यह इसका फायदा उठाकर आतंकियों को बेहिसाब पैसा उपलब्ध करा रही है। संसद की एक समिति ने सरकार से कहा है कि यह इस बात की जाँच कराए कि जिन विदेशी कंपनियों के साथ इस कागज की आपूर्ति को लेकर समझौता किया गया है, कहीं उन्होंने किसी दूसरे देश को भी इस कागज की आपूर्ति को लेकर समझौता किया गया है, कहीं उन्होंने किसी दूसरे देश से भी इस कागज की सप्लाई तो शुरू नहीं कर दी।''[404]

सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह की आशंका पहले भी रही है। खुफिया ब्यूरो के एक सूत्र ने कहा कि सरकार को इस बात की जानकारी है। सूत्रों का मानना है कि नोट छपाई में उपयोग आने वाली विशेष स्याही और कागज आई. एस.आई. को उपलब्ध है। अनुमान तो यह भी है कि भारतीय बाजार में उपलब्ध मुद्रा में 10 से 15 फीसदी नकली हो सकती है। वित्त मंत्रालय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि कई दशक बाद भी नोट का कागज बनाने और छपाई से जुड़ा पूरा काम अपने देश में नहीं होता। उसने सरकार से पूछा है कि हम अब तक क्यों विदेशी कंपनियों पर निर्भर है। नोट का कागज बनाने के लिए अब तक संयुक्त उद्यम पेपर मिल क्यों नही बना। सुरक्षा पेपर और इंक के लिए विदेशों के भरोसे रहने से देश पर नकली मुद्रा के प्रसार का खतरा मंडरा रहा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक नोट छपने वाला कागज देश में नहीं बनता। सरकार इसे ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों की छह कंपनियों से मंगाती है। इसके लिए कंपनियों से समझौता किया गया है कि वे किसी अन्य देश या संगठन को वह कागज नहीं बेचेंगी जिस पर भारतीय नोट छापे जा रहे हैं। समिति की रिपोर्ट में हालाँकि ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया गया है जिससे इस कागज के दुरूपयोग की बात सामने आए।

''जाली नोट के कारोबार के लिए करीब एक दशक पहले खड़े किये गये अपने नेटवर्क में आई.एस.आई. अब नई जान फूट्टकने की कोशिश में जुट गयी है। बीच के दिनों में नेपाल में जारी माओवादी हिंसा के भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमले की उसकी साजिश पर विराम लग गया था। माओवादियों और राजनीतिक दलों के बीच समझौता होने के बाद नेपाल में राजनीतिक स्थिरता आने के बाद काठमांडु में ठिकाना बनाया आई.एस.आई. ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर नये सिरे से हमला शुरू कर दिया है।''[405]

---

[404] अमर उजाला, 21 दिसम्बर 2008

[405] दैनिक जागरण, 4 दिसंबर 2006

आई.एस.आई. द्वारा नये सिरे से जाली नोटों की खेप भारत पहुँचाने की भनक मिलने के बाद सजग हुए महराजगंज के पुलिस अधीक्षक अमिताभ ठाकुर ने सीमा क्षेत्र के थाने और चौकियों की विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये थे। इसके परिणाम स्वरूप महराजगंज पुलिस को पिछले दिनों जाली नोटों की बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी मिली। साथ ही आई.एस.आई. के नेटवर्क से जुड़े तीन लोग गिरफ्तार किये गये। उन्होंने पूछताछ में आई.एस.आई. द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमले की नई रणनीति के बारे में चौंकाने वाली जानकारियाँ दी हैं। इस संबंध में पुलिस ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। सूत्र बताते हैं कि नये सिरे से शुरू किये गये 'आर्थिक युद्ध' (Economic War) का संचालन पहले की ही तरह काठमाण्डु स्थित पाक दूतावास से किया जा रहा है। पिछले दिनों महराजगंज पुलिस द्वारा सौनौली से जाली नोटों की बड़ी खेप के साथ पकड़े गये इस रैकेट के लोगों ने पूछताछ में इसकी फष्टि भी की है। उन्होंने कबूल किया है कि जाली नोटों की खेप पाकिस्तानी दूतावास द्वारा सप्लाई होती है। जिसे वे छुटभैया अपराधियों की मदद से भारत के विभिन्न शहरों में इस नेटवर्क से जुड़े लोगों के पास पहुँचाते हैं। वह लोग इन नोटों को अलग–अलग तरीकों से बाजार में उतार देते हैं।

यहाँ बता दें कि आई.एस.आई. ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए एक दशक पहले (वर्ष 1995) जाली नोट का खेल शुरू किया था। उसने काठमाण्डु स्थित पाकिस्तानी दूतावास के सहयोग से इस खेल के लिए पहले मजबूत नेटवर्क खड़ा किया था। इसके लिए मुख्य मोहरा बनाया गया नेपाल में रह रहे भारत से भगोड़े अपराधी मिर्जा दिलशाद बेग को। किन्तु वर्ष 1997 में मिर्जा की हत्या हो गयी। इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमले की कमान संभाल रहे काठमाण्डु स्थित पाक दूतावास में कार्यरत अशंद चीमा ने नये मोहरों की तलाश की इसके लिए उसने एक कुछ लोगों के माध्यम से भारत के भगोड़े और छुटभैया अपराधियों को अपने रैकेट मे जोड़ा। चीमा ने काठमाण्डु स्थित होटल करनाली और भैरहवां में अपना सेंटर बना कर जाली नोटों की खेप भारत भेजना शुरू कर दिया। इस बीच वर्ष 2001 में महराजगंज बॉर्डर पर जाली नोटों की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद चीमा का नाम पहली बार इस मामले में प्रमाणिक तौर पर आया। लेकिन पाक दूतावास जाली नोटों के कारोबार में उसके संलिप्तता से बराबर इन्कार करता रहा। काठमाण्डु में नेपाल पुलिस ने बड़े पैमाने पर जाली भारतीय मुद्रा के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ के बाद नेपाल पुलिस चीमा के आवास पर भी छापा मारा था। इस कार्यवाही के दौरान जाली नोट के कारोबार में उसके शामिल होने के कई ठोस प्रमाण मिले थे। इसी कारण नेपाल सरकार ने उसे देश छोड़ने का आदेश भी दिया था। अशंद चीमा के नेपाल से जाने के बाद भारत विरोधी इस अभियान की कमान सीधे तौर पर आई.एस.आई. ने संभाल ली। उसने मुम्बई से जान बचाने के लिए नेपाल में छिप कर रह रहे शातिर बदमाश अतिध्यान उर्फ लाली की जाली नोट के रैकेट की कमान सौंपी। उसके सहयोग से आई.एस.आई. ने नेपाल में

शरण लिये भारत के छोटे अपराधियों पर अपना दाव लगाना शुरू किया। अपना दाव लगाना सबसे मुनासिब मान लिया। इनकी मदद से भारत के सीमाई इलाके से लेकर बड़े शहरों तक में जाली नोट के कारोबारियों का नेटवर्क खड़ा करने में उसे कामयाबी मिली। हालाँकि इस बीच गोरखफर जागरण के 21 सितम्बर 2014 के अंक में जाली नोट के नेटवर्क पर छपी एक खबर के बाद दिल्ली पुलिस ने पाँच पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ कर बड़े पैमाने पर जाली नोटों की बरामदगी की थी। दिल्ली पुलिस की सूचना पर कई अन्य स्थानों से इस रैकेट से जुड़े लोग पकड़े गये। इसी दौरान नेपाल में माओवादी हिंसा के चलते वहाँ राजनैतिक अस्थिरता का माहौल बन गया। परिणाम स्वरूप आई.एस.आई. और पाकिस्तानी दूतावास को जाली नोट के खेल को अस्थाई तौर पर रोकना पड़ा था। अब नये सिरे से इस खेल के शुरू होने पर खुफिया एजेंसियाँ चौकन्नी हो गयी हैं।

''भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट देने के लिए पाक खुफिया एजेन्सी आई. एस.आई. एक बार फिर से सक्रिय हो चुकी है। इस बार हाईटेक तैयारियों के साथ वह धंधे में उतरी है। आई.एस.आई. की ताजा सक्रियता से पुलिस व अभिसूचना तंत्र के कान खड़े हो गये हैं। पिछले एक वर्ष में जाली नोट के कारोबार में पाक खुफिया संगठन आई.एस.आई. की सक्रियता बढ़ी है। इसके लिए भारत–नेपाल की 1600 कि.मी. की खुली सीमा कारोबारियों के लिए मुफीद बन गयी है। इसके जरिये वह पूरे भारत में जाली नोटों का संजाल फैला रहे हैं।''[406]

सूत्रों के मुताबिक आई.एस.आई. द्वारा इस बार दो किस्म के भारतीय जाली नोट तैयार किये गये हैं। इनमें से एक को उनके एजेंट 65 रूपये व दूसरे को 50 रूपये सैकड़ा की दर पर भारत में बैठे सहायक एजेन्टों को सप्लाई कर रहे हैं 65 रूपये वाले जाली नोट इतनी बारीकी सै तैयार किये गये हैं कि बैंक कर्मी तक धोखा खा रहे हैं। बैक कर्मी भी मानते हैं कि कारोबारियों ने इस बार वास्तविक नोट की कॉपी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी गत 16 सितम्बर को जिले के सदर थाना की पुलिस ने 14 हजार के नकली नोटों के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा था। पुलिस के मुताबिक बरामद नोट नेपाल से आये थे। इसके अलावा 7 दिसम्बर को गोरखफर की खजनी पुलिस ने नंदापार मोड़ से गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जनप्रिय बिहार कॉलोनी निवासी दीपक व प्रखर जायेसवाल नामक युवकों के पास से 46 सौ के जाली नोट बरामद किये थे। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने स्वीकार किया था कि नेपाल में बैठे आई.एस. आई. के एजेन्टों के माध्यम से उन्हें जाली नोट मिलते रहे हैं।

खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाक खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. नेपाल के वीरगंज, बुटवल, भैरहवां, कृष्णानगर में बैठे एजेन्टों के माध्यम से इनका कारोबार करती है। ताजा सूत्रों के मुताबिक आई.एस.आई. अब पाकिस्तान के बजाये नेपाल में ही जाली नोटों का प्रिंटिंग व स्केनिंग का काम कर रही है। पुलिस के

[406] दैनिक जागरण, 20 दिसम्बर 2007

मुताबिक इस कारोबार मे कोई भारतीय सफेदपोश भी शामिल है। भरोसेमंद सूत्रो पर यदि यकीन करें तो नेपाल के वाहन लिफ्रटरों का गिरोह इस समय जाली नोट के सौदागरों के कैरियर बड़े हुए हैं। उन्हीं के जरिये वह भारतीय क्षेत्रों में जाली नोटों की खेप पहुँचा रहे हैं।

जाली नोटों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद करने के लिए पाक खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई. ने इस बार नयी चाल चली है। अरबों रूपयों के नकली नोटों को खपाने के लिए उसने नकली माओवादियों पर दांव लगाया है। नेपाल की जरायम की दुनिया की जानकारी न रखने वाले लोगों के लिए नकली माओवादी जैसा शब्द सुनने में अटपटा लग सकता है, परन्तु यह वास्तविकता है कि ऐसे तत्त्व माओवादियों के गिरोह में भारी तादाद में अपनी पैठ बनाये हुए हैं नेपाल के तमाम छुटभैये बदमाशों के अलावा समृ(किसानों व अधिकारियों के परिवारों के अनेक लोगों ने माओवादी संगठन की सदस्यता ले रखी है। ऐसे लोगों के माओवादी सदस्य बनने के लिए अनेक कारण है। किसी को अपनी जमीन जायेदाद बचानी है तो किसी को नौकरी और किसी को जान। ऐसे लोगों में भारतीय मूल के किसानों व अपराधियों की तादाद अपेक्षाकृत जयादा है। वर्तमान में भारत से सटे नेपाल की तराई पट्टी में कम–से–कम पाँच हजार व्यक्ति ऐसे हैं, जो भारतीय मूल के होते हुए भी माओवादी सदस्यता ग्रहण किये हुए है।

भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक आई.एस.आई. ने ऐसे ही नकली माओवादियों को इस बार अपना मोहरा बनाया है। आई.एस.आई. की नेटवर्किंग के प्रमुख सदस्य नकली माओवादियों को 40 प्रतिशत कमीशन की दर पर एक हजार रूपये का जाली नोट सौंपते हैं। ये लोग नोटों के बंडल को अपने बलबूते पर भारतीय क्षेत्रों में सप्लाई करते हैं। चूँकि जाली नोटों के यह कैरियर माओवादी खेमे और भारतीय मूल के होते हैं। इसलिए सीमा के इस पार या उस पार ऐसे लोगों पर कोई संदेह नहीं होता है। यह नकली माओवादी नकली नोटों के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा माओवादी नेतृत्व को दे देते हैं, जिससे नेतृत्व उन पर मेहरबान रहता है शेष पैसे वह गिरोह की महिला सदस्यों पर खर्च करते हैं अथवा अपने परिवार को दे देते हैं। नेपाली अण्डरवर्ल्ड की जानकारी रखने वालों की बातों पर विश्वास करें तो तीन वर्ष पूर्व काठमाण्डु स्थित पाकिस्तानी दूतावास के प्रथम सचिव अरशद चीमा को जाली जाली नोटों के कारोबार के आरोप में नेपाल से निकाले जाने के बाद ठप पड़ गया फिर यह धंधा चार महीने से पुनः शुरू हो गया है। इस बार यह धंधे का संचालन पाकिस्तानी दूतावास के सचिव स्तर पर का एक अधिकारी कर रहा है। खबर है कि इस बार एक हजार के नोटों की छपाई का कार्य बांग्लादेश स्थित चटगाँव की पहाड़ियों में हो रहा है। यहीं पर आई.एस.आई. का प्रशिक्षण केन्द्र भी है, जिसका सरगना भारतीय भगौड़ा व पिलखुआ (गाजियाबाद जनपद) का शातिर अपराधी अब्दुल करीम टुण्डा है। बताया जाता है कि टुण्डा नकली नोटों को काठमाण्डु के एक चर्चित होटल में लाते हैं, वहीं से

उन्हें नकली माओवादियों के हवाले कर दिया जाता है। फिर तथाकथित माओवादी बिहार के सिकटा, उत्तर प्रदेश के सोनौली, बढ़नी, बहराईच, लखीमफर व उत्तरांचल के पिथौरगढ़, धारचूला आदि क्षेत्रों की खुली सीमा से नोटों की खेप भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करा देते है। यद्यपि एक हजार के जाली नोटों के प्रचलन के बारे में दैनिक जागरण के रहस्योद्घाटन के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों से नकली नोटों की बरामदगी की सूचनाएँ मिल रहीं हैं, परन्तु इसका सर्वाधिक प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। सिद्धार्थनगर जनपद में तो एक हजार, पाँच सौ, सौ व बीस रूपये के नकली नोटों के प्रचलन के कई मामले प्रकाश में आयें है। गत दिवस सीमावर्ती कस्बा ककरहवा में एक हजार, अलीगढ़वा में बीस रूपये के जाली नोट बरामद हुये। इसके अलावा फरान नौगढ़ कस्बे में जुआ खेलते पकड़े गये कथित जुआरियों के पास से भी हजार के जाली नोट बरामद हुए। इसके अलावा गोरखफर, कुशीनगर, बनारस आदि स्थानों पर भी जाली नोटों की बरामदगी की सूचनाएँ मिली है। जाहिर है कि आई.एस.आई. को ताजा सरगर्मी से पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई प्रांतों में जाली नोटों का कारोबार तेजी से जड़ें जमा रहा है। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक असीम अरूण ने बताया कि उनके जवान सीमा क्षेत्रों में दिन–रात सक्रिय रहते हैं। अतीत में जाली नोटों के साथ पकड़े जाने पर लोगों के खिलाफ मुकदमें भी लिखें गये है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भी ऐसी सूचनाएँ मिलने पर पुलिस तत्काल कार्यवाही करती है। उन्होंने जनपदवासियों से इस प्रकार की जानकारी मिलने पर निकटतम थानों में तत्काल सूचना देने की अपेक्षा की है।

जम्मू–कश्मीर के आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की करेंसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। यह खुलासा होने के बाद अब सोलन पुलिस का एक दल कुपवाड़ा जिला के ऋशिकुंड जाने की तैयारियों में जुट गया। एसपी ने कुपवाड़ा ने एसपी सुनील कुमार से संपर्क साध रफीक अहमद का पूरा लेखा–जोखा माँगा है पुलिस पूछताछ में यह पता चला है कि उसका एक दोस्त रात्रि के समय पाकिस्तान से आकर वहाँ के कश्मीरियों को नकली नोट देता है।

सोलन पुलिस का दल इस संदर्भ में कुपवाड़ा जिला के ऋशिकुंड में जाने की तैयारियाँ कर रहा है। इस संदर्भ में जिला के पुलिस अधिकारी भले ही चुप्पी साधे हो मगर सूत्र बताते है कि सोलन पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार जम्मू–कश्मीर पुलिस से संपर्क साधे हुए है। रफीक के बयान के अनुसार एक आतंकी संगठन ने एक लाख की नकली करेंसी भारत के विभिन्न हिस्सों में असली करेंसी में बदलने के उद्देश्य से दी है। पहली खेप में इस कश्मीरी को 20 हजार की नकली करेंसी दी गई थी और वह इसी माह कुपवाड़ा जाकर इस नकली करेंसी के बदले भारत की असली करेंसी देने वाला था। पुलिस को उसके पास से हजारों रूपये के लुधियाना (पंजाब) की एक कंपनी के बिल भी बरामद हुए है।

गौरतलब है कि जम्मू–कश्मीर के आतंकियों द्वारा नकली नोट देकर हिमाचल में भेजने के मामले में सदर पुलिस ने 13 कश्मीरी युवकों से भी पूछताछ की है, जिनके अनुसार रफीक को कुछ ही समय में अमीर बनता देख हम लोग भी हिमाचल में रोजगार के लिए आ गए। सदर पुलिस ने एक कश्मीरी युवक को दो हजार के नकली नोटों के साथ पकड़ा था, बाद में पुलिस ने उसके निवास से 17 हजार के नोट बरामद किये। पुलिस का कहना है कि उक्त रफीक वर्ष 1998 में सोलन में आता जाता रहा है लेकिन वर्ष 2004 में यह सोलन कब आया इसकी जानकारी कागजों में कही दर्ज नहीं हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरोह के अन्य सदस्य भी हिमाचल में ही कहीं छिपे है जिसकी जानकारी रफीक को है। उसका एक भाई भारतीय फौज में है और यह व्यक्ति आतंकवादियों के इशारे पर हिमाचल, हरियाणा, पंजाब में अलग–अलग नामों से रहकर नकली नोटों को बाजार में चलाता था। सदर पुलिस ने 17 हजार के नकली नोट बरामद कर उसके खिलाफ भादस की विभिन्न धाराओं के के तहत हिरासत में लेकर आठ दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया।

''सोलन के विधायक एवं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि देश द्रोही तत्त्व हिमाचल प्रदेश को अपनी शरणस्थली बनाने में जुटे है। सोलन में जिस प्रकार नकली नोटों का मामला बार–बार सामने आ रहा है वह चिंता का विषय है। लखनऊ पुलिस ने पिछले महीने पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आई.एस. आई. के दो एजेण्टों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से जो नोट बरामद किये, वे नकली हैं, यह पुष्ट करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जुलाई में अयोध्यया में हुए आतंकवादी हमले में शामिल रहे आतंकवादियों ने भी दिल्ली व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जाली नोट चलाये। पुलिस सूत्रों पर भरोसा करें तो उत्तर प्रदेश में जो जाली नोट आ रहे हैं उनमें बड़ी संख्या आतंकवादियों द्वारा भेजे जाने वाले नोट की है।''[407]

ईओडब्लू के विशेष सेल के पुलिस महानिरीक्षक अरविन्द कुमार जैन का कहना है कि कुछ स्थानीय लोग स्कैनर से जाली नोट बना रहे हैं पर वे पाकिस्तान से आ रहे नोट के मुकाबले बाजार में नहीं टिकते। यही वजह है कि पाकिस्तान से आने वाली जाली नोट की माँग अधिक है। पुलिस उन्हीं को पकड़ती है जो जाली नोटों को चलाते हुए पकड़े जाते हैं। कई बार उन्हें भी नहीं पता होता कि ये नोट कहाँ से आ रहे हैं। यही वजह है कि गिरोह का सरगना पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता। पुलिस सुत्रों पर भरोसा करें तो देश में जाली नोटों का संचालन पिछले 20 वर्षों से हो रहा है पर इधर एक दशक से इसमें तेजी उस समय आई जब पाकिस्तान से नोटों का आना शुरू हुआ। जाली नोट पाकिस्तान से आ रहे हैं। इसका खुलासा पहली बार 1993 में हुआ था। उस समय नेपाल से बढ़नी के रास्ते जाली नोटों की खेप प्रदेश में पहुँचायी जा रही थी। नेपाल में पाकिस्तान से ये नोट वहाँ के दबंग सांसद रहे मिर्जा दिलशाद बेग तक पहुँचते थे। मिर्जा नेपाल की

[407] सहारा समय, 17 सितम्बर 2005

सीमा पार कराकर प्रदेश में फैले एजेण्टों तक भिजवाता था। एजेण्ट 30 से 40 रूपये में सौ रूपये का एक जाली नोट बेचते थे। पुलिस ने कई बार मिर्जा को घेरे में लेने की कोशिश की लेकिन वह पकड़ा नहीं जा सका। जब कभी वह नेपाल से गोरखफर तक आता था, पुलिस को इसकी खबर नहीं लग पाती थी। एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि मिर्जा दिलशाद बेग जाली नोटों के साथ ही अपनी चोरी की गाड़ियों का कारोबार देखने के लिए गोरखफर तक आता था।

ईओडब्ल्यू (EOW) की विशेष सेल की एक रिपोर्ट पर गौर करें तो हम महीने 50 से 60 करोड़ रूपये के जाली नोट प्रदेश में आ रहे है। इनमें स्कैनर से छापे जाने वाले नोट भी शामिल है। पाकिस्तान से आने वाले जाली नोट काठमाण्डु के रास्ते बढ़नी व भैरवां होते हुए उत्तर प्रदेश में पहुँचते है। नेपाल की बिहार व उत्तरांचल से लगने वाली सीमा के रास्ते से भी जाली नोट आते हैं। जम्मू–कश्मीर के रास्ते से भी देश में जाली नोट भेजे जा रहे हैं दरअसल पाक अधिकृत कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठन भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराते हैं और साथ में जाली नोट भेज देते है। कभी ये घुसपैठ कश्मीर के फंछ के रास्ते होती है तो कभी नेपाल के रास्ते। अगस्त के पहले हफ्ते में जाली नोटों की खेप के साथ पकड़े गये। ''मोबिन अंसारी व अशफाक अहमद उर्फ राजू ने लखनऊ पुलिस के समक्ष खुलासा किया था कि उन्हें काठमाण्डु स्थित पाकिस्तानी दूतावास से जाली नोटों की खेप मिली थी। दरअसल ये दोनों युवक पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आई.एस. आई. के लिए भी काम करते है। राजू उर्फ अशफाक जाली नोट गोरखफर होते हुए दिल्ली तक पहुँचाता है।''[408]

प्रदेश में जाली नोट कश्मीर में सक्रिय तीन आतंकवादी संगठन प्रमुख रूप से पहुँचा रहे है। ये आतंकी संगठन है लश्कर–ए–तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश–ए–मुहम्मद। जैश–ए–मुहम्मद ने इसी साल पाँच जुलाई को अयोध्या में राम मन्दिर पर आतंकवादी हमला किया था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अयोध्या में पुलिस के हाथों मारे गये पाँच आतंकवादी भी जाली नोट लेकर फंछ के रास्ते कश्मीर पहुँचे। फिर वहाँ से दिल्ली व अलीगढ़ होते हुए अयोध्या तक गये। दिल्ली में इन आतंकवादियों ने जाली नोट चलाये। इन आतंकवादियों के सरगना मुहम्मद कारी ने इन्हें जाली भारतीय नोट ही दिये थे। अभी हाल में यूपी खुफिया एजेन्सियों की सूचना पर दक्षिण–पश्चिमी दिल्ली व बिहार पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में 55 हजार रूपये के जाली नोट के साथ वीरेन्द्र कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी जब तक वीरेन्द्र के जरिये 40 लाख रूपये का जाली नोट चला चुके है। बिहार का असलम अंसारी

---

[408] डॉ. कृष्णानन्द शुक्ल, ''लाल शीत युद्ध की दास्तान – भारत और पाकिस्तान'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, दूरभाष 011–23255141, पृष्ठ संख्या – 191

जाली नोटों का बड़ा दलाल बताया जाता हैं। असलम को ये जाली नोट जाबू उर्फ डैडी जो लश्कर का आतंकवादी है उसके जरिये मिलते है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि असलम के देशभर में 50 से अधिक दलाल है। इसमें 25 दलाल तो उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। विशेष सेल के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक ए.के.जैन का कहना है कि फिलहाल उनका सेल जाली नोटों के उन मामलों की जाँच करता है जो अन्तरप्रान्तीय हैं।

सी.बी.आई. द्वारा बहुचर्चित जाली नोट प्रकरण में डुमरियागंज से उठाए गए ईंट भट्ठा मालिक अब्दुल गनी का नेटवर्क सीमावर्ती सोनौली–नौतनवां से लेकर नेपाल तक फैला हुआ है। नौतनवां में अब्दुल गनी का अपना एक मकान भी हैं जहा उसकी एक दूसरी बीवी रहती है। बताया जाता है कि अब्दुल गनी का व्यक्तित्व शुरू से ही रहस्यमय है। सन् 2005 के आसपास वह रीयल स्टेट के धंधे में पहली बार यहाँ आया और फटाफट कई जमीनों को खरीद कर उसे बेचने का काम शुरू कर दिया। सूत्रों का कहना है कि उसके नेटवर्क नेपाल तक फैले हुए है और एक तलाकशुदा युवती सलमा को बतौर बीवी के रूप में यहाँ रखे हुए है। उसने उसके लिए एक मकान भी बनवा दिया है।

आज अखबारों में सी.बी.आई. द्वारा उसे डुमरियागंज के बहुचर्चित जाली नोट प्रकरण में उठाए जाने की खबरें छपने के बाद उसे लेकर सीमार्वी बाजार में चर्चाओं और अफवाहों की बाजार गर्म रही। ''सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 10 नवंबर को अब्दुल गनी अंतिम बार नौतनवां आया था तथा अपनी कथित बीवी से भी मिलने गया था कहा जाता है कि नौतनवां में एक तलाकशुदा मुस्लिम युवती को बतौर बीवी के तौर पर रखे जाने से अब्दुल गनी ने घर वाले भी उससे रूष्ट रहते थे और सार्वजनिक तौर पर दूसरी बीवी को लेकर मारपीट तक हुई। आज इस संवाददाता द्वारा अब्दुल गनी के बारे में की गई छानबीन में पता चला कि उसका नेटवर्क नेपाल तक फैला हुआ है तथा वह स्क्रैप के धंधे में भी शामिल है।''[409] सूत्रों का कहना है कि फिलहाल सीबीआई उससे डुमरियागंज बैंक से गायब 70 लाख रूपये के बारे में पूछताछ कर रही है। मूल रूप से डुमरियागंज के ग्राम अवसानफर (मिश्रौलिया) का निवासी अब्दुल गनी नौतनवां बाईपास पर बनाए गये अपने एक मकान में भी थोड़े दिन रहता था जिसे बाद में उसने बेच दिया जबकि शुरूआती दिनों में वह यहाँ एक किराए के मकान में रहा करता था। वैसे भी जाली नोटों का कारोबार सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी दिनों से फैला हुआ है।

नेपाल से भारत में जाली नोटों की बड़े पैमाने पर आवक तथा काठमांडु स्थित पाकिस्तानी दूतावास में पाकिस्तानी राजनयिक सीमा भी भारी मात्रा में जाली नोट के साथ पिछले दिनों गिरफ्तारी के दौरान यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि जाली नोटों की खेप एक साजिश के तहत यहाँ भेजी जाती है। सीमावर्ती थानों में कई बार पकड़े गए लोगों ने

---

[409] राष्ट्रीय सहारा, 25 नवम्बर 2008

भी यह स्वीकार किया है कि नेपाल में बड़े पैमाने पर भारतीय जाली नोट उपलब्ध है। ग्लोबल मंदी के चलते घुटने के बल रेंगती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुबई पर हुआ आतंकवादी हमला घातक साबित हो सकता है। इससे बेदम शेयर बाजार को तगड़े झटके लग सकते है और पहले से ही खस्ताहाल पर्यटन, एविएशन और होटल उद्योग के लिए बेहद मुश्किल वक्त आ सकता है। आर्थिक राजधानी में इस तरह की घटना होने से देश में होने वाले विदेशी निवेश पर भी असर पड़ने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। हमला के मद्देनजर जानकारों का मानना है कि डॉलर की तुलना में कमजोर रहे भारतीय रूपये की कीमत और गिरने की उम्मीद है।

वर्ष 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए विस्फोटों की जाँच पड़ताल में जुटी एजेंसियों ने इस बात का खुलासा किया था कि आर्थिक महत्त्व के कारण ही मुंबई आतंकवादियों के लगातार निशाने पर है। मुंबई के अलावा हैदराबाद, बेंगलूर, कोयंबटूर, दिल्ली को भी आतंकवादियों ने इसलिए चुना कि ये शहर भी आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र हैं। जानकारों का मानना है कि जान–माल को नुकसान पहुँचाने के हैदराबाद के गोकुल चाट भंडार के धमाकों में संदिग्ध दो लोग भारत में नकली नोट लाने के मामले में भी वांछित : जाँच एजेंसियाँ। इस साल जुलाई में कोलंबों में भारतीय नकली नोटों की बड़ी खेप के साथ दो पाक नागरिक गिरफ्तार।

किसी गफलत में मत रहिये, यह तथ्य इस बात के सुबूत है कि भारत में अब आतंक का खेल भारतीय पैसे से भी खेला जा रहा है। आतंक को पालने–पोषने के वर्षों के अनुभव के सहारे पाक खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. ने आतंक के वित्त पोषण को काफी हद तक संगठित कर लिया है और नकली नोट इस अर्थतंत्र का एक मजबूत आधार बन गए है। आई.एस.आई. डी कंपनी की मदद से बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड और दुबई के अपने अड्‌डों के जरिये नकली नोट भारत में झोंकती है। हालात यह है कि अब देश के कई इलाकों में आतंक की फसल को पालने के लिए आई.एस.आई. को बाहर से पैसा लाने तक की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के करीब दो दर्जन शहर इस कारोबार का गढ़ बन रहे है, इस साल जुलाई में उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में स्टेट बैंक की शाखा से 1.5 करोड़ रूपये के नकली नोटों की बरामदगी लोगों को भले ही याद हो पर अप्रैल में ढ़ाका में 50 लाख रूपये की भारतीय मुद्रा के साथ नौशाद आलम खान की गिरफ्तारी बहुतों के दिमाग से उतर चुकी होगी। लेकिन नौशाद आलम खान की गिरफ्तारी के साथ बांग्लादेश में सक्रिय आतंकी संगठन हुजी और नकली नोटों के रिश्ते एक बार फिर प्रमाणित हुए है। नौशाद खान के हुजी प्रमुख मुफ्रती अब्दुल हन्नान से सीधे संपर्क पाए गए है और दोनों तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में जंग लड़ चुके है।

इसी हन्नान के खिलाफ ढ़ाका में चार्जशीट दायर की गई है। अगर खुफिया एजेंसियों के अंदरूनी आकलन पर भरोसा किया जाए तो भारत में 20 फीसदी मुद्रा नकली हो सकती है। यह आकलन यदि आधा भी सही है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह साजिश कितनी गहरी और बड़ी है।

साजिश यकीनन बड़ी है क्योंकि पिछले साल गोकुल चाट भंडार धमाके से पहले हैदराबाद में नकली नोटों की एक बड़ी खेप मिली थी और इन बमों को रखने के दौरान घायल हुए दो संदिग्ध व्यक्ति नकली नोटों की बरामदगी के सिलसिले में भी वांछित थे। मुंबई पुलिस ने पाया है कि नकली नोटों के एजेंट करीब 30 फीसदी डिस्काउंट पर नकली से असली नोट बदलते हैं और यह पैसा आतंकी स्लीपर सेल्स को जाता है। अकेले मुंबई में इस साल अलग–अलग मामलों में 27 लोग पकड़े गए हैं जिनमें 13 बांग्लादेशी हैं और मार्च में पकड़े गये दो बांग्लादेशियों के पास तो नकली मुद्रा के साथ दो किलो आरडीएक्स भी मिला था। ''खुफिया सूत्र मानते हैं कि पाक सरकर में पहुँच के जरिये नोट छापने वाली सिक्योरिटी इंक यानि स्याही और कागज को हासिल करना आई.एस.आई. के लिए बायें हाथ का खेल है, इसलिए नकली नोट इतने 'असली' दिखते हैं।''[410]

भारत में आतंकियों को मौत की नींद सुलाने वाले सुरक्षा बल जरूर है लेकिन आतंक की वित्तीय नस काटने वाले दक्ष हाथ नहीं तभी तो सूचनायें और तथ्य होने के बाद भी आतंकी अर्से से सभी वित्तीय चैनलों का इस्तेमाल कर रहे है। यहाँ फलता–फूलता हवाला है, फर्जी कंपनियाँ है, मनी लॉड्रिंग के असंख्य रास्ते है, कैश कुरियर्स है, फर्जी पहचान के जरिये मिलने वाले क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड व बैंक खाते हैं और सबसे ऊपर है एक सोता हुआ और अक्षम सुरक्षा तंत्र। इसलिये भारत में उद्योग लगाना भले ही मुश्किल हो आतंक फैलाना खासा आसान हो चला है।

कहने को भारत में एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) भी है, जिसने पिछले दो साल में बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से संदिग्ध वित्तीय लेन–देन की करीब 1000 सूचनायें व रिपोर्ट जुटा कर खुफिया एजेंसियों को भेजी है। सूत्रों का कहना है कि इसमें 200 से ज्यादा रिपोर्ट सीधे आतंक के धंधे से जुड़ी हो सकती है। लेकिन इनसे मगजमारी कर आतंक की नस पकड़ने की फुर्सत किसे है। भारतीय एजेंसियों में आतंक के वित्तीय तंत्र से निपटने की विशेषज्ञता भी नहीं है इसलिए ही तो आतंक के इतने लंबे दौर के बावजूद वित्तीय तंत्र को भेद कर आतंक की गर्दन पकड़ने की सफलता कभी नजर नहीं आई।

आतंकियों के **बैंक खातों** पर चौकिये मत! भारतीय बैंकिंग तंत्र अर्से से आतंकियों के प्रयोग में आ रहे है। लगभग आठ साल पहले गिरफ्तार एक आतंकी मेहराजुद्दीन हफीज ने जाँच एजेसियों को बताया था कि वह खाड़ी के देशों से पैसा मट्टगाने के लिए एक सरकारी बैंक के खाते का इस्तेमाल 1995 से कर रहा था। यह बात गृह मंत्रालय ने 2002 में संसदीय समिति को बताई थी। भारत में बैंक खाता खोलना आम लोगों के लिए कठिन है लेकिन आतंकियों के लिए आसान। अक्टूबर 2006 में मैसूर में गिरफ्तार अलबदर का आतंकी मुहम्मद फहद भी काफी समय में एक निजी बैंक के खाते के जरिये आतंक का खेल खेल रहा

---

[410] दैनिक जागरण, 3 दिसम्बर 2008

था। हाल में ही इंडियन मुजाहिदीन के गिरफ्तार आतंकियों के बैंक खाते भी सील हुए है जिसमें देश के बाहर से पैसा आया है।

और **क्रेडिट कार्ड!** मुंबई हमले में मारे गए लश्कर के आतंकियों से मिले क्रेडिट कार्डों ने जाँच एजेंसियों को चौका दिया है लेकिन अगर एजेंसियों ने सितंबर 2006 में उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार पाकिस्तानी एजेंट लारीब के पास मिले डेबिट कार्ड के सूत्र को पकड़ा होता तो शायद देश में आतंकियों द्वारा क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की कई पर्ते खुलती। टेरर फाइनेंसिंग पर एफएटीएफ की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के कई देशों में आतंकी संगठनों ने संगठित तौर पर क्रेडिट कार्ड चुराकर उसके जरिये धन का लेन–देन किया और अवैध धन को वैध करने का काम यानि मनी लॉड्रिंग भी। बेल्जियम और यूनाईटेड किंगडम ने आतंक के ऐसे रैकेट तोड़े है। ध्यान रहे कि भारत में भी क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के मामलों की संख्या बढ़ रही है। जिस देश के जरिये एक खराब डॉलर की मनी लॉड्रिंग हर साल की जाती हो वहाँ आतंक के लिए पनपने नहीं बल्कि फलने–फूलने का हर मौका मौजूद है। फर्जी कंपनियों के जरिये विदेश से धन मङ्गाकर आतंकियों को धन पहुँचाने के मामले कई देशों में पकड़े गए है। भारत में ऐसा होना अचरज नहीं है पर यह बात जरूर आश्चर्यजनक है कि भारत में मनी लॉड्रिंग रोकने का कानून 2005 से मौजूद है। लेकिन तीन साल बाद हाल में ही सरकार को इसे आतंकियों पर लगाने की सुध आई है। बेंगलोर में विस्फोट की साजिश करते पकड़े गए अलबदर और लश्कर के उन आतंकियों पर हाल में ही यह कानून लगाया गया है। जिन्होंने हवाला के जरिये पैसा हासिल किया था। और **हवाला!** आतंक से इसके रिश्ते स्थापित है। एक आकलन के मुताबिक वैध रास्ते से आने वाले कुल धन के 40 फसीदी के बराबर राशि हवाला से आती है। भारत में रिजर्व बैंक के जरिये सालाना करीब 28 अरब डॉलर आते है। लेकिन अब 9/11 के बाद दुनिया में नया रूख उभरा है और आतंकी अब कैश कुरियर्स के जरिये पैसा भेजने लगे है। भारत में इस पर निगाह ही नहीं है। अमेरिका में आतंकवाद और वित्तीय सतर्कता के उप मंत्री स्टुअर्ट लेवी ने 9/11 के बाद कहा था कि "आतंकियों का वित्तीय तंत्र तालाबों जैसा नहीं बल्कि नदियों जैसा है। जिसमें धन लगातार आता–जाता रहता है।"[411]

किसी को इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि आतंक का अर्थव्यवस्था से कोई सीधा रिश्ता नहीं है। भूल जाइये वह दौर जब फिदायीन किसी अलगाववादी मकसद को हासिल करने भर के लिए मौत बाँटते थे अब बात बदल चुकी है। किसी देश को आर्थिक तौर पर अस्थिर करना भी आतंक की मुहिम का अहम मकसद बन रहा है। जिसमें प्रत्यक्ष हमलों से लेकर वित्तीय तंत्र को कमजोर करने तक की रणनीतियाँ शामिल है। भारत में तो पिछले दो दशक के दौरान आतंक की बाढ़ बार–बार बड़े भयानक ढ़ंग से यह संदेश देती रही है लेकिन

---

[411] दैनिक जागरण, 4 दिसम्बर 2008

सुरक्षा और सतर्कता हमारे चरित्र में नहीं है। मुंबई पर ताज आतंकी हमले ने आतंक के इस आयाम को और मुखर रूप से सामने ला दिया है।

पिछले करीब एक दशक में अंतर्राष्ट्रीय आतंक का डिजाइन काफी बड़ा और बहुआयामी हो गया है। यह बात अलग है कि भारत को राजनीति और सुरक्षा तंत्र अक्सर आतंक को सीमित दायरों में रखकर देखता रहा है। भारत में इस्लामी आतंक पारंपरिक तौर पर कश्मीर केंद्रित या प्रेरित रहा है, इसलिए नवें दशक से पहले तक आतंक का सबसे भयानक दौर घाटी और आस–पास के इलाकों ने ही देखा। यही वजह है कि कश्मीरी अलगाववाद को समर्थन या देश के सांप्रदायिक ताने–बाने को बिखेरना आतंक का मुख्य मकसद माना जाता रहा है। लेकिन नब्बे के दशक में स्थिति बदली है और हम यह अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि भारत की आर्थिक रीढ़ पर लगातार सुनियोजित हमला भी आतंक का बड़ा मकसद बन रहा है। यह महज संयोग नहीं है कि भारत में इस्लामिक आतंक ने कश्मीर की सीमा के बाहर अपनी प्रभावी और नियमित उपस्थिति ठीक उस समय से दर्ज करानी शुरू की है जब से देश में आर्थिक विकास ने रफ्तार पकड़ी। देश में आर्थिक प्रगति और घाटी से बाहर आतंकी घटनाओं की रफ्तार एक साथ बढ़ी है। अगर भारत में पिछले करीब डेढ़ दशक में भारत में अर्थव्यवस्था सात–आठ फीसदी की रफ्तार से दौड़ी है तो आतंक की घटनाओं की रफ्तार भी पूरी दुनिया से तेज रही है। भारत में आतंक के ताजे अतीत को जरा गहराई से देखने पर आर्थिक विकास के खिलाफ आतंकी मुहिम की यह डिजाइन स्पष्ट हो जाती है। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू होने के बाद से आतंकियों ने लगातार उन शहरों को निशाना बनाया है, जो आर्थिक प्रगति और विकास के केन्द्र बन कर उभर रहे है। नब्बे के दशक में कश्मीर के बाहर के आतंक की सबसे पहली और बड़ी उपस्थिति मार्च 1993 में मुंबई बम धमाकों के तौर पर दर्ज हुई। 257 लोगों की जान लेने वाला हमला भारत के आर्थिक तंत्र पर पहली चोट थी। पिछले डेढ़ दशक में आतंक के लगभग अधिकांश बड़े हमले व्यापक भारत में हुए है और इन हमलों की आवृत्ति लगाकर बढ़ी है। मुंबई ने अगर निवेशकों को आकर्षित किया तो आतंकियों ने वहाँ खून बहाना शुरू कर दिया। 1991 से अब तक मुंबई अकेले लगभग दस बड़े आतंकी कमोबेशी की है। जहाँ भारत में तेज आर्थिक विकास का दौर शुरू होने के बाद करीब आठ बड़े आतंकी हमले हुए हैं। दक्षिण की तरफ चले तो बेंगलौर अगर सूचना तकनीक का केन्द्र बना तो आतंकियों ने उसे भी अपना केन्द्र बना लिया बेंगलौर में पिछले कुछ वर्षों में कई बार आतंकी हमले हुए है, जो सूचना तकनीक उद्योग को कंपाने के लिए पर्याप्त हैं। 1998 में माइक्रोसॉफ्ट हैदारबाद पहुँची थी और तब ये पारंपरिक शहर दुनिया के सामने सूचना तकनीक के नक्शे पर उभर आया था लेकिन तब से लेकर अब तक आतंकी लगातार इस शहर को कंपाते रहे हैं। गुजरात अगर पश्चिम में समृद्धि का केन्द्र बन कर उभरा तो आतंकियों ने इसे रह–रह कर निशाना बनया। यहाँ तक कि आर्थिक विकास की जद्दोजहद में लगे जयफर पर भी आतंकी निगाह पड़ चुकी है। 2004 के बाद से अब तक भारत में आतंक ने जितनी जानें ली हैं वह उत्तर, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका, यूरोप व यूरेशिया

में आतंक से हुई मौतों से कही ज्यादा है। इस अवधि के दौरान इन इलाकों में हुई मौतों से कहीं ज्यादा है। इस अवधि के दौरान इन इलाकों में आतंकवाद से अभी तक 3280 जानें गई है जबकि इसी भारत में आतंकियों ने 4000 से अधिक जीवन छीन हैं। चार साल में चार हजार मौतें किसी युद्ध से कम नहीं है और मौतों की यह संख्या सिर्फ इराक से कम है।

अचरज इस बात पर नहीं होता कि आतंक इतनी बुरी तरह हमें मार रहा है बल्कि इस बात पर होता है कि दुनिया में सर्वाधिक आतंक प्रभावित देश होने के बाद भी हम पर विदेशी निवेश और निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। शायद यही वजह है कि आर्थिक प्रगति में अग्रणी देश के सभी शहरों में बेहद लचर सुरक्षा माहौल होने के बाद भी निवेशक आए हैं और देश के भीतर व बाहर से भरपूर निवेश हुआ है। लेकिन यह भरोसा अनंतकाल के लिए नहीं है। आतंकी गतिविधियाँ अब जिस स्तर पर जा पहुँची हैं, वहाँ इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि आतंकी मौत बाँटते रहेंगे और फिर देशी और विदेशी निवेशक अर्थव्यवस्था को निवेश से नवाजते रहेंगे। सुरक्षा आर्थिक विकास की पहली शर्त है, किस्मत वाले हैं कि शर्त पूरी किये बिना हम यहाँ तक सफर कर आए हैं लेकिन अब शायद अति हो गई है। अब भी अगर सुरक्षा का माहौल नहीं सुधरा फिर मंदी नहीं बल्कि आतंक अर्थव्यवस्था की गाड़ी की हवा निकाल देगा।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को अस्थिर करने के लिए एक गहरी साजिश रच डाली है और इस कार्य में उसे भारत के पड़ोसी देशों विशेष रूप से चीन, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार का सहयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रहा है। नेपाल की खुली सीमा और बांग्लादेश की असुरक्षित सीमा तस्करों और आतंकवादियों के लिए काफी मुफीद बन चुकी है, जिसका व्यय आई.एस.आई. उठा रहा है। जाली नोट के कारोबारियों के हाथों नोट छापने में प्रयुक्त होने वाला कागज हाथ लग जाना भी किसी साजिश की ओर इशारा करता है। इस दिशा में सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकती है, बल्कि देश की भावी पीढ़ी इसके गिरफ्रत में आकर अकर्मण्य और लाचार हो सकती है और यह एक बड़ी राष्ट्रीय क्षति होगी।

आतंकवाद का 'नशीला त्रिकोण'

''पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो अकसर कबूल करती थी कि तीन 'ए' यानि – अल्लाह, आर्मी और अमरीका ही पाकिस्तान पर हुकूमत करते हैं। यह एक कड़वी सच्चाई भी है। लेकिन बेनजीर तीन 'अ' को भूलती रही है, जो पाकिस्तान की सियासत, अर्थव्यवस्था और मनसूबों की बुनियाद हैं। ये तीन 'अ' है – आतंकवाद, ओसामा बिन लादेन और अफीम। अफीम और दूसरे नशीले पदार्थों की तस्करी आतंकवाद की रीढ़ है और ओसामा 'आतंक' का आका। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान इस नशीले आतंकवाद के तीन कोण है, जिन्हें दुनिया 'सुनहरी त्रिकोण' (Golden Triangle) के विशेषण से जानती है।

इसी त्रिकोण के जरिए दुनिया भर में नशीले पदार्थों की तस्करी जारी है और तस्करी की इस अर्थव्यवस्था के जरिए आतंकवाद दिनोदिन फल–फूल रहा है।''[412]

अफगानिस्तान पर हमलों के दौरान अमरीका ने इस त्रिकोण के आधारों पर भी चोट की है। अमरीका का मानना है कि अफीम की तस्करी और पैदावार तालिबानों के लिए आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत था। तालिबान हुकूमत नशीले पदार्थों के नेटवर्क के जरिए दुनिया भर के देशों में 70 फीसदी से ज्यादा अफीम की सप्लाई करती थी। इस मद में हुकूमत को करों के तौर पर 3 सौ लाख डॉलर सालाना मिलते थे। हालाँकि तालिबान ने बीते साल ऐलान किया था कि वह अफीम की खेती और उसे पैदा करने वाले किसानों पर पाबंदी चस्पा करेंगे, क्योंकि वे इसे इस्लाम विरोधी मानते थे। यह ऐलान तालिबान हुकूमत का सामाजिक और मजहबी चेहरा हो सकता था। कारण, न तो अफीम की पैदावार पर पाबंदी लगी और न ही 'नशीले त्रिकोण' के माफिया ने तालिबान को ऐसा करने दिया। ''अफगानिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था अफीम पर ही टिकी है। युद्ध और गरीबी से लुटे–पिटे इस देश के 30 प्रदेशों में से 22 ऐसे है, जहाँ अफीम की फसलें उगाई जाती है।''[413]

प्रतिबन्धित संगठनों के वित्तीय लेन–देन रोक मे बैंकों की भूमिका (Role of Banks in Prevention of Financial Transaction of Prohibited Organisations)

आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001 जो कि मुख्य रूप से आतंकवाद में शामिल वित्तीय लेन–देन को रोकने से सम्बन्धित है, को भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह देश भर में फैले राष्ट्रीयकृत, सार्वजनिक, सहकारी व प्राईवेट बैंकों तथा वित्तीय लेन–देन करने वाली कम्पनियों को यथा शीघ्र सूचित कर उक्त अध्यादेश का कड़ाई से पालन करायें।

बैंकों को यह भी निर्देश दिये गये कि वह खाता खोलने से पहले अपने ग्राहकों की भली–भाँति जाँच पड़ताल (KYC) कर ले तथा संदिग्ध खातों की जाँच प्राथमिकता के आधार पर हो। जिन बैंकों की शाखायें देश के बाहर अन्य राष्ट्रों में भी है उन्हें विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकवादी संगठन ऐसे बैंकों को ज्यादा पसन्द करते हैं। ''बैंक खातों की जाँच में आवश्यक गोपनीयता रखनी चाहिए। ताकि ग्राहक और बैंक दोनों की साख बनी रहे यदि प्रथम दृष्टया खाता और खाताधारक संदिग्ध पाया जाता है तो तत्काल स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को जाँच एवं अग्रिम कार्यवाही के लिए

[412] विवेक सक्सेना, सुशील राजेश, ''जेहाद का जुनून'', 2011, सत्साहित्य प्रकाशन, 205–बी, चावड़ी बाजार, दिल्ली – 110006, पृष्ठ संख्या –165

[413] वही, पृ.सं. – 165

बुला लेना चाहिए।"[414] जाँच के दौरान इस बात पर भी ध्यान केन्द्रित करना चाहिए कि कहीं इस काम में बैंक का कोई अधिकारी या कर्मचारी तो नहीं मिला हुआ है।

कम्पनियों एवं गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका (Role of Company & NGO)

जहाँ तक वित्तीय विनिवेश कम्पनियों (Financial Investment Companie) का सवाल है यह बैंकों को मुकाबले ज्यादा स्वछन्द और स्वतन्त्र है। इनमें कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी ज्यादातर संविदा पर होते हैं और एक–दूसरी कम्पनियों में आते–जाते रहते हैं इस कारण ये इतने जिम्मेदार नहीं होते। चूँकि विनिवेश पूँजी (Investment Capital) बढ़ाने के लिए कम्पनियों को ऊपर से दबाव रहता है अतः बिना पर्याप्त जाँच पड़ताल के धन जमा कर लिया जाता है। "जाँच रिपोर्टों से पता चला है कि आतंकवादियों को उनकी कुल आमदनी का लगभग 20 से 30 प्रतिशत धन एन.जी.ओ. के द्वारा प्राप्त होता है। प्रायोजित राज्यों द्वारा प्राप्त धन तथा दान एवं चन्दे के धन का प्रयोग ट्रस्ट व एन.जी.ओ. के माध्यम से करना सुरक्षित समझा जाता है।"[415]

आतंकवाद के वित्तीय स्रोत (Financial Resources of Terrorism)

आतंकवादी गुटों को निम्नलिखित प्रकार से धन प्राप्त होता है –

1. **प्रायोजित राज्यों द्वारा प्राप्त धन –** पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा पोषक राष्ट्र है। यहाँ विभिन्न आतंकवादी गुटों को प्रशिक्षण, हथियार, तकनीकी व धन आदि मुहैया कराया जाता है। पाकिस्तान को मिलने वाली विदेशी सहायता का एक बड़ा हिस्सा आतंकवादी मदद में जा रहा है। बुश प्रशासन 10 अरब डॉलर की सैन्य मदद दी थी पाकिस्तान ने इस धन का उपयोग भारत विरूद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने तथा आतंकवादियों की मदद में खर्च की।
2. **अवैध व्यापार से प्राप्त धन –** भारत ड्रग्स निर्यातक देशों के बीच स्थित है। थाईलैंड, लाओस और म्यांमार से हेरोइन, अफीम, गाट्टजा तथा नशीली दवाओं का अवैध कारोबार भारत के रास्ते से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान आदि देशों में होता है। यह व्यवसाय अरबों डॉलर का है और कई प्रमुख आतंकवादी गिरोहों का इस पर कब्जा है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और समुद्री मार्गों का उपयोग कर दाऊद जैसे माफिया डॉन अरबों रूपये इकट्ठा करते हैं। 1991 तक ड्रग्स तस्करी का यह कारोबार लगभग 74 बिलियन डॉलर था। आई.एस.आई. जैसी संस्था भी इस काम में स्मगलरों की मदद करती है। भारत जैसे देशों में नकली नोटों का कारोबार काफी फल–फूल रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के रास्ते यहाँ नकली नोट लाया जाता है यह भारतीय अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने की एक गम्भीर साजिश है। इस क्षेत्र में एक और बड़ा अवैध करोबार होता है वह है हथियारों का। इस क्षेत्र में आतंकवादी गुटों और माफिया संगठनों की भरमार है इससे यहाँ छोटे से लेकर

---

[414] डॉ.आर.बी.सिंह, "भारत में आतंकवाद", 2010, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, फोन 23247003, पृष्ठ संख्या – 311

[415] वही, पृ.सं. – 311–312

मध्यम दर्जे तक के हथियारों की काफी खपत है। सबसे ज्यादा विदेशी हथियारों की माँग है बड़े गुटों जैसे तालिबान, अलकायदा, लिट्टे को उनके सरपरस्त देशों, उनकी सेनाओं और कम्पनियों से सीधा हथियार मिलता है, और युद्ध तथा संघर्ष के दौरान छीने और लूटे गये हथियार भी अवैध रूप से छोटे गुटों तथा माफियाओं तक पहुँचा रहे हैं। यह व्यापार भी अरबों डॉलर का है।

3. **सुरक्षा वसूली से प्राप्त धन –** माफिया और आतंकवादियों का यह फराना व्यवसाय है। उद्योगपतियों, ठेकेदारों, फिल्म निर्माताओं और व्यवसाइयों से यहाँ तक कि क्षेत्र की जनता से भी मोटी रकम वसूली जाती है, जो पैसा नही देते उन्हें मार दिया जाता है और जो निर्धारित समय पर रकम पहुँचाते रहते हैं, उनकी सुरक्षा अन्य गुटों से भी की जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1990–95 के दौरान 7.30 करोड़ डॉलर आतंकवादियों को वसूली से प्राप्त हुआ।
4. **ट्रस्ट एवं एन.जी.ओ. से प्राप्त धन –** विभिन्न कम्पनियों, सोसाइटियों और ट्रस्टों द्वारा आतंकवादियों को काफी धन प्राप्त होता है। ऐसी तमाम संस्थाओं और उनके खातों का पता चला है जिनके धन का लेन–देन आतंकवादी गतिविधियों में हुआ है। कश्मीर मेडिकल ट्रस्ट, झेलम वेली मेडिकल कॉलेज, इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी, इकबाल मेमोरियल ट्रस्ट आदि अनेक ऐसी संस्थायें चिन्हित की गयी जिनके द्वारा सीमा पार सरकार से भी धन का लेन–देन हुआ। आतंकवादी हाई टेक नेटवर्क और इन्टरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी दुनिया से पैसा वसूल रहे हैं। उनके संरक्षण में ही तमाम ट्रस्ट और एन.जी.ओ. काम कर रहे हैं जो आतंकवादी कार्यवाहियों में प्रयोग होने वाले धन का लेखा–जोखा रखते हैं।

आतंकवादी गुटों के वित्तीय स्रेतका अनुपात

क्रम सं.	स्रोत	धन प्रतिशत
1.	प्रायोजित देशों द्वारा	20 प्रतिशत
2.	नार्कोटिक्स/ड्रग्स	15 प्रतिशत
3.	चन्दे एवं अनुदान	10 प्रतिशत
4.	सुरक्षा वसूली	10 प्रतिशत
5.	नकली नोटों का कारोबार	10 प्रतिशत
6.	हथियारों का व्यापार	15 प्रतिशत
7.	हवाला व्यवसाय	10 प्रतिशत
8.	ट्रस्ट एवं एन.जी.ओ.	10 प्रतिशत

5. **दान एवं चन्दे –** आतंकवादी गुटों को अपने संरक्षकों और समान विचारधारा वाले संगठनों तथा लोगों से दान स्वरूप मोटी रकम प्राप्त होती है। 1980 के दशक में इसकी शुरूआत रूसी सेना से लड़ रहे मुजाहिदीन संगठनों को मुस्लिम देशों और उनके शुभ चिन्तकों द्वारा धन देने से हुई। अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन तालिबान, लश्करे– तैयबा सहित कई संगठनों को धन देता

है। इस्लामिक देशों और संस्थाओं से भी दान के रूप में करोड़ों रूपये मिलते हैं जिसका इस्तेमाल प्रशिक्षण, हथियार व आतंकी कार्यवाहियों के लिए किया जाता है।

6. **हवाला से प्राप्त धन** – यह एक पैरा बैंकिंग व्यवस्था है। दुनिया भर में फैले कालेधन को सुरक्षित रखने में सहायक हवाला व्यवसाय खरबों डॉलर का है। जम्मू–कश्मीर में ही सालाना लगभग 5 बिलियन डॉलर का यह कारोबार है तथा आतंकवादियों के धन का आवागमन भी ज्यादातर इसी माध्यम से होता है।

आतंकवादी वित्तीय स्रोतपर नियन्त्रण के उपाय (Solution of Control on Financial Resources of Terrorism)

1. आतंकवाद प्रायोजित देशों पद अन्तर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाये।
2. इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की निगरानी में एक दल का गठन हो जो संदिग्ध राष्ट्रों और उनके कृपापात्र संगठनों पर नजर रखे।
3. अवैध व्यापार के संभावित मार्गों पर कड़ी निगरानी हो और स्मगलरों की पहचान कर इनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
4. स्थानीय माफिया गुटों से आतंकवादी गुटों के सम्बन्ध विच्छेद किया जाये।
5. एन.जी.ओ. तथा ट्रस्टों पर भी कड़ी निगरानी हो तथा इनके वित्तीय लेन–देन का लेखा परीक्षण हो, खास तौर से आतंकग्रस्त क्षेत्रों में चल रहे ट्रस्टों व सोसाइटियों पर अधिकारिक निगरानी हो।
6. लोगों को उपयुक्त सुरक्षा मुहैया हो। आतंकवादी गुटों व माफियाओं से मिल रही धमकी की जाँच कर कानूनी कार्यवाही हो, पुलिस को और चुस्त दुरूस्त बनाया जाये।
7. आतंकवादियों और अपराधियों को दान, अनुदान देने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं पर भी कार्यवाही हो।
8. हवाला व्यवस्था का पर्दाफाश हो। इसमें राजनैतिक संरक्षण की भूमिका की भी जाँच हो।
9. सीमा पार से हो रहे अवैध व्यापार पर नियन्त्रण के लिए सघन और अनवरत तलाशी अभियान शुरू किया जाये।

उत्तर प्रदेश सरकार ने उग्रपंथी घटनाओं से निपटने के लिए ''एंटी टेररिस्ट स्कवाएड'' (एटीएस) का गठन किया है। इसमें एक आईजी, एक एसपी, 4 एएसपी, 12 इंस्पेक्टर, 36 उपनिरीक्षक, 15 मुख्य आरक्षी, 110 सिपाही, अभियोजन व रेडियो अधिकारी तथा कार्यालय के लिए मिनिस्टीरियल स्टाफ उपलब्ध कराने का आदेश किया है। इस संगठन में तैनात अफसरों और पुलिसकर्मियों को वाहन, हथियार, कम्प्यूटर और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं। इनका कार्य आतंकी हमलों को विफल करना, उग्रपंथी मुहिम फेल करना, नकली नोटों और नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के फैले जाल को ध्वस्त करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मकोका और पोटा जैसा सख्त यूपी कोका (उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियन्त्रण) कानून लागू करने जा रही है।

यूपी कोका, मकोका, पोटा एक नजर में

यूपी कोका	मकोका	पोटा
1. हत्या के मामले में मृत्युदंड या आजीवन कारावास, 1 लाख का न्यूनतम अर्थदण्ड	हत्या के मामले में मृत्युदंड या आजीवन कारावास, 1 लाख का न्यूनतम अर्थदण्ड	मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजायेपता अंतिम उचित अर्थदण्ड लगाया जाये
2. हत्या के इतर मामले में कम–से–कम 5 वर्ष का कारावास और 5 लाख का जुर्माना	हत्या के इतर मामले में कम–से–कम 5 वर्ष का कारावास और 5 लाख न्यूनतम जुर्माना	हत्या के इतर मामले में जिसमें न्यूनतम 5 वर्ष की सजा हो, उचित जुर्माना लिया जाए।
3. संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य को कम–से–कम 5 वर्ष आजीवन कारावास की सजा, 5 लाख का अर्थदण्ड	संगठित अपराध में लिप्त गिरोह के सदस्य को 5 वर्ष की सजा से लेकर आजीवन कारावास और 5 लाख का अर्थदण्ड	ऐसे अपराधी गिरोह के सदस्य को कम–से–कम 5 साल की सजा, आजीवन कारावास व उचित अर्थदण्ड
4. पुलिस के समक्ष अपराधी का दिया गया बयान मान्य नहीं, विशेष अदालतों का गठन	पुलिस के समक्ष अपराधी का दिया गया बयान मान्य, विशेष न्यायालय का गठन	पुलिस के समक्ष अपराधी का दिया गया बयान मान्य, विशेष न्यायालय का गठन
5. उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपीलीय प्राधिकरण का गठन	गठन नहीं	गठन नहीं
6. पूछताछ के दौरान वकील रखने की अनुमति	अनुमति नहीं	अनुमति नहीं

इन प्रयासों में उत्तर प्रदेश सरकार की चिन्तायें दिखायी देती हैं अन्य राज्यों में भी सुरक्षा और कानून में फनर्गठन की आवश्यकता है ताकि लोकतन्त्रा के इस विपरीत बयार की दिशा मोड़ने के साथ–साथ उसे कमजोर बनाकर निष्क्रिय किया जा सके। नस्लवाद चाहे वैचारिक संघर्ष हो, या व्यावसायिक, इसके पीछे चाहे बुनियादी मुद्दे काम कर रहे हों या सुनियोजित रणनीति, बहरहाल इसने नेपाल को निगल लिया, भारत पर दावेदारी मजबूत कर रहा है। भारत के टूटते

ही दक्षिण एशिया का कोई भी राष्ट्र सुरक्षित नहीं बचेगा, यह आन्तरिक समस्या किसी भी बाह्य समस्या और युद्ध से भी अधिक खतरनाक है।

आतंकवादियों को आतंकी गतिविधियों के दौरान दिया जाने वाला भुगतान[416]

क्रम संख्या	भुगतान विवरण	विदेशी आतंकी
1.	भर्ती के समय	50,000
2.	मासिक भुगतान	10,000 – 12,000
3.	कार्यवाही अंजाम देने के बाद	2,00,000 – 2.50 लाख
4.	विशेष सराहनीय कार्य करने पर	1–2 लाख
5.	प्रमुख लीडर को भुगतान (प्रतिमाह)	50,000

उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि पाक प्रायोजित आतंकवाद भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है अभी तक आतंकवादी पारम्परिक हथियारों से आतंकवादी कार्यवाही को अन्जाम देते रहे हैं। अब यह एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है कि यदि आतंकवादियों के हाथ ए.बी.सी वेपन्स लग गया तो क्या होगा? आतंकवादी यदा–कदा बायोलॉजिकल एवं केमिकल शस्त्र का प्रयोग यदा–कदा कर रहे हैं, किन्तु यदि उन्होंने बड़े स्तर पर इसका प्रयोग किया तो भारी तबाही होगी। इसी प्रकार यदि आतंकवादियों के हाथ परमाणु शस्त्र लग गया तो एक बड़ी जनहानि से कोई नहीं बचा सकेगा। यह भारत सहित पूरे विश्व के लिए एक गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। पाकिस्तान का परमाणु शस्त्र सुरक्षित नहीं रहा गया है और इसे तालिबानों के हाथ लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ''पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान का चरित्र भी संदेहास्पद रहा है और ऐसी सम्भावना है कि यदि इस वैज्ञानिक ने आतंकवादियों को परमाणु बम उपलब्ध करा दिया तो क्या होगा?''[417]

''आज इस्लामी आतंकवाद अरब देशों से निकलकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और काकेशस तक फैल चुका है। आज पाकिस्तान की इस्लामी पार्टियों में करीब डेढ़ लाख आतंकवादी हैं, जिन्हें कश्मीर, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में युद्ध का पूरा अनुभव है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा दुनिया के और भी कई देशों के मदरसों में उन्मादी शिक्षा दी जा रही है और वहाँ आतंकवादी तैयार करने तथा उन्हें प्रशिक्षण देने वाले शिविर लगाए जा रहे हैं। आज लीबिया, सूडान, अलबानिया, यमन, सीरिया और लेबनान में भी आतंकवादियों को तैयार करने के उद्योग बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। वास्तव में आतंकवाद को किसी धर्म या नस्ल से नहीं जोड़ना चाहिए, परन्तु आतंकवादी इसे धर्म से इसलिए जोड़ते हैं कि

---

416 Indian Journal of Strategic Studies, 2007, Allahabad, p. 99-102

417 नर्वदेश्वर शुक्ल, डॉ. गुलाब चन्द्र ललित, ''भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में हिमालयी क्षेत्रा का स्त्राातेजिक महत्त्व'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, दूरभाष 011–23255141, पृष्ठ संख्या 216–217

इस्लामी जनता इस्लाम के नाम पर उन्हें अकूत पैसा देती है। फलतः वे पर्याप्त मात्रा में धन और धन जुटा लेते हैं।''[418] जाहिर सी बात है कि वित्तीय संसाधनों के अभाव में आतंकवादी संगठनों के मंसूबे पूरे हो ही नहीं सकते और अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए प्रायोजक देश और आतंकवादी संगठन एक–दूसरे की ओर ताक लगाए रहते हैं और यही परस्पर जीविता ही आज आतंकवाद को एक नीति के रूप में स्थापित करती चली जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया को हम निम्न चार्ट में देख सकते है –

[418] प्रो. लल्लन जी सिंह, ''राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा'', पृष्ठ संख्या – 66

आतंकवाद का प्रयोजन

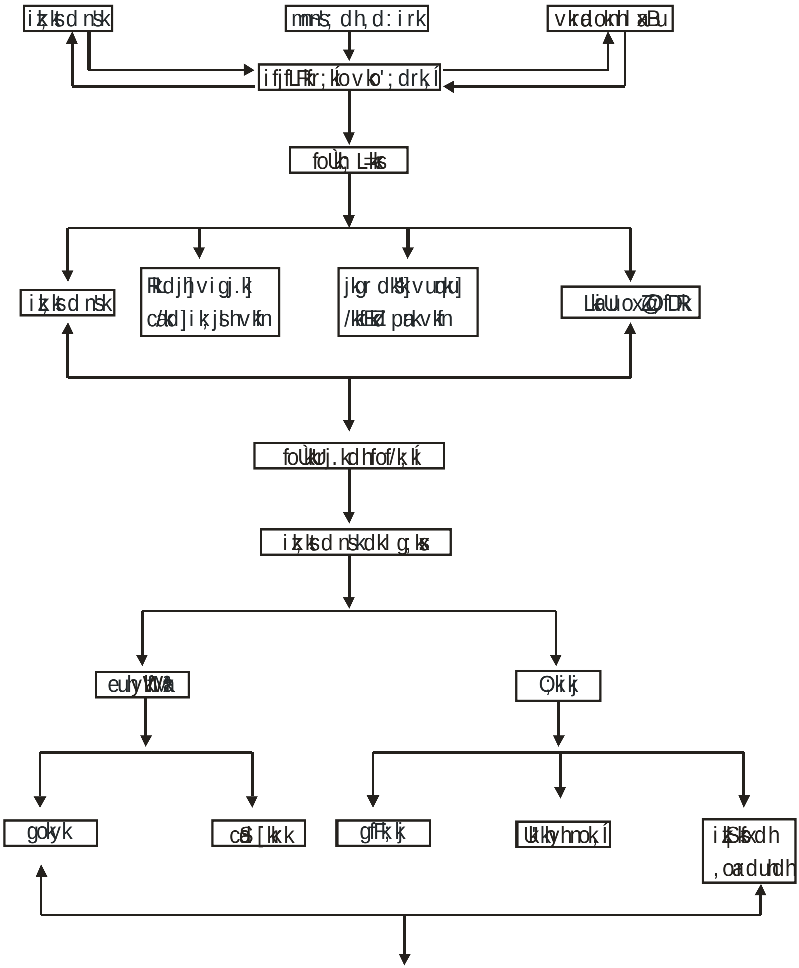

"11 सितम्बर 2001 को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पर आतंकवादी हमले के पश्चात् अमेरिकी सरकार द्वारा आयोग का गठन किया गया था। "इस आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना को अंजाम देने के लिए 'अलकायदा' को चार लाख से

पाँच लाख डॉलर तक व्यय करना पड़ा था। इन में से लगभग तीन लाख डॉलर विमान अपहरणकत्ताओं के अमेरिकी बैंक खातों में जमा कराए गये थे।''[419] अपहरणकर्त्ताओं ने 10 सितम्बर को लगभग 26 हजार डॉलर रकम संयुक्त अरब अमीरात में किसी मध्यवर्ती को वापिस कर दिए थे। अपहरणकर्त्ताओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न बैंकों में गलत पहचान, गलत सामाजिक सुरक्षा संख्या एवं गलत कागजों की सहायता से 24 खाते खोल रखे थे। अमेरिका में यह धन विदेशों से वायर ट्रांसफर, भौतिक अन्तरण के द्वारा नकद या ट्रेवलर चेक के माध्यम से तथा विदेशी वित्तीय संस्थाओं में जमा धन निकालने हेतु क्रेडिट का भी इस्तेमाल किया गया। विमान अपहरणकर्त्ताओं ने जर्मनी स्थित किसी मध्यवर्ती तथा संयुक्त अरब अमीरात या सीधे खालिद शेख महमूद से धन लिया। ''रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि आम धारणाओं के विपरीत ओसामा बिन लादेन ने अपनी ओर से अपहरणकर्त्ताओं को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी, क्योंकि उसके सूडान से अफगानिस्तान चले जाने के बाद किसी सम्पत्ति पर उसका अधिकार नहीं था। व्यक्तिगत सम्पत्ति या व्यवसाय उसकी पहुँच से दूर हो गया। वस्तुतः आतंकवादियों के पास धन विभिन्न इस्लामिक चैरिटी या मध्यवर्ती लोगों द्वारा तीन करोड़ डॉलर प्रतिवर्ष पहुँचता रहा। ग्लोबल रिलीफ फाउण्डेशन, बेनीवोलैंस इण्टरनेशनल फाउण्डेशन, अल हरमियन जैसे चैरिटेज का नाम 9/11 आयोग ने लिया है।''[420]

हाल ही में वाशिंगटन पोस्ट में खुफिया स्रोतों से यह खबर छपी थी कि मध्य अगस्त 2006 में कतिपय ब्रिटिश वायुयानों को हवा में ही उड़ा डालने का जो षड़यंत्र रचा गया था, उसके लिए धन पाकिस्तान द्वार मुहैया कराया गया था और यह धन अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान एवं कश्मीर में आए भूकम्प के राहत कोष से दिया गया था। इसके लिए एक पाकिस्तानी चैरिटी 'जमायत–उद्–दवा', जो कि 'लश्कर–ए–तैयबा' से सम्बद्ध हैं, पर अंगुलियाँ उठाई जा रही हैं। वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी (UNRWA) द्वारा फिलीस्तानी अधिकारियों के शरणार्थियों के लिए 521.7 मिलियन डॉलर में धन दिया गया था, किन्तु इन में से अधिकांश धन 'हमास' जैसे कुख्यात आतंकवादी संगठनों की जेब में चला गया। प्रतिबंधित सामग्रियों एवं नशीली दवाओं का अवैध कारोबार लेबनानी 'हिजबुल्लाह' की आमदनी का एक बड़ा जरिया बन चुका हैं एक आट्टकड़े के अनुसार जम्मू–कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को पहुँचने वाले धन का पन्द्रह प्रतिशत भाग सीधे पाकिस्तान सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। हाल के कुछ वर्षों में पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भण्डार में खासी बढ़ोतरी आँकी गई है, जो उसके निर्यात व्यापार अथवा वहाँ की कम्पनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण नहीं हुआ है, अपितु 9/11 की घटना के पश्चात् पाश्चात्य देशों में प्रवासी पाकिस्तानियों द्वारा स्वदेश धन

---

[419] कृष्णानन्द शुक्ल, ''शांति, सुरक्षा और विकास की समस्यायें'', 2009, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, पृष्ठ संख्या – 238–239

[420] सिविल सर्विसेज, क्रानिकल, अक्टूबर 2006, पृष्ठ संख्या – 10

प्रेषण के कारण है। ऐसा बताया जा रहा है कि यह स्वदेश धन–प्रेषण धन जब्ती की आशंका के कारण किया गया है, जिसका अन्तर्प्रवाह आतंकी संगठनों की ओर पाकिस्तान सरकार द्वारा मोड़ दिया गया है। यानि जो धन पहले पश्चिमी देशों की विभिन्न संस्थाओं, संगठनों व्यक्तियों आदि द्वारा आतंकवादियों को मिला करता था, वह अब सीधे पाकिस्तान से उन्हें मिलने लगा है। इसमें पाकिस्तान को भी अपना आर्थिक फायदा साफ नजर आ रहा हैं दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो 'आतंक की नीति' का अनुगमन पाकिस्तान के लिए अपनी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति का एक माध्यम बनता जा रहा है। साथ ही साथ में आतंकवादी बलूचिस्तान जैसी इनकी घरेलू समस्या और कश्मीर जैसी समस्या में सहयोगी भी सिद्ध हो रहे हैं।

आतंकवादी संगठनों को धन–प्रवाह (flow of money) रोकने के लिए सभी स्तरों पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी जिससे इच्छित परिणामों को सुनिश्चित किया जा सके।

'धन वह इंजिन है जो आतंकी–कार्यों को चलाता है' और यह कहना आश्चर्यजनक नहीं होगा कि जो लोग (संगठन) आतंकवादी कार्यों को रोकना, उनमें अवरोध डालना और उनका पता लगाना चाहते हैं, उनके लिए यह अति आवश्यक हो जाता है कि आतंकवाद के लिए धन जुटाने की क्रियाओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाये।

अमेरिका पर 11 सितम्बर 2001 के आत्मघाती हमलों ने तो इस आवश्यकता को और भी अधिक महत्त्वपूर्ण बना दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन (Interpol) के अनुसार ''अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी कार्यों की आवृत्ति और गम्भीरता का, आतंकी–समूहों को प्राप्त होने वाले धन से, अक्सर सीधा सम्बन्ध होता है।''

11 सितम्बर 2001 का आतंकी हमला, जो इतना जटिल, योजनापूर्ण, तैयारी के साथ क्रियान्वयन किया गया, वह बिना पर्याप्त स्त्रोतों के सम्भव ही नहीं हो सकता था। इसके विपरीत धन की उपलब्धता में कमी इस प्रकार के आक्रमणों को अक्सर सीमित कर देती है। **इस बात के पक्ष में एक उदाहरण** पाकिस्तान में इस्लामाबाद स्थित मिस्र दूतावास पर बम्बबारी का दिया जा सकता है –

ओसामा बिन लादेन का विश्वसनीय और निकटतम माने जाने वाले **आयमन अल–जवाहिरी (**Ayman al-Zawahiri**) के अनुसार,** ''उसका समूह अमेरिका और मिस्र के मध्य हुई कुमैत्राी (बुरी–मैत्री) का बदला लेना चाहता था। उनकी पहली इच्छा (लक्ष्य) इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास को बम से उड़ाना था, अगर यह संभव न हो सके तो दूसरा विकल्प (Second choice) मुसलमानों के लिए ऐतिहासिक घृणा हेतु प्रसिद्ध एक पश्चिमी राष्ट्र का दूतावास था और उनका तीसरा विकल्प मिस्र–दूतावास था।'' अन्त में धन ही निर्णायक तत्त्व बना। **अल–जवाहिरी के शब्दों में**, ''(इस्लामाबाद स्थित) मिस्र के दूतावास में बम्ब विस्फोट के कुछ ही समय पूर्व, बम्बबारी करने वाले समूह ने हमसे कहा कि यदि आपने हमको पर्याप्त धन दिया होता तो हम मिस्र और अमेरिका दोनों के

दूतावासों को अपने आक्रमण का निशाना बनाते। हमारे पास जितना धन था वह हमने उनको दे दिया और इससे और अधिक धन हम एकत्र नहीं कर सकते थे। इसीलिए आतंकी समूह ने केवल मिस्र के दूतावास पर ही बम्बारी करने का लक्ष्य बनाया।''

एक अन्य उदाहरण

''1993 में 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर (WTC) पर बम्बबारी का मूलभूत योजनाकार रैमजी यूसफ (Ramzi Yusef) जिसने अपना अपराध कबूल करते हुए कहा कि धन की कमी के कारण, आतंकवादी उतना बड़ा बम्ब नहीं बना पाए जितना कि उन्होंने सोचा था।''

इन उपर्युक्त दोनों उदाहरणों से यह तो स्पष्ट होता ही है कि आतंकवादी कार्यों के लिए धन का प्रबन्धन (उपलब्धता) कितनी अनिवार्य है।

आतंकवाद के लिए धन की परिभाषा

आतंकवाद के लिए धन जुटाने को समाप्त करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'आतंकवाद के लिए धन' को निम्न शब्दों द्वारा परिभाषित किया गया – ''हर प्रकार की मूल्यवान वस्तु या सम्पत्ति, चाहे वह मूर्त (स्पर्शनीय) हो अथवा अमूर्त (अस्पर्शनीय), चल हो या अचल, चाहे प्राप्त ही क्यों न की गई हो, और वैधानिक प्रमाण–पत्र अथवा किसी भी प्रकार (रूप) के साधन, इलैक्ट्रोनिक अथवा डिजिटल यंत्रों को सम्मिलित करते हुए, किसी संदर्भ का साक्ष्य / प्रमाण / सबूत, अथवा किसी वस्तु या प्राणी में रूचि, इस प्रकार की मूल्यवान वस्तु अथवा सम्पत्ति शामिल करना किन्तु सीमित नहीं, बैंक में जमा धन, यात्री चैक, मनी आर्डर, शेयर, सिक्योरिटीज, बॉण्ड्स (Bonds), ड्राफ्ट्स (Drafts), क्रेडिट प्रपत्र ये सभी आतंकवाद के लिए धन (निदके वित जमततवतपेउ) की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं।''

आज आतंकवाद वित्तीय साधनों और विभिन्न गतिविधियों के संदर्भ में विश्वस्तरीय (Global) पहुँच बना चुका है। अमेरिका द्वारा आतंकवादियों के वित्तीय संसाधनों को जब्त करने के उपायों के जवाब में अल–कायदा के नेता **ओसामा बिन लादेन** ने अमेरिका को खुले विरोधी तेवर दिखाते हुए अतिशयोक्ति पूर्ण लहजे में कहा कि, ''अल्लाह की कृपा से, (By the grace of Allah), अल–कायदा के पास तीन से अधिक विभिन्न वित्तीय नेटवर्कों के विकल्प मौजूद हैं।'' उसने आगे कहा कि ''अल–कायदा, सुशिक्षित नवयुवकों द्वारा सम्पूर्ण दुनियाँ में फैला हुआ है। हमारे पास सिर्फ कुछ सैंकड़ों या हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में उच्च शिक्षित नवयुवक हैं जो संगठन के वित्तीय साधनों से भली–भाँति परिचित और जागरूक हैं और विकल्पों को भली–भाँति जानते हैं।''

अमेरिका के अटोर्नी जनरल जोन एश्क्रोफ्ट (Attorney General John Ashcroft) ने कहा कि ''आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध, एकाण्टेण्ट्स और आडिटर्स के साथ–साथ हथियारों और वकीलों द्वारा लड़े जाने वाला युद्ध है।''

आतंकवाद के लिए वित्तीय साधनों को प्राप्त करने की विधियों में अक्सर वैधानिक और अवैधानिक दोनों संसाधनों का मिश्रण होता है। इस मिश्रण में व्यक्तिगत

प्रयासों की पहचान नहीं होती है और परस्पर दोनों भी एक–दूसरे से अनजान बने रहते हैं। एक तरफ तो धन वैधानिक धर्मार्थ संगठनों से आता है जबकि इसके विपरीत दूसरी तरफ धन क्रेडिट कार्ड प्रफोड, तस्करी (Smuggling), सुरक्षित घोटालों, डरा धमका कर धन वसूलना आदि गलत कार्यों से धन आता है। विभिन्न आतंकवादी संगठन अपनी गतिविधियों को सम्पन्न करने के लिये जिन **वित्तीय साधनों, स्त्राोतों, विधियों और विविध मार्गों का प्रयोग करते हैं वह निम्नलिखित हैं –**

1. आतंकवादियों को विभिन्न धर्मार्थ एवं धामिक संगठनों (चैरीटेबिल ट्रस्टों) से धन प्राप्त होता है।
2. आतंकवादियों को राजनीतिक नेता लोगों से आर्थिक मदद मिलती है।
3. आतंकवादियों को विश्व के कई देशों से आर्थिक मदद मिलती है।
4. किसी प्रतिष्ठित या ऊँचे पद पर विराजमान व्यक्ति को डरा धमकाकर धन वसूल किया जाता है।
5. धर्म के नाम पर कट्टरपंथी कठमुल्लों द्वारा आतंकवादियों को वित्तीय सहायता दी जाती है।
6. मादक पदार्थों की तस्करी (गाँजा, अफीम, हेरोईन, अमल, चरस, स्मैक आदि) द्वारा आतंकवादियों को धन प्राप्त होता है।
7. छोटे व बड़े हथियारों की तस्करी द्वारा आतंकवादियों को धन प्राप्त होता है।
8. किसी नेता या फिल्मी हस्ती को ब्लैकमेल करके उनसे धन प्राप्त किया जाता है।
9. इस्लामिक बैंक एवं मस्जिदों व चर्चों से आतंकवादियों को धन मिलता है।
10. सत्ताधारी सरकार के विरूद्ध आगजनी, लूटपाट, डकैती, विस्फोट, अपहरण आदि गलत कार्य करने पर आतंकवादियों को विभिन्न संगठनों द्वारा (विरोधी पार्टी) वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
11. विश्व के विभिन्न प्रकार के गैर कानूनी कार्यों द्वारा आतंकवादियों को आर्थिक सहायता मिलती है।
12. सोना–चाँदी, हीरे–जवाहरात आदि वस्तुओं की तस्करी से आतंकवादियों को धन प्राप्त होता है।
13. विश्व के विभिन्न पूँजीपति लोगों (बिजनेस मैन) से आतंकवादियों को धन प्राप्त होता है।
14. आतंकवादियों के लिये 'धन वह इंजिन है' जिसके माध्यम से विभिन्न आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। धन के अभाव में यह अपने लक्ष्य या उद्देश्य को मूर्त रूप नहीं दे सकते हैं।
15. आतंकवादियों को विश्व में विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार की सहायता दी जाती है जैसे वस्तुयें देकर या उपलब्ध कराकर, सोना–चाँदी, हीरे–जवाहरात देकर, नशीले पदार्थ देकर, हथियार देकर, नकद आर्थिक सहायता देकर, विस्फोटक पदार्थ देकर व मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराकर इनको सहायता दी जाती है।

16. जकत (गरीबों को रोटी, कपड़ा और धन इत्यादि का दान देना। यह इस्लाम धर्म का पाँचवा स्तम्भ है। गरीबों के नाम पर जो पैसा एकत्र होता है उसको आतंकवादियों तक पहुँचा दिया जाता है), हवाला और कोरियर (जब धन का लेन–देन अवैधानिक तरीकों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अथवा एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक पहुँचाया जाता है तो उसे हवाला (Hawal) कहते हैं जबकि वैधानिक तरीके से धन का लेन–देन बैंकों के द्वारा होता है। आतंकवादी संगठन हवाला के मार्गों से पैसा का लेन–देन करते हैं क्योंकि इसमें समय भी कम लगता है और इसमें विश्वसनीयता भी ज्यादा है क्योंकि यह गुप्त रहता है और किसी सरकार को इस लेन–देन का पता भी नहीं लगता है) व विभिन्न धर्मार्थ संगठनों के नाम पर आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं।
17. अवैध शस्त्र व्यापार से भी आतंकवादियों को वित्तीय सहायता मिलती है।
18. आज विश्व के विभिन्न संगठन आतंकवादियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहे हैं। जिस संगठन के पास नकद धन राशि है, वह नकद धन राशि दे देता है। और जिस संगठन के पास नकद धन राशि नहीं है वह आतंकवादियों को कोई वस्तु या धातु या पदार्थ या अन्य सामग्री किसी–न–किसी रूप में भेंट करके आतंकवादियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हैं।
19. अफीम जैसे मादक पदार्थों की कृषि उत्पादन से आतंकवादियों को वित्तीय सहायता मिलती है।
20. पाकिस्तान की I.S.I. (इन्टर सर्विस इन्टेलिजेन्स) खुफिया एजेन्सी से आतंकवादियों को वित्तीय सहायता, हथियार व प्रशिक्षण मिलता रहा है। भारत में मुम्बई हमला 1993 व मुम्बई हमला 26 नवम्बर 2008 आदि में पाकिस्तान का हाथ रहा है। पाकिस्तान हमेशा भारत के विरूद्ध आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देता आया है।

नोटः–उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि आतंकवादियों के वित्तीय स्रोतों, मार्गों, साधनों पर प्रतिबंध लगाकर आतंकवाद पर काबू पाया जा सकता है।

4.2 आतंकवाद–विरोधी संक्रियात्मक उपाय (Operational Measures to Counter Terrorism)

यह सही कहावत है कि “Prevention is better than Cure” **ईलाज से रोकथाम अच्छी होती है।** अर्थात् हम ऐसा प्रबन्ध करें कि बीमारी को फैलने से पहले ही रोक दिया जाये तो अधिक लाभकारी होता है। ताकि बीमारी अर्थात् हिंसा एवं आतंक के ईलाज की आवश्यकता न पड़े तो यह अच्छी नीति मानी जाती है। परन्तु यदि किसी कारण वंश हम आतंकवाद को रोकने में सफन न हो सके तो अन्त में हमें यौद्धिक – संक्रियात्मक उपायों द्वारा ही उसे कुचलना पड़ता है। **संक्रियात्मक उपायों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है –**

4.2.1 आधुनिकतम उपक्रम के साथ सुप्रशिक्षित एवं कुशल सुरक्षाबलों द्वारा (Well-Equipped and Trained Personnels with latest Infrastructure)

राज्यों की पुलिस बल और पैरामिलिट्री दलों को श्रेष्ठ और कठोर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण के लिए अच्छे प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाये जैसे I.M.A. (Indian Military Academy) देहरादून, प्रति–छापामार और जंगल युद्धकर्म के स्कूल जो मिजोरम के वैराग्टे नामक स्थान पर स्थित है आदि। अच्छे प्रशिक्षण के साथ हथियार भी उच्च कोटि एवं आधुनिकतम श्रेणी के होने चाहिये क्योंकि अच्छे हथियारों से सुरक्षाबलों का मनोबल ऊँचा होता है और वे खतरनाक–से–खतरनाक आतंकवादी संगठनों के आत्मघाती–दस्तों का मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं।

राज्यों की पुलिस बलों में सुधारों (Police Reforms) की अत्यन्त आवश्यकता है। जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी डी.जी.पी. प्रकाश सिंह की याचिकाओं के संदर्भ में पुलिस सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। जब पुलिस में सुधार आ जायेगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जायेगा तो स्वयं ही पुलिस एक मजबूत बल के रूप में संगठित हो जायेगी और प्रत्येक परिस्थिति में आत्मघाती–दस्तों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर पायेगी।

फलिस और उसके सहायक बलों का खुफिया और सूचना–तंत्र श्रेष्ठतम होना चाहिये जिससे कि आतंकवादियों की प्रत्येक गतिविधि के बारे में सटीक एवं सही सूचना घटनाक्रम से पहले ही मिल जाये और इस प्रकार आतंकवादियों को उनकी गतिविधि को क्रियान्वित करने से पहले ही सुरक्षाबलों द्वारा रंगेहाथों पकड़ लिया जा सके।

सभी देशों को आज दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है जो वोट बैंक की राजनीति से प्रभावित न हो और सब राजनीतिक पार्टियों के लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए तभी आतंकवाद पर काबू पाया जा सकता है अन्यथा नहीं।

1. हमारे पुलिस बल व अन्य सुरक्षा बलों के पास आतंकवादियों से निपटने के लिये अच्छा प्रशिक्षण व अच्छे हथियार और अच्छे दर्जे का आधुनिकतम साजो–सामान होना चाहिए। पुलिस तंत्र में सुधार करना चाहिये। छापामारों को छापामार बनके मारो और जंगल में छिपे विद्रोहियों को नष्ट करने के लिये जंगल युद्ध कर्म का पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।
2. सैनिकों को अच्छे किस्म के बुलेट प्रुफ जैकेट, आधुनिकतम रायफल प्रदान की जानी चाहिये। कमाण्डोज को शारीरिक रूप से सक्षम व फूर्तिला बनाने के लिए प्रतिदिन कठिन से कठिन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। ताकि वो हर संकट का मुकाबला करने के लिये हर समय तैयार रहे। उनको धन की कमी नहीं होने देनी चाहिए।
3. सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिये उनको अच्छी ट्रैनिंग, अच्छे हथियार और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखा जाना चाहिये जिससे उनको किसी भी प्रकार की

मानसिक चिन्ता या घरेलू परेशानी से मुक्त होना चाहिये। जिससे वे अपनी पूरी शक्ति के साथ दुश्मन से लड़ सके। ये काम उनके उच्च्य अधिकारियों को करने चाहिये। सैनिकों को सभी आवश्यक सामग्री उचित समय पर मिल जानी चाहिये। इन सभी बातों से सैनिकों का मनोबल ऊट्टचा बना रहेगा और वे आतंकवादियों व विद्रोहियों को समाप्त करने या नष्ट करने में सफल हो सकेंगे।

4. भूमिगत बारूदी सुरंगों से बचने के उपाय (मशीनों), दुश्मन के घात और बूबी ट्रेप (Booby Trap) से बचना चाहिए। अपनी योजनाओं को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाये और इसके विपरीत शत्रु की योजनाओं का सही–सही पता लगवाना चाहिए।
5. अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको सभी सुविधायें, अच्छे आधुनिकतम हथियार, उपकरण, अच्छा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। जवानों के शहीद होने के बाद पूरा राष्ट्रीय सम्मान और परिवार के कल्याण की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए।
6. बहुराष्ट्रीय फौजों द्वारा संयुक्त मोर्चा बनाकर अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोका जाये।
7. ''पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जाये, सी.आई.डी. शाखा को चुस्त दुरूस्त व क्रियाशील बनायी जाये तथा सम्बन्धित क्षेत्र के अधिकारियों को उनके गैर जिम्मेदार कार्य के लिए किसी दूसरे विभाग द्वारा जाँच करायी जाये और दोषी पाये जाने पर दण्डित किया जाये। पुलिस की निष्क्रियता व लापरवाही से ही अपराध व अव्यवस्था फैलती है, अतः इस इकाई के कार्यकलाप अत्यन्त सोचनीय है, इनमें पर्याप्त सुधार लाना आवश्यक है।''[421] साथ ही देश की गुप्तचर व्यवस्थाओं जैसे आई.बी., सी.बी.आई. व रॉ आदि को देश की आन्तरिक व बाह्य गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी होगी तथा हर समय, हर क्षण देश हित में तत्पर रहना होगा।
8. आतंकवाद से पीड़ित देशों की सेनायें परस्पर सहयोग से मिल–जुलकर आतंकवादियों का सामना करके उनको नष्ट करने का अभियान (Operation/Campaign) चलायें जैसा कि अमेरिका एवं पश्चिमी देशों की मिली–जुली सेनाओं एवं NATO सैन्य बलों ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं इराक में सैन्य अभियान चलायें है।

4.2.2 छापामार विरोधी युद्धकर्म की उपयुक्त स्त्रातेजी एवं सामरिकी के प्रयोग द्वारा (Application of Appropriate Strategy and Tactics of Counter-Guerrilla Warfare)

आतंकवादी कमजोर होने के कारण छापामारों की स्त्रातेजी एवं सामरिकी को अपनाते हैं अतः सुरक्षाबलों को भी स्वयं छापामार बनकर उनके आतंकवादियों के दस्तों को नष्ट कर देना चाहिये। प्रति–छापामार युद्धकर्म के प्रशिक्षण के दौरान

---

[421] डॉ. आर.बी.सिंह, ''भारत में आतंकवाद'', 2010, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, फोन 23247003, पृष्ठ संख्या – 333

ही सुरक्षाबलों द्वारा अपनायी जाने वाली उपयुक्त स्त्रातेजी एवं सामरिकी का अध्ययन करवाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि स्थानीय जनता का सहयोग बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। जब छापामार आतंकी दल भ्पज ंदक त्नद की सामरिकी अपनाकर भागता है तो वह कई बार स्थानीय जनता में छिपने और शरण लेने का प्रयास करता है तो स्थानीय जनता को चाहिये कि वे आतंकवादियों को कोई शरण या सहयोग प्रदान न करें और न उनको आर्थिक सहायता दें।

1. जासूसी–तंत्र (Spying and Intelligence System) और आधुनिकतम संवादवाहन के साधनों (Satellite System, GPS – Global Position System, E-governance) का प्रयोग करके विद्रोहियों का सफाया किया जाये।
2. आतंकवादियों (विद्रोहियों) के खिलाफ विरोधी कार्यवाही करने से पूर्व उनके बारे में सही–सही जानकारी अपने जासूसी तंत्र द्वारा प्राप्त कर लेनी चाहिए और अपनी योजनाओं के बारे में कोई भी जानकारी आतंकवादियों तक नहीं पहुँचनी चाहिये।
3. आतंकवादियों को संग्राम में हराने के लिए छापामार युद्ध कर्म की स्त्रातेजी व सामरिकी (समरतंत्र) अपनाई जानी चाहिए। दुश्मन को घात लगाकर, बूबी ट्रेप (Booby Trap) में फंसाकर, जमीन में बारूदी सुरंगे बिछाकर मार देना चाहिये। और दुश्मन द्वारा किये गये इन कामों से अपने आपको बचाना चाहिये।
4. आतंकवादियों को मिलने वाली किसी भी प्रकार की आन्तरिक व बाहरी दोनों प्रकार की सहायता को काट देना चाहिये।
5. विद्रोहियों से वार्तालाप एवं संधियाँ करके उनकी समस्याओं का गहन अध्ययन किया जाये तथा उनकी उचित माँगो को सरकार को तुरन्त मान लेना चाहिए।
6. जनजातियों एवं विद्रोहियों का सर्वागींण विकास करके उनको राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए।
7. ड्रोन बम्ब वर्षक (पायलेट रहित) विमानों से आतंकियों के गुप्त अड्ड़ों, आधार क्षेत्रों एवं भूमिगत अड्ड़ों पर भारी बम वर्षा करके आतंकियों का विनाश किया जा सकता है, जैसा कि अमेरिका, अफगानिस्तान में कर रहा है।
8. आतंकवादियों को शरण, आर्थिक सहायता प्रदान करने वालों और उनके प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट किया जाये।

5

सारांशः शोध–परिणाम एवं समस्या–समाधान हेतु सुझाव
(Conclusion : Findings, Recommendations and Suggestions to Solve the Problem)

प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध को पाँच अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्राक्कथन के अन्तर्गत शोध का प्रयोजन एवं शोध विधि का उल्लेख किया गया है। शोध का विषय सम्पूर्ण मानव जाति के कल्याण एवं उसकी वर्तमान समस्या के समाधान से जुड़ा होना चाहिए। शोधार्थी ने अपने शोध का विषय 'अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद में आत्मघाती–हमलों की भूमिका' को चुना है क्योंकि आज अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद विश्व की सबसे ज्वलंत समस्या है जिसमें न सिर्फ निर्दोष नागरिक ही मारे जाते हैं बल्कि विश्व के अनेकों प्रमुख व्यक्ति, देशों के शासनाध्यक्ष, प्रसिद्ध व्यक्ति एवं व्यक्तित्व के धनी, महापुरूष भी इसका शिकार हो रहे हैं। इससे सम्पूर्ण मानव जाति की प्रगति को गहरी चोट पहुँची है इसीलिये इस समस्या के समाधान के लिए प्रस्तुत शोध–प्रबंध में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मूल कारणों का पता लगाकर उसके समाधान हेतु कारगर उपायों को खोजने का एक प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत शोधकार्य में Secondary Data का प्रयोग किया गया है और यह शोध विधि वर्णात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध के अन्तर्गत आती है।

प्रथम अध्याय में विषय की प्रस्तावना की प्रस्तुती के साथ–साथ आत्मघाती–हमलों एवं आतंकवाद की अवधारणा, परिभाषा, प्रकार और आतंकवाद के मूल, प्रमुख, तत्कालीन एवं गौण कारणों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। आतंकवाद की सबसे सरल, सुबोध, पर्याप्त, पूर्ण, व्यावहारिक एवं सर्वमान्य परिभाषा निम्न शब्दों में देने का प्रयास किया गया है – **"निश्चित राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, निर्दोष एवं निरपराध नागरिकों की हत्या का दुष्कार्य ही आतंकवाद कहलाता है। "**

उपर्युक्त परिभाषा का प्रयोग करते हुए आतंकवादियों की पहचान होती है कि कौन आतंकवादी है? और कौन नहीं? इसके बाद ही कठोरतम कानून बनाया जा सकता है। आतंकवाद सात प्रकारों में बाँटा गया है। 1. क्रांतिकारी आतंकवाद 2. क्षेत्रीय आतंकवाद 3. राज्य/राष्ट्रीय आतंकवाद 4. अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद 5.राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद 6.मादक पदार्थों एवं आर्थिक अपराध से संबंधित आतंकवाद 7.साइबर आतंकवाद।

इसके पश्चात् मूल कारणों का विस्तृत अध्ययन किया गया है जो इस प्रकार है – अशिक्षा, घोर गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि हैं इसके अतिरिक्त द्वितीय (गौण) कारण अनेक हैं जिनका विस्तार से वर्णन उप–अध्याय 1.4 में किया जा चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद एवं आत्मघाती–हमलों के कारणों का पता लगाकर

समस्या के निवारण एवं अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की सम्पूर्ण समाप्ति के लिए कारगर उपायों की दिशा में शोध–प्रयास किया गया है।

शोध–प्रबंध के द्वितीय अध्याय में प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। इस अध्याय में मुख्य रूप से 'अल–कायदा' एवं इसके सहयोगी संगठनों के अतिरिक्त 'हमास' एवं 'लिट्टे' नामक आतंकी संगठनों पर विशेष प्रकाश डाला गया है क्योंकि ये तीनों संगठन ऐसे हैं जिन्होंने आत्मघाती–दस्तों का बड़ी मात्रा में खुलकर प्रयोग किया है और सम्पूर्ण विश्व की महाशक्तियों को हिलाकर रख दिया है। आज इनसे बचाव के लिए विश्व में त्राही–त्राही मची हुई है और विश्व जनसमुदाय इनसे मुक्ति पाने के लिए व्याकुल है।

अमेरिका के 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर (WTC) पर आत्मघाती हमला करने वाला विश्व का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन 'अल–कायदा' की स्थापना 1988 में अब्दल्ला अज्जाम ने की थी। इसके बाद 1990 के दशक में ओसामा बिन लादेन ने बागड़ोर सम्भाली जिसकी हत्या 2 मई 2011 को पाकिस्तान के ऐपटाबाद में अमेरिकी सील कमाण्ड़ो द्वारा की गई। 'अल–कायदा' की विश्व के अनेक देशों में इसकी शाखायें और नेटवर्क फैला हुआ है। जहाँ से यह संगठन और इसके सहयोगी संगठन अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की गतिविधियों को क्रियान्वियत करते हैं। 'अल–कायदा' का उद्‌देश्य विश्व में एक 'एकीकृत इस्लामिक राज्य' की स्थापना करना है। इस संगठन ने पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम देशों में शिविर स्थापित करके आत्मघाती–दस्ते तैयार किये हैं। जिनको आधुनिकतम हथियारों का कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार 'हमास' फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन (PLO) का ही एक आत्मघाती आतंकी संगठन हैं जो इजरायल से पृथक्क फिलीस्तीन राज्य की माँग के लिए संघर्षरत है। इसके विरोधी इजरायल को अमेरिका से सहायता मिलती रहती है। इस संगठन में भी आये दिन आत्मघाती–दस्ते विस्फोटक गतिविधियाँ करते रहते हैं।

'लिट्‌टे' की स्थापना वेलूपिल्लई प्रभाकरण ने 5 मई 1976 में की 'लिट्‌टे' को विश्व का सबसे खतरनाक, संगठित और आत्मघाती–दस्तों के लिए प्रसिद्ध संगठन माना जाता है। इसी संगठन के कुछ आत्मघाती–दस्तों के सदस्यों ने 21 मई 1991 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी की हत्या कर दी थी और विडम्बना है कि 24 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारतीय न्यायालयों की सुस्त प्रक्रिया ने अभी तक उनको फांसी की सजा नहीं सुनाई जिससे कि आतंकवादियों के हौंसले और बढ़ जाते हैं। इस प्रकार आतंकवाद पर काबू नहीं पाया जा सकता।

तृतीय अध्याय के अन्तर्गत शोधार्थी ने आत्मघाती–दस्तों की संरचना का एक मनौवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है जिसके अन्तर्गत आत्मघात को प्रेरित करने वाले तत्त्वों एवं कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन किया है। इस अध्याय के अन्तिम चरण में इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि आज विश्व के विभिन्न आतंकवादी संगठन जिहाद और धर्म के नाम पर किस प्रकार नवयुवकों को भ्रमित करते हैं और उनको तथाकथित 'जन्नत' के दिवास्वप्न के भंवर जाल में फंसा दिया जाता है और

इस प्रकार उनको आत्मघाती बनाकर आतंकवादी रूपी मौत के कुएँ में धकेल दिया जाता है।

इसी अध्याय में आत्मघात को प्रेरित करने वाले कुछ प्रमुख तत्त्वों एवं कारणों को खोजा गया है जो इस प्रकार है – घोर गरीबी, अशिक्षा, कच्ची उम्र के नवयुवकों का चयन, जन्नत का झूठा आश्वासन, जीवन के प्रति घोर निराशा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृ(ि शिक्षा के अभाव में देशभक्ति की गलत परिभाषा, भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षण और विकसित राष्ट्रों की गलत नीतियाँ आत्मघात को प्रेरित करने के लिए उत्तरदायी है अगर इन कारणों को दूर कर दिया जाये तो कोई भी नवयुवक आत्मघाती–दस्तों में शामिल नहीं होगा और इस प्रकार इस समस्या पर काबू पा लिया जायेगा।

इस शोध–प्रबंध का चतुर्थ अध्याय बड़ा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के समाधन हेतु विभिन्न उपायों की विस्तृत समीक्षा की गई है जिससे कि सम्पूर्ण विश्व को अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद एवं आत्मघाती–हमलों से मुक्ति दिलाई जा सके ताकि विश्व के सम्पूर्ण देशों के नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हुए विश्व में विकास, कल्याण, शांति एवं समृद्धि की चिरस्थायी स्थापना कर सके। इन उपायों को मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा गया है। पहले उपाय, रोकथाम के अन्तर्गत आते हैं और दूसरे प्रकार के उपायों को, संक्रियात्मक उपायों की श्रेणी में रखा गया है जैसा कि कहा गया है कि ईलाज के बजाय उसकी रोकथाम करना ज्यादा हितकारी होता है अगर हम पहले ही किसी बीमारी के शुरू होने से पहले उसकी रोकथाम कर लेंगे तो अधिक कारगर होगा परन्तु यदि सम्पूर्ण रोकथाम के बावजूद भी आतंकवादी रूपी बीमारी फैल जाती है तो उसको काबू करने के लिए अन्त में संक्रियात्मक उपायों का सहारा लिया जाता है इस अध्याय में धन एवं वित्त की भूमिका का भी विस्तृत अध्ययन किया गया है क्योंकि **'धन वह इंजिन है जो आतंकी कार्यों को चलाता है'** अतः अगर अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकना है तो आतंकवादियों को मिलने वाली सम्पूर्ण आर्थिक सहायता को जड़–मूल से समाप्त करना होगा क्योंकि धन की कमी से कोई भी आतंकी गतिविधि नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य संस्थाओं द्वारा आतंकवाद की रोकथाम के उपायों की भी खोज की गई है। संक्रियात्मक उपायों के अन्तर्गत पुलिस सुधार, पैरामिलिट्री फोर्स की भूमिका, आधुनिक हथियारों एवं जंगल युद्धकर्म (छापामार युद्धकर्म) के कठोर प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है अन्त में यह भी बताया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के लिए विभिन्न देशों में कठोर कानून और परस्पर सहयोग के बिना आतंकवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका सबसे अहम है क्योंकि यह शान्ति, सुरक्षा और विकास के लिए गम्भीरतम खतरा है। इसलिए दुनिया के सभी देशों को मिलकर आपसी सहयोग के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विधि, परम्पराओं एवं मानवाधिकारों के आदेशों के अन्तर्गत आतंकवाद को रोकने और उससे लड़ने के लिए आपसी सहयोग करना चाहिये अगर सम्पूर्ण रोकथाम के बावजूद भी

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति न हो सके, उस स्थिति में अन्तिम उपाय संक्रियात्मक ही रह जाते है। अन्त में उचित बल प्रयोग के द्वारा आतंकवादियों को कुचल देना चाहिए। आतंकवादी मूलतय नियमित सेना के सामने कमजोर होता है इसलिए वह LIC (न्यून तीव्रता संघर्ष) का सहारा लेकर आतंकवादी रूपी हथियार का प्रयोग करता है और यह गतिविधि छापामार युद्धकर्म का ही एक रूप है और छापामारों को समाप्त करने के लिये स्वयं को भी छापामार बनना पड़ता है। अतः राज्यों के पुलिस बलों, अर्द्धसैनिक बलों को प्रति–छापामार युद्धकर्म और जंगल युद्धकर्म का कठोरतम प्रशिक्षण देकर आतंकवादियों का समूल नाश किया जा सकता है। राज्यों के पुलिस बलों में आवश्यक सुधार करके उनको आधुनिकतम हथियारों का कठोरतम प्रशिक्षण दिया जाये ताकि उनका मनोबल ऊट्टचा रहे। इस शोध–प्रबंध के अन्तिम अध्याय में सारांश प्रस्तुत किया गया है जिसमें शोध–परिणाम एवं समस्या–समाधान हेतु समुचित सुझावों को प्रस्तुत किया गया है। आज सम्पूर्ण विश्व के लिये आतंकवाद व आत्मघाती हमले एक गम्भीर चुनौती है। आत्मघाती व आतंकवादी गतिविधियों के सन्दर्भ में सभी का कर्त्तव्य है कि **'विश्व–बन्धुत्व की भावना'** जाग्रित कर सभी आतंकवादी संगठनों को नष्ट करने का प्रयास करें। **आत्मघाती–हमलों व आतंकवाद को समाप्त करने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं –**

1. **राष्ट्रीय समस्याओं पर आम सहमति निर्मित करना –** आतंकवाद को जन्म देने वाले मूल कारणों को समझकर उन्हें दूर करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति निर्मित करने का प्रयास करना चाहिये। राष्ट्रीय समस्याओं को दलगत राजनीति और वोट बैंक की राजनीति से पृथक्क रखने की आवश्यकता है।
2. **शासन और जनता के बीच व्यापक सहयोग –** किसी भी सरकार के लिये जनसहयोग के अभाव में आतंकवाद व आत्मघाती–हमलों को समाप्त करना सरल नहीं है। अतः इस संबंध में सरकार और जनता के परस्पर सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है।
3. **कानून और न्याय व्यवस्था में सुधार –** वर्तमान न्याय व्यवस्था जटिल, व्यय साध्य और लम्बे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। परिणामस्वरूप साधन सम्पन्न अपराधी सरलता से दीर्घकाल तक दण्डनीय कार्यवाही से मुक्त रह सकता है। अतः वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन कर आतंकवाद व आत्मघाती–हमलों पर नियंत्रित करने हेतु अपराधी के लिये तत्काल दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिये। कानून और न्याय व्यवस्था के प्रति जनता में विश्वास उत्पन्न करना चाहिये। श्री राजीव गाँधी के हत्यारों को 24 वर्ष बीत जाने के बाद भी फांसी नहीं हुई है। इतना विलम्ब उचित नहीं है।
4. **आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा हो –** आतंकवाद की सर्वसम्मति एवं सर्वमान्य परिभाषा तैयार करके आतंकवादियों के विरूद्ध सख्त कानून बनाये जायें और विश्व के सभी देश अपने मतभेद भुलाकर आपसी सहयोग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का समूल विनाश कर सकते हैं।

5. **राजनीतिक स्तर पर बन्धुत्व / भाईचारा (Brotherhood) की भावना को प्रोत्साहन** – आत्मघाती–हमलें व आतंकवाद के मूल कारणों को समझकर उन्हें दूर करना चाहिये। जनता में आपसी बन्धुत्व की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया जाना चाहिये। केवल बल प्रयोग के आधार पर आत्मघाती–हमलों व आतंकवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

6. **सामाजिक–आर्थिक न्याय की स्थापना के प्रयास** – कानून निर्माण ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें कठोरता से लागू भी किया जाये। यदि ऐसे कानूनों में कोई कमियाँ हैं तो उन्हें दूर किया जाना चाहिये। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करायें जायें। नक्सलवादी आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिये भूमि सुधार कानून बनायें जायें। सुलभ और अविलम्ब न्याय सभी नागरिकों को मिलना चाहिए।

7. **नैतिकता का विकास** – सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा वैज्ञानिक प्रगति के साथ प्रत्येक राष्ट्र को नैतिक क्षेत्र में भी प्रगति करनी चाहिये। अनुशासनबद्ध रहते हुए उज्ज्वल चरित्र की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होना चाहिये। इसके अभाव में राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। समाज में व्याप्त धर्मान्धता, कट्टरवादिता, निरक्षरता, अन्धविश्वास, कुप्रथायें, सम्पूर्ण राष्ट्र को विघटन की ओर ले जाती हैं। अतः इनका उन्मूलन आवश्यक है।

8. **राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों में अच्छा समन्वय** – प्रायः राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था का दुरूपयोग किया जाता है। अतः आवश्यक है कि दलगत राजनीति से उफपर उठकर संवैधानिक प्रावधानों को लागू करना चाहिये। केन्द्र–राज्य संबंधों में संतुलन स्थापित करने के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिये। राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार में अच्छा सामंजस्य स्थापित करके ही राष्ट्रीय आतंकवाद–निरोधक केन्द्र (NCTC) स्थापित किये जा सकते हैं।

9. **सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण एवं सशक्तिकरण** – आतंकवादी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं और उनके पास आधुनिकतम हथियार उपलब्ध हैं। इनका सामना करने के लिए सुरक्षा बलों को भी आधुनिकतम हथियार, श्रेष्ठ प्रशिक्षण, बेहतर दर्जे के साजो–सामान एवं तकनीक उपलब्ध करायी जानी चाहिये। उनका मनोबल बढ़ाने के लिये सेवा–शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये। राज्यों के पुलिस बलों में सुधार करके उनका सशक्तिकरण किया जाये क्योंकि पुलिस बल राज्य सरकारों के अन्तर्गत कार्य करते हैं।

10. **राष्ट्र की सुरक्षा को प्राथमिकता** – राष्ट्र की सुरक्षा महत्त्वपूर्ण है। देश की एकता और अखण्डता को नष्ट करने वाले तत्त्वों से सतर्क रहना चाहिये।

11. **आतंकवादियों को मिलने वाली विदेशी सहायता पर प्रतिबंध** – विश्व में ऐसे अनेक देश हैं जो आज भी आतंकवादियों को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। वे दूसरे देशों को आतंकवाद रोकने में सहायता नहीं देते बल्कि दूसरे देशों में अस्थिरता उत्पन्न करने के लिये आतंकवादियों को

आर्थिक और राजनीतिक सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे देश जो आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। इन देशों द्वारा आतंकवादियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

12. **विभिन्न समस्याओं का समाधान –** आज युवा वर्ग की विभिन्न समस्याओं जैसे – बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, कुरीतियाँ, भाई–भतीजावाद, कालाबाजारी, नशाखोरी आदि समस्याओं का समाधान किया जाये ताकि युवा वर्ग को गलत व हिंसक कार्य करने से रोका जा सके और अच्छा नागरिक बनकर देश का अच्छे काम में सहयोग दे सके और देश को विकसित बनाया जा सके।

13. **अवैध शस्त्र व्यापार पर प्रतिबंध –** वर्तमान में छोटे अवैध शस्त्र (small arms) व्यापार इतना अधिक बढ़ गया है कि आधुनिकतम और भयानक शस्त्रों को अवैध रूप से प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं रह गया है। ऐसे अवैध छोटे शस्त्रों की सहज उपलब्धि के कारण आतंकवाद गंभीर रूप ले लेता है। इस प्रकार जब अवैध शस्त्र व्यापार पर प्रतिबंध लग जायेगा तो आतंकवाद पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है।

14. **स्वच्छ राजनीति –** स्वच्छ राजनीति या साफ–सुथरी राजनीति को अपनाकर आतंकवाद व आत्मघाती–हमलों को समाप्त किया जा सकता है। भ्रष्ट राजनीति के कारण भ्रष्ट राजनेता वोट बैंक के लिये युवकों को गलत मार्गदर्शन देते हैं। युवक भ्रष्ट राजनीतिक दलदल में फंस कर अपना जीवन व कैरियर समाप्त कर लेता है और वह घोर निराशा से पीड़ित होकर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जाता है इसलिये हमें हमारे देश में स्वच्छ राजनीति को अपनाना होगा। सफल लोकतंत्र के लिए अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव में खड़ा होने का मौका न दिया जाये।

15. **आर्थिक क्षेत्र में संतुलित विकास करना –** आर्थिक क्षेत्रों का संतुलित विकास करके आतंकवाद व आत्मघाती–हमलों को समाप्त किया जा सकता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक असन्तुलन की स्थिति है। महाराष्ट्र अन्य राज्यों की अपेक्षा सम्पन्न राज्य है लेकिन महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। असम में पैट्रोल जैसी प्राकृतिक सम्पदा है लेकिन इस प्राकृतिक सम्पदा का लाभ असम को कम मिलता है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों, उत्तर–पूर्वी भारत के सात राज्यों और आन्ध्रप्रदेश के तेलगांना क्षेत्र आदि के विकास की ओर सरकार का अपेक्षित ध्यान नहीं गया है। इसीलिए इन आठों राज्यों में नक्सलवाद (माओवाद) का विद्रोह फैल गया है। 6 अप्रैल 2010 को CRPF के 76 जवानों को नक्सलवादियों ने घात (mbush) लगाकर मौत के घाट उतार दिया। अतः सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का विकास करवाये ताकि देश को आतंकवादी गतिविधियों से बचाया जा सके।

16. **मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक –** मादक पदार्थों (हेरोईन, गाँजा, चरस, स्मैक, अफीम, अमल आदि) की तस्करी पर रोक लगाकर हम आतंकवादी व

आत्मघाती–हमलों को रोक सकते हैं। इन मादक पदार्थों की तस्करी से आतंकवादियों को धन मिलता है और आतंकवादी धन के बल पर विभिन्न गतिविधियाँ करते हैं जब इनको धन नहीं मिलेगा तो यह विभिन्न गतिविधियाँ अपने आप बन्द कर देगें।

17. **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवायें –** स्थानीय जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जायें। लोगों के सर्वागींण विकास के लिये इनकी मूलभूत आवश्यकतायें (रोटी, कपड़ा, मकान) पूरी की जाये। विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल व चिकित्सालय खोले जायें ताकि वहाँ कि जनता मुख्य धारा से जुड़ सके। अतः इन क्षेत्रों का विकास आवश्यक है। बिजली, पानी, यातायात एवं संचार सेवायें विकसित की जायें।
18. **आतंकी समूहों से वार्तालाप –** तत्कालीन सरकार आतंकवादी संगठनों से वार्तालाप करके व उनकी समस्याओं का समाधान करके और विभिन्न माँगों को पूरा करके ही आतंकवाद पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है।
19. **आतंकवाद के धन–प्रबन्धन स्रोतों, विभिन्न वित्तीय विधियों एवं मार्गों पर प्रभावशाली रोक लगाकर –** 'धन वह इंजिन है जो आतंकी–कार्यों को चलाता है।' आतंकवाद और आत्मघाती–दस्तों का कार्य इतना जटिल और योजनापूर्ण तैयारी के साथ क्रियान्वयन किया जाता है कि वह बिना पर्याप्त वित्तीय–स्रोतों के सम्भव हो ही नहीं सकता। इस कार्य में सभी वैधानिक एवं अवैधानिक तरीके शामिल होते हैं। विभिन्न चैरीटेबल (धर्मार्थ) ट्रस्टों के नाम पर इकट्ठा होने वाला धन अन्त में आतंकी समूहों के पास पहुँच जाता है। गरीब, अनाथों, विधवाओं, बेघरों, वृद्धाश्रमों, नारी निकेतनों, शरणार्थियों, असहायों आदि के नाम इकट्ठा होने वाले धन का दुरूपयोग होकर आतंकी संगठन चलाये जा रहे हैं। इन पर रोक लगनी चाहिए। जकत (Zakat), हवाला, कोरियर अनेकों आर्थिक अपराधों एवं षड्यन्त्रों द्वारा पैसा एकत्र किया जाता है। इन सभी पर प्रभावशाली रोक लगाने की महती आवश्यकता है।

आतंकवाद की समस्या को हल करने के अन्य सुझाव

1. प्रत्येक क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय राजनीतिक दल को यह समझना जरूरी है कि वोटों की राजनीति की तुलना में पूरे राष्ट्र का हित अधिक महत्त्वपूर्ण है तभी आतंकवाद को रोकने के लिए एक ऐसा कानून बनाया जा सकता है जिसके द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने अथवा आतंकवादियों को शरण देने वाले लोगों को दण्डित किया जा सके।
2. आतंकवाद से सम्बन्धित जिन लोगों को पकड़ा जाता है उनकी कानूनी कार्यवाही में बहुत अधिक समय लगता है जिसके कारण उन्हें कोई दण्ड नहीं मिल पाता है। इससे पुलिस और सुरक्षाबलों का मनोबल गिरता है अतः आवश्यक है कि उन्हें शीघ्र ही दण्डित किया जाए।

3. आतंकवादी संगठनों से किसी तरह का राजनीतिक समझौता नहीं किया जाना चाहिए। दूषित राजनीति के कारण इस तरह का कोई समझौता भविष्य में आतंकवादियों को फिर से सक्रिय होने का अवसर देता है।
4. यदि किसी राजनीतिक दल का नेता अथवा अधिकारी आतंकवादी को सहायता देने का दोषी पाया जाए तो उसके लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होना चाहिए।
5. आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम रक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए। ऐसी समितियों का नेतृत्व वहाँ के युवा वर्ग को देना चाहिए। इनके द्वारा सुरक्षाबलों को आतंकवादियों के ठिकानों की सूचना मिलने पर उनसे सही ढ़ंग से निपटा जा सकता है।
6. जनसंचार से साधनों जैसे – टेलीविजन, समाचार–पत्रों के द्वारा लोगों में यह भावना पैदा करना जरूरी है कि राष्ट्र का हित धर्म क्षेत्र, भाषा तथा जाति से ऊपर है। राष्ट्रीय चरित्र के बिना आतंकवाद की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।
7. आतंकवाद पर नियंत्रण रखने के लिए एक सक्षम गुप्तचर एजेन्सी का गठन करना आवश्यक है। ऐसा संगठन आतंकवादियों के अड्ड़ों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने में अधिक सहायक सिद्ध हो सकता है। उन सब प्रयासों के अतिरिक्त वर्तमान समय में हवाई अड्ड़ों, रेलवे स्टेशनों पर विशेष सर्तकता रखना आवश्यक है। जिससे वायुयान के अपहरण और ट्रेनों में होने वाली लूटपाट को रोका जा सके। इन प्रयत्नों के बाद भी आतंकवाद की समस्या का स्थायी समाधान तभी हो सकता है जब देश के राजनीतिक ढ़ाँचे को स्वस्थ बनाने के साथ ही राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के प्रयत्न किए जाये।
8. भारत की कुल थलीय सीमा रेखा 15,106 किलोमीटर और तटीय सीमा रेखा 7,516 किलोमीटर की है। मुख्य भूमि के अलावा इसके अधिकार क्षेत्र में 1197 द्वीप है। भारत अस्थिर पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे देश की आंतरिक समस्याओं से घिरे है। सरकार को यह समझना होगा कि आतंकवाद से निपटने की सभी रणनीतियाँ विफल हो जायेगी। जब तक भारत की खुली सीमा के आस–पास घुसपैठ और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक नहीं लगाई जाती जो इसको रोकने की आवश्यकता है सीमा क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने समुद्री इलाकों की सुरक्षा के लिए जल्द–से–जल्द केन्द्रीय नौ वाहन बोर्ड का गठन कर दिया जाना चाहिए ताकि नौ सेना के रक्षा बलों के बीच अधिक तालमेल सुनिश्चित किया जा सकें। भारत–नेपाल खुली सीमा रेखा पर अतिरिक्त चौकसी बरती जानी चाहिए।
9. आतंकवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। संविधान में उचित संशोधनों के माध्यम से आतंकवाद को कानून और व्यवस्था से अलग कर देना चाहिए। कानून और व्यवस्था राज्य सूची का हिस्सा बने रह सकते हैं जबकि आतंकवाद को संघ सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इससे केन्द्र सरकार

को आतंकवाद से निपटने के लिए और अधिक शक्तियाँ मिल जायेगी और सरकारी निकायों द्वारा चलाये जा रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों और अन्वेषणों पर राजनेताओं और धार्मिक–समूहों के प्रभाव पर भी रोक लगेगी।

10. सरकार को अपने खुफिया तंत्र को और अधिक मजबूत करना होगा जो आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए अति महत्त्वपूर्ण है। भारत सरकार को सशस्त्र बलों की एकीकृत कमान की तर्ज पर एक केन्द्रीय संयुक्त खुफिया एजेन्सी का गठन का देना चाहिए। इसकी भूमिका संयुक्त राज्य अमेरिका में सी.आई.ए. की भूमिका के समान होगी। भारत में किसी भी स्थान से एकत्रित की हुई खुफिया जानकारी इस केन्द्रीय संगठन को पहुँचाई जानी चाहिए जो उनका विश्लेषण करके सम्बन्धित रक्षा संगठनों को आगाह कर सके।
11. गृह मंत्रालय में एक अलग विभाग का गठन कर दिया जाना चाहिए जो केवल देश भर में चल रही आतंकवाद विरोधी अभियानों की निगरानी करें।
12. विदेश मंत्रालय में भी एक अलग विभाग का गठन किया जाना चाहिए जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से मुकाबला करने संबंधित कूटनीतिक पहलुओं से निपट सकें।
13. फलिस और अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए उन्हें सुसज्जित किया जाना चाहिए और उन्हें ऐसे अधिकार दिये जाये जो आवश्यकतानुसार निर्णय ले सकें।
14. आतंकवाद सम्बन्धित सभी मामलों की सुनवाई दैनिक आधार पर होनी चाहिए। ऐसे मामलों मे जल्द सुनवाई और फैसला आ जाने से आतंकवादी संगठनों से अपने गिरफ्तार साथियों को छुड़वाने के लिए आतंकवादी योजना बनाने हेतु कम गुन्जाईस रहेगी। एक बार देश की उच्च न्यायपालिका ने किसी व्यक्ति को आतंकवाद के कृत्यों के लिए दोषी ठहरा दिया हो तो उसे ऐसी सजा से बचने के लिए कोई मौका नहीं देना चाहिए जो दूसरों के लिए एक मिशाल साबित हो।
15. संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए और आतंकवाद से सम्बन्धित मामलों में राष्ट्रपति से की जाने वाली क्षमा याचना की प्रक्रिया का क्रियान्वयन शीघ्रतम किया जाना चाहिए।
16. आतंकवादी युवा बेरोजगारों को जिनका व्यवस्था से मोह भंग हो चुका है, को अपने संगठन में भर्ती करते है। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सभी कदम उठाये जाने चाहिए।
17. युवा वर्ग को शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराये जायें।
18. आतंकवादी घटनाओं की रोकथाम हेतु सुरक्षा संरक्षक का गठन किया जाये, जैसा कि इजरायल और अमेरिका में किया गया है। इन सुरक्षा संरक्षणों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाये कि वे आतंकवाद के पैदा होने से पूर्व ही नष्ट कर डाले या उसकी योजनाओं को विफल कर दें।

19. अपहरण एवं बंधक जैसी आतंकवादी कार्यवाहियों से निपटने हेतु विशिष्ट कमाण्डो बल तैयार किया जाये।
20. खुली समुद्री सीमा पर भी कारगर तंत्र स्थापित करना होगा।
21. जनता को जागरूक बनाना बेहद जरूरी है।
22. हमें राज्य में स्थित देशद्रोही एवं देशभक्त की पहचान होना अत्यन्त आवश्यक है। जाति, धर्म और भाषा का भेदभाव किए बिना देशभक्ति को संरक्षण देना चाहिए और देशद्रोही कोई भी हो दण्डित किया जाना चाहिए। आतंकवादियों की सूचना देने वालों को संरक्षण देना चाहिए और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखनी चाहिये। आज कश्मीर में राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन में अनेक ऐसे अधिकारी है जो आतंकवादियों की सहायता करते हैं। सेना और नागरिक के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो भी व्यक्ति आतंकवादियों को पकड़वायें, उनसे संघर्ष करें, हथियार के भण्डार पकड़वायें ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करना चाहिए।
23. आतंकवाद से निपटने के लिए 10 फरवरी 1998 ई. को मिस्र की राजधानी काहिरा में आतंकवाद पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत सहित विभिन्न देशों के शीर्ष सुरक्षा विशेषज्ञों ने आम सहमति से यह माना था कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझ कर की जाने वाली आतंकवादी कार्यवाही, चाहे उसका मकसद कुछ भी हो, एक अन्तर्राष्ट्रीय अपराध है। इसके अलावा इस बात पर भी सहमति बनी थी कि किसी भी देश को अन्य देशों में आतंकी गतिविधियों में लिप्त किसी भी आतंकवादी को राजनीतिक शरण नहीं देना चाहिए क्योंकि जब तक अन्य देश आतंकवादी संगठनों को धन और आतंकवादियों को शरण देते रहेंगे, तब तक आतंकवाद के खिलाफ एक राय रखने वाले देश इस भयंकर समस्या से नहीं निपट पाएँगे। विश्व में आतंकवाद के फैलने से चिंतित 46 देशों के सुरक्षा विशेषज्ञों, अनुसंधानकर्त्ताओं और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए आचार–संहिताओं को शामिल किया। घोषणा–पत्र के दस्तावेज में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अभियुक्त (आतंक का आरोपी) के इधर–उधर जाने पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्यार्पण को सरल बनाने की जरूरत है।
24. आतंकवाद को समाप्त करने के लिए यह समझना होगा कि ओसामा बिन लादेन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक नहीं अनेक ओसामा बिन लादेन पैदा हो रहे हैं। 'ऑपरेशन इंडयोरिंग फ्रीडम' के बाद अल जवाहिरी का नाम उभर कर सामने आया, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह एक कड़वा सच है कि आतंकवाद के खात्मे के जो प्रयास तथा उसके प्रभाव परिलक्षित हो रहे हैं, उससे आतंकवाद खत्म होने वाला नहीं है। "आतंकवाद तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक कि विकसित और विकासशील देश सामूहिक रूप से खुले हृदय से प्रयास न करें। आतंकवाद के बढ़ते जनाधार को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उन परिस्थितियों पर दृष्टि डाली जाए, जिनके

कारण करीब चालीस देश इसकी गिरफ्रत में आ चुके हैं। पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, उत्तरी अफ्रीका से लेकर अफगानिस्तान, यूरोप तक आतंकवाद के बढ़ते जनाधार के पीछे इन राष्ट्रों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सन्दर्भ, क्षेत्रीय राजनीति और पश्चिमी विशेषकर, अमेरिकी हस्तक्षेप का योगदान रहा है।

25. आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है और इस समस्या से निजात तभी पाई जा सकती है, जब उसका मुकाबला पूरी दुनिया मिलकर करे। यदि राष्ट्र आतंकवादियों को अपने शत्रु देशों के विरूद्ध प्रशिक्षण, शरण और शह देना बन्द कर दें, तो वास्तव में आतंकवाद में कमी आ सकती है, उसके खात्मे के प्रयास सफल हो सकते हैं। साथ ही विश्व स्तर पर एक आचार–संहिता बनाई जाये और उसका पालन विश्व के सभी देश करें, तो इससे यह होगा कि आतंकवादियों को पहचानने में मदद मिलेगी। सभी देश एक–दूसरे के यहाँ आतंकवाद को समूल नष्ट करने का संकल्प लें। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों से सम्बन्ध तोड़ दिया जाए, रंग–भेद और जाति–भेद को दूर करने का प्रयास किया जाए तथा शिक्षित बेरोजगार युवकों की समस्याओं को तन–मन–धन से दूर किया जाए। तभी वास्तव में आतंकवाद का सफाया हो सकता है। आतंकवाद निरोधक संकल्पों और उपायों को अमल में लाते समय यह भी ध्यान में अवश्य रखा जाना चाहिए कि यह मानवता रूपी शरीर में एक घाव नहीं बल्कि नासूर के रूप में स्थापित होता जा रहा है और यदि अब भी नहीं चेताया गया, तो मानवता की गति क्या होगी? बताने या कहने की आवश्यकता नहीं है।

26. आतंकवाद आज एक ऐसी समस्या बन चुकी है जिसका दंश समूचे विश्व को झेलना पड़ रहा है। इस समस्या ने इतना जटिल रूप अख्तियार कर लिया है कि इससे बाहर निकलने की जितनी भी कोशिशे की जा रही है, जटिलताएँ उतनी ही सामने आ रही हैं। कारण एकदम स्पष्ट है, आतंकवाद आखिर है, क्या? और इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? विश्व के अधिकांश राष्ट्र अभी यही तय नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर विश्व के तमाम देशों ने आतंकवाद को एक नीति के रूप में अपना चुके हैं और इसकी बदौलत वे एक ऐसी व्यूह रचना तैयार करना चाहते हैं, जिससे 'साङ्प भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे' अर्थात् अपने अभीष्ट लक्ष्य (शत्रु देश का विनाश) की प्राप्ति भी हो जाए और उसका नाम कहीं से भी आतंकवाद के साथ न जुड़े। लेकिन ऐसे राष्ट्रों को यह जान लेना चाहिये कि आतंकवाद के 'मकड़जाल' में बैठकर व्यूह रचना करते–करते कहीं ऐसा न हो कि आतंकवाद खुद उसे ही निगल जाए, क्योंकि भस्मासुर पैदा करने से शत्रु समाप्त नहीं होते बल्कि एक और शत्रु पैदा हो जाता है। अमरीका के साथ क्या हुआ था? 9/11 की घटना इसी का प्रमाण है। मेरी समझ से यदि आतंकवाद का सफाया करना है, तो सबसे पहले इस बात को मन में बैठानी होगी कि आतंकवाद किसी देश विशेष का नहीं, अपितु समूचे विश्व का दुश्मन है और इसकी गाज किसी पर भी गिर सकती है। इस सोच के साथ यदि आतंकवाद निरोधक कार्य किये जायँगे, तो कार्य और व्यवहार

में पारदर्शिता आयेगी, जिससे आतंकवाद के विरूद्ध किसी प्रकार की पक्षपातपूर्ण कार्यवाही को स्थान नहीं मिल सकेगा क्योंकि इसी पक्षपात पूर्ण नीतियों के नाते आतंकवाद को पल्लवित व फषित होने का अवसर मिलता है। राष्ट्रों को यह भी समझ लेना चाहिए कि हम इसलिए सुरक्षित है क्योंकि सभी राष्ट्र सुरक्षित है, तभी आतंकवाद के उन्मूलन का स्वप्न साकार हो सकेगा और यदि ऐसा हो सका, तो यह सदी की एक महान उपलब्धि होगी।

27. आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हमें जाति–धर्म व सम्प्रदाय की संकीर्ण भावना से ऊपर उठकर सभी व्यक्तियों को एकजुट होकर सामना करना होगा।
28. विश्व के सभी राष्ट्रों को एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी होगी और एक मंच पर आना होगा।
29. आतंकवाद को जड़ से कुचलने के लिए न्यायपालिका द्वारा लंबित अपराधों, विवादों एवं प्रकरणों का निराकरण त्वरित करना एवं संविधान में आतंकवाद के लिए कठोरतम दण्ड के प्रावधान बनाने होगें।
30. विश्व जनमत से पाकिस्तान के ऊपर यह दबाव डलवाना चाहिए कि वह भारत विरोधी विघटनकारी तत्त्वों को जन–धन और शस्त्रों के रूप में सहयोग देना बंद करे भारत में वर्तमान आतंकवाद के अस्तित्व में पाकिस्तान की भूमिका निश्चय ही हमारे लिए निराशाजनक है।
31. हमें संसाधनों के न्यायपूर्ण एवं समान वितरण पर भी ध्यान देना होगा। यह भी समाज एवं प्रशासन का दायित्व है कि जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर कभी किसी को अन्याय और अपमान न सहना पड़े। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना के विकास से आतंकवाद को समूल नष्ट किया जा सकता है।
32. सर्वोच्च न्यायालय में 2006 से लंबित पड़े पुलिस सुधार कछुए की चाल से आगे बढ़ रहे हैं। खुफिया तंत्र भी जस का तस है। समुद्री तटरक्षक दल के पास आज भी संसाधनों का अभाव है। सबसे दुःख की बात यह है कि हमारे पास आज भी शीर्ष राजनीतिक स्तर पर ऐसी कोई दूरगामी सामरिक रणनीति नहीं है, जिसमें कि आक्रमण और आत्मरक्षा दोनों का सम्मिश्रण हो तथा केन्द्र में चाहे जिस राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, हर सरकार इसी रणनीति पर चलती है।
33. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद आज निश्चय ही विश्व शांति, सुरक्षा एवं विकास के लिए एक गंभीर आपदा के रूप में निरूपित हुआ है। अतः इस पर अंकुश लगाने के लिए संपूर्ण संसार के देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में सामूहिक रूप से निजी स्वार्थों का परित्याग कर आगे आना होगा। अब आतंकवाद को पोषित व प्रायोजित करने वाले देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहिष्कार होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ से उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। मानव ने स्वार्थ के वशीभूत होकर आतंकवाद की चादर ओढ़ ली है और 'जिस डाल पर बैठा है,

उसी को काट रहा है।' इस सदी में निः संदेह आतंकवाद सबसे घातक इंसानी आपदा बन चुकी है। अतः समय रहते इस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है।

34. आतंकवाद मुक्त समाज की स्थापना का सपना तभी साकार हो सकता है, जब राजसत्ताओं के चरित्र में बुनियादी बदलाव आए और वे एक समतावादी व न्यायोचित समाज को जन्म लेने दें।
35. मुस्लिम समाज को 'अल्लाह के इस्लाम' और 'मुल्ला के इस्लाम' का फर्क समझाना होगा।
36. मकान किराये पर देते समय उस व्यक्ति का पहचान–पत्र जरूर माँगे और उनकी जाँच करें तथा उसकी गतिविधियों पर निगाहें रखे।
37. अगर आतंकवादियों एवं उग्रवादियों की माँगें न्यायोचित एवं संविधान के अनुरूप हो तो उन्हें सरकार को तुरन्त मान लेना चाहिये और आतंकवादियों को देश की मुख्य धारा में जोड़कर उनके आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए।
38. किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने पर फौरन पुलिस व अधिकृत व्यक्तियों को इसकी सूचना दी जाये।
39. आतंकवाद की शुरूआत एक पवित्र उद्देश्य से हुई थी अर्थात् साम्राज्यवाद के जुएँ या भ्रष्ट प्रशासन को उखाड़ फेंकने के लिए। परन्तु शनैः शनैः इसका स्वरूप भयावह होता गया और आज इसकी चपेट में दुनिया के तमाम देश आ गये हैं। क्षेत्रीय विवाद, धार्मिक उन्माद, भाषायी हिंसा और जातीय उग्रवाद ने आतंकवाद को सशक्त, विनाशकारी, घृणा से ओत–प्रोत परम्परा को अपनाने और महत्त्वाकांक्षाओं को शीघ्र पूरा करने की उतावली, विदेशी प्रलोभन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था और नैतिक आदर्शों के पतन के कारण राजनीतिक नेताओं ने अपने चुनावी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जन–विश्वास जीतने की कठिनाई महसूस करते हुए जनता में आतंक के माध्यम से अपना प्रभाव विस्तार शुरू किया। इसके लिए राजनीतिज्ञों ने जातीय, धार्मिक एवं क्षेत्रीय आधारों में जनता को बाँटकर आपराधिक तत्त्वों का सहारा लिया। लेकिन जब अपराधी तत्त्वों को यह अनुभव हुआ कि राजनीतिज्ञ उनके सहारे अपना पद और सत्ता बचा रहे हैं तो उन्होंने स्वयं को नेता घोषित कर दिया और उसको आतंकवादी गतिविधियों से पुष्ट किया। उनकी महत्त्वाकांक्षा जैसे–जैसे बढ़ती गयी वैसे–वैसे क्षेत्रीय आतंकवाद फैलता गया। उदाहरणार्थ, पंजाब के जनरेल सिंह भिण्डरवाले को उत्प्रेरित करने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने किया था परन्तु इसी कारण बाद में वह श्रीमती गाँधी का दुश्मन बन गया। ऐसे ही गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, नागा और मिजो विद्रोहियों, उल्फा, जे.के.एल.एफ. आदि संगठनों तथा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आदि कई राज्यों में इस तरह की पृथक्कतावादी गतिविधियों के कई नेता अपने उद्देश्यों में सफल रहे हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के अलावा आतंकवाद को पनपाने में कुछ विदेशों का हाथ है जो खुलेआम आतंकवादियों को शरण और प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। जैसे पंजाब और कश्मीर आतंकवादियों को पाकिस्तान एवं चीन द्वारा नागा और मिजो विद्रोहियों को, चीन द्वारा तमिलनाडु राज्य में लिट्टे छापामारों को प्रशिक्षण, हथियार सप्लाई, धन आदि दिया जाता रहा है। आतंकवादी बेखौफ होकर सारी दुनिया में दहशत का माहौल तैयार कर चुके हैं और इनमें सबसे ज्यादा दहशत इस्लामी आतंकवाद से दुनिया को है। वास्तव में शिया कट्टरवादी ईरान और सुन्नी कट्टरवादी सूडान ने एक तरह से सबसे ज्यादा लड़ाकू अरब इस्लामी मोर्चा तैयार किया है और इसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने इस्लामी आतंकवाद फैलाने की कमान संभाली। इस्लामिक आतंकवाद बढ़ जाने के पीछे अरब और मुस्लिम देशों की सामाजिक–आर्थिक समस्याएँ है। साम्यवादी देशों के टूटकर बिखर जाने के कारण सैद्धान्तिक खालीपन आ गया था तथा मुस्लिम देशों के लोगों को बेरोजगारी, सामाजिक अस्थिरता और आर्थिक ठहराव से उत्पन्न परेशानियों को भुलाने के लिए सिर्फ उग्र इस्लाम का ही सहारा नजर आया और चरमपंथी इस्लामी संगठनों को अपने राजनीतिक अरमान पूरा करने का सही मौका मिल गया। इस्लाम ने सिद्धान्त का सहारा लिया जिसमें शरीअत (इस्लामी कानून) के आधार पर एक विशाल इस्लामी साम्राज्य स्थापित करने की अवधारणा बलवती हुई। इसी मौके का फायदा उठाया ओसामा बिन लादेन जैसे अरबपति ने।

आज इस्लामी आतंकवाद अरब देशों से निकलकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और काकेशस तक फैल चुका है। आज पकिस्तान की इस्लामी पार्टियों में करीब 1,50,000 आतंकवादी है, जिन्हें कश्मीर, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में युद्ध का पूरा अनुभव है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा दुनिया के और भी कई देशों के मदरसों में उन्मादी शिक्षा दी जा रही है और वहाँ आतंकवादी तैयार करने तथा उन्हें प्रशिक्षण देने वाले शिविर लगाये जा रहे हैं। आज लीबिया, सूडान, अलबानिया, यमन, सीरिया और लेबनान में भी आतंकवादियों को तैयार करने के उद्योग बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। वास्तव में आतंकवाद को धर्म या किसी नस्ल से नहीं जोड़ना चाहिए परन्तु आतंकवादी इसे धर्म से इसलिए जोड़ते हैं कि इस्लामी जनता इस्लाम के नाम पर उन्हें बहुत पैसा देती है। फलतः वे पर्याप्त मात्रा में धन और जन जुटा लेते हैं। यहाँ यह बताना प्रासंगिक होगा कि अगर आतंकवादी इस्लाम का दुरूपयोग कर रहे हैं तो पूरे इस्लामी समाज को आतंकवादी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। 9 दिसम्बर 1985 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने एक प्रस्ताव द्वारा आतंकवाद को गम्भीरता से लिया और **विश्व की सरकारों से अपील की गई –**

1. वे आतंकवाद के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करें और इस समस्या के समाधान हेतु कठोर कदम उठायें।

2. अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह करें और किसी दूसरे देश के प्रति आतंकवादी गतिविधियों को संगठित न करें, न ही प्रोत्साहन दें, न सहायता दें और न ही उसमें शामिल हों।
3. आतंकवादियों को पकड़ने पर उन पर मुकदमा चलाने तथा उन्हें प्रत्यार्पित करने में एक–दूसरे की मदद करें।
4. अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारणों को खत्म करने हेतु प्रयास करें तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील रहे।

परन्तु आज तक इससे सफलता नहीं मिली। सार्क के 5 वें शिखर सम्मेलन (21–23 नवम्बर, 1990) में एक प्रस्ताव द्वारा आतंकवाद को समाप्त करने, उन पर मुकदमा चलाने, अपराधियों को प्रत्यार्पित करने, आतंकवादियों के मध्य साँठ–गाँठ तोडने के उपायों पर (मालद्वीप की राजधानी माले में) बल दिया गया। यहाँ तक कि गुट–निरपेक्ष देशों के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन (4–7 सितम्बर, 1989) में आतंकवाद के बढ़ते चरण पर चिन्ता प्रकट की गई तथा इसके खात्मे पर बल दिया गया। फिर भी इन प्रस्तावों को सम्बन्धित राष्ट्र अपने गले से नीचे नहीं उतार सके हैं। यदि राष्ट्र आतंकवादियों को अपने शत्रु देशों के विरूद्ध प्रशिक्षण, शरण और शह देना बन्द कर दें तो वास्तव में आतंकवाद में कमी आ सकती है उसके खात्मे के प्रयास सफल हो सकते हें। साथ ही विश्वस्तर पर एक आचार–संहिता बनाई जाये और उसका पालन विश्व के सभी देश करें तो इससे यह होगा कि आतंकवादियों को पहचानने में मदद मिलेगी। सभी देश एक–दूसरे के यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा न देने का संकल्प लें। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों से सम्बन्ध तोड़ दिया जाये, रंग–भेद और जाति–भेद को दूर करने का प्रयास किया जाये तथा शिक्षित बेरोजगार युवकों की समस्याओं को तन–मन से दूर किया जाए तभी वास्तव में आतंकवाद का सफाया हो सकता है।

आतंकवाद कैसे समाप्त किया जाये? आज एक प्रमुख विषय बन चुका है क्योंकि इसके शिकार विकसित और विकासशील दोनों देश है। हालाँकि आतंकवाद से सबसे ज्यादा नुकसान विकासशील देशों को हुआ है। वैसे विकसित देशों को भी आतंकवाद से जूझना पड़ा है परन्तु साधन–सम्पन्न होने के कारण वे अधिक प्रभावशील ढ़ंग से उसका मुकाबला करने में सक्षम है। इसके विपरित विकासशील देशों को, जिनके पास साधनों का पहले से ही अभाव है, भारी नुकसान उठाना पडता है। कहाँ तो वे भूख, बेरोजगारी, कुपोषण और अशिक्षा से लड़ेंगे उल्टे उन्हें अपने संसाधनों का इस्तेमाल आतंकवाद से लड़ने में करना पड़ता है। मई 1998 में सम्पन्न हुए जी–15 सम्मेलन में आतंकवाद को समाप्त करने की वचनबद्धता प्रकट की गई क्योंकि यह प्रस्ताव भारत ने रखा था। भारत आज सबसे अधिक प्रभावित राष्ट्र है जो संसाधन विकास में लगाने चाहिए आज वह आतंकवाद का सामना करने में लगा रहा है, न केवल जम्मू–कश्मीर बल्कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य भी इसके शिकार हुए हैं। इनके पीछे विदेशी खुफिया एजेन्सियों का हाथ है। आतंकवाद तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि विकसित और विकासशील देश सामूहिक रूप से खुले हृदय से

प्रयास न करें। आतंकवाद के बढ़ते जनाधार को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उन परिस्थितियों पर दृष्टि डाली जाये जिनके कारण करीब 40 देश इसकी गिरफ्रत में आ चुके हैं। पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, उत्तरी अ़्रीका से लेकर अफगानिस्तान, यूरोप तक आतंकवाद के बढ़ते जनाधार के पीछे इन राष्ट्रों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संदर्भ, क्षेत्रीय राजनीति और पश्चिमी विशेषकर अमरीकी हस्तक्षेप का योगदान रहा है। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए यह समझना होगा कि ओसामा बिन लादेन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक नहीं अनेक ओसामा बिन लादेन पैदा हो रहे हैं। चूँकि आतंकवाद एक विश्व व्यापी समस्या है और इस समस्या से निजात तभी पायी जा सकती है जब उसका मुकाबला पूरी दुनिया मिल कर करे। 11 सितम्बर, 2001 की अमरीकी घटना ने यह साबित कर दिया है दुनिया का ताकतवर से ताकतवर देश भी अकेले आतंकवाद से मुकाबला नहीं कर सकता। भारत ने दर्जनों बार विश्वमंच पर यह साबित करने की कोशिश की है कि दुनिया के किसी भी देश की सरहद आतंकवाद से सुरक्षित नहीं है।

न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर महज अमरीकी अर्थशास्त्र का ही नहीं बल्कि आधुनिक पूंजीवादी अर्थशास्त्रा के एक वैभव का प्रतीक था। वह मनुष्य के आधुनिक विकास प्रक्रिया के शिखर का भी प्रतीक था लेकिन उन्मादवादी हमलों से इस वैभव के प्रतीक, इस आधुनिक विकास प्रक्रिया के शिखर को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। अभेद्य दुर्ग पेंटागन की विध्वंसता ने भी साबित कर दिया कि अगर शैतानियत से मिलकर नहीं लड़ा गया तो एक अकेला मुल्क चाहे वह जितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अतः वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर और पेंटागन पर हुए आतंकवादी हमलों ने दुनिया को बता दिया है कि आतंकवाद, वैश्विक मंदी और पर्यावरण विनाश से भी बड़ी समस्या एवं मानव निर्मित आपदा है। आतंकवादियों का संबंध चाहे जिस क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म या समुदाय से हो वे किसी एक जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म और समुदाय के शत्रु नहीं बल्कि समूची मानव जाति के संवेदनशील शत्रु है। मार्च 2001 में ब्रिटेन में 25 और अमरीका में 30 सितंबर, 2001 को 27 संगठनों और व्यक्तियों को आतंकवादियों के रूप में पहचान करके उनकी सम्पत्ति ़्रीज एवं प्रतिबन्धित करने से पश्चिमी देशों के रूख में आए परिवर्तन का मात्रा इतना ही संकेत है कि अपने ऊपर बने हुए आतंकवादियों के दबाव को झेल रहे भारत जैसे दूसरे देशों की कठिनाई को समझने के लिए मजबूर किया है।

6

संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

प्राथमिक स्रोत : (Primary Data)

1. अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट
2. विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट
3. पार्लियामेंट की डिबेट
4. साक्षात्कार

द्वितीय स्रोतः (Secondary Data)

1. A. Subramanyam Raju, "Terrorism in South Asia: Views from India", 2004, India Research Press, B-4/22, Safdarjung Enclave,New Delhi-110029.
2. Ashok Bhatt, "Global Terrorism", 2007, Saurabh Publishing House, 4263/3, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi – 110002.
3. अरूण त्रिपाठी, अरूण पाण्डेय, आनंद प्रधान, दिलीप चौबे, बृज बिहारी चौबे, अखिलेश सुमन, ''मुस्लिम आतंकवाद बनाम अमेरिका'', वाणी प्रकाशन, 21–ए, दरियागंज, नई दिल्ली–110002.
4. अर्चना शर्मा, गुलाब चन्द्र ललित, ''भारत की आन्तरिक सुरक्षा को खतरे'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, दूरभाष 011–23255141.
5. डॉ. अर्चना उपाध्याय, ''भारतीय विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय संबंध'', 2005, संजय प्रकाशन, 4378/4–बी, 209 जे.एम.डी. हाउस, गली मुरारीलाल, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, फोन 23245808, 30957691.
6. आशा कौशिक, ''मानवाधिकार और राज्य : बदलते संदर्भ, उभरते आयाम'', 2004, पोइन्टर पब्लिशर्स, व्यास बिल्डिंग, एस.एम.एस. हाइवे, जयपुर 302003 (राज.) फोन 2578159.
7. डॉ. ए.पी. शुक्ल, डॉ. राहुल मिश्र, ''राष्ट्रीय सुरक्षा की समसामयिक समस्यायें'', 2006, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, फोन 9350551515, 23254306.
8. डॉ. अर्चना पारीक, ''भारत–श्रीलंका संबंध'', 2009, Research Publications, Tripolia, Jaipur-2, Ph. 0141-2312156.
9. Andrew O'Neill, "Terrorist Use of Weapons of Mass Destruction: How Serious is the Threat?", 2003, Australian Journal of International Affairs, 57(1). http://www.tandf.co.uk/journals
10. B.P. Singh Sehgal, "Global Terrorism", 1995, Deep & Deep Publications, F-159, Rajouri Garden, New Delhi-110027.
11. डॉ. बाबूराम पाण्डेय, ''राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध'', 2008, प्रकाश बुक डिपो, बरेली (उ.प्रद्ध।

12. डॉ. बी.एल.फड़िया, ''अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति'', 2008, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
13. Bruce Hoffman, "Rethinking Terrorism and Counterterrorism since 9/11", 2002, Studies in Conflict and Terrorism, 25(5).
14. Badruddin, "Global Peace and Anti–Nuclear Movements", 2003, Mittal Publications, A-110, Mohan Garden, New Delhi – 110059.
15. B.C. Upreti, Shashi Upadhyay, "Emerging Challenges of Security in South Asia", 2012, Kalinga Publications, 10–A, Pocket–1, Phase–1, Mayur Vihar, Delhi–110091.
16. डॉ. चन्द्रशेखर पाण्डेय, ''नवीन अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की उभरती प्रवृत्तियाँ एवं भारतीय सुरक्षा'', 2009, अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ.प्र.द्ध, अप्रकाशित शोध–प्रबन्ध।
17. D.P. Sharma, "Countering Terrorism", 1992, Lancers Books, P.O. Box 4236, New Delhi – 110048.
18. डॉ. दीपा सिंह, के.पी.सिंह, ''मानवाधिकार एवं पुलिस तंत्रा'', 2002, दि ब्राइट लॉ हाउस, 426/427, द्वितीय तल, कूट्चा बृजनाथ, चाट्दनी चौक, दिल्ली–110006, दूरभाष 011–23946275.
19. डॉ. धीरेन्द्र द्विवेदी, संजय कुमार, अनुराग जायसवाल, गुलाब चन्द्र ललित, ''अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति'', 2006, अध्ययन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली–110094.
20. David Cook and Olivia Allison; "Understanding and Addressing Suicide Attacks", 2007, Pentagon Press, A-38 Hauz Khas, New Delhi.
21. Daniel Byman, "The Logic of Ethnic Terrorism", 1998, Studies in Conflict and Terrorism, 21(2). http://www.informaworld.com
22. David Claridge, "State Terrorism? Applying a Definitional Model", 1996, Terrorism and Political Violence, 8(3). http://www.informaworld.com
23. Dr. Deepak Rao, Dr. Seema Rao, "Terrorism: A Comprehensive Analysis of World Terrorism", 2004, A.P.H. Publishing Corporation, 5, Ansari Raod, Daryaganj, New Delhi – 110002.
24. Giri Raj Shah, "Encyclopaedia of International Terrorism", 2002, Anmol Publications Pvt. Ltd., 4374/4B, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-110002.
25. Gilles Kepel, "The War for Muslim Minds", 2008, Viva books Private Limited, 4737/23, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi –110002.
26. Gretchen Peters, "Seeds of Terror", 2009, Published by Hachette India, MG Road, Sector – 28, Gurgaon – 122001.
27. डॉ. गुरूराम जी विश्वकर्मा मधुकर, ''भारत–तिब्बत–चीन का अस्तित्व'', 2011, कल्पज पब्लिकेशन्स, सी–30, सत्यवती नगर, दिल्ली–110052.
28. Harlan Ullman, "Is the US Winning or Losing the Global War on Terror and How Do We Know?", 2006, Australian Journal of International Affairs, 60(1). http://www.informaworld.com
29. (Col.) Harjeet Singh (Retd.), "Terrorism in South Asia", 2011, Pentagon Press, 206, Peacock Lane, Shahpur Jat, New Delhi–110049.

30. जे.एन.दीक्षित, ''भारत की विदेश नीति और आतंकवाद'', 2006, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, 5, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002.
31. जगदीश्वर चतुर्वेदी, ''साम्प्रदायिकता, आतंकवाद और जनमाध्यम'', 2005, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लि., 4697/3, 21ए, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002.
32. Jasjit Singh, "Kashmir, Pakistan and the War by Terror", 2002, Small Wars and Insurgencies, 13(2). http://www.informaworld.com
33. K.P. Gupta, "International Terrorism", 2002, Atlantic Publishers and Distributors, B-2, Vishal Enclave, Opp. Rajouri Garden, New Delhi-110027.
34. Kulwant Kaur, "Global Terrorism: Issues, Dimensions and Options", 2005, Kanishka Publishers, Distributors, 4697/5-21A, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi – 110002.
35. के.के.मिश्रा, सुभाष शुक्ला, ''अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्त'', 2010, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि., 4697/3, 21ए, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, दूरभाष 23281655, 23270239.
36. कृष्णानन्द शुक्ल, ''शांति, सुरक्षा और विकास की समस्यायें'', 2009, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002.
37. डॉ. कृष्णानन्द शुक्ल, ''पाकिस्तान एक सुरक्षा चुनौती'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, दूरभाष 011–23255141.
38. डॉ. कृष्णानन्द शुक्ल, ''लाल शीत युद्ध की दास्तान–भारत और पाकिस्तान'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, दूरभाष 011–23255141.
39. डॉ. कृष्णानन्द शुक्ल, ''भारत–पाक संबंध (विवादों के आइने में)'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, दूरभाष 011–23255141.
40. Karin von Hippel, "The Roots of Terrorism: Probing the Myths", 2002, The Political Quarterly, 73(SI).
41. डॉ. कृष्णकुमार रत्तू, ''दक्षिण एशिया में आतंक का साया और सार्क घोषणायें'', 2005, बुक एनक्लेव, जैन भवन, एन.ई.आई. के सामने, शांति नगर, जयफर – 302006.
42. कमलेश्वर, ''अघोषित आपात काल'', आलेख प्रकाशन, वी–8, नवीन शाहदरा, दिल्ली – 110032.
43. डॉ. लल्लन जी सिंह, ''राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा'', 2006, प्रकाश बुक डिपो, बरेली– 233003 (उ.प्र.), दूरभाष 2470217.
44. Dr. Lokesh, Dr. Anil Dutta Mishra, "Terrorism A Global Challenge", 2009, Regal Publications, F-159, Rajouri Garden, New Delhi – 110027.
45. Martha Crenshaw, "The Causes of Terrorism", 1981, Comparative Politics, 13(4).

46. Manoj Joshi, "On the Razor's Edge : The Liberation Tigers of Tamil Eelam", 1996, Studies in Conflict and Terrorism, 19(1). http://www.informaworld.com
47. Mahendra Gaur, "Terrorism and Human Rights", 2003, Anamika Publishers & Distributors (p) Ltd., 4697/3, 21A, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi – 110002.
48. प्रो. मानचन्द खंडेला, ''भारत–पाक और अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद'', 2010, आविष्कार पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 807, व्यास बिल्डिंग, चौड़ा रास्ता, जयफर 302003 (राज.) फोन 0141–2578159.
49. डॉ. मानचन्द खंडेला, ''अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद'', 2011, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, 807, व्यास बिल्डिंग, चौड़ा रास्ता, जयफर 302003 (राज.) फोन 0141–2578159.
50. मानिक लाल गुप्त, ''अन्तर्राष्ट्रीय संबंध'', 2005, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, बी–2, विशाल एन्क्लेव, राजौरी गार्डन के सामने, नई दिल्ली–110027, दूरभाष 25413460.
51. Mia M. Bloom, "Palestinian Suicide Bombing: Public Support, Market Share and Outbidding", 2004, Political Science Quarterly, 119(1).
52. Mahavir Singh, "International Terrorism and Religious Extremism", 2004, Anamika Publishers & Distributors (p) Ltd., 4697/3, 21A, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi – 110002.
53. Max G. Manwaring, "Non-State Actors in Colombia: Threats to the State and to the Hemisphere", 2002, Small Wars and Insurgencies, 13(2). http://www.informaworld.com
54. M. Rajamanickam, "Psychological Perspective of International Terrorism", 2009, Concept Publishing Company, A/15-16, Commercial Block, Mohan Garden, New Delhi – 110059.
55. Nimrod Raphaeli, "Financing of Terrorism: Sources, Methods and Channels", 2003, Terrorism and Political Violence, 15(4). http://www.tandf.co.uk/journals
56. Dr. Nazrul Islam, "Islam 9/11 and Global Terrorism", Viva Books Private Limited, 4262/3, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi–110002.
57. नर्वदेश्वर शुक्ल, डॉ. गुलाब चन्द्र ललित, ''भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में हिमालयी क्षेत्र का स्त्रातेजिक महत्त्व'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, दूरभाष 011–23255141.
58. नरेन्द्र कुमार शर्मा, ''भारत में नक्सलवाद'', 2012, ओमेगा पब्लिकेशन्स, 4378/4बी, जी–4, जे.एम.डी. हाउस, गली मुरारीलाल, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, दूरभाष 65901906, 23278062.
59. Omprakash Mishra, Sucheta Ghosh, "Terrorism and Low Intensity Conflict in South Asian Region", 2003, Manak Publications Pvt. Ltd., B-7, Saraswati Complex, Subhash Chowk, Laxmi Nagar, New Delhi-110092.
60. Proshanta K. Nandi, "Socio-Political Context of Sikh Militancy in India", 1996, Journal of Asian and African Studies, XXXI (3-4).

61. Dr. Prashant Agarwal, “South Asia: Peace, Security & Development”, 2006, Published by Kilaso Books, 2/19, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi–110002.
62. P.N. Mishra, “Transnational Terrorism in a Globalising World”, 2003, Published by Authors Press, E-35/103, Jawahar Park, Laxmi Nagar, Delhi – 110092.
63. Paul J. Smith, “Terrorism and Violence in Southeast Asia”, 2005, Pentagon Press, A-38, Hauz Khas, New Delhi – 110016.
64. पवन कुमार सिंह, संदीप पाण्डेय, ''दहशतगर्द अमेरिका'', 2005, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि., 4697/3, 21 ए, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, दूरभाष 011–23281655.
65. Robert Allison, “Global Terrorism Ideology and Operation”, 2008, Global Vision Publishing House 20, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-110002.
66. Rob Schultheis, “Hunting Bin Laden”, 2009, Jaico Publishing House, A-2, Jash Chambers, 7–A Sir Phirozshah Mehta Road Fort, Mumbai – 400001.
67. डॉ. रामतिवारी, ''आतंकवाद का विश्व शांति पर प्रभाव'', 2007, छत्रापति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानफर (उ.प्र.), अप्रकाशित शोध–प्रबन्ध।
68. आर.के. ओहरी, ''इस्लाम के बढ़ते कदम'', 2007, मानस पब्लिकेशन्स, 4858, गली प्रहलाद, 24, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, फोन 23265523.
69. डॉ. आर.बी.सिंह, ''भारत में आतंकवाद'', 2010, राधा पब्लिकेशन्स, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, दूरभाष 23247003.
70. Robert A, “The Strategic Logic of Suicide Terrorism”, 2003, Pape American Political Science Review, 97(3).
71. Richard Jackson, Eamon Murphy and Scott Poynting, “Contemporary State Terrorism”, 2010, Published by Routledge Taylor & Francis Group, London and New York.
72. S.K. Shiva, “Counter Terrorism”, 2003, Authors Press, E-35/103, Jawahar Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092.
73. डॉ. एस.के. मिश्रा, ''राष्ट्रीय रक्षा व सुरक्षा'', मॉडर्न पब्लिशर्ज, रेलवे रोड़, जालंधर।
74. डॉ. एस.के. मिश्रा, ''आतंकवाद व आपदा प्रबंधन'', 2010, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली–110002, फोन नम्बर–23247003.
75. सुस्मिता बन्धोपाध्याय, ''तालिबान, अफगान और मैं'', राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., 1–बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली–110002.
76. संजय कुमार, गुलाब चन्द्र ललित, ''राष्ट्रीय सुरक्षा (मुद्दे और चुनौतियाँ)'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, दूरभाष 011–23255141.
77. डॉ. संजय कुमार, ''असम का नृजातीय संघर्ष और भारतीय सुरक्षा'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, दूरभाष 011–23255141.

78. Sridhar K. Khatri, Gert W. Kueck, “Terrorism in South Asia”, 2003, Shipra Publications, 115-A, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092, Ph. 22500954.
79. Sankar Sen, “Terrorism around the World: Challenges and Responses”, 2009, Concept Publishing Company, A/15-16, Commercial Block, Mohan Garden, New Delhi – 110059.
80. Sudhir Kumar Singh, “Terrorism A Global Phenomenon”, 2000, Authors Press, E-35/103, Jawahar Park (Shree Ganesh Complex), Laxmi Nagar, Delhi – 110092.
81. Sudhakar Raje, “Pakistan’s Intelligence: Export House of Terror”, 2012, Manas Publications, 4402/5-A, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi – 110002.
82. डॉ. (मेजर) एस.के.एस.सेंगर, डॉ. अशोक कुमार तिवारी, ''साइबर आतंकवाद'', 2012, चन्द्रान्ती पब्लिकेशन्स, कानफर–208001 (उ.प्र.)।
83. Subramaniam Swamy, “Sri Lanka in Crisis : India’s Options”, 2007, Har-Anand Publications Pvt. Ltd., E-49/3, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020, Tel. 41603490.
84. Sunil Sondhi, “Global Terror”, 2001, Sanjay Prakashan, 4378/4B, 209, J.M.D. House, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi–110002.
85. Tore Bjorgo, “Root Causes of Terrorism”, 2005 Published by Routledge Taylor & Francis Group, London and New York.
86. Thomas Matyok, Jessica Senehi, Sean Byrne, “Critical Issues in Peace and Conflict Studies”, 2011, Rowman & Littlefield publishers, Inc., 4501 Forbes Boulevard, Suite 200, Lanham, Maryland 20706.
87. Thomas Perry Thornton Harry Eckstein (ed.), “Terror as a Weapon of Political Agitation”, 1964, Internal War : Problems and Approaches (New York : Free Press).
88. (मेजर जनरल) विनोद सहगल, ''अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद'', 2006, प्रभात प्रकाशन, 4/19 आसफ अली रोड़, नई दिल्ली–110002.
89. डॉ. विपिन कुमार मिश्रा, डॉ. आशुतोष पाण्डेय, ''भारत और आतंकवाद'', 2012, विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली–110002.
90. डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव, ''आतंकवाद का समकालीन परिदृश्यः स्वरूप एवं समस्यायें'', 2011, ओमेगा पब्लिकेशन्स, 4378/4बी, जी–4, जे.एम.डी. हाउस, गली मुरारीलाल, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002.
91. डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव, ''वैश्विक आइने में आतंकवादः वर्तमान परिदृश्य एवं भविष्य की चुनौतियाँ'', 2011, ओमेगा पब्लिकेशन्स, 4378/4बी, जी–4, जे.एम. डी. हाउस, गली मुरारीलाल, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, फोन 65901906.
92. विवेक सक्सेना, सुशील राजेश, ''जेहाद का जुनून'', 2011, सत्साहित्य प्रकाशन, 205–बी, चावड़ी बाजार, दिल्ली–110006.

93. वेद प्रकाश वैदिक, ''अफगानिस्तान–कल आज और कल'', राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., 1–बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली–110002.
94. डॉ. वी.एन. अरोरा, डॉ. नन्द किशोर, डॉ. अभय कुमार सिंह, ''दक्षिण एशिया में सुरक्षा चुनौतियों के नये आयाम'', 2012, मोहित पब्लिकेशन्स, 4675/21, गणपति भवन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, दूरभाष 011–23255141.
95. Vinita Priyedarshi, "Typology of Counter Terrorism Strategies", 2010, KW Publishers Pvt. Ltd., 4676/21, First Floor, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi – 110002.
96. V.K. Sharma, "War Against Terrorism", 2003, Published by: Book Enclave, Jain Bhawan, opp. N.E.I., Shanti Nagar, Jaipur-302006.
97. (Major General) Vinod Saighal, "Dealing with Global Terrorism", 2003, Sterling Publishers Private Limited, A-59, Okhla Industrial Area, Phase – II, New Delhi – 110020.
98. Wilson John, Vishwas Kumar, "Investigating the Mumbai Conspiracy", 2009, Published by Pentagon Press, 206, Peacock Lane, Shahpur Jat, New Delhi – 110049.
99. Yoram Schweitzer, Shaul Shay, "The Globalization of Terror", 2004, Viva books Private Limited, 4262/3, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi – 110002.
100. Yevgeny M. Primakov, "A World Challenged", 2005, Manas Publications, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi – 110002.
101. Zachary Abuza, "Tentacles of Terror : Al Qaeda's Southeast Asian Network", 2002, Contemporary Southeast Asia : A Journal of International and Strategic Affairs, 24(3). http://www.bookshop.iseas.edu.sg
102. Zachary Abuza, "Militant Islam in Southeast Asia", 2005, Viva Books Private Limited, 4262/3, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi–110002.

जर्नल्स (Journals)

1. स्ट्रेट्जिक एनालिसिस, IDSA, नई दिल्ली।
2. स्ट्रेट्जिक डायजेस्ट, IDSA, दिल्ली।
3. इण्डियन डिफेंस रिव्यू, नई दिल्ली।
4. इन्टरनेशनल स्टडी, JNU, नई दिल्ली।
5. यू.एस.आई. जर्नल्स, नई दिल्ली।
6. इण्डिया क्वाटरली, ICWA, नई दिल्ली।
7. वर्ल्ड अपेफयर्स, जे.सी. कपूर पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
8. साउफथ एशियन सर्वे, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
9. इण्डियन जर्नल ऑफ पोलिटिक्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
10. वर्ल्ड फोकस, जी. किशोर बाबू पब्लिकेशन, दिल्ली।

पत्रिकायें (Magazines and Periodicals)

1. India Today
2. Competition Success Review

3. प्रतियोगिता किरण
4. क्रोनोलॉजी
5. प्रतियोगिता दर्पण
6. समसामयिक महासागर
7. दैनिक जागरण वार्षिकी
8. पत्रिका ईयर बुक
9. आउट लुक इंडिया
10. सैनिक समाचार
11. विजारड
12. नील दिप्त

समाचार–पत्र (News Papers)

1. The Times of India
2. Hindustan Times
3. दैनिक भास्कर
4. दैनिक जागरण
5. पंजाब केसरी
6. दैनिक हरिभूमि
7. राजस्थान पत्रिका
8. सीमा सन्देश
9. राष्ट्रीय सहारा
10. सहारा समय
11. अमर उजाला
12. दैनिक ट्रिब्यून